उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

----:0:-

खंड १३६

सोमवार, ३ मई, १९५४ से शुक्रवार, ७ मई, १९५४ तक



सुद्रक

मशीक्षक, राजशीय गुर्वणालय एवं लेखन-सामग्रं, उत्तर प्रदेश, ल**सम्ब**। १९५४

मूल्यः विना महसूल ४ ग्राने; महसूल हित ५ **ग्राने।** वाकिक चन्दाः विना महसूल १० दपये; महसू । तहित १२ दण्ये।

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	• •	• •	१-५
प्रश्नोत्तर	• •	• •	4-3 8
श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्ता	रो के संबंध में सूचना	• •	3 8
पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थान	**	• •	3 \$
श्री नारायगदत्त तिवारी द्वारा उठा विशेषाधिकार समिति के प्रति श्री राजनारायण की पुनः गि	विदन पर विचारार्थ समय		३ २
सदन के ग्रागामी कार्बंक्रम के सम्ब		• •	₹ २
उत्तर प्रदेश श्रीद्योगिक गृह-व्यवस्थ	**	sandra Georg man l	*
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोध		•	**
द्वारा संशोधित विषेयक पर		ुस्त अपर सामात	₹₹-७३
नित्थयां	,,,,,,,,,		43-8v
	गलवार, ४ मई, १६५	(४	
उपस्थित सदस्यों की सूची	• •	• •	60-100
सदस्य का शपथ ग्रहण करना	• •	• • •	१०१
प्रक्तोत्तर (जारी)	• •		१०१-१२१
ब्रनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननी	य मंत्रियों द्वारा " प्रक्त नह	ों उठता " कहने पर	
श्री श्रध्यक्ष का निर्णय	• •	• •	१२ १- १२ ३
प्रश्नोत्तर	• •	• •	१२२-१ २५
लाउड स्पीकर भौर पंत्रों की लराव	ît ··	• •	. १२४
भी राजनारायण की कथित गैरका कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचन	ि(प्रस्तुत करने की ग्रनुज्ञ	ा नहीं दी गयी)	१२५-१२७
कानपुर में भी राजनारायण की गिर ग्रवहेलना का प्रक्त उठाने की		षाधिकार की	, १ <i>२</i> ७
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन		तर जारी)	220-202
क्तिपय स्थायी समितियों के निर्वाच	•		१७ २
नत्थी		• • 1	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •	१७३
_	व्वार, ४ मई, १६५४	ş-m	. 1
उपस्थित सबस्यों की सूची	1 1	• •	१७१-१७=
प्रश्नोत्तर	4 6	1.4	16-161

विषय			पृष्ठ-संख्या
श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विद	ोषाधिकार की श्रवहेलना का	प्रश्न उठाने	
की प्रार्थना 🕠	• •	• •	१८१
इलाहाबाद यूनिवसिटी (संशोधन)) १६१
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन	r) विधेयक, १६५४ (विचार	र जारी)	१ ६२ –२३४
ग्रगले दिन के कार्यक्रम की सूचना	• •	• •	२३४
तृत्थियां • •	• •	• •	२३६–२६०
, .	हृहस्पतिवार ६ मई, १६	KR	
-द्रफ्स्थित सदस्यों की सूची	• •	• •	२६१-२६ ४
ःप्रक्नोत्तर • •		• •	२६५-२≈७
वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा सरि समितियों के तिर्वाचन में आ			₹ =% ₹ £ ¥
	विदन पर विचार (ग्रगले दि		त) २६४–२६८
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोध न	न) विघेयक, १९५४	* *	335
श्री नाराय ण इत स्तिवा री की गिरप पर विशेषाधिकार समिति का			ासा) २६६
किलेगिषिकार का प्रदुन उठाने के वि (भी अध्यक्ष की निर्णय अगले	लये श्री महन मोहन उपाय दिन के लिये स्थगित)	राय की प्रार्थना ••	₹00
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोध		त प्रवर समिति ह	
संशोबित विषेयक पर विचार	जारी)	• •	\$00-\$ <i>\$</i> 8
नेत्यियां	• •	• •	マスモーメ マ
शुः	कवार, ७ मई, १९५४		
उपस्थित सदस्यों की सूची	• •	• •	3×5>×6
. ६४१ से इस	• •		३ ५६-३८८
्र इसिनारायण की पुनः गिरकतार का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर	ी के सम्बन्ध में विशेषाधिका र श्री मध्यक्ष की व्यवस्था (ऽ	र की म्रवहेलना स्तुत करने की	
अनुसा नहा दा गया)	• •	• •	३८८-३८०
्ष्यनुकु यूनिवसिटी (संशोधन) रि सी नारायण बक्त विवारी ही गिरफ	तारों से सम्बद्ध विजेबाधिका	र की ग्रायकेसना	३६०
्र कावपय न विश्वाधकार साम	ात क प्रातवदन प्र विचार	जारी)	\$\$*0-80R
्र्यापृी समितियों के निर्माचन से ना ्रदेतर प्रवेश पंचायत राज (संशोधन	म वापस ज़ेने के समय में वृ ।) विषेयक, १६५४ को १२	द्धि की सूचना सर्वे १६५४ वर्ष	808-80X
्रवृत्तर प्रवेश पंचायत राज (संशोधन पारित करने के सम्बन्ध में प्र	स्ताव की सूचना	***	KoK '
श्री नारायण बत्त तिवारी की गिरण के विवय में विशेषाधिकाइ मु	सित के का सरावेश पर जिला	र (प्रदन	
्रामात का सव	सम्मात सं पुनः निविष्ट कि	या गुमा,)	४०४-४२६
्रृंडज़्द्रप्रदेश पंचायत राज (संशोधन मस्यियां) विषयकः/ १६५४ (विचाः	र चारी)	₹ 5€-₹ 3 €
नात्यया ।	+ 4	i s	みまの一名食中

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी । मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री सथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता ग्रौर नियोजन मंत्री।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, विघान समा-सदस्य, वित्ते तथा विद्युत मन्त्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, विधान सभा-सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासम् मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण-मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, स्वास्थ्य तथा ग्रन्न मंत्री।

श्री सैयद ग्रली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा-सदस्य, न्याय तथा मादक-कर मन्त्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभी-सवस्य, भाल तथा कृषि मंत्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी॰ एस-सी॰, एल-एल॰ बी॰, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा तंथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी॰ ए॰ (श्रानर्स), विधान सभा-सदस्य, स्वशासन मैत्री। श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिचाई मंत्री। श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, परिवहन मन्त्री।

उपमन्त्री

श्री मंगलात्रसाद, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, विधान सभा-सदस्य, सहकारिता उप-

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन उपमंत्री। श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी॰ एस-सी॰, एल-एल॰ बी॰, विधान-सभा सदस्य, कृषि उपमेत्री।

श्री मुजफ्फ़र हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमंत्री। श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमंत्री। श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

स्वशासन मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा-सबस्य।

अन्त-मन्त्री के सभा-सचिव

१--श्री बलवेवसिंह श्रायं, विधान सभा-सदस्य।

२--श्री बनारसीदास, विधान सभा-सदस्य।

उद्योग मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य ।

माल मन्त्री के सभा-सचिव

भी द्वारका प्रसाद और्य, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी॰ (विस), पी-एच० डी०, विघान सभा-सदस्य।

संदस्यों की वर्णातमक सूची तथा उनके निवचिन-क्षेत्र

	e	
सदस्यों का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—- ग्रंसमान सिंह, श्री		बस्ती (पूर्व)
२ग्रक्षयवर सिंह, श्री		गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—-ग्रजीज इमाम, श्री		मिर्जापुर (दक्षिण)
४ ग्रतहर हुसैन ख्वाजा, श्री		रुड़को (दक्षिण)
५ग्रनन्त स्वरूप सिंह, श्री		फ़नेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—-ग्रब्दुल मुईज खां, श्री		खलीलाबाद (मध्य)
७ग्रब्दुल रऊफ़ खां, श्री		फ़तेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—-ग्रमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री		मिर्जापुर (उत्तर)
६ग्रमृतनाथ मिश्र, श्री		उतरौला (दक्षिण)
१०—-ग्रली जहीर, श्री सैयद	• •	लखनऊ नगर (मध्य)
११ग्रवधशरण वर्मा, श्री	• •	फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—-ग्रवधेशचन्द्र सिंह, श्री	• •	छिबरामऊ (पूर्व)-फ़र्रुखाबाद (पूर्व)
१३——ग्रवधेशप्रताप सिंह, श्री	• •	बोकापुर (पूर्व)
१४—-ग्रशरफ़ ग्रली खां, श्री	• •	सादाबाद (पूर्व)
१५—-ग्रात्माराम गोविन्द खेर, श्री	• •	झांसी (पूर्व)
१६—–ग्रार्थर ग्राइस, श्री	• •	नाम-निर्देशित श्रांग्ल भारतीय
१७—–ग्राशालता व्यास, श्रीमती	• •	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इतिजा हुसैन, श्री	• •	बुलन्दशहर (उत्र-पश्चिम)
१६—इसरारल हक, श्री	• •	फिरोजाबाद–फ़तहाबाद
२०—=इस्तफा हुसैन, श्री		गोरखपुर (मध्य)
२१उदयभाने सिंह, श्री	• •	डलम्ऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री	• •	सगरी (पश्चिम)
२३––उमाशंकर तिवारी, श्री	• •	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनग्र
२४उमाशंकर मिश्र, श्री		नवाबगंज (दक्षिण)-हैद्रगढ़-रामसनेही घाट
२५—उम्मेदसिंह, श्री	• •	ज्तरौला (जत्तर–पूर्व)ू
२६—–उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्रो		ऐतमादपुर–्य्रागरा (पूर्व)
२७—-ऐजाज रसूल, श्री	• •	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—म्रोंकार सिंह, श्री	• •	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२६—कन्हैयालाल, श्री	• •	सिधौली (पश्चिम)
३०कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	• •	शाहाबाद (पूर्व) –हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
३१—-कमलापति त्रिपाठी, श्री	• •	चुकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३२कमला सिंह, श्री	• •	सैदपुर
३३—कमाल ग्रहमद रिजवी, श्री	• •	मोह्मदो (पूर्व)
३४—करण सिंह यादव, श्री	• •	गुन्नौर (उत्तर)
३५—करनसिंह, श्री	• •	निघासन–लखीमपुर (उत्तर)
३६—कल्याणचन्द मोहिले		
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	• •	इलाह्बाद नगर (म्ध्य)-इलाहाबाद
३७—कल्याण राय, श्री	• •	हजूर मिलक (उत्तर)

३८कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्रो		चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री		लालगंज (दक्षिण)
४०काशीचरण टण्डन, श्री		कन्नौज (उत्तर)
४१—काशीप्रमाद पाण्डेय, श्री		कादोपुर
४२—किन्दरलाल, श्री		हरदोई (पूर्व)
४३—किशनस्वरूप भटनागर, श्री		खुरजा -
४४—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री		सुल्तानपुर (पश्चिम)
४५—कृपाशंकर, श्री	• •	हरैया (पूर्व) – बस्ती (पश्चिम)
४६कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	• •	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४७कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री		लितपुर (दक्षिण)
४६—कृष्णशरण ग्रायं, श्री	• •	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६ के दारनाथ, श्री	• •	मुरादाबाद (दक्षिण)
५०-केवल सिंह, श्री		सुरायाय (पायाय) सिकन्दराबाद (पूर्व)
५१—केशभान राय, श्री		बांसगांव (मध्य)
५२क्रेशवगुप्त, श्री		कराना (उत्तर)
५३—केशव पाण्डेय, श्री	• •	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
४४ —के शवराम, श्री	• •	सहसवान (पूर्व)
५५—कैलाश प्रकाश, श्री	• •	भरेठ नगरपालिका
५६—खयालीराम, श्री	• •	श्रमरोहा (पूर्व)
५७—खुशीराम, श्री	• •	प्रयोगायु-चम्पावत
५८—ब्बसिह, श्री	• •	धासवर (जनर गर्ने) ज्योग (-१)
५६—गंगाघर, श्री	• •	घामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६०—गंगाघर जाटव, श्री	• •	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर) फ़िरोजाबाद—फतेहाबाद
६१—गंगाघर शर्मा, श्री	• •	मिश्रिख
६२—गंगाप्रसाद, श्री	• •	
६३—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	••	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६४गजेन्द्र सिंह, श्री	• •	रसरा (पश्चिम) विघूना (पूर्व)
६५—गज्जूराम, श्री	••	सङ्गोर (विकार) कांची ()
	• •	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम) लुलितपुर (उत्तर)
६६—गणेशचन्द्र काछी, श्री	• •	मैतपरी (उन्नर) भोनं ()
६७—गणेगप्रसाद जायसवाल, श्री		मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६८—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री		इलाहाबाद नगर (पूर्व) बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६गिरजारमण शुक्ल, श्री		पट्टी (दक्षिण)
७०—गिरघारी लाल. श्री	• •	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
७१गुप्तार मिह, श्री		डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	• •	संजुहा (पश्चिम)
७३—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	• •	संसाफिरवाना (अधिकार)
७४गलजार. श्री	• •	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—ग्रमेठी (पश्चिम)
७५—गेंदासिंह, श्री	• •	मुसाफिरलाना (उत्तर)-सुलतानपुर (उत्तर) पडरौना (पूर्व)
७६—गोपोनाथ दोक्षित, श्री	• •	इटावा (दक्षिण)
७७गोवर्घन तिवारी, श्री		अल्मोड़ा (दक्षिण)
७८—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	• •	बरेली नगरपालिका
७६—गौरीराम, श्री	• •	फरेंबा (मध्य)
		(

८०घनश्यामदास, श्री		नवाबगंज (दक्षिण)–हैदरगढ़–
		रामसनेही घाट
द १—्घासीराम जाटव, श्री		बिधूना (पश्चिम)-भरथना
		(उत्तर)–इटावा (उत्तर)
८२—चतुर्भ् ज शर्मा, श्री		उरई–जालीन (दक्षिण)
द३चन्द्रभानु गुप्त, श्री		लखनऊ नगर (पूर्व)
८४—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री	- •	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व) –गोंडा (दक्षिण)
८५—चन्द्रवती, श्रीमती		बिजनौर (मध्य)
८६—चन्द्रसिंह रावत, श्री		पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८७च द्रहास, श्री		हरदोई (पूर्व)
दद—चरणसिंह, श्री		बागपत (पश्चिम)
८६—चित्तरसिंह निरंजन, श्री		कोंच
६०-चिरंजीलाल जाटव, श्री		जलेसर-एटा (उत्तर)
६१—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री		छिबरामऊ (दक्षिण) – कन्नौज (दक्षिण)
६२—चुझीलाल सगर, श्री		बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
६३—छेंदालाल, श्री		शाहाबाद (पूर्व) –हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
६४ छेदालाल चौधरी, श्री		लखोमपुर (दक्षिण)
६५जगतनारायण, श्री		नवाबगंज (उत्तर)
६६—जगदीशप्रसाद, श्री		हसनपुर (देक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
. ६७जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	• •	सम्भल (पूर्व)
६८ जगनप्रसाद रावत, श्री		खैरगढ़
६ ६—जगन्नाथ प्रसाद, श्री		निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
१००—जगन्नाथबख्श दास, श्री		रामसनेही घाट
१०१—जगन्नाथ मल्ल, श्री		पडरौना (उत्तर)
१०२—जगन्नाथ सिंह, श्री		बलिया (उत्तर-पूर्व)–बांसडीह
		(दक्षिण-पश्चिम)
१०३जगपति सिंह, श्री		मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०४जगमोहन सिंह नेगी, श्री		लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०५—–जटाशंकर शुक्ल, श्री	• •	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
१०६—जयपाल सिंह, श्री		रुड़को (पश्चिम) –सहारनपुर (उत्तर)
१०७जयराम वर्मा, श्री	• •	श्रकबरपुर (पश्चिम)
१०८—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	• •	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०६—-जवाहरलाल, श्री	• •	करछनो (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
११०—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	• •	कानपुर नगर (पूर्व)
१११—-जुगलिक्ञोर, श्री	• •	मथुरा (दक्षिण)
११२जोरावर वर्मा, श्री	• •	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
११३—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	• •	गोंडा (दक्षिण)
११४—झारखंडे राय, श्री	• •	घोसी (पश्चिम)
११५—टोकाराम, श्री	• •	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्वे)
११६—-डल्लाराम, श्री	• •	मिश्रिल (
११७—डालचन्द, श्री	• •	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११५—तिरमल सिंह, श्री	• •	कासगंज (उत्तर)
११६—-तुलसीराम, श्री	• •	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
१२०—तुंलाराम, श्री	• •	भ्रौरैया-भरयना (दक्षिण)

१२१—-तुलाराम रावत, श्रो	• •	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२२—जेंजप्र तथ सिंह, श्री	• •	मौदश (दक्षिण)
१२३—–तेजबहादुर, श्री	• •	नालगंज (उत्तर)
१२४—तेजासिंह, श्री	• •	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२५—-त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	• •	बहराइच (पश्चिम)
१२६—दयालदास भगत, श्री	• •	घाटमपुर–भोगिनीपुर (पूर्व)
१२७ —द र्शन राम, श्री	• •	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२म —दलब हादुर सिंह, श्री		सलोन (दक्षिण)
१२६—-दाऊदयाल बन्ना, श्री		मुरादाबोद (उत्तर)
१३०—्वाताराम, श्री		नकुड़ (दक्षिण)
१३१—दीनदयालु शर्माः श्री		भ्रन् पेशहर (उत्तर)
१३२—दोनदयालुँ ज्ञास्त्री, श्री		रुड़ेकी (पूर्व)
१३३—दीपनारायण वर्मा, श्री		जौनपुर (पिर्दचम)
१३४—देवकीनन्दन विभव, श्री	• •	ग्रागरा
[≉] १३५—दोवान सु दर दास, श्री		कैसरगंज (उत्तर)
१३६देवदत्त मिश्र,श्री		पुरवा (दक्षिण)
१३७देवदत्त शर्मा, श्री		बुलंदशहर (दक्षिण)—स्रनूपशहर (दक्षिण)
१३८—देवनन्दन शुक्ल, श्री	• •	संलीमपुर (पश्चिम)
१३६—-देवमूर्ति राम, श्री	• •	बनारसँ (पेदिचम)
१४०—-देवराम, श्री	• •	सैदपुर
१४१—देवे द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	• •	गोरखपुर (पश्चिम)
१४२—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	• •	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४३—द्वारका प्रसाद मौर्य,श्री	• •	मरियाहूं (उत्तरे)
१४४—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	• •	फरेंदा (दक्षिण)
१४५धनुषवारी पाण्डेय, श्री	• •	बलीलाबाद (दक्षिण)
१४६—धर्मसिह, श्री	•••	बुलन्दशहर (दक्षिण)-ग्रनुपशहर (दक्षिण)
१४७—धर्मदत्त वैद्य, श्री	• •	बहुड़ा (दाक्षण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्यूसिह, श्री	• •	ग्राश्रोंना (पूर्व)~फरीदपुर
१४६नन्बकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	• •	हाथरस
१५०—नरदेव शास्त्री, श्री	• •	पश्चिमी वून-(बिक्षण)-पूर्वीय दून
१५१—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	• •	पिथारागढ्-चम्पादत
१५२—नरोत्तम सिंह, श्री	• •	दातागंज (दक्षिण)—बदायं (दक्षिण-पूर्व)
१५३—नवलिक्योर, श्री	• •	आश्राला (पारचम)
१५४—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	• •	मछलीशहरं (उत्तरं)
१५५—नाजिम ग्रली, श्री	• •	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५६—नारायण दत्त तिवारी, श्री	• •	ननाताल (उत्तर)
१५७ नारायणदास, श्री	• •	फैजाबाद (पूर्व)
१५८—नारायणदोन वाल्मोकि, श्री	• •	पवायां-ताहजहांपुर (पूर्व)
१५६—निरंजन सिंह, श्री १६०—नेकराम शर्मा, श्री	• •	पालाभात (पूर्व)-बीसलपर (पश्चिम)
१६१—नेत्रपाल सिंह, श्री	• •	।सकन्दराराव (दक्षिण्)
१६२—नौरंगलाल, श्री	• •	सिकन्दराराव (उत्तर) -कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नारपलाल, श्रा	• •	नवाबगंज

^{*} ४ मई, १६५४ को निर्वाचित ।

	• •	मृहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६४परमानन्द सिन्हा, श्री •	•	सोरावं (दक्षिण)
	• •	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६६परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	• •	महाराजगंज (उत्तर)
	• •	बांदा
१६५—पातीराम, श्री		छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६६—पुत्त्ताल, श्रो		ऐतमादपुर-श्रागरा (पूर्व)
१७०-पुद्दनराम, श्री	• •	बांसी (उत्तर)
१७१—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री		लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७२—प्रकाशवती सूद, श्रीमती		हापुड़ (उत्तर)
१७३—प्रतिपाल सिंह, श्री		शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)
१७४प्रभाकर शुक्ल, श्री		हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७५—प्रभुवयाल, श्री		बस्ती (पश्चिम)
१७६ — प्रेमिकशन खन्ना, श्री		पवायां-शोहजहांपुर (पूर्व)
१७७—फजलुल हक्र, श्री		रामपुर नगर
१७८—फतेह सिंह राणा, श्री		सरधना (पश्चिम)
१७६—फूलसिंह, श्री		देवबन्द `
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री		सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसीदास, श्री		बुलन्दर्शहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री		बनारस (मध्य)
१८३—बलदेल सिंह स्रार्य, श्री		पौड़ी (देक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री		गाजियोबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री		उतरौला (उत्तर)
१८६—वलवन्त सिंह, श्री	• •	मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८७—वशीर श्रहमद हकीम, श्री		सीतापुर (पूर्व)
१८८—वसन्तलाल, श्री		कालपी-जालौन (उत्तर)
१८६—बसन्तलाल शर्मा, श्री	• •	नानपारा (उत्तर)
१६०बाबूनन्दन, श्री		शाहगंज (पूर्व)
१९०—चाबुराखाः, आ		कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री		रामसनेहीघाट
१६२—बाबूलाल कुंसुमेश, श्री १६३—बाबूलाल मित्तल, श्री		ग्रागरा नगर (उत्तर)
१६२—बाबुलाल स्टाराजकमार		देहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९४—बालेन्द्रशाह, महाराजकुमार		सरघना (पूर्व)
१६५—-बिशम्भर सिंह, श्री १६६—-बेचनराम, श्री		ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
		ज्ञानपुर (पूर्व)
१६७—बेचनराम गुप्त, श्री	• •	कानपुर तहसील
१६५—बेनीसिंह, श्री		बांसडीह (मध्य)
१६६—वेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री		कानपुर नगर (दक्षिण)
२००—बहादत्त दोक्षित, श्री	• •	. जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	• •	. बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०२भगवतीप्रसाद दुवे, श्री	• •	. बातगाय (तूम)-गारखपुर (याया <i>ग)</i> . प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	•	. त्रतापाढ़ (त्रूप) . फतेहपुर (दक्षिण)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	•	. कतहत्रुर (बासण) . फतेहपुर (बक्षिण)-खागा (बक्षिण)
२०५भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	• •	. नतहरू (दाक्षण)-सामा (दाक्षण) . तिलहर (दक्षिण)
२०६—भगवान सहाय, श्री	•	

२०७—भोमसेन, श्री	खुरजा
२०६—भुवरजी, श्री	फूँल _{ोु} र (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०६-भूपाल सिंह खाती, श्री	ग्रल्मोड़ा (उत्तर)
२१०-भूगुनाय चतुर्वेदी, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११भोला सिंह यादव, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मकसूद ग्रालम खां, श्री	पोलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१४—मयुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद (परिचम)-छिबरामऊ
२१५-मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री	फैजाबाद (पूर्व)
२१७मदनगोपाल उपाध्याय, श्री	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	महोबा-कुलेपहाड़-चरखारी
२१६—मलखान सिंह, श्री	कोइल (मध्य)
२२० — महमूद ग्रली खां, श्री	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद ग्रली खां, श्री	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२२—महाजन, श्री सी० वी० .	श्रागरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेव प्रसाद, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४ महाराज सिंह, श्री	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री .	हंडिया (दक्षिण)
२२६ — महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री .	मोहनलालगंज 🦳
२२७ महाबीर सिंह, श्री	हाटा (उत्तर)
२२५—महोलाल, श्री	बिलार <u>ी</u>
२२६—मान्याता सिंह, श्री	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३०—मिजाजी लाल, श्री	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३१—मिहरबान सिंह, श्री	विघूना (पेश्चिम)-भरथेना (उत्तर)-
	इटावा (उत्तर) ।
२३२ मुजफ्फर हसन, श्री	चायल (उत्तर)
२३३ — मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	पूरनपुर-बोसलपुर (पूर्व)
२३४ मुन्नूलाल, श्रो	बिसवां-सिघौली (पूर्वे)
२३४ मुरलीघर कुरील, भी	बिल्हौर-श्रकबरपुरे ेे 🖊
२३६—मुश्ताक मली खां, श्री	सहस्वान (पश्चिम)
२३७मुहम्मद श्रदील श्रव्वासी, श्री	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३५ मुहम्मद म्रब्दुल लतोफ़, श्री	विजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३६मुहम्मद घ्रब्दुस्समद, श्री	बनारस नगर (उत्तर)
२४० - मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-घामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४१ - मुहम्मद तको हादी, श्री	अमरोहा [ं] (पश्चिम)
२४२मुहम्मद नबी, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (विक्षण)
२४३—मुहम्मद नसीर, श्री	टाडा
२४४मुहम्मद फाल्क्न चिस्ती, श्री	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४५ - मुहम्मव मंजूरलनबी, श्री	सहारनपुर नगर
२४६ — मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	मछलीशहर (दक्षिण)
२४७ मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	उतरीला (मध्य)
२४८ - मुहम्मद सम्रादत म्रली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)
२४६ - मुहम्मद सुलेमान झबमी, श्री	डुमरिया गंज (उत्तर-पूर्व)
	== *

```
सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०--मोहन लाल, श्री
२५१--मोहन लाल गौतम, श्री
                                       खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
                                       बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२--मोहन सिंह, श्री
                                       म्रलीगंज (दक्षिण)
२५३--मोहन सिंह शाक्य, श्री
                                       बहराइच (पश्चिम)
२५४---यमुना प्रसाद, श्री
                                       गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५---यमुना सिंह, श्री
                                       बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६--यशोदादेवी, श्रीमती
                                       मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७--रघुनाथ प्रसाद, श्री
                                       तरबगंज (पश्चिम)
२५८--रघुराज सिंह, श्री
                                       बागपत (दक्षिण)
२५६--रघुंबीर सिंह, श्री
                                       श्रमेठी (मध्य)
२६०--रणंजय सिंह, श्री
                                       नजीबाबाद (उत्तर)
२६१--रतनलाल जैन, श्री
२६२--रमानाथ खेरा, श्री
                                       महरौनी
२६३--रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
                                       मरियाहं (दक्षिण)
२६४---रमेश वर्मा, श्री
                                       किराउली
                                       उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५--राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
२६६—राजिकशोर राव, श्री
                                       बहराइच (पूर्व)
२६७--राजकुमार शर्मा, श्री
                                       चुनार (उत्तर)
                                       बनारस (दक्षिण)
२६८--राजनारायण , श्री
                                       चुनार (दक्षिण)
२६६-राजनारायण सिंह, श्री
                                      पहरौना (दक्षिण-पश्चिम) -वेषरिया (वक्षिण-पश्चिम)
२७०--राजवंशी, श्री
                                       ग्रतरौली (दक्षिण)-कोईल (पूर्व)
२७१--राजाराम, श्री
                                       प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुन्डा (उत्तर)
२७२---राजाराम किसान, श्री
                                       फैजाबाद (पश्चिम)
२७३--राजाराम मिश्र, श्री
२७४---राजाराम शर्मा, श्री
                                       खलीलाबाद (उत्तर)
                                       मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७५---राजेन्द्र दत्त, श्री
२७६—राघाकृष्ण ग्रग्रवाल, श्रो
                                       बिलग्राम (पूर्व)
                                       बलिया (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री
२७८--राम भ्रधार तिवारी, श्री
                                       प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पि
२७६--रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
                                       पुरवा (मध्य)
२८०-रामग्रनन्त पांडेय, श्री
                                       बलिया (मध्य)
२८१--राम ग्रवघ सिंह, श्री
                                       फरेंदा (उत्तर)
२८२--रामकिंकर, श्री
                                       प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम
                                       बांसी (दक्षिण)
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री
२८४--रामकृष्ण जैसवार, श्री
                                       मिर्जापुर (दक्षिण)
                                       जलालाबाद (पश्चिम)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री
२८६--रामचन्द्र विंकल, श्री
                                       सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७--रामचरनलाल गंगवार, श्री
                                       बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजी लाल सहायक, श्री
                                       देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८६--रामजी सहाय, श्री
                                 • •
२६०--रामदास ग्रार्य, श्री
                                       बुढाना (पूर्व)-जानसठ (बक्षिण)
                                 • •
                                 . .
२६१—रामदास रविदास, श्री
                                       म्रकबरपुर (पश्चिम)
२६२--राम बुलारे मिश्र, श्री
                                       ग्रकबरपुर (दक्षिण)
२६३--रामनरेश शुक्ल, भी
                                       कुन्डा (वक्षिण)
```

```
5
                                                निर्वाचन-क्षेत्र
     सदस्य का नाम
                                       म्रकबरपुर (पूर्व )
२६४--रामनारायण त्रिपाठी, श्री
                                      राय बरेली--डलमऊ (उत्तर)
२९५---रामप्रसाद, श्री
                                      खर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९६--रामप्रसाद देशमुख, श्री
२६७--रामप्रसाद नौटियाल, श्री
                                      लैन्सडाउन (पूर्व)
                                      महराजगंज (दक्षिण)
२६८--रामप्रसाद सिंह, श्री
                                      मुल्तानपुर (पूर्व)-म्रमेठी (पूर्व)
२६६--रामबली मिश्र, श्री
३००---रामभजन, श्री
                                      मोहमदी (पश्चिम)
३०१--राममूर्ति, श्री
                                      बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
                                       रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०२--रामरतन प्रसाद, श्री
                                       पट्टी (पूर्व)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री
                                       चिकया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०४---शमलखन, श्री
                                       डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री
                                       बस्ती (पश्चिम)
३०६--रामलाल, श्री
                                       फूलपुर (दक्षिण)
३०७---रामवचन यादव, श्री
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री
                                       रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०६--रामशंकर रविवासी, श्री
                                       लखनऊ (मध्य)
३१०--रामसनेही भारतीय, श्री
                                       बबेरू (पश्चिम)
                                 . .
                                       गरोठा मोठ (उत्तर)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री
३१२--रामसुन्दर पांडेय, श्री
                                       घोसी (पूर्वं)
३१३---रामसुन्दर राम, श्री
                                       खलीलाबाद (वक्षिण)
३१४---रामसुभग वर्मा, श्रो
                                       पडरौना (पश्चिम)
३१५--रामसुमेर, श्री
                                       टांडा
                                 . .
३१६---रामस्वरूप, श्री
                                        दूघी-राबर्टसगंज
                                       भौगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३१७--रामस्वरूप गुप्त, श्री
                                 • •
३१८--रामस्वरूप भारतीय, श्री
                                        कुंडा (दक्षिण)
                                 . .
३१६--रामस्वरूप मिश्र,"विशारद",
                                        महाराजगंज (पश्चिम)
३२०--रामहरख यादव, श्री
                                        बीकापुर (पश्चिम)
३२१---रामहेत सिंह, श्री
                                        छत्ता
३२२--रामेश्वर प्रसाद, श्री
                                        महराजगंज (पश्चिम)
३२३--रामेश्वर लाल, श्री
                                        देवरिया (दक्षिण)
 ३२४--लक्मणदत्त भट्ट, श्री
                                        नैनीताल (दक्षिण)
                                  • •
                                        मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर
 ३२५—लक्ष्मणराव कदम, श्री
                                         (उत्तर)
 ३२६--लक्मोदेवो, श्रीमती
                                         संडीला-बिलग्राम (दक्षिण पूर्व)
 ३२७—लक्ष्मी रमण प्राचार्य, श्री
                                         माट-सादाबाद (पश्चिम)
 ३२८--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
                                         शाहगंज (पूर्व)
                                   . .
 ३२६--लताफ़त हुसैन, श्री
                                         हसनपुर (उत्तर)
                                   • •
 ३३०--लालबहादुर सिंह, श्री
                                         कराकट-जौनपुर (दक्षिण)
 ३३१ — लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री ...
                                         बनारस (उत्तर)
```

ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम) • •

उन्नाव (दक्षिण)

हापुड़ (दक्षिण)

सम्भल (पूर्व)

३३२—लोलाबर ग्रष्ठाना, श्री

३३५—वंशनारायण सिंह, श्री

३३६ - वंशीवास धनगर, श्री

३३३--लुत्फ अली खां, श्री

३३४—लेखराज सिंह, श्री

करहल (परिचम)-शिकोहाबाब (पूर्व)

सदस्य का नाम		Manager and
३३७वंशीधर मिश्र, श्री		लखीमपुर (दक्षिण)
३३८—वसी नकवी, श्री		महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३६वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री		कानपुर नगर (मध्य-पिइचम)
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री		गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री		महम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती		एँटा (पूर्व) श्रलीगढ़ (पश्चिम)कासगंज-(दक्षिण)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री		गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विश्राम राय, श्री		सगरीँ (पूर्व)
३४५—विष्णु दयाल वर्मा, श्री		जसराना े
३४६—विष्णुशरण बुब्लिश, श्री		मवाना
३४७—वीरसन, श्री		हापुड़ (दक्षिण)
३४८—वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री		बिलग्राम (पिर्चिम)
३४६—वीरेंद्रपति यादव, श्री		मैनपुरी (दक्षिण)
३५०-वीरद्र वर्मा, श्री	• •	कैराना (दक्षिण)
३५१वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री		नानपारो (पूर्व)
३५२—वीरेंद्रशाह, राजा		कालपी-जालौन (उत्तर)
३५३—-व्रजभूषण मिश्र, श्री		दूधी-राबर्टसगंज
३५४व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	• •	बिल्होर-श्रकबरपुर
३५५—व्रजवासी लाल, श्री	• •	बीकापुर (मध्य)
३५६ वजिंबहारी मिश्र, श्री	• •	फूलपुर (उत्तर)
३५७—-व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	• •	घोटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५८—शंकरलाल, श्री		कावीपुर (मध्य)
३५६शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री		बाह
३६०शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री		चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री		तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री		बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	• •	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	• •	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण , श्री	• •	हरेया (पूर्व)-बस्ती-(पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री		मुहम्मदोबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	• •	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री		बांसडीह (पश्चिम)
३६६शिवमंगल सिंह कपूर, श्री		डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—िशवराज ब्ली सिंह, श्री	• •	खजुहा (पूर्व) – फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री		बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पांडेय, श्री	• •	डोरापुर (उत्तर)
३७३शिवराम राय, श्री		सदर (श्राजमगढ़-उत्तर)
३७४—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	• •	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७५—-शिववचन राव, श्री		सलीमपुर (उत्तर)
	e s	
३७६—शिवशरण लाल श्रीवास्तव	, =11	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	• •	ठाकुरद्वारा महराजगंज (वक्षिण)
३७६शुकरेव प्रसाद, श्री	• •	नहराजगज (दासाग) रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (जुत्तर)
३७६—-शुगन चन्द्र, श्री	• •	रक्षा (भारचन)-तहारनपुर (उत्तर) मन्त्रियानम् जाराजंदी (जन्म-मन्त्रिम)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	• •	मिलहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)

३८१—श्यामलाल, श्री	उतरौला (उत्तर)
३८२—स्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री	नरैनी
३६३श्रीचन्द, श्री	बुढाना (पश्चिम)
३८४श्रीनाथ सार्गव, श्री	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाय राम, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	उतरौली (उत्तर)
३८६—श्रीनिवास पंडित, श्री	बबायूं (उत्तर)
	राठ
३८८—श्रीपति सहाय, श्री	
३८६—मईद जहांमखफी शेरवानी, श्रीमती	कासगंज (पूर्व) – ग्रलीगंज (उत्तर)
३६० — संप्राम सिंह	सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)
३६१—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	सलीमपुर (पूर्व)
३६२—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	गोंडा (पूर्व)
३६३—सत्यनारायण दत्त, श्री	भ्रोरेया-भरथना (वक्षिण)
३६४—सत्यसिंह राणा, श्री	देवप्रयाग
३६५ — सिफया ग्रब्दुल वाजिद, श्रीमती	बरेली (पूर्व)
३६६ — सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	बन्।रस नगर (दक्षिण)
३६७-सहदेव सिंह, श्री	जलेसूर (एटा) (उत्तर)
३६८ सावित्रीदेवी, श्रीमती	मुसाफिरखाना (मध्य)
३६६—सियाराम गंगवार, श्री	फुरेलाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
४००—सियाराम चौघरी, श्री	कैसरगंज (मध्य)
४०१सोताराम, डाक्टर	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०२ सीताराम शुक्ल, श्री	ह्रैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०३—सुस्तीराम भारतीय, श्री	सिरायू-मंझनपुर
४०४ सुन्दरलाल, श्री	श्राश्रौंला (पूर्व)–फरीदपुर
४०५ सुरुजूराम, श्री	सदर (श्राजमगढ़) (उत्तर)
४०६ सुरॅद्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०७ सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	बिसवा-सिघौली (पूर्व)
४०५ सुल्तान म्रालम खां, श्री	कायमगंज (पिक्चमे)
४०६ - सूर्य्य प्रसाद ग्रवस्थी, भी	कानपुर नगर (उत्तर)
४१०—सूर्यंबली पांडेय, श्री	हाटा (मध्य)
४११—सेवाराम, श्री	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
४१२—हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री	सिघौलो (पश्चिम)
४१३ - हबीबुर्रहमान ग्रन्सारी, श्री	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१४ — हबीबुर्रहमान भ्राजमी, श्री	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
४१५ —हबीबुर्रहमान खां हकीम. श्री	शाहजहांपुर (मध्य)
४१६हमाद खा, श्री	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१७ हरखयाल सिंह, श्री	बागपत (पूर्व)
४१६—हरगोविन्द पंत, श्री	रानीखेत (विक्षण)
४१६—हरगोविन्द सिंह, श्री	जौनपुर (पूर्व)
४२०—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	हायरस
हरदव सिंह, श्री	देवबन्द
४२२—हरसहाय गुप्त, श्री	विलारी विलारी
^० ४२हारप्रसाद, भी	विसलपुर (मध्य)
V3V	नितापुर (चळ्य) सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
	३८ (<i>७ तरन्</i> याश्रम्भ)

निवचिन-क्षेत्र

४२५—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री .. लखनऊ (मध्य)
४२६—हरिसिंह, श्री .. हापुड़ (उत्तर) .
४२७—हुकुम सिंह, श्री .. कैसरगंज (विक्षण)
४२६—हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री .. करछना (उत्तर)—चैल (विक्षण)
४२६—होतीलाल वास, श्री .. एटा (विक्षण)
४३०—(रिक्त) .. गाजीपुर (विक्षण-पूर्व)
४३१—(रिक्त) .. सिराथू-मंझनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रे

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ग्रात्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राघेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल०, एस-सी० ।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम, एल-एल० बी०।

अधीक्षक '

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एत० बी०। श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में श्रध्यक श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर की श्रध्यक्षता में श्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

ग्रक्षयवर सिंह, श्री ग्रजीज इमाम, श्री श्रनन्तस्वरूप सिंह, श्री ग्रब्दुल मुईज खां, श्री म्रमरेशचन्द्र पांडेय, श्री ग्रमुतनाथ मिश्र, श्री श्रली जहीर, श्री सैयद ग्रवधशरण वर्मा, श्री ग्रवधेश चन्द्र सिंह, श्री श्रवारफ श्रली खां, श्री ग्राशालता व्यास, श्रीमती इरतजा हुसैन, श्री इस्तफा हुसैन, श्री उदयभान सिंह, श्री उमाशंकर, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री उम्मेद सिंह, श्री उल्फर्तसिंह चौहान निर्भय, श्री ऐजाज रसूल, श्री ग्रॉकार सिंह, श्री कन्हैयालाल , श्री कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री कमाल ग्रहमद रिजवी, श्री करन सिंह, श्री कल्याणराय, श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री कालीचरण टंडन, श्री किन्दरलाल, थी किञ्जहर्वरूप भटनागर, श्री

कूंवरकृष्ण वर्मा, श्री कृपाशंकर, श्रो कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री कृष्णशरण श्रार्य, श्री केवल सिंह, श्री केशभान राय, श्री केशव गुप्त, श्री केशव पांडेय, श्री केशवराम, श्री कॅलाश प्रकाश,श्री खुशीराम, श्री गंगाघर, श्री गंगाघर जाटव, श्री गंगाधर शर्मा, श्री गंगा प्रसाद, श्री गंगा प्रसाद सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री गणेश प्रसाद पांडेय, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्री गुप्तार सिंह, श्री गुरु प्रसाद पांडेय, श्री गुरुप्रसाद सिंह, श्री गुलजार, श्री गेंदा सिंह, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री गोविन्द बल्लभ पंत, श्री गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्री चन्द्रवती, श्रीमती चन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्रहास, श्री चरण सिंह, श्री चित्तर सिंह निरंजन, श्री चिरंजीलाल पालीवाल, श्री चुन्नोलाल सगर, श्री छेदालाल, श्री छेदालाल चौधरी, श्री जगतनारायण, श्री जगदीश प्रसाद, श्री जगन प्रसाद रावत, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगन्नायबस्य दास, श्री जगन्नाय मल्ल, श्रो जगन्नाथ सिंह, श्री जगपति सिंह, श्री जगमोहन सिंह नेगी, श्री जटाशंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री जयराम वर्मा, श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री जवाहरलाल, श्रो जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर जोरावर वर्मा, श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री झारखंडेराय, श्री टीकाराम, श्री डल्लाराम, श्री डालचन्द, श्री तुलसीराम, श्री तुलाराम, श्री तुलाराम रावत, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री तंजबहादुर, श्रो तेजा सिंह, श्री त्रिलोकीनाथ कौल, श्री देयालदास भगत, श्री दर्शनराम, श्री बलबहादुर सिंह, श्री दीनदयालु शर्मा, श्री दोपनारायण वर्मा, श्री वेवदत्त मिश्र, श्री देवदत्त शर्मा, श्री

देवनन्दन शक्ल, श्रो देवराम, श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री धनबधारी पांडेय, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री नत्थू सिंह, श्रो नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री नरदेव शास्त्री, श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री नरोत्तम सिंह, श्री नवलिक्शोर, श्री मागेश्वर द्विवेदी, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री नारायणदास, श्री न।रायणदीन वाल्मीकि, श्री निरंजन सिंह, श्रो नेकराम शर्मा, श्री नेत्रपाल सिंह, श्री पद्मनाथ सिंह, श्री परमानन्द सिन्हा, श्री परमेश्वरीराम, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्रो पहलेवान सिंह चोधरी, श्री पातीराम, श्री पुत्तूलाल, श्री पुद्दनराम, श्री पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री प्रकाशवती सूद, श्रीमती प्रतिपाल सिंह, श्री प्रभाकर शुक्ल, श्री प्रभ्वयाल, श्री प्रेमकिशन खन्ना, श्री फजलुल हक, श्री फतेहसिंह राणा, श्री बद्रीनारायण मिश्र, श्री बनारसी दास, श्री बलदेव सिंह, श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री बलवन्तसिंह, श्री बशीर ग्रहमद हकीम, श्री बसन्तलाल, श्री बसन्तलाल शर्मा, श्री बाबनन्दन, श्री बाबूलाल कुसुमेश, श्री बाबुलाल मीतल, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

बालेन्द्रशाह, महाराजकुमार बिशम्भर सिंह, श्री बेचनराम, श्रा बेचनराम गुप्त, श्री बेना सिह, श्रा बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्रं। ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्रा भगवती प्रसाद दुबे, श्रा भगवतं। प्रसाद शुक्ल, श्रा (प्रतापनद्) भगवतोप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) भगत्रानदोन वाल्मोक्ति, श्री भगवान सहाय, श्रो भःमसेन, श्र भुवरजी, श्री भूपाल सिंह खाती, श्री भृगुनाथ चतुर्येदा, श्री भोला सिंह यादव, श्री मकसूद श्रालम खां, श्री मंगला प्रसाद, श्री मयुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री मयुराप्रसाद पांडेय, श्री मदनगोपाल वेद्य, श्री वदनमोहन उपाध्याय, श्री मन्नीलाल गुरुदेव, श्री मलखा । सिंह, श्री महमूद ग्रली खां, श्री (रामपुर) महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) महावेव प्रसाद, श्री महाराज सिंह, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री महावीर सिंह, श्री महोलाल, श्री मान्धाता सिंह, श्री मिजाजीलाल, श्री मिहरबान सिंह, श्री मुजफ्फर हसन, श्री मुनोन्द्रपाल सिंह, श्री मुन्नूलाल, श्री मुरलीधर कुरील, श्री मुश्ताक ग्रली खर्र, श्री मुहम्मद ग्रदील ग्रद्धासी, श्री मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज मुहम्मद नसीर, श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री मुहम्मद सुलेमान ग्रधमी, श्री

मोहनलाल, श्री मोहनलाल गौतम, श्री मोहन सिंह, श्री मोहन सिंह शाक्य, श्री यमुना सिंह, श्री यशोदादेवी, श्रीमती रवुन।थप्रसाद, श्रो रघुराज सिंह, श्री रघुंबीर सिंह, श्रो रमेश वर्मा, श्रो राजिकशोर राव, श्री राजकुमार शर्मा, श्रो राजनारायण सिंह, श्री राजबंशी, श्री राजाराम किसान, श्री राजाराम मिश्र, श्री राजाराम शर्मा, श्रो राजेन्द्र दत्त, श्री राधाकृष्ण श्रग्रवाल, श्री राधामोहन सिंह, श्रो रामग्रधार तिवारी, श्री राम ग्रघोन सिंह यादव, श्री रामग्रनन्त पांडेय, श्री राम भ्रवध सिंह, श्री रामिककर, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री रामकृष्ण जैसवार, श्री रामगुलाम सिंह, श्री रामचन्द्र विकल, श्री रामचरण लाल गंगवार, श्री रामजीलाल सहायक, श्री रामजी सहाय, श्री रामदास ग्रार्य, श्री रामदास रविदास, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री राम नरेश शुक्ल, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री रामप्रसाद, श्री रामप्रसाद नौटियाल, श्री रामप्रसाद सिंह, श्री रामबली मिश्र, श्री रामभजन, श्री रामरतन प्रसाद, श्री रामराज शुक्ल, श्री रामलखन, श्री रामलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री रामवचन यादव, श्रो रामशंकर द्विवेदी, श्री रामशंकर रविवासी, श्री रामसनेही भारतीय, श्री रामसहाय शर्मा, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री रामसुन्दर राम, श्री रामसुभग वर्मा, श्री रामसुमेर, श्री रामस्वरूप, श्री रामस्बरूप गुप्त, श्री रामस्वरूप भारतीय, श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री रामहरल यादव, श्री रामहेत सिंह, श्री रामेश्वरप्रसाद, श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री लक्ष्मीदेवी, श्रीमती लक्ष्मीशंकर यादव, श्री लालबहादुर सिंह, श्री लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री लोलाघर ग्रष्ठाना, श्रो लुत्फग्रली खां, श्री लेखराज सिंह, श्री वंशनारायण सिंह, श्री वंशोदास धनगर, श्री वंशीघर मिश्र, श्री वासूदेव प्रसाद मिश्र, श्री विजयशंकर प्रसाद, श्री विद्यावती राठौर, श्रीमती विष्णुदयाल वर्मा, श्री विष्णुशरण दुब्लिश, श्री वीरसेन, श्री वोरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री बीरेन्द्र वर्मा, श्री वीरेंद्रशाह, राजा नजमूबण मिश्र, श्री वजरानी मिश्र, श्रीमती वजबासी लाल, श्री वजिवहारी मिश्र, श्री वजिंहारी मेहरोत्रा, श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री शिवनारायण, श्री शिवप्रसाद, श्री

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री शिवराजबली सिंह, श्री शिवराज सिंह यादव, श्री शिवराम पांडेय, श्री शिवराम राय, श्री शिववक्ष सिंह राठौर, श्री शिववचन राव, श्रो शिवशरण लाल श्रोवास्तव, श्री शिवस्वरूप सिंह, श्रो शुकदेव प्रसाद, श्री शुगन चन्द, श्री इयाममनोहर मिश्र, श्री श्यामलाल, श्रो श्रीचन्द, श्री श्रीनाथराम, श्री श्रोनिवास, श्रो श्रोनिवास पंडित, श्री श्रीपति सहाय, श्री सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती संग्राम सिंह, श्री सिच्चदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री सज्जन देवो महनोत, श्रीमती सत्यसिंह राणा, श्रो सावित्री देवी, श्रीमती सियाराम गंगवार, श्री सियाराम चौधरी, श्री सोताराम, डाक्टर सीताराम शुक्ल, श्रो सुबीराम भारतीय, श्री सुन्दरदास, श्रो दीवान सुन्दरलाल, श्री सुरुजूराम, श्री स्रेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री सुरेशप्रकाश सिंह, श्री सूय्यंत्रसाद ग्रवस्थी, श्री सुर्यवली पांडेय, श्री सेवाराम, श्रो हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री हबीबुरहमान ग्रंसारी, श्री हबोबुरहमान ग्राजमी, श्री हबीबुर्रहमान खाँ हकीम, श्री हमीद खां, श्री हरखयाल सिंह, श्री हरगोविन्द पंत, श्री हरगोविन्द सिंह, श्रो हरदयाल सिंह पिपल, श्री

हरदेव सिंह, श्रो हरिप्रसाद, श्री हरिञ्चन्द्र ऋष्ठाना, श्री हरिश्चन्द्र याजपेयी, श्री हरिसिंह, श्रो हेमवतो नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

ग्रत्प सूचित तारांकित तक्ष्म बनारस जिले के जिक्सी काठतकारों की बेटलली

*१--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बनारस के शिकमी काश्तकारों को बेदखल होने से बचाने तथा जबरन बेदखल किये गये लोगों को जमीन वापस दिलाने के लिये वह कोई विधेयक वर्तमान सेशन में प्रस्तुत करने जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत) -- जी नहीं।

श्री गेंदा सिह—माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई विधेयक ग्रगले सेशन में लाने का वे विचार कर रहे हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह) -- जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिले के विधान सभा के सदस्यों ने माननीय राजस्व मंत्री से वहां के शिकमी काश्तकारों की बेदखली के संबंध में कोई मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाय?

श्री चरण सिंह—यह तो मुझको याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मांग की या नहीं की परन्तु गवर्नमेंट ने इस प्रश्न पर विचार किया है। लैंड रेबेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट, १३५६ फसली से लागू होने वाला या लेकिन श्रव १३६१ फसली है। यदि श्रव ऐक्ट को लागू करें तो श्रफसरों को दो साल के पहले के कब्जे के बारे में जिसके बारे में कोई तहरीरी सबूत नहीं है मालूम करने में दिक्कत है इसलिये लागू नहीं किया गया है। इसीलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि इसके संबंध में इन्दराज हो जाय श्रीर जब उसके मुताबिक इन्दराज हो जायगा तो लैन्ड रेबेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट लागू करना जरूरी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट बनारस में लागू नहीं है ?

श्री चरण सिंह -- बनारस स्टेट के किसी भी गांव में लागू नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि सरकार जमींदार विनाश ग्रौर भूमि व्यवस्था ग्रिधिनियम या इसी से संलग्न इस संबंध में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—बनारस स्टेट के उस इलाके में जहां सरकार की जमींदारी थी वहां जमींदारी विनाश श्रीर भूमि व्यवस्था श्रिधिनियम के लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। वह कठिनाइयां श्रव दूर हो गई हैं श्रीर बहुत जल्द ही वह कानून लागू हो जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला श्राजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सूचना है कि बनारस में जबरन कितनी बेदखली हुई है ?

श्री चरण सिंह—जबरन तो बहुत से काम दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन कोई बनारस में समस्या के तौर पर हुई है ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला श्राजमगढ़)—क्या यह सही है कि ५६ फसली में जिन किसानों के नाम में कबजा दर्ज हो गया वह ६० से श्रब तक बेदखल किये गये हैं?

श्री चरण सिंह—इसका मुझको कोई इल्म नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में वे म्रब जमींदारी विनाश ग्रौर भूमि व्यवस्था म्रधिनियम लागू करने का विचार कर रहे हैं उसके लागू हो जाने के बाद यह जो बेदललियां हो रही है वे रुक जायेंगी?

श्री चरण सिंह--जो शिकमियों के सिलसिले में कानून में प्राविजन्स है वे वहां भी लागू हो जायेंगे।

भिम सम्बन्धित समस्त नियमों तथा ग्रादेशों के संहित प्रकाशन की ग्रावश्यकता

*२—श्री गेंदा सिंह—क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था श्रिधिनियम, उसकी नियमावली तथा इससे संबंधित श्रादेशों को जो श्रव तक प्रचलित हुये है एक पुस्तक के रूप में करके सरकार प्रकाशित करने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत-जी नहीं। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इसका पता है कि साधारण कानून जानने वालों को इस वजह से बड़ी कठिनाई हो रही है कि रेवेन्यू संबंधी कानून बहुत से हैं और वे ऐसे हो गये हैं जिन्हें वे एक साथ नहीं जान सकते ?

श्री चरण सिंह—जी, जिसे कानून कहना चाहिये वह तो केवल एक संशोधन जमींदारी अबालिशन का हुआ है। हां, नियमों में बहुत सी तरमीमें हुई है। जो नियमावली छपी हुई हैं उन सबका एक कंसालिडेटेड एडीशन छप रहा है वह बहुत जल्द शाया होने वाला है। इसके अलावा गांवों के लोगों से ताल्लुक रखने वाले श्रौर उनकी जानकारी के लिये जो नियम हैं वे सब गांव समाज मैनुग्रल में दिये हुये हैं श्रौर वह छप चुकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—वया यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था श्रिधिनियम, १९५० में दूसरा श्रमींडग बिल ता रहेहैं?

श्री चरण सिंह-जी हां, इस पर विचार हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था श्रधिनियम लागू हो जाने के बाद उसमें ११ मरतबा संशोधन हो चुके हैं?

श्री चरण सिंह—मुझे नम्बर तो याद नहीं है लेकिन श्रगर ११ मर्तवा तरमीम हुई भी हो तो भी कोई ज्यादा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जीनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति

*१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या यह सच है कि गत तारीख २४, २४ श्रगस्त सन् १९४३ को जौनपुर में गोमती नदी में बाढ़ श्राई थी श्रौर उसके कारण बहुत से व्यक्तियों को घर द्वार छोड़ना पड़ा ? यदि हां, तो सरक।र ने इस संबंध में क्या प्रबन्ध किया ?

प्रश्नोत्तर ७

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, सरकार ने इस संबंध में जो कार्यवाही की वह इस प्रकार है—

- (१) जिन लोगों के घरों में पानी भ्रा गया था उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। इस कार्य के लिये ट्रकों तथा नावों का प्रबन्ध किया गया।
- (२) जौनपुर नगर में ११ सहायता केन्द्र खोले गये, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन दिया गया।
- (३) देहाती क्षेत्र में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने में मदद की गई तथा जरूरतमंदों को मुफ्त स्रनाज स्रादि दिया गया ।
 - (४) स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां बांटी गईं जिससे बीमारी को रोका जा सका।
 - (५) पुलिस ने खाली मकानों की देख भाल को।
- (६) पीड़ित क्षेत्र में २४ ए० प्रेन्त , आली गई ग्रौर सस्ते गल्ले का प्रबन्ध किया गया ।
- (७) पशुश्रों के चारे की कमी को दूर करने के लिये बाहर से भूसा मंगाया गया श्रौर क्रय मूल्य पर किसानों को दिया गया ।
 - (८) रबी के बीजों के लिये तकावी बांटी गई।
 - (६) गिरे मकानों को पुनः बनाने के लिये तकावी तथा मुफ्त सहायता दी गई।

*२--श्री बाबूनन्दन-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगर-पालिका के श्रन्दर कितने मकानों को क्षति पहुंची श्रौर उसमें कितने सरकारी मकान थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--जौनपुर नगरपालिका में कुल १४ मकानों को क्षिति पहुंची, जिनमें ५ मकानों को ग्रधिक क्षिति पहुंची। सरकारी मकान इनमें केवल १ था। पुरातत्व विभाग की १ गुमटी जो गोमती पुल पर स्थित थी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में बाढ़ की वजह से गोमती का पुल बड़ी खतरनाक हालत में पड़ा हुग्रा है, उसके लिये सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है?

श्री चरण सिंह—मैं इसका एकदम जवाब देने में ग्रसमर्थ हूं। नोटिस की श्रावश्यकता होगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में श्रभी तक कुछ लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिली है ?

श्री चरण सिंह—मुझे इसका पता नहीं है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो ग्रनुदान हेतु सहायता तथा तकावी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा दी गई थी वह सब बांट दी गई है या ग्रभी बाकी है ?

श्री चरण सिंह—में समझता हूं कि वह बांटी जा चुकी होगी लेकिन श्रगर कहीं जरूरत नहीं होगी तो मुमकिन है कि कुछ रुपया बचा हुश्रा हो। श्रापकी इजाजत से में इतना श्रौर श्रजं कर देना चाहता हूं कि पहले भी माननीय मित्र ने इस तरह से प्रश्न किये थे श्रौर उनका तफसील में जवाब दिया गया था। एक तो बाढ़ के लिये ही उनको मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जिस तरह से यह सवालात पूछे जाते हैं उसमें श्रौर भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिये मेरी दरस्वास्त यह है कि जितना श्रच्छा हल मौके पर जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हो सकता है

उतना यहां से सवाल पूछने पर नहीं हो सकता है। वैसे उनको हक है श्रौर वह सवाल पूछ सकते है लेकिन मेरी यह सिर्फ दरस्वास्त है, में उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं।

तराई स्टेट फार्म के सम्बन्ध में पूछताछ

*३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितनी यांत्रिक मशीनें हैं ग्रीर उनमें से कितनी कार्य कर रहा है तथा कितनी बेकार हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल ८१ यांत्रिक मशीनें हैं, इसमें से ४८ काम कर रही हैं तथा २३ मरम्मत के लिये कारखाने गई हुई है। बेकार मशीन यहां कोई नहीं है।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितने कर्मचारी किस पद पर कार्य करते हैं श्रीर उन्हें क्या-क्या वेतन, भत्ते तथा श्रन्य सुविधार्ये दी जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल २१६ कर्मचारी कार्य करते हैं। इनके पद तथा वेतन-क्रम संलग्न सूची में दिये हैं। उन्हें सामान्य भत्ता तथा वेतन का २० प्रतिशत तराई भत्ते के रूप में दिया जाता है। रहने के लिये उन्हें िना किराये के मकान भी दिये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' ग्रागे पृष्ठ ७४ पर)

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि स्टेट फार्म की पिछले ४ वर्षों में कुल कितनी भ्रामदनी श्रीर कितना खर्चा रहा ?

श्री जगन प्रसाद रावत-पिछले ४ वर्षों की श्रामदनी तथा खर्च का व्यौरा निम्न प्रकार है:---

वर्ष			म्रामदनी	खर्च	लाभ
<i>\$686</i> -४०	• •		२७,६१,२०४	२६,६२,०२=	१,०७,१७६
१६५०-५१	• •	• •	इद,१४,४६६	३०,२१,७८२	७,६२,७१७
१६५१-५२	• •	• •	४७,७६,०६२	४४,२६,१७८	3,86,558
१९४२-५३	• •	• •	५०,३१,५८०	४७,३३,११२	२,१६,४६८
	योग	••	१,६३,६१,३४५	१,४८,४३,१००	१४,४८,२४५

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ८१ यांत्रिक मशीनों में से कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने बुल डोजर्स हैं थ्रीर कितने हारवेस्टर्स हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यांत्रिक मशीनों में द१ द्रैक्टर्स हैं भ्रीर यांत्रिक मशीनों का जो उत्तर दिया गया है उसका संबंध टैक्टर्स से है। उसके भ्रलावा १८ कम्बाइन्स तथा २४ वेहिकिल्स हैं।

श्रो नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यांत्रिक मशीनों में उन्होंने ट्रैक्टर ही केवल शामिल किये हैं तथा उसके म्रलावा श्रापके कितने हारवेस्टर्स बेकार हैं ग्रौर कितने काम कर रहे हूँ ?

प्रश्नीतर

E

श्री जगन प्रसाद रावत--बेकार कोई नहीं है। सब काम कर रहे है।

श्री गारायण्य तिवारी—स्या यह सही है कि तराई स्टेट फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों में से बहुत से कर्मचारी अभी तक अस्थायी है और उन्हें छुट्टियों की सहस्रियतें ठीक से नहीं है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सही है कि उनमें से बहुत से ग्रस्थायी है। लेकिन यह सही नहीं है कि उन्हें छुट्टियों की सहूलियतें नहीं है। जो कर्मचारी ग्रस्थायी होते है उन्हें जिन नियमों से छुट्टिया दी जाती है उन्हों नियमों से उन्हें भी छुट्टियां जाती है।

श्री बीरेंद्र वर्मा (जिला मुज़फ़्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जो यह बताने का कष्ट करेगे कि तराई स्टेट फार्म का कुल कितना एकरेज है। क्या यह तमाम भूमि श्रन्डर कल्टीवेशन श्रा चुकी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म का कुल क्षेत्रफल लगभग १६,५०० एकड़ है इसमें से १० हजार के लगभग काश्त होती है ग्रौर तीन हजार के लगभग ग्रास बेल्ट है जो जंगल से लगी हुई है ग्रौर बाकी में कई बगीचे है ग्रौर कुछ जमीन बिल्डिंग वगैरह में लगी हुई है।

श्री वीरेद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगे कि इस फार्म में पानी की क्या सुविधा है, सिंचाई की क्या सुविधा है?

श्री जगन प्रसाद रावत--दो प्रकार से इस क्षेत्र मे पानी दिया जाता है, कुछ तो नहरे है, कुछ ट्यूबवेल्स है उनके द्वारा सिचाई होती है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेगे कि जो २३ मशीनें कारखाने में भेजी गई वे कब भेजी गई ?

श्री जगन प्रसाद र वह—ये तारी लें तो मेरे पास नहीं है कि कब भेजी गई। लेंकिन जब खराब हो जाती है तो वे कारखाने में मरम्मत के लिये भेज दी जाती है। यह भी में माननीय सदस्यों को सूचना के तौर पर बता दूं कि उनमें से अधिकतर मशीने ऐसी है जो इन पांच वर्ष के अन्दर जो उनका साधारण जीवन होता है उससे अधिक काम कर चुकी है और मरम्मत करके उनके कार्यकाल को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कारण बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में लगातार खर्चा क्यों बढ़ता चला जा रहा है श्रीर लाभ क्यों कम होता चला जा रहा है?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में खर्चा श्रौर लाभ दोनों श्रनुपात से ही करीव-करीव बढ़ एहें हैं। बीच में एक स्थान पर १६५०-५१ में जो यह बताया गया है कि ७,५२,७१७ का फायदा था श्रौर १६५१-५२ में एकदम से ३,४६,५६४ का रह गया, इसका एक कारण तो यह है कि १६५०-५१ में जो जमीन जोती गई उसका क्षेत्रफल लगभग १३ हजार एकड़ के था लेकिन वह जमीन जोतने के बाद जो वहां का कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट हैं उसमें जो लोग बसाये गये हैं उनको करीब-करीब ६ हजार एकड़ जमीन देदी गई है। इसलिये १६५१-५२ में जोत का रक्षवा करीब ७ हजार एकड़ के रह गया जिसकी वजह से लाभ कम हुश्रा है। इसके श्रलावा माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले तीन चार वर्षों में तराई में पानी की काफी कमी रही, सूखा पड़ा श्रौर गन्ने का दाम भी जो १६०६२ श्रा० था वह १६० ५ श्रा० रह गया श्रौर बूहों से भी नुकसान हुश्रा जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने प्रक्रन भी पूछे श्रौर बजट में भी उसकी चर्चा की। तो इन कारणों से लाभ में कमी हुई श्रौर खर्च जो था वह ज्यों का त्यों रहा।

मड़ियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की ग्रावश्यकता

*६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के ग्रन्तर्गत रामपुर बाजार तथा मड़ियाहूं कस्बे के ग्रन्दर पशु चिकित्सा लय खुलने वाला है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—स्त्रार्थिक कठिनाइयों श्रौर पशु चिकित्सकों की कमी के कारण कुछ समय तक नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

*७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा(ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहू तहसील के नेवढ़िया बाजार सरसरा बड़ेटी में पशुग्रों के रोग दूर करने के लिये स्टाकमैन रक्खे जाने वाले हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—जी हां। इसक प्रबन्ध किया जा रहा है।

देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से खेती को हानि

*द—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (श्रनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भाटपार रानी N. E. R. स्टेशन (जिला देवरिया) के उत्तर बेलपार पंडित के ताल में पानी घिर जाने से कितने एकड़ खेती को क्षति हो रही है?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में गत वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से लगभग १५० एकड़ खेती को हानि हुई।

* ह—श्री बद्री नारायण मिश्र (ग्रनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि ग्रभी भी वहां मीलों लम्बा ग्रौर करीब ६ फर्लाग चौड़ा पानी घिरा हुग्रा है ?

श्रो चरण सिंह—वहां लगभग ६ फर्लाग लम्बे ग्रौर ४ फर्लांग चौड़े घेरे में पानी घरा हुग्रा था।

*१०—श्री बद्री नारायण मिश्र (ब्रनुपस्थित)—क्या नाला बनवाकर इस पानी को निकालने की ध्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां, एक ऐसे नाले के बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे ताल का पानी निकाला जा सके।

भूदान यज्ञ में दी गयी भूमि

*११—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश से जिलावार श्री विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में कुल कितनी कितनी जमीन दान में मिली है ?

श्री जगन प्रताद रावत—ग्रल्मोड़ा गढ़वाल, श्रौर टेहरी-गढ़वाल जिलों को छोड़कर श्रन्थ ४८ जिलों में कुल मिला कर २,४४,८६८.२४ एकड़ भूमि ३१ विसम्बर, १६४३ ई० तक भूदान यज्ञ में दान की गई। जिलेवार सूचना एक सूची में देवी गई है जो मेज पर रख दी गई है।

(देखिये गत्थो 'ख' श्रागे पृष्ठ ७४-७६ पर।)

*१२—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि कितने परिवार ावलों को जिलावार, उस जमीन का बटवारा हो चुका है ? श्री जगन प्रसाद रावत--इसमें से ३१ दिसम्बर, १६५३ ई० तक कुल २३,६६९.६३ एकड़ भूमि का ६,४६७ परिवार वालों को बटवारा हुआ है। जिलेबार सूचना एक सूची में देवी गई है, जो मेजपर रखदी गई है।

[देखिये नत्थी 'ख (१)' द्यागे पृष्ठ ७७-७८ पर]

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उस दा न में हो हुई बहुत सी जमीने झगड़े की है श्रौर बहुत सी परती, बंजर या दूसरे सार्वजनिक उपयोग की जमीनें है ? श्रगर हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या ध्यवस्था की है या करना चाहती है?

श्री चरण सिंह—यह ठीक है कि कुछ जमीन ऐसी हो सकती है कि जो सार्वजिनक उपभोग की हो श्रीर कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस पर विवाद चल रहा हो। तो जिनके बारे में विवाद चल रहा है उनका श्रंतिम निर्णय कोर्ट से हो जायगा श्रीर उसके मुताबिक यह जमीन मिलेगी। जो सार्वजिनक उपभोग की जमीन है उसके लिये भू-दान यज्ञ ऐक्ट में एक घारा दी हुई है कि उसका दान नाजायज माना जायगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेगे कि जो जमीन ग्रभी बांटी नहीं गई है वह कब तक बांट दी जायगी?

श्री चरण सिंह—जमींन बांटने की कोई जिम्मेदारी गवर्नमेट की नहीं हैं, इसिलये कोई इसकी बाबत जवाब भी नहीं दिया जा सकता। उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। यथा सुविधा वह उसको तक्षसीम कर देगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें श्रायी है कि भूदान ऐक्ट के श्रनुसार जो श्रिधकारियों को जमीन का प्रख्यापन करना चाहिये उसमें बहुत देरी हो रही है?

श्री चरण सिह—जी नहीं। श्रगर इस सप्लीमेंटरी को में शिकायत मान लूं तो इसके श्रलावा श्रीर कोई ऐसी शिकायत नही श्रायी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूदान सिमिति से सरकार का कोई संबंध है?

श्री चरण सिंह—सरकार ने तथा इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कानून बनाया है उसके मातहत वह समिति बनाई गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कालोनाइजेशन श्रौर खाम क्षेत्र में जो काश्तकार जमीन दान में देना चाहते है उसमे नियम जो खाम क्षेत्र के बने है वहां पर भूदान ऐक्ट लागू नहीं हो पाता श्रौर न वह जमीन दे पायेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह माननीय सदस्य को स्वयं मालूम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह बात सही है कि खाम श्रीर कोलोनाजेइ जन क्षेत्र में जो सरकारी नियम है उनके कारण भूदान में जमीन नहीं दी जा सकती?

श्री चरणः सिंह—सरकार की जमीन तो दी नहीं जा सकती है ग्रौर सरकार से जिन शर्तों पर जमीन ली है उसके विपरीत यदि कोई कार्यवाही की जाय ते वह नहीं की जा सकती है। बाकी जो प्रश्न है उस पर सरकार विचार कर रही है।

र र श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन भूदान समिति द्वारा बांटी जाती है वह किस हिसाब से बांटी जाती है?

श्री ग्रध्यक्ष--जवाब दिया जा चुका है कि सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—यह जो दान में जमीन मिली है इसका इन्दराज सरकारी कागजात में हो चुका है?

श्री चरण सिंह—जो कानून बना है उसके मुताबिक इंदराज हो जाना चाहिये श्रीर यदि कहीं नहीं हुन्ना है श्रीर माननीय सदस्य यदि नोटिस में लायेंगे तो में कोविश करूंगा कि इंदराज हो जाय।

श्री नार:यणदत्त तिवारी--क्या सरकार राजस्थान सरकार की तरह भूदान में जमीन देनेवाली है ?

श्री चरण सिंह—जो श्राचार्य विनोधा जो का उसूल है उसके मुताबिक दफा ६ म के मातहत गांव सभाग्रों को श्रधिकार दे दिया है कि वह जमीन वितरण कर दें, जिनके पास जमीन है वह चाहें तो सारी जमीन भूदान में दे दें, इससे श्रच्छी कोई बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि लैंड मैनेजमें ट कमेटी ने बहुत से स्थानों पर भूमिहीनों को जमीन न देकर दूसरों को देदी है। यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री चरण सिंह—यदि नियम विरुद्ध जमीन दे दी है तो उसके श्रमुक्ल कार्यवाही कीजा सकती है श्रौर वह तकसीम नाजायज है। यदि कहीं ऐसा हुश्रा हे तो वह नाजायज करार दे दी जायगी।

*१३-१५-श्री राम सुन्दर पांडेय--[२५ मई, १६५४ के लिये प्रश्न संख्या ७-६ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१७-श्रो खुझोराम (जिला ग्रल्मोड़ा)-- [३१ मई, १६५४ के लिये स्यगित किये गये।]

फैजाबाद तथा स्राजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को वदलने के लिए सुझाव

१८—श्री राम नारायण त्रियाठी—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेगे कि फैजाबाद तथा श्राजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के लिये कोई सुझाव भेजे हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत-जी हां, सरकार के सामने फैजाबाद तथा श्राजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के निम्नलिखित सुझाव थे:—

- (१) बन्दीयुर क्षेत्र को फैजाबाद से निकालकर ग्राजमगढ़ में मिला दिया जाय।
- (२) जमुग्रारी क्षेत्रको ग्राजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद से मिला दिया जाय।
- (३) फैजाबाद से ६ गांव निकाल कर श्राजमगढ़ में तथा २ गांव श्राजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद में मिला दिये जायं।

*१६—श्री राम नारायण त्रिपाठी—सरकार उन सुझावों में किन-किन को स्वीकार कर रही है?

श्रो जगन प्रसाद रावत—सरकार ने उक्त प्रस्तावों में से प्रथम दो को तो ग्रस्वीकार कर दिया है ग्रौर तीक्षरे को स्वीकार कर लिया है। इस विषय में एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' ग्रागे पृष्ठ ७६ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बंधीपुर क्षेत्र को फैजाबाद में मिला देने के सम्बन्ध में जिलाधीशों के पत्रों का सम्बन्धित उद्धरण पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रध्यक्ष —— (माल मंत्री से) श्राप उसको कृपा करके संक्षेप में पढ़ें। श्र^{गर} बहुत देर उसे ढूंढ़ने में होती हो तो रहने दें।

श्री चरण सिंह—जी नहीं। बहुत देर तो नहीं है। लेकिन इसकी चार फाइलें थीं। तीन तो मैंने श्रलग कर दी थीं। चौथे में उनका १६ नम्बर का खत है जो कि बहुत लम्बा है। उसमें इसके वजूहात दिये हैं कि किस वजह से बंधीपुर एरिया को श्राजमगढ़ में मिलाना वहां के लोगों की सुविधा के श्रनुकूल न होगा बल्कि उसके विपरीत पड़ेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या जिलाधीशों ने यह भी लिखा है कि ग्रगर किसी वजह से बंधीपुर क्षेत्र, ग्राजमगढ़ में मिलाया जा सके तो जलालपुर-तिगड़ा रोड को ठीक कराना ग्रनिवार्य है ताकि लोगों को मुनासिब सुविधा मिल सके ?

श्री चरण . सिंह—जी हां। जलालपुर से जो स्थान श्रापने बतलाया उसके लिये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन रामगढ़ तक जो सड़क है उसके लिये उन्होंने पोख्ता करने के लिये कहा है श्रौर माल विभाग की तरफ से पी० डब्ल्यू० डी० से दरख्वास्त की गई है कि यथासंभव शीघ्र वह उसको श्रपने प्रोग्राम में शामिल कर लें।

हरदोई जिले से भूमि व्यवस्था सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२०—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हरवोई जिले की विभिन्न तहसीलों से जिलाधीश या हाकिम तहसील के यहां उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (ग्रनुपूरक) ग्रिधिनियम, १९५२ के ग्रनुसार कितनी-कितनी दरस्वास्तें प्राप्त हुई हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत -- १५ मार्च, १६५४ तक तहसील हरदोई से .. ४७

, तहसील शाहाबाद से .. २१०

,, तहसील संडीला से .. ६४

, , तहसील बिलग्राम से . . २४०

जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग के कमंचारी

ं *२१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग में कुछ कितने कर्मचारी विभिन्न पदों में हैं?

श्रा जगन प्रसाद रावत—जौनपुर जिले में सिम्मिलित संग्रह योजना में कुल १७१ कर्मचारी है जिनमें से ७ नायब तहसीलदार, १० सहायक वासिल बाकी नवीस, ७४ ग्रमीन, १ ट्रेजरी क्लकं, ५ तहबीलदार श्रौर ७४ चपरासी है, किन्तु कुछ ग्रौर पदो के मंजूर होने से श्रब कुल कर्मचारियों की संख्या २०८ हो जावेगी जिनमें से ६ नायब तहसीलदार, १३ सहायक वासिल बाकी नवीस, ६० ग्रमीन, १ ट्रेजरी क्लकं, ५ तहबीलदार तथा ६० चपरासी होंगे।

श्री बाब्नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जो कर्मचारी रखे गये हैं, उनमें से कितनी जगहें स्थायी है ग्रौर कितनी ग्रस्थायी?

श्री चरण सिंह—जगहे सब ग्रस्थायी है। केवल फर्क इतना है कि ये जो रखे जा रहे हैं ये ग्रब १२ महीने काम करेंगे। पहले जो थे वह ६-६ महीने काम करते थे, एक-एक फसल में।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ग्रौर जगहो के लिये श्रार्डर भेजा गया है उसके साथ-साथ यह भी ख्याल किया गया है कि हरिजनों ग्रौर ग्रौर पिछड़ी जाति की सुरक्षित सीटों को पूरा करने की कोशिश की जाय?

श्री चरण सिह—ग्रापकी इजाजत से में यह कह दूं कि इस सवाल का जवाब देना में गैर जरूरी समझता हूं क्योंकि वह ग्रार्डर सबके लिये पहले ही हो चुका है। बार-बार उसी बात का जिन्न करना उचित नहीं है।

गाजीपुर कलक्टरी में विचाराधीन मुकदमें

*२२-श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर कलेक्टरी में १ जनवरी, १९५३ को माल व फौजदारी के कितने मुकदमे विचाराधीन थे?

*२२---१ जनवरी, ५३ से ३१ दिसम्बर, ५३ तक कितने माल व फौजदारी के ग्रलग-ग्रलग नये मुकदमें दाखिल हुये ?

*२४---१ जनवरी, ५४ को कितने मुकदमें माल व फौजदारी के विचारा-भीन थे?

श्री जगन प्रसाद रावत—

		माल	फौजदारी
२२	• •	9,88	१,३६१
₹	• •	१३,७४५	४,१५७
२४	• •	8,750	१,२८६

श्री यमुना सिंह—क्या जो मुकदमे दाखिल होते हैं उनके फैसले की कोई निश्चित ग्रविष भी होती हैं?

श्री चरण सिंह—कोई रिचिड भवि नहीं होती। यह मुकदमे के ऊपर होता है, मसलन श्रगर मुकदमा स्टे हो गया तो साल दो साल भी पुराने हो सकते है।

श्रो राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १६५३ के पहले इस दौरान में कलेक्टरी कचहरी, गाजीपुर की ब्रदालत में कितने मुकदमें दाखिल थे?

श्री चरण सिंह—यह तो सारे जिलों के ग्रांकड़े दिये हैं। वहां श्राठदस ग्रदालतें होंगी। तो किस ग्रदालत में कितने मुकदमें थे यह तो में नहीं बतला सकता।

*२५-२६--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)-- [३१ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

बनारस जिले के कसबार राजा परगने में स्रोले से क्षित

*२७--श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस) (ग्रनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले के कसबार राजा परगने में कितने गांव श्रोले गिरने के कारण क्षति-ग्रस्त हुये हैं?

श्री चरण सिंह—कसबार राजा परगने में कुल १०२ ग्रामों को श्रोले गिरने से हानि पहुंची, जिस में ८७ ग्राम ऐसे हैं जहां क्षति ८ ग्राने या उससे श्रधिक हुई।

*२८—श्री देवमूर्ति राम (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षति ग्रस्त ग्रामों के किसानों के लिये कौन-कौन सी सहायतायें देने की सरकार ने व्यवस्था की है?

श्री चरण सिंह -- क्षति ग्रस्त ग्रामों को निम्नलिखित सुविधाये दी गई:---

- (१) क्षति ग्रस्त क्षेत्र में दो सड़कों पर टेस्ट वर्क खोले गये।
- (२) = सस्ती गल्ले की दूकाने खोली गईं।
- (३) १,८०,००० र० की तकावी बांटी गई जिसमें कुछ रुपया परगना कसवार सरकारी तथा देहात श्रमानत के भी कुछ ग्रामो में बांटा गया।
 - (४) ग्रसमर्थ तथा ग्रसहाय व्यक्तियों को मुफ्त गल्ला दिया गया।
 - (५) सरकारी नल कूपों से सिंचाई के लिये निःशुल्क जल देने की व्यवस्था की गई।
- (६) पशुस्रों के चारे के लिये १ रु० मन के सस्ते भाव पर पुत्राल दिये जाने का प्रबन्ध किया गया।
 - (७) समस्त सरकारी मतालबों की वसूली स्थगित कर दी गयी।
- (प्र) मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने के संबंध मे उचित कार्यवाही की जा रही है।
 - (६) जन स्वास्थ्य एवं पशु रक्षा संबंधी सारे उपाय कार्यान्वित किये गये।
- (१०) क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यान्वित होने वाली सार्वजनक योजनाश्रों की गति में तेजी लाई गई जिससे श्रमिकों को कार्य मिल सके।
 - (११) इषकों को गल्ले के बीज दिलाने की व्यवस्था की गई। जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का नीलाम

*२६—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर मंडी में दो-तीन साल के श्रन्दर नयी बाजार बनाने के लिये लाल इमली पड़ाव के इर्द गिर्द कुछ प्लाटों का नीलाम दुकान वालों में लिये किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*३०--श्री खुशीराम--दया यह सही है कि लालइमली पड़ाव में ३०-४० साल पूर्व से गोची, दर्जी, वर्गरह जंगल कटान करके बसे थें जो ग्रब उठाये जा रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत -- कुछ लोग इस पड़ाव में बसे हुये है पर यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि वे कब से हैं। उनके हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३१--श्री खुशीराम---क्या इस लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी यगेरह दुकानदारों के लिये कोई जगह तजवीज की गई? यदि हां, तो कहां पर?

श्री जगन प्रसाद रावत--भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने यह श्रहकमात जारी कर दिये हे कि जब तक लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी, वगैरः दुकानदारों की दूसरी जगह ब आने का इत्तजाम न हो जाय उनको इस जगह से न हटाया जाय।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जो श्राज्ञा निकाली है यह कबतक कार्यान्वित की जायगी ?

श्री चरण सिंह—इसके कार्यान्वित होने की कीई श्रविध नहीं है। जब वह उस वक्त तक हटाये हीं नहीं जायेंगे जब तक दूसरी जमीन का इन्तजाम न हो जाय तो कार्यान्वित होने की श्रविध का सवाल ही क्या पैदा होता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन प्लाटो को नीलाम करने वाला ग्रिधकारी या विभाग कौन है ?

श्री चरण सिंह- –गवर्नमेट स्टेट सुपरिनटेडेट के जरिये यह नीलाम हुआ है। या तो उन्होंने खुद किया या अपने किसी मातहत श्रधिकारी से नीलाम कराया। जिम्मेदारी उनकी

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो लाल इमली पड़ाव में मोची दर्जी बसे हैं उनको इन्हीं खाम सुपरिनटेंडेट ने जमीन श्रलाट की थी ?

श्री चरण सिंह—कोई जमीन ग्रलाट करने का सवाल ही नहीं

श्रमदान सप्ताह में लेखपालों को सड़कों की निशान देही करने की आजा!

*३२-श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) —क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में लेखपालों को श्रपने श्रपने हल्के में रह कर डहरों श्रीर सड़कों की निज्ञान देही करने की श्राज्ञा थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जिन लेखपालों ने निशानदेही की है उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो लोगों को दी है ?

श्री चरण सिह—जी नहीं। यह मुझे को नहीं मालूम है कि रिपोर्ट दी है या नहीं दें है। झासी जिले में जंगली गायों व देलों से फसल को हानि

*३३—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी) (श्रनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में जंगली गायें व बैल फसल का बहुत नुकसान करते है जिसके कारण किसान लोग बहुत दुखी श्रौर परेशान है? यदि हां, तो उसने उनके पकड़वाने का क्या प्रबन्ध किया है?

श्री चरण सिंह—यह पता चला है कि झांसी तहसील के कुछ गांवों में जंगली गाय व वैल फसल का नुकसान करते हैं। उनके पकड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्रन्न की पैदावार में वृद्धि

*३४--श्रो धर्म सिंह (जिला बुलन्द शहर)--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के ग्रन्न को पैदावार में कुल कितनी बढात्तरी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार के पास केवल मुख्य श्रन्नों श्रर्थात् गेहं, जो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का चावल, सांवां, मटर, महुग्रा व कोदों के पैदावार के श्रांकड़े उपलब्ध हैं। उनके श्रनुसार १६४६—४६ को तुलना में १६४२—५३ वर्ष में श्रर्थात् ५ वर्ष के उपरान्त प्रदेश के उक्त मुख्य श्रन्नों की फसलों की कुल पैदावार में लगभग ११,४६,००० दन या १२ प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है।

श्री धर्म सिह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो झांकड़े सरकार ने अन्न में १२ प्रतिशत बढोत्तरी के दिये है वे फार्म से संबंधित है या केवल निजी किसानों से?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये तो सारे सूबे के ग्रांकड़े हैं।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपया करेगी कि पिछले पांच वर्ष में जो सन्न में बढोत्तरी हुई है उसमें कितना खर्ची हुस्रा है ?

श्रो जगन प्रसाद रावत--सरकार ने बहुत काफी रुपया व्यय किया है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो श्रन्न में वृद्धि हुई है वह एवरेज में कितनी हुई है ?

श्री चरण सिंह-इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह नई जमीन बढ़ने से हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सही नहीं है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह केवल नई जमीन बढ़ने से ही हुई हैं।

श्री गेंदा, सिह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी फार्म्स में किस श्रनुपात से वृद्धि हुई है?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता। पूरे प्रान्त के लिये इसमें पूछा गया है। श्री गेंदा सिह--क्या सरकारी फार्म्स भी इन ग्रांकड़ों में शामिल है?

श्री जगन प्रसाद रावत--में पहले ही कह चुका हूं कि ये जो श्रांकड़े है वे सारे सूबे के हैं सरकारी फार्म्स भी उनमें सिम्मिलित हैं।

जिला मुजफ्फर नगर में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी

*३५—श्री श्रीचन्द (जिला मुजपकरनगर) (श्रतुपस्थित)—स्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मुजपक्ररनगर में सरकार नें कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकाबी दी? यदि हां, तो किस-किसको श्रीर कितनी-कि तनी?

श्री चरण सिंह--जिला मुजफ्फरनगर में जितनी तकाबी ट्रैक्टर के लिये सरकार ने ही है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' झागे पष्ठ ८० पर)

जौनपुर जिले में 'घोड़ा रोशन घास' को नष्ट करन का प्रबन्ध

*३६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरार को पता है कि जौनपुर जिले के गड़वारा परगने में पूरा रामसहाय, कोटिला, भुंडघरा श्रीर भेंसहा रामपुर के एक बहुत बड़े भाग में 'घोड़ा रोशन' नाम की एक घास बहुत तेजी से फैलती जा रही है श्रीर उससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, उक्त स्थानों में 'घोड़ारोशन घास' के फैलने की सूचना शासन को मिली है। इस घास का खेतों की उर्वरा शक्ति पर कैसा श्रीर कितना प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर श्रभी तक पूर्ण विवरण सुलभ नहीं हो सका है।

*३७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार इस घास के संबंध में श्रनुसंधान कर्त कर इसके नष्ट करने का प्रबन्ध करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस घास के संबंध में श्रावश्यक श्रनुसंधान कराकर उक्ति कार्यवाही की जायगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रनुसंधान कार्य कब तक हो जायगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—श्रनुसंधान कार्य के लिये कोई समय तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन प्रयत्न किया जा सकता है कि वे जल्दी ही पता लगा सकें।

कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का वितरण

*३८—श्री गंगाघर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या यह सही है कि सन् १६४० में कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन के वितरण के लिये बोली बुलाई गई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*३६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि बोली बोलने वाले कुछ लोगों है रुपया जमा कराया गया था ? क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। एक सूची मेज पर रखी है। (वेलिये नत्थी 'ङ' ग्रागे पृष्ठ ८२ पर)

*४०-श्री गंगाघर मैठाणी-क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन लोगों को किन ग्राघार पर भूमि एलाट की गयी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिस भूमि को सन् १९५० में वितरण करने की इराव श्रीर जो नीलाम की गयी है, उसे किसी को एलाट नहीं किया गया।

श्री गंगाघर मैठाणी—क्या यह सही है कि सन् ४० से स्टेट के ग्रन्दर कोई भी भूषि किसीं को भी एलाट नहीं की गयी है ?

श्री चरण सिह—यह सही नहीं है।

अों नंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिन लोगों से यह कपया लिया गया थ उन्हें भूमि एलाट महीं की गयी है, बल्कि और लोगों को की गई है ? श्री चरण सिह—डिप्टी कमिश्नर न मुकामी सज्जनों की कमेटी बना दी थी श्रीर उसने जमीन का एलाटमेंट किया। उसने श्रपना गज श्रीर पैमाना रक्खा हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या खाम स्टेट में जमीनों के वितरण के लिये बोली बोलने की प्रथा स्रव भी जारी हैं?

श्री चरण सिंह—यह म्राम प्रश्न म्राप ने पूंछा, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि यह इसके नहीं उठता।

श्री ग्रध्यक्ष--उत्तर में यह लिखा है कि बोली बुलाई गई थी।

श्री चरण सिंह—यह तो जमीन एक्वायर की गयी थी श्रौर एक्वायर करके नोटि-फाइड एरिया में कमेटी बनी श्रौर उसने जमीन एलाट की । जो जमीन पहले एक्वायर की गई थी सन् ४० से पहले उसके लिये बोली बुलवाई गयी थी ।

खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर मे किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार

*४१—श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल) (श्रन्पस्थित)—क्या सरकार खाम स्टेट कोटद्वार, तराई व भावर को खत्म करके वहां के किसानों को हिस्सेदार (proprietors) बनाने जा रही हैं?

श्री चरण सिंह—सम्प्रति ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रार० टी० ग्रो० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेन्सों की श्राजाग्रों के विरद्ध श्रपीले

*४२—श्री लक्ष्मण राव कदम (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रार० टी० ग्रो० द्वारा रह किये जाने वाले मोटर लारियों ग्रादि लाइसेन्सों की ग्राजाग्रों के विरुद्ध कितनी ग्रपीलें सन् ५२ व कितनी सन् ५३ की स्टेट ट्रांस्पोर्ट ग्रथारिटी के सामने पेश हैं?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायन शर्मा)—सन् १९५२ में २४६ ग्रपीलें दायर की गर्यी जिसमें से ११० पर ग्रन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं ग्रौर १३६ ग्रभी बाक़ी हैं।

सन् १६५३ में २१२ भ्रपीलें दायर की गई हैं जिनमें से ६७ भ्रपीलों पर ग्रन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं, १६ स्वीकृत जांच के श्रन्तर्गत हैं ग्रौर ६६ भ्रभी बाक़ी हैं।

*४३--४५--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--[३१ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

*४६--४८--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[२४ मई, १९५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

लखनऊ भ्रौर फैजाबाद डिवीजन के सुपरवाइजर कानूनगो

*४६—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (ग्रनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ ग्रीर फंजाबाद डिवीजन के जिलों में कुल कितने सुपरवाइजर कानूनगी काम कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह--लखनऊ श्रीर फेंजाबाद डिवीजन के जिलों में निम्नलिखित संख्या में सुपरवाइजर कानूनगो काम कर रहे हैं।

लखनऊ डिवी	ज न		फैजाबाद	डिवीजन		
लखनऊ		5	फैजाबाद	• •	+ (38
उन्नाव	• •	१४	गोंडा	• •		. २०
रायबरेली	• •	१४	बहराइच	• •		. १६
	• •	१८	सुल्तानपुर	• •		n.,
हरदोई	• •		प्रतापगढ़			8.
सीतापुर हरदोई खीरी	• •	१३	बाराबंकी	• •	• •	. १
	योग	٠. ٤٧			योग	१०

^{*}५०--श्री दल बहादुर सिंह (अनुपिस्थत) --जो सुपरवाइजर कानूनगो डिवीजन के हर जिले में काम कर रहे हैं उनमें कितने स्थायी हैं ग्रीर कितने अस्थायी ?

श्री चरण सिंह—दोनों डिवीजनों के स्थायी तथा ग्रस्थायी सुपरवाइजरों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है:

लखनऊ डिवीजन

जिला			स्थायी	ग्रस्थायी
लखनऊ	• •	• •	* •	5
उन्न.व	• •	• •	२	१२
रायबरेली	• •	• •	₹	8.8
सीतापुर हरदोई स्रीरी	• •	• •	8	१४
हरदोई	• •	• •	२	१५
सोरी	• •	• •	8	3
	यं	ोग	१४	ફ્દ

फैजाबाद डिवीजन

जिला			स्थायी	ग्रस्थायी
फेंजाबाद				
गोंडा	• •	• •	¥	8 \$
बहराइच	• •	• •	રે	१४ १४
बु ल्तानपुर	• •	• •	Ę	१ १
प्रतापगढ्	• •	• •	3	8
बाराबंकी	• •	• •	¥	88
		योग	ই ড	ξυ

*५१--श्री दलबहादुर सिंह (ग्रनुपिस्थित)--क्या सरकार ने कोई ग्रादेश जारी किया है कि १० साल से ज्यादा कोई कानूनगो एक जिले में न रहेगा? यदि हां, तो क्या इसका पालन रायबरेली जिलें में हुग्रा है? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री चरण सिंह— जी हां। इस ग्रावेश का पालन रायबरेली जिले में भी हुग्रा है। केवल एक व्यक्ति जिसके लिये स्थानान्तरण का श्रावेश हो चुका है श्रभी तक नहीं जा सका, क्यों कि उनके स्थान पर ग्राने वाले कानूनगों को जबरदस्ती ग्रवकाश ग्रहण करना पड़ा। यह एक कानूनगों भी शी छ ही स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

*ধ্२—श्री राम ग्रथार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)——[१७ मई, १९५४ के लिये स्थिगत किया गया।]

लखनऊ कलक्टरी में हरिजन कलर्को तथा चपरासियों की भती

*५३—-श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—-लखनऊ कलेक्टरी में सन् ५२ से ग्रब तक कितने क्लर्क तथा चपरासी भर्ती किये गये हैं? उनमे हरिजनों की संख्या कितनी हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—लखनऊ कलेक्टरी में सन् १६५२ से ग्रब तक क्लर्क ग्रौर चपरासियों की भर्ती निम्न प्रकार से हुई:

	الحددد	क्लर्क	च परासी	हरिजन क्लर्क	हरिजन चपरासी
 स्थायी ग्रस्थायी	• •	१ १ ६	६ ३००	• •	<i>\$</i> .

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेगे कि यह जो २० क्लर्क रखे गये है उनमे १८ फीसदी के हिसाब से ४ हरिजन होने चाहिये थे वह क्यों नहीं रखे गये ?

श्री चरण सिंह—जो लोग पहले बन्दोबस्त में काम कर चुके थे श्रौर बटवारे का काम कर चुके थे वहां से जो लोग छटनों में श्रा गये थे या जो सेटिलमेट का काम बन्द होने पर बेरोजगार हो गये थे तो पहले उनको रखा गया श्रौर बाहर से उन जगहों पर कोई नहीं लिया गया श्रौर ५६ तक बाहर से नहीं लिये जायंगे।

श्री कन्हेया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १,३०० चपरासी जो रखे गये हैं उसमें केवल १४ हरिजन क्यों रखे गये हैं १८ फीसदी के हिसाब से ५४ होने चाहिये थे?

श्री ग्रध्यक्ष--यह तो बहस का प्रश्न है। ग्राप सीधा सवाल पूछिए।

श्री कन्हेया लाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगे कि १,३०० में केवल १४ हरिजन चपरासी क्यों रखे गये हैं इसका क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—जी, कारण तो मैं दिरयापत कर के बतला सकता हूं। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट में जिस्ट्रेट से पूछने में कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं मालूम है।

श्री करहैया लाल वाल्मी कि--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कारण को पूंछने के लिये कम से कम कितना समय लगेगा? श्री ग्रध्यक्ष-यह तो मामूली बात है इसको ग्राप स्वयं समझ सकते हैं।

टेंस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें

*५४—श्री गेंदा सिह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में पिछले ६ महीनों के भीतर कहां कहां टेस्ट वर्क चलाये गये, उनमें कितने मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया ग्रीर यदि कहीं बन्द हो गये तो उन हे क्या कारण हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—श्रपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है। (देखिये नत्थी 'च' श्रागे पृष्ठ ५३ पर)

*पूर्—श्री गेंदा सिंह—क्या उत्तर प्रदेश में टेस्ट वर्करों पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न जिजों की भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। मैवानी क्षेत्र में टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें सब जिलों में एक समान है परन्तु पहाड़ी क्षेत्र में दरें मैदानी क्षेत्र से भिन्न है। दरें इस प्रकार हैं:--

मैदानी क्षेत्र			सबसे	सस्ते	श्रप्त	की	मात्रा
		<u> </u>					छुटांक
फावड़ा चलाने वाले	• •	• •			•	•	२४
मिट्टी ढोने वाले 🕠	• •	• •					२०
मिट्टी ढोने वाले १४ वर्ष से बड़े बच्चे	• •	• •	• •		•	•	१६
पहाड़ी क्षेत्र प्रत्येक वयस्क	• •	• •		१	२ ध्रान	ग प्र	तिदिन

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दो प्रकार की मजदूरी रखने का क्या कारण है श्रौर दोनों में कितना श्रन्तर है ?

श्री चरण सिंह—कारण यह है कि वहां पहाड़ों में शायद रहन-सहन का खर्चा ज्यादा है। पुराने जमाने से जब से कि यह फेमिन कोड बना हुन्ना है तभी से यह फर्क रखा गया है। पैरा १७४ रिवाइज्ड फेमिन कोड के मातहत ४० फीसदी तक ग्रन्तर हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला ग्रल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि पहाड़ों में १२ ग्राना बड़े लोगों को मिलता है, द ग्राना जो ग्रौरतें काम करने के लिये ग्राती है उनको मिलता है। तो क्या यह ६ ग्राना जो १२ वर्ष तक के बच्चे हैं उनको भी मिलता है?

श्री श्रष्ट्यक्ष--उसमें तो वयस्क लिखा हुग्रा है कि प्रत्येक वयस्क को मिलता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या मेहरबानी करके सरकार बतायेगी कि एक दिन में १५० क्यूबिक फिट मैदानी इलाके में खोदना पड़ता है। ग्रगर वह उससे ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा काम करना चाहे ग्रौर द ग्राने के बजाय १ रुपया कमाना चाहे तो क्या इसकी मुमानियत है?

श्री चरण सिह—यह तो जमीन की किस्मों पर निर्भर करता है। उनको २०० क्यू० फु॰ खोदना चाहिये तब उनको पूरी मजदूरी मिलेगी लेकिन जहां पर कड़ी जमीन है वहां पर १५० केवल रखा गया है। लेकिन यह २०० तक है ऐसा मुझे मालूम है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यदि कोई द म्राने से ज्यादा कमाना चाहे तो क्या म्राधिक मिट्टी खोदने की सरकार म्राज्ञा देगी, इजाजत देगी?

श्री चरण सिंह—इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहाड़ी क्षेत्रों मे महिला वयस्कों को क्या मजदूरी दी जाती है, क्या माननीय मंत्रो जी बतलाने की कृपा करेगे?

श्री चरण सिह—मै माफ़ी चाहता हूं कि इस समय नहीं बता सकता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला देवरिया)—देवरिया जिले में कुल कितना रुपया टेस्ट वर्को पर खर्च हुग्रा?

श्री ग्रध्यक्ष-इसमे रुपये का सवाल नहीं है, यह इससे नहीं निकलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर स्रोतिहर मजदूर टेस्ट वर्क चाहते थे ग्रौर जिलाधीश ने उन्हें बन्द करा दिया?

श्री चरण सिंह—जब हारवेस्टिंग का समय श्राया तो जिलाधीश ने मुझसे मशविरा करके बन्द किये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर श्रभी भी टेस्ट वर्क की मांग है ?

श्री चरण सिंह—ग्रभी २३, २४ तारीख को एक कान्फ्रेंस में हमने बहुत से फैसले किये हैं जिनमें यह भी है कि ३ जगहों पर टेस्ट वर्क जारी किये जावें ग्रौर उसके ग्रार्डस जारी हो चुके हैं। वे ३ जगह मुझे इस समय याद नहीं है, एक तो शायद तमकोही की तरफ सड़कें हैं एक तमकोही-सलैसगढ़ रोड ग्रौर एक दूसरी गालिबन वहां है, जहां फ्लड से ज्यादा ग्रफ़ैक्टेड हैं जहां से शायद राम जी सहाय जी ग्राते हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में सब से बड़े बाढ़ प्रस्त क्षेत्र में राकी-कछार में कोई टेस्ट वर्क नहीं किया गया है?

श्री चरण सिंह-यह में इस समय नहीं बता सकता।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कब्द करेंगे कि इन क्षेत्रों में स्त्रियां मदों से ज्यादा परिश्रम करती है ?

श्री ग्रध्यक्ष--यह राय का सवाल है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)-- स्या सरकार मजदूरी के बारे में, श्रकाल के समय, विचार करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह-ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या देवरिया जिले में टेस्ट वर्क से वहां के निवासियों को विशेष सुविधा हुई है, क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे ?

भी चरण सिंह--जी हां, इसी उद्देश्य से टेस्ट वर्क जारी किये जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि देवरिया के जिलाधीश ने फेमिन कोड के विरुद्ध २०० फिट मिट्टी लोदने का ग्रादेश दिया था ग्रीर इससे मजदूरों को तकलीफ़ हुई?

श्री चरण सिंह—गेंदा सिंह जी के ज्यादा मिट्टी खुदवाने की बात मेरे नोटिस में लाने पर मेने इसे बन्द करवा दिया। लेकिन तकलीफ की बात में नहीं मानता क्योंकि माननीय रामनारायण जी ने पूछा कि अगर कोई २०० फीट से ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा कमाना चाहे तो क्या सरकार उसे ज्यादा मङदूरी देगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिस दिन जिलाधीश ने काम बन्द करने की सलाह दी ग्रौर मन्त्री जी की सलाह से काम बन्द किया गया उस दिन वहां ४,००० ग्रादमी काम कर रहे थे?

श्री चरण सिंह -इसके लिये नोटिस चाहिये।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ग्रोलों से हानि

*५६--श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद) -- क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेगे कि क्या यह सही है कि तहसील बिलारों, जिला मुरादाबाद के कुछ ग्रामों में ग्रोला वृष्टि के कारण रबी की फसल को विशेष हानि हुयी हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितने प्रतिशत हानि हुयी हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के ७४ ग्रामों मे ग्रोलों मे रबी की फसल को साधारण हानि पहुंची। यह हानि रुपए में ग्राठ ग्राने से कम थी।

श्री मही लाल-क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना जो ७५ ग्रामों में हानि को मिली है क्या वह केवल लेबपालों की रियोर्ट पर ही ग्राधारित है ?

श्री चरण सिंह—-जी, यह रेवेन्य् मैनुएल के मुताबिक रिपोर्ट लेखपालों से ली जाती है लेकिन कभो-कभी तहसीलदार भी जाते है श्रीर श्रगर कभी ज्यादा नुकसान होता है एस० डो० श्रो० भी जाते हैं। इस विशेष जगह में किस कर्मवारी ने रिपोर्ट दो यह नहीं कहा जा सकता।

श्री मही लाल — क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर हाकिम परगना या तहसीलदार में से कोई नहीं पहुंचा ?

श्री चरण सिह--नोटिस की ब्रावश्यकता है।

*४७-५८--श्री गोवर्थन तिवारी (जिला ग्रत्मोड़ा)--[३१ मई, १९४४ के लिए स्थिगत किये गए।]

*४६--श्री राम सुभग वर्मा--[२४ मई, १६४४ के लिए स्थगित किया गया।] देवरिया जिले में तरया सुजान के टेस्ट वर्क का बन्द होना

*६०--श्री राम सुभग वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में तरया सुजान का टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। टेस्ट वर्क उस समय बन्द किया गया था जब कि जिले में रवी की कटाई हो रही थो। फसल को तैयारी के समय श्रमिकों को कृषि कार्य से ही पर्याप्त काम मिल जाता है।

प्रश्नोत्तर २५

श्री राम सुभग वर्मा — क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त टेस्ट वर्क बन्द किया गया उस वक्त हजारों की तादाद में मजदूर वहां काम करने के लिए आए थे?

श्री ग्रध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गेंदा सिह—-क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फेमिन कोड के अनुसार कितने दिन तक टेस्ट वर्क चलाया जाता है जबकि रिलीफ वर्क शुरू होता है ?

श्री चरण सिंह—फेमिन कोड की जो परिभाषा है वह पूरे तौर से इस में लागू नहीं होती क्योंकि उस के मुताबिक केवल मालूम किया जाता है कि लोग इस शरह मजदूरी पर स्रा सकते हैं या नहीं स्रीर स्राया रिलीफ की वहां जरूरत है या नहीं, इस केस में जो मजदूरी वहां वी जाती है उस से हम ज्यादा दे रहे है इसलिए वह कोड उस की कसौटी नहीं हो सकता।

श्री गेंदा सिंह—-िकस स्थान पर टेस्ट वर्क चलाने की जरूरत है इसके लिये मंत्री जी क्या ग्राधार समझते हैं ?

श्री चरण सिंह—-जैसा कि मैंने ग्रर्ज किया कि फेमिन कीड के ग्रनुसार मजदूरी बहुत थोड़ी है। वहां चारों तरफ से तकाजा हुग्रा कि मजदूरी बढ़ायी जाय ग्रीर उस पर ग्रगर सरकार ने बढ़ा दी तो उस का मतलब यह नहीं है कि वहां फेमिन है। द ग्राने तो देवरिया के बहुत से हिस्सों में नार्मल वेज है।

श्री गेंदा सिंह--जो मजदूरी देवरिया में दी जाती है वह श्राना पाई में क्या है?

श्री चरण सिंह---२४ छटांक सस्ते से सस्ते गल्ले की जो कीमत नजदीक के बाजार में हो वह रखी जाती है श्रीर इसीलिए गोरखपुर श्रीर देवरिया में जहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं वहां भाव के मुताबिक मुख्तलिफ वेजेज हो जाती है।

*६१--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला ग्रलीगढ़)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थिगत किया गया ।]

*६२--श्री देवसूर्ति राम--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*६३-श्री राम प्रसाद(जिला रायबरेली)--[३१ मई, १६४४ के लिए स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में रोडबेज की बसों को चलाने का विचार

*६४—श्री राम प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में किन-किन लाइनों में १९५४-५५ में सरकार श्रपनी बसें चलाने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १६५४-५५ में जिला रायबरेली में निम्नलिखित मार्गी पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार है:

१---रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़

२---रायबरेली, बछरावां-महराजगंज होकर

३-तिलोई, इनहोना, भाग रायबरेली, शंकरगंज तिलोई रूट का ।

बाराबंकी जिले के भूमिधर किसान

*६५—श्री वनश्याम दास (जिला बाराबंकी) (श्रनुपस्थित) - - क्या गवनंमेंट बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने किसान भूमिधर बने हैं श्रौर इनमें से कितने किसान भूमिधरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हैं श्रौर कितने को पाना शेष ह ?

श्री चरण सिंह-- बाराबंकी जिले में कुल ३४,८४४ भूमिश्वर बने है श्रीर ये सब भूमिश्वरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हे ।

#६६-६८-श्री धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली) -- [६ मई, १६५४ के लिए प्रक्ष संख्या ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

*६९--श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मेनपुरा)---[१७ मई, १९५४ के लिए स्थिगित किया गया।]

तहसील ठाकुरद्वारा, जिला दुरादाबाद मे स्रोलों से हानि

*७०--श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद) --क्या माल मंत्री को विदित है कि तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के श्रीधकाश भाग की रबी की फसल श्रोलों के पड़ जाने से बिल्कुल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तहसील ठाकुरद्वारा मे ११६ ग्रामों में श्रोला पड़ने से रबी की फसल को हानि पहुंची है। नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृषा करेंगे कि ११६ गांवों में से कितने गांवों में द श्राने से ज्यादा नुक्सान हुन्ना है ?

श्री चरण सिंह— ८५ गांवों मे ।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ६५ गांवों में ग्रोलों के कारण वहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। दयनीय नहीं है। उन्हें दयनीय न बनाइये।

श्री शिव स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इन ८४ गांवों में छूट के श्रलावा वहां तकावी बं वाने का भी इन्तजाम कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—केवल इस कारण तकावी बांटने के लिए हमने वहां नहीं कहा है। जो नार्मल तकावी हर जिले में दी जाती है उसी तरीके से वहां के लिए भी है। वहां इस किस्म का कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ है कि जिस बिना पर खासतीर से तकावी बांटी जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय -- क्या यह सही है कि इन श्रोले-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी सस्ती के साथ वसूल की जा रही है ?

श्री चरण सिंह--यह बात सरासर गलत है।

प्रक्तोत्तर २७

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में श्रोले से हानि

*७१--श्री कृष्ण शरण श्रार्य (जिला रामपुर) --क्या कृषि मंत्री बताने की कृषा करेगे कि जनवरी मास में श्रोलों की श्रधिक वर्षा के कारण रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसोल का किन-किन ग्रामों में कृषि की भारो हानि हुयी श्रीर कितने-कितने प्रतिशत ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तहसील शाहाबाद के केवल ६६ गांवों में ६ जनवरी, १६५४ को ग्रोला पड़ा जिससे पहले रबी को फसल को ग्रधिक हानि होने की संभावना थी, परन्तु बाद में वर्षा के कारण फसल की हालत सुधर गयी ग्रौर फसल को केवल साधारण हानि हुयी। जिन गांवों में ग्रोला पड़ा उसकी सूची संलग्न है।

तहसील मिलक में ग्रोलों से फसल को कोई नुक्सान नहीं हुग्रा।

(देखिये नत्थी 'छ' स्रागे पृष्ठ ५४ पर)

*७२--श्री कृष्ण शरण स्रार्य--क्या कृषि मंत्री बताने की कृषा करेंगे कि उपर्युक्त ग्रामों के कृषकों को सरकार की स्रोर से क्या-क्या सुविधायें दी गयी ह स्रथवा दी जायेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--केवल एक तहसील में साधारण हानि होने के कारण कोई सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्ण शरण श्रार्थ--क्या यह हानि = श्राने से कम की है?

श्री चरण सिंह--विलासपुर तहसील के ६९ गांवों मे प्राने से ज्यादा हानि है।

श्री कृष्ण शरण श्रार्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब एक साधारण नियम = श्राने से ज्यादा नुकसान में छूट देने का है तो इन गांवों के लिये क्यों नहीं छट दी गयी ?

श्री चरण सिंह—जैसा कि मैने कहा कि ग्रगर द ग्राने से ज्यादा नुक्सान है तो जरूर छूट दी जायगी।

महालों का कम्पेन्सेशन रोल

*७३--श्रो सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या सरकार बताने की कृप करेगी कि श्रव तक कुल कितने महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हो गया है श्रौर वह कुल महालों का कितना प्रतिशत है?

श्री चरण सिंह—-३१ मार्च १९४४ तक २,७६,३९६ महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हुआ जो कुल महालों का ६९.६ प्रतिशत है।

*७४—श्री सियाराम चौधरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना क्पया प्राविजनल कम्पेन्सेशन निर्धारित किया गया है श्रौर उसमें से कितने का बांड दिया जायेगा तथा कितना नकद ?

श्री चरण सिह—कुल प्राविजनल कम्पेंसेशन ७० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें से लगभग १३ करोड़ रुपया नक्षद श्रीर लगभग ५७ करोड़ रुपया बांडों में दिया जायगा।

*७५--श्री सियाराम चौधरो--वया सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में तथा कितना इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका है? श्री चरण सिंह—३१ मार्च १९५४ तक ३,६३,४७,९६७ रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में ग्रीर २०,७१,१४८ रुपया इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका हे।

जीनपुर जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता

*७६--श्री नागेश्वर दिवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में ब्रब तक किन-किन बाढ़ पीड़ित गांवों को गृह निर्माण योजना के श्रन्तगंत कितनो-कितनी सहायता दी गयी है श्रीर वह सहायता किस रूप में दी गयी है ?

*७७—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में पिछली बाढ़ से किन किन-गांबे में कितने कितने मकान गिरे थे?

श्रो चरण सिह—मांगी गयी सूचना संलग्न सूची में दी हुयी है। (देखिये नत्थी 'ज' ब्रागे पृष्ठ ८५-८६ पर)

लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में छूट

*७८-श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)-क्या सरकार यह बताने की कृषा करेगी कि लखनऊ जिला के गत वर्ष के बाढ़-पीड़ितों के लगान की मुलतबी खोर छूट का एलान किया गया है? यदि हां, तो कब ख्रीर यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृषा करेगी?

श्री चरण सिंह--जिलाधीश ने तहसील सदर श्रीर मिलहाबाद के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी श्रीर लगान की वसूलयाबी १६५० के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश श्रीर भूमि व्यवस्था श्रीविनयम के श्रधीन बनायी गयी नियमावली के नियम २६३ (४) के अन्तर्गत प्राप्त श्रीविकारों के श्रनुसार केंबल मुल्तबी कर दी है। इसका कारण यह है कि जिलाधीश के प्रस्तावों पर कुछ श्रीर जांच की जा रही है श्रीर उसके बाद मालगुजारी की खूट या मुल्तबी के श्रादेश नियमानुसार दिये जायेंगे।

*७६-श्री हरिश्चन्द्र वाजपेटी--क्या सरकार लखनऊ जिला की उन गांवों की सूची देने की कृपा करेगी कि जहां पिछली बाढ़ के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी श्रीर किसानों को भारी क्षति पहुंची ?

ः श्री चरण सिंह--अपेकित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६७ पर)

बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में गबन

*द०-श्रीबलालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--श्या सरकार बतायेगी कि बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में जो गवन हुआ था और जिसमें कई कर्मचारियों पर मामला चल रहा था उसमें क्या हुआ ?

श्री चरण सिंह—बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कीय में जो गबन हुआ था उसमें एक मुन्तरिम तथा एक तहसीलदार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसमें अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री टी॰ डी॰ सेठ तहसीलदार निलम्बित (under suspension) है। उनके तथा ग्रन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रका विचाराधीन है।

बस्ती जिले में अने र गांदी की वर्षा से क्षति

* द १ — श्री राम लुन्दर राम — व्हार सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष वर्ष काल में श्रति वृद्धि तथा कुंग्रानों निकास के बाढ़ से निकायम्तो से मुखालसपुर, पड़री तथा सिगर। सऊ के काफी मकान कर कर नदी थे बले गए?

श्री चरण सिंह—ग्राम मुखलिसपुर पड़री तथा सिगरामऊ मे कोई मकान कट कर नदी में नहीं गणा परन्तु प्रथिक वर्षा रो सन्तानों को कुछ क्षति स्रवश्य पहुंची।

* ५२--श्री राम सुन्दर राम --क्या सरक र यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मौजों में क्षित ग्रस्त लोगों को सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह—इन गांदों ने लोगों को प्रनाज, नमक. लिट्टी का तेल, दियासलाई, मुरती, दूध तथा दयाइयां पुष्त ही गयीं। ३० व्यए की गकद सहायता भी दी गयी। मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयो। श्रीर ियनानुसार छट देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

मुजक्फरनगर, भेरठ तथा सहारतपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स

*द३-श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर की जनींदारी खातमे के पहले कुल मालगुजारी श्रीर लगान क्या था श्रीर जमींदारी खातमे के बाद प्रब श्रलग-श्रलग इन जिलों की मालगुजारी श्रीर लगान क्या है ?

श्री चरण सिह--- आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८४--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार कृषया बतायेगी कि १६५२ मे जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ग्रौर मेरठ का कृषि टेक्स कितना कितना था ग्रौर ग्रब नये संशोधनों के बाद यह कितना रह गया है?

श्री चरण सिंह— २८,फरवरी १९४४ तक जिला सहारनपुर श्रौर मेरठ का १३४९
 श्रौर १३६० फसली का कृषि श्राय कर निम्नलिखित है:—

जिला		कृषि	ग्राय कर	१३५६ फ०	१३६० फ०
सहारनपुर	• •			२,६१,५८३	७०३,४८,६०७
मुजपफ़रनगर	• •	• •	• •	१,८२,४२६	१,५७,५६२
मेरठ	• •	• •	• •	२,६६,७०१	४,५५,५७४

महोबा एवं चरखारो के तहसोलदारों द्वारा कागजात में सेहत

*दभ्र--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की घारा ३६ ग्रीर भूमि सुधार ग्रनुपूरक ग्रिधिनयम की धारा ४ के ग्रिधीन तहसीलदारान महोबा एवं चरखारी जिला हमीरपुर ने श्रपने जनवरी, सन् १६५४ के दूर में ग्रलग-ग्रलग कुल कितनी दुरुस्तियां सेहत काग्रजात की है?

श्री चरण सिंह—तहसीलदार महोबा ने लंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ३६ के स्रधीन १०८ और भूमि सुधार स्रनुपूरक स्रधिनियम १६४२ की धारा ४ के स्रधीन ६८ तथा तहसीलदार चरखारी ने लंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ३६ के स्रधीन ८२ सेहत कागजात की कार्यवाही ते की। तहसीलदार चरखारी के न्यायालय में भूमि सुधार स्रनुपूरक की धारा ४ के स्रधीन कोई वाद पेश नहीं हुस्रा।

*६६--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सेहत कागजात का भ्रधिकार भ्रदालत पंचायतों से छीन कर फिर तहसीलवारों के श्रधिकार में वे दिया गया है? यदि हो, तो कब?

श्री चरण सिंह—१६ जून, १६५३ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ग्रीर भूमि व्यवस्था (संशोधन) ग्रिधिनियम, १६५२ के श्रनुसार पंचायत राज श्रिधिनियम में परिवर्तन हो गया है जिसके श्रधीन सेहत कागजात के मुकदमें तहसीलदार तथा कलेक्टरों के न्यायालय में होते हैं।

कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के पर्रामट

*८७--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)-क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४१-४२ श्रीर ४३ के दिसम्बर तक कानपुर रीजन में कितने मोटर ट्रकों, प्राइवेट लारियों श्रीर कारों के परिमट दिये गये ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--१६५१-१६५२ व १६५३ में कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों, लारियों व कारों के निम्नलिखित परिमट दिये गये:

8848

१९४२				• •	• •	50
पब्लिक कैरियर						
सवारी गाड़ी	• •	• •	• •	• •		Ę
टैक्सी कार	• •	• •	• •		• •	२६
प्राइवेट कैरियर	• •	• •	• •	• •	• •	• •
१६५३	• •	• •	• •	• •		२८
पिंक्लिक कैरियर						
सवारी गाड़ी	• •	• •	• •	• •	• •	११५
टैक्सी कार	• •	• •	• •	• •	• •	२४
प्राइवेट कैरियर	• •	• •	• •	• •		₹
	• •	• •	• •			ሂሂ

मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गयी बसें

^{*}दद—श्रो रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या परिवहन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में मेरठ के सरकारी रोड़वेज कारखाने के हार

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १६४२-४३ में २७६ गाड़ियां मरम्मत की गयीं। इनमें से १७८ तो रोडवेज की थीं व ६८ दूसरे विभागों की थीं।

बलिया जिले में हरिजन लेखपालों की संख्या

*८६--श्री राम रतन प्रसाद (जिला बिलया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलया जिले की प्रत्येक तहसील में कितने कितने लेखपाल लिये गये है और उनमें से प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपाल कितने कितने हैं?

श्री चरण सिंह—बिलया जिले के प्रत्येक तहसील में लेखपालों की संख्या तथा प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपालों की संख्या निम्नलिखित है:

तहसील				कुल संख्या	लेखपाल	हरिजन	लेखपाल
बलिया	• •	• •		• •	१२०	• •	y
बांसडीह	• •	• •	• •	• •	३०६	• •	२
रसङ्ग	• •	• •	• •	• •	१२८	• •	ሂ
			- योग · •		३४७	<u> </u>	\$ &

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री ग्रध्यक्ष--मेरे पास जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर ने श्री राजनारायण सिंह की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना भेजी है, वह इस प्रकार है:--

"ग्रपने २५ ग्रप्रैल, १६५४ के पत्र-संख्या ५४१—बी/५४ के कम में, ग्रापके सूच-नार्थ मुझे यह निवेदन करना है कि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह को पहली मई, १६५४ को जमानत पर छोड़ दिया गया, परन्तु दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन ११७ (३) के साथ पिठत सेक्शन १०७ के ग्रन्तगंत कार्यवाही जारी रहने के कारण एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट ने विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह से ३० ग्रप्रैल, १६५४ को यह चाहा कि वे १,००० रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दें तथा २ प्रतिभू, प्रत्येक उसी धनराशि का देवें ताकि जब तक दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन १०७ के ग्रन्तगंत मामला विचाराधीन रहे, वे शांति भंग न करें। चूंकि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह ने वह मुचलका नहीं दिया तथा वे प्रतिभू भी नहीं दिये, जो उनसे मांगे गये थे, उनको कानपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में हिरासत में रखा गया है।"

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री ग्रध्यक्ष—पुस्तकालय सिमित में ३ स्थान रिक्त हो गये थे क्योंकि कौंसिल के कुछ सबस्यों का विधान परिषद् का समय समाप्त हो गया था। उनमें से श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी फिर से चुन कर ग्रा गये हैं इसलिये उन्हें में पुस्तकालय सिमित के लिये नामजद करता हूं। ग्रब दो सदस्यों का प्रश्न रह जाता है। एक श्रीमती महादेवी वर्मा, उनके संबंध में यदि निर्णय हुग्रा कि वे नियुक्त हो गयीं तो वे सिमित में नियुक्त हो जायेंगी। तीसरे श्री मुकुट विहारी लाल चुनाव में हार जाने के कारण नहीं चुने गये। उनका स्थान रिक्त है, जिसके विषय में फिर विधान परिषद् के किसी माननीय सदस्य की नियुक्त होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रशिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुलः गिरफ्लारी

श्री ग्रध्यक्ष—मैने पिछले शुक्रवार को यह कहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है उसके विचार के लिये कोई दिन नियत करूंगा। विचार विनिमय के बाद में यह निर्णय करता हूं कि गुरुवार, तारीख ६ को प्रश्नों के समाप्त होने के बाद १२ बजे से उसके ऊपर विचार होगा। उसके लिये दो घंटे का समय इस प्रकार से होगा——१२ बजे से सवा बजे तक, श्रीर सवा दो बजे से तीन बजे तक। ३ बजे उसके ऊपर विचार समाप्त होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय ऋध्यक्ष, क्या सरकार श्री राज नारायण जी की दुबारा गिरफ्तारी पर इस सदन में श्रपने वक्तव्य द्वारा श्रीर ऋषिक सूचना देना उचित समझती है?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) — जो सूचना श्रध्यक्ष महोदय ने दी है उससे श्रधिक कोई ग्रौर जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। उससे श्रधिक जानने के लिये कोई बात ज्यादा जरूरी भी नहीं मालूम देती। जो कुछ है वह खेदजनक है, मगर है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, क्या ग्रापको इसकी सूचना है कि माननीय राज नारायण जी को जेल से रिहा नहीं किया गया ग्रीर जेल में ही शांति भंग का नोटिस दे दिया गया?

श्री ग्रध्यक्ष—मुझे एक यह सूचना मिली है कि जेल में ही नोटिस दिया गया था लेकिन उनको रिहा किया गया ऐसा एक तार माननीय राज नारायण जी का भी मेरे पास ग्राया है कुछ ऐसा मुझे स्मरण है कि ऐसा कोई तार उनका भी मेरे पास ग्राया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान् जी जो श्राप ने विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में तिथि नियुक्त की उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि मेरे दो पत्र तथा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के नोट में नहीं छपे हैं। इसलिये यदि उनके प्रकाशन की व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय कर दें तो उचित होगा ताकि सदन को विचार करने से पहले वस्तुस्थिति क्या है, यह मालूम हो जाय।

श्री ग्रध्यक्ष—इसके ऊपर विचार कर के निर्णय दूंगा लेकिन इसके विषय में उसी हिन प्रश्न उठाया जा सकता है ग्राज नहीं।

सदन के श्रागामी कार्यश्रम के संबंध में सूचना

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—ग्रध्यक्ष महोदय, में श्रापके द्वारा जानना चाहूंगा कि ग्रसेम्बली कब तक चलेगी?

मुस्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) — मुझे तो यह उम्मीद श्री कि ७ तारीख़तक काम खत्म हो जायगा और ७ के बाद सब लोग घर जा सकेंगे, मगर वह तो सदस्यों के हाथ में हैं, वह जब चाहें उस काम को पूरा कर दें और तब असेम्बली का इस वक्त का सेशन खत्म किया जाय। अब उसके बारे में उनके मन में क्या है वह में नहीं जानता। वे निश्चित कर दें कि फला दिन तक यह हो जायगा, तो उसी के मताबिक्त कार्यवाही हो जाय।

उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक गृह-ब्यवस्था विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्रो सैयद श्रली जहीर) — ग्रध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश श्रौद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९४४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङा' स्नागे पृष्ठ ८८--१५ पर)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४

†खंड १३ (ऋमागत)

श्री ग्रध्यक्ष—म्ब्रब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुम्रा है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रत्मोड़,)—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में उस दिन संशोधन पर बोलते हुये यह चाहता था श्रौर यह चाहता हूं कि जो एक्जीक्यू दिव ग्राम सभाश्रों की बने उसका नम्बर श्रभी से निर्धारित कर दिया जाय श्रौर वह काम प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी को न सौंपा जाय। श्र-यक्ष महोदय, प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी के जिम्मे बहुत से काम हो ग्रो है श्रौर श्रगर यह मेम्बर की संख्या तय करने का भी काम दे दिया जाय तो इसमें बड़ी दिक्तत पड़ जायगी। में चाहता हूं कि कम से कम ग्राम सभाश्रों पर यह छोड़ दिया जाय कि वह ११ मेम्बरों को श्रपनी एक्जीक्यू दिव में रखना चाहती है या उससे ज्यादा। इसके श्रलावा गांव सभाश्रों के श्रधिकार में टेक्सेशन का भी प्राविजन रखा गया है। में समझता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद गांव वालों की होगी, तो जब कभी टेक्सेशन का प्रपोजल होगा उस समय जितने ही ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उनकी सहमति प्राप्त हो जायगी। यह तो मेने श्रपनी बात कह दी लेकिन, श्रगर माननीय मंत्री जी इसको साफ़ कर दें कि वे क्यों इसे गांव सभाश्रों पर न छोड़ कर प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी पर छोड़ना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद में श्रौर जो कुछ श्रर्ज करना होगा श्रर्ज करूंगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम) — माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, १२ के दूसरे उपखंड में जो है वह प्रेस्काइ इब प्रथारिटी नहीं है। 'The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed. जितने भी तय हों। ११ से ४१ हों या इससे ग्रागे के संशोधन में १५ से ३५ हो इसमें मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कुछ दिक्कत यह है कि ग्रभी इस प्रकार की चीज के रखने से दुक्वारी होगी, क्योंकि ग्रभी श्रन्तिम स्वरूप मेरे सामने नहीं है। हमारी कोशिश यह भी है कि एक यूनिट गांव समाज ग्रौर गांव सभा की हो जाय ग्रौर सारा झंझट दूर हो जाय। जब गांव सभा ग्रौर गांव-समाज की शक्त नजर ग्रायेगी उस वक्त यह तय होगा कि कितनी संख्या हो। प्रेस्काइ इब ग्रथारिटी क्या हो इसके बारे में रूल्स में होगा। रूल्स हाउस के सामने ग्रायेंगे उस वक्त श्राप ग्रपनी राय दे दें। मुझे मुनासिब बात के मानने में कभी कभी कोई ग्रापत्ति नहीं होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ३२, ३३ ग्रौर ३३ (ग्र) को इस समय न पेश कर के ग्रौर उन पर इस वक्त जोर न दे कर वे रूल्स के वक्त इस पर गौर कर लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्राश्वासन दे दिया है कि रूत्स के वक्त विचार कर लेंगे ग्रौर फिजूल सदन का समय नष्ट न हो, इसलिये में इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

^{*}संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ ध्रप्रैल, १९४४ की कार्यवाही में छपा है।

[🎁] ३० भ्रप्रैल, १६५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री ग्रध्यक्ष-श्री गेंदा सिंह, ग्राप ग्रब ग्रपना संशोधन नहीं पेश करेंगे?

श्रो गेंदा सिंह (जिला देवरिया) -- जी नहीं।

श्री ग्रध्य —श्रो जोरावर वर्मा, ग्राप भी नहीं पेत फरेगे?

श्री जोरावर वर्मा (जिलाहमीरपुर) — जी हां, ग्रगर नियमों के वक्त इस पर विचार

श्री ग्रध्यक्ष--जी हां, वह तो उन्हों ने कह ही दिया है।

श्री ग्रहदुल मुईज खां (जिला बस्ती)—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "and the Up-Pradhan" तथा पंक्ति ४ में शब्द "and Up-Pradhan" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, श्राप देखेंगे कि उपघारा २ की विडिंग जो है 'The number of members of a Goan Panchayat shall be such as may be prescribed" श्रीर इन्ही मेम्बर्स के बारे में फिर कहा गया है कि जिनको प्रधान श्रीर उपप्रधान चुना जाय, उसके अलावा जितने मेम्बर्स होंगे उनका टर्म ५ साल का होगा। श्रीमन्, श्राप देखेंगे कि उपप्रधान ११ बी में जो कर दिया गया है उसमें गांव पंचायत पहले ही सदस्यों मे से एक सदस्य को उप-प्रधान की हैसियत से चुन लेगी। तो ऐसी सूरत में उप-प्रधान का यहां पर रख देना मुनासिब नहीं मालूम होता है क्योंकि उप-प्रधान के लिये ११ बी में दिया ही हुआ है कि उप-प्रधान का चुनाव हर साल होगा, इसलिये उसके आगे यह फिर कह देना कि उसकी अवधि ५ साल नहीं होगी, उससे शुभा सा पैदा होता है। में उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मंजूर फरमायेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोवय, 12 (2) में दो चीजें शामिल कर दी गई हैं। एक तो गांव पंचायतों का नम्बर श्रौर दूसरे प्रधान श्रौर उप प्रधान का एक्स श्राफिशियो गांव पंचायत का प्रधान श्रौर उप प्रधान होना। यह कंसीड्रेशन कैसा है, यह तो सवाल दूसरा है। एक श्राइडिया इसका यह है कि "The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed"

श्रीर दूसरा श्राइडिया यह है कि "President and Vice-President of the Gaon Sabha shall be ex-Officio President and Vice-President of the Gaon Panchayat"

श्री ग्रध्यक्ष-उप प्रधान के चुने जाने का क्या तरीका है?

श्री मोहन लाल गौतम—उप प्रधान का चुनाव ११ बी में दिया हुन्ना है:
"The Vice-President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed...... ग्रीर प्रधान के चुनाव का तरीका ऊपर 11—A में दिया हुन्ना है: "The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed......"

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्राप इजाजत वें तो उसमें ग्रगर सफाई हो जाय तो ज्यादा ग्रन्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्पयूजन पैदा होने की संभावना कम से कम उन लोगों को है जो कि कानून को इन्टरप्रेट नहीं करते हैं। इसलिये ग्रगर कोई इस तरह का कन्पयूजन हो तो उसका साफ हो जाना ही मुनासिब है। गांव सभा ने प्रेसीडेंट चुन दिया तो वह गांव सभा का ही प्रेसीडेंट होगा, यह इम्पलाइड मान लिया गया है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट को चुना है गांव पंचायत ने ग्रोर वह वाइस प्रेसीडेंट होगा गांव सभा का, मेरे ख्याल से यह दिक्कत ग्रब्धुल मुईज साहब

को मालूम होती है, क्योंकि ऊपर साफ नहीं है। वाइस प्रेसीडेंट चुना जायगा श्रोर वह गांव सभा का प्रेसीडेंट होगा, ऐसा गांव सभा के कांस्टीट्यूशन में है। यहां पर इसिलिये प्रेसीडेंट ऊपर जो दिया गया गांव सभा का उसी को वाइस प्रेसीडेंट पंचायत का चुना जायगा यह अर्थ है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट जब गांव पंचायत का चुना तो वह गांव सभा का बाइस प्रेसीडेंट हुआ।। इसके समझने में कुछ दिक्कत होती है। मुझे साफ़ नजर श्राती है। लेकिन अगर आप की आज्ञा हो तो १२ को रीड्राफ्ट करा दूं। इसमें दिक्कत जरूर है और उसमें अगर भाषा साफ भी हो तो वह थोडा सा साफ हो जायगा। तो इसमें कोई आपित्त नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष—में समझता हूं 11—B में श्राप को करना चाहिये था: He shall be Up-Pradhan of the Gaon Sabha as well..... जिस पंचायत ने चुना उसका तो उप-प्रधान हुन्ना हो। उसमें कोई झगड़ा नहें। है। लेकिन गांव सभा का भी वह है। यह बात ग्रापने मेंन्शन नहीं की। में इस समय पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि यह पास हो चुका है। पु हो सफता है कि खंड के ग्रलावा एक उपखड ग्राप इसमें लगा दे।

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्राप की ग्राज्ञा हो तो उसको रीड्राफ्ट करा दूं। क्योंकि ग्रगर यह हो जाय कि The Vica-President of Gaon Sabha shall be elected annually by tehG aon Panchayat तो वह ज्यादा साफ हो सकता है। ग्रगर ग्राप ग्राज्ञा दें तो यह हो जाय "and the UP-Pradhan of the Gaon Sabha elected under 11 (b) मैं इसको ड्राफ्ट करवा कर मंगा लूं तो कुछ ग्रापत्ति नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष--तो में इसको छोड़े देता हूं ग्रीर ग्रागे बढ़ा जाता हूं, इसे फिर लें लूंगा।

श्री ब्रब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, मेरे संशोधन का एक मतलब यह भी था कि धारा १२ की उपधारा (२) में जो शब्द "एक्सब्राफ़िशियो" ब्राया है, तो चूंकि उप-प्रधान तो स्वयं ही उस पंचायत का मेम्बर होगा, लेकिन प्रधान पंचायत का मेम्बर नहीं होगा.....

श्री ग्रध्यक्ष—तो उसका नतीजा तो यही होगा कि ग्रगर ऊपर ग्राप चेंज करते हैं तो ग्राप का ग्रमेंडमेंट यहां स्वीकार किया जायगा। तो इसिलये ग्रगर दोनों को ग्राप ग्रको-मोडेंट कर दें कि उप-प्रधान गांव सभा तथा गांव पंचायत दोनों का है, यह पहले ग्रगर ग्रा जायगा तो ठीक होगा। तो में खंड १३ के ग्रौर ग्रागे के प्रस्ताव ले लेता हूं। बाद में फिर उसके ऊपर वापस ग्रा जाऊंगा। श्री ग्रब्दुल मुईज खां, ग्रापका दूसरा संशोधन

श्री ग्रब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, यह भी उसी से संबंधित है श्रौर चूंकि ११-बी में यह स्पष्ट रूपसे नहीं दिया हुमा है कि उप प्रधान गांव सभा का होगा या गांव पंचायत का होगा। लेकिन चूंकि गांव पंचायत हो उसे चुनेगी इसलिये नेचुरली यह अन्दाजा होता है कि गांव पंचायत का होगा।

श्री ग्रध्यक्ष—में समझता हूं कि माननीय श्रब्दुल मुईज खां माननीय स्वशासन मंत्री से इस बात पर राय ले लें वयों कि ११—बी को न बदल कर यह भी एक तरीक़ा हो सकता है जो श्री ग्रब्दुल मुईज खां ने जो श्रभी बात कही उसे मान लिया जाय। इसको भी माननीय मंत्री विचार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम-इसको थोड़ी देर के लिए मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष--हां। यह भी तरीका हो सकता है कि खंड १२ पर न जा कर जो तरीक़ा ग्रब्हुल मुईख खां जो ने बतलाया है कि उनके दोनों संशोधनो स्वीकार कर लिये जायं इससे ग्राप की दिक्कृत का हल हो जाता है। श्री ग्रब्दुल मुईज खां—ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित वारा १२ की उपधारा (३) की पंक्ति दो में शब्द "Pradhan or" निकाल दिये जायं। इसके निकालने के बाद वह इस प्रकार से हो जायगी:—

"The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be 5 years"

इसका मतलब यह होगा कि प्रधान और उपप्रधान निकल गये। उपप्रधान तो इसलिये निकल गया कि चाहे वह उपप्रधान हो या न हो उसकी गांव पंचायत की मेम्बरिशाप तो पांच साल के लिये हैं ही चाहे वह उप-प्रधान रहें या न रहें। रह गया प्रधान के बारे में, तो उसके लिये तो पहले ही च साल दिया हुन्ना है। ग्रगर इसमें से यह नहीं निकाला जाता है तो कुछ कन्पयूजन होता है क्योंकि उसके माने यह होंगे कि उप-प्रधान गांव पंचायत का मेम्बर नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—प्रधान शब्द भी निकाल दिया जाय क्योंकि प्रधान भी पांच साल रहेगा ग्रौर मेम्बर ग्राफ दि एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी होगा।

श्री अब्दुल मुईज खां--मुझे स्वीकार है।

श्री ग्रध्यक्ष-प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ को उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "Pradhan or Up-Pradhan or a" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रोर स्वोकृत हुग्रा।)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—ग्रध्यक्ष महोदय, मै श्रापकी श्राज्ञा से इस संशोधन में ३ लंड है उसमें से एक को पेश करना चाहता हूं।

। श्री ग्रध्यक्ष--ग्राप कौन सा पेश करना चाहते हं।

श्री वीरसेन-मैं बीच का पेश करना चाहता हूं। में श्राणकी श्राज्ञा से उपलंड (६) की दूसरी पंक्ति में.....

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरो गढ़वाल) — ऋध्यक्ष महोदय, जिस संशोधने को माननीय सदस्य वेश करना चाहते हैं वह उपखंड ६ है। में उपखंड ४ की स्रोर स्नापको घ्यान स्नाक्षित करना चाहता हूं। हालांकि मेरा कोई संशोधन नहीं है। यदि स्नापका स्नाजा हो तो में पेश कर दूं। मेरा संशोधन यह है कि उपखंड ४ में शब्द "afore-aid or when the period has beed extended before the expiry of such extended period," निकाल दिये जायं क्योंकि यह व्यर्थ है।

श्री मोहन लाल गीतम— अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। असल में शाह साहब का जो श्राब्जेक्शन हैं उस पर विचार करने को जरूरत हैं। अगर दोनों चाजां को एक साथ पढ़ा जाय तो अच्छा हो। इसके पहले के तांसरे प्रावोजों में हैं कि: "Provided that the State Government may, by notification in the official gazette, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." डिलोट हो गया। यह पहले ड्रापट हुआ था जबिक at a time. यानों एक साल से ज्यादा न हो और कितने दिनों के लिए हैं इस ही कोई लिमिट नहीं था। अब "at a time" निकालने के बाद क्या करेरीफि केशन है था नहीं। यह सवाल है जो महाराज कुमार बाले न्दुशाह जो ने उठाथा है, उस पर विचार कर लिया जाय कि: "extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." क्या वह एक ही साल के लिये होगा था ज्यादा के लिये यह अगर यहाँ साफ हो जाय तो दो चीजें साफ होनी चाहिएँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए हो सकता है और प्रार

एक साल के लिए रखा जाता है तो वह क्या एक ही बार हो सकता है या कई बार हो सकता है? यह साफ हो जाना चाहिए, पहले ऊपर हमते थोड़ा सा अमेडमेट किया है और आगे यह अमेडमेट शायद कृपाशंकर जो के नाम से आ रहा है। टोटल पीरियड आफ वन योयर होना चाहिए। उसका मतलब यह होगा कि एक साल से ज्यादा का एक्सटेशन तो नहीं होगा लेकिन ऐट ए टाइम कम भी हो सकता है। तान-तोन महीने के चार एक्सटेशन भो हो सकते है, चार चार महीने के तीन भो हो सकते हैं। तो यह जाहिर करता है कि एक्सटेशन चाहे जितने दिन का मिला हो लेकिन टोटल पोरियड आफ एक्सटेशन शुड नाट एक्सोड वन योयर। यह है इसका अर्थ।

श्री ग्रध्यक्ष—इसके पहले भी शायद यह हो चुका है कि गाँव पंचायत का टर्म १ साल का रहेगा ग्रोर उसने १ साल से ज्यादा टोटल पीरियड एक्सटेड नहीं होगा। उसमें फाम टाइम दु टाइम हटा दिया गया है। तो यह किस तरह से होगा कि पंचायतों का टर्म तो न बढ़ाये श्रोर मेम्बर का टर्म बढ़ा दे यह तो नहीं हो सकता है। श्रगर पंचायत का टर्म बढ़ा दिया गया तो वह तो एक साल के लिए बढ़ा सकते हे लेकिन फिर मेम्बर का क्या तोन महीने के लिए बढ़ाया जायगा, ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है?

श्री मोहन लाल गौतम—जो नहीं। यह चीज तो ग्रसंगत हो जायगी, चलेगी नहीं। पंचायत का टर्म बढ़ाने पर मेम्बरों का भी श्राटेमेटिकली बढ़ेगा हो।

श्री ग्रध्यक्ष—तो इसके लिए ये लफ्ज फ्राम टाइम दु टाइम जो उसमे हटा दिये गर्ये है, वैसे ही इसमे से भो हटा दिये जायं।

श्री मोहन लाल गौतम—जां हाँ। हटा दिवे जायं श्रोर जो टोटल लफ्न हं वह बढ़ा दिया जाय। "Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year". जो वहाँ हे वही यहाँ रोओड्यूस हो जाय तो फिर गलतो नहीं होगा।

स्वशासन मंत्री के सभा सिवव (श्री कृपाशंकर) — श्रगर वह टोटल पोरिएड एक साल का है श्रोर उसमें दो बार या तोन बार में एक्सटेड करने का ख्याल हो तो फ्र.म टाइम टुटाइम रहने दिया जाय तो श्रच्छा होगा। यह श्रगर निकाल दिया जायगा तो फार दो टोटल पोरियड श्राफ वन योयर का मतलब यह होगा कि एक हो साल का एक्सटेसन हो। श्रगर सदन की यह मंशा हो कि दो बार या तीन बार में एक्सटेशन किया जाय तो उसे भी रहने दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष—पहले जो हुन्ना है वैसा हो यह भी हो तो उचित है। ग्रगर पंचायत का टर्म एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया हो तो मेम्बर का टर्म बोच में थोड़े हो दिनों के लिए बढ़ाने का कोई ग्रोचित्य मालूम नहीं होता।

श्री मोहन लाल गौतम—दोनों चीजे एक ही तरह से हों, यही श्रच्छा होगा । जो प्राविजन वहां है वही यहां भो रख दिया जाय ।

श्री ग्रध्यक्ष—तो मं यह संशोधन शापका लिए लेता हूं कि यह "total" शब्द बढ़ा दिया जाय ग्रोर " from time to time" निकाल दिया जाय। " Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year".

श्री श्रब्दुल मुईज खां—"for a total period of one year" का भी वहीं अर्थ होगा जो "from time to time" का होगा। "for a period of one year" अगर होता तब तो यह अर्थ हो सकताथा कि एक ही साल का एक दका बढ़ाया जा सकताथा। लेकिन इसका तो माने यही होगा कि कई दका बढ़ाने पर भो सबका टोटल एक ही साल आये। तो टोटल पोरियड में भो वह चोज नहीं आतो है।

श्री ग्रध्यक्ष — हां टोटल का मतलब यही हो सकता है। "for a period not exceeding one year" हो ग्रीर "from time to time" हटा दिया जाय तो यह चीज हो सकती है। माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल गौतम —जो मुईज साहब का कहना है कि फार ए टोटल पोरियड नाट एक्सोडिंग वन इयर इसमें ऐट एक टाइम इंग्लाइड तो नहीं हो जाता, ग्रौर ग्रगर हो जाता है तो यह देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्त-तो श्री बालेन्दुशाह जी का संशोधन स्थगित रहेगा।

श्री वीर सेन —माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में घारा १२ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति से शब्द "on joint electorate system" निकाल दिये जायं।

म्राच्यक्ष महोवय, जब से हमारा कांस्टीटुयूशन लागू हुम्रा हं तबसे सेपेरेट एलेक्टीरेट सिस्टम खत्म किया जा चुका है और जितने भी एलेक्शन उस के बाद हुए है जनरल एलेक्शंस ग्रीर म्युनिसिपल एलेक्शंस सब ण्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम से हुए है। तो यह शब्द ग्रान ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम बिलकुल रिडेडें है। इन शब्दों को कायम रखने से ऐसा मालूम होगा कि जैसी किसी मरी हुयी चोज की याद दिलाने के लिए एक यादगार बनायी जा रहें। हो। किसो जमाने में सेपेरेट एलेक्टोरेट सिस्टम था लेकिन ग्रव वह चोज नहीं है। मेने रिप्रेजेंटेशन ग्राफ प्युपुल्स ऐक्ट में देखा। उसमें भी किसी तरह का रेफरेंस नहीं है। कांस्टीट्यूशन के ग्राटिकिल ३२५ में सिर्फ यह प्राविजन है कि जनरल एलेक्टोरल रोल होगा ग्रीए उसमें रिलोजन कास्ट ग्रीर कीड के ऊपर किसी को डिबार नहीं किया जायगा एनलिस्ट होने के लिये। तो मेरा ख्याल है कि ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम रखना बिलकुल बेकार है। बिना इसके रखे हुए ही यह स्पष्ट हो जाता है। ग्रीर ग्रव इस तरह का कोई क्लम भी नहीं है कि हम।रा एलेक्शन सेपेरेट होना चाहिए। न तो मुसलमानों की तरफ से यह मांग है ग्रीर न शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ से हैं। इसलिये में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो ३२५ श्रनुच्छेद में भाषा है वह यह है,

"There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, racer, caste, sex on any of them"

इसमें ज्वाइंट एलेक्टोरेट को ज्यादा एक्स्प्लेन कर दिया है कि इस बेसिस पर न किसी को रोल में शामिल होने से ग्रौर न किसी कौस्टीटुएँसी के लिये क्लेम करने से रोका जा सकता है। उस भाषा की यहाँ जरूरत नहीं मालूम होती। ऐसा नहीं हैं कि सेपेरेट एलेक्टोरेट की कोई माँग नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय सदस्य को यह याद होगा कि ग्रलोगढ़ कानफ समें मुसलिम जमायत ने एक अपनी यह माँग रखी थी कि सेपेरेट एलेक्टोरेट ग्रौर रिजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए वह इस विषय को जितना मरा हुआ जानते हैं, उतना मरा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में इन शब्दों का रखना ग्रावश्यक है।

श्री वीरसेन--अध्यक्ष महोदय, में तो समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय जैसा बतला रहे हैं कि लोग डिमांड भी करते हैं तो में अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन बायस लिया गया।)

श्री कृपा शंकर— ग्रध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ (३) के श्रन्त से दूसरी पंक्ति में शब्द "from time to time" कोष्ठक में रख लिया जावे तथा "for" व "period" के बीव "total" लिख कर रेखांकित कर दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष--म.ननीय स्वज्ञासन मंत्री इस पर ग्रभी विचार कर रहे है इसलिये यह ग्रभी पेंडिंग रक्खा जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय ग्रध्यक्ष महोवय, ग्राप की ग्राज्ञा से मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) के ग्रन्त का प्रतिबन्ध निकाल विया जाय ।

श्री अध्यक्ष-- 9h संशोधन आपका अवैध है। यों अवैध है कि आपने पंचायत का टर्म एक साल के लिये बढ़ाने का प्रक्त पहले पास कर दिया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—स्त्रपना विरोध प्रकट करने के लिये पेश करना चाहता था क्योंकि एक दफा पुले कोशिश को थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ।

श्री ग्रध्यक्ष--वह इस मर्तजा भी नहीं किया जा सकता।

श्री कृरा शंकर जो का संशोधन जो २७-ख पर है वह बालेन्दु शाह जी का जो संशोधन है उसी में वह भी ग्रा जायगा।

श्री कृपा शंकर — लेकिन तीसरा ऐसा है। जिस में कई शब्द छूट गये है, वह कहीं नहीं ग्राता।

श्री ग्रध्यक्ष-तो बाक्ती छोड़ कर तीसरा पढ़ दीजिये।

श्री कृपा शंकर— ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हू कि उपलंड (८) के रेलांकित शब्द "Where a" ग्रीर शब्द "prescribed under Sub-section" के बीच में शब्द "a Gaon-Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिया जावे।

श्री ग्रध्यक्ष— उपवारा द यह ग्राप बाद में पेश करें क्योंकि ग्रभी इससें पहले बहुत से संशोधन बाक़ी है। उपधारा (४) (७) (८) पर ग्राप का नाम उपा हुग्रा है ग्रीर वह ग्राप के ही नाम पर है तो उनको में बाद में ले लूगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मं श्राप की श्राज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपवारा (४) निम्न प्रकार से रखी जायः

"The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into single member constituencies."

इससे यह होगा कि जितने भी हम गांव पंचायत के मेम्बर बनायेगे मान लीजिये कि अगर १४ हजार की आवादी हुयी और उसमे ४० ग्राम पंचायत का बनाना हुआ तो सारी ग्राम सभायें ४० हिस्सों में बट जायंगी और वह सिंगिल मेम्बर कांस्टोट्यू एन्सी हो जायगी। ताकि उसमें एक इलाके से एक ग्रादमी चुनकर आ सके। यह हमारा इरादा है और में समझता हूं माननीय मंत्री जी इसकी स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—यह तो ठीक है कि कांस्टीट्यूएन्सी बनेगी लेकिन उसमें रिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी बनाना फायदेमन्द नहीं होगा ब कि उससे बड़ी दिक्कत पैदा होगी।

[श्री मोहनलाल गौतम]

ग्रगर ३०, ४० लाख मेम्बर हुये तो उनके लिये उतनी कांस्टीट्यूएन्सी बनाना काफी महिकल हो जायगा। कई बार देखने मे श्राया है जब कि डिल्ट्रिक्ट बोर्ड का कांस्टीट उएन्सी बनी तो करी कर लाइन । बचता नहा हा। इसालय कास्टाट्यूएन्सा बनाव यह तो ठीक है लेकिन सिगिल मेम्बर हों इससे ।दक्कत पैदा होगी। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि कठिनाई बढ़ेगी। इसलिये में समझता हूं कि ग्रगर मेम्बर साहब इसको वापस ले ले तो ग्रन्छा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमित से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री मलखान सिंह (जिला श्रलीगढ़) — - माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्राप की श्राज्ञा से यह संशोधन रखता हूं : खंड कि १३ में प्रस्ताबित धारा १२ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में शब्द "authority" श्रीर शब्द "into" के बोच में शब्द "in consultation with a representative of the Gaon Panchayat" रख दिये जायं।

मं समझता हूं कि इससे कठिनाई पैदा नहीं होगी बल्कि इससे सह्लियत बड़ेगी । श्रगर वह गांव पंचायत के प्रतिनिधि से बात करने पर इस काम को करेगा तो उससे सह्लियत होगी। मं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि श्रौर जगहों पर भी जब एलेक्शन होते हे तो यह सलाह ले ली जाती है श्रौर इस कन्वेन्शन को बढ़ा रहे हैं। हम कन्वेन्शन के तौर पर इसको करना चाहते हैं लेकिन यहां पर इसका रखना श्रच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि उनसे सलाह ली जाय मगर यहां पर रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे बजाय श्रासानी के प्रेस्काइ इ श्रयारिटी को कठिनाई पैदा हो जायगी। में इसको स्त्रिट में तो मान सकता हूं लेकिन इसका यहां पर रखना ठीक नहीं है।

श्री मलखान सिंह—ग्रगर इस ऐक्ट के ग्रन्दर कहीं पर वह भुझे दिखला दें तो में इसको वापस ले लूंगा। ग्रीर ग्रगर कहीं पर नहीं तो वह यह शब्द लिख दें तब भी मेरा काम चल सकता है।

श्री ग्रध्यक्ष — उनका मतलब यह है कि वह इसको रूल्स में ले ग्राना चाहते है यहां पर इस ऐक्ट में रखना नहीं चाहते है।

श्री मोहनलाल गौतम—मं यह चाहता हूं कि उनका बेसिस गांव पंचायत की सला हु हो जैसा कि लोकल बाडीज का है। लेकिन यहां इसके हाथ बांधने में में दिक्कत देख रहा हूं झौर जितना में कहता हूं उता में चाहता हूं कि पूरा हो जाय। इसलिये उनकी सलाह से कंस्टोट्यऐसीज शुरू में बो, ऐसा कनवेंशन डेवलप हो, यह में नहीं चाहता। रूल्स के बारे में सभी में नहीं कह सकता।

श्री मलखान सिंह—में बापस नहीं लेता। इस पर बोट चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित बारा १२ की उपधारा (५) की पंक्ति २ में शब्द "authority" ग्रीर शब्द "into" के बीच में शब्द "in consultation with a representative of the Gaon Panchayat" रख दिये जाये।

(प्रक्न उपस्थित किया गया और ग्रस्बीकृत हुन्ना।)

श्ची राज्यपाराध्य त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)—-ग्रध्यक्ष महोदय, मै श्रापकी श्राज्ञा से यह तंत्रोधन पेज्ञ करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ श्रीर ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जायः—

"the payment of fees and"

ब्रय्यक्ष नहोदय जिस उपधारा में यह संज्ञोधन चाहा गया है वह इस प्रकार है :

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such member as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit".

भ्रौर भेरे तंशोधन से वह इस प्रकार हो जायगी--

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the furnishing of security deposit"

यह भ्रापकी भी जानकारी है श्रौर सदन के सभी सदस्यों की जानकारी है कि लोकसभा, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया इत्यादि के जितने भी चुनाव है उनमें उम्मादवारों से केवल जमानत का इन्तजाम किया जाता है कि ख्वाहमख्वाह लोग न खंडे हो जा है जिन्हें जनमत प्राप्त नहीं हो । सीक्योरिटी तो एक सर्वमान्य चीज बन गई है ग्रौर केवल वही यहां रखनी चाहिये। फ़ीस का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। जानकारी है, प्रधानों के लिये पहले फास द रुपये से १२ रु० कर दिये गये है, उपप्रधानों के लिये ५ से = रुपये श्रीर मेम्बरों के लिये ४ से ५ रुपये कर दिये गये हैं। इस तरह से यह बड़ी धनराशि हमारी सरकार जमा कर लेती है, ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय देहातों में बहुत गरीब लोग खासकर हेरिजन ग्रौर पिछड़े लोग हैं जो यह रुपया नहीं दे सकते ग्रौर इस प्रकॉर वे ग्रपने गाँव की सेवा से वंचित रहेंगे। फ़ीस से तो केवल धनी लोग ही ग्रा सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धनियों से भ्रच्छी सेवा कर सकते है, उनसे भ्रधिक योग्य होते है लेकिन गरीब होते हैं, श्रौर वे बेचारे इस काम के लिये रुपया जमा नहीं कर सकते। इसलिये में समझता हं कि यह बहुत ही गलत व्यवस्था फ़ीस की की जा रही है। केंबल सीक्योरिटी होनी चाहिये। प्रक्छे लेकिन गरीब लोगों को महरून नहीं करना चाहिये। फ़ीस भी लगाने से ग्रच्छे व्यक्ति चुनाव में भाग न ले सकेंगे श्रीर इस सदन के कई विषयों पर बहस करते हुए क्वालिफिकेशन्स श्रीर ३० साल की उम्र के सवाल पर बड़े जोरदार शब्दों में राय जाहिर की गयी कि पिछड़ी हुई जातियों को इसमें ज्यादा हिस्सा लेने दिया जाय। इसलिये इसमें कोई प्रतिबन्ध ऐसा नहीं लगाना चाहिये कि जिससे उनके थ्राने में दिक्कत हो तथा लोगों को प्रैक्टीकली कठिनाई हो। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि चुनाव के लिये यह फीस की व्यवस्था निकाल दी जाय जैसा कि ग्रौर चुनावों में है।

अहाराज कुमार ब लेन्दु नाह — ग्रध्यक्ष महोदय, में श्री राम नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं। में समझ नहीं पाया कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्था किस कारण से की गयी है। जहां तक दूसरे चुनावों की बात है उनमें केवल डिपाजिट ही लिया जाता है चाहे वह शख्ध हार ही क्यों न जाय। लेकिन ग्रगर वह काफी संख्या में वोट ले ग्रातः है तो उसका डिपाजिट भी लौटा दिया जाता है। यहां डैमोक्रेसी है, उसके लिये इलेक्शन्स होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो इलेक्शन्स को समझ हैं ग्रौर न डैमोक्रेसी को। जो योग्य व्यक्ति हैं वे ही ठीक तरह से उसको समझ प ते हैं ग्रौर चुनाव में सफलता प्राप्त करते हैं। जो जो सज्जन चुनाव में सफल हो जाते हैं या काफी वोट पा जाते हैं उनको यह डिपाजिट वापिस हो जातः है। लेकिन इसमें जिस फीस की व्यवस्था की जा रही है वह ग्रगर एक दफा दे दी गयी तो फिर किसी सूरत में वापस न ग्रायेगी, में समझता हूं कि इससे लोगों का ग्रहित होगा। इसका एक दुष्परिणाम यह भी होगा कि ग्रच्छे लोग चुनाव में न ग्रा

[महाराजकुमार बालेन्द्र शाह]

पायेंगे। मेरे ख्याल में यह एक ऐसा हैडीकैप होगा जो चुनावों के लिये बुरा साबित होगा।
यह तो मानी हुई बात है कि गांवों में योग्य व्यक्तियों की कमी है। ग्रगर १-२ भी इस कारण से चुनाव में भाग न ले पाये तो यह एक बुरी बात होगी। इसमें कोई सिद्धांत का भी प्रकृत नहीं है दूसरे माननीय मंत्री जी शायद यह भी नहीं कहेंगे कि यह श्रामदनी का जरिया है। लेकिन ग्रगर यह ग्रामदनी का जरिया हो भी तो डैमोकेसी को चलाने के लिये सरकार को ऐसा खर्व स्वयं बरदाइत करना चाहिये। इससे जो थोड़ी सी रकम वसूल होगी उसका लालच करने की में समझता हूं न तो माननीय मंत्री जी की इच्छा है, श्रौर न उससे विशेष लाभ होगा। इसलिये में राम नारायण जी का समर्थन करता हूं श्रौर सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बीच के हिस्से को निकाल दे श्रौर केवल डिपाजिट को ही रहने दे।

्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय ग्रध्यक्ष भहोदय, मै त्रिपाठी जी क् मं गोत का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो फीस की रकम रक्खी गयी है उसने मे समझता है कि पंचायतों में उनके कारण सही भ्रादमी न चन पायेंगे। पहले का तजुर्बा यह है कि पहले जो ४-४-१० रुपया जो फीस रखी गयी थी उस फीस के कारण बहुत से ऐसे ग्रांदमी जिनको लोग चाहते थे, वे नहीं पहुंच पाये। वे ऐसे ग्रादमी थे जिनके पंचायतों में ग्राने के बाद गांव की समस्यायें श्रच्छी तरह से सुलझ सकतो थीं लेकिन वे लोग फीस के कारण नहीं श्रा पाये क्योंकि वे फीस इकट्ठी नहीं कर पाँये ग्रौर न दे पाये। जिनको पब्लिक नहीं चाहती थी वह पंचायतों में पंसा देकर पहुंच गये। श्रौर लोग जिनको भेजना चाहते थे उनके लिये पंसा भी इकट्ठा किया और उन हो चुने जाने के बाद पंचायत उन्हीं की बन गयी तथा जिन लोगों को जनता चाहती थी वे लोग नहीं भ्रा पाये। तो फीस रखने से बहुत बड़ी गड़बड़ी यह होगी कि जो श्रच्छे लोग गांव में रहते हैं वे फीस न देने की वजह से नहीं ग्रा पायेंगे। इसलिये यह फीस नहीं रखनी चाहिये। हां, यह बात में मान सकता हूं कि उनके लिये स्नाप कुछ जमानत रख दीजिये कि वे जमानत ग्रदा करें। अगर वे न जीतें तब तो उनकी जमानत जब्त कर लें और श्रगर जीत जायं तो उनकी जमानत वापस कर दें। लेकिन फीस लगाने से यह होगा कि जो ईमानदार श्रौर सही श्रादमी है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है श्रौर चाहते है कि हम ईमानदार। से अपने देश भ्रौर गांव की सेवा करें वे नहीं थ्रा पायेंगे। बिल्क जो लोग तीन पांच करने वाले हैं, और इधर-उधर करने वाले हैं वे चोहेंगे कि पंचायतों में उन्हीं की मेजारिटी हो जाय ताकि जिस तरह से पहले लोगों को अपने काबू में रखते थे उसी तरह से ग्रव भी लोगों को ग्रपने काबू में रख सकें। जब फीस रखने की बात आयेगी तो बहुत से सही लोग जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे, पंचायतों में नहीं भ्रा पायेंगे तो जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको भौका मिल जायगा कि वे अपने हेली-मेली के लिये भी पैसा दाखिल कर दें। फिर इस तरह से जितने लोग चुनकर मा ज रेंगे उनकी वजह से पंचायतों मे बड़ गड़बड़ी होगी स्रौर पंचायतों का काम श्रच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। जो मंशा माननीय मंत्री जी का है कि पंचायतें ग्रच्छी तरह से तरक्की कर सकें ग्रौर जो वे गांवों को स्वर्ग बनाना चाहते है वे स्वर्ग न बन कर नर्क बन जायेंगे। मं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फीस रखने की बात को हटा दें श्रीर जसा कि मैने कहा वही जमानत वाली चीज रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहर न्याल गीतस्—माननीय अध्यक्ष महोवय, मुझे अफसोस है कि में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि संशोधन में है कि फीस तो हटा वी जाय और डिपोजिट को रखा जाय। डिर्नेशिट रखने से कितनी विक्कत पैवा होगी यह जरा सो में की वात है। अगर २० लाख आदिमयों को चुनना है तो फिर २० लाख आदिमयों का डिपोजिट जमा होगा, और फिर यह इन्तजाम करना कि १/८ बोट न मिले तब जब्त होगा, और हर कोई का रिकार्ड रखना और तब फिर उसकी जमानत जब्त करना और बाकी का वापस इरना, इस संशोधन से जैसा कि जाहिर होता है जमानत रखने से बड़ी विक्कत पड़ेगी।

ग्रगर ग्राप जमानत को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। जैसा कि ४१-स में है
"एँड दि फीनीर्राग ग्राफ सेक्युरिटी डिपोजिट" ग्रगर श्री राम नारायण जी ग्रपना ग्रमेंड मेंट
ऐसा कर दें कि वे फीस के बजाय सेक्युरिटी डिपोजिट खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार
है। हमारा विचार है कि सेक्युरिटी रखने से काफी दिक्कत होगी ग्रौर इसके साथ यह भी
देखना है कि इसमें कितना खर्च पड़ेगा। फीस जो ली जाती है, इस एलेक्शन
का खर्चा लोकलबाडीज के जिम्मे भी थोड़ा पड़ता है। ग्रगर फीस न रखे ग्रौर जमानत
रखें तो में समझता हूं कि उससे दिक्कत पड़ेगी ग्रौर खर्च भी नहीं निकलेगा। इसलिये
मुझे ग्रफसोस है कि फीस हटाने की बात में इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

महाराजकुमार वालेन्दुशाह—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ग्रगर माननीय मंत्री जी दोनों को हटा दें तो क्या श्रापत्ति होगी?

श्री मोहनलाल गौतम—मं सेक्युरिटी डिगेजिट हटाने के हक में हूं लेकिन फीस हटाने के हक में नहीं हूं।

श्री गेंदा स्टिह-माननीय ब्रध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सेक्युरिटी लक्ज को हटाने की बात कही है। ऐसी उनकी इच्छा मालूम होती है कि वे इस चीज को मान लेगे लेकिन फीस न लगाने की बात को स्वीकार नहीं कर सकते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का प्रस्ताव है कि जो फीस का लफ्ज है उसे हटा दिया जाय। अगर फीस का लफ्ज हटा दिया गया तो गांव वालों को फीस का रूपया नहीं देना पड़ेगा . माननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो कहा है, में चाहता हूं कि माननीय स्वयासन मंत्री जी का ध्यान उधर जाना चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको पंचायतों से कुछ लाभ की कोई ग्राशा नहीं है, में निजः लाभ की बात नहीं कह रहा हूं, वैसे सामृहिक लाभ की ग्राशा तो हर व्यक्ति कर सकता है ग्रौर फिर एक बार तीन रुपया, पांच रुपया या दस रुपया निकाल कर पंचायत का ेम्बर बनने के लिये या ग्रदालती पंचायत का मेम्बर बनने के लिये वह देगा तो उसके ामने एक दिक्कत का सवाल खड़ा हो श्री रामसुभग वर्मा जी ने ग्र ने श्रनुभव की बात बतलायी कि इससे पंचायतों के काम में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। ग्रब रही बात यह कि चुनाव में जो खर्चा पड़ता है वह कहां से श्रावे । उस चुनाव के खर्च के लिये कुछ गुंजाइश की जाय इसकी चिन्ता है मै तो मंत्री जी से कहंगा कि यह पंचायतें बुनियाद हैं स्टेट श्रौर समाज के लिये। पंचायतें जितनी भी श्रधिक मजबूत हों उतना ही श्रच्छा है श्रौर यही सरकार की इच्छा होनी चाहिये। पैसे की कठिनाई भी लोगों के सामने रहती है श्रौर ३ रुपया श्रौर ५ रुपया न दे सकने वालों की तादाद भी गांवों में काफी रहती है श्रौर इसलिये उनको इससे बरी रहने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये। श्रतः निष्पक्ष लोगों को लाने के लिये यह जरूरी है कि हम फीस को हटावें। चुनाव के खर्च के लिये मे कहूंगा कि पंचायतों पर भ्रगर कुछ रुपया खर्च हो जाय तो उसके लिये सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये। हमारे संविधान में भी गुंजाइश की गई है कि शासन की इकाई गांव पंचायतें ही होंगी उत्पादन और लाएन्ड ग्रार्डर के लिये श्रीर सब चीजों के लिये हम को उन्हीं पर भरोसा श्रगर हमें यह करना है श्रौर प्रजातंत्र की रक्षा करना है तो हमें इस इकाई पर निर्भर रहना चाहिये थ्रौर जिस इकाई पर हमें सारे देश के प्रजातंत्र की दीवार खड़ी करन है उसे हमें सुवृढ़ बनाना चाहिये ग्रौर उसको जहां तक हो सके हमें ग्रधिक से ग्रधिक स्वतंत्र श्रौर दूसरे प्रभावों से बरी रखना चाहिये। श्रगर हमें इस काम में ५-१०-५० लाख या एक करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े, तो जिस पर हम ग्रपने राष्ट्र की बुनियाद बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की दीवार खड़ी करना चाहते हैं तो कर देना चाहिये। इस तरह से हम फीस ले कर उस रुपये की पूर्ति नहीं कर सकते।

श्रागे जो संशोधन श्राने वाले हैं उन में कहा गया है कि पंचायतों के लिये सरकार रुपये का बन्दोबस्त करे श्रौर श्रगर मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे तो उन को इस तरह की दिक्कत न होगी कि जमानत के रुपये से ही पंचायतों का चुनाव करावें। श्रगर मंत्री जी इस बात को

भी गेंदारिही

मान लेते हैं तो में समझता हूं कि झागे झाने वाले संशोधनों में हम को इस बात की गुंजाइश निकानने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और हम मजबूर होंगे कि हम पंचायतों को झात्मिनिर्भर बनाने के लिये किन्हीं दूसरे उपायों की शरण लें। में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं भी यह नहीं चाहते होंगे कि पंचायतों के मुताल्लिक ऐसी विकारों बनी रहें। इतना कहने के बाद में दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेने की कृपा करेंगे।

श्री रामदास ग्रार्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय ग्रध्यक्ष पहोदय, मैं माननीय पंत्री जी के उन विचारों की सराहना करता हूं जिन के श्रनुसार उन्होंने जमानत को समाज करने का ग्राद्या न दिया है। इससे हम बहुत सी दिक्कतों से बच सकते है। जो लोग रुपया इकटठा कर के सठिकल में जमा करने है उन को उस पर पर पर करने के स्व

रहेंगी। इस ब्राव्यासन को लिये में माननीय मंत्री जी को धन्य गढ़ देता हूं। हमारे सामने यह भी एक गम्भीर प्रक्त है कि यह फीस रखी जाय या नहीं। ब्राज हम अपने गांवों का निर्माण करना चाहते हैं और हम गांव की गरीबी की हालत भी जानते हैं कि वहां श्रिधकतर लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। रोजगार की भी परेशानी है तो में माननीय मंत्री जी से प्राथंना करूंगा कि जो उनका विचार है कि एलेक्शन में खर्च पड़ता है उसकी पूरा करने के लिये कुछ योड़ा सा लगा दिया जाय तो भ्रव्यल तो मेरा हृदय इसके लिये गवाही नहीं दे रहा है फिर भी हमारी प्रार्थना है कि जो उम्मीदवार सुरक्षित सीट से खड़े हों कम से कम उनके लिये कोई फीस न ली जाय और उनको ब्रानरेरी तरीके से सेवा करने का मौका दिया जाय। जो सुरक्षित सीट से खड़े होन वाल है वे यों भी समय नहीं दे पाते भ्रपने बाल बच्चों के पेट भरने के साधन में यों भी जुटे रहने के कारण, फिर वह फीस दे कर खड़े हों यह तो भ्रजीब सी बात है। उनको खड़े होना पड़ता है इसलिये कि सीट सुरक्षित है लेकिन उनसे फीस लगा देना ठीक नहीं है। इसलिये में नम्र निवेदन करता हूं कि उनसे जो कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट की सुरक्षित सीटों पर खड़े हों उनसे कोई फीस न ली जाय।

ंश्री मदनमोहन उपाध्याय—जो संशोधन माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। में भ्रपने पुराने तजुर्वे से कहता हूं कि इससे यदि फीस ली जाती है तो जो गांवों में सम्पत्ति वाले है उनका प्रभाव पूर्ण रूप से हो जायेगा या जैसा कि रामसुभग वर्मा जी ने कहा कि कुछ लोग उनके लिये रुपया जमा कर देगे श्रौर उनको ग्राम पंचायतों का मेम्बर बना देंगे श्रौर बाद में उन्हीं के हाथों से उनके ही श्रधिकारों का दुरुपयोग करायेंगे। माननीय मंत्री जी को स्वयं इतने सालों के तजुर्वे के बाद फीस की बात को हटा लेना चाहियेथा लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। प्रध्यक्ष महोदय, एक ग्रफवाह यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चुनाव चेयरमैन का होने वाला है वह गांव पंचायतों के मेम्बर के जरिये से होंगे। प्रबन्नगर फीस लेकर गांव पंचायतों के मेम्बर बनेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसके म्रतिरिक्त गरीब लोग यों ही प्राम पंचायतों में दिलचस्पी नहीं ले पाते ग्रौर जब यह फीस लेकर ग्राम पंचायतों के मेम्बर हो सकेंगे तो उनको भ्रौर भी दिलचस्पी लेने से महरूम कर दिया जायगा। प्राध्यक्ष महोदय, ग्रगर एक ग्रादमी रुपया जमा करना चाहता है ग्रौर उसके पास पैसा नहीं है तो वह किसी से पैसा लेकर जमा करेगा। ग्रौर इसका ग्रसर सबसे ज्यादा हरिजनों पर पड़ेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स फडेरोशन श्रौर दूसरे लोग रुपया जमा करके ऐसी सीटों पर खड़े हो सकते हैं जो देश के हित के लिये ठीक नहीं होगा श्रीर जो काम करने वाले हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके म्रतिरिक्त डिमोक्रेसी के ग्रौर बड़े बड़े भाग है उनमें पैसा नहीं जमा करना पड़ता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्युनिसिपल बोर्ड के, असेम्बली के, पालियामेंट के किसी के चुनाव में पैसा नहीं देना पड़ता फिर इस छोटी सी

[🕇] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिमोक्रेसी की जगह पर जहां लोग गांवों की सिवस करना चाहते है यह क्यों किया जाता है कि वह पैसा दें तब सिवस करें। में समझता हूं कि यह उचित नहीं है और माननीय मंत्री जी को माननीय राम नारायण जी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष—(श्री मोहनलाल गौतम से) ग्रब ग्राग ग्रपना भाषण बाद में जारी रखें। में यह पूछता हूं कि वह संशोधन ग्रापने क्या तैयार कर लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम—हां, तैयार है श्रभी में श्रापके श्राफिस में भेज देता हूं। श्री श्रध्यक्ष—तो वह बाद में श्राजायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुन्ना ग्रीर २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की ग्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः ग्रारम्भ हुई।)

*श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—न्त्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मे प्रस्तुत् संशोधन की मुखालिकत करने के लिये खड़ा हुप्रा हूं। इससे पहले बोलने वाले कुछ मेरे लायक दोस्तों ने उसूल की बात कहा। यह उसूल यह था कि गांव के गरोब लोगों को गाँव पंचायतों के चुनाव में खड़े होने के रास्ते में कोई माली वाधायें कानून द्वार। न डाली जायं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरांव तानके के लोग खड़े हो सकें ग्रीर चुनें जा सकें जिससे उनको इज्जत भिले। यह बिल्कुल दुबस्त बात है स्रोर इसमें दो रायें नहीं हो सफतों। लेकिन मुझे श्रकसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो संशोधन इस वक्त सदन के लामने प्रस्तुत है उसमें कहा गया है कि गाँव पंचायती श्रार न्याय पंचायती के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हों उनसे फीस न लो जाय। लेकिन सेक्योरिटा डिपाजिट ला जाय। श्रव उक्त उसुल के मातहत इस प्रश्न पर विचार करने के लिये दो कसीटियाँ बन जाती हैं। एक तो यह कि कौन सी चोज, फीस और सेक्योरिटी डिपाजिट इन दोनों में से बड़ी श्रप्तुविधा वाली है श्रीर दूसरे कौन सी ग़ैर जरूरी मालूम होती है। मोटे तरीक़े से हम जानते हैं कि फोस की रकम हमेता सेक्योरिटी डिपोजिट की रक्रम से छोटी होता है इसलिये यह स्वयं-सिद्ध हो जाता है कि सेक्योरिटी डिपाजिट की रक्रम मुहइया करने में अधिक असुदिधा होगी। दूसरी बात यह है कि फीस जमा करने के बाद उसकी वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिये वह असुविधा जो वापस करने में गाँव वालों को होगी भ्रगर फोस ली जाय तो नहीं होगी। गाँव वालों को कम फुर्सत, कम जानकारी स्रीर कम टाइम होने की वजह से सेक्योरिटी डिपाजिट वापस करने में बड़ी मुक्किल होगी। इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गाँव वालों को सेक्योरिटी डिपाजिट की वजह से बड़ी ग्रस्विधा होगी।

दूसरी कसीटी जो मैंने इस सवाल को तय करने में लगाई यी वह यह कि कीन सी गैरज़रूरी है। हर चुनाव में रुपया खर्च होता है। इस चुनाव में भी सरकार को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। कुछ लायक दोस्तों ने कहा था कि म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वग्रैरह के जो चुनाव होते हैं उनमें फीस नहीं है। लेकिन वह भूल गये कि उनके लिये सरकार बजट में चुनाव कराने के लिये प्राविजन करती है। ग्रब हमारे सामने यह सवाल है कि या तो इन पंचायतों के चुनाव के लिये बजट में प्राविजन किया जाय या यह कि जो लोग खड़े हों चुनाव में वह थोड़ी सी रकम दे दें जिससे चुनाव हो जाय। पब्लिक स्प्रिटंड जो होंगे वे थोड़ी सी फोस भी दे दें तो अनुचित नहीं होगा। इसलिये में समझता हूं कि यह संशोधन इस प्रकार से मान लिया जाय कि सेक्योरिटी डियोडिट न ली जाय ग्रीर फीस ली जाय।

श्री मोहन लाल गौतम-- ग्रापने ग्रपना ग्रवेंडमेंट नूव कर दिया।

^{*} वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरो-गढ़ वाल)—माननोय उपाध्यक्ष महोद्य, गाँव पंचायतों के उम्मोदवारों से फांस का लिया जाता और डिपोजिट का तिया जाता यही सदन के सामने विचार के लिये हैं, सभी माननोय सदस्य ने तर्क दिया कि डिपोजिट क्यादा होगो इसलिये डिपोजिट क्रिस कर दी जाय श्रीर फांस बहुत थोड़ी होगें। इसलिये उसे रख दिया जाय श्रीर माननीय मंत्रें। का भी यही विश्वास हैं। जहाँ तक इस तर्क को में देखता हूं, यह कोई तर्क नहीं हैं, डिपोजिट माननीय मंत्रें। इसलिये छोड़ने को तैयार हैं। क्योंकि उसमें उनको कुछ दिक्कत हैं। शासकीय दृष्टि से डिपोजिट जमा करने श्रीर उनको वापस करने श्रीर उनका एकाउष्ट रखने में किठनाई हैं; उनका यह प्रस्ताव ठीक हो हैं। लेकिन यह कहना कि डिपाजिट स्रिक होता है श्रीर फोस कम होती है। इसलिये फोस रखी जाय श्रीर डिपोजिट ब्रिस कर दी जाय, उचित नहीं हैं। देखना यह है कि किसका भार सदस्यों पर क्या पड़ता है। डिपाजिट श्रीक होती है लेकिन वापस मिल जाती है। किसो भी सदस्य को कोई श्रापत्ति नहीं होती। श्रगर कोई माननीय सदस्य ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का सदस्य डिपाजिट जमा करता है तो इस उम्मीद पर कि उसको वापस मिल जायगी। लेकिन जहाँ तक फीस का प्रश्न है वह तो वापस नहीं मिलेगी। इसलिये चाहे वह मद में छोटी हो लेकिन भार उसका श्रीक पड़ेगा।

इसलिये में यह समझता हूं हमें प्रगर पंचायत राज को कामयाब करना है, पंचायत राज को चलाना है और लीगों को पंचायत तथा न्याय की सुविधायें देनी है श्रीर पंचायतों में योग्य व्यक्ति श्रायें तो हमें कोई हैण्डोकेप नहीं रखना चाहिये जिससे योग्य व्यक्ति पंचायत में न श्रा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्राम पंचायतीं का चुनाव होगा उसी प्रकार न्याय पंचायत के सदस्यों का भी होगा। प्रेल्काइब्ड श्रथारिटी चाहे मंत्री जी उसका कुछ नाम रखें इन्हों में से न्याय पंचीं की चुनेंगे। तो जहीं तक में समझता हूं कि श्रापने नाम तो न्याय पंचायत रखा लेकिन इसमें एक श्रड्यन यह पड़ जायगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गांव पंचायत के चुनाव से त्याय पंचायत के लिये खड़ें नहीं होंगे। इसके कारण हैं। एक कारण यह है कि चुनाव जी होगा, जो व्यक्ति न्थाय पंचायत के लिये खड़ा होगा उसको प्रथम तो निर्वाचन में सकल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि अगर सकल हो जायगा तो गारन्टी नहीं है कि प्रेस्काइब्ड अयारिटी उन्हीं व्यक्तियों को जिनको कि ग्राम सभा न्याय पंचायत का सदस्य बनाना चाहती है उनकी न्याय पंचायत का सदस्य चुने। तो इस तरह से जो न्याय पंचायत में आना चाहता हो वह कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसकी डबल ट्राइल पास करना पड़ेगा। श्रीर अगर फीस रखते हैती उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति जी समय दे सकते हैं तथा मेहनत कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, भ्रापकी प्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत कहिये, उसमें नहीं थ्रा सकते हैं थ्रौर श्रापकी पंचायत जो होगी वह श्रच्छी नहीं होगी। इसलिये में चाहता हूं कि प्रगर हम चाहते हैं कि पंचायतों में प्रच्छे-प्रच्छे व्यक्ति ब्रायें मीर इस पैसे वाला प्रतिबन्ध की न रख करके सब को खुली सुविवायें प्रदान कर दाजिए ताकि अच्छे व्यक्ति जो आना चाहें उनको दिक्कत महसूस न हो। जैसा कि मेरे माननोय मित्र कहते हैं कि पैसा रखने से यह ग्रहचने पैदा हो जायंगी:। जैसा माननीय रामसुभग वर्मी ने कहा था फीस रखने से यह श्रद्भन पैवा है। जायगी कि बहुत से व्यक्ति जो योग्य हैं वे पैसों के कारण नहीं आ सकते हैं और उनके एवज में ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, जो पंचायत में श्रपना बहुमत चाहते हैं वे डिपाखिट देकर, फीस देकर न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में ग्रंपना बहुमत प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण भ्रापका पंचायत राज कभी सकल नहीं हो सकता है। इसलिये इसमें खर्चे का लिहाज न करके फीस की व्यवस्था की तुरन्त खत्म कर दिया जाय।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने हैं में समझता हूं कि जहाँ तक कीस का मनता है श्रगर हमजो लोग चुनावों में भाग लेंगे उनसे नहीं लेते है तो इसके माने यह हो जाते है कि हमारो प्रदेशीय सरकार का करोड़ो रुपया जो चुनाव ने लर्च होता है ग्रीर जिसे दूसरे उन्नति के कार्य में लगाया जा सकता है उसका पूर्ति नहीं हो सकता। यह कहना कि गांव में रुपये, दो रुपये या ऐसी कोई छोटो रकम कोई दे नहीं सकता है तो मेरा समझ मे ऐसी परिस्थिति किसी गाँव की नहीं है जिसमे इतनी छोटी रक्रम लोगन दे सकते हों। हम लोकल बाडीज के चुनावों की यदि देखे तो हमारी यह प्रया चली प्राया है कि उसमे चुनाव का जितना खर्च होता है उसके लिये वे खुद प्रबन्ध करती है। अगर हमारी गाँव सभायें खर्च का प्रबन्ध नहीं कर सकतीं, तो मेरी समझ मे श्रीर कोई भा तरीका नहीं निकल सकता कि जिससे हम इस खर्चे की पूर्ति कर सके। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि कोई न कोई फीस हम मुक़र्र करें जिसको जो लोग गाँव सभाग्रों के चुनाव में खड़े होना चाहते है आसानी से दे संके। जो न्याय पंचायत की बात श्रभी हमारें माननीय सदस्य ने कही, उसकी तो इसमें कोई चर्चा भी नहीं है कि न्याय पंचायत के लिये जो लोग चुने जायंगे उनसे भी फीस ला जायगा। इसमे तो जो गाँव पंचायत के लिये चुने जायंगे उन्हीं के लिये है। इसलिये न्याय पंचायत की बात इसमे शामिल करना उचित नहीं है। मैतो यही उचित समझता हूं कि फीस कुछ न कुछ जरूर लो जाय। सिक्योरिटी डिपाजिट की रक्तम जरूर कुछ न कुछ अधिक होता है अ। र अगर सिक्योरिटी डिपाजिट उनसे माँगी गई तब तो जरूर कुछ अड़चन आ जाती है। इसलिये तिरयोरिश डिपा-जिट तो नहीं रखनी चाहिये लेकिन फोस जरूर लेना चाहिये ग्रीर में समझता हं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि श्रव प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि भ्रब प्रश्न उपस्थित किया गया। (प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रीर स्वीवृत हुन्ना।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल के कई माननीय सदस्यों ने मेरे इस संशोधन पर भाषण किया, लेकिन उन्होंने यह वात जताने की कोशिश की कि में सिक्योरिटी डिपाजिट को रखना चाहता हूं ग्रीर कीस को हटा देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी डिपाजिट ग्रीर कीस दोनों सरकार रखना चाहती है। मेरा संशोधन तो केवल इतना था कि में कीस को निकाल देना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि वह सिक्योरिटी हटा सकते है, ग्रगर वह इसको हटा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को दिक्कत हो ग्रीर कानूनी परेशानी हो।

खासतौर से सरकारी दल की तरफ से जो दलीलें दी गयीं उसमे यह बतलाया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव में काफी रुपया लगता है, यदि फीस नहीं लीत जायगी तो यह रुपया कहां से आयगा। वैसे तो रुपया हर चीज में खर्च होता है। मिनिस्टरों की जगह के लिये रुपया लगता है, हम लोगों के चुनाव में रुपया लगता है। अगर रुपया लगता है तो फिर चुनाव ही न किये जायं और सब काम ही खत्म हो जायं लेकिन यह जरूर है कि यह विचार करने की बात है कि कितना रुपया लगता है।

यदि हम यह मान लें कि हमारे सूबे में २४ हजार गांव सभायें है ग्रौर उनमें ३० से लेकर ५१ तक पंचायत हैं। में इसलिये ग्रौसतन प्रति गांव पंचायत ४० मान लेता [श्री रामनारायण त्रिपाठो]

हूं। ग्रगर एक रुपया फीस लेली जाय तो १४ लाख रुपया होता है ग्रौर फीस १२ से लेकर ५ रुपये रखी जा रही है। में इसको ग्रौसत कि लिये लेता हूं। इस तरह से ग्रगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक करोड़ १२ लाख रुपया सरकार वसूल करती है ग्रौर में इतना तो वावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुपया किसी भी चुनाव में खर्च नहीं हुग्रा। सरकार इसको रुपया कमाने का साधन बनाना चाहती है। एक करोड़ १२ लाख रुपये वसूल किये जायं ग्रौर मेंने पिछले बजट में देखा कि करीब ६५ लाख रुपये वसूल किये जायं ग्रौर सेक्रेटरीज का वेतन भी है। में कमझता हूं कि इतना रुग्या बचाया जाता है ग्रौर सरकार मुफ्त में वाह ाही ले लेती हैं कि सरकार सेक्रेटरीज को तनख्वाह दे रही है ग्रौर यह रहस्य जनता की निगाह में नहीं ग्राता है कि यह फीस भी लीजा रही है। में वावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुग्या नहीं लग सकता है। सरकार जरूर ग्रामदनी करती है।

मब रह गया पिछले चुनाव के बारे में बतलाया गया है। उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में किसी भी कानूनगो को भत्ता नहीं मिलों क्योंकि उनको ग्रपने हल्के में मिलता नहीं है। कहीं-कहीं नायब तहसीलदार गये। उनको भत्ता मिला होगा। ग्रगर माननीय मंत्री जी उनके ग्रांकड़े पेश करेंगे तो में समझता हूं कि वह रकम एक नगण्य रकम होगी। मेरे सामने मध्य भारत, बंगाल ग्रौर पंजाब वगरा के ऐक्ट्स मौजूद है। वहां कहीं भी इस तरह से फीस नहीं ली जाती है। बारों सुन्नों में कहीं भी इस बात का प्रावीजन नहीं है। हमारे यां यह नई व वस्था की जा रही है। में समझता हूं कि इसमें दलील की कोई बात नहीं है बिल्क वास्तविकता तो यह है कि में गरीब ग्रादिमयों को पंचायतों में लाना चाहता हूं। ग्राज एक समस्या हमारे सामने है कि ग्रच्छे लोग पंचायतों में नहीं ग्राते हैं ग्रीर यही कारण है कि गांव पंचायतें निविक्रय सी रहती हैं। ग्रगर कुछ कार्यशीलता दिखाई पड़ती है तो न्याय पंचायतों में। गांव पंचायतों में लोग सेवा कार्य से वैसे ही दूर रहना चाहते हैं ग्रौर इस पर भी ग्राप फीस की शक्त में यह जुर्माना रखना चाहते हैं। तो वह फिर इसके नजदीक भी नहीं ग्रावें। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी पंचायतों का कार्य सुचाह रूप से नहीं हो पायगा, जो श्रनुचित है। इन शब्दों के साथ, में समझता हूं कि यह तो है ही कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन में ग्रावरणीय सदन से ग्रील करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कुपा करे।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी को जो आंकड़े उनके किसी मित्र ने दिये हैं उसमें अर्थमेटिक की गतिती हो गई है। उनका कहना है कि जितनी रकम आती है उससे हम उसको थोड़ा सा घटा कर पंचायतों के कामों पर सरकार खर्च कर देती है और सरकार वैसे ही वाहवाही ले लेती है। उनको यह पता नहीं है कि यह रकम चार पांच साल बाद एक मर्तबा ही आती है और पंचायतों को ऊपर तो हर साल रकम खर्च होती है। इसलिये यदि माननीय त्रिपाठी जी के आंकड़ों को ही मान जें तब भी यह रकम कई गुना बढ़ जाती है और फिर ऐसी सूरत में वाहवाही की बात ठीक ही होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुछ चीजें तो अवश्य ऐसी रखी जानी चाहियें जिससे बेकार के लोग खड़े न हों। जो सीरिअस नहीं हैं, जो चाहते नहीं हैं, इस तरह की एक चीज कई तरफ से कही गई। अब अगर यह बात है तो इसमें देखना यह होगा कि कौन सी चीज सुविधाजनक है—कीस या सेक्योरिटी। इस संशोधन के पेश करने वालें माननीय सदस्य ने भी सेक्योरिटी को रखा है और सेक्योरिटी को खत्म करने का कोई

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन नहीं दिया। दूसरे लोगों ने सेक्योरिटी के बजाय फीस को रखा है। तो आम तौर से अगर इस सब का निचोड़ रखा जाय तो कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेक्योरिटी रखी जाय और कोई चाहते हैं कि फीस रखी जाय। अब दोनों में से कौन आसान है यह देखना है। इस बात को रोकने के लिए कि गलत लोग न आयें एक प्रकार की सेक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जैसा मेने पहले निवेदन किया २०, २५ लाख आदिमियों का चुनाव होगा। २०, २५ लाख आदिमियों की सेक्योरिटी जमा करना गांव-गांव में और फिर उसका हिसाब रखना, जिसकी सेक्योरिटी जब्त हो जाय उसकी जब्त करके बाकी को वापस करना, यह सब एक बहुत किन चीज हो जायगी और एक बहुत लम्बा चौड़ा हिसाब किताब हो जायगा। अब इसमें यह है कि फीस रख दी जाय, एक एक या दो दो रुपये का फार्म है, लेकर और दस्तखत करके नामिनेशन पेपर फाइल कर दिया जाय तो इसमें वह फीस जमा हो जायगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है।

तो सदन यह देखेगा कि कोई न कोई चीज रखने की तो जरूरत है श्रौर में समझता हं कि इसमें सुविधाजनक फीस मालूम होती है। दिक्कत यह बतलाई गई कि गरीब श्रादमी नहीं श्रायेंगे। कुछ गरीब श्रगर ऐसे भी हैं, जो कि र साल में एक या दो रुपया पंचायत की मेम्बरी के लिए नहीं खर्च कर सकते यह मै मान भी लूं। लेकिन, एक बात की तरफ में तवज्जह दिलाऊंगा कि सिर्फ तीन-चार रुपये खर्च करके कोई ईमानदार आदमी अगर इसलिये नहीं आयेगा कि उसे वहां कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तो में समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जायगा, पालियामेंट ग्रौर भ्रसेम्बली के लिए किसी का ग्राना क्योंकि जो २०० रुपये एलाउंस के मिलते हैं, श्रगर ५ साल के लिए भी उनको जोड़ा जाय तो भी वह इतना नहीं होगा, जितना कि एक मर्तबा एलेक्शन में खर्च हो जाता है। उसमें पार्टियां भी देती हैं और इंडिविज्यल भी खर्च करते हैं, लेकिन जो खड़ा होता है वह केवल यह नहीं देखता कि १० हजार खर्च करके १२ हजार पावेगा या नहीं। तो हर एक मेम्बर जो खड़ा होता है और जिसको पूरा खर्च जितना वह करता है नहीं मिलता है वह बेईमान ही हो, यह ठीक नहीं है। इस सदन के बहुत से सदस्य हैं जिनको उनको पूरा खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी में समझता हूं गेंदा सिंह जी यह नहीं कहेंगे कि वह किसी दूसरे मकसद से आये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हुं कि दो चार रुपये खर्च है श्रौर ५ साल को बात है। इतना देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय रामनारायण जी वापस लेलें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ३ ग्रीर ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय— "The payment of fees and"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुन्ना।)

श्री शिवराज सिंह यादव—में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ४ के शब्द "and the furnishing of security deposite" निकाल दिये जायं।

्रिपछले संशोधन पर विचार करते समय माननीय मंत्री महोदय श्रौर सदस्यगण इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये इस पर वुबारा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। में समझता हूं कि इस क्लाज को निकाल देना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपवात (6) की पंक्ति ४ में शब्द "and the furnishing of security deposit" निकास विये जायं।

(प्रक्त उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राह्म से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ की उपधारा (७) की दूसरी व चौथी पंक्ति में "Gaon Panchayat" शब्दों के बाद "and Nyaya Panchayat" जोड़ दिये जायं तथा श्राटवीं पंक्ति के शब्द "and from" के बाद "the twenty 6th day of January, 1960" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जाय।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत राज के जो चुनाव हुये थे गांव सभाग्रों ग्रीर पंचायती ग्रदालतों दोनों के चुनाव जनता द्वारा हुये थे। लेकिन श्रव की इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जो न्याय श्रदालतें होंगी उनमें प्रेस्त्राइ॰ड ग्रथारिटी के द्वारा चुनाव होना है। श्रगर इसमें इस तरह का प्राविजन नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई भी हिरजन पहुंच सकेगा। यह मानी हुई बात है कि इस संबंध में पूज्य बापू ने समानता देने के लिये बहुत से प्रयत्न किये ग्रौर यदि न्याय पंचायतों मे ग्रौर इस तरह के स्थानों में उनको समानता नहीं दी जाती तो वह जो समानता की भावना है उसका कोई ग्रथं नहीं निकलता।

दूसरे जहां तक रिजर्वेशन होने या न होने की बात है वहां कांस्टीट्यूशन श्राफ इंडिया में श्रीर सेक्शन २८, श्राई० पी० सी० में भी दिया हुश्रा है कि किसी भी श्राफिस में रिजरवेशन हो सकता है। श्रीर पंचायत श्रदालतों में जो होंगे वह गवर्नमेंट सर्वेट कहलाये जायेंगे। श्रीर गवर्नमेंट सरविस के किसी भी श्राफिस में रिजरवेशन हो सकता है इस सिलसिले में पंचायती श्रदालतों में रिजरवेशन होना श्रावश्यक है। श्रगर प्रेस्त्राइ इ श्रथारिटी न होती तो जिस तरह से पिछले चुनावों में बहुत काफी लोग पहुंच गये थे इसी तरह से इसमें भी उम्मीद थी। इसलिये श्रगर इसमें यह प्राविजन रखा जाय तो श्रच्छा होगा।

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि १६६० में जो रिजरवेशन समाध्त कर देने की बात है उसमें जैसा कि संविधान में दिया हुआ है उसके मुताबिक रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वह अगर पहले समाप्त हो तो इसे भी पहले समाप्त कर दिया जाय और अगर वह बाद में समाप्त हो तो इसे भी बाद में समाप्त किया जाय। उसमें और इसमें फर्क नहीं मालूम होता है कि जब कि उसमें इस तरह का प्राविजन दिया हुआ है। तो मेरी राय में असके लिये तारीख नियत कर देना अच्छा नहीं मालूम होता है।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रभी जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है में समझता हूं कि यह बहुत ही श्रनुचित चीज होगी कि हम न्याय पंचायत में भी जाति-पांति की बात लाकर रखें। न्याय पंचायतों में यह बात पैदा करना कि एक श्रष्ट्रत प्रतिनिधि हो। दूसरे श्रीर जातियों के हों यह चीज बहुत ही हानिकारक, न्याय के लिये होगी। जहां पर हम को मुकदमों को फैसल करना है, जहां पर हमको हर एक चीज पर निस्पक्ष भाव से गौर करना है वहां पर कोई श्रष्ट्रत जाति का प्रतिनिधि हो, यह बहुत ही गैरमुनासिब श्रौर श्रनुचित होगा। में समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है। यह एक किस्म का जहर फैलाना होगा श्रौर इस चीज को न्याय पंचायत में कभी भी गवारा नहीं करना चाहिये, तो इस लिहाज से में यह समझता हूं कि इस संशोधन के इस श्रंग का कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई श्रादमी रक्सा जाय, में विरोध करता हूं।

दूसरी चीज स्राती है कि स्राया जो तारील हमने इसमें रक्ली है वह इसमें रक्ली जाय या न रक्ली जाय। में समझता हूं कि हमारा पंचायत राज ऐक्ट इस सूबे में जारी है। शेड्यूल्ड-कास्ट के लोगों को हम जो मौका दे रहे हैं गांव पंचायतों में वह चीज तो चल ही रही है स्रौर

जान चाहिय ग्रार इस का। बल हा जाना चाहित न जरना ग्रनुचित होगा। जो तारील में उसको मुजबजब रखना श्रीर कोई तारील निश्चित न करना ग्रनुचित होगा। जो तारील रक्ली गई है बहुत हो मुनासिब है। उस तारील तक वे श्रपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जायेंगे ग्रीर उनको इस बात की जरूरत न पड़ेगी कि उनको रिजर्वेशन दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

ंश्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, में मुरलीधर कुरील जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं। वैसे जो बात हमारे कुंवर कुष्ण वर्मा जी ने कही कि यह प्रच्छा नहीं जंचता कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजवेंशन हो, वास्तव में में भी इसका कायल हूं कि इस तरह की चीज पैदा करना उचित नहीं है। लेकिन ग्रगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो वह भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजवेंशन न होना वास्तव में बहुत ग्रन्याय होगा। ग्राप देखेंगे कि जहां रिजवेंशन का सवाल न हो वहां हजार केसेज में ग्रगर प्रतिनिधित्व का सवाल ग्राता है तो एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां हरिजनों को प्रतिनिधित्व मिला हो या उसकी ग्रोर विशेष ध्यान जाता हो। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी जब गवर्नमेंट द्वारा पंचायत राज ग्रमेंडमेंट ऐक्ट कमेटी बनी थी, तो उसमें हरिजनों का एक भी सदस्य नहीं था। तो समझ में नहीं ग्राता कि जब विधान सभा ग्रौर गवर्नमेंट में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की ग्रोर ध्यान नहीं दिया जाता तो हरिजनों का यह कोशिश करना कि रिजवेंशन वाली धारा हर जगह लागू हो जाय, में समझता हूं कि यह प्रनुचित नहीं है ग्रौर ग्रगर सरकार या हमारे ग्रन्य साथी यह चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न इस हाउस में न लाया जाय तो मेरी राय में वे इस बात की कोशिश करें कि जहां कायदे से हरिजनों का एक प्रतिनिधि होता हो वहां दो कर दें ग्रौर फिर देखें कि इस पर भी हरिजन मांग जारी रखते हैं या नहीं।

भ्रभी हाल ही में, उपाध्यक्ष महोदय भ्रापने देखा होगा कि कौंसिल के इलेक्शन में द भ्रादमी चुने गये भ्रौर कायदे से एक से ज्यादा हरिजनों के रिप्रेजेंटेटिक्स होने चाहिये थे लेकिन एक भी नहीं हुआ। भ्रगर हम हरिजन एम० एल० एज० भ्रपने ही वोट्स से चुनते तो में समझता हूं कि कम से कम एक भ्रादमी भ्रवश्य चुन सकते थे। तो इस प्रकार भ्राये दिन ये बातें हुआ करती हैं कि जहां पर रिजवेंशन वाली बात भ्रायद नहीं होती वहां हरिजनों को कम्प्लीटली इगनोर कर दिया जाता है। इसी तरह से सर्विसेज में भी माननीय सदस्यों को नागवार मालूम होता है कि जब देखो हरिजनों के बारे में ही प्रश्न हुआ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ एक मतलब है और वह यह है कि हम हाउस के सामने सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि जो नीति १८ फीसदी की है वह वास्तव में दिखावटी है और इसके अन्दर कोई सार नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग प्रश्नों के उत्तर में यह न सुनते कि ३०० चपरासियों में सिर्फ १४ चपरासी रखे गये जब कि उनको ५४ रखना चाहिये था। तो यह प्रश्न एक बड़ा गहरा प्रश्न है जब आप चपरासी जैसी जगह के लिये पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं दे सकते हैं जहां पर योग्यता और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर बड़ी जगह के लिये हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जायगा। इसलिये में यह समझता हूं कि जब तक संविधान में हरिजनों के लिये रिप्रजेन्टेशन का प्रश्न है और जिस प्रकार की चीजें हरिजनों के लिये रखी गयी है उनकी जनसंख्या के अनुपात से तो उसी आधार पर न्याय पंचायत में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

[†]वस्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री जोरावर वर्मा]

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है कि इसको ६० तक रखा जाय और तब उसके बाद यह खत्म हो जायगा, तो इस प्राविजन के रखने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन तो ग्रपने ग्राप हो इस ऐक्ट में हो जाता है। मान लीजिये कि ऐक्ट में खत्म नहीं होता है जो ग्रभी म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट पास हुग्रा है उसमें भी इस प्रकार का प्राविजन नहीं है कि ६० तक या १० साल तक हरिजनों का प्रतिनिधि रखा जाय। वह तो उस संविधान के ग्रमुसार जैसा भी होगा चलेगा या नहीं चलेगा। उसके ग्रमुसार ही होगा। इसलिये में ग्रपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह ग्रपने हृदय पर हाथ रखकर ईमानवारी से सोचें कि ग्राज हरिजन जो यह ग्रपनी बात रोजाना कहते हैं वह क्यों कहते है। ग्रभी रामनारायण त्रिपाठी जो ने फीस के लिये संशोधन रखा था। उसको हम भी रख सकते थे लेकिन ग्रगर इस बात को कोई दूसरा ही रख दे जिसको हम चाहते हों तो फिर हमको उस पर जोर देने की ग्रावश्यकता नहीं है। इसलिये ग्रगर जो उस बात को, जो हमारी हो, ग्राप ही कर दिया करें तो फिर हमारे लिये कहने मुनने की कोई ग्रावश्यकता नहीं रह जाती है ग्रीर हाउस का समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिये में इस संशोधन का समर्थन करता हूं ग्रीर ग्राशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—में तो ग्रसल में इसका विरोधी हूं कि यह १६६० क्यों रखा गया है। जब एक जगह ग्राप रख रहे हैं फिर उसको क्यों बैन करते है ? हमारा संविधान जो है वह हमारे लिये मान्य है ग्रौर उसके लायल हैं। इसलिये हम यह समझते हैं कि वह उचित नहीं है। यह जो संशोधन ग्राया है इसको में मानने के लिये तैयार हूं लेकिन ग्राप बीच में इस तरह की बात क्यों रख देते हैं कि यह रिजर्वेशन ६० तक ही रखो जाय ? इसके ग्रन्थर रिजर्वेशन रखा गया है जो कि इंडियन संविधान के मुताबिक है तो फिर बीच में ग्राप यह दूसरी बात कैसे ले ग्राते हैं कि इसको फलां समय तक रखा जाय ग्रौर इसको बैन कर देते हैं ? ग्राज भी मैंने देखा कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा कि १४ वपरासी रखे गये जब कि ज्यादा होने चाहिये थे। तो चपरासी के लिये किस योग्यता की ग्रावश्यकता है जिसकी वजह से ग्राप यह पूरी जगह नहीं देना चाहते हैं ? इसलिये में यह निवेदन कहंगा कि यह डेमोकेसी सफलीभूत नहीं हो सकती है ग्रगर हम ग्रपने संविधान के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। जो ग्रौर बात संशोधन में कही गई है वह बड़ी सुन्दर है ग्रौर माननीय मंत्री महोदय को उसको मान लेना चाहिये क्योंकि यह संशोधन बहुत सुन्दर है।

*श्री हिर्सिह (जिला मेरठ) — ग्राज जो इस पंचायत राज के विषेयक में संशोधन हो रहे हैं और उसमें जो यह रिजर्वेशन के लिये संशोधन हुआ है तो फिर मेरी समझ में नहीं श्राता कि जब एक ऐसा संविधान हमारे देश में मौजूद है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन जब तक वह उचित समझेंगे रहेगा तो फिर मेरी समझ में एक बात नहीं श्रायी कि इस संशोधन में यह कहां से ग्रा गया कि सन् १९६० तक यह रहेगा। यह चीज कहां से ग्रपनायी गयी, किस तरी के संग्रपनायी गयी? यह देखकर कहना पड़ता है कि किसी भी ऐक्ट में ऐसा नहीं ग्राया कि उस सीमा तक रहेगा सिवाय विधान के जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ है। में ग्रापके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ऐक्ट में मीयाद को निकाल दें क्योंकि जब तक यह समस्या है उस समय तक रिजर्वेशन रहेगा। जब तक हमारी ग्रापिक स्थिति गिरी हुई है, हमारी उन्नति न हो जाय तब तक रिजर्वेशन होना चाहिये। यह समझ में नहीं ग्राता कि एक तरफ तो रिजर्वेशन की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ म्याद कायम की जाती है। यह बड़े खेद की बात है। में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर्डगा कि वे श्री मुरलीघर कुरील के संशोधन को मान लें।

^{*}वस्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपूर)--ग्रध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो श्री मुरलीधर करील ने उपस्थित किया है, में उसकी मुद्राफिकत में कुछ कहने को खड़ा हुन्ना हूं। संविधान का संबंध है उसमें बिलकुल साफ है कि पालियामेंट और ग्रसेम्बली के लिये हरिजनों को कोटा या सुरक्षित स्थान रखे गये हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या ग्राम पंचायतों में जो स्थान सुरक्षित रक्खे जाते हैं वे थारा के मातहत नहीं रक्खे जाते बल्कि वह ग्रार्टि-किल १५(४) भ्रौर १६(१) (४) के मातहत रक्ले जाते हैं। चूंकि वह बहुत पिछड़े हुये हैं, वह दूसरे लोगों के मुकाबिलें में नहीं श्रासकते जब तक कि उनको सुरक्षित स्थान न दिये जाये, इसलिये यह रक्खा जा रहा है। जहां तक संविधान का ताल्लुक है वह बिलकुल साफ है, उसमें तो पालियामेंट और ग्रसेम्बली के लिये सुरक्षित स्थान रक्खे गये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसि निटी, टाउन एरिया और ग्राम पंचायत के लिये उसमें कोई जिक्र नहीं ग्राया है लेकिन उनकी गिरी हुई हालत को देखते हुये इन संशोधनों में सुरक्षित स्थान रक्खें गये हैं। फिर यह कह देना कि चंकि संविधान में सन् ६० तक या १० साल के लिये रक्खा गया है, उसके बाद वह खत्म कर दिया जायगा इसलिये इसमें भी वही कर दिया जाय, बारे में मेरा यह कहना है कि चाहे १० साल के बाद में ग्रसेम्बली ग्रौर पार्लियामेंट में हरिजनों के मुरक्षित स्थान न रहें लेकिन ग्रगर उस समय भी यह हाउस यह उचित समझे कि टाउन एरिया, म्यनिसिपैलिटी, डिस्ट्क्ट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों में उनके स्थान रक्खे जायं तो वही रहेगा जो हाउस मंजूर करेगा। ऐसी हालत में यह तय कर देना कि फलां तारीख तक स्थान सुरक्षित करते हैं, उचित नहीं है या संविधान का सहारा लेकर हम कहें कि जब तक ग्रसेम्बली ग्रीर पालियामेंट में स्थान सुरक्षित रहेंगे तभी तक इसमें भी सुरक्षित रक्खे जायं, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

एक बात यह भी कही गयी कि ये न्याय की एजेंसी है इसलिये उसमें रिजवेंशन होना उचित नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि उनके लिये मुंसिफी श्रौर जुडिशियरी में भी स्थान सुरक्षित रक्ले जाते हैं इसलिये यह सोचना कि न्याय पंचायतों में हरिजनों के स्थान सुरक्षित न रक्षे जायं, अनुचित हैं। इसके अतिरिक्त अब तक जो चुनाव होते थे वे गांव सभा के द्वारा होते थे उसमें बहुत कुछ गुंजाइश थी कि लोग वहां चुन कर थ्रा जायं। लेकिन ऐसी भ्रवस्था में हम कैसे उम्मीद करें कि वहां पर उनकी नामजदगी हो जायगी जब कि नामजदगी का भ्रधिकार डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट जो कि प्रेसाइडिंग भ्रथारिटी होगा, को होगा? ऐसी चीजों को देखते हुये जब कि नाना प्रकार की नौकरियां चाहे जिस तरीके से भर ली जाती है श्रौर उसमें नामजदिगयां होती है, उनमें हरिजनों को नहीं लिया जाता, तो मै नहीं समझता कि यह कैसे कहा जा सकता है कि ग्रब ऐसी ग्रवस्था ग्रागई है कि वे हमारे साथ न्याय रोजमर्रा के कार्यों को देखा जाय तो पता लगता है कि उतना अंचा स्तर हमारे समाज का नहीं हो पाया है कि वे हरिजनों को समान अधिकार देने के लिये हो जावें। यहीं तक नहीं, म्रफसरों में भी कहीं पार्टीबन्दी के श्राधार को लेकर, कहीं किसी प्रकार के श्राधार को लेकर, वह उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में, में समझता हूं कि इस तरीके से न्याय अदालतों में उनका रिजर्वेशन न करना और उनको यह कहना कि इन दूसरे तरीकों से, या नामजदगी से, उसमें श्रासकोंगे, यह नामुमिकन बात है। मान लो कि हरिजन कोई वैसे भी चुनकर श्रागया तो उसे उस श्रवस्था में छोड़ना होगा या यों कहिये कि एक सीट बढ़ जायगी श्रीर हरिजन उससे वंचित रह जायगा। तो इस तरीके से वह इलेक्शन ही ऐसा होगा जिसमें हरिजनों को उनकी भ्राबादी के भ्रनुपात से, जैसा कि इस ऐक्ट में सेक्शन है, उसको पूरा नहीं किया जायगा श्रौर फिर यह सोचा जायगा कि उस सीट को बाद में पूरा किया जाय चाहे नामजदेगी से पूरा करें या कैसे भी किया जाय। इस तरह से या तो नामजदगी करनी होगी या दूसरा चुनाव होगा ऐसी हालत में में यह साफ कह देना चाहता हूं कि क्यों न न्याय पंचायतों में भी उनका रिजर्वेशन स्वीकार किया जाय थ्रौर उस थ्राधार पर उनकी नामजदगी या एप्वाइंटमेंट किया जाय । किसी हइ तक न्याय श्रदालत का पंच गवर्नमेंट सर्वेट माना गया है, ऐसा तसलीम किया गया है,

[श्री जयपाल सिंह]
कि उसे सरकारी नौकरी के तमाम श्रधिकार प्राप्त हैं, यह श्राप देख सकते हैं जो डे फेनीकान कार।
२१ के श्रनुसार गर्दनमेंट सर्वेट के बारे में बतलाई गई है। गांव सभा का मेम्बर या पंचायती
ग्रदालत का मेम्बर गर्दनमेंट सर्वेट की परिभाषा में श्राता है श्रौर इस तरह की पाबन्दी ज
पर लगाई जाने की बात है। तो ऐसी हालत में यह कहना कि उनके लिये स्थान सुरक्षित न खे
जावें, यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

यों तो यह भी कहा गया है श्रौर कहा जाता है हमेशा कि हर जगह हरिजनों को पूरे स्थान दिये जावेंगे मगर होता ऐसा कहीं भी नहीं है। मुंसफी में, जुडि शियरी में या डिप्टी कलेक्सी में जितने भी सरकारी स्थान है उनमें उनकों कोटा नहीं मिल पाता है। इसलिये में यह निवेक करूंगा कि मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें कि उनके स्थानों को फिस प्रकार से सुरक्षित किया जाय । मैं यह साफ साफ कहंगा कि श्रव तो कहीं-कहीं पर पंचायती श्रदालतों में सर्पंच हो भी गये हैं लेकिन इसके बाद मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि सरपंच हो सकेंगे। तो ऐसी प्रवस्था में इस बात को देखते हुये उनका स्थान सुरक्षित रखना निहायत जरूरी है और इसी तरीके से ब्रदालती पंचायतों में भी उनको सुरक्षित स्थान देना चाहिये। कोई ब्रवधि मुकर्रर करना या यह कहना कि संविधान के भ्राटिकल के भ्रनुसार जब भ्रसेम्बली या पालियामेट में सुरक्षित स्थान का प्राविजन खतम हो जायगा उस वक्त तक ग्राम पंचायतों में स्थान सुरक्षित रहेगा, यह तो में समझता हूं कि मुनासिब नहीं है कि जब इस हाउस को पूरा श्रधिकार है कि वह कभी भी ग्रपने कानून में कीई ग्रमेंडमेंट ला सकता है ग्रौर उस ग्रमेंडमेंट के जरिये उसे खत्म कर सकता है। क्या यहां पहले मुसलमानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट नहीं था? क्या इसी हाउस ने उसको खत्म नहीं किया? क्या इसी हाउस ने सेपरेट एलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट एलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं कायम किया? जब उस हाउस को पूरा ग्रधिकार है तो यह कहना कि इस हाउस को कोई अधिकार नहीं कि वह कोई अमें अमें उसेंट ला सके। में समझता हूं कि उचित नहीं है। इसका माने तो यह है कि इस हाउस के ऊपर शायद सरकार को भरोसा ही नहीं है इसी से तारीख निश्चित करके उनके लिये सुरक्षित रखा जा रहा है। यह मुनासिब नहीं है यह हाउस हर समय अपना कानून बनाने के लिये स्वतंत्र है और इस प्रकार कोई कानून अमेंडमेंट के जरिये या कोई मुकम्मल कानून बनाने का उसे पूरा श्रधिकार है। तो में यह साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दोनों चीजों पर विचार कर लें श्रौर विचार करके देखें कि यह कहा तक पूरा हो सकता है। इसलिये में यह बात नहीं कहता हूं कि यह हरिजनों की बात है बल्कि में समझता हूं कि इसके लिये अभी उचित अवसर नहीं है।

मेरा यकीन है कि ६-७ साल के बाद समाज में कोई तब्दीली नहीं भ्रा जायगी। भ्रगर ऐसी कोई तब्दीली समाज के अन्दर भ्रा जाय और हिन्दुस्तान से खम्राछत दूर हो जाय, वर्ण व्यवस्था व ऊंच नीच की कोई भावना न रहे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन में नहीं समझता हूं कि जब ६-७ साल की आजादी के बाद हमारे अन्दर कोई तब्दीली खास नहीं भ्रायी है तो अगले दो चार साल में वैसी तब्दीली भ्रा जायगी। ऐसी सूरत में में माननीय मंत्री जो से फिर यह दरख्वास्त करता हूं कि वे ठंढे दिल से विचार कर भ्रौर विचार करके उस पर अमल करने की कोशिश करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय में प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-प्रदन यह है कि ग्रब इस संशोधन पर वाद-विवाद खत्म किया जाय। (प्रदन उपस्थित किया गया ग्रीर स्वीकृत हुग्रा।)

श्री उपाध्यक्ष—में माननीय सदस्य का ध्यान उनके संशोधन की भाषा की स्रोर श्राकांवत करना चाहता हूं। पहले वाक्य की बाबत तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन दूसरे बाक्य की बावत कहना है कि वे यह चाहते है कि म्राठवीं पंक्ति के शब्द " and from " के बाद "the twenty sixth day of January, 1950" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जावे, में समझता हूं कि इसका कोई म्रथं नहीं निकलता है। यह म्रनुचित वाक्य है। में तो समझता हूं कि वे उचित समझे तो " and from " को हटाने के लिये कोई संशोधन पर संशोधन पेश कर दे। उसके बाद जो उनके संशोधन का मंशा है वह पूरा हो जायगा। वे स्वयं इसके ऊपर विचार कर लें।

श्री मुरलीधर कुरील---- ग्रभी तो शायद माननीय मंत्री जी को तरफ से इसका जवाब होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है और जिस तरफ ध्यान ग्राक जित करना था वह भी हो गया है। इसलिये में माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हैं कि वे इसको वापस ले ले।

श्री मरलीधर कुरील—जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस के पक्ष विपक्ष में भाग लिया उनका में श्राभारी हूं श्रीर माननीय मंत्री जी ने जो श्राक्वासन दिया है उसके श्रनुसार में इस संज्ञोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, श्राप की श्राज्ञा से में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्ध हटा दिए जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्राविजन्स के हटाने से जो मन्शा श्री शिव-नारायण जी का है या दूसरे सदस्यों का है वह भी पूरा हो जायगा। मुझे श्रक्षसोस है कि श्रभी जो संशोधन पेश था वह बहस मुवाहिस के बाद वापस हो गया। मेरा सैशोधन ग्रगर पेश हो तो माननीय सदस्य वोट दे सकते है। जो रिजर्वेशन मिला है वह तो चालू ही रहेगा चाहे वह संविधान से मिले या सदन चाहेगा तो वह बढ़ भी सकता है और अगर हटाने की बात होगी तो उसे हमे आगे बढ़ाने में रोकटोक न होगी। जब विधान में खत्म हो जायगा या हमें उसे बढ़ाने का मौक़ा न मिलेगा तो इतने से भी हमारा काम चल जाता है, यही काफी है। इसलिये आगे इन प्रावि-जन्स के रखने से परपज सर्व नहीं होता। ब्रब तक जो कानून बने है उनमें कोई तारीख निर्घारित नहीं की गई है, कहीं रिजर्वेशन दस साल का है कहीं कितने का है। इससे कन्फयूजन पड़ जायगा ग्रौर इस कन्फयूजन को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि इन प्राविजन्स को हटा दिया जाय। उनका रिजर्वेशन बराबर जारी रहे। जैसे जैसे प्रगति चल रही है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऐसा करना उनके ही हक में ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो कांस्टीटचूरान में समय है उसमें उनकी हालत न सुधरे श्रीर कभी मौका हो सकता है कि उसकी श्रागे बढ़ाया जाय, इसलिए इसमें हाथ पैर बांध देना ठीक न होगा। इसलिए ग्रगर मंत्री जी इसको मान ले तो माननीय शिवनाराायण जी की भी इच्छा पूरी हो जायगी और काफी लाभ होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीटचूशन में लिखा है कि रिजर्वेशन दस साल तक रहेगा। इसके दोनों प्राविजन्स का ग्रर्थ है कि बह दस साल तक

[🕇] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो रहेगा ही ग्रौर दूसरे प्राविजन में यह है कि ग्रगए उस वक्टा गांव सभायें बनी हुई है तो यह गांव सभायें जारी रहेगी जब तक कि ५ साल उनके पूरे हो जायंगे। मान लीजिये कि ग्रंग नवम्बर दिसम्बर में चुनाव हुग्रा श्रौर उसके बाद दिसम्बर या नवम्बर '५६ में चुनाव हो गया, तो वह चुनाव ५ साल तक कायम रहेगा ग्रौर वह लोग सदस्य बने रहेंगे ग्रागे ५ साल तक यानी दिसम्बर्ट सन्' ६४ तक। तो इन दोनों प्राविजन के माने यह है कि आज से १० साल तक कायम रह सकता है। एक बात बिल्कुल साफ इसके बनाने वालों के दिमाग मे है कि जनव तक कांस्टीटचूजन में रिजवेंगन है तब तक तो रहेगा ही तब तक के लिये तो यह गारन्टी करता है लेकिन जब कांस्टीटचूशन में नहीं होगा उस समय रिजरवेंशन रहे या न रहे इस पर यह सदन विचार कर सकता है; ऋगेर उस समय जरूरत हो तो तय कर सकता है। इसलिय यह जो प्राविजन जैसा है वैसा हो रहने दिया ज्ञाय श्रोर में समझता हुं कि माननीय उपाध्याय जी ग्रयने संशोधन को वापसे लेलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्बुझे माननीय मंत्री जी की दलील समझ में नहीं स्रायी। वह यह कहते हैं कि शिडचूल कास्ट्स के लिये जितना कांस्टीटचुशन में प्रोवाइडेड है उससे भी वे आगे बढ़ रहे हैं श्रीर ६० के आगे भी देना चाहते है।

श्री मोहनलाल गौतम-मैने यह नहीं कहा।

श्री मदनमीहन उपाध्याय--अगर श्रापने यह नहीं कहा तो क्या कहा समझा दीजिय । में समझता हूं कि जितना कांस्टीटचूशन में हैं उसके बाद जो शिड यूल्ड कास्ट के लोग है वे स्वयं ग्रपनी ज्ञान के खिलाफ समझेगे रिजर्वेशन का लेना। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें समझा, वे तो कहते हैं कि मैं ने नहीं कहा लेकिन जैसा में समझा कि उनका यह कहना है कि वे ६० के भ्रागे भी इस रिजर्वेशन को बढ़ातों है। तभी मेरा यह भ्रामें सेंड मेंट श्रीर जरूरी हो जाता है कि यह कंफचूजन क्रियेट करता है। मेरा श्राश्रमेंट उनकी बात से तो श्रीर भी ज्यादा वजनी हो जाता है श्रीर रीजने बिल हो जाता है। मं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे श्रार्गूमेंट को स्वीकार करके मेरे श्रमेंडमेंट के मानेंगे।

श्री मोहन जाल गौतम - जो मंने कहा था वह यही था कि भ्रव तक कांस्टीटचूरान में है तब तक के लिये तो गारंटीड है हो। लेकिन वह तो २६ जनवरी, १६६० तक है। म ह तब तक का जिन ता नार्या है वह यह है कि उस डेट को जो पंचायते चुनी हुई होंगी उनका वह रिजर्बेशन कायम रहेगा जब तक उनकी मियाद है। वह कई साल बाद तक जा सकता है। कांस्टीटचूशन में जो स्रविध है उसके लिये नारटीड है। उसके बाद इस सदन को श्रिविकार होगा कि कांस्टीटचूरान की श्रविध को रखं या न रखे। ग्रगर कास्टाटचूशन में बढ़ जाता है तो उसमें भी बढ़ जायगा लेकिन ग्रगर कांस्टीटचूशन में न रहे तो भी सदन को ग्रधिकार रहेगा कि उसको रखे यान रखे।

श्री जयपाल सिंह—में एक प्रश्न करना चाहता हूं। पालियामेंट श्रीर ब्रसम्बितयों के लिये तो सुरक्षित स्थान है कांस्टीटचूशन में लेकिन उसके ब्रलावा तो नहीं हैं। उससे यह किस तरह से सम्बन्धित हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें कास्टाटचूशन हे सीट्स का रिजवेंशन असेम्बली भीर पालियामेट के लिये हैं लेकिन उसी के भाव को लेकर यह गांव सभाग्रों के लिये रिजर्बेशन कर दिया गया है श्रीर कह दिया गया है कि जब तक कांस्टीटचूशन में हैं नव तक तो रिजर्बेशन रहे श्रीर उसके बाद सदन की श्रिष्टिकार हो।

श्री जयताल सिह—कास्टीटचूशन से पहले से था?

श्री सोहननाल गौतम—कांस्टीटचूरान से पहले से गांव सभा में ही क्यों इस मुल्क में रिजर्वेशन था शेंडचूल्ड कास्ट श्रोंर माइनारिटीज का इसलिये जो वसूल है यह तो हिस्टारिकल चला श्राता है उसकी बहस नहीं है। सवाल यह है कि कांस्टीटचूशन में इस वक्त जब तक है तब तक नहीं हट रहा है। उसके बाद श्रापको खुद श्रष्टितयार होगा कि श्राप बढ़ाये या न बढ़ाये।

श्री उपाध्यक्ष-प्रकृत यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्घ हटा दिये जायं।

(प्रक्त उपस्थित किया गया ग्रौर ग्रस्वीकृत हुग्रा।)

श्री मोहनलाल गौतम—श्री रतनलाल जी का जो संशोधन है ४२-ग है वही पहले कृपाशंकर जी का था जो कि उस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया था, पेज ५ पर ३७-स । श्रौर वह इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया था कि उसका ग्राठवे हिस्से से ताल्लुक था इसलिये जब तक कि ५ श्रौर ६ न लिये जायं तब तक वह पोस्टपोन कर दिया गया था। इस वक्त रतनलाल जी नहीं है इसलिये कृपाशंकर जी को ३७-स पेश करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री कृपाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि उपलंड (8) के रेखांकित शब्द "Where" श्रौर शब्द "prescribed under Sub-Section" के बीच में "a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members"रस दिये जावे।

जपाध्यक्ष महोदय, "where" के आगे जो 'a' निखा हुआ है वह निकाल दिया जाय क्योंकि फिर दो मर्तबे ''a-a'' हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ स्पष्ट नहीं मालूम होता है क्योंकि श्रंग्रेजी की प्रतियों में यह जुड़ता नहीं है, उसमे तो यही मौजूद है। इसलिये इसका श्रन्तिम रूप जो हो वह पढ़ दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—ग्रब यह इस तरह से होगा "Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (७) के ग्ररम्भ में शब्द "a" व "prescribed" के बीच में शब्द "Gaon Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिये जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म ग्रापकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ की प्रस्तावित नई घारा 12 (8) के रेखांकित ग्रंश की ग्रंतिम चार पंक्तियां निकाल दी जायं ग्रीर उनके स्थान पर निम्निलिखत शब्द समृह रख दिया जाय:—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, जो इस विभेयक की प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है:-

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected"

्माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो इसका जो

रूप बनेगा वह इस प्रकार होगा।

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the re'mainin-number of members. But if it again fails to elect the full number of refmainging members it shall be lawful for the so elected members to fill in the seats So remaining vacant of Gaon Sabha and any member so Coropted shall-

be deemeds to have been duly elected"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह बिल्कुल प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल है। जो यहां पर प्रस्तावित घारा विषेयक में दी हुई है वह प्रजातन्त्र की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। उसमें यह बतलाया गया है कि प्रगर कोई गांव सभा अपने पूरे मेम्बरों को चुनने में फेल होती है जो कि सब-सेक्शन (२) में प्रेंस्काइब्ड है और सीट खाली रह जाती है तो उन सीटों को नियत अधिकारी या सरकार पूरा कर देंगी। तो श्रीमान् जी यह भावना ठीक नहीं है। पंचायतें जो कि महात्मा गांधी के तिद्धान्तों के श्रनुकूल बनी हैं कि ग्राम निवासी श्रपनी भावना क अनुसार जिसे चाहें चुनें, वहां परें सरकार को तरफ से या नियत श्रिषकारी को तरफ से उनके ऊपर ग्रथारिटी इम्पोज करना यह प्रजातन्त्र के प्रतिकूल है। श्रीमान् जी, जहां तक कोन्राप्यान का सम्बन्ध है वहां तक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऐक्ट था उसमें भी इस तरह की ब्यवस्था की गई थी श्रीर कुछ सदस्य कोग्राप्शन द्वारा लिये जाते थे। तो इस तरह का अधिनियम में प्रोवीजन किया जा रहा है यह किसी तरह से प्रजातंत्र की भावता का समर्थक ही है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय पंचायतों ग्रौर न्याय पंचायतों से करण्यान हटाना चाहते हैं ग्रौर ईमानदार सदस्यों को पंचायत में रखना चाहते है। लेकिन जो तरीका वे ग्रपनाने जा रहे हैं वह में समझता हूं कि किसी तरह से प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल नहीं है। वरन् प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रतिकूल है। वह एक तानाशाही तरीक़ा है और में उसका विरोध करूंगा। श्रीमान् जी, जो संशोधन रखा गया है उसके माने यह होंगे कि मान लीजिये किसी ग्राम सभा के लिये ३५ सदस्य चुनने हैं ग्रौर उनमें से किन्हीं कारणों से २५ ही चुने गये ग्रौर १० सीटे खाली रह गर्यों तो ये १० सीटें माननीय मंत्री जी के ग्रनसार गवर्नमेंट द्वारा पूरी की जायंगी, लेकिन संशोधन में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि वे पहले जो २४ मेम्बर चुन लिये गये है वेही कोग्राप्शन के द्वारा पूरी कर लेंगे। स शोधन मेरी समझ में बहुत ही प्रच्छा है और प्रजातन्त्र की भावना के ग्रनुकूल है। में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे मान लें। इससे देश का कल्याण ही होगा धौर पंचायतों में जो करप्शन का उनको डर है वह भी किसी तरह से नहीं ग्राने पायेगा वरन् वहदूर ही होगा।

श्री कृपा शंकर—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन ग्रभी माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मतलद केवल इतना ही है कि ग्रगर गांव सभा पूरे मेम्बरों को न चुन सके ग्रौर कुछ जगहें खाली रह जायं तो बजाय इसके कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी उन्हें नामिनेट करे जो मेम्बर चुन कर ग्राये हैं उन्हीं को कोग्राप्ट करने/ का श्रिषकार विया जाय । इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि को प्राप्तान का लफ्ज ऐसी जगह इस्तेमाल होता ह जहां पर कनेटी की कोई ताबाद फिक्स नहीं होती है और प्राविजनल तौर पर बनाली जाती है श्रौर लोगों को प्रस्तियार दिया जाता है कि अगर वे चाहें तो २,४, १०, ५ मेम्बर को ग्राप्ट कर सकते है। प्राम तौर से जो इस तरह की कनेटियां बनती है उनके लिये को ग्राप्तान का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो तादाद मुकर्रर थी उसको नहीं चुना गया। उसके बाद उनसे फिर कहा गया कि वे बाकी जगहों के लिये चुनें। फिर भी उन्होंने नहीं चुना। इसके बाद फिर वे लोग जो चुनकर आये वे ही को ग्राप्ट करे यह कुछ बहुत अच्छा नहीं मालूम होता है। इसमें यह प्राविजन तो मौजूद ही है कि अगर पहली बार पूरे मेम्बर नहीं चुने जायंगे तो उनसे दो बारा कहा जायगा और दो बारा अगर वे फेल हो जायंगे तब यह मौका प्रेस्काइब्ड अथारिटी को आयोगा कि वह जिसको चाहे नामिनेट कर दे। इसलिये को आप्रप्तान की कोई बात उठती नहीं। मौका तो उनको दिया ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जहां दो बारा काल अपान करने के बाद भी पूरी सीटें न भरी जा सकें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्य ने इसको पेश किया है शायद इन दिक्ततों को देखकर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, में श्री विष्णुदयाल वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं श्रौर श्राशा है कि बावजूद माननीय कृपा शंकर के भाषण के श्रौर जो विचार उन्होंने प्रकट किये है उनके यह सदन श्रौर माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। प्रश्न कोई बहुत गृढ़ या संगीन नहीं है। प्रस्तुत घारा के अनुसार जो विधि बनायी गयी है यह हैं कि यदि पहली बार गांव सभा पूरी संख्या में मेम्बर न चुन पाये तो उसको एक बार फिर चुनने का ग्रादेश मिलेगा ग्रीर यदि दूसरी बार भी वह पूरी संख्या मे गांव पं चायत को नहीं चुन पाती है तो प्रेस्काइब्ड "ग्रथ।रिटी को ग्रधिकार होगा कि वह उतने सदस्यों को नामजद कर दे। माननीय विष्णु दयाल के संशोधन का भाव यह है कि बजाय प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को यह ग्रधिकार देने के जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको यह प्रधिकार हो कि जितने सदस्यों की कमी है उनको छांट लें। प्रश्न बहुत सरल है। माननीय कुपा शंकर जी ने कोग्राप्शन के ऊपर कुछ कहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि ग्रक्सर उन व्यक्तियों के लिये होता है जो संख्या जितनी निश्चित होती हैं उससे ग्रधिक व्यक्ति लिये जाते है तो उनके लिये वह प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु जो सुझाव श्री विष्णुदयाल जी वर्मा ने दिया है उसके सिद्धान्त के ऊपर माननीय कृपा शंकर जी ने कुछ कहा जिसकी में समझ नहीं पाया हूं। शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा या लेकिन ग्रंत में जो उन्होंने कहा वह स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। लेकिन में समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि यदि किसी कारण से गांव सभा के पूरे प्रतिनिधि नहीं छांट पाये जितने कि गांव पंचायत में प्रतिनिधि भेजने है। यह स्पष्ट है कि उन्हीं सदस्यों को यदि ग्रधिकार दे दिये जायं जो कि चुनकर ग्रायं है कि जितने सदस्यों की कमी है उनको वह छाँट लें तो इसमें किसी को कोई ब्रापित नहीं होनी चाहिये। इसलिये में इस संशोधन में एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहता हूं श्रीर वह संशोधन यह है कि जहां शुरू में लिखा गया है कि "so elected member" के स्थान पर शब्द "the member so elected" रख दिये जायं। इससे भाषा शुद्ध हो जाती है। जहां देखों वहां पर प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी को घुसेड़ा जा रहा है। यहां प्रेस्काइब्ड अयारिटी को यह अधिकार देना बेकार है। चुनाव में अगर पूरी पंचायत नहीं चुन पाती है तो कोई श्रापत्ति नहीं दिखाई देती कि जिनको लोगों ने चुन लिया है, उनको ही ग्रंधिकार दे दें कि वह जितनी कमी हुई है, उनको चुन ले।

महाराजकुमार बालेन्द्रशाह]

में मान सकता हूं कि यह ग्रापत्ति उठाई जाय कि वहां पर पक्षपात हो सकता हूं ग्रोर जो चुन लिये गये हैं वह लोग चुनने में फेवरटिज्म करेंगे। ग्रगर यह ग्रारोप इनके अपर लगाया जा सकता है तो इसके साथ ही साथ प्रेस्काइण्ड ग्रथ रिटी पर भी लगाया जा सकता है ग्रौर यह बहस कहीं भी खत्म नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा-माननीय उपाव्यक्ष महोदय, यह जो विष्णुदयाल जी ने संशोधन पेश किया है और साथ ही साथ माननीय बालेन्दु शाह जी का जो उसमें संशोधन हैं में उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो म्राज सेवा में संशोधन पेश किया गया है उसका मंशा यह है कि जो पंचायत चुनी जायगी और जो मेम्बर उसमें चुने जायंगे उसमें यदि कमी पड़ेगी तो उनको पूरा करने के लिये सरकार की तरफ से नियत ग्रंधिकारी होगा वह उस कमी को पूरी करेगा। लेकिन उन्होंने संशोधन रखा है कि इस कमी को पूरी करने के लिये जो लोग चुनकर ग्रायेंगे वह को आप्शन कर लेंगे। में ग्रापक सामने यह रखूं कि पंचायत किस तरह से चुनी जाती है तो यह सवाल पैवा नहीं होता है क्योंकि जो लोग ग्राना चाहते हैं वह फीस नहीं दे पाते, इसमें कमी पड़ जायगी, इसलिये कि वह चुने नहीं जायंगे। ग्रगर सही सही पंचायतों का चुनाव माननीय मंत्री जी कराना चाहते हैं तो इसको फ्री कर दें श्रौर किसी प्रकार की फीस श्रौर प्रतिबन्ध न हो तो पंचायतों क चुनाव में कमी का सवाल नहीं होता। जहाँ पंचायतों का चुनाव होता है तो वहां के बसने वाले ईमानदार लोगों को चुन लें ग्रौर पूरा पूरा चुनाव हो जाय। इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि इसमें पैसा दाखिल करने का सर्वाल है। जितने लोग दाखिल कर देंगे वही चुने जायंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वह चुनें नहीं जायंगे। जब वह चुने नहीं जायंगे तो कमी पड़ जायगी। बहुत से ऐसे म्रादमी हैं जो सोचते हैं कि चार रुपया मजदूरी करके इंकट्ठा करके फीस दे दें। और फीस देने के बाद हम पंच हो जायं तो इससे हमको कोई फायदा नहीं है और न हमको वह पैसा वापस मिलेंगा। तो जब ऐसी चीज उनके सामने है तो वह सोचते हैं कि हम चार रुपये क्यों दें? वह इस वजह से पंचायतों में पंचों के श्राने में कुछ कमी पड़ जायगी। जो उन्होंने संशोधन रखा है उसके अनुसार जो लोग चुने जायंगे वह उस गांव के प्रतिनिधि होंगे और प्रतिनिधि स्वरूप होने के नाते उस गांव का सुधार करने के लिए अपने माफिक अच्छे लोगों का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद इस तरह से एक अच्छी पंचायत वन जायगी और वह उस काम को अच्छी तरह कर सकती है। तो माननीय मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि उन लोगों को वह अवस्य यह अधिकार दें कि जो चुनकर आयें वह बाकी लोगों का चुनाव करें। यही सब से अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ में माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का समर्थन करता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन मेरे माननीय साथियों ने इस तरमीम को पेश किया उन्होंने एक बात को महेनजर नहीं रखा और वह यह है कि यह ग्रापित्त किन सूरतों में ग्रा सकती है। गांव समा के मेम्बरान को यह हक दिया गया है कि वह पंचायत के मेम्बरान का चुनाव करें। लेकिन ग्रगर वह किसी वजह से पूरी तादाद जो कानून के मुताबिक रखी गयी है उतने लोगों का चुनाव न करें, चुनाव न करना चाहें तो ऐसी सूरत हो सकती है कि उनसे यह कह सकें कि तुम बाकी लोगों का चुनाव करो। ग्रगर कोई ग्रापित्त है तो वह दूर हो जानी चाहिए ग्रौर उन्हें

वंज्ञायत के मेम्बरान का चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन श्रगर वह इस पर भी चनाव नहीं करते तो इसके माने यह है कि उनके रास्ते में कोई भ्रापत्ति नहीं, बल्कि जानबझ-कर वे कायदे का पालन नहीं करना चाहते श्रीर कवायद की पूर्ति नहीं करना चाहते। उनमें किसी किस्म की सी पार्टीबाजी, या दलबन्दी जैसी कोई चीज मौजूद है जिसकी वजह से वह कानून को रोकना चाहते है, रद्द करना चाहते है और पूरी तादाद मे पंचायतों का चुनाव करना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में फिर उनके साथियों को, उसी जमात को यह हक दे देना कि वह मेम्बर्स को चुने इसके तो माने यह है कि उनको एक ऐसा प्रीमियम दे दिया जाय, एक ऐसा मौका दे दिया जाय कि पहले तो चतेंगे नहीं, कहने पर भी नहीं चुनेंगे श्रौर चुने जाने के बाद उनको यह उम्मीद रहे कि जिनको चना है वही बाक्ती को भी कोग्राप्ट कर लेंगे। तो इस किस्म से एक खास किस्म के ग्रादमी उसम पहुंच जायंगे। इसलिये किसी निस्पक्ष पार्टी को, किसी निस्पक्ष ताकत को यह हक देना चाहिए कि वह उस जगह नामजदगी कर सके ग्रीर ऐसी सुरत में जब कि ग्राम सभा ग्रपना काम न करे, ग्रपना काम करने से कासिर रहे, बार बार कहने पर भी चुनाव न करें तो फिर उनके चुने हुए मेम्बरों को यह हक देना कि वह ग्रापस में कोग्राप्ट करके ग्रपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बरों को बढावें यह मुनासिब नहीं होगा। में समझता हूं कि सरकार को यह हक अपने पास रखना चाहिये कि मुनासिब लोगों को देखकर कि कौन इसके अहल हैं उनको नामजह करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में उसकी मुखालिफत करता हं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोवय, श्री विष्णुदयाल वर्मा जी ने ज़ो संशोधन रखा है में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें जो प्राविजन है वह यह है कि वो बार एलेक्शन हो जाने पर भी अगर गांव पंचायतों के सदस्य न पूरे हो सके तो उन सदस्यों को प्रेस्त्राइन्ड आयारिटी नामजद करेगी। उनका संशोधन है कि कोआप्शन के द्वारा हो में समझता हूं कि कोआप्शन और नामिनेशन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जहां तक आम पिन्किक का प्रश्न है गवर्नमेंट या प्रेस्त्राइन्ड अथारिटी जो है उसको अधिक अच्छी तरह से समझ सकती है बिनस्बत लोकल आदिभयों के प्योंकि जब कानून ने पंचायत को एक बार मौका दिया और किर दोबारा मौका विया कि जिन सदस्यों की कमी है उनको एलेक्ट करो, लेकिन उसके बाद भी अगर इस संस्था को वह पूरी नहीं कर सकते तो प्रस्त्राइन्ड आयारिटी नामजद करे। ऐसी परिस्थित में में समझता हूं कि डेमोक्सी में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। इसलियें में समझता हूं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसको स्वीकार न किया जाय और जो इसमें लिखा हुआ है वही माना जाय।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में श्री विष्णुदयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मेरा विरोध इसमें निहित सिद्धांत से उतना नहीं हैं जितना एक विशेष कानूनी दिवकत पैदा होने से। यदि गौर करके इसकी पढ़ा जाय तो इसमें यह लिखा है—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected."

यदि इस संशोधन को मान लिया, यद्यपि यह कोई जरूरो नहीं है लेकिन कानून में हर परिस्पित का मुकाबला करने के लिये प्राविजन होना भ्रावश्यक है, तो ऐसी स्थिति भ्रा सकती है कि कोई भी मेम्बर न चुना जाय, कोई भी नामिनेशन न हो भ्रौर सब लोग किसी तरह से इलेक्शन को बाईकाट कर दें तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस संशोधन में कोई [श्रो केशमान राय] प्राविजन नहीं है। इसलिये में इसका विरोध करता हूं। मेरा यह ख्याल है कि माननीय श्री विष्णुदयाल वर्मा श्रपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—ग्रध्यक्ष महोदय, में विष्णुशरण वर्मा जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं। इसमें दो दली जें दी गयी हैं। एक तो यह है कि प्रश्न इसमें सिर्फ यह है कि जो ग्राम सभाएं पंचायत के पूरे मेम्बरों को निर्वाचित न करें तो उस काम को कैसे पूरा किया जाय। इसमें यह प्राविजन रखा गया है कि एक बार ग्रौर उनको मौका दिया जायगा ग्रौर ग्रगर उस बार भी नहीं चुनते हैं तो सरकार प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के जिरये से उन सदस्यों को नामजद करवा सकती है। जहां तक नामिनेशन ग्रौर कोग्राप्शन का संबंध है उसमें कोई विशेष ग्रन्तर नहीं है लेकिन उन्होंने जो संशोधन रखा है उसका ग्रर्थ यह है कि जो काम पूरा किया जायगा वह प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के जिरये नहीं होगा बल्क एलेक्टेड मेम्बर्स से पूरा किया जायगा।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर श्रिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए 1)

दोनों कोग्राप्शन से और नामिनेशन से भी, जिन मेम्बर्स की कमी चुनाव में न श्राने की वजह से रह गई है उनकी कमी इस तरह से पूरी की जायगी? प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी नामजद करेगी लेकिन अगर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा कमी पूरी होती तो वह संतोष की बात होगी। उसमें कुछ अन्तर मालूम नहीं होता। अन्तर केवल इतना है कि जो अतिरिक्त मेम्बर्स चुने जाने चाहिये थे, जो नहीं चुने गये हैं उनको बजाय प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी नामजद करे, इस संशोधन का ग्रर्थ यह है कि गांव सभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वे ही यह ग्रधिकार पायें कि उनको चुन लें। यह सैद्धान्तिक रूप से सही भी है क्योंकि सरकारी सदस्यों में प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी के विषय में जो एतराज किया है उसमें शायद उनको भय है, जैसे जोरावर सिंह जी ने विरोध किया, उनको शायद यह खतरा महसूस होता है कि प्रेस्काइन्ड प्रयारिटी रक्को जाय तो मुमकिन है कि उसमें हरिजन लोगों को ज्यादा नामजद करेगी। लेकिन यह प्रक्त ही नहीं है। जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी हरिजनों को चुन सकते हैं। प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को ग्राप उचित समझते हैं या निर्वाचित सदस्यों को, जो कि ग्राम सभा के चुने हुर सदस्य हैं। में समझता हूं कि इससे दो दिक्कतें हल हो सकती हैं। एक तो फीस की कमी की जो बात है जैसा माननीय सर्दस्य ने कहा कि किसी के पास फीस न हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता और दूसरे यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्यों को वक्त से इत्तिला न मिल सके या नियत समय से पहले फार्म्स न भर सकें। यह कारण हो सकते हैं जिनसे पूरे मेम्बर्स न भा सकें। लिहाजा फीस न देने की वजह से जो कमी हो सकती है वह दूर हो जाती है और बह व्यक्ति निर्वाचित सदस्य बन कर ग्रा सकता है।

दूसरी बात नामिनेशन की है। आपने दो ब्लाक्स रक्खे हैं नामिनेटेड ग्रौर इलेक्टेड। दोनों ब्लाक्स में मतभेद होने की गुंजाइश रहती है। ग्रांम तौर से यह होता है कि जो नामिनेटेड ब्लाक के सदस्य होते हैं वे सब एक हो जाते हैं ग्रौर इलेक्टेड ब्लाक के सदस्य सब एक हो जाते हैं। टाउन एरियाज ग्रौर म्युनिसिपल बोर्ड स में नामिनेटेड सदस्य रक्खें जाते हैं। टाउन एरियाज ग्रौर म्युनिसिपल बोर्ड स में नामिनेटेड सदस्य रक्खें जाते हैं वहां तो यह ग्रथं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ नामिनेटेड सदस्य दे सकें लेकिन यहां पंचायतों का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के बेसिस पर होना नहीं है तो न मिनेशन का सेक्शन रखने से वह उद्देश्य हल नहीं हो पाता। तो ऐसी नामिनेटेड ग्रौर एलेक्टेड ब्लाक में ग्रापस में मतभेद होगा ग्रौर पंचायतों में गड़बड़ होगी इसिलये में समझता हूं कि यह संशोधन मुनासिब है ग्रौर मंजूर किया जाय।

श्री शिवनारायण——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रापकी इजाजत से में श्रपने विरोधी-दल के सदस्य से कहना चाहता हूं कि श्रगर उन्होंने पहला सेंटेंस पढ़ा होता "व्हेश्चर ए गांव सभा हैज फेल्ड टु इलेक्ट दी फुल नम्बर श्राफ मेम्बर्स"। जब गांव सभा फेल हो जाय तभी इस बात की जरूरत होगी। हमने गांव सभा को फुल श्रथारिटी दे रक्खी है। डेमोक्रेसी की श्रसली जड़ वहां बो रक्खी है। उनको चुनने का पूरा श्रधिकार दिया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—म्ब्रिघिष्ठाता महोदय, में ब्रापके द्वारा माननीय शिव नारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक बार फिर उसको पढ़ लें।

श्री शिवनारायण—मंने उसको पढ़ा है श्रीर मं श्रापको समझाने की कोशिश करूंगा उसमें यह लिखा है कि "where a Gaon sabha has failed to elect the full number of members' जब गांव सभा फेल हो जाय श्रपने यहां के सारे मेम्बरों का चुनाव करने में, तब यह दशा श्रायेगी कि उसको इस प्रकार के नामजद करने की जरूरत पड़े। यहां पर डेमोक्रेसी की गर्दन नापने की कोशिश नहीं की गयी है। इस बिल के श्रन्दर यह साफ दिया हुशा है कि श्रगर किसी गांव में ऐसी परिस्थित पैदा होजाय किसी वजह से कि लोग वोट न करे श्रीर वह पंचायत न बन सके तो ऐसी सूरत में सरकार क्या करेगी। उस समय सरकार को यह करना पड़ेगा कि नामिन्देट करके उसको पूरा करेगी श्रीर बनायेगी। श्रगर वहां पर मेम्बर एलेक्ट नहीं हुए है तो उसके लिये इन्तजाम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी हालत में जो भी श्रथारिटी प्रेस्काइच्ड या श्रीर जो भी होगी वह उसको नामिनेशन के जरिये से पूरा करेगी श्रीर वह फारमल गांव सभा कहलायेगी तो हमारे भाई ने जो यह संशोधन दिया है वह तो इसी प्रकार का है जैसे बैसाख के महीने में बवन्डर श्राने से पत्ते उड़ जाते हैं तो यह भी हवा में बात करना चाहते हैं। इसलिये जो यह संशोधन श्राया है में उसका विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्तो)—में चाहता हूं कि ग्रब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

ग्रिधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह को ग्रक्सर ग्रवसर देने के बाद यह प्रक्रन ले लिया जायगा।

श्री गेंदासिह--में मतनीय विष्णुदयाल जी वर्मा के संशोधन का समर्थन करने के लिये बड़ा हुआ हं। में अपने माननीय समस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अब तो बह अपने विचार प्रकट कर चुके हैं लेकिन माननीय रामसुभग वर्मा जी का जो संशय था उसका उत्तर उन्होंने देने की कृपा नहीं की उस पर फिर विचार कर लें। मै बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनता रहा जब श्री रामसुभग वर्मा जी ने यह कहा था कि रुपये की कमी के कारण जो लोग चुनने से बाकी रह जायेंगे उनको फिर नामिनेट करने का काम प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के हाथ में दे देना उचित नहीं होगा । यदि उनके पास रुपया होता तो संभव था कि वह खड़े होकर यदि जनता का उनको विश्वास प्राप्त था, जनता के वह विश्वासभाजन थे, तो वे चुने जा सकते थे। परन्तु रुपये के कमी के कारण वह उस समय खड़े न हो सके। ऐसा हो सकता है कि प्रेस्काइडड ग्रयारिटी जनता की उस भावना की कदर न करें। जनता की भावना की कदर करने की संभावना हम गांव पंचायत से कर सकते हैं क्योंकि गांव पंचायत तो उसी जनता की चुनी हुई है और वह गांव पंचायत उसी जनता में रोज की रहने वाली है। इसलिये उससे यह आशा की जा सकती है कि जनता की उस पुरानी भावना की उस वक्त भी वह कदर करेगी। लेकिन परेशानी तब होती है जब हम प्रेस्क इब्ड ग्रयारिटी को समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रेस्काइब्ड भ्रयारिटी क्या होगी। प्रेस्काइब्ड भ्रयारिटी इस विघेयक में इतनी मर्तवा भ्रायी है कि उसको यह कह देना कि एक ही प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी समुचे विषेयक के लिये होगी, कठिन है। मै नहीं कह सकता है कि माननीय स्वशासन मंत्री ने इस मामले में घ्रपने मांइंड की मेक ग्रप कर लिया या नहीं। प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी नामजद करने के लिये जो होगी वही प्रेस्काइब्डम्र थारिटी नहीं कही जा सकती कि वही खाली जगहों को भरेगी भी। या गांव पंचायत

[श्री गेंदा सिंह]

की बैठक ग्रगर न हो ग्रौर वह टैक्स न लगाये तो फिर टैक्स लगाने के लिये भी वही प्रेस्क हब्द म्रयारिटी होगी या गांव सभा का काम करने के लिये भी वही प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी होगी यह इसमें स्पष्ट नहीं है। इसिलये प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी के लिये कोई राय कायम करना वहत कठिन है इस प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी की सुरत शक्ल सामने होती तो इस पर कुछ विचार हो सकता था परन्तु वह नहीं है। प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी की सूरत शकल सामने हो भो तो वह पंचायत का स्थान नहीं ले सकती है। जोरावर वर्मा जी से मै यह कहना चाहता हूं कि मझे ब्राज पहली मर्तबा जोरावर वर्मा जी के भाषण से ऐसा लगा कि जिस समय वह बोलने के लिये आये वह तैयार होकर नहीं आये और वह क्षमा करेंगे मुझे यह कहने के लिये कि कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं क्योंकि ग्रगर पढ़े होते तो वह माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का विरोध नहीं करते। वह विष्णुदयाल जी के उद्देश्यों को बिलकुल भूल गये। विष्णुदयाल जी का स्पष्ट यह कहना है कि गांव पंचायत कोग्राप्ट करलें लेकिन जोरावर सिंह जी कहते हैं कि वह उनसे इंसाफ की उम्मीद न करें, वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी से मेरा भरोसा करते हैं, जिसे हम हवा में समझते हैं। मै समझता हं कि माननीय जोरावर सिंह जी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने उचित नहीं कहा। माननीय केशभानराय जी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिये गुंजाइश श्रवश्य रहनी चाहिये। मैने माननीय मंत्रियों को यहां कहते हुए सुना है कि सारो बीमारियों का इ नाज एकदम मत करो, भ्राखिर सरकार यहां मौजूद है। वह समय समय पर इलाज करती रहेगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के इस विधेयक से हमें मालूम होता है कि वह न केवल अपनी ही बल्कि श्रपने वारिसों की भी सारी बीमारी दूर करना चाहते है। तो वह श्रपनी म्राने वाली पीढ़ियों पर भी कुछ भरोसा करें। प्रेस्काइब्ड म्रथारिटी नामजद करेगी स्रौर उससे एक दूसरी भावना जैसा कि माननीय जयेन्द्र सिंह जी ने व हा, इन पंचीं श्रौर सदस्यों के मन में हो सकती है श्रौर वह हमेशा श्रपना उत्तरदायित्व प्रेस्क्राइब्ड श्रथारिटी की श्रोर समझेंगे। वे उस गांव पंचायत और गांव सभा के प्रति ग्रपना उत्तरदायित्व नहीं समझेंगे।

माज माननीय केशभान जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति गांव में स्रायेगी कि लोग श्रपने पंचों को न चुनें। यह मेरी समझ में नहीं ग्राता कि ऐसा वह कैसे सोचते हैं। माननीय शिवनारायण जी यह कह रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि तुम वोट ही मत दो या कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि डुमरियागंज की तरफ कि तुम ग्रपना बोट ही मत दो श्रौर इस पर गांव वालों ने कह दिया दिया कि हम ग्रपनी गांव पंचायत नहीं चुनेंगे। यह संभव नहीं है कि काल्पनिक बात पर कानून बनाना बहुत अच्छी बात नहीं। कानून तो जनता की मांग और आन्दोलन के अनुसार बनता है और वह ठीक काम करता है लेकिन कल्पना शक्ति से कल्पना जगत में कोई कानून बना दें तो उससे जनता को उचित लाभ होगा उसमें श्रन्देशा रहता है में माननीय केशभान राय जी से कहना चाहता हूं कि वह माननीय स्वशासन मंत्री जी की क्षमता पर विश्वास करें । क्योंकि उनके स्वकासन मंत्रित्व के हाथ में रहते हुए इस प्रकार के गांव के गांव श्रौर इलाके के इलाके कहने लगे कि बोट हो न करेंगे और ग्राम पंचायत ही न बनायेंगे, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। चाहे वह हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी हो या हम लोग हों, इस समय सभी लोग बैलेट की प्रथा को मान रहे हैं और इसी प्रथा के अनुसार चल कर कुछ भी करना चाहते हैं। ऐसी हालत में इस बात में ब्रंदेशा नहीं हो सकता कि लोग वोट करने ही न जायं। दूसरी बात यह हो सकती है कि किसी गांव में कोई दूसरा कारण हो और एक दो जगहें खाली रह जायं। उनके खाली रह जाने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी कहेंगे कि यह दो आदमी रह गये हैं प्रेस्काइव्ड प्रथारिटी उनको नामजद कर दे। लेकिन हम नहीं समझ सकते कि प्रयारिटी कौन लोगों को जानतो है, किन लोगों पर उसका भरोसा है, वे लोग जिसे प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी नामजद करेंगे क्या जनता के विश्वासयात्र ही है. इसमें हमें संदेह होता है। प्रेस्काइ इस्थारिटी

कोई भी हो लेकिन वह गांव पंचायत का मुक बला नहीं कर सकती। गांव पंचायत को ग्रपने लोगों का ज्यादा ज्ञान होता है। जो भला ग्रौर ईमानदार ग्रादमी है, जो किसी कारणवश नहीं चना जा सकश है उसको पंचायते कोग्राप्ट कर लेगी।

माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन को मानने से कोई नुरसार नहीं होने वाला है तथा प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी भी श्रनावश्यक तौर से बदनाम होने से बच जायगी । इसके ग्रतिरिख्त पंचायतो को ग्रदने चुनने वालों का ज्यादा ध्यान रहेगा। इसलिये ग्रगर उनको ग्रधिकार दे दिया जायग कि जो जगहे खाली हों उनको गांव पंचायत भर ले तो वह ग्रपनी ग्रावश्यकतानुसार वैसा कर लेगी तथा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जायगी ग्रौर गांव पंचायत ग्रपने निर्वाचकों के प्रति ज्यादा उत्तरदायत्व के साथ काम कर पायेगी। में प्रार्थना रकरता हूं शौर ग्राशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी तथा वे माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर संदेह प्रकट किया है, फिर इस पर विचार करेगे तथा विचार करने के बाद इसको स्वीकार करेगे।

श्री रामलखन मिश्र--ग्रधिष्ठाता महोदय, ग्रब विवाद समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय ।

ग्रिधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्रव वादिश्वाद समाप्त किया जाय ।

(प्रक्त उपस्थित किया गया ग्रोर स्वीकृत हुग्रा।)

श्री विष्णु दयाल वर्मा--माननीय प्रधिष्ठाता महोदय, माननीय गेदासिह जी के समर्थन करने के बाद कुछ श्रीर कहना नहीं रह जा ।। है लेकिन फिर भी हो एक माननीय सदस्यो ने जो प्रकाश डाला है उसका उत्तर देना म ग्रावश्यक समझता हूं। सबसे पहले माननीय जोरावर जी ने यह बतलाया था कि कोग्र प्यान भ्रौर न मीनेशन में कोई भ्रन्तर नहीं है लेकिन यह बात नहीं है। को ग्राप्शन ग्रौर न मीनेशन में बहुत ग्रन्तर है। नौमीनेशन के यह मानी है कि वह श्रादमी जो चापलस है, दलाल है, उसका नामिनेशन प्रे काइब्ड ध्रथारिटी से होगा। लेकिन कोग्र प्शन के मानी यह है कि विश्वास पात्र ग्रादमी यह जानने है कि ग्रमुक ग्रादमी समझदार भ्रौर ईमानदार है पर किसी कारण से, जैसे कि फीस न दे सकने की वजह से न भ्रा सके। लेकिन नामिनेशन में वही भ्रादमी भ्रायेगा जो कि टाउट का काम करता है। वैसे तो माननीय मंत्री जी मे मुझे पुरा विश्वास है, मै समझता हूं कि उनमे यह भावना है कि पंचायतों मे ऐसे भ्रादमी न भ्रा जायं जो कि उसको बदनाम करे श्रीर प्रजा का श्रहित करें। लेकिन मै समझता हूं कि यहां नामिनेशन के माने यही है कि सरकार श्रपने ऐसे **ग्रादिमयों** को लाना चाहतीं है जो उसकी जी हुजूरी करे ग्रीर ग्रागामी ग्राने वाले चुनाव में उनकी मदद करे और उनकी पार्टी के लिये प्रोपेगेडा करे। ग्रगर इस तरह का उनका कोई मंशा हो तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है लेकिन एक सही किस्म के म्रादमी को लेने के लिये कोम्राप्शन के प्रश्न पर ही गौर करना होगा। श्री केशभान राय की राय यह थी कि ऐसी भी परिस्थिति ग्रा सकती है कि किसी गांव सभा में एक भी मेम्बर न चुना जाय। वैसे तो यह पासिबल नहीं है कि कहीं एक भी ग्रादमी न चुना जाय लेकिन फिर भी में यह बतला देना चाहता हूं कि जहां पर ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत नहीं बनाना चाहते है श्रौर पंचायत बना कर श्रपनी इस तरह की व्यवस्था नहीं रखना चाहते है तो फिर सरकार को क्या परवाह कि वहां पर ग्राम पंचायत बनायी ही जाय। में तो इस विचार धारा का हुं कि जहां के लोग इसको

[श्री विष्णुदयाल वर्गी]
मुनासिव नहीं समझते है वहां नहीं बनाना चाहिये। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि
यदि ऐसी परिस्थित आ जाय तो उसके लिए जैसे जमींदारी एबालिशन अधिनियम
या दूसरे अधिनियनों के लिए संशोधन हुए है उसी तरह से इसमें भी संशोधन हो
सकता है। तो इन बातों के साथ मै माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि
वे इस संशोधन को मान लें। इस तरह के संशोधन से कल्याण ही होगा। इससे अहित
होने की कोई सम्भावना नहीं है।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन साहब, सब से श्रन्तिम वाक्य इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य का यह है कि जिस तरह से दूसरे अधिनियमों में जल्दी-जल्दी अमेडमेट आते है वैसे ही इसमें भी आ सकते हैं अगर यही चीज है तो में इसको श्रवश्य स्वीकार कर सकता हूं, जो संशोधन कि यहां पेश किया गया है लेकिन भ्रगर इस चीज को भ्रच्छा न समझ कर बार-बार संशोधन लाना हमारी कमजोरी समझी जाय तो मुझे ग्रफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। श्रब तक कोई भी ऐसा प्रोवीजन कानून मे नहीं था कि ग्रगर गांव सभा चुनाव न करे तो भी कोई नामजदंगी कर दी जाय क्योंकि ग्रब जो गांव सभाग्रों के लिए खयाल था वह यह कि जो म्युनिसिपल फंक्शंस है, जैसे सफाई, लालटेने लगाना, कुछ टैक्स लगाना तथा श्रमदान के जरिये वे ग्रपने गांव का इन्तजाम कर सकती है। लेकिन परिस्थिति श्रब बदली हुई है श्रौर कुछ हद तक बदली गयी है। जमींदारी एबालिशन के बाद जो प्रापर्टी थी गांव सभा की वह वेस्ट कर रही है गांव समाज मे। तो जब तक कोई कारपोरेट बाडी नहीं होगी तब तक इन प्रापटींज का इन्तजाम कौन करेगा। इस समय खास तौर से सवाल भ्राता है प्रापर्टी के इन्तजाम करने का। पहले प्रापर्टी के इन्तजाम करने का कोई सवाल नहीं था इसीलिये नामिनेशन का कोई प्राविजन नहीं था। अभी भी तीन चार गांव ऐसे हैं जहां गांव सभाये नहीं है और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां गांव सभायें नहीं है। लेकिन हम अब उस परिस्थित को नहीं रखने देना चाहते है। म्राखिर इन तीन चार गांव सभाग्रों मे जो प्रापर्टी वैस्ट करेगी वह कहां जायगी। इसलिये जरूरी है कि हर गांव मे सभा बनायी जाय जो वहां के सब कामों का इन्तजाम करे। ग्रब सवाल यह है कि कैसे हो। इसलिये चेयरमैन साहब, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार नामजदगी करे। इसलिये कि गांव सभाग्नों का चुनाव होगा ग्रौर ग्रगर वे चुनाव न करें तो दोबारा मौका दिया जायगा कि वे चुनाव कर लें। भ्रगर वे दोबारा भी चुनाव नहीं कर पाये तब फिर नामजदगी का सवाल भ्राता है। मैने बहुत इन्तजार किया या मगर सब से महत्वपूर्ण प्रक्त जो श्री केशभान राय का था उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और वह यह कि अगर किसी गांव सभा का एक भी मेम्बर गांव समाज न चुने श्रौर वहां नोमिनेशन न हो तो फिर वहां गांव पंचायतों मे जो प्रापटीं वेस्ट हो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा । तो इस परिस्थित के लिए कि कभी इमर्जेसी आ सकती है, यह क्लाज रखा गया है। माननीय गेंदा सिंह जी जो खास तौर से इस चीज को समझते हैं मुझे ग्रफसोस है कि फिर भी इस कंटिजेसी का कोई इल ज वे नहीं बतला रहे हैं। इसिलये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिवा इसके ग्रौर कोई नहीं है। में निवेदन कर दूं कि हमारा इरादा कोई नामिनेशन करने के ग्रीधकार को लेने का नहीं है लेकिन जैसा कि संशोधन में चाहा गया है उससे तो और फेबरेटिज्म और बिटरनेस बढ़ती है और इसी को सोच समझ कर हमने म्युनिसिनंतिटीज से और टाउन एरियाज से हमने नामिनेशन के सिस्टम को हटा दिया है हालांकि स्त्रियों की ग्रोर से ग्रोर बहुत से लोगों की तरफ से बहुत सी मांग इसकी

^{*} बरता ने भाषण का पुनर्जीक्षण नहीं किया।

हुई थी। इस पर भी इसमें एक बार नहीं दोबारा मौका दिया गया है श्रौर ध्रगर दोबारा भी न चुने जायं तब कहीं हमने यह रखा है कि उनको नामिनेट कर दिया जाय। श्रगर जरूरत पड़ेगी तो प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी उन जगहों को भरेगी श्रौर वह लाफुल होगा। रहा श्रच्छे श्रादिमयों के या बुरे श्रादिमयों के श्राने की बात वह तो दोनों तरीक़ों से श्रच्छे श्रौर बुरे दोनों तरह के श्रादमी श्रासकते हैं। को श्राप्शन द्वारा भी गलत श्रादमी श्रासकते हैं। इसिलये खराब या श्रच्छे का सवाल नहीं हैं। जिन्होंने पैसा नहीं दिया हो उनका ही सवाल नहीं हैं श्रगर मुख्तिलफ पार्टियां श्रावेगी तो वह किन्हों भी सही या गलत श्रादिमयों को ला सकती हैं, चाहे वह पैसा देने वाले हों या न हों। इसिलये में समझता हूं कि को श्राप्शन के द्वारा बाकी सीट्स को भरना मुनासिब न होगा श्रौर यह प्रथा श्रच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक तरह से गांव समाज की प्रापर्टी की देखभाल हो श्रौर उसका नुकसान किसी प्रकार से न हो। इसिलये मुनासिब होगा कि हम इस संशोधन को स्वीकार न करे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—यह जो दिया हुम्रा है "It shall be lawful" इसमें यह है कि म्रावश्यक नहीं है। यह सूरत हो सकती है कि नामिनेशन न करे, इसमें कहीं प्राविजन नहीं है, ग्रगर पूरा बाड़ी तैयार नहीं है तो उसका कार्य लाफुल बनाने के लिए कोई क्लाज है या नहीं?

श्री मोहनलाल गौतम—वह तो रूत्स मे दिया जायगा कि गांव पंचायत के कितने श्रादमी चुने जायं तब वह फंक्शन कर सकती है। नामिनेशन की बात तो उस वक्त होगी जब काम नहीं चलेगा।

श्रिघिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 12 (8) के रेखांकित श्रंश की श्रिन्तम चार पंक्तियां निकाल दी जायं श्रौर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द समूह रख दिया जाय:—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

(प्रक्त उपस्थित किया गया श्रौर श्रस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—(श्री गेंदासिंह से) श्राप इसको रखना चाहते है या नहीं?

श्री गेंदासिह—श्रगर उस संशोधन पर कुछ सुलह जैसी बातें हो गई होतीं श्रौर वह स्वीकार हो गया होता तो इस संशोधन को पेश करने की जरूरत न पड़ती। में समझता था कि माननीय मंत्री जी उस संशोधन को स्वीकार करने जा रहे है लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिय। उससे हमको बड़ी निराशा हुई श्रौर श्रब श्रगर श्रापकी इजाउत हो तो इस संशोधन को पेश करूं।

म्रधिष्ठाता--ग्रच्छा, पेश कीजिये।

श्री गेंद्रासिह--मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित घारा 12 की उपवारा (8) निकाल दी जाय।

जैसा कि अधिष्ठाता महोदय मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर माननीय विष्णुद्याल जी का संशोधन स्वीकार हो गया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती और इसीलिये मैंने उसी पर अपने को कंसेंट्रेट किया था। यह तो ऐसी चीज है जिसके लिये कहा जा सकता है कि कभी अगर आवश्यकता पड़े तो फिर कैसे काम लें। माननीय केशभान राय जी ने कहा या कि ऐसी हालत में सरकार के हाथ में ताकत रहनी चाहिये कि अगर कोई स्थान खाली रह जाय तो उनकी [श्री गेंदा सह]

भरने के लिये कोई उपाय करे। माननीय मंत्री जी ने वर्मा जी का संशोधन श्रस्वीकार कर दिया तो श्रव में यह उचित समझता हूं कि इसका कानून में से निकाल देना ही उचित होगा।

श्रिधिष्ठाता—मं गेंदासिंह जी श्रापसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी केंटिजेंसी एराइज हो सकती है कि कोई गांव सभा न चुन तो फिर क्या होगा। क्योंकि जब श्राप कानून बनाने बैठते हे तब हरएक एक्स्ट्रीम को सोच लेना चाहिये। मंत्री जी ने उस एक्स्ट्रीम तक को सोच लिया है कि किसी के बहुकावे में श्राकर या यों ही न चुने तो उस सूरत में क्या होगा?

श्री गेंदासिह—मं वही बात बिलकुल कहने जा रहा हूं। ग्रगर माननीय स्वशासन मंत्री जी यह ग्राशा करते हे कि कोई गांव बिल्कुल ऐसा हो जायगा जहां पर गांव पंचायत बनेगी नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम--इस सूबे में तीन चार ऐसे है।

श्री गेंदासिह--मुझे बड़ी खुशी हुई कि ३६ हजार गांव सभाग्रों में से तीन चार गांव सभाओं को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ऐसी बतलाया जहां पर पंचायतें नहीं बनी। ऐसी हालत में दरख्वास्त करूंगा कि उनके पास तो बड़ी भारी ताकत है। जैसे ऐडिमिनिस्ट्रैटर म्यूनिसियल बोर्ड में रखती है श्रौर ताकत श्रपने हाथ में ले लिया करती है या नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को अपने हाथ में लेकर किसी अधिकारो को उसका अधिकार देते। है। इसी तरह से सरकार को अधिकार बना रहेगा कि जब काई गांव के लोग खड़े होकर कहें कि हम गांव पंचायतें बनायेंगे नहीं तो सरकार के अधिकारी जो आज है वे रहेंगे ही। मैं मंत्रों जी का ध्यान जमींदारी विनाश भ्रधिनियम की तरफ ले जाऊंगा, मुझे वह धारा ठीक याद नहीं पड़ती सम्भवतः १२७वीं घारा है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति अपने कर्तव्य पालन से पीछे रह जाय तो उस हालत में सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त करके अपना काम ले सकती है। म्राज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस जमींदारी विनाश के बाद इन गांव समाजों को जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है इसे निबाहना चाहिये श्रौर में उनकी इस चिन्ता में शामिल होना चाहता हूं कि कोई न कोई ग्रथारिटी होनी चाहिये। तो उस ग्रय रिटी के सम्बन्ध में में यह कहना चाहता हूं कि या तो गांव पंचायत जिसे सारो जनता मिल करके बनाये भ्रोर ग्रगर वह नहीं बनाना चाहती है तो सरकार के हाथ खुले हुए है कि सरकार जिस तरह से चाहे उस गांव का शासन कर सकती है लेकिन उसको गांव पंचायत का नाम नहीं दिया जाय। हमको बड़ी भ्राज्ञा हुई ग्रौर बड़ा उत्साह बढ़ा जब कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने यह कहा कि ३६ हजार पंचायतों में केवल ३-४ गांव सभायें ऐसी निकलीं जिन्होंने भ्रपनी पंचायत नहीं चुनी क्योंकि में तो यह आञा करता हूं कि अगले वर्ष यह तीन चार भी ऐसी नहीं निकलेंगो, वह भी अपनी पंचायतें बना लेंगी। तो कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं मालूम होती है जिसके लिये इस कानून के बनाने की जरूरत हो।

दूसरी तरफ इस कानून के बनाने में जो श्रम उत्पन्न होता है धौर श्रहित होगा, उसकी तरफ भी में उनका ध्यान श्राकित करना चाहता हूं। वह यह है कि कुछ ऐसे लोग मिल जायं श्रौर मिल करके यह चाहें कि हम गांव सभा बनने ही न दें तो वैसी हालत में प्रेस्काइट्ड ग्रथारिटी को यह श्रिवकार होगा कि वह उसे बना सकें तो ऐसी हालत में एक इनकरेज नेंट मिल रहा है। इसलिये मुझे डर लगता है कि ग्रभो तक तो सिर्फ ४-५ गांव सभायें नहीं बन पाई थीं लेकिन कहीं उनकी संख्या ग्रौर न बढ़ जाय ग्रौर बढ़ कर हजार दो हजार के करीब हो जाय, तो ग्रिधिष्ठाता महोदय, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। वैसे तो रामनारायण त्रिपाठी जी का जो संशोधन ग्रायेगा उसे ग्रगर माननीय स्वशासन मंत्री जी मान ले कि २५ प्रतिशत मालगुजारी का गांव सभाग्रों को मिले तो में समझता हूं कि भला कौन ऐसी गांव सभा होगी जो ग्रपने गांव में पंचायत नहीं बनायेगी। उनका संशोधन ग्रगर न भी मान तो मेरे संशोधन को ही मान ले तो भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो ग्रपने यहां पंचायत की स्थापना में बाधा डाले क्योंकि उसके ग्रनुसार भी गांव सभाग्रों के पास कुछ धन मिलने की ग्राशा है। उससे तो उनकी तरक्की होगी इसलिये कौन नहीं चाहेगा कि उसके गांव की तरक्की हो। इसलिये में समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेगे कि इस भाग को विधेयक से निकाल दिया जाय।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय भ्रधिष्ठाता महोदय, मैने बड़े ध्यान से ग्रपने दोस्त गेदा सिंहजी की बातों की सुना श्रीर ग्राज ग्रिधिष्ठाता महोदय, पहली बार सदन का मेरा यह ब्रानुभव है कि माननीय गैदा सिंह जी ने किसी ऐसी बात को कहा है जिसकी मजबूती पर उन्हें खुद भी यकीन ग्रौर विश्वास नहीं है पूरे तौर पर। इस मेरे अनुभव मे उनके बोलने का तरीका और वह जिस तरीके पर इसकी आरगू कर रहे थे उत्तरे एसा मालुन हुन्ना जैसे न्नापकी बहस की पहली चीज लेली जायतो ग्रधिष्ठाता महोदय, वह मानते है कि ऐसी बाधा हो सकती है जिसकी वजह से गांव सभाग्रों का चुनाव नही और फिर उसी के लिये रास्ता बताते हैं कि पहले तो कभी ऐसी बात होगी ही नहीं और अगर होती है तो उसके लिये आपका रास्ता यह है कि जमींदारी उन्मुलन में धारा १२७ ऐसी है कि ग्रगर गांव सभा फेल कर जाय तो सरकार अपने नियत अधिकारा के द्वारा उस काम को करावे। अधिष्ठाता महोदय, में माननीय गेंदासिंह जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं स्रोर वह बात यह है कि कानून जो है वह कानून के ही रास्ते पर हमेशा चला करता है। कानून कभी इस बात को नहीं देखता। तो जहां तक जमींदारी उन्मूलन की उस धारा का ताल्लुक है उसमें साफ तौर पर यह है कि यदि गांव सभा ग्रौर गांव समाज उस कर्तव्य मेफेल हो सो सरकार उसको अपने अधिकारों के द्वारा उस कार्य को करायेगी। लेकिन यहां तो गांव सभा ग्रीर गांव समाज के चुनने का प्रश्न है। तो माननीय गेदा सिंह जी के कहने के अनुसार अगर कहीं ऐसी स्थित पैदा हो गरा कि किसी गांत्र में गांव सभा न स्थापित हुई ग्रीर सरकार ने जनींदारा उन्मूलन की उस धारा के ग्रनुसार श्रिधिकार करने की कोशिश की तो कानून श्रपनी जगह पर साफ है कि चूंकि उस गांव में गांव सभा श्रीर गांव समाज नहीं है इसलिये उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह प्रक्त ही नहीं है कि फेल हुई। म्रतएव उस म्रधिकार को सरकार श्रपने हाथ में नहीं ले सकती है श्रीर न उसकी कर सकती है। इसलिये श्रापके द्वारा मैं माननीय गेदा सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जरा बड़ा बीहड़ होता है। वह भावना की दुनिया में नहीं चला करता है। उसका जो वर्क होता है वह सीधे रास्ते पर चला करता है और इसलिये कानून बनाने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसी तमाम परिस्थिति और स्थिति पर विचार करे कि कानून उनकी मदद के लिये आ जाय भ्रौर इस प्रकार की बहस की इस वर्ष तीन है भ्रौर अगर अपले वर्ष ईश्वर चाहेगा तो एक भी नहीं होगी और अगर होगो तो देखा जायगा। ऐसी कोई बहस कानून बनाने वालों के लिए कोई मतलब नहीं रखती है। खास तौर पर यह बहस इस तरीके से हो सकती है कि मान लीजिये कि किसी प्रान्त का प्रबन्ध

^हवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेग शुक्त]

इतना प्रच्छा हो जाय कि साल भर में कुल तीन क़रल हों तब फिर माननीय गेवा सिंह जी यह बहस करेंगे कि माननीय मंत्री जी ख्रव तो केवल तीन क़रल हुए है ख्रौर भगवान चाहेगा तो कोई क़रल नहीं होगा। लिहाजा यह धारा हटा दो जाय तो जैसा कि यहां कहा गया है कि शुरू में कानून इमरजेंसी के लिये बनाया जाता है। मं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह इस स्थित के लिए विचार करते हैं कि ऐसी बात ख्रा सकतो हैं तो फिर क्या संकोच है। जब इन बात के लिथे व तंयार है मान लीजिये धारा १२७ जमींदारी उन्मूलन कानून का इन्टर प्रिटेशन सही हैं और उसके ख्रनुसार सरकार नामजद कर सकती हैं, काम को ख्रपने हाथ में ले सकती है नो फिर हिचक क्या है। उसका स्पष्टीकरण ख्रगर पंचायत राज के संशोधन में ख्राया है तो हिचकिचाहट किस बात की है। ख्रौर यह स्थित न हो तो हमे मौका मिल जाय ख्रपने को नामजद करने का, यह कसौटी पर नहीं उतरता और इसलिये नहीं उतरता कि ख्रइंगा लगाने वाले निगेटिव काम में सफल नहीं होते।

यह निगेटिव तरीका है कि वोट देने कोई मत जाग्रो, या चनाव में भाग न ली. गांव सभा का चुनाव न हो सके ग्रीर ग्रगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समह इस बात के लिये प्रयत्न करता है तो थोड़े से ब्रादिमयों का चाहे ब्रल्पमत क्यों न हो, कामयाब होने की गुंजायश होती है। इसलिये जो बहस रखी गई है उसमे मेरी समझ में तो कम से कम कोई चीज म्राती नहीं म्रौर जब में माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को देखता हूं तो मे तो यह समझता हूं कि यह कितने कदम पीछे चले जा रहे है। एक प्रगतिशील व्यक्ति इस बात के लिये इशारा करे ग्रपने संशोधन में कि भ्रगर गांव सभाभ्रों का चुनाव फेल हो जाय तो सरकार इस बात को भी निकाल दे कि गांव सभाग्रों को तुम चुनो । श्रापका संशोधन श्रगर पूरे तौर पर मान लिया जाय जैसा ब्रापने रखा है तो उससे यह फल होगा कि ब्रगर[°] गांव सभाग्रों का चनाव न हो तो सरकार का कर्तव्य नहीं होगा कि फिर अपने आदिमयों को चुने। यह प्रतिक्रियाचादी कदम हो सकता है और किसी प्रगतिशील व्यक्ति के लिए यह कहना कि अपर नहीं चुनी जाती तो छोड़ दिया जाय भगवान के भरोसे । तो मै अधिक्ठाता महोदय स्रोपके द्वारा माननीय गेंदासिंह से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोवन कुछ ऐसा संशोधने है जिस पर वे स्वयं विश्वास नहीं करते। ऐसा मुझे जान पड़ता है कि ऐसी चीज के लिए फिर वे जोर न दें और इसे वापस ले लें क्यों कि जहां तक मैने देखा है यह संशोधन ग्रपनी जगह पर परफेक्ट नहीं है। कानून की नजर से कानून के ग्रन्दर कोई गुंजायश नहीं छोड़ देनी चाहिये कि स्रागे पीढ़ी जो भ्रायेमी वह सुधार करेगी। कानून बनाने वाले जिस वक्त कानून बनाने बैठते हैं वे यह नहीं सोचते हैं कि ग्रागे ग्राने वाले उसमें संशोधन करेंगे। जहां तक मैने पढ़ा है, कानून वही अच्छा माना जाता है जिसमें संशोधन करने की गंजाइश कम हो और अगर हो तो बहुत कम हो और अगर कम संशोधन करने की बात हो तो बहुत दिनों के बाद संशोधन करने की बात म्राये फिर वारिसों के लिये यह उम्मीद करना कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ उनके लिये छोड़ दें यह बात मेरी समझ मे नहीं श्राती है। इसलिये इस संशोधन का में बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला ब्राजमगढ़)—माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस संगोघन को देख कर बड़ा ब्राञ्चर्य हुआ। जिस वक्त में पहला संशोधन जो माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया था जिस पर अभी वोट लिया गया है और जिस पर माननीय मंत्री महोदय का भाषण हुआ और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिसका समर्थन किया उसके बाद माननीय गेंदा सिंह जी हारा यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसकी देख कर मेरा ब्राञ्चर्य श्रीर बढ़ गया। में माननीय गेंदासिंह जी को जानता

हूं, प्रवर समिति में भी वह हमारे साथ बैठे थे ग्रौर इस विषय पर वहां भी बाते हुई थीं। माननीय मंत्री महोदय का भषण सुन लेने के बाद उसका संशोधन उपस्थित करना भ्रौर भी श्राश्चर्यजनक है। माननीय चेयरमैन महोदय, मै इस बात पर ग्रौर ग्राइचर्यचिकत है। जो विधेयक में क्लाज रखा गया है वह उस परिस्थिति का मकाबिला करने के लिये रखा गया है कि जिस वक्त में एक मर्तबा गांव सभा चनाव नहीं करती है और दूसरी मर्तबा उसकी फिर श्रादेश दिया जाता है पंचीं की चुनने के लिए तब भी वह चुनाव नहीं करती है उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जायगा। म्रगर यह नही किया जाता है तो फिर उसका इलाज क्या रह जाता है। वहां तक तो बात समझी जा सकती थीं जो माननीय वर्मा जी का संशोधन था कि गांव सभा ऐसे शेष सदस्यों को कोग्राप्ट करले, जिनका चुनाव नहीं हुन्रा है, लेकिन भ्रब माननीय गेदा सिंह जी के इस संशोधन के प्रस्तुत करने का ग्रर्थ यह होगा कि ग्रगर दोबारा भ्रादेश देने पर भी गांव सभा चुनाव नहीं करती है तो उसके लिये कोई प्राविजन न रखा जाय। दूसरे शब्दों में इसका ग्रर्थ यह होगा, जैसा कि ग्रंग्रेजी में कहा जाता है, 'प्लेसिंग कार्टंबिफोर दिहार्स'। यानी कोई कार्य ही नहीं हो सकेगा। में ऐसा तो नहीं कहंगा कि माननीय गेदा सिंह जी ने इसकी समझा नहीं है, जैसा कि याननीय रामनरेश जी ने कहा कि वह जानबूझ कर ऐसा प्रस्ताव लाये है, ऐसा तो मेरा विश्वास कदापि नहीं हो सकता। में समझता हूं कि कुछ गलतफहमी में माननीय गेंदा सिह जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस पर में ज्यादा समय माननीय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ इस संशोधन का मै विरोध करता हूं श्रौर माननीय गैदासिह जी से प्रनुरोध करता हूं कि वे तुरन्त श्रपने संशोधन को वापस ले ले ताकि हम धौर भ्रागे बढ सके।

महाराजकुमार बालेन्दुराह—श्रिघळाता महोदय, माननीय गेदा सिंह जी के इस संशोधन को प्रस्तुत करने में कुछ श्राक्चर्य प्रकट किया गया है विशेषकर इसलिये कि जबकि माननीय विष्णु दयाल वर्मा जी के संशोधन को इस सदन ने स्वीकार नहीं किया तो फिर यह पूछा जाता है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन को कैसे पेश करते है। जब कि में कहुंगी कि मै भी इस संशोधन का समर्थन करने के लि ! खड़ा हुआ हूं तो श्रवश्यमेव मेरे ऊपर भी ग्राश्चर्य प्रकट किया जायगा । किन्तू में समझ नहीं पाया कि भ्राश्चर्यजनक की बात भ्राखिर है क्या । माननीय दिष्णु दयाल वर्मा ने एक अनपैलेटएबिल और आध्जेक्शनएबिल चीज को एक संशोधित रूप में प्रस्तृत किया था। माननीय गेदा सिंह जी ने कहा कि यदि यह श्राब्जेक्शनएबिल चीज इस रूप मे रखी जाती है तो संभवतः में उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाऊंगा। में इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं हूं किन्तु सदन श्रौर माननीय मंत्री महोदय इस क्लाज को इस रूप में रखेंगे तो शायद मै इसको मान लूंगा। जबिक मंत्री महोदय ने ग्रीर इस सदन ने उस धारा को संशोधित रूप में स्वीकार नहीं किया तो इसमें ग्राश्चर्य की क्या बात है कि वह ग्रपने पूराने भौर पहले स्टैन्ड पर वापस भ्रा गये जबकि भ्रापने उस भ्रा-जेक्शनएबिल धारा को परि-वर्तित रूप में नहीं माना तो फिर में अपना स्टैंड लेता हूं कि आप इस पूरी आ क्जेव्यानएबिल चीज को ही दूर कर दें। इसलिये जो भ्रापत्ति श्रौर श्राश्चर्य माननीय गेदा सिंह जी के संशोधन उपस्थित करने में दिखाया गया है वह में समझता हूं कि एक गलत बात है। माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने लेजिस्लेशन के सवाल में बहुत कुछ कहा ग्रौर कहा कि जहां तक हो सके लेजि-स्लेशन बनाते समय हमे बहुत दूर की बातों को देखना चाहिये श्रौर जितने श्रमेडमेट्स की श्रागे श्रावश्यकता पड़ सकती है उनको जहां तक हो सके फोरसी करके एक ही बिल मे रख दिया जाय तो अच्छा है। इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहुंगा क्योंकि यह ग्रवश्य उचित बात है कि किसी बिल मे, जहां तक हो सके ग्रमेंडमेंट कम से कम हों, किन्तु कहना और दावे के साथ कहना कि इस संशोधन स्रौर संशोधित विधेयक के बाद कभी पंचायत राज विधेयक में कोई भी संशोधन पेश नहीं किया जायगा,

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह] मंसमझता हूं किन तो मंत्री महोदय का ग्रौर न रामनरेश जी का यह कहने का इरादा था।

जहाँ तक पूरी धारा के हटाने का प्रक्त है में उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं हालांकि उन्होंने कुछ कारण बतलाये है ग्रौर में उनका साथ देता हूं एक सबसे ग्रधिक ग्रापत्ति जो मुझे है इस घारा में वह यह है कि इस घारा के द्वारा, स्वशासन मंत्री द्वारा यदि सदन स्वीकार करता है तो इस सदन द्वारा पंचायत राज के मूल सिद्धांत की ग्रवहेलना की जा रही है। बीच श्रौर जनता में पारस्परिक भरोसा श्रौर विश्वास पैदा करना ही पंचायत राज का मुल सिद्धांत है। मे यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता भविष्य में किसी पार्टी या दलबन्दी के कारण श्रपनी भलाई की चीज को ठुकरा जायगी। उधर से, एक दल की श्रोर से कुछ बाते की जा नी है। उधर से भी सिद्धांत के ग्रनुसार कुछ बाते की जाती है। मेने इधर का हूं न उबर का हूं और हालांकि में भ्रपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना भ्रवश्य कहूंगा कि में परतंत्र भी नहीं हुं इसलिये में यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हुं कि जनता ४-५ साल के प्रनुभव के बाद प्रपने हित की बात को ठुकरा देगी। हां जनता ने प्रपनी प्रच्छी ग्रौर बरी बाते देख ली है उसको ग्रगर भ्रवसर दिया जाय कि मिल जुल कर राय मशिवरा करने के बाद श्रपनी भलाई के लिये गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत बनाये तो जनता उनको नहीं बना पायेगी, तो मैं समझता हूं यह एक गलत बात होगी। इस संबंध में यह भी कहा गया कि यदि भविष्य के लिये यह स्वीकार किया जाय कि जनता ऐसा नहीं करेगी लेकिन यदि वह कर लेगी तो हमारा उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर विधेयक मे दिया हुआ है। जो कुछ मंत्री महोदय ने फोरसी कर रक्खा है। ऐसा होने पर जब कि गांव पंचायत या न्याय पंचायत को सस्पेड करने या डिजाल्व करने की श्रावश्यकता हो जायगी तो जो उपाय उन्होंने सोच रक्ला होगा वह उस पर क्यों लागू नहीं हो सकता है। यह तो अधिकार रक्खा हुआ है कि प्रेस्काइ ड श्रयारिटी जब वह उचित समझे उसको सस्पेड कर दे या डिजाल्व कर दे श्रीर डिजाल्व होने के बाद रिइलेक्शन होने की भ्रावश्यकता है लेकिन सस्पेंशन के बाद रिइलेक्शन नहीं होगा। रिजोल्यूशन श्रौर रिइलेक्शन के बीच में जो विधि उन्होंने सोच रक्खी होगी वह उस समय ऐसी परिस्थित में क्यों काम में नहीं लाई जा सकती। में यह नहीं समझ पाया कि इतने छोटे विषय पर इतनी बड़ी बहस क्यों की जा रही है प्रश्न बहुत सरल छौर छोटा सा है कि श्राया मंत्री महोदय इस प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को ग्रधिकार देना चाहते है ग्रौर यदि वे देना चाहते है तो श्रवश्य उसको श्रधिकार दिये जायं, मुझे इसमे कोई श्रापत्ति नहीं है। जब कि उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिये गये है तो इस छोटे से अधिकार को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु में उनमें यह कहुंगा कि यदि वह ग्रधिकार देना चाहते है तो वह खुल्लमखुल्ला कहे फिर उनको अधिकार दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनमें सबसे प्रमुख ब त यहाँ होगी और उसी को में केवल दोहराना चाहुंगा कि यदि प्रेस्क्रोइ ड ग्रयारिटी द्वारों नामजद किया जाता है तो यह स्वाभाविक है और यह एक ग्रवश्यम्भावी बात होगी कि जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्काइन्ड म्रयारिटी नामजद करेगी उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति न होगा बल्कि उस प्रेस्काइ ड प्रयारटी के प्रति होगा क्योंकि उस प्रेस्काइडड ग्रयारिटी ने उनको नामजद किया है। कभी भी, चाहे माननीय मंत्री जी जितना भी उस पर विक्वास भ्रौर भरोसा रखें, चाहे प्रेस्काइ ड क्रयारिटी कितना ही भरोसा रखे, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह कहना कि क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का या माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्काइब्डे क्रथारिटी का भरोसा उन पर है इसलिये स्वतः जनता का भी भरोसा उन पर होगा, मै समझता हूं कि सही नहीं है। जब कि इन व्यक्तियों की नियुक्त प्रेस्काइन्ड अथारिटी द्वारा की जा रही है यह एक गसत बात होगी स्रोर इसका यही परिणाम होगा कि वह बजाय जनता को स्रपने साथ रखने के, बजाय जनता की पुकार सुनने के, प्रेस्काइब्ड अथारिटी के संकेत देखेंगे और उनके इशारों के अनुसार, इचित या अनुचित. इस पर में अभी नहीं जाता, चलेंगे।

यह एक बड़ी ही गलत बात है श्रौर एक ऐसी गलत बात है जो कि पंचायत राज के मुल सिद्धांत पर चोट लगाती है क्योंकि एक ऐसे साधारण स्थान पर जब कि जनता १८ अविश्वास प्रगट किया जा रहा है तो फिर भविष्य में यह ग्राज्ञा करना कि इस ग्रविक्वास के बावजूद जनता प्रपने काम चलाने के कार्य को सीरिग्रसली लेगी, यह कैसे उम्मीद की जा सकती है जब कि इस भारा के द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं। अधिष्ठाता महोदय अधिक न कहकर में फिर यही ब्रापके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसे गेंदासिंह जी ने बताया कि पहले इस प्रकार की कोई घारा न थी श्रीर मैने जो प्रश्न उठाया कि सस्पेंशन के समय जो कार्यवाही की जायगी या जिस प्रकार काम चलाया जायगा, में समझता हूं ग्रौर में ग्राशा करता हं कि में गलत नहीं समझता कि उस प्रकार से भी ऐसी परिस्थित में किसी न किसी प्रकार काम चलाया जा सकता है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि यदि जनता इस पंचायत राज का महत्व न समझे तो उसको इस महत्व को समझाने की कोशिश बारम्बार करे। मै मानता हं कि पहले दफा ग्रगर न चुने जायं तो उनको एक बार किर ग्रवसर दिया जा रहा है। में कहता है कि ग्रगर एक दफाँ श्रवसर देने पर भी नहीं चुन पाते तो उनको साफ साफ यह बता दिया जाय कि यह एक ऐसी शक्ति हमने जनता के हाथ में दी थी जिसका उन्होंने प्रयोग करना उचित ग्रौर ग्रावश्यक न समझा इसलिये एक विशेष जनता को ग्रभी इस पंचायत राज के एक्सपेरिमेंट के भ्रयोग्य वह समझती है और इसलिये उसके हाथ में यह भ्रधिकार ग्रभी वह नहीं देगी। यह करना बेहतर होगा बनिस्त इसके कि भ्रपने नियुक्त किये हुए व्यक्तियों द्वारा वहां पर इस प्रजातंत्र राज्य के भीतर पंचायत राज का एक फाल्स स्वरूप रखा जाय।

श्री रामलखन मिश्र--में प्रस्ताव करता हूं कि ग्रब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

स्रिधिष्ठाता--प्रक्त यह है कि माननीय गेंवासिंह जी के संशोधन पर वादिववाद सम्राप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री गेदासिह—माननीय ग्रिधिष्ठाता महोदय, में सबसे पहले तो माननीय रामनरेश जी की इस बात को मान लूंगा जो उन्होंने यह कहा कि बहुत ध्यान से इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन में यह भी उनसे कहूंगा कि जो दोश मेंने किया है उससे वह भी खाली नहीं है कुछ श्रौर सम्मानित सदस्यों ने भी जिनकी बुजुर्गी ग्रौर बुद्धि पर हम भी भरोसा करते है, उन्होंने भी शायद इस धारा को, जिस को निकाल देने को कहते है, पढ़ा नहीं।

ग्रधिष्ठाता महोदय, इसमें लिखा हुग्रा है:--

"Where as prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full numbber of remaining members it shall be law ful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected"

(इसके बाद सदन ५ ब े श्रगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनःगर, सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : मई, १६५४।

नत्थी 'क' 'देखिये नाराकिन प्रक्ष्त ४ का उत्तर पीछे, पृष्ठ ८ पर ।)

त्रस-	पद	वेतन-कम 	पद स द्य
5	डिप्टर डाय <i>ेक्टर</i> , तराई स्टेटफार्स	₹0	?
5	महायक कृषि इजोनियर	रु० २५०-२५-४००-प्र० ग्र ०-३०- ७००-५०-६५०	१
3	एक्रउन्ट्स ब्राफियर		9
6	ग्रेग्रोक्न्चरल ग्राफिसर	र० २५०-२५-४०० - प्र०ग्र०-३०- ७००-५०-द५०	3
×	में:नियर एप्रोकल्चरल इस्रेक्टर	₹० २१०-१५-३५०	Ę
£	ए प्रोकल्चरल इंस्वेक्टर	₹0 १२0-६-२१0-१0-२५0	१८
و	महायक एप्रोकत्चरस इंस्पेक्टर	रु० ७५-५-१२०	, 8,3
=	एकाउन्टेट	₹० १ ५० –१०–३५०	3
3	कॅशियर	₹0 50-1-180	₹
۶.	नोटर ड्राफ्टर	₹0 50-1-100-1-130	Ŕ
કે કે	क्लर्क	₹0 €0-3-€0-6-880	j j
१२	चोकीदार	रु० २०-१/२-२ ५	5
१३	ं यून	"	११
१४	ड्राइवर	₹0 ४५-२-६५-३- =0	१०
	क्लोनर	₹0 २0-१/२-२×	3
	स्टोर कीपर	₹0 8x-2-6x-3-50	२
	मईस	₹0 २0-१/२२×	Ę
	डाक रनर		રે
-	ब्लेक् स्मिथ	रु० ३०-२-४०-प्र० म्र०-२-५०	રે
70	भाग्येटर	n	<u>ب</u>
		योग	१३६
		ट्रैक्टर स्टाफ	
၁ ခု	टक्टर मॅकेनिक	क्० १२०-६-२१०-१०-२५०	
ככ	दंक्टर ग्रापरेटर	€0 =0-X-650	ሂ
マヨ	क्लुकं	£0 £0-3-60-8-660	४ ४
₹ 8	ट्रॅक्टर क्लीनर	€0 &X-3-€0	. ۶
υų	फीरमैन मैकेनिक	रु० २००-१५-३५०	३० २
		—— योग	~= ≈३
-		कुल योग	२१६

नत्थी 'खं' (इंक्रिये ताराकिन प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर १)

र्द्ध पारलंडेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१६५४) के ६वे सोमवार के लिए पूछे गये नारांकित प्रश्न ११ के उत्तर से प्रवंगित सूची ३१ दिसम्बर, १६५३ तक भ्दान यज से दान की गई भूमि का जिलेवार विवरण

क्रन मंख्या		४ मार्च, १६४३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों मे)	६ मार्च, १९५३ से ३१ दिनम्बर, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकडों मे)	दान को गयी भूमि का कुल योग (एकडों मे)
ş.	२	₹	8	<u>ل</u> ا
	 बलिया	 キャ・キュ		£8.93¥
२	हरदोई	१४२६.२६	१७२ ४३	१६०१.७२
3	ग्रःजमगढ <u>़</u>	७३२.०६	२ ७८	७३४.८७
દ	मॅनपुरी	४७४.२५	२४५ ७८	७२०.०३
ሂ	बुलन्दशहर	१५०५.००	६८४३.०	८३४८.००
Ę	शाहजहापुर	७३.३४७	••	<i>७४</i> ह. ५७
હ	इटावा	६१७.६३	६० २८	१७०७.१
5	बांदा	80,000.00	₹,०००.००	63,000.00
ŝ	देहरादून	७०१.८२	"	७०१.८२
१०	बरेली	१४६.२२	३४६.८१	₹0.338
8 8	बहराइच	३०५६.१६	30.€⊌≎	३३४६ २=
१२	फतेहपुर	१४.५४३	१६६४.४०	१११४७.३५
१३	जासौन	११४५२.११	••	११४५२.११
१४	ग्रलीगढ़	१६१५.४६	₹€२.१=	२३०७.६४
१५	मेरट	२६६.३७	१७१ ६१	४४१.२८
१६	फर्रुखाबाद	<i>છ</i> છ.૪૩	१०३.७	७७.७३१
१७	हमीरपुर	१७६.३३	••	०६.३३३४१
१८	सुन्तानपुर	••	८७.१७	५७.१७
38	बनारम	३७.१ २ ४७	३४.३४	७६१६.१३
२ ०	जौनपुर	१७५३.१२	५०६२.८८	६८१६.०
२ १	ग्रागरा	४५१.८६	१६०.३७	६११.६९
२२	गाजीपुर	७६.०	६२.३७	१६८.३७
२३	मुत्रपक्ष रनग	ार २४०.८५	••	२४०.५४

ऋम- संख्या	জিলা	प्रमार्च, १६५३ तक दान का गयी भूमि का क्षेत्र फल (एकड़ों में)	६ मार्च, १६५३ से ३१ िसम्बर, १६५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (उकड़ों में)	दान की गयी भूमि का जुल योग (एकड़ों मे)
	2	3	8	¥
⊃ & ⊃ &	मथुरा	<u> ७</u> =	२१.२४	\$8.33
		१५३६.४१	१०५.५३	. १६४१.७६
२४	झांनी	00.038\$	••	१४६०.७०
₽€	न बनऊ	••	••	••
२७	इलाह्राबाद	२६२०६.०६	१६.३=	२६२२५ ४४
२=	गोंडा	६५२१.६८	३०६.६६	६ ६ २ ६ . ३४
२६	नं नीतःल	••	••	••
30	मिर्जापुर	१२५५५.०	५५५६.०	१८४११.०
३१	सीतापुर	१२६१.६=	१४०.००	१४३१.६८
३२	रायबरेली	२३०२४.५१	53. <i>6</i> 8	₹₹₹₹.४४
३३	खेरी	१७५५.११	२६६.३४	२०२१.४६
<i>38</i>	प्रतापगढ़	७१६५.≂२	••	७१६५.5२
३४	गोरखपुर	५३.१६	••	५३.१६
3 &	बस्ती	४१७.२=	१.३०	४१८.५८
३७	कानपुर	१२४००.००	۷۷.00	१२४५५.००
३८	बाराबंकी	१६२६.००	२१०.३१	१८३६.८८
38	बदायूं	२०३.६२	ah	२०३, ६२
80	मुरादाबाद	५४८.५१	४९५६.५२	¥¥0¥.03 _.
,6 \$	सहारनपुर	२६७८.१०	२४.३४	२७०३.४४
४२	एटा -	३१७१.५७	३१८.३६	₹४5.8€
<i>ጹ\$</i>	बिजनौर	२८४६.००	१४.००	२८६०.००
ጸ ጲ	पीलीभीत	६६२८.३१	••	६६२८.३१
ጸጸ	देवरिया	२००.५२	२.४ २	२०२.६४
<u>የ</u> ደ	उन्नाव	34E0.0	६६४.०	४४४४.०
४७	फे जाबाद	० ७.४ थथ 🕫	\$6.00	२७६४.७०
ጸ።	रामपुर	१०१.६=	• ••	१०१.६८
38	म्रल्मोड़ा	_		
ሂ የ ሂ၀	गढ़वाल टेह्री-गढ़वःस	, }	सूचना उपलब्ध नहीं है।	

नत्थी 'ख (१)'

(देखिये तारांकित प्रक्त १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर।)

श्री झारखंडेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१६५४) के ६वें सोमवार के लिए पूछे गय तारांकित प्रक्त संख्या १२ के उत्तर में प्रसंगित सूची

३१ दितम्बर, १९५३ तक भूदान यज्ञ में वितरित की गयी भूमि का जिलेवार विवरण

कम- संख्या	- जिला	उस भूमि का क्षेत्र- फल (एकड़ों में) जो ४ मार्च, १६५३ तक दान में प्राप्त हुई थी ग्रोर जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षे फल (एकड़ों मे जो ४ मार्च, १६ के बाद ग्रॉर ३१ दिसम्बर, १६४ तक दान मे प्राप हुई थी ग्रौर जि वितरण भी हो चुका है) वितरित १३ भूमि का १ कुल योग ३ (एकड़ों व्त में)	उन परि- वारों की संस्या जिनको भूमि चितरित हुई
8	२	₹	R	¥	Ę
5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	बलिया हरदोई ग्राजमगढ़ मंनपुरी बुलन्दशहर शाहजहांपुर इटावा बाँदा देहरादून बरली बहराइच फतहपुर जालीन ग्रलीगढ़	\$ = \cdot \c		\$ = \$.\$ = \$.\$ = \$.\$ = \$.\$ = \$.\$ = \$.\$ = \$.\$ & \$.	
* 9 5 6 0 * 8 8 8 8	फर्रुखाबाद हमीरपुर सुल्तानपुर बनारस जौनपुर	२४३.० ४८ <i>५.७७.</i> ४१ १८७.४१	 = ७.१७ १०.१२	 ६९७७.४१ =७.१७ ३७६ २४३.०	 १७०२ ६१ ३७६ २४०
	श्रागरा गाजीपुर	११३.० ५२.०	१२६.६२ १६.६	२४ २. ६२ ६८.६	११२ ३२१

क्रम मंख्या		उस भूमि का क्षेत्र- फल (एकड़ों में) जो ४ मार्च, १६४३ तक दान मे प्र.प्त हुई थी श्रौर जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षेत- फल (एकड़ों में) जो प्र माच, १६५३ के बाद ग्रीर ३१ दिसम्बर, १६५३ त त्र दान में प्राप्त हुई थी ग्रीर जिसका विक्षरण भी हो चुका है	वितरित भूमि का कुल योग (एवःड्रों ने)	वारों की
१	₹	Ę	8	ሂ	Ę
२३	मुजफ्फरनगर		***		
२४	मथुरा	६०.५२	••	६०.५२	ሂሂ
ગ્ય	झांसी	••	••	4-7-4	77
3 C	लखनऊ	••	••	••	
२७	इलाहाबाद	६१५.४२		६१५.४२	30€
२५	गोंडा	*1****	••	4 (2.0 4	406
38	नैनोताल	••	••	••	
30	मिर्नापुर	१६५६.०	 ४७.०	 २०३६.०	५७२
3 €	सीतापुर		•	\	१४१२
32	रायबरेली	४४०१.१२५	**	४४०१.१२५	२०३
33	खेरी	२२७.०	••	२२७.०	(- (
58	प्रतापगढ्	••	••		
31	गोरखपुर	••	**	••	४६६
₹ ६	बस्ती	२०२.६७	१-३०	२०३.६७	६७८
३७	कानपुर	२१७६.५०	٧.0	२१८१.५०	•
35	बाराबंकी	••	••	••	
38	बदायूं	१२.४७	•	१२.४७	x
&o	मुरादाबाद	••	••		
८ १	सहारनपुर	88.60	४१.८४	द६.द१	द ३
४२	एटा	११.0	••	११.0	Ę
४३	विजनीर	**	••	••	
ዲጸ	पीलीभीत	••	••	••	
8 X	देव रिया	४२-१८	२.४२	४४.६०	२०
४ ६	তন্মা ৰ	<i>६७</i>	አ ጾ	१२१	१६१
४७ ४८	फेजाबाद राजार	२२२	••	२२२	१७२
38 38	रामपुर	••	**	**	
४०	श्रल्मोड़ा गुरुवान	1	~~~~~		
४१	गढ़वाल <i>देवरी-गळ्</i> या		सूचना उपलब्ध नहीं	ह ।	
45	टेहरी-गढ़वाल	ι,			

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर :) उत्तर प्रदेश सरकार

माल (ख) विभाग

सं० ५३४०/-१सी--६३०-सी-५३ लखनऊ, २३ फरवरी, १६५४ ई०

विज्ञप्ति

य० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ (यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १६०१) की घारा ११ की उपधारा (२) द्वारा प्रवत्त ग्रधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित गांवों के फैजाबाद जिले से ग्राजमगढ़ के जिले को ग्रौर ग्राजमगढ़ जिले से फैजाबाद के जिले को संकामण (transfer) का ग्रादेश देते ह, किन्त प्रतिबन्ध यह है कि इसमें उल्लिखित किसी बात से किन्हीं ऐसी ग्रधिक कार्यवाहियों (ligal proceedings) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस विज्ञप्ति के दिनांक पर किसी ऐसे माल के न्यायालय में विचाराधीन हों जो ग्रब तक इन गांवों के सम्बन्ध में ग्रधिक्षेत्र का प्रयोग करता रहा हो।

7637 — IT	ांव का नाम	क्षेत्रफल	तहसील	जिला	कमिश्नरी	तहसील	जिला ः	 क्रमिश्नरी
नस — । संख्या	ाय का नाम	क्षत्रफल (एकड़ों मे) जिसर	ते संक्र मित	किया गया	जिसको	संक्रामित (कया गया
१	ग्रोरिल	१,८७१	ग्रकबरपुर	फैजाबाद	फैजाबाद	फूलपुर	ग्राजमगढ़	गोरखपुर
7	रम्मोपुर	७०६	"	"	"	11	72	"
3	चक लहसुग्रा	२६	"	77	11	"	11	"
४	चक चिकया	११६	"	"	**	11	11	,,
ሂ	चक दुलहा	३	"	**	"	11	11	11
Ę	चक दुलहिन	१	17	77	27	7.7	"	11
৩	देवदिह	४१८	22	"	"	1)	,,	"
5	चक किरता	२२	"	"	"	•,	17	"
3	मुही उद्दीनपुर	308	77	"	"	***	"	"
१०	रुधौली ग्रदाई		फुलपुर ह					
११	रुधौली माफी		"	"	n	"	"	"

ग्राज्ञा से,

जहूरल हसन, सोचव।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित	प्रका ३५ का उत्तर व	तिछे पष्ठ१७ प	र ।
जिला मुजप्फरनगर में जिसको	जितनी तकावी दैक्टर	र के खरीदने	के लिये ग्रा
तक दी गई है उसकी सूची:			
१६४८–४६			হ ০
१—श्री दीवान इकबाल नाथ	• •		28,000
\$ E & E — X 0	• •	• •	(-,
२श्री भजन सिंह			80,000
३—श्री इन्द्र प्रकाश			₹0,000
४—श्री महेश बाल	• •		20,000
५—श्री हरद्वारी सिंह			₹0,000
६—श्री इनायत ग्रली खां			20,000
७—श्री कुंवर स्रसगर म्रली खां		• •	१०,०००
द—श्री हरि रतन स्वरूप	• •		80,000
६श्री चन्द्र प्रकाश		• •	१०,०००
१०श्री जहर हैदर	• •	• •	9,000
११श्री एमे॰ रहमान	•	• •	¥,000
१६४०-४१	•	• •	2,000
१२श्री संयद मुरतजा	• •		१०,०००
१३—श्री प्रेम सिंह			१०,०००
१४श्री ग्रब्दुल कासिम			5,000
१५श्री रतनलाल	• •	• •	20,000
१६श्री करम पाल सिंह	• •	• •	9,000
१७—श्री मुस्तार सिंह	• •	, .	9,000
१८—श्री चुन्नी सिंह	• •	• •	१०,०००
१६श्री डेरावाल कलेक्टिव फार्म	• •		20,000
२०श्री विश्वम्भर दास	• •	• •	20,000
१९५१—५२		• •	(0)000
२१श्री बलवन्त सिंह	• •		१०,०००
२२—श्री तुंगल सिंह	• •	• •	<u>لا</u> ,٥٥٥
२३श्री इयामलाले	• •	• •	१०,०००
२४—श्री जगजीत सिंह	• •	• •	१०,०००
२५—श्री माघो प्रसाद	• •	• •	5,000
२६—श्री ग्रतर सिंह	• •	• •	5,000
२७—श्री सिसोना कोग्रापरेटिव कार्म	• •	• •	१०,०००
२८—श्री बलजीत सिंह	• •	••	₹,000
२६—श्री बृजभूषण प्रकाश	• •	•	१०,०००
३०—श्री धर्मवीर सिंह	• •		ج,ooo
३१—श्री ग्रमर सिह	• •	• •	न,००० ह
१६ ५२–५३		, ,	4,000
३२—श्री पन्नाल ल			9 00 005
\$ <i>E</i> ¥ <i>3</i> —X&		• •	१,००,०००
३३—श्री उदिवाली कोग्रापरेटिव फार्म	• •	_	12
३४श्री गुलाम मुस्तफा	• •	• •	¥,000
३५ —श्री हसन महिदी	• •	• •	¥,000
३६श्री लक्ष्मी सरन	• •	4 -	¥,000
		• •	¥, 000

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर।)

जिन लोगों से सन् १९४० में कोटद्वारा हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में रूपया जमा कराया गया था उनकी सूची:—

		ব৹
१—केटेन गबर सिंह, सोल्जर्स बोर्ड, लेसडाउन		
The state of the s	• •	१००
२श्री धन सिंह, कन्ट्रैक्टर, फारेस्ट डिवीजन	• •	Xoo
३—श्री कीरत सिंह सूबेदार, शिबूनगर	• •	१००
४—श्री चन्द्र सिंह रावत, वकील, पौड़ी	• •	₹ ₹
५—सूबेदार मेजर श्री सुदामा सिंह, मेरुवा सिला	• •	१,०५०
६—श्री दौलतराम, फौरेस्ट कन्ट्रैक्टर, सकालो सिला	• •	२००
७—श्री रामप्रसाद काला, रुद्रप्रयाग	• •	०१६
द—श्री लाला श्यामलाल, कोटद्वारा	• •	२००
६—गढ़वाल मोटर भ्रोनर्स यूनियन, कोटद्वारा	• •	90
१०—केप्टेन इन्द्र सिंह, सतीचौर	• •	५७
११—श्री बुद्धि बल्लभ भदोला, लैन्सडाउन	• •	१८०
१२—श्री सोवन सिंह, कोटद्वारा		२३०
१३—श्री कुन्दन सिंह गुसाईं, वकील, लैन्स डाउन	• •	१५०
१४—िशवराजपुर सोसाइटी	• •	१२०
१५—श्री मनोहर सिंह, ग्राम पदमपुर	• •	२००
१६—श्री वार्नासह विष्ट, शिबूनगर	• •	१३०
१७—श्री कीमत सिंह, ग्राम नीबूचौर मोटाढांक	• •	१२४
१५—श्री त्रिलोकॉसह, ग्राम शिवराजपुर मोटा ढांक	• •	१५०
१६कर्नल लक्ष्मण सिंह भार्फत कैप्टेन गबर सिंह, लैन्सडाउन	• •	१०५
२०श्री मुरलीधर कुकरेती		१५०
२१—श्री नन्दन प्रसाद	• •	344
२२-श्री बद्रीदल, नन्दपुर मोटाडढंक	• •	१३०
२३श्री ग्रमरदत्त पोखरिया, कोटद्वारा	• •	ХŞ
२४देवरामपुर सोसाइटी कोटद्वारा द्वारा त्रिलोक सिंह		२०
२४—श्री विश्वन सिंह रावत, कोटद्वारा	• •	१०
२६—श्री ठगराम, कोटद्वारा	• •	ሂዕ
२७श्री जैदेव प्रसाद वुकानदार, कोटद्वारा	• •	50
२६—कैप्टेन मान सिंह, ग्राम नगरासू	• •	Ę¥
२६—रामारि सोसाइटी	* *	37
		· -

= ?	विघान सभा		[३ मई, १	{ E
				₹₀
३०—श्री लक्ष्मणॉसह सोरग्रोह ल	ालपानी सनेह	• •		४७
३१—श्री जैदेव ग्राम शिवराजपुर	: मोटाढांक	• •		ሂሂ
३२—श्री योगेदवर प्रसाद बहुखंडी	• •	• •		२०
३३—श्री कुंवरसिंह रावत, विशनपु	_] र	• •		४०
३४—श्री रामप्रसाद नौटियाल, ग्र		• •		१०
३५—श्री राघेलाल दुकानदार कोट	द्वारा	• •		२००
३६—श्री भवानी सिंह रावत, ग्राम	•			* 8
३७—श्री मोहनसिंह रावत, ग्राम	•	• •		५२
३८—श्रीमती कुंवारी देवी, ग्राम	नन्दपुर	• •		२०
३६श्री कृपाराम मुस्तार, ग्रार		• •		४५
४०-श्री इन्द्रमणि, लोकमनीपुर	हत्दूखाता	• •		ሂ ፡
४१—श्री खुबल सिंह, ग्राम पव	मपुर सुखरौ	• •		१५
४२-धी बन्सीराम; लेंसडाउन	• •	• • •		१६५
४३—श्री ला० महाबीर प्रसाद,	कोटद्वारा	• •		50
४४श्री उमराव सिंह चौघरी, रा	•	• •		χo
४५-श्री हरदेव सिंह, दुकानदार	कोटद्वारा	• •	!	१५०
४६—श्री घासीराम कोटद्वारा	• •	• •		२६०
•		• •		- >-
	योग	• •	Ę,;	२७४

,

नत्थी 'च' (देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पूष्ठ २२ पर) प्रश्न संख्या ४४ से संबंधित सूची

ऋम- संख्या	टेस्ट वर्क का नाम	कार्य प्रारम्भ को तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल मजदूरों की संख्या	कार्यःसमा का व	
 १ २	पटेहरवा-जरमऊ र तमकोही-सिसवा	तोड ६-७-४३	१४-७-५३	* 1	मजदूरों का	ग्रभाव
•	नहर रोड	५ –७–५३	१२ -१ २-५३	५१, ५६५	मिट्टी भ काम पूरा	
Ę	पिपरा घाट-साहब	•			•	
_	गंज रोड	२६ -5-५३	११-१२-५३	४३,१२१	"	,,
४	रुद्रपुर-बरहज रोड	१ –६–५३	६-१०- ४३	• •	मजदूरों के प्र	ाभाव से
ሂ	तमकोही-सलेमगढ़-		-		**	
	सुजान रोड		-x3 ११—३x	४ ६२,१७२	रबी की फ कटाई का श्रमिकों कृषि कार्यः कोपार्जन	। समय के लिये में जीवि- करने का
_					पर्याप्त ग्रव	।सरया।
Ę	बेदपुर-साहबगंज- तमकोही रोड	७-१-५४	११ –३ –५४	£2,७७=	"	"
ی	सिरसिया पुल से नौतनवांबजार रोव	5 €−२− ४ ४	₹- ३ -५	१२,⊏२३	"	11

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर ।) प्रश्न संख्या ७१ से सम्बन्धित सूची

सूची गांव तहसील शाहाबाद जिनमें म्रोला पड़ा

本 H-	郊 中一
संख्या ग्राम का नाम	संख्या ग्राम का नाम
१ शेखूपुरा	३६ गदमर पट्टी टीका सिंह
१ शेब्रूपुरा २ मोतीपुरा	३७ रवानी पट्टी जवाहर
३ सुहाना,	३८ भगवतीपुर
४ ट.डा	३६ गहुखुलापुर
५ मिल्क सुरखेड़ा	४० परौता
६ तुरखेड़ा	४१ पचतौर
७ महूनागर	४२ किरा
< चन्दूपुर सालिस	४३ रेवड़ी कलां
६ गजरंला	४४ रेवड़ी खुदं
१० वीरपुर	४४ उदयपुर
११ रमपुर	४६ मनसूबपुर
१२ मुहलिया	४७ पीपल वाला
१३ खनूपुरा	४८ श्रसालतपुर
१४ भगवन्तपुर	४६ मङ्यान बुघपुर
१५ ताल्बाबाद	५० ढ़ीलसर
१६ दुकरिया _	५१ मीरामपुर
१७ परबतपुर नगरिया	४२ गुलड़िया खुर्द
१= भिलक काजी	४३ भौपतपुर
१६ ककरोवा	४४ गंगापुर गरबी
२० बन्दार	४५ स्रहमदनगर
२१ रसूलपुर	४६ मोहम्मदपुर उर्फ नया गांव
२२ चतरपुर	५७ ढ़िकया
२३ नन्दर्गाव	४८ नसुरतनगर
२४ अंचा गांव	४६ नादरगंज
१ चुकरपुर भूड़ा	६० खंजीपुरा
६ भौपतपुर रायपुर	६१ नवाब नगर
७ जगसर	६२ वस्तमनगर
द नबी गांव	६३ यूसुफनगर
६ याकूबगंज	६४ मदकर
॰ ईशा खेड़ा	६५ गैनी
१ कूप	६६ ठिरिया
२ शहदरा	६७ खदेली
३ पंगम्बरपुरा	६८ लोबीपुर
४ गदमर पट्टी मोतीसिह	६८ घंकाशी
८ रहवानी पट्टी उदा	

नत्थियां

नत्थी 'ज' (देखिये तारांकित प्रश्न ७६ व ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर ।)

जौनपुर जिले के बाढ़-पीड़ित गांवों की सूची, जिनमें गृह निर्माण योजना के ग्रन्तर्गत सहायता दी गई

षम- संख्या			गिरे हुये मकानों की संख्या	धन जो रूप में			घन जो रूप में		
१	२		₹		४		\	۷.	
				₹०	म्रा० '	ग०	₹ ০	म्राo	पा०
	तहसीलजौ	नपुर							
ş	रामदयालगंज		२	३०	0	0	१००	•	0
२	जौनपुर	•	. 9	१५०	0	0			
₹	हरीरामपुर		२०		• •		३७४	0	0
8	गढ़हा सेनी	• •	<u>ጻ</u> ሂ				9860	0	0
ሂ	ककोहिया		१७				१२५	0	0
Ę	बिशुनपुर	• •	१३		• •		₹००	0	0
ف	खम पुर	• •	२३		• •		キモメ	0	0
5	घोरहा		u		• •		१७५	0	0
3	लेधवा		₹		• •		७४	0	0
१०	पोखरियापुर		ጸ		• •		१००	0	0
११	मसीदा ु		२				४०	0	0
१२	ग्रहमदपुर		ঙ				१७५	0	0
१३	सेखवारा		Ę				१२५	0	٥
१४	श्रासमान पट्टी		३०				४२४	0	0
१५	मल्हनी		• •		• •		२४	0	0
	योग	• •		१८०	0	0	३,७७४	0	٥
	तहसील-मद	दलीश	<u>ह</u> र						
१६	ग्रचकरी		२६	२७०	0	0		• •	
१७	बेकापुर		१३	१७०	0	0		• •	
१८	केवटली	• •	१३ १	२७०	0	0		• •	
38	चांदपुर		१२१	460	0	0		• •	
२०	सकरा	• •	६८	२००	•	0		• •	
	योग	ī	• •	१,५००	0	•		• •	

कम- संख्या	नाम ग्राम	गिरे हुए मकानों की संख्या	धन जो तकावी के रूप में दिया गया		धन जो दान के रूप में दिया गया	
?	२	ą	Y			
	तहसील-शाहगं	ज	रु०	श्रा०	पा०	र० आ ० पा
२१	सम्मनपुर •	, १०	₹o	0	0	• •
२२	यहियापुर •	१३	033	0	0	• •
२३	मादी •	, १	४०	0	0	• •
२४	लखमापुर		४०	0	0	• •
२५	गोरीला •	. {	२४	0	0	• •
२६	भ्रदनाथपुर •	१ . १	४०	0	0	• •
२७	कौरिया (कस्बा शाहर		२५	0	•	• •
२५	गोपालापुर	G	४००	0	0	• •
२६	ताखा मशरिक	₹	२००	0	0	• •
	योग	•	२,४००	0	0	• •
	तहसील—केराव	त				
	३० बिझवर सागर	११५	७२४	0	0	• •
		• •	७२५	0	0	• •
	कुल योगः	•	४,६०५	•	<i>y,</i>	७० ४००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।) प्रश्न संख्या ७६ से संबंधित सूची

लखनऊ तहसील के ग्रामों की सूची

- १---चेला
- ३--- दाऊंदनगर
- ४----श्रलीनगर
- ५--सरसवां
- ६---दुग्गौर
- ७—कुँलुवा गांडा
- द-मेंबद्मपुर
- ६---उजरियाव
- १०--मलेसेमऊ
- ११---श्रहमनमऊ ,
- १२-सरोरा
- १३---श्ररदोनामऊ
- १४--बाघामऊ
- १५--चंदियामऊ
- १६--गाजीपुर बलराम
- १७--- रूपपेर खदरा
- १८---लौहिरामऊ
- १६—जेहटा]
- २०-सैथा
- २१--बरावन कलां
- २२--बरावन खुर्व
- २३---गजराहार
- २४-वरीकलां
- २५--ग्राराजी महताबबाग
- २६---जियामऊ

मलिहाबाद तहसील के ग्रामों की सूची

- १--सुल्तानपुर
- २--- अकड़रिया कलां
- ३---बुघरा
- ४---जमखनवां

नत्थी 'ङा'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

श्रौद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार श्रथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गृह बनाये गये है श्रौर इसके पश्चात् भी बनाये जायेंगे ;

ग्रौर यह ग्रावश्यक है कि ऐसे गृहों के प्रशासन ग्रौर प्रबन्ध के लिए प्राधिकारियों की व्यवस्था की जाय ग्रौर उसे संस्थापित किया जाय,

म्रतएव एतव्हारा निम्नलिखित म्रिधिनियम बनाया जाता है--

ग्रध्याय १

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार श्रोर प्रारम्भ

- १—(१) यह म्रधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक गृह-व्यवस्था म्रधिनियम, १६५४ कहलायेगा ।
 - (२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (३) यह उन क्षेत्रों में श्रौर उस दिनांक से प्रचलित होगा जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित करे।

परिभाषाएं

में—

- २-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस म्रिधिनियम
 - (क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य धारा ; क के ब्राधीन संगठित परामर्श समिति से हैं ;
 - (ख) "प्रवेशना" (allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा प्रथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रथवा उनकी ग्रोर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग ग्रोर ग्रध्यासन (occupation) के ग्रधिकार प्रवान से है किन्तु इसके ग्रन्तर्गत पट्टे (lease) द्वारा प्रवान नहीं है;
- (ग) "गृह" का तात्पर्य धारा ३ की उपघारा (१) में ग्रभिदिष्ट गृह से है ग्रौर इसके ग्रन्तर्गत उसका कोई भाग ग्रौर निम्नलिखित भी है:
 - (१) कोई बाग्र भूमि श्रयवा बाहरी घर (out houses) जो इस गृह से संलग्न हों,
 - (२) राज्य सरकार ग्रथवा स्थानीय प्राधिकारी ग्रथवा गृह श्रायुक्त द्वारा गृह में प्रयोग के लिए दिया हुन्ना उपस्कर (furniture);
 - (३) ऐसे गृह में लगी हुई कोई फिटिंग जो उसके ग्रधिक लाभप्रद उपभोग के लिये हो ;
- (घ) "गृह-म्रायुक्त" (Housing Commissioner), "गृह-उपायुक्त" (Deputy Housing Commissioner), "सहायक गृह मायुक्त" (Assistant Housing Commissioner) का

तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उक्त अधिकारियों से हैं;

- (ड) "स्रौद्योगिक श्रमिक" का तात्पर्य फक्ट गेज ऐक्ट, १६४८ में परिभाषित शब्द worker से हैं;
- (च) "नियत" का तात्पर्य इस म्रिधिनियम के प्रधीन बने नियमो द्वारा नियत से है;
- (छ) "िकराये" का तात्पर्य गृह के उपभोग ग्र ध्यासन के लिए प्रदेशना गृहीता (allottee) ग्रथवा ग्रन्य किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से है, ग्रौर
- (ज) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।
- ३—(१) यह म्रिधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त भौद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Industrial Housing Scheme) [जिसे यहां पर म्रागे चल कर राजसहायता प्राप्त मौद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Subsidised Industrial Hou ing Scheme) कहा गया है।] म्रथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को म्रन्य किसी योजना के म्रधीन जो गज्जट मे इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, म्र द्यौगिक श्रमिकों के म्रध्यासन के निमित्त राज्य सरकार म्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निमित गृहों पर प्रवृत होगा।
- (२) राज्य सरकार स नय-समय पर सरकारी गजट मे प्रख्यापन प्रकाशित करके उन नगरों के नाम सिंहत जहां वह ृह स्थित हों, उन गृहों को निर्दिष्ट करेगी ग्रौर ऐसा प्रख्यापन इस बात का निर्णायक साक्ष्य (Conclusive evidence) होगा कि ऐसे गृह राज्य सरकार ग्रथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो ग्रौद्योगिक श्रिकों के ग्रध्यासन के हेतु राज्य सहायता प्राप्त ग्रौद्योगिक गृह-व्यवस्था यो जना के ग्रधीन बनाये गये थे।
- ४——(१) राज्य सरकार सरकारी गजट मे विज्ञप्ति प्रकाशित करके गृह श्रायुक्त की नियुक्ति करेगी।

गृह ग्रयुक्त

- (२) गृह भ्रायुक्त (Housing Commissioner) एकल निगम (Corporation Sole) होगा जो गृह भ्रायुक्त, उत्तर प्रदेश कहलायेगा, उसका सतत श्रनुक्रम (perpetual Succession) होगा, उसकी भ्रधिकारिक मुद्रा (Official Seal) होगी; वह भ्रपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, श्रीर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।
- ५—(१) राज्य सरकार इस ग्रधिनियम के कार्य के प्रशासन, पर्वत्रेक्षण ग्रौर सम्पादन के हेतु एक या एक से ग्रधिक उप-गृह-ग्रायुक्त, सहायक गृह-ग्रायुक्त तथा ग्रन्य पदाधिकारी ग्रौर कर्मचारी, जैसा वह ग्रावश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।
- (२) उपगृह-म्रायुक्त तथा सहायक गृह-म्रायुक्त राज्य सरकार क सामान्य नियंत्रण में तथा गृह-म्रायुक्त के म्रावेशों के म्रधीन गृह-म्रायुक्त के किसी भी कर्लंक्य को कर सकेंगे तथा मधिकार का प्रयोग कर सकेंगे म्रीर ऐसे कर्लंब्य करते सबद म्रथवा मधिकार प्रयोग करते समय उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन्हीं वायित्वों से म्राबद्ध होगा जो गृह म्रायुक्त के हैं।

इडियन पीनल कोड की धारा २१ के प्रधीन गृह् फ्राउंक्त तथा अन्य प्रधिकारी पब्लिक सर्वेन्ट (जनसेवक) होगे। गृह—ग्रायुक्त

६—गृह म्रायुक्त तथा धारा ५ की उपधारा (१) के म्रघीन नियुक्त म्रन्य म्रधिकारी प्रथवा सेवक इंडियन पीनल कोड की घारा २१ के म्रर्थ मे पिल्लक मर्वेन्ट (जनसेवक) समझे जायेगे।

- ७—नाज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, गृह-ब्रायुक्त गृहों के प्रदेशना उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों से अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उत्तरदायी हीगा।
- परामर्ग समिति

के क्लंब्य।

- ट—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट मे विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस प्रधितयम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों मे परामशे के हेतु, जिन्हे राज्य सरकार प्रथवा गृह ब्रायुक्त उसके परामशे के लिये ब्रिभिदिष्ट करे, परामशे समिति संगठित कर सकती है।
- (२) परामर्श समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगे। सभापति महित उनकी मख्या ७ से ग्राधिक न होगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि परामर्श समिति मे कम से कम एक सदस्य स्रोद्योगिक श्रमिकों का तथा एक उनके नियोजकों (Employers) का प्रतिनिधि स्रवश्य होगा।

- (३) परामशं समिति के सभापित की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।
- ६---इस ग्रधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस ग्रधिनियम में ग्रन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के ग्रपने ग्रनिष्ठित ग्रध्यासन में समझा जायगा---
 - (क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति मे किया हो, जो गृह ग्रायुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के ग्रन्तर्गत ग्रथवा ग्रनुसार न हों;
 - (ख) यदि प्रदेशना गृहीता (allottee) होते हुए धारा १२ की उपधारा (२) के ब्रधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के ब्रध्यासन का ब्रधिकारी न रहा हो ;
 - (ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित श्रौद्योगिक श्रमिक न रहे।

स्पष्टीकरण —केवल किराया दे देने के श्राधार पर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि उसने गृह पर प्रदेशना गृहीता की हिमयत से कब्बा किया ह।

प्रदेशना क लिये प्रार्थना-पत्र १०-गृहों की प्रदेशना के लिय प्रार्थना-पत्र ऐसे झाकार (form) में दिया जायगा जो नियत किया जाय।

गृहीं की **देखना** ११--गृह-स्रायुक्त उस रीति से गृहो की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय।

ग्रनधिकृत ग्रध्यासन मे मम ने गये व्यक्ति।

१२-(१) किसी व्यक्ति द्वारा गृह का ग्रध्यालन उम व्यक्ति द्वारा मर्वदा उन शर्तों के पालन के अधीन होगा जो ऐसे गृह के अध्यासन के सम्बन्ध में नियत की जाय अथव। जिन्हे गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित करे।

अध्यासन की

- (२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, गृह-ग्रायुक्त भ्रध्यासी को नोटिस दे कर ग्रौर उसके स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण ग्रिभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त (Cancel) कर सकता है जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति या ब्रध्यासन में हों। प्रदेशना के निरमन की ब्राज्ञा की एक प्रतिनिधि व्यक्ति पर तामील की जायेगी।
- १३--इस ग्रधिनियम द्वारा ग्रथवा ग्रधीन ग्रधिकारों के प्रयोग मे राज्य सरकार श्रथवा गृह श्रायुक्त द्वारा दी गयी किसी श्राज्ञा पर किसी न्यायालय मे ब्रापत्ति नहीं की जा सकेंगी (shall not be called in question) तथा इम म्रिधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी य्धिकार के म्रनुसार किये गये प्रथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय त्रथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा (injunction) जारी नही कर मकेगा।

न्यायालयों के ग्रविकार-क्षेत्र का बाधित होना ।

१४--प्रत्येक गृह का ग्रध्यासी ऐसे ग्राकार मे ग्रनुबन्ध-पत्र (agreement) श्रनुबन्ध-पत्र निष्पादित करेगा जो नियत किया जाय।

का निष्पादन ।

१५-प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रदेशना प्राप्त हो, किराया तथा ग्रन्य परि- किराये की व्यय (harges) उन दरों से तथा उन दिनांको पर देय होगे जिन्हे गृह-ग्रायुक्त निश्चित करे।

दरे और ग्रदायगी के दिनांक १

१६—सब किराया तथा श्रन्य परिव्यय नकदी मे वसूल किये जायेगे ग्रौर प्रत्येक ग्रनुगामी मास (frllowing month) की दसवीं तारील तक देय होगे। किराया तथा श्रन्य परिव्यय देने का ढंग।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-श्रायुक्त उन ग्रादेशों के ग्रधीन जिन्हे राज्य सरकार प्रचारित करे, समय-समय पर किराया तथा ग्रन्य परिच्ययों के देने का दिनांक बढ़ा सकता है।

१७---देय दिनांक पर ऋथवा गृह-ऋायुक्त द्वारा बढ़ाई गई ऋवधि मे न दिया गया किराया, तथा ऋन्य परिव्यय बकाया समझा जायगा।

किराया तथा श्रन्य परिव्ययों को बकाया।

१८—गृहः ग्रायुक्त, उप गृह श्रायुक्त, सहायक गृह-श्रायुक्त ग्रथवा इस ग्रधि-नियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशा-सित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह मे, जिसमें दाखिल होना वह स्रावश्यक समझे, यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलास्रों मे दाख़िल हो सकता है।

गृह में दाखिले का ग्रधिकार।

१६-यदि किराये पर ग्रन्य परिव्ययों की वह बकाया जिसके लिये मांग को नोटिस तामील हो चुकी हो, गृह-ग्रायुक्त के पास ग्रथवा उसके ग्रिधिकृत ग्रन्य ग्रिधिकारों के पास तामील के ३० दिन ग्रथवा ऐसी बढायी हुई भ्रविध के भीतर, जिसकी वह भ्रनुज्ञा दे, नहीं दी जाती है तो ऐसी बकाया, वसूली के व्यय सहित, मालगुजारी की बक्ताया की भांति वसूल की जा सकेगी और उनको अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सम्बद्ध गृह का अन्धिकृत प्रध्यासी समझा जायगा।

किराया इत्य दि के बका या की वसूलो

वेतन में किराया की कटौती । २०—(१) किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए, कोई व्यक्ति गृह-आयुक्त के साथ ऐसा अनुबन्ध-पत्र निष्पन्न कर सकता है जिसके अनुमार नियोजक, जिसके अधीन वह नियुक्त हो, उसको देय वेतन अथवा मजदूरी में से ऐसी धनराशि जो अनुबन्ध-पत्र में निर्दिष्ट हो, काट सके और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि प्रदिष्ट गृहादि (Premises) के किराये तथा अन्य परिज्ययों की भरपाई के रूप में गृह-आयुक्त को दे सके।

ऐसे अनुबन्ध -पत्र के निष्पादन हो । पर पे नेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में किमी बात के होते हुए भी, गृह - आयुक्त द्वारा मांग-पत्र मे निर्दिष्ट धनराशि की कटौती के लिए लिख कर कहे जाने पर नियोजक श्रमिक के वेतन अथवा मजदूरी में से वह धनराशि काट लेगा और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि को गृह - आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अदा करेगा, और इस मांग-पत्र के विपरीत अदा की हुयी किसी धनराशि के लिये नियोजक उत्तरदायी (licble) होगा।

(२) यदि इस सम्बन्ध में नोटिस की तामीली ३० के दिन के भीतर नियोजक गृह- ग्रायुक्त को उपधारा (१) के ग्रधीन कडौती की हुयी धनराशि न दे ग्रथवा श्रमिक को उक्त उपधारा के ग्रधीन मांग-पत्र के विपरीत कोई भी धनराशि दे तो, वह कटौनी की हुयी या इस प्रकार श्रमिक को दी हुई धनराशि वसूली के सब व्यय सहित उससे मालगुजारी की बक्राया की भांति वसूल की जा सकेगी।

गृहादि से वेदलली।

- २१--(१) यदि गृह-म्रायुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि-
 - (क) किसी गृह के ग्रध्यासन के लिए ग्रधिकारी व्यक्ति ने:--
 - (१) ऐसे गृह के सम्बन्ध में विधितः देय किराया तथा ग्रन्य परिव्यय दो मास तक बकाया में रखा है, यदि धारा १६ के अधीन गृह-ग्रायुक्त द्वारा किराये के देने की श्रविध बढ़ा न दी गयी हैं; ग्रथवा
 - (२) पूर्णतः ग्रथवा ग्रंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, ग्रथवा
 - (३) ग्रन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट ग्रथवा ग्रस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है जिसके भ्रधीन वह गृहादि के ग्रध्यासन का ग्रिंघिकारी है, ग्रथवा
 - (४) वह इस ग्रधिनियम में पारिभाषित ग्रौद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है, श्रथवा
- (ख) कोई व्यक्ति जो गृहादि के भ्रनधिकृत ग्रध्यासन में हो, तो गृह-म्रायुक्त उस समय प्रचलित किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी,
 - (१) डाक द्वारा; ग्रथवा
 - (३) उस गृह के सदर दरवाजे ग्रयवा ग्रन्य किसी प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकवा कर; ग्रयवा
 - (३) ग्रन्य ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस की तामील करके ऐसे व्यक्ति को तथा उस व्यक्ति को जो सम्पूर्ण गृह ग्रथवा उसके किसी भाग के श्रव्यासन में हो,नोटिस की तामीली से एक मास के भीतर झाली करने की श्राका दे सकता है।

- (२) यदि उपधारा (१) के अधीन दो हुयी आज्ञा का पालन करने में कोई व्यक्ति असफल रहे अथवा पालन करने से इनकार करे तो गृह-आयुक्त उस गृह से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है और उस गृह पर क़ब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उतने बल प्रयोग का अधिकार दे सकता है जो आव-यक हो। आजा की एक प्रतिलिपि उक्त व्यक्ति पर तामील की जायगी।
- (३) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) ग्रथवा (३) के ग्रधीन गृह खाली करने की ग्राज्ञा दी गई हो, नोटिस की तामीली के दिनांक से एक मास के भीतर प्रथवा उस बढ़ी हुयी ग्रवधि के भीतर जिसकी गृह-ग्रायुक्त ग्रनुज्ञा दे गृह-ग्रायुक्त को बकाया किराया ग्रथवा ग्रन्य परिच्यय दे दे ग्रथवा ग्रपने द्वारा उल्लंघन की हुयी शर्तों का पालन ग्रौर ग्रनुपालन गृह-ग्रायुक्त के संतोष के ग्रनुसार करे, तो गृह-ग्रायुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के ग्रधीन दी गयी ग्रपनी ग्राज्ञा को निरस्त कर सकता है ग्रौर तत्पचात् वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों के ग्रनुसार ग्रध्यासीन रहेगा जिनके ग्रन्तर्गत वह नोटिस की तामीली से ठीक पूर्व ग्रध्यासीन था।
- २२—(१) धारा १२ ग्रथवा धारा ३१ की उपधारा (२) के ग्रधीन गृह ग्रायुक्त की ग्राज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त धाराग्रों के ग्रधीन ग्राज्ञा का तामील से १५ दिन के भीतर राज्य सरकार के पास ग्रपील कर सकता है:

ग्रपोल का ग्रधिकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उक्त १५ दिन की श्रवधि के पश्चात् भी श्रपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे संतोष हो कि प्रार्थी पर्याप्त कारणवज्ञ निश्चित समय में श्रपील प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

- (२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार गृह-आयुक्त से आख्या प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे और राज्य सरकार की यह आज्ञा अन्तिम होगी।
- (३) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो राज्य सरकार उस आज्ञा का निष्पादन (enforcement), जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, उस अवधि के लिये और उन शर्तों पर रोक सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
- २३—(१) जब कोई व्यक्ति किसी गृह के ग्रनिधकृत ग्रध्यासन में हो तो गृह-ग्रायुक्त ऐसे गृह के उपभोग ग्रौर श्रध्यासन के लिये ऐसे हर्जा (demages) नियत रीति से ग्रवधारित कर सकता है जिसे वह उचित ग्रौर उपयुक्त समझे ग्रौर उस व्यक्ति पर डाक द्वारा श्रथवा ग्रन्य रीति से नोटिस तामील करके ग्राज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट ग्रविध के भीतर हर्जा ग्रदा करे।

हर्जे की वसूली के ग्रधिकार।

- (२) यदि कोई व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट श्रविध के भीतर हर्जा देने से इनकार करे श्रथवा देने में श्रसमर्थ रहे तो हर्जा मालगुजारी की बक्राया की भांति वसूल किया जा सकेगा।
- (३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह ग्रर्थ नहीं लगाया जा रेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको हर्जा देने की ग्राज्ञा दी गई हो, ग्रपने दायित्व के प्रतिवाद में (to contest his liability) क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) न्यायालय में वाद (suit) प्रस्तुत करने से रोक सके:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (२) के श्रधीन धनराधि वसूल नहीं की जा चुकी हो तो ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहुले उस्त व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि गृह-श्रायुक्त के पास जमा कर देगा और जमा की हुई धनराशि न्यायालय की ग्राज्ञों के ग्रंधीन जमा रहेगी।

ग्रधिनियम के ग्रघीन देय धन्र-राक्षियों की वसुली ।

२४-(१) इस अधिनियम के अधीन देय सभी धनराशियों की वसली मालगुजारी की बक्राया की भाति की जा सकेगी।

(२) इस ऋधिनियम के ऋधीन वसूल की गयी सभी धनराशियां राज्य सरकार के नाम सरकारी खजाने में ग्रथवा इम्पीरियल बैक में, जैसा भी नियत किया जाय, जमा की जायंगी।

ब्रपराघों सी ग्रदेशा ।

२५-जब तक कि ग्रन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो कोई न्यायालय गृह-ग्रायक्त के अथवा उसके द्वारा इस संबंध में ग्रिधिकृत किसी कर्मचारी (officiai) के श्रमियोग-पत्र (Complaint) श्रथवा उनसे प्राप्त की सूचना के बिना इस श्रिधिनियम के श्रन्तगैत दण्डनीय किसी श्रपराध की श्रवेक्षा (Cognizance) नहीं करेगा।

इम श्रधिनियम श्रधीन की रक्षा।

२६--इम प्रधिनियम की प्रधीन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी किये गये कार्यों व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, श्रभियोजन या श्रन्य विधिक कार्यवाही (suit. prosecution or leval proceeding) नहीं की जा सकेगी।

दण्ड

- २७--(१) जो कोई इस ग्रधिनियम के किसी उपबन्ध ग्रीर ग्रथवा तदन्त-गंत बने नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो ६ मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दिये जा सकते हैं।
- (२) किसी भी व्यक्ति को, जो इस ग्रिधिनियम के ग्रधीन दिये गये किसी विधिक प्रधिकार के प्रयोग में बाधा डालता है, दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंढ जो छः मास तक हो सकता है, ग्रथवा भ्रथं दंड जो एक हजार इपये तक हो सकता है या दोनों, दिये जा सकते है।

नियम बनाने का ग्रधिकार।

- २८-(१) राज्य सरकार इस भ्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के प्रधीन नियम बना सकते है।
- (२) पूर्वोक्त प्रधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है:---

(१) गृह आयुक्त के कर्तव्य श्रीर कृत्य;

(२) थारा द के अधीन परामर्श समिति का संगठन और सदस्यता;

(३) प्रार्थना-पत्र का आकार तथा श्रावास की प्रदेशना की रीति भौर उसके ग्रध्यासन की शर्ते:

(४) ग्राकार ग्रौर रीति जिसमें धारा २२ के ग्रधीन ग्रपील प्रस्तत को जायगी;

(४) घारा २२ के अधीन अपीलों मे देय शुल्क, यदि कोई हो;

(६) घारा १४ और २० में भ्रभिदिष्ट ग्रनुबंध-पत्र का श्राकार;

(७) घारा १२ या घारा २१ की उपधारा (२) के श्रधीन ग्राजा की तामील की रीति ;

(८) किराया तथा ग्रन्य परिव्यय दिये जाने का ढंग;

(६) घारा २३ में अभिदिष्ट हर्जे का अवधारण;

(१०) गृहों की देख-रेख ध्रौर मरम्मत;

(११) वें विषय जो नियत कियें जाने वालें है या नियत किये जायें।

उद्देश्य ग्रौर कारण

भारत सरकार की राज सहायता प्राप्त इंडिस्ट्रियल हार्जीसग रकीम के अर्थान राज्य में ब्रोहोगिक श्रिमिकों के लिये गृहों के निर्माण में प्रगित हो रही है। बहुत से गृह बन भी खुके हैं प्रीर इस संबंध में समृचित व्यवस्था होने तक उनके प्रशासन, प्रदेशना, नियंत्रण इत्यादि के लिये अन्तर्कालीन प्रबंध कर दिया गया है। किन्तु उनक प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, मरम्मत, फिराया बसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिये अधिनियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती हैं। इस विधेयक द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गयी है।

सम्यूर्णानन्द,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ मईं, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रध्यक्ष, श्री ग्रात्माराम गोविंद खेर की ग्रध्यक्षता में ग्रारम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की स्वी (३२६)

प्रक्षयवर सिंह, श्री म्रनन्तस्वरूप सिंह, श्री म्रब्दुल मुईज खां, श्री ब्रमरेशचन्द्र पांडे, श्री ब्रमृतनाथ मिश्र, श्री म्रली जहीर, श्री संयद ध्रवध शरण वर्मा, श्री ग्रशरफ ग्रली खां, श्री ग्रार्थर ग्राइस, श्री ग्राशालता व्यास, श्रीमती इरतजा हुपैन, श्री इस्तफा हुसैन, श्री उदयभान सिंह, श्री उमाशंकर, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री उम्मेद सिंह, श्री उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री ऐजाज रसूल , श्री ग्रोंकार सिंह, श्री कन्हैयालाल, श्री कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री कमाल ग्रहमद रिजवी, श्री करनसिंह, श्री कल्याण राय, श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री काली चरण टंडन, श्री किन्दर लाल, श्री किशन स्वरूप भटनागर, श्री क्वरकृष्ण वर्मा, श्री

कुपा शंकर, श्री कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री कृष्ण शरण भ्रार्य, श्री केवलसिंह, श्री केशभान राय, श्रो केशव गुप्त, श्री केशव पांडेय, श्री केशव राम, श्री कैलाश प्रकाश, श्री बुशोराम, श्री गगाधर, श्री गंगाघर जाटव, श्री गंगाधर शर्मा, श्री गंगाप्रसाद, श्री गंगा प्रसाद सिंह, श्री गजेन्द्रसिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री गणेश प्रसाद पांडेय, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्री गुप्तार सिंह, श्री गुरु प्रसाद पांडेय, गुरु प्रसाद सिंह, श्री गुलजार, श्री गेदासिंह, श्री गोपी नाथ दीक्षित, श्री गोवर्घन तिवारी, श्री गौरीराम, श्री चनश्यामबास, श्री

चतुर्भज शर्मा, श्री चन्द्रवती, श्रीमती चन्द्रमिह रावत, श्री चिरंजी लाल पालीवाल, श्री चुन्नी लाल सगर, श्री छेंदा लाल चौधरी, श्री जगदीश प्रमाद, श्री जगदोशसरन रस्तोगी, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगन्नाथ बस्ता दास, श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जगन्नाथ सिंह, जगपति सिंह, जटाशंकर शुक्ल, श्री श्री जयपाल सिंह, जयराम वर्मा, जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री जवाहर लाल, जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर जुगलिक्शोर, श्री जोरावर वर्मा, झारखंडे राय, श्री टोकाराम, श्रो ड ला राम, श्री डालच द, श्रो तुलसीराम, श्री तुलाराम, श्री तुलाराम रावत, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री श्री तेजबहादुर, नेजासिह, श्री त्रिलोकी नाथ कौल, श्री दयालदास, श्री दर्शनराम भगत, श्री दोनदयानु शर्मा, श्री दोपनारायण वर्मा, श्री देवकोनन्दन विभव, श्री देवदत्त मिश्र, श्रो देवदत्त शर्मा, श्री देवमूर्ति राम, श्री देवराम, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री धनुषधारी पृष्टिय, श्री नत्युसिंह, श्री नग्दक्मारदेव वाशिष्ठ, श्री

नरदेव शास्त्री, श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री नरोत्तम सिंह, श्री नवलिक्शोर, श्री नागेश्वर द्विवेदी, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री नारायण दास, श्रो नारायणदीन वाल्मीकि, श्री निरंजन सिंह, श्री नेकराम शर्मा, श्री नेत्रपाल सिंह, श्री नौरंगलाल, श्री पद्मनाथ सिंह, श्री परमेश्वरीराम, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री पहलवान सिंह चौधरी, श्री पातीराम, श्री पुत्त्लाल, श्रो पुद्दनराम, श्री पुलिनविहारी बनर्जी, श्री प्रकाशवती सूद, श्रीमती प्रतिपाल सिंह, श्रो प्रभाकर शुक्ल, श्री प्रभूदयाल, श्री फजलुल हक, श्री फतेहसिंह राणा, श्री बद्री नारायण मिश्र, श्री बलदेव सिंह, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री बलवन्त सिंह, श्री बशीर ग्रहमद हकीम, श्री बसन्त लाल, श्री बस त लाल शर्मा, श्री बाबूनन्दन, श्री बाबुलाल कुसुमेश, श्री बाब् लाल मीतल, श्री बालेन्दुशाह, महाराजकुमार बिशम्बर सिंह, श्री बेचन राम, श्री बेचन राम गुप्त, श्री बेनी सिंह, श्री बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री भगवती प्रसाद दुबे, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री

भगवान दीन वाल्मीकि, श्री भगवान सहाय, श्री भीममेन, श्री भुवर जी, श्री भूपाल सिह खाती, श्री भूगुनाथ चतुर्वेदी, श्री भोलासिंह यादव, श्री मकसूद ग्रालम खां, श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री मदनगोपाल वद्य, श्री मदन मोहन उपाध्याय, श्री मन्नी लाल गुरुदेव, श्री मललान सिंह, श्री महमुद भ्रली खां, श्री (रामपुर) महम्द ग्रली खां, श्री (सहारनपुर) महादेव प्रसाद, श्री महाराज सिंह, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री महावीर सिंह, श्री महीलाल, श्री मान्धाता सिंह, श्री मिजाजी लाल, श्री मिहरबान सिंह, श्री मुन्नू लाल, श्रो मुरलीघर कुरील, श्री मुक्ताक ग्रली खां, श्री मुहम्मद ग्रदील ग्रब्बासी, श्री मुम्मद श्रब्दुल लतीफ, श्री मुहम्मद श्रब्दुस्समद, श्री मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज मुहम्मद तकी हादी, श्री मुहम्मद नसीर, श्री मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री मुहम्मद सुलेमान श्रधमी, श्री मोहनलाल, श्रो मोहन लाल गौतम, श्री मोहर्नासह, श्री मोहन सिंह शाक्य, श्री यमुना सिंह, श्री यशोदा देवी, श्रीमती रघुनाथ प्रसाद, श्री रघुवीर सिंह, श्री रणंजय सिंह, श्री

रमशचन्द्र शमां, श्री रमेश वर्मा, श्री राजकिझोर राव, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राजवंशी, श्री राजाराम किसान, श्री । राजाराम मिश्र, श्री राजाराम शर्मा, श्री । राजेन्द्र दत्त, श्री राधाकृष्ण ग्रग्रवाल, श्री राधामोहन सिंह, श्री राम ग्रधार तिवारी, श्री राम भ्रधीन सिंह यादव, श्री राम ग्रवध सिंह, श्रो रामकिंकर, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री रामगुलाम सिंह, श्री रामचन्द्र विकल, श्रो रामजी लाल सहायक, श्री रामजी सहाय, श्री रामदास ग्रार्य, श्री रामदास रविदास, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री रामनरेश शुक्ल, श्रो रामनारायण त्रिपाठी, श्री रामप्रसाद, श्री रामप्रसाद नौटियाल, श्री रामप्रसाद सिंह, श्री रामबली मिश्र, श्री रामभजन, श्री राममूर्ति, श्री रामरतन प्रसाद, श्री रामराज शुक्ल, श्री रामलखन, श्री रामलखन मिश्र, श्री रामलाल, श्रो रामवचन यादव, श्रो रामशंकर द्विवेदी, श्री रामशंकर रविवासी, श्री रामसनेही भारतीय, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री रामसुन्दर राम, श्री रामसुभग वर्मा, श्री रामसुमेर, श्रो राम स्वरूप, श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री

राम स्वरूप भारतीय, श्री राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्रो रामहरख यादव, श्री रामहेत सिंह, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्रो लक्ष्मण राव कदम, श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी शंकर यादव, श्री लालबहादुर सिंह, श्री लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री लुत्फ ग्रली खां, श्री लेखराज सिंह, श्री वंशनारायण सिंह, श्री वंशीदास घनगर, श्री वसी नक़वी, श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री विजय शंकर प्रसाद, श्री विष्णु शरण दुव्लिश, श्री विष्णुदयाल वर्मा, श्री वीरसेन, श्री वोरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री वीरेन्द्रपति यादव, श्री बीरेन्द्र वर्मा, श्री वीरेन्द्रशाह, राजा व्रजभूषण मिश्र, श्री वजरानी मिश्र, श्रीमती वजवासी लाल, श्री वजिवहारी मिश्र, श्री वजिवहारी मेहरोत्रा, श्री शम्भूनाय चतुर्वेदी, श्री शांति प्रपन्न शर्मा, श्री शिवकुमार मिश्र, श्री शिवनारायण, श्री शिवप्रसाद, श्री **जिवमंगल सिंह कपूर, श्री** शिवराज बली सिंह, श्री शिवराज सिंह यादव, बी शिवराम पांडेय, श्री शिव वचन राव, श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री

शिवस्वरूप सिंह, श्री ज्ञकदेव प्रसाद, श्री शुगनचन्द, श्री इयाम मनोहर मिश्र, श्री इयामलाल, श्री श्रीचन्द, श्री श्रीनाथ राम, श्री श्रीनिवास, श्री श्रीपति सहाय, श्री सईद जहां मलफी शेरवानी, श्रीमती संग्रामसिंह, श्री सिच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती सत्य सिंह राणा, श्री सावित्री देवी, श्रीमती सियाराम गंगवार, श्री सियाराम चौधरी, श्री सीताराम शुक्ल, श्री मुखीराम भारतीय, श्री सुन्दरदास, श्री दीवान सुन्दर लाल, श्री सुरुजु राम, श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री स्रेश प्रकाश सिंह, श्री सूर्य्य प्रसाद ग्रवस्थी, श्री सूर्य्य बली पांडेय, श्री सेवा राम, श्रो हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री हबीबुर्रहमान ग्रंसारी, श्री हबीबुर्रहमान ग्राजमी, श्री हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री हमीद खां, श्री हरस्याल सिंह, श्री हरगोविंद पन्त, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री हरदेव सिंह, श्री हरिप्रसाद, श्री हरिश्चन्द्र भ्रष्ठाना, श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री हरि सिंह, श्री हेमवतो नन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना दीवान सुन्दर दास ने शपय ग्रहण की।

मश्नोत्तर

म्रल्पपूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन को एयर कण्डीशण्ड कराने की भ्रावश्यकता

**१ -श्री झारखंडे राय (जिला ग्राजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह विधान भवन को एयर कन्डीशन्ड कराने पर विचार कर रही है ?

विन्न मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी नही।

**२--श्री झारखंडे राय--ग्रगर हां, तो इसमे सरकार का कितना खर्च होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सवाल नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या वित्त मंत्री बतलायेगे कि एयर कंडोशण्ड करने में सरकार के सामने क्या दिक्कते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—दिक्कतो का सवाल पैदा नहीं होता। मैने तो जवाब दिया है कि यह बात विचाराधीन नहीं है।

श्री गेदा सिह—क्या माननीय वित्त मंत्री जी के पस कुछ इस तरह के सुझाव भी आये है कि इस सदन को एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कम से कम मंत्री के पास तो नहीं श्राये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला श्रत्मोड़ा)—क्या सरकार को यह खबर है कि इस हमारे हिन्दोस्तान के श्रौर प्रांतों की जो विधान सभायें है वे सब करीब-करीब एयर कंडोशन्ड है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—है भी, नहीं भी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते क्या यह प्रावश्यकीय नहीं है कि यहां का जो सदन है उसे एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जरूर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय झारखंडे राय जी के स्वास्थ्य को दृष्टि में रख कर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे

श्री ग्रध्यक्ष—में इसकी इजाजत नहीं देता । श्रापने नाम ले कर व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है।

सैदपुर में जनाने ग्रस्पताल की ग्रावश्यकता

**३--श्रो कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (ग्रनुपस्थित)-क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सैदपुर में १६५४ तक एक जनाना ग्रस्पताल बनाने तथा वर्तमान मर्दाना ग्रस्पताल का प्रांतीयकरण करने का वादा किया है?

स्रत्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) — वादा तो नहीं किया था परन्तु इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया था। विचार हो रहा है।

तारांकित प्रक्न

*१-२--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८ मई, १६५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३-५--श्री धर्मीसह (जिला बुलन्दशहर)--[२४ मई, १६४४ के लिए स्थिगत किये गरे।]

*६-৩--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला म्रलीगढ़)--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित कि ग्रे गये।]

*द-१०-भी जगन्नाथ प्रसाद (जिला खोरी)--[१८ मई, १६५४ के लिए स्थगित किये गरे।]

*११-१२-- श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---[२४ मई, १६५४ के लिए स्थगित किये गरे।]

*१३-१५-भी रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जूरी प्रया के सम्बन्ध में भारत सरकार का ग्रादेश

*१६—श्री म तलान सिंह (जिला ग्रलीगढ़) (ग्रनुपस्थित)—वया यह सत्य है कि न्याय मंत्री ने उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के एसो सियेशन के एक डेपुटेशन से गत ग्रक्तूबर म स में यह बात कही थी कि यू० पी० गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि निकट भविष्य में राज्य भर में फिर से जूरी सिस्टम चालू कर दिया जाय ? यदि ऐसा है, तो कब से यह सिस्टम चालू हो जायगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद ग्रली जहीर) — जी नहीं, गत ग्रक्तूबर मास में उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के डेपुटेशन से न्याय मंत्री ने केवल यह कहा था कि जनमत जूरी प्रथा के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश के केवल छः जिलों में जूरी प्रथा रखना ठीक नहीं है जबकि श्रौर जिलों में जूरी द्वारा मुकदमें नहीं सुने जाते।

*१७--श्री मलखान सिंह (ग्रनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ग्रादेश दिया है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद श्रली जहीर—जी हां, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जूरी प्रथा के सिलसिले में जो बिल पेश करने वाली है उसे स्थगित कर दिया जाय क्योंकि भारत सरकार स्वयं फौजदारी कानून के संशोधन करने के लिए बिल पेश कर रही है।

पंचवर्षीय यौजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण

*१८--श्री धर्मींसह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के श्रन्दर कौन-कौन से सिंचाई के नर्ने साधन निर्माण किये जाने को हैं?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—संशोधित पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तगंत बुलन्दशहर जिले में १२८ नलकूप ६०० नलकूपों की योजना के ग्रन्तगंत ग्रीर १८ नलकूप २०० ग्रितिरक्त नलकूपों की योजना (ट्यूब वेल सर्किल पश्चिम में) के ग्रन्तगंत बनने थे। यह सभी नलकूप बन गये हैं ग्रीर इनसे सिंचाई होने लगी है। उपरोक्त योजनाग्रों के ग्रितिरक्त ग्रपर गंगा नहर की क्षमता बढ़ाने की योजना से भी जिस पर कार्य प्रगति पर है, बुलन्दशहर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री धर्मिसिह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना लागू होने के पहले बुलन्दशहर में कितने ट्यूबवेल बने थे?

श्री राममूर्ति-इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री धर्मीसह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये १२८ तथा १८ ट्यूबवेल्स कब से बनने शुरू हुए और कब बनकर समाप्त हुए?

श्री राममूर्ति—यह सन् १६४६ ई० में बनने शुरू हुये श्रीर इस साल मार्च तक करीब करीब सब बन चुके हैं, जिसमें १५७ चालू हो गये हैं श्रीर बाकी पर श्रभी बिजली नहीं लग पायी है। इसलिए वह काम में नहीं श्राये है।

श्री दोनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल्स सन् १९४६ ई० में लगे थे उनमें ग्रब पानी बहुत कम निकलता है ग्रौर ग्रब वह बेकार होते चले जाते हैं।

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना कोई हमारे पास नहीं है। श्रगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो वह लिखकर दें, उसकी जांच करायी जा सकती है। उनके लिए एक निर्धारित कोटा पानी का रहता है। श्रगर वह उससे कम पानी देते हैं तो उनकी रिबोरिंग करायी जायगी।

श्री धर्मीसह—क्या यह सही नहीं है कि जो कुएं सन् १९४६ ई० के पहले बने थे वह पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत नहीं ग्राते हैं?

श्री राममूर्ति—पंचवर्षीय योजना ५ साल की है झगर वह इससे पहले के हैं तो उसमें नहीं द्याते होंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री को विदित है कि बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील के पिर्चिमी हिस्से, के लिये लोगों ने श्रनेक बार दरस्वास्त दी कि सरकार वहां पर सर्वे कराये मगर वहां पर श्राज तक एक भी ट्यूबवेल नहीं बना है?

श्री राममूर्ति--- ब्राज तक नहीं बने हैं तो ब्रागे बनेंगे।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत कब से ट्यूबवेल बनने शुरू हुये?

श्री राममूर्ति-में ग्रापका ग्राशय समझा नहीं।

श्री बलवन्त सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि बुलन्दशहर जिले में जो ट्यूबबेल बनने शुरू हुए हैं वह पंचवर्षीय योजना के किस साल से बनने शुरू हुये हैं?

श्री राममूर्ति—सन् १९४६ ई० में बनने शुरू हुए यानी पंचवर्षीय योजना के इ साल पहले शुरू हुए थे।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृषा करेंगे कि १६५१-५२, १६५२-५३, १६५३-५४ के सालों में कितने ट्यूबवेल बने?

श्री राममूर्ति—यह दो योजनाएं थीं, एक ६०० ट्यूबवेल की योजना थी जिसमें १६२ वन चुके हैं। दूसरी में १८ वने है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय सूचना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सिकन्दराबाद तहसील के पिच्छमी भाग में कुएं बनाने के लिए योजना है तो क्या वहां पर कुएं बनाने पर विचार सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—श्रभी हमारे यहां ७५ ट्यूबवेल बनाने की योजना श्रीर श्रायी है, उसके श्रन्तर्गत ऐसा स्थाल किया जाता है कि बुलन्दशहर जिले में १५ ट्यूबवेल श्रीर बनेंगे। उनका स्थान श्रभी निश्चित नहीं हुआ है। सम्भव है कि वह सिकन्दराबाद तहसील में ही हो।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सूचना मन्त्री बतलायेंगे कि ५१-५२ के बारे में श्राप का जवाब साफ नहीं हुआ।

श्री स्रध्यक्ष-स्राप बहुत देर से पहुंचे। उन्होंने बहुत साफ उत्तर दिया था।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सन् १६५३-५४ में कितने ट्यूबवेल बुलन्दशहर जिले में बने ?

श्री राममूर्ति—यह तो एक कान्टोनुग्रस प्रोग्राम है ग्रौर बराबर टयूबवेल बनते रहते है। उनकी तो सूचना नहीं है, कि ५३-५४ में कितने टयूबवेल बने।

सुल्तानपुर जिले में सहकारी नलकूप

*१६--श्री काशी प्रसाद पांडे (जिला सुल्तानपुर) (ग्रनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में सिवाई के लिए कितने कोग्रापरेटिव ट्यूबवेल बनाये जा रहे है श्रौर वे कब तक तैयार हो जायेंगे?

सूचना मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) — इस जिले में दो सौ राजकीय नलकूप बनने वाले हें इसलिए सहकारां नलकूप उनके स्थान नियुक्त हो जाने के बाद बनाये जायेंगे।

सुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये ग्रधिकृत भूमि

*२०—श्री गुरु प्रसाद (जिला मुल्तानपुर) (श्रनुपस्थित)—क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर विस्तार योजना के ग्रन्तर्गत मुल्तानपुर जिले में गत वर्ष कितनी कृषि भूमि नयी नहर की खुदवाई के लिए श्रिविकृत (aqcuire) की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच के निर्माण हेतु लगभग ६०० एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है। *२१--श्री गुह प्रसाद (ग्रनुवस्थित) -- क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन किसानों की भूमि ली गयी उन्हें ग्रभी तक मुग्रावजा नहीं मिला श्रौर उन्हें लगान भी देना पड़ रहा है ?

श्री कमला पित त्रिपाठी—इस भूमि को ग्रिधकृत करने का कार्य ग्रभी पूर्ण नहीं हुआ है जिस कारण मुत्राविजा देने में विलम्ब हो रहा है। भूमि को श्रिवकृत करने की कार्यवाही में तत्परता की जा रही है। जिलाधीश को लिखा गया है कि वे किसानों से उस भूमि का लगान जिस पर जौनपुर बांच के निर्माण के लिए ग्रिधकार कर लिया गया है वसूल न करें, ग्रीर जो लगान उन्होंने ऐसी भूमि का वसूल कर लिया है, उसे तुरन्त ही ग्रामीणों को वापस कर दें।

बस्ती जिले में बांधों की मरम्मत की श्रावश्यकता

*२२--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती) -- क्या सरकार को यह जात है कि कुश्रानों नदी के बाढ़ को रोकने के लिये जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद में मौजा महली से भटपुरा तक श्रीर परसहर से डुट्टिया घाट तक श्रीर डु.ट्टिया घाट से वरपरवा तक तथा पड़री से मझौरा तक इन क्षेत्रों के निवासियों ने बांध बनाया था?

श्री राममूर्ति--यह बांध पुराने थे श्रौर सम्भवतः ग्रामवासियों ने बनाये थे।

*२३—-श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष बाढ़ से उप-र्युक्त चारों बांध ट्ट गये, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को काफी नुकसान भोगना पड़ा है?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र में हर वर्ष कुग्रानों नदी में बाढ़ ग्राने के कारण मइली भटपुरा व पड़री को छोड़कर ग्रन्य सभी बांध पहले ही टूट चुके थे। पिछले वर्ष मैली भटपुरा व पड़री बांध भी टूट गये, जिससे कुछ ऐसे क्षेत्र में, जो ग्रभी तक बचा था, नुकसान हुग्रा।

*२४—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार को यह जात है कि उपर्युक्त बांधों की मरम्मत कराने के लिए किसी विधान सभा के सदस्य ने जिलाधीश बस्ती के पास टेस्टवर्क में मरम्मत कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था और जिलाधीश ने हाथों हाथ उस पत्र को नहर विभाग के इन्जीनियर की जांच के लिये दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति -- जी हां। श्री घनुषधारी पांडेय जी ने पिछले वर्ष इन बांधों की टेस्टवर्क के ग्रन्तर्गत मरम्मत कराने के लिए जिलाधीश को लिखा था, जिलाधीश ने नियमानुसार नहर विभाग से राय मांगी। नहर विभाग के मतानुसार केवल सभी मइली भटपुरा व पड़री बांधों की मरम्मत श्रमदान द्वारा की जा सकती थी ग्रीर शेष दो बांध के पुनः निर्माण से ग्रधिक हानि की ग्राशंका थी। चूंकि जिले में ग्रभाव की स्थित समाप्त हो जाने के फलस्वरूप टेस्टवर्क बन्द हो गये थे, इसलिए नहर विभाग ने मरम्मत के कार्य को श्रमदान द्वारा करने की राय दी थी।

श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार को जात है कि मइली श्रौर भटपुरा के बांघ टूट जाने से सैकड़ों गांवों की फसल नष्ट हो गयी?

श्री राममूर्ति--बांघ टूट गया होगा, तो जरूर नब्ट हुई होगी।

श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाघीश ने किस तारीख को सम्बन्धित बांधों की रिपोर्ट नहर विभाग के इन्जीनियरों से मांगी थी ग्रौर वह कितने दिनों बाद दी गयी?

श्री राममूर्ति—एक्जीक्यूदिव इंजीतियर गोंडा की राय देने की तारीख तो मेरे पास है जो २४ फ़रवरी, सन् ४४ है।

श्री रामसुन्दर राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बाढ़-क्षेत्र मे श्रमदान सम्भव है?

श्री राममूर्ति—जी हां, जात है।

श्री शिवनारायण--सरकार श्रमदान में कितने रुपये की सहायत। देने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--सरकार ने तो टेक्निकल राय उस पर दे दी है, बाकी काम श्रमदान से होगा।

जिला टेहरी-गढ़वाल की निदयों की घाटियों में सिंचाई के साधनों का स्रभाव

*२४—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत गंगा, भिल्लंगना, अलकनन्दा निदयों की घाटियों में विस्तृत समतल जमीन बिना सिचाई की है?

श्री राममूर्ति--उक्त निवयों की घाटियों में विस्तृत समतल भूमि हे, जो सिचाई साधन से रहित है।

*२६—श्री सर्त्यासह राणा—क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है या करेगी, जिसके ग्रनुसार इन निंदयों से ऐसी जमीनों को सींचने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री राममूर्ति—इस भूमि की सिचाई के सम्बन्ध में कौन सा उपयुक्त उपाय हो सकता है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उपर्युक्त निवयों से पंप द्वारा जल उठाकर सिचाई की व्यवस्था की जा सकती है, पर जब तक सस्ती विजली न मिले तब तक वह उपाय काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह लाभकर न होगा।

श्री सर्त्यांसह राणा-क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस भूमि का रकबा कितना है ?

श्री राममूर्ति -- मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार को विदित है कि टेहरी जिले में श्रन्न का श्रभाव है ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) -- क्या यह सही है कि गढ़वाल सर्वे डिवीजन ने तमाम घाटियों की सबें करके एक निश्चित योजना सिचाई के लिए प्रस्तुत की थी ?

श्री राममूर्ति—सर्वे की रिपोर्ट तो है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा पड़ती है कि उससे कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार को विदित है कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ी प्रदेशों में छोटे छोटे बिजली घरों को बनाने की योजना है। यदि हां, तो क्या विद्युत मन्त्री से परामर्श करके उनको शोध्र कार्यान्वित किया जायगा।

श्री राममूर्ति—सर्वे तो वक्तन फवक्तन होता रहता है, लेकिन कोई डेफिनिट प्रपोजल ही, ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

" श्री झारखंडे राय → क्या सरकार े सामने कोई ऐसा सुझाव श्राया है कि इन निवयों के पानी को बरसात में इकट्ठा करके वहां से नहर निकाली जाय ? श्री रामभूति--यदि कोई ब्राया भी हो, तो मेरे नोटिस मे नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—-क्या सरकार के सामने एक स्कीम भेजी गयी कि पहाड़ों पर हाइड्रोलिक रैन्मस के द्वारा पानी ऊपर उठाया जा सकता है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—हमारे सामने ऐसी तजबीज ग्रायी है ग्रीर उस पर ग्रत्मोड़ा में कार्य वाही को जा रही है, बाको ग्रीर जगहों से जब मालूमात ग्रा जायेगी, तब वहां काम चाल किया जायगा।

तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहर के विस्तार की आवश्यकता

"२७--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (ग्रनुपस्थित)--क्या सरकार रायबरेली जिले की सलोन तहसील के ग्रन्तर्गत नहर का विस्तार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां, ग्रौर कितने मील ?

श्री कमलापित त्रिपाठी—-तहमील सलोन, जिला रायबरेली में नहरों के विस्तार की स समय कोई योजना नहीं है।

*२८--श्री दलबहादुर सिंह (ग्रनुपस्थित)--स्या इस विस्तार योजना में कन्दरावां ग्राम भी शामिल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

बिखरा (बस्ती) झील से नहर निकालने का कार्य

*२६--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि बिखरा (बस्ती) झील से जो नहर निकलने वाली है, उस पर खुदाई का काम कब से शुरू हो जायगा?

श्री राममूर्ति—इस योजना पर कार्य, १६५३-५४ की रबी फसल कट जाने पर प्रारम्भ किया जायगा।

*३०--श्री राजाराम शर्मा--इस झोल से जो नहर निकलेगी, उससे कितने एकड़ को सिचाई श्रनुमानतः होगी?

श्री राममूर्ति--जो नहर बिलरा झोल से निकलेगी, उससे निम्नांकित सिचाई होगी :-

शासित क्षेत्र .. २७,६०० (culturable commanded area) वर्षिक सिंचाई .. ११,३००

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नहर की खुदायी मई की कौन सी तारीख से शुरू हो जायगी?

श्री राममूर्ति——मैने बताया कि फसल कट जाने के बाद काम शुरू हो जायगा श्रौर श्रव फसल कट चुको है।

श्री रामदास श्रार्य (जिला मुजफ्करनगर) -- क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कृपः करेंगे कि यह नहर कहाँ कहाँ से होकर जायगी श्रीर इस पर कितना खर्चा होगा?

श्री राममूर्ति—यहाँ से दो नहरें निकलेगी। बस्ती जिले में ६ मील लम्बी ग्रीर गौरखपुर जिले में १० मील लम्बी। इन दोनों का खर्चा केवल १२ लाख के लगभग होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा - - इन नयी झोलों के लिए कितनी श्रीर जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी?

श्री राममूर्ति—झील के लिए जमीन एक्वायर करने की स्रावश्यकता नहीं है, लेकिन जिस जमीन में से नहर निकलेगी, उसकी जरूर एक्वायर करने की स्रावश्यकता होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती) -- चालू वित्तीय वर्ष मे इन नहरों में कितना रूपया लग जाने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—इसका ठीक तखमीना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन नहरीं के चालू वर्ष में वन जाने का अनुमान हे।

श्री राजाराम शर्मा—क्या दोनों नहरें एक जगह से निकलेंगी या श्रलग-ग्रलग स्थानों से?

श्री राममूर्ति-झील तो एक ही है, लेकिन नहरे श्रलग-श्रलग निकलेगी।

*३१--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला ग्रागरा)--[२१ मई, १६४४ के लिए प्रश्न संख्या ३५ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३३--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर) -- [६ मई, १९५४ के लिए प्रक्रम संख्या ६८-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार

*३५-श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा) --क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला गोंडा में राप्ती नदी पर बलरामपुर श्रीर तुलसीपुर के बीच एक पुल बनाने का वह विचार कर रही है।

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भु ज शर्मा) — बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर स्थित रेल के पुल पर सड़क क यातायात के लिए डेक बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेगे कि डेक बनाने में सरकार को कितना पे करना पड़ेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—३ लाख ५४ हजार।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल — क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेगे कि एक स्वतंत्र पुल निर्माण कराने में कितना व्यय होगा?

श्रीं चतुर्भुज शर्मा इसके लिए सो सूचना की जरूत पड़ेगी लेकिनइस से बहुत ज्यादा होगा, इममें कोई शक नहीं हैं।

*३६-३७--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--[१८ मई, १६५४ के लिए स्यगित किये गये।]

*३८-४०--श्री स्रक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)--[१८ मई, १६४४ के लिए स्थिगत किये गये।]

*४१-४२--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--[५ मई, १६४४ के लिए प्रश्न संख्या ५६-६० के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ग्राबकारी से ग्राय

*४३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १६५१-५२ व १६५२-५३ में एक्साइज विभाग से क्या-क्या ग्राय हुई ग्रौर उसमें ग्रंग्रेजी व देशी शराब की ग्राय का श्रलग-श्रलग विवरण क्या है?

श्री सैयद ग्रली जहीर—-१६५१-५२ ग्रौर १६५२-५३ के वर्ष मे राज्य की ग्राब-कारी से कुल ग्राय (gross income) तथा ग्रंग्रेजी ग्रौर देशी शराब की ग्राय का विवरण निम्नलिखत है:--

वर्ष		देशी शराब की श्राय	श्रंग्रेजी शराब की श्राय	कुल म्राय	
		रु० में	रु० मे	र ० में	
१६५१-५२	• •	३,७३,०२,०१४	५०,६५,१८६	६,६६,१५,६५८	
१९४२-५३	• •	३,१६,५७,४८६	४७,६३,६८६	६,०४,१२,७६१	

भी महीकाक सामा का कार्य की कारण क्या है?

श्री सैयद श्रली जहीर—इसके कारण तो बहुत से है, लेकिन खुला हुआ कारण यह है कि हमारी तरफ से यह कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके मद्यनिषेध हो, लोग कम इस्तेमाल करें। इसकी वजह से आय तो कम हो ही जानी चाहिये।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विदेशो शराख देश में कब तक श्राती रहेगी श्रौर इसको बन्द करने का विचार सरकार का है या नहीं?

श्री सैयद श्रली जहीर—यह मामला तो मेटे ख्याल में केन्द्रीय सरकार के मुताल्लिक है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेगे कि सन् १६५१-५२ व ५२-५३ में दूकानों में भी कमी हुई या दूकानें उतनी ही रहीं?

श्री सैयद ग्रली जहीर--दूकानों में भी थोड़ी कमी हुई, ज्यादा नहीं।

श्री रामदास ग्रार्य—क्या यह सही है कि ग्रामदनी में कमी का कारण एक यह भी है कि हमारे प्रदेश में गैरकानूनी तरीक़े से श्रधिक शराब निकाली जा रही है?

श्री सैयद ग्रली जहीर--मुमिकन है, किसी हद तक यह भी हो।

60

श्री नेकराम शर्मा (जिला ग्रलीगढ़) — स्या माननीय मंत्री जी बताने की कृषा करेंगे कि इल्लीगल शराब को रोकने के लिये सरकार ने स्या प्रयत्न किये है ?

श्री संयद श्रली जहीर—इसके लिये बहुत से प्रयत्न किये गये है। जैसे जो और बहुत से मुस्तिलफ किस्म के जरायम हैं उनको रोकने के लिये कोशिश की जाती है उसी तरह से यह भी एक जुर्म है और इसको रोकने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

बांदा जिले में नरैनी-कालिजर सड़क पर पुल निर्माण योजना

*४४—श्री इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (ग्रनुपस्थित)— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरेनी तहसील के कालि जर तक जाने वाली सड़क के ऊपर वाली नदी पर पुल बनाने का काम श्रारम्भ होने जा रहा है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---नरैनी-कालिजर सड़क पर वरवन नदी पर पुल निर्माण योजना पर सरकार विचार कर रही है।

*४५—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (ध्रनुपस्थित) ---यदि हां, तो कब से?

श्री गिरधारी लाल-यह श्रभी नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब से

*४६--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (म्रनुपस्थित) -- [५ मई, १६५४ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के स्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बोर्ड बस्ती को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा वापस की हुई सड़कें

*४७—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने कौन-कौन सी सड़कें जिला बोर्ड बस्ती को वापस कर दी है श्रौर उसके साथ-साथ कितना रुपया दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बोर्ड बस्ती को जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० ने १ स्रगस्त, १९५२ई० से वापिस कर दी है उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। जिला बोर्ड बस्ती को इन सड़कों के रख-रखाव तथा उन्नति के लिये सरकार ने निम्नलिखित स्रन्दान प्रदान किया :—

きとよろーよる	• •	• •	• •	• •	१६,०००
もをおきーおみ	• •	• •	• •	• •	86,800

(देखिये नत्थी 'क' ग्रागे पृष्ठ १७३ पर)

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बस्ती जिले तथा नैपाल राज्य को मिलाने वाली वरनी रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा-मालूम नहीं है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ होगा।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों में से महत्वपूर्ण कों को ले कर उनका सुधार करने का विचार रखते हैं ? श्री चतुर्भुज शर्मा—दूसरी पंचवर्षीय योजना बनने के समय पर जो सड़कें किसी महत्व की होंगी उनके बारे में विचार किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं, उनकी दशा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दिलाई के कारण ग्रत्यन्त शोचनीय हो गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन ग्रगर माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम हो ग्रौर ग्रगर वह लिखें तो जांच करायी जायगी।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह सड़कें क्यों वापस कीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है कि केबिनेट ने यह तय किया था कि जो सड़कें बनने के क्राबिल थीं उनको ठीक कर दिया जाय श्रौर फिर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा स्थानीय मरम्मत श्रच्छी तरह से हो सकती है श्रौर उनको स्थानीय सहायता मिल सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फेंकाफेंकी या श्रदलबदल पी० डब्ल्यू० डी० श्रीर जिला बोर्ड के बीच कब तक जारी रहेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कोई फेंकाफेंकी नहीं है, निश्चित बात है। पी० डब्ल्यू० डी० जरूरी सड़कें ले लेती है श्रौर जब मुनासिब समझा जाता है उनको वापस भी कर दिया जाता है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

*४८-४६--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--[१ जून, १६५४ के लिये स्थिगत किया गया।]

*५०-५१--श्री व्रजभूषण मिश्र--[१३ मई, १६५४ के लिपे प्रश्न संस्था ३०-३१ अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में नल-कूपों का निर्माण

*५२—श्री बलवन्त सिह—क्या सरकार ने जिला मुजफ्फरनगर में जो श्रीर १५ नलकूप सहकारिता के श्राधार पर बन रहे हैं उनको भी कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा हो बनवाने का श्रादेश भेजा है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। संबंधित सहकारी समिति को ग्रधिकार है कि वह ग्रपना नलकूप कृषि इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा बनवाये ग्रथवा निजी तौर पर बनवाये।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ट्यूबवेल्स सहकारी समितियां बना रही हैं वे कितने रुपयों में तैयार हो जायेंगे श्रौर सरकार उनमें कितनी सहायता देगी?

श्री राममूर्ति—यह उम्मीद की जाती है कि १५ हजार रुपये में ट्यूबवेल लग सकता है और उसमें ५ हजार सरकारी समितियां इकट्ठा करती हैं और १० हजार रुपया सरकार देती है। इनमें से कुप्रां बनने के बाद ५ हजार रुपया ग्रांट के तौर पर, ५ हजार रुपया लोन के तौर पर भीर शेष तकावी के रूप में दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो किसान लोग श्रपनी सहकारी समितियों के जरिये से ट्यूबबेल बनायेंगे उसमें सरकार के इंजीनियरिंग विभाग की ऐडवाइस प्राप्त रहेगी?

श्री र।ममूर्ति—जी हां। एडवाइस मिल सकती है।

श्री रामदास आर्य—यह जो १४ द्यूबवेल्स मुजफ्फरनगर में बनाये जा रहे है वे किन-किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—१५ नहीं, १८ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। जिन माननीय सबस्य ने सवाल किया है उनके पास पूरी सूची है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार बतलायेगी कि मुजयफ़रनगर का कोई हिस्सा श्रभी ऐसा बाक़ी है जहां कोई सिंचाई का प्रबन्ध श्रभी नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मुझे ठीक तो नहीं मालूम है। मगर हर जिले में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में किसी इंजीनियर से सम्मित ली गयी है कि १५ हजार रुपये से कम में कुंग्रा बन सके ?

श्री राममूर्ति—जी हां। बग़ैर-सोचे समझे श्रौर बगैर इंजीनियर की राय के तो कोई मामला नहीं हो सकता। वह बाकायदा सोच समझ कर एक स्टैंडर्ड ट्यूबवेल की क़ीमत समझी गयी इसलिये ऐसा बनाया गया।

*५३-५४--श्री कमला सिंह (ग्रनुपस्थित) --[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५--श्रो कमला सिंह (ग्रनुपस्थित)--[१ जून, १६५४ के लिये स्थिगत किया गया ।]

शारदा नहर, पुरवा बांच, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि

*५६—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५० को शारदा नहर पुरवा ब्रांच ६६ मील ४ फरलांग पर जो खांदी हुई थी उससे नहर के निकट लगा हुआ खिलहान बह गया था? यदि हां, तो कितने किसानों ने नुक़सान के मुखावजे के लिये प्रायंनापत्र दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापित त्रिपाठी—पुरवा बांच के मील ६६ फर्लांग ४ पर ३०-३-४० को कोई खांदी (breach) नहीं हुई। किन्तु २३-३-५० को पुरवा बांच की दाहिनी पटरी में मील ६६-३-३०० पर एक खांदी हुई थी। खांदी से हुए नुक्सान के लिए केवल एक प्रार्थना-पत्र ग्राम सुठा, डाकखाना गौरा, जिला रायबरेली के काइतकारों की ग्रोर से प्राप्त हुग्रा किन्तु इस पर न तो किसी के हस्ताक्षर ही थे ग्रौर न ग्रंगूठे के निशान ही।

श्रतः खांदी के कारण जो खेत जलमग्न हो गये थे उनकी एक सूची विभाग द्वारा बनाई गई जिसके श्रनुसार १८ रुपये का मुग्राविजा केवल ३ व्यक्तियों को वितरित किया गया, क्योंकि श्रीर किसी काश्तकार की फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

*४७-४८--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बिलया) -- [५ मई, १६५४ के लिये प्रश्न संख्या ६६-७० के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

१६-६१-- भी इसरारुलड्क (जिला न्नागरा) (यनुपस्थित) --[२८ मई, १६५४ के लिये स्थापन किये गये ।]

विधायक निवामों के फरीशों तथा लिफ्टमेनों मे हरिजनों को न लेना

'६२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों में सन् १६५२ ग्रौर १६५३ में कुल कितने फर्राश ग्रौर लिफ्टमैन किस योग्यता के रक्ले गए ग्रोर उनमें परिगणित जातियों (Scheduled Casta) की क्या संख्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सन् ४२-४३ मे रक्खे गए फर्राशो तथा लियट-मंनो का व्यौरा यों है:--

	१६५२	१६५३	परिगणित	जातियां
फरीश	२१	૪		कोई नहीं
लि फ्टमैन	ሄ	२		

शारीरिक पश्चिम करने के योग्य व्यक्तियों को फर्राश तथा लिफ्ट चलाने का काम जानने वालों को लिफ्टमैन रक्खा गया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि सन् १९४२ के पहले विधायक निवासो में कितने फरीश श्रौर कितने लिफ्टमैन थे?

श्री ग्रध्यक्ष--मं इसकी इजाजत नहीं देता। श्रापने ४२-४३ का प्रश्न पूछा है इसलिये उसके पहले का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १६४२-४३ में कई हरिजनो ने फर्राशी में भर्ती होने के लिये दरस्वास्त दी लेकिन उनको क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बजा तो यह है कि वह जो काम है उस काम के करने के लिये जिसको मौजूं समझा जाय उसको दिया जाय लेकिन इस सवाल के ब्राने के बाद मैने हिदायत कर दी है कि उनमें से ब्रादमी जरूर लिये जाया करे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हरिजन शारीरिक परिश्रम में किसी से कम नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी उनको फर्राशों में भर्ती क्यों नहीं किया गया है ?

श्री ग्रध्यक्ष--इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि ग्राइन्दा श्रव यह किया जायगा। इससे श्रापको समझ लेना चाहिये कि वह ग्रलती को महसूस करते है।

साहित्य की प्रतियों के ग्रंग्रेजी में प्रकाशन पर ग्रापत्ति

*६३--श्री सिच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की जो साहित्य की प्रतियां हिन्दी में छाप कर बांटी जाती है उनकी प्रतियां श्रंप्रेजी में छापकर क्यों बांटी जाती है जब कि इसमें दोहरा खर्च होता है ?

श्री राममूर्ति—साहित्य के प्रकाशन की नीति तो प्रदेश के कार्य की जानकारी श्रधिक से ग्रीं से कराने की होती है। यह साहित्य श्रन्य प्रदेशीय राज्यों एवं विदेशी सरकारों

ग्रीर मंन्थाओं ग्रादि को भी जाता है जहां ग्रंग्रेजी का प्रयोग है। इस कारण इसका ग्रंग्रेजी भाषा में भी छपवाना ग्रावश्यक होता है। श्रंग्रेजी साहित्य की संख्या हिन्दी की संख्या से बहुत कम, लगभग एक चौथाई होती है।

श्री मिन्चदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष श्रंग्रेजी साहित्य तथा हिन्दी साहित्य की छपाई में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ?

श्री राममूर्ति-इसकी इन्फार्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री सिच्चदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी श्रंग्रेजी साहित्य की छपाई के व्यय को घटाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राममूर्ति—श्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रभी ग्रजं किया कि केवल एक चौथाई छुपाया जाता हे जो कि ग्रनिवार्य है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सूचना मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि जब देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी है तब फिर अन्य प्रदेशों में हिन्दी में साहित्य भेजने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राममूर्ति—लोकप्रिय सरकार का यह फर्ज हं कि वह श्रपने देश के श्रलावा और भी सब जगह श्रपनी एक्टिविटीज के बारे में बतलाती रहे। इसलिये इस किस्म का यह प्रचार अंग्रेजी में भी किया जाता है।

श्री वृजिवहारी मिश्र (जिला ग्राजमगढ़)—हिन्दोस्तान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी मानी गयी है तो हम ग्रन्य प्रदेशों में हिन्दी की प्रतियां भेजने मे कोई ग्रापित्त समझते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री राममूर्ति——चूंकि पढ़ने वाले अंग्रेजी के ह इसलिये हमें उस जवान मे भी भेजना पड़ता है।

शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेड क्वार्टर बरेली मे रखने का कारण

*६४—श्री हरि प्रसाद (जिला पोलीभीत) (ब्रनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेगे कि शारदा नहर के हेड वर्क्स का हेड क्यार्टर किन सुविधाओं के कारण बरेली में रखा गया है ?

श्री कमलापित त्रिपाठी—हेड वर्क्स डिवीजन की सीमाये नैनीताल, पीलीभीत, खेरी, बरेली श्रीर शाहजहांपुर जिलों में फैली हुपी है श्रीर बरेली सब के मध्य में स्थित है। इस कारण इस डिवीजन का हेड क्वार्टर बरेली में रखा गया है।

*६५—श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केवल उक्त हेड क्वार्टर मे पीलीभीत को प्रतिदिन डाक लेजाने के लिए और वहां से लाने के लिए ही वो व्यक्ति रखें गए हैं?

श्री कमलापित त्रिपाठी—जी नहीं। दो हरकारे जो बरेली ग्रौर बनबसा के मध्य काम करते हे एक सिंकल ग्राफिस, ४ डिबीजन ग्राफिस लगभग १५ दूसरे गजटेड श्रफसर तथा भिन्न-भिन्न डिबीजनो के ५० श्रन्य श्रफसरों की डाक वितरित करते है। इस कारण यह व्यवस्था डाकखाने के द्वारा डाक भेजने से कम व्ययकारक है। *६६—श्री हरि प्रसाद (ग्रनुपस्थित)—क्या यह सही है कि हेडक्वार्टर के पीलीभीत जिले से दूर होने के कारण वहां के किसानों को उनके मुकदमों की सूचना ठीक समय पर नहीं मिल पाती ग्रौर बहुत से मुकदमें किसानों के वहां पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं?

श्री कमलापित त्रिपाठी—जी नहीं। इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, हेड वक्षं डिवीजन नहर के मुकदमें कर्तई नहीं करते हैं श्रौर न किसानों के नहर के मुकदमों के बारे में कोई सूचना या सम्मन भेजते हैं। यह कार्यंडिप्टी रेवेन्यू श्रफसर करते हैं जो दौरे पर मुकदमें ते करते हैं।

ाजला भांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की ग्रावश्यकता

*६७—श्री गज्जू राम (जिला झांसी) (श्रनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर वह पुल बनाने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं । इस पुल के निर्माण के विषय में श्रगली पंच-वर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत विचार किया जायगा ।

*६=-श्री बाबू नन्दन--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]
निर्मद्य क्षेत्रों में ताडी ग्रौर नीरा बेचने की सुविधा

*६६—श्री पाती राम (जिला फर्वेखाबाद) (श्रनुपस्थित)—क्या सरकार Dry districts में ताड़ के पेड़ों में से ताड़ी श्रीर नीरा निकालने श्रीर बेचने की कोई व्यवस्था श्रारम्भ करने वाली है? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसे जिलों में शराब की दुकानें, जहां शराब परिमद से मिल सकेगी, खोलने की कोई व्यवस्था हो रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद स्रली जहीर—ताड़ी निकालने स्रौर बेचने की तो नहीं पर नीरा निकालने स्रौर बेचने की सुविधा देने के लिए सरकार ने Dry districts तथा १४ स्रन्य ऐसे जिले में जहां ताड़ो का प्रयोग नहीं होता, उत्तर प्रदेशीय नीरा (मीठी ताड़ी) नियम, १६५१ लागू कर दिये गये है।

ऐसा इसलिए किया गया है ताफि इन जिलों में खड़े हुए खजूर तथा ताड़ के पेड़ों का रस एक स्वास्थ्य बर्द्धक खाद्य सामग्री के रूप में जनता द्वारा प्रयोग किया जा सके। Dry District में शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*७०-७१-श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)--[१ जून, १६५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*७२-७३--श्री राम लाल (जिला बस्ती)--[१६ मई, १६४४ के लिए प्रक्त संस्था ३६-३७ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७४-७५--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रबाबाद)--[२४ मई, १६४४ के लिए स्थागत किये गये।]

जालीन भ्रौर इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुक्म

*७६--श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला ग्रलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालीन जिला झांसी ग्रीर इंगलास जिला श्रलीगढ़ में वह रजिस्ट्री देशतर फिर से सोलने का विचार रखती हैं?

श्री मैयद ग्रली जहीर--जालीन ग्रीर इगलास में रिजस्ट्री के उपतर १ मई १९५४ ई० में बोबारा खोल देने के लिये हुक्स जारी कर विया गया है।

"৩৩-७६--श्री राम लखन (जिला बनारस)--[१ जून, १६५४ के लिए स्थिगित किये गये।]

४=०-श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--[१८ मई, १६४४ के लिए स्विगित किया गया ।]

*८१--श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला ब्राजमगढ़)--[११ मई, १६४४ के लिए स्थित किया गया ।]

तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में सिचाई का प्रबन्ध

*द२-श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी) -- क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायें। कि तहमील जसराना जिला मैनपुरी में कितनी भूमि पर खेती होती है ग्रीर उसमें से कितनी की सिचाई होती है तथा कितनी की नहीं ?

श्री राममूर्ति—-जसराना तहमील में १,२४,३८४ एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिसमें ने ४४,७६६ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र में स्थित है और लगभग ७६,४८४ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र के बाहर है।

*=3-श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या सिचाई मंत्री कृष्या बतायेगे कि वे तहसील जसराना में उस भूमि की मिवाई के लिए जहाँ पानी के श्रभाव में सिचाई नहीं होती सिचाई का कुछ प्रबन्ध करने जा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—उक्त भूमि की सिचाई के लिये राजकीय नलकूप बनाये जा रहे है जिससे ३३,४०९ एकड़ भूमि की सिचाई सुविधा प्राप्त होगी ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेगे कि जी भूमि नहरी क्षेत्र से बाहर है उसमें कैसे सिचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—जो भूमि नहरी क्षेत्र के बाहर है उसमे लोग अपने मिश्री नरीके में आबपाशी करते हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा -- क्या मंत्री जी यह बताने की कृषा करेंगे कि जो नलकूष बनाये जा रहे है उनकी संख्या कितनी है ग्रीर कब तक तैयार हो जायेंगे।

श्री राममूर्ति—उनकी संख्या ६८ हं श्रोर श्रभी काम शुरू हुश्रा है । यह जरा कहना मृश्किल है कि कब नक तैयार होंगे। हमारी कोर्शिश है कि जल्द से जल्द बनें।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या यह मच है कि जो नलकूप बनाये जा रहे है वे उसी क्षेत्र में बनाये जा रहे है जहाँ का वाटर लेवल ऊंचा है और जहाँ नीचा है वहाँ नहीं बनाए जा रहे है ?

श्री राममूर्ति-इसकी कोई इनकार्मेशन मेरे पास नहीं है।

बस्ती जिले में राप्ती के किनारे बने हुये बांध पर व्यय

*=४-श्री झारखंडे राय-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले मे राप्ती के किनारे जो बांध बना है उममें कृल कितना रुपया ग्रव तक लगा है ग्रोर ग्रागे लगने का तखमीना है ?

श्री राममूर्ति—मिचाई विभाग द्वारा ऐमा कोई बाँध बस्ती जिले मे नहीं बनाया गया। प्रत. यह बाँध कमें बना नथा इस पर क्या व्यय हुन्ना यह मूचना जिलाधीश बस्ती क्यांना गयी ह ग्रीर प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायगी।

श्री झारखंडे राय-क्या माननीय मंत्री महोदय के पास कोई ऐसी शिकायत आपी हु क्षा मुचन। मिली ह कि यह बाँध नदी के किनारे होने के नाने, बनुई मिट्टी के कारण क्रमचोर ह ग्रीर बरसात में भजबूत कर देना चाहिये?

श्री राममूर्ति—मंन ग्रजं किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैं जिस्ट्रेट में सूचना मगायी है ग्राने पर पेश की जायगी।

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क मे ली गयी भूमि का मुम्रावजा

*दूर—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (स्रतु निश्वत)—क्या मरकार कृपा करके बनायेगी कि जौनपुर जिले में रामपुर बाजार में परिचत बाजार तक की सडक बनाने में क्या उम क्षेत्र के किसानों की जमीन भी ली गयी थी ?

श्री गिरधारी लाल--जी हाँ।

*ट६--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (ग्रनुपस्थित) --यदि हाँ, तो क्या किमानो वे खेत का मुग्रावजा दिया गया था ?

श्री गिरधारी लाल--जी हाँ।

*=७--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (ग्रनुपस्थित) --क्या सरकार बताने रा कृपा करेगी कि जिन किसानों को अब तक मुग्रावजा नहीं दिया गया है उन्हें कब तक दिया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—जो लोग ग्रपना मुग्राविका लेने जिलाधोश के पास गये उनको मुग्रावका दे दिया गया। जो लोग ग्रपना मुग्रावका लेने श्रव तक नही श्राये ह वे जब उसकी लेने जिलाधीश के पास जायेंगे तब इस सम्बन्ध में श्रावश्यक कार्यवाही की जाथगी।

जिला मथुरा की तहसील छाता में गर्की का नाला निकालने का कार्य

*दद-शी रामहेत सिंह (जिला मथुरा) -- क्या सिचाई मंत्री बताने की कृषा करेगे कि मथुरा जिला तहसील छाता में जो गर्की का नाला निकालने की स्कीम थी उस पर कब से कार्य शुरु होगा ?

श्री राममूर्ति—जिला मयुरा तहसील छाता में हलवाना, वर्थन, धर्म सिंहा नालों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम हेर्तीसह—क्या मंत्री जा यह बतायेंगे कि इस नाले को निकालने की माँग वहाँ के लोगों की १० साल से बराबर चली श्रा रही हैं?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है श्रीर सन् १६४२-५३ में ३.६०,६०० का तखमीना हुआ था कि नाला बनाया जाय लेकिन फाडनेंशियल स्ट्रिन्जेसी होने की वजह से काम नहीं चालू किया गया। इसलिए इस बात के जानने की कोशिश की गयी कि वहाँ के लोग अभदान के लिए तैयार है। उस वक्त इस बात का पता नहीं लगा। दुबारा पता लगा कि नैयार ह श्रोर इस काम को पुरा किया जाय।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां यह नाला निकालने की योजना है वहाँ विकास योजना के श्रन्तर्गत एक ब्लाक इम वर्ष स्वीकार हो गया है उसते इम स्कीम को चलाने में श्रापको मदद मिलेगी ?

श्री राममूर्ति—इस इन्फार्मेशन के लिये में माननीय सबस्य का बहुत शुक्रिका श्रदा करता हूं।

द्रागरा तथा मथुरा जिलों की सिचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की ग्रावश्यकता

*दह-शी तेजा सिंह (जिला मेरठ) (ग्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बनायेगी कि हिन्डन नदी पर गाजियाबाद के निकट कोई डैम ग्रागरा तथा मथुरा जिलो की निचाई के हेतु बनाया जा रहा है?

श्री कमलापित त्रिपाठी--ग्रागरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई की दृष्टि से, ग्रागरा नहर के जल की मात्रा बढ़ाने के लिए, गाजियाबाद के निकट हिन्डन नदी पर बाँघ वनाकर जल एक्जित करने का प्रस्ताव है। इस विषय में जाँच हो रही है।

तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में नल-कूपों का कार्य

*१०-श्री दाताराम (जिला सहारनपुर) (ग्रनुपस्थित)-क्या सरकार कृषा करके बतायेगी कि तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में १९५२ ई० मे जो ट्यूबवेल्स लगने वाले ये वह श्रभी तक क्यों चालू नहीं हुए हैं ?

श्री कमला पितित्रिपाठी—तहसील नकुड़ (जिला सहारनपुर) में बनने वाले ३६ नलकू वों का ठेका में सर्व ऐसोशियेटेड ट्यूब बेल्स लिमिटेड को दिया गया था। उक्त कम्पनी को प्रदेश के श्रन्य जिलों में भी नलकूप बनाने थे। क्योंकि सहारनपुर जिले में भू: स्तर कड़ा था. कन्यनी वहाँ नलकू पों के बोरिंग का कार्य जून १९५३ के पहले प्रारम्भ न कर सकी। मार्च १९५४ के श्रन्त तक नकुड़ में ४ नलकूप बनाकर चालू कर दिये गए है।

*११--श्री दाताराम (श्रनुपस्यित) - - नया सरकार वतायेगी कि वह ट्यूबवेल्स कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्राज्ञा है कि जून १९४४ तक ग्रधिकतर नलक्ष तैयार होकर चालू कर दिये जायेंगे।

वहादुरीपुर और सिहजनी के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना

*हर-श्री राज कुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)-व्या सरकार को ज्ञात है कि बहादुरीपुर श्रीर सिंहजनी के कृषकों ने गरई नहर के शेरवा माइनर से श्रमदान द्वारा एक छोटी माइनर खोदने के लिए सरकार से एक प्रार्थना-पत्र द्वारा उसकी पैमाइश श्रीर दागवेल करने के लिए प्रार्थना की है? यदि हों, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री राममूर्ति—उक्त ग्रामों के किसानों ने शेखा माइनर खोदने के लिए प्रार्थना की थी। परन्तु इस सम्बन्ध में जाँच से पता चला कि वहाँ के किसानों के लिये ग्रन्थ कोई माइनर निकालने की ग्रावञ्यकता नहीं है क्योंकि ये ग्राम चिकया रजबहे के कुलाबा संख्या १३ के ग्रिवकार क्षेत्र के ग्रन्थर है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर मुझे दिया गया है यह चिकया रजबहा बनारस से सम्बन्ध रखता हे श्रीर मेरा प्रश्न मिर्जापुर की गिरई नहर से सम्बन्धित हैं?

श्री राममूर्ति--मेरे पास तो जो इन्फा मेंशन है, ग्रध्यक्ष महोदय, वह मैने पढ़ दी।

श्री ग्रध्यक्ष--श्री राजकुमार शर्मा जी, ग्राप जरा इसको स्पष्ट करे कि क्या बात ह।

श्री राजकुमार गर्मा—श्रध्यक्ष महोदय, मेरा प्रक्त गिरई नहर मिर्जापुर जिले से सम्बन्ध रखता है, श्रोर यह उत्तर मुझे मिला है चिकया रजबहा, जिला बनारस से सम्बन्ध रखता है जो इन गांघों से दस मील की दूरी पर है।

श्री ग्रध्यक्ष—जो इत्तला उनके पास थी, वह उन्होंने दे दी। गांव तो वही ह, या गांव भी दूसरे जिले के हैं ?

श्री राजकुमार शर्मा--जी हां, गांव तो वही है।

श्री अध्यक्ष —तो आपको पहले ही जिला लिख देना चाहिए था। इसमे तो दोष आपका हो मालूम होता है।

मेरठ मे विदेशी शराब बेचने के स्थान

*६३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या ब्राबकारी मन्त्री बताने की कृया करेगे कि क्या यह सही है कि मेरठ में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक ब्रौर ७ फुटकर दुकानों तथा २ होटल श्रौर एक रेस्ट्रां को लाइसेस दिये गये थे श्रौर पिछले साल कुछ श्रौर भी लाइसेस दिये गये है ? यदि हां, तो किस-किस को ?

श्री सैयद ग्रली जहीर—मेरठ शहर में पिछले साल के शुरू में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक, प्रकुटकर, २ होटल तथा १ रेस्ट्रां के लाइसेंस थे। पिछले साल एक रेस्ट्रां लाइसेंस क्वीन्स रेस्ट्रां के मालिक श्री सत्यबीर लुम्बा को दिया गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब सरकार की नीति शराब बन्द करने की हैं, तो ऐसी हालत में नये लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं ?

श्री सैयद श्रली जहीर—बजाय इसके कि कोई एक दूकान की मानोपली हो ग्रौर श्रकेले वही बेचे, यह बेहतर समझा जाता है कि दो दूकाने हों, ताकि जनता को एक दूकान होने की वजह से जो तकलीफे हो जाती है, वे न होने पायें।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—क्या ग्रानरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जो दुकाने ज्यादा खोली जा रही है, या ज्यादा लोगों को लाइसेस दिये गये है उसके मुताल्लिक गवर्नमेट के पास कोई शिकायते ग्रायी है कि उसकी वजह से शराबखोरी बढ़ रही है?

श्री सैयद श्रली जहीर-जी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं श्रायी हे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेगे कि इन लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए श्रीर रजिस्टर्ड दुकानदारों तथा होटल वालों की भी दरस्वास्तें सरकार के सामने श्रायी थीं ?

श्री सैयद श्रली जहीर—जी नहीं, सरकार के सामने दरस्वास्तें नहीं श्रायी थी। होता यह है कि एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसके सामने दरस्वास्ते पेश होती है, जब वह

सिफारिश करती है, तो वह जिलाधीश के पास जाती हैं, श्रौर जब वह मंजूर करते हैं, तो एक्साइज किमश्नर के पास श्राती है। इसके बाद सरकार के पास दरख्वास्त श्राती है। जब वह मुत्तफिक नहीं होते हें कि कोई लाइसेंस दिया जाय या नहीं, उस वक्त फैसला किया जाता है। श्रगर सब मुत्तफिक होते हैं, तो कोई बात नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या श्रानरेबिल मिनिस्टेर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनकी दरख्वास्तों पर कायदे के मुताबिक जैसा कि उन्होंने बतलाया, सिफारिश हुई था?

श्री सैयद श्रली जहीर--जी हां, इसके बगैर कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये लाइसेंस देने के बाद शराब की बिक्री मेरठ में कम हुई है या बढ़ी है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में तो जो पहले थी वही है। बजाय इसके कि

श्री देवदत्त मिश्र(जिला उन्नाव)—क्या सरकार होटल में बैठकर शराब पीने के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने पर विचार कर रही हैं?

श्री सँयद ग्रली जहीर—यह तो पालिसी का मामला है। यह सवाल इससे उठता नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—मैं यह ग्रर्ज कर रहा हूं कि 'सवाल उठता नहीं है' क्या गवनंमेंट को यह जवाब देने का हक हं जब कि ग्रापने उनको जवाब देने के लिए बुला लिया है तो यह सवाल उठता है या नहीं।

श्री श्रध्यक्ष—ग्रगर यह माना जाय कि जवाब मुझे है तब तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन ग्रगर उनके जवाब का एक हिस्सा वह भाग हो कि इस प्रश्न से प्रश्न नहीं उठता तो उसमें कोई बात नहीं हूं। यह जवाब का हिस्सा माना जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या ग्रानरेबुल मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी दरस्वास्त पर किसी पोलिटिकल पार्टी ने या उसके मेम्बरों में उसकी सपोर्ट में दस्तखत किये थे ?

श्री ग्रध्यक्ष--यह तो इससे उठता नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवमंगलिंसह कप्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहाड़ पर ठंडक ज्यादा होने की वजह से वहां पर नये लाइसेंस देने के प्रक्षन पर वह विचार कर रही है?

श्री ग्रध्यक्ष—इसकी भी में इजाजत नहीं देता।

श्री क्यामलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दूकानें हटायी जाती हैं, वह गरीबों के मुहल्ले में भेज दी जाती हैं ?

श्री ग्रध्यक्ष--यह भी इस से नहीं उठता। में समझता हूं कि इस शराब के मामले में बहुत मुस्तिलिफ किस्म की दिलचस्पी दिखलायी पड़ती है। मुझे श्रागे बढ़ना पड़ेगा।

चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की स्रावश्यकता

*१४—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौराहा कासगंज सड़क पंचवर्षीय योजना में पक्की होने के हेतु शामिल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचवर्षीय योजना मे ग्रधिकतर प्रथम चरण के ग्रपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है। चौराहा कासगंज सड़क प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं थी, ग्रौर इस कारण इसको पक्का करने का कोई ग्रायोजन पंचवर्षीय योजना मे शामिल नहीं है।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेगे कि सरकार ने इस सड़क पर पिछले वर्ष में मिट्टी डलवायी थी श्रौर इस सड़क को जिला बोर्ड से श्रपने हाथों में लिया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ग्रौर सड़कों के साथ इसको भी लिया गया होगा ग्रौर बाद मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया होगा।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की ग्रावक्यकता को देखते हुए सरकार इस सड़क को कब ग्रपने हाथ में लेकर बनवायेंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क को बनाने का ग्रभी विचार नहीं है, क्योंकि यह कोई सास महत्व की सड़क नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या माननीय मिनिस्टर को यह मालूम है कि जिस वक्त उन्होंने यानी गवर्नमेट ने इस सड़क को ग्रपने हाथ में लिया था, उस वक्त से श्राज तक उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-जी नहीं। खराब नहीं हुई।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—यह सड़क जिस वक्त जिला बोर्ड को दी गयी थी, तो जिला बोर्ड की इच्छा से दी गयी थी, या जबरदस्ती दी गयी थी कि वह उसको बनवायें?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इच्छा से तो कोई बात नहीं की गयी थी। न तो इच्छा से ली गयी थी ग्रीर न इच्छा से दी गयी। वह तो एक पालिसी के मुताबिक सब किया गया।

श्री राम चन्द्र विकल-क्या माननीय मन्त्री जी महत्वपूर्ण सड़कों की कोई सूची रखते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

(प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुम्रा।)

भ्रतुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रश्न नहीं उठता' कहने पर श्री भ्रध्यक्ष का निर्णय

श्री नेकराम दार्मा—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ ग्रापका घ्यान ग्राक्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि ग्रध्यक्ष महोदय किसी प्रश्न को स्वीकार कर लेते है, ग्रौर माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि वह जवाब दें तो क्या माननीय मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता ?

श्री श्रध्यक्ष—जो प्रश्न में स्वीकार कर लेता हूं, उसका तो जवाब वह दे देते हैं। पूरक प्रश्नों में कुछ ग्रगर सिर्फ इतना ही कहें, कि 'प्रश्न नहीं उठता' ग्रौर बैठ जायं, तो में उसको ग्राक्षेप समझता हूं। वह उन्हें नहीं कहना चाहिए। वैसे भी ग्रपने जवाब के साथ ऐसा मत जोड़ना नहीं चिह्ए। साधारण नियम यही है। लेकिन उसके साथ ग्रगर पहले कुछ उन्होंने शब्द कहे ग्रौर थोड़ा सा ग्राधा जवाब दिया ग्रौर बाद में ग्रगर कह दिया कि उठता भी नहीं है, तो उससे मेरे निर्णय पर ग्राक्षेप नहीं होता।

[श्री ग्रघ्यक्ष]

इसलिए मैंने इसको ग्राक्षेप नहीं समझा, क्योंकि कुछ जवाब दिया ग्रौर जब वह जवाब का ही हिस्सा था, तो यह कह दिया कि 'प्रश्न नहीं उठता'। श्रगर वह खाली यह कह देते कि प्रश्न उठता नहीं तो मुझे कहना पड़ता कि मैं ठोक समझता हूं कि उठता है। ग्रौर ग्रापके लिए यह कहना उचित नहीं है। ग्राइन्दा के लिए मैं मन्त्री महोदयों से कह देना चाहता हूं कि ग्राखिर में भी यह शब्द न जोड़ें, तो ग्रधिक उचित होगा। जिसमें मेरे निर्णय पर टीका होने की सदस्यों को शंका होती है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

हाथरस तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप

*ध्य-श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हाथरस में कितने टचूब वेल श्रीर बनने बाकी हैं, श्रीर वे कब तक चालू हो सकेगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाथरस तहसील में बनने वाले ३८ नलकूपों में से २४ नल- कूप श्रभी बनने बाकी हैं।

आञा की जाती है कि यह नलकूप मार्च, १६५५ के ग्रन्त तक बन कर तैयार हो जायेगे।

*ह६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार सासनी क्षेत्र के १२ नलकूप को चालू करने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो वह कब तक पानी देने की स्थित में हो जायेगा?

श्री कमलापित त्रिपाठी—सासनी ग्रुप नलकूप संख्या १२ का बोरिंग पूरा हो चुका है। ग्रब इसका परीक्षण किया जायगा और यदि पानी का निकास (discharge) सन्तोषप्रद हुन्ना तो इसको पूरा करके जुलाई, १९५४ तक चालू कर दिया जायगा।

जिला हमीरपुर में निर्माण की गई पक्की सड़कें

*१७—श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १६५१-५२ तथा १६५२-५३ में जिला हमीरपुर में कुल कितने मील पक्की सड़क बनवायी गयो ?

श्री गिरघारी लाल—सन् १६५१-५२ में २३ मील ५ फर्लागं नयी तथा ११ मील पुनः निर्माण, कुल ३४ मील ५ फर्लागं पक्की सड़क बनायी गयी।

सन् १९५२-५३ में ११ मील ४ फर्लांग, नवीन तथा ६ मील ४ फर्लाग पुनः निर्माण,

*६८-श्री मन्नी लाल गुरुदेव-स्या सरकार को ज्ञात है कि कुल जिला भर में कोलतार की कितनी सड़क है ?

श्री गिरधारी लाल-मार्च, १९५४ के ग्रन्त तक हमीरपुर जिले में तारकोल की कुल सड़कों की लम्बाई ११ मील है।

रिखणी खाल-बनजीया देवी सड़क पर लट्ठों के पुल का निर्माण

*६६—श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पौ० डब्ल्यू० डी० सड़क रिलणीलाल व कोटडी के बीच का पुल बन कर तैयार हो गया है, जिस से उस पर जानवर चल सकें ? यदि नहीं, तो उसको ग्रघूरा छोड़ने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—अनुमान किया जाता है कि सदस्य महोदय का ग्रभिप्राय रिखणी-खाल बनजीया देवी सड़क पर स्थित लट्ठों के पुल से है। बायें ऐप्रोच रोड छोड़कर यह पुल पूर्ण हो गया है। श्राशा की जाती है कि यह ऐप्रोच रोड चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगी। पुल की वर्तमान स्थिति में ग्रावागमन में कोई रुकावट नहीं है।

जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत

*१००--श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्हिरिया सागर बांघ (तहसील मौदहा) जिला हमीरपुर की मरम्मत कब से नहीं हुई है? क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी है कि उक्त बांघ की मरम्मत तीन वर्षों से नहीं हुई और उसमें तीन चार जगह तो इतने बड़े कटाव हो गये है कि उसके टूट जाने का भय है? इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापित त्रिपाठी-कम्हिरिया सागर बांध की मरम्मत १६५१-५२, १६५२-५३ तथा १६५३-५४ में की गयी है श्रीर उक्त वर्षों में इस कार्य पर क्रमशः ७१८ ६०, ६०० ६०, तथा १,६७३ ६० व्यय हुए। इस बांध की मरम्मत के विषय मे कोई शिकायत सरकार के पास नहीं श्रायी है। गत तीन वर्षों में यह बांध श्रपनी पूर्ण क्षमता तक भरा गया था, परन्तु उसमें कोई खांदी (कटाव) नहीं हुई।

प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क पर व्यय

*१०१-श्री राम ग्रधार तिबारी (जिला प्रतापगढ़)--वया सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ से गड़वारा व पूरबगांव होती हुई, सागीपुर तक जाने वाली सड़क पर जब कि यह सड़क P. W. D. के पास कुछ समय के लिए थी सरकार ने कितना व्यय किया था?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का केवल गड़वारा से सागीपुर तक का भाग सार्वजिनक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था तथा जब तक वह इस विभाग के ग्रन्तर्गत रहा तब तक उस पर २६,७२५ रु० व्यय किया गया।

*१०२--श्री राम ग्रधार तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उपर्युक्त सड़क को फिर से अपने हाथ में लेकर पक्का करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल-उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के ग्रन्तर्गत लेने तथा पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर जिले के पिश्चमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप

*१०३—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर) (ग्रनुस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में कितने Tubewells बनने जा रहे हैं ग्रीर वे कब तक बन जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में १९ नलकूप बनने जा रहे हैं ग्रौर ग्राशा की जाती है कि यह नलकूप सितम्बर, १९४४ के ग्रन्त तक बनकर तैयार हो जायेंगे।

बहराइच जिले में सरयू नदी से नहर निकालने की योजना

*१०४--श्रो बसन्त लाल शर्मा-क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले के प्रकार नानपारा एवं बहराइच तहसीलों में बहनें वाली कोई नहर को सरयू नहीं से निकालने की बीजना स्वीहात ही चुकी है? श्री कमलापति त्रिपाठी—सरयू नदो से नहर निकालने की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिम्मिलित करने का विचार है।

*१०५—श्री बसन्त लाल शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उक्त योजना के निमित्त कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और अब तक कितना ब्यय हो चुका है?

*१०६ स्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त योजना में अभी तक कितनी अगित हुई है और उसके कब तक सफल हो जाने की आशा है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—ये प्रश्न नहीं उठते। क्योंकि ऐसी कोई योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिम्मिलित नहीं है। गत महोनों में इन इलाकों में सिचाई की सुविधा के लिये उपायों की लोज करने की दृष्टि से जो परीक्षण हुए हैं, उनके श्राधार पर सर्य से नहर निकालने की स्कीम बनायी गयी है, जिसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिम्मिलित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

म्राजमगढ़ जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण

*१०७—श्री श्रीनाथराम (जिला ग्राजमगढ़)-क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृषा करेंगे कि ग्राजमगढ़ जिलें में मऊ कासिमाबाद सड़क के लिए १९५२-५३ में कितना रुपया स्वीकृत हुग्रा था?

श्री गिरधारी लाल—१९५२-५३ में ५०,००० रु० का श्रनुदान (ग्रान्ट इन एड) जिला बोर्ड, ग्राजमगढ़ को इस सङ्क पर श्रकाल पीड़ित सहायतार्थ निर्माण के लिये दिया गया था।

*१०८—श्री श्री नाथ राम—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क को बनाने में अब तक कितना रुपया व्यय हुआ और कितना शेष हैं ?

श्री गिरधारी लाल—मार्च, १६५४ तक २०,६३२ रु० व्यय हो चुकें है ग्रौर १६,०७८ रु० गेष है।

*१०६-श्री श्रीनाथराम-क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क का निर्माण का कार्य बिलकुल बन्द है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—कुछ काम छऽवें मील में भूमि उपलब्ध न होने के कारण बन्द है। इस सम्बन्ध में श्रावस्थक कार्यवाही की जा रही है?

आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण

*११०—श्री उमाशंकर (जिला प्राजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि ग्राजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर ग्रौर बलिया में २०० नलकूपों की योजना में से ग्राजमगढ़ तथा गाजीपुर में जो ७० तथा ४० नलकूप बनने वाले हैं, वे कहां-कहां बनेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—-२०० नलकूपों की योजना के ग्रन्तगंत ग्राजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों में नलकूपों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है:---

श्राजमगढ़ जिले में :		
घोसी तहसील में	• •	२४
मुहम्मदाबाद जोहना	• •	२३
संगड़ी जोहना	• **	હ
श्राजमगढ़ जोहुना	* *	X
		50

इनके म्रतिरिक्त इस जिले में जो १० नलकूप भ्रौर बनेंगे, उनकी स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायगी ।

इस जिले में बाकी १५ नलकूपों की स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायेगी। जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की दुकानें

*१११—श्री महीलाल—क्या मादक कर मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कुल कितनी दूकान देशी व विलायती शराब की है ?

श्री सैयद ग्रली जहीर—मुरादाबाद जिले में देशी शराब की ३८ ग्रौर विलायती शराब की ५ दूकानें हैं।

*११२--श्री महीलाल-क्या यह सत्य है कि ग्राम ग्रकरौली के निवासियों ने ग्रनेक बार यह प्र र्थना सरकार से की है कि उनके यहां शराब की दूकान न रखी जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर ग्रब तक क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, सरकार के थास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्वतारांकित प्रक्न

१-श्री हरि प्रसाद-[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

२-३-श्री मोहन सिंह शाक्य (जिला एटा)--[१६ मई, १६४४ के लिए प्रश्न संख्या ४-६ के ग्रन्तर्थत स्थानान्तरित किये गये।]

४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[१८ मई, १९५४ के लिये स्थागित किया गया]। ५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[११ मई, १९५४ के लिए स्थागित किया गया।]

लाउडस्पीकर भ्रौर पंखों की खराबी

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि पीछे सुनाई नहीं देता ग्रीर पंखों की हवा भी नहीं लगती।

श्री ग्रध्यक्ष—पंखों की हवा तो मैं समझता हूं कि लगती होगी। लाउडस्पीकर के के लिये मैं कार्यवाही करूंगा, जो हो सकेगी।

श्री राजनारायण की कथित ग़ैरकानूनी गिरपतारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री ग्रध्यक्ष — मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठो जी ने मेजा है। वह इस प्रकार है —

"श्री राजनारायण, नेता विरोशी दल को, जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ और ११७ के मातहृत, गैरकानूनी गिरफ्तारी पर, जिससे कि उनको विधान सभा की सेवा से बंधित रक्षा [श्री ग्रध्यक्ष]

जा रहा है, से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद-विवाद के लिये विधान सभा भ्रपना कार्य स्थिगित करती है।"

एक तो इसमें यह शब्द श्राये हैं कि उनको विधान सभा की सेवा से वंचित रखा जा रहा है। कामरोको प्रस्ताव के संबंध में जो नियम ७० है उसके चौथे श्रंश में यह है——

"the motion shall not raise a question of privilege"

काम रोको प्रस्ताव में कोई प्रिविलेज का सवाल उठाया नहीं जा सकता।

तो इसमें एक ग्रंश तो यह है कि जो विधान सभा की सेवा से वंचित रखने का सवाल है इसलिये प्रिविलेज का होता है, वह काम रोको प्रस्ताव में नहीं ग्रा सकता । यह ग्रंश शामिल होने से प्रस्ताव श्रवंध है।

दूसरे जो वह यह कहते हैं कि १०७ श्रौर ११७ धाराश्रों के मातहत जो गिरपतारी हुई वह गैरकानूनी है, यह प्रश्न भी रोज के इन जाम से सम्बन्धित है। इस विषय पर कई विधान सभाश्रों की रूलिंग्स हैं। केन्द्रीय विधान सभा के दो एक निर्णय में माननीय सदस्यों को सुनाय देता हूं।

एक ऐंड जर्नमेंट मोशन तो १६४१ में केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्राया था।

"Action taken by authority in due administration of law: cannot be subject of:"

उसका यह हेडिंग है:

"On the 22nd February, 1941, a member sought to move the adjournment of the Assembly to discuss the arrest of a candidate for the Central Assembly. The Home Member said he had no information about the matter but it appeard that the action had been taken by the Provincial Government under its own powers. The President disallowing the motion remarked:—

"This Assembly is not a tribunal for trying these cases, it is the matistrates and the judges who have got to try such cases, and it has been repeatedly laid down in this House and in the Parliament that with regard to any act done by any authority in the due course of the amdinistration of law whatever the law is —the matter cannot be discussed on an adjournment motion. Therefore, the motion is disallowed."

यानी साधारण इन्तजाम का मसला, जो ग्रिधिकारी ग्रपने ग्रिधिकार के साथ कार्यवाही कर देता है, उसके बारे में चाराजोई यहां पर नहीं हो सकती, बल्कि श्रदालत में होनी चाहिये, मैजिस्ट्रेटों के सामने होनी चाहिये।

श्रौर भी है, सन् १६४० केंद्रीय सभा में ग्रध्यक्ष द्वारा यह फैसला हुन्ना है कि--

"Arrest of a Member under the ordinary law of the land does not tantamount to breach of privilege nor can be the subject matter of an Adjournment Motion."

यह २८ फरवरी, १६४० को स्पीकर ने फैसला किया था। यह निर्णय स्रभी हाल का

ऐसी स्थित में गिरफ्तारी का कार्य कि यह वैध था या अवैध था, इस प्रश्न का सबन फैंसला नहीं कर सकता। मैंने कल सबन को इस संबंध में मैजिस्ट्रेट के पत्र की इस्ता वे बी थी और इस इस्ता के बाद यह काम रोको प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ। मैंने इसका जिक इसलिये यहां पर विशेषतीर पर कर दिया कि विरोधी दल के नेता से संबंधित प्रश्न होने के कारण यह महत्वपूर्ण है और इस विषय के अपर बहुत से माननीय सबस्यों की भावनाएं भी उसेजित होंगी। तो यह तो नियम के संबंध में बात हुई इस कारण काम रोको प्रस्ताव की हैसियत से में इसकी अनुनित

नहीं देता हूं कि वह पेश हो और इसको अवैध करार देता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह सूचना देना उचित समझता हूं कि मुझसे श्री राम नारायण जो ने मेरे कमरें मे यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मत्री जी से उनकी बातचीत हुई थी और वह कुछ इस घटना पर प्रकाश डालना चाहते है इस विषय पर कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी कोई बात हो तो में अपने नेता माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं, इस कार्य के उपर जो हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) — यह मामला तो इस वक्त श्रदालत में पहुंच चुका है श्रीर इस हैसियत से उसके ऊपर कोई बहस श्रीर गुफ्तगू तो यहां नहीं हो सकती है हाउस में श्रव। बाकी यह कि किन हालत में गिरफ्तारी हुई, वह खुद ऐसी चीजे हैं, जो श्रदालत के सामने होंगी। तो मंं तो श्रव श्रजं करूंगा कि इस वक्त इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष--तो श्राप इसके ऊपर जरा भी कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं समझते?

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की स्रवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला ग्रत्मोड़ा)—ग्रध्यक्ष महोदय, मं एक विशेषा-धिकार की ग्रवहेलना का प्रदन श्राप के सामने उठाना चाहता हूं। माननीय राज नारायण सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य है उनको कानपुर की ग्रथारिटीज ने इल्लेगली मालेस्ट कर के इस विधान सभा के कार्य से वंचित कर के इस ग्रादरणीय सदन का भी ग्रपमान किया है ग्रौर उसके विशेषाधिकार की भी ग्रवहेलना की है। में उसके लिये फ़र्स्ट ग्रपार्चुनिटी ले रहा हूं ग्रौर लिख कर के यह कम्प्लेट ग्राप के सामने पेश कर दूंगा।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ ंखंड १३ (ऋमागत)

श्री ग्रध्यक्ष--- ग्रब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुम्रा है, विचार जारी होगा।

श्री गेदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में कल निवेदन कर रहा था कि मेरे ऊपर रामनरेश जी ने यह दोष लगाया था कि मेने इस विधेयक को पूरी तरह से पढ़े बिना ही इस संशोधन को रखा है मेन उनसे यह दरख्वास्त की थी ग्रगर मेरे ऊपर यह दोष लगाया जा सकता हो तो शायद मेरी ही श्रेणी में माननीय राम नरेश जी भी ग्रायेगे। मैंने यह भी निवेदन किया था कि में उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यहां जो मेरा संशोधन है वह इस घारा को उठा देने के लिये हैं इसमें यह लिखा हुग्रा है "यदि पंचायतों के चुनाव में कुछ जगहें ऐसी रह जाय जिन पर चुनाव न हो सके तो उन जगहों को पूरा करने का प्रधिकार गांव पचायतों को न होना चाहिये बल्क जो प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी स्टेट की तरफ से बनेगी उसको यह ग्रधिकार होना चाहिये कि वह उन जगहों को भर दे। कहीं यह प्रश्न तो था हो नहीं कि सारी की सारी गांव पंचायत न बन सकें तो ऐसी हालत में सरकार क्या करे। में तो यह कहना चाहता हूं कि ग्रगर सारा का सारा गांव पचायतें नहीं बनाना चाहता है तो यह बदिकस्मती सरकार

^{*}संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९४४ की कार्यवाही में छुपा है। इं३० अप्रैल, १९४४ की कार्यवाही में छुपा है।

[श्री गेदा सिंह]

की नहीं है बिल्क बदिकिस्मती उस गांव की भी है और सरकार को उसके लिये बन्दोबस्त करना चाहिये कि गांव के लोगों को समझाया जा सके तािक गांव में पंचायत बनाने के लिये कोरम पूरा हो सके और ऐसी हालत में में समझता हूं कि गांव पंचायते बन जांयगी। कोरम के लिये भी अभी कुछ दिन पहले जब इस सदन में विचार हुआ था तो माननीय राम नारायण जी का संशोधन सरकार ने इसलिये अस्वीकार कर दिया था कि कोरम बहुत बड़ा न होना चाहिये और ऐसा कोरम होना चाहिये जो कोरम कि आसानी से इकट्ठा हो सके। इसलिये इसमें कोरम का भी कोई झंझट नहीं रहता। अगर एक भाग के ही लोग ग्राम पंचायतें बनाने के लिये राजी हो जायं तो फिर सरकार को कोई परेशानी नहीं रहेगी कि सरकार पूरे के पूरे गांव पर अपनी प्रेस्काइब्ड अथारिटी द्वारा कोई गांव पंचायत लावे। तो यह चिन्ता तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिये। मै उन माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा, जिन्होंने गांव की पूरी पंचायत न बनाने की जिम्मेदारी इस उपधारा पर बहु जिम्मेदारी नहीं है।

श्रव दूसरी बात यह है कि श्रगर कुछ जगहें खाली रह जाती है तो उनके लिये क्यों न स्रिधकार दे दिया जाय उसी गांव पंचायत को जो पहले से बन चुकी है। उसी को श्रिधकार दिया जाय कि जो जगहें खाली है वह उनको भी भर ले। मेरी जानकारी है कि किसी भी कमेटी मे या किसी भी पंचायत मे इस तरह का, श्रिधकार देना कोई श्रसाधारण बात नहीं है, साधारण तौर पर इस तरह के श्रिधकार दिये जाते है। एक बड़ी कमेटी बनेगी श्रीर उस कमेटी के बन जाने के बाद श्रगर उसमें कुछ स्थान खाली है तो बड़ी कमेटी वाले श्रपनी रुचि के मुताबिक श्रादमी चुन सकते हैं जैसे कि श्रगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया हो जिसके श्राने से पंचायत के कार्य में क्षमता बढ़ सकती हो या किसी कम्युनिटी का कोई ऐसा श्रादमी छूट गया हो जिसके छूटने से पंचायत की बदनामी होती हो या पंचायत के काम में दिक्कत होती हो उस कमेटी को ही इन बातों का ज्यादा एहसास हो सकता है बनिस्वत प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी का जिक्र हुआ है श्रीर इस विधेयक मे यह कह देना कि एक ही प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी हर जगह काम करेगी बहुत कठिन है तो फिर बेसी हालत में ऐसी जगहों को भरने के लिये प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी क्या होगी यह नहीं कहा जा सकता।

श्रध्यक्ष महोदय, में प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी के संबंध में कुछ श्रधिक तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो श्रधिकारी है उनके बारे में हमारे विचार कुछ बदलते जाते हैं और अगर दुर्भाग्यवश कानपुर जैसे ही श्रधिकारी सूबे भर में निकल जांय तो फिर उन श्रधिकारियों के लिये एक बड़ी दुर्भावना फैलेगी। मैं उस बात के लिये बहुत जोर देना चाहता हूं और उतना में ध्यान माननीय मंत्री जी का और सदन का जरूर श्राक्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे विरोधी दल के नेता जैसी हैसियत के व्यक्ति को कानपुर अथारिटीज ने रोक रखा है वह कोई शोभनीय बात नहीं है और इस डेमोक्रेसी के लिये यह बड़ी भारी खतरनाक बात है। यह बात ठीक है कि हम ऐसे कानून में श्रदालत में ही चाराजोई जा कर कर सकते है लेकिन.....

श्री ग्रध्यक्ष—यह विषय इस से संबंधित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि वह इस बहस की चीज नहीं है लेकिन में अपनी भावना को जो अथारिटी के संबंध में हो सकता है उसके बारे में संकेत करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के अधिकारों है तो उनके बारे में क्या भावना रख़ं और हम उनके अपर कैसे विश्वास करें और हम उनके साथ में अपनी गर्दन को कैसे दे दें। हमारी मजबूरों है कि हम माननीय मंत्री जी के इस सुझाव को स्वीकार करने में असन थें हैं जिसमें वह यह कहते हैं कि जितनों भी जगहें खाली हों उनके लिये प्रेस्काइ अथारिटी को अधिकार दे दें कि वह जिसकों चाहें उसको कर दें। हमारा जो अनुभव है वह हमकी बतलाता है कि ऐसी बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे यह दरक्वास्त करूंगा कि वह इस बात के लिये जोर न दें और न

पिछले कानून में ऐसी बात रही है श्रौर न इस कान्न में रखने की उसकी कोई जरूरत मालूम होती है। मैने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि जो पंचायत श्रगर नहीं बनी तो उनके लिये क्या किया जाय। में फिर इस बात के लिये कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश श्रिधिनियम में इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया है कि जहां पर पंचायत कामयाब नहीं हुयो, जहां पर पंचायत श्रपने उत्तरदायित्व को श्रच्छी तरह से वहन नहीं करती हैं तो ऐसी हालत होने पर उन पंचायतों के स्थानों पर दूसरी मशीनरी सरकार बना सकती है। इस विधेयक में भी श्रनेक स्थानों पर इस बात का जिकर किया गया है कि जहां पर पंचायत श्रपने कामों को श्रंजाम नहीं दे सकें वहां पर सरकार को श्रधिकार है कि सरकार उनके स्थानों पर दूसरी मशीनरी बना दे बिल्क यह है कि कोई कारण भी नहीं दिया गया है, कि सरकार यदि उचित समझें, सरकार यदि श्रपनी इच्छा से उचित समझें तो वह पंचायत को हटा सकती है श्रौर उसको पूरा श्रधिकार है कि वह उस पंचायत को हटा दे। तो फिर ऐसी हालत में श्रगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसमें सरकार को इतने प्रकार का श्रधिकार मिला हुआ है तो फिर में नहीं समझता कि प्रस्काइन्ड श्रथारिटी को खाली हुये स्थानों की पूर्ति करने के लिये ऐसा श्रधिकार क्यों दिया जाय।

मं फिर उनसे दरस्वास्त करूंगा कि ग्रगर पंचायतों को इतना ग्रधिकार नहीं देते हैं कि जो जगह खाली हों, जितने श्रादमी चुनाव होकर जाना हो, श्रगर वह नहीं जाते हैं तो उसको पूरा करने का अधिकार आप पंचायत को नहीं देते है तो फिर हम उन पंचायतों की सफलता की **ब्राशा किस प्रकार से कर सकते हैं। पंचायतों को इस प्रकार का श्रधिकार मिलने पर ही** वह ग्रपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निवाह सकती हैं ग्रौर उनको सफलता प्राप्त होगी। में यह भी जानता हूं कि इनके लिये टैक्स लगाने का प्राविजन भी पास होगा और उनको टैक्स लगाने का भी ग्रधिकार होगा। तो एक तरफ तो विशासन मंत्री हमसे यह कहते हैं कि यह टैक्स स्वयं गांव वाले ग्रपने ऊपर लगाते हैं ग्रौर उसके वसूल करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होगी श्रौर उसकी नेकनामी या बदनामी सरकार श्रपने ऊपर नहीं ले सकती। तो फिर प्रेस्का-इब्ड ग्रथारिटी के जरिये से पंचायतों को श्रगर बनाया जाता है तो उस टैक्स लगाने का श्रधिकार भी उसी ग्रथारिटी को होगा। टैक्स लगाने का ग्रधिकारी कौन होगा? वह तो यही प्रेस्काइटड भ्रथारिटी टैक्स लगायेंगी भ्रौर उसका परिणाम यह होगा कि उसके भ्रसेसमेंट में ज्यादती होगी श्रौर फिर गांव की उन्नति के लिये जो कार्य होंगे उन उन्नति के कार्य करने में गांव वालों की रुचि नहीं होगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के मुताबिक में समझता हूं कि ५ करोड़ या इससे ज्यादा रुपयों का श्रमदान का काम हुआ है। प्रेस्काइब्ड अयारिटी पंचायत लाद सकती है गांव के ऊपर, लेकिन प्रेसकाइ उड भ्रयारिटी डेवलपमेंट के काम में जनता में उत्साह पैदा नहीं कर सकती है। प्रेस्काइड्ड ग्रथारिटी में भले ही लोग ऊंचे किस्म के हों परन्तु वे गांव वालों को प्रेरणा नहीं दे सक ो में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बात स्वीकार कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो जाय।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रक्षन पर मुझे दुल है कि ग्रसली प्वाइन्ट का किसी ने जवाब नहीं दिया जिसे माननीय केशभानराय जी ने उठाया था। मेंने पहली बहस में भी निवेदन किया था पहले फंक्शन्स म्युनिसिपल थे पचायतों के। ग्रब जबकि गांव समाज ग्रौर गांव सभा को इकट्ठा करने का सत्राल है तो गांव समाज में जो प्रापर्टी बेस्ट की उसकी देखभाल के लिये कोई कारपोरेट बाडी होनी चाहिये। इसकी देखभाल कौन करेगा, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सिर्फ म्युनिसिपल फंक्शन्स में या जैसा पहले था, सिर्फ ३,४ जगह गांव सभा न बने तो कोई ज्यादा नुकसान शायद न हुन्ना हो। गांव सभा ग्रौर गांव समाज एक हो इस विचार से हम चल रहे हैं तो सवाल यह है कि उस प्रापरटी की देखभाल कौन करेगा। मुझे ग्रफसोस है

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण न_{टी}ं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया जिससे कि में इस संशोधन को समझ सकता। मंने कल भी माननीय गेंदा सिंह जी से कहा था कि भाई, इसका क्या जवाब है ग्रौर में समझता था कि मेरी बात वह समझ गये हं लेकिन कम से कम वह मुझे समझा नहीं पाये है। इस वात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कारपोरेट बाडी चाहिये। कम से कम में उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि यह पंचायतें स्वयं चुनी हुई होनी चाहिये ग्रौर सरकार उनमे दखल न दे। ग्रगर कोई एक दफा में न चुन पाये तो दूसरी दफा चुन ग्रौर ग्रगर कोई दूसरी दफा भी न चुन पाये तो क्या हो, यह प्रश्न है केवल। यहां एक प्रोसीज्योर दिया है कि इम तरह से बना दी जाय। गेंदा सिंह जा कहते हैं कि इसे हटाग्रो लेकिन इसके बाद क्या हो उन गांव सभाग्रों का, यह जवाब नहीं देते। इसलिय गेंदा सिंह जी एक ऐसी स्थित पैदा करेगे जिसका इलाज वह सोच तो रहे हें लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हं ग्रौर इसके कारण जो दिक्कतें होंगी उनको हल करने का कोई उपाय नहीं बतला रहे हैं।

एक बात तो गेदा सिंह जी श्रौर बालेन्दुशाह जी ने भी कही कि इसमें बहुत बहुत श्रिषकार है। श्राप ससपेंड या डिसाल्व कर दीजिय। यह एक प्वाइन्ट बालेन्दुशाह जी ने कहा। मेरा खयाल है कि ससपेंसन या डिसोल्यूशन उसी बाड़ी का होता है जो एग्जिस्ट करे। लेकिन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वह ससपेंड या डिसाल्व कैसे हो सकती है? जब इलेक्शन नहीं हुश्रा तो ससपेंशन या डिसाल्व करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। श्रब सवाल है गांव पंचायतों का। जब बनी ही नहीं तो उनका सस्पेशन या डिजोल्यूशन कैसे हो जायगा। गेदा सिंह जी ने कहा कि ऐडिमिनिस्टेटर बना दीजिये। श्रव सवाल यह है कि श्राया वहां एडिमिनिस्टेटर बना दिया जाय श्रयवा वहीं के किसी श्रादमी को मुकर्रर करके गांव समाज को चलाया जाय। वहीं का श्रादमी क्योंकि वहां काम श्रच्छी तरह से चला सकता है इसलिये उसका मुकर्रर किया जाना ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये गांव सभा बनानी चाहिये। श्रगर गांव सभा नहीं बनेगी तो दिक्कत होगी श्रीर उसके बनाने का तरीका यह है इसलिये इसको यहां से हटाने म नुकसान होगा जिसको फेस करने के लिये में तैयार नहीं हूं श्रतः माननीय गेदा सिंह जी के संशोधन को में स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (८) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर ग्रस्वीकृत हुग्रा।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कल जो रिड्र।पिटग के लिये छोड़ दिया गया उस खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिये जाने के लिये पेश करता हूं। वह इस प्रकार है:-

खण्ड १२ (पुनरागत)

श्रो श्रध्यक्ष--नीचे खंड १२ का संशोधन ग्राया है। पहले उसको ले लिया जाय ही उसको बाद में लाने में दिक्कत होगी--

श्री मोहनलाल गौतम—कल जो परिस्थित पैदा हो गयी थी यानी खंड १३ में कुछ कंफ्यूजन मालूम होता था। उसको ठीक करने की ग्रापने ग्राज्ञा दी थी। इसके साथहः साथ ११-ए जो नीचे दी गयी है उसकी वजह से कुछ कांट्रेडिक्शन हो जाता था; इसलिये दोनों को रींड्राफ्ट करके रखने की ग्राज्ञा चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष-प्रश्न यह है कि क्या इस सबन की श्रनुमित है कि खंड १२ को पुनिवचार करके संशोधित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री मोहनलाल गौतम—-ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——

"11-AA. There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

- 11-A. (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.
- (2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years., or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix.
- (3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesa'd, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

म्रध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन चीजें थीं जिसके ड्राफ्टिंग में माननीय सदस्यों को म्रापित्त थी म्रौर कुछ कन्प्यूजन माल्म होता था इसलियें उसको रीड्राफ्ट कर दिया गया। बालेन्द्रशाह जी ने पेज ७ पर (४) पर म्रापित्त की थी — —

श्री ऋध्यक्ष--जरा इसको देखिये। यह छपाई में गलती हो गयी है या इसी प्रकार से रक्खा गया है ? इस 11-A में ऋँ। र 11-A में कुछ गलती मालूम होती है।

श्री मोहन लाल गौतम-पहले 11-A ब्रायगा और फिर 11-AA ।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पहले प्रधान गांव सभा द्वारा चुना जायगा, उसके बाद उप प्रधान ग्राता है कि उसका चुनाव कैसे होगा।

श्री ग्रध्यक्ष—यहां पर 11-A तो पहला हिस्सा है ग्रौर 11-AA दूसरा हिस्सा है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--ग्रध्यक्ष महोदय, 11-A. के तीन हिस्से हैं (१), (२), (३)। पहले 11-A A ग्राया है।

श्री अध्यक्ष--पहले तो 11-A ग्राना चाहिये उसके बाद ही प्रधान के चुनने की बात ग्राती है। तो इस नम्बर को परिवर्तित कर दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में सदन का श्रधिक समय नहीं लेना चाहता। चूंकि कल थोड़े से वोर फिकेशन की जरूरत थी वह यह कि एक तो प्रधान का चुनाव गांव सभा द्वारा होगा और उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायतें करेंगी। तो उप प्रधान गांव सभा का कैसे होगा, इसके ऊपर कल काफी वहस हुई थी। उसकी साफ करने के लिये में कह देना चाहता हूं कि गांव सभा द्वारा प्रधान चुना जायगा और उपप्रधान उस तरीके से चुना जायगा जैसा कि मेंने बतलाया। दूसरी बात यह देखी गयी है कि जो लेग्वेज हैं उस पर कल डिस्कशन कर रहे थे जो पेज ६ के लास्ट लाइन मेंहैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यू जन है कि एक वक्त में एक साल की मियाद बढ़ायी जाय या यह कि इसका टोटल पीरियड एक साल हो। इसको साफ करने के लिये में कहता हूं कि जो ५ साल की मियाद है उसको बढ़ा कर ६ साल करने की बात है। इसमें वास्तव में कंफ्यू जन की कोई बात नहीं है, इसका दूसरा इंटर प्रिटेशन नहीं हो सकता है। इसलिये कि ६ साल की मियाद है और उसको बढ़ा कर ६ साल तक किया जा सकता है। अब ग्राप एक-एक महीना करके बारह महीने में उसको बढ़ा सकते हैं या एक बार ही एक साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जो होगा वह ६ साल के बार होगा। जितनी मियाद बढ़ेगी वह ६ साल खतम होने के बाद ही बढ़ेगी। इससे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है, इसलिये मुझे उम्मीद है, कि सदन इसको स्थीकार कर लेगा।

महाराजकुमार बालन्द्शाह—-ग्रध्यक्ष महोदय, में चाहता हूं कि जहां 11-A A (2) में आया है "such longer term not exceeding 6 years as it may fix." वहां "in all 6 years" कर दिया जाय। अगर माननीय मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं कि यह गलत नहीं है तो इसको ऐसा कर दें तो श्रच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मै समझता हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है श्रौर हमारे ला डिपार्टमेंट ने भी इसका दूसरा माने नहीं लगाया।

श्री श्रध्यक्ष—यह बिलकुल साफ है। इसमें कहीं नहीं श्राता कि ६ साल जोड़ दिया जायगा। तो श्रव में इसको पेश कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"11-A There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

- 11-AA (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.
- (2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longe term not exceeding 6 years iast may fix.
- (3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी ग्राज्ञा से में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित घारा 11-B की उपधारा (१) में शब्द "Vice President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" रख दिये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-Pradhan." निकाल दिये जायं।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय श्रध्यक्ष महोवय, यह संशोधन जो श्रभी उपस्थित किया गया है उसमें जब यह संशोधन स्वीकार हो जायगा तो यह इस तरह से पढा जायगा:—

"The Pradhan of the Gaon Sabha shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed." मं समझता हूं कि "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" यह पढ़ने में अच्छा नहीं मालूम होता है और इसकी भाषा इतनी सुन्दर नहीं है जैस। कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री अब्दुल मुईज खां ने ३३ आ आ में उपस्थित किया था कि—

"The Up-Pradhan elected by the Gaon Panchayat under section 11-B shall also be the Up-Pradhan of the Gaon Sabha."

भ्रौर उन्होंने उससे पहले संशोधन में जहां उपप्रधान ग्राया है उसको निकाल देने के लिये भी रखा है। जैसा कि मंत्री जी चाहते हैं श्रगर केवल वही रख देते है तो उस के बाद जैसे कि उन्होंने खंड १३ में जो रखा है कि गांव पंचायत जो उपप्रधान चुनेगी वही गांव सभा का भी उपप्रधान होगा। इसलिये इसको देख दिया जाय। यह कुछ पढ़ने में सुन्दर नहीं मालम होती है।

श्री अध्यक्ष-तो आप संशोधन का विरोध कर रहे हुँ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--जी हां।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस में जो स्कीम्स ग्राफ थिनाज में फर्क हैं ग्रौर इसीलिये यह मतभेद हैं जो माननीय सदस्य ने जाहिर किया है। काम तो दोनों तरह से चल सकता है। यह तो जाहिर है कि एक प्रधान होगा ग्रौर एक उपप्रधान होगा। प्रधान इस तरह से चुना जायगा ग्रौर उपप्रधान इस तरह से चुना जायगा ग्रौर उपप्रधान इस तरह से चुना जायगा, यह इस में हैं। जो उपप्रधान चुना जायगा वही ग्रागे चलकर गांव पंचायत का भी उपप्रधान होगा। यह चुनाव गांव सभा के उपप्रधान का है ग्रौर गांव पंचायत का नहीं है। श्री ग्रब्दुल मुईज खां के संशोधन को मानने से तो ग्रौर कंफ्यूजन ग्रागे चल कर हो जायगा। सिर्फ उनके स्कीम ग्राफ थिनज में फर्क है। इसलिये जो मेंने पेश किया है उसी को स्वीकार किया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष——इसी ग्रड्चन को दूर करने के लिये उस वक्त यह रखा था कि छोटी बाडी के उपप्रधान का चुनाव छोटी बाडी यानी गांव पंचायत करे श्रौर उस के बाद श्राप यह कहें कि जिसे छोटी बाडी ने उपप्रधान चुना है वही बड़ी बाडी का उपप्रधान कहलायेगा। इसके बजा उल्टा इसमें श्रा गया है कि गांव पंचायतें ही बड़ी बाडी के लिये उपप्रधान चुनेंगी "एंड ही शंल बि काल्ड उपप्रधान श्राफ दि गांव सभा" "हि मे बी काल्ड" कार्लिंग दूसरी चीज है श्रौर चुनने का श्रधिकार गांव सभा को गांव पंचायत को दे देना यह दूसरी बात है यह श्रापने उल्टा कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि यह जरा साधारण रवेंग्रे में परिवर्तन हो रहा है। मेने यह सुझाव दे दिया, वैसे जो श्राप करना चाहें कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरी जो स्कीम ग्राफ थिंग्ज है वह यह है कि गांव सभा का एक प्रधान ग्रौर उपप्रधान होगा ग्रौर फिर यह कहा कि प्रधान इस तरह से चुना जाय ग्रौर उपप्रधान इस तरह से चुना जाय। यह सही है कि एलेक्टोरल छोटा है लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि छोटी बाडीज चुनते हैं लेकिन काफी बड़ी पावर्स बड़ी बाडी की हो सकती है। मेरी दिक्कत यह है कि ग्रगर एकाध जगह इस तरह से कर दिया जाय तो उसका कांसीक्वें जितने ग्रौर होते हैं उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिये उसमें कहीं कहीं कंट्रेडिक्शन है। लेकिन यह ग्रमेंडमेंट ठीक है ग्रौर वह दिक्कत हल हो जाती है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा-में ग्रपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-B की उपधारा (1) में शब्द "Vice-President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon sabha" रख विये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-pradhan" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पुनर्स शोधित खंड १२ इस विधेयक का श्रंग माना जाय । (प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३ (कमागत)

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित वारा 12 की उपधारा (2) के स्थानपर निम्नलिखित रख दिया जाय: —

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be ex-officio member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be ex-officio Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

[श्री मोहन लाल गौतम]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कल कंपयूजन था उसमें कई चोजें कल आयी थीं।
प्रधान और उपप्रधान का तो पांच साल का टर्म रहेगा ही च हे वह गांव पंचायत का मेम्बर रहे
या न रहे लेकिन उसको छोड़कर बाकी मेम्बरों का पांच साल का टर्म होगा इसमें थोड़ी सी दिक्कत
है क्योंकि मेम्बरों का टर्म भी पांच साल का ही है। तो उसमें आपित्त यह उठाई गयी थी कि यह
जो प्रधान है वह पंचायत का मेम्बर है या नहीं। तो इसको भी जरा साफ कर दिया गया है।
तीसरी बात यह है कि प्रधान और उपप्रधान जो है वह एक्स आफिशिओ पंचायत के प्रधान और
उपप्रधान होंगे। इसकी रिड़ाफ्टिंग भी हो गई है इसलिये मुझे आशा है कि यह मेम्-रों को
स्वोकार हो ग।

श्री ग्रध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित घारा 12 की उपधा । (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be ex-officio member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be ex-officio Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

(प्रक्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्रा।)

श्री ग्रब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—ग्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी का पास हो चुका है उसको देखते हुये में ग्रपना संशोधन वापस लेता हूं। (सदन की ग्रनुमित से संशोधन वापस लिया गा।)

श्री मोहन लाल गौतम्—श्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित

धारा 12 को उपघारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

यह वही हैं जो हम पास कर चुके हैं थ्रौर उसकी भाषा भी उसी तरह से रख दी गई है। मैं थ्राशः करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेगें।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रक्त यह है कि खंड १३ में प्रस्तावि । धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

(प्रक्त उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृतं हुन्ना ।)

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर) — में ग्रपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित

धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(4) The declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

कल बालेन्दुशाह जी ने क्लैरिफिकेशन की जो कुछ बात कही थी वह इसमें हो जाती है कि बढ़ी हुई मियाद या ६ साल से पहले ही प्रेसीडेंट का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष--(महाराजकुमार बालेन्दुशाह के खड़े होने पर) माननीय बालेन्दुशाह ग्रापको कछ कहना है ?

महाराजकुनार बःने दुगःह-- प्रध्यक्ष महोदय, मे यह कहना चहुंगा कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) में ग्री एनलार्ज्ड का प्रयोग किया गया है वह बहुत ब्रजीब सा लफ्ज है। एक्सटेन्डेंड इससे बेहतर है। उसमे स्पष्ट हो जाता है।

श्री ग्रध्यक्ष--बात यह है कि ग्रभी जो ग्रास्ते संशोधन स्वीकार किया उसमे एनलार्ज शब्द स्वीकार किया है।

महाराज कुमार बालन्दुशाह-एनलार्ज्ड मे कोई ब्रापित नहीं होगी। उसको कर है। शरू में मेरा संशोधन इस बहुस पर था कि एक्सटेशन कुल एक साल का होगा अगर गुंजाइश है तो एक महीने २ महीने का एक्सटेशन हो सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये ऐक्सटेशन के बजाय एक्सटेंडेड रखा जाय बजाय एनलार्ज के।

श्री मोहन लाल गौतम-मुझे एक्सटेन्डेड लफ्ज से कोई श्रापत्ति नहीं थी। लेकिन भ्रम होने का अन्देशा है कि अगर ५ साल का एक्सटेशन ६ साल हुआ तो फिर ११ साल कोई माने ने लगा ले । इस लिये यह फिट इन करता है मुझको यह बतलाया गया कि यह लफ्ज ठीक है और मे स्राशा करूंगा कि श्री बालेन्द्रशाह इस पर गौर करेगे।

श्री ग्रध्यक्ष--ग्रापको कोई ग्रापत्ति तो नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्द्रशाह—मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष--- प्रक्त यह है कि खंड १३ मे प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(4) the declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ग्रध्यक्ष- प्रश्न यह है कि श्री बालेन्द्रशाह का संशोधन वापस लिया जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया भ्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री ग्रध्यक्ष-- प्रदन यह है कि संशोधित खंड १३ विधेयक का ग्रंग माना जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

१४--मूल ग्रिधिनियम की धारा १२ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 12-A, 12-B. 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J, श्रीर12-K के रूप में बढ़ा दी जायं-

Number of persons to be elected or Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat,

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority

has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

यु ०पी० ऐ २६, १६४ मे नई घारा 12-A से 12 K तक बढ़ार

- 12-B. (2) In addition to the members prescribed under section 12 the State Government may, by a general or special order, direct Additional that one or more members of Prantiya Rakshak Dal having such qualifications as may be prescribed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat or any committeee thereof as may be specified. Such persons shall not, however, by virtue of this sub-section be entitled to vote in the meetings of the Gaon Panchayat or the committees.
- 12-C. (1) The election of a person as Pradhan of a Gaon Sabha or as member of a Gaon Panchayat including the election of a person Appliaction who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under for question-section 43 shall not be called in question except by an elections. application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—
 - (a) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or
 - (b) that the result of the election has been materially affected—
 - (i) by the improper acceptance or rejection of any nomination; or
 - (ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the the rules framed thereunder.
- (2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act:—
- (A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—
 - (a) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate at an election; or
 - (b) an elector to vote or refrain from voting at an election; or as a reward to—
 - (i) a person from having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidatures; or
 - (ii) an elector for having voted or refrained from voting.
- (B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right:

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

- (i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or any elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or
- (ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will

be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as

may be prescribed.

Explanation—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made

shall, in the matter of-

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing.

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner,

have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribed authority upon an application under sub-section (1) shall be final and conclusive, and shall not be questioned

in any Civil Court.

- 12-D. Any dispute relating to the election of Up-Pradhan of a Gaon Disputes pertain. Sabha or of Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya ing to the election Panchayat shall be referred in the manner prescribed to of Up-Pradhan the prescribed authority whose decision thereon shall be Sarpanch or Saha-final and conclusive and shall not be questioned in any yak Sarpanch. Civil Court.
- 12-E. (1) Every member of a Gaon Sabha shall, before entering upon Oath of office.

 any office referred to in sections 11-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed an oath or affirmation in the form to be prescribed.
- (2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.
- 12-F. A Pradhan, Up-Pradhan or a member of a Gaon Panchayat may, Resignation, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed, resign his office and his office shall thereupon become vacant.
- 12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-General Elections. section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.
- 12-H. If a vacancy in the office of a member of a Gaon Pahchayat arises
 Casual vacancies, by reason of his death, removal or resignation it shall,
 subject to the provisions of section 12, be filled for the
 unexpired part of his term in the manner provided therein
 and if the member vacating the office was also a [President]
 Pradhan or Up-Pradhan then that office shall also be
 filled as far as may be in the manner laid down in and
 under section 11-A or section 11-B as the case may be.

- 12-I. No civil court shall have jurisdiction to question the legality Jurisdiction of of any action taken or any decision given by an officer Civil Courts in or authority appointed under this Act, in connection with conduct of elections thereunder.
- 12-J. The Up-Pradhan shall exercise such powers of the [President] Power of Up-Pradhan.

 Pradhan as may be prescribed.
- 12-K. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of sec-Tenure of tion 11-A or of 11-B the Pradhan and the Up-Pradhan shall continue in office until their respective successors are elected Up-Pradhan. [or appointed.]

श्रो विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—-अध्यक्ष महोदय, मै आपकी श्राज्ञा से यह संज्ञोचन पेश करता हूं:—

खंड १४ में प्रस्तावित घारा 12-A के रेखांकित ग्रंश की पंक्ति ७ में शब्द 'after' के बाद तथा पंक्ति में शब्द 'five' के पूर्व का शब्द समूह 'the prescribed authority has selected' के स्थान पर शब्द समूह 'the elected members have elected' रख दिया जाय ।

श्रष्यक्ष महोदय, इस रें कोश्राप्टेड शब्द छपा है, मैं चाहता हूं कि कोश्राप्टेड के बजाय शब्द 'एलेक्टेड' रख दिया जाय।

म्राध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक में प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

मेरा संशोधन रखने के पश्चात् यह इस प्रकार हो जायगी---

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any caseas shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of Section 12 but only such of them as remain after the elected members have elected five persons or as such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

श्रीमान् जी, इसमें जो प्रस्तावित घारा है उसका मतलब यह है कि जितने भी न्याय पंचायत के लिये सदस्य नियत किये जायं प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी उनमें से चुन ले श्रीर उसके बाद जो बचेंगे वे ग्राम पंचायत के मेम्बर होंगे। इस तरह का मेने कल एक संशोधन पेश किया था। उसमें मैने बतलाया था कि जो नामिनेशन का तरोक़ा है वह पंचायत राज के मूल सिद्धान्त का विरोध करता है क्योंकि पंचायतें प्रजातंत्र प्रणाली पर बनायी गयी है श्रीर उनमें प्रजा श्रयने नुमायन्दों को खुद चुने चाहे वह न्याय पंचायत हो चाहे श्रीर कोई एक्जीक्यूटिव बाडी हो। जो मेने संशोधन रखा है उसमें नामिनेशन श्रीर सेलेक्शन जो कि नियत अधिकारी द्वारा होगा उसमें यह रखा गया है कि जो उसके चुने हुये मेम्बर हैं खुद न्याय पंचायत के लिये जितने सदस्यों की जरूरत हो उतनों को चुन लें श्रीर इसके पश्चात् जो बचें वह ग्राम पंचायत के मेम्बर

माने जायं। श्रीमान्, नियत श्रिषकारी द्वारा जो न्याय पंचायत के लिये सदस्य चुनं जायंगे वह सही तरीके से नहीं चुने जायंगे क्योंकि श्रंग्रेजी राज्य में भी इसी तरह की न्याय पंचायतें बनाई गई थीं, उनमें भी जो पंच चुने जाते थे वह नामीनेटेड किये जाते थे। लेकिन वह करण्यान से खाली नहीं थी श्रीर उनमें से दोष थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। श्रव उसी प्रणाली को हमारी सरकार पुनः श्रपनाने जा रही है, में नहीं समझता हूं कि यह कहां तक सही है कि जो चीज पहले खराब साबित हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति की जाय।

दूसरी बात यह है कि जो नियत ग्रधिकारी चुनेगा उसको ग्राम के रहने वालों का सही जान नहीं होगा। उनके पास तो जो सूचना प्रापर चैनेल से जायगी उसी पर वह नामीनेट करेंगे। तो इस तरह से जो नुमायन्दे जायंगे चुनकर नियत ग्रधिकारी द्वारा वह सही नहीं होंगे क्योंकि वही श्रादमी जा सकते हैं जो लोग मिलते जुलते रहते हों, ग्रौर बलाल टाइप हों। में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से चुने हुये मेम्बरों के द्वारा यदि न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाते हैं तो दोनों चीजों का पालन हो जाता है। एक तो यह कि सही पंच पहुंचेंगे ग्रौर दूसरे यह कि जो इसका मूल सिद्धान्त है वह भी इससे पूरा होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लें।

श्री कृपारांकर— अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है यह एक प्रकार स गैरकानूनी है। यहां यह प्रश्न है कि गांव पंचायत में इतने मेम्बर चुने जायंगे जो संख्या है उससे ४ ग्रधिक या कम जो प्रेस्काइब किये जायं ग्रौर इसके बाद प्रेस्काइब्ड अथौरिटी न्याय पंचायत के लिये ५ ग्रादमी चुन लेगी, बकीया ग्राम पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। ग्रापका संशोधन है कि प्रेस्काइब्ड अथौरिटी के बाद यह कर दिया जाय कि "the elected member have co-opted" जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको कोन्नाप्ट करने का क्या सवाल हैं। जब किसी कमेटी में ग्रौर मेम्बर लेने होते हैं तब कोन्नाप्टान का सवाल ग्राता है। लेकिन जब एक कमेटी दूसरे को इलेक्ट करेगी तो यहां शब्द "इलेक्शन" तो हो सकता था लेकिन कोन्नाप्टान का सवाल नहीं है। बहुत सी पंचायतों के लिये मेम्बर चुनने हैं इसलिये बजाय कोन्नाप्टान के लिये ग्रगर इलेक्शन कहा जाता तब तो कुछ सही था....।

श्री ग्रध्यक्ष—में समझता हूं कि ग्राप इसे ग्रवैध कह रहे हैं। कहीं ग्रापने तय कर दिया है कि प्रेस्काइब्ड ग्रयौरिटी ५ ग्रादिमयों को चुनेगी।

श्री कृपाशंकर—जी नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि भ्रापने लफ्ज को आप्शन रखा था यहां पर गांव सभा करेगी भ्रौर न्याय पंचायत के लिये करेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि को आप्शन तो किसी कमेटी के लिये श्रादमी बढ़ाने के लिये होता है लेकिन यहां पर दूसरी बात है। यहां पर शब्द ठीक नहीं बैठता है। भ्रगर भ्राप यह कहें कि मेम्बर चुन लेंगे तब तो ठीक बैठता है। एक तो यह लफ्ज सही नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी द्वारा १ आदमी चुनने के लिये रखें गये हैं। इसका मतलब यह है कि जो न्याय पंचायत का इलेक्शन हुआ पिछले वक्त में उसमें कुछ ऐसे लोग आ गये जिन्होंने अपनी ताकत का दुख्योग किया और जबर्दस्ती वोट ले लिया। तो इस बात को मिटाने के लिए कि कोई आदमी जबर्दस्ती वोट लेकर, दूसरों को डरा धमका कर न आ जाय यह रखा गया कि जो मेम्बर्स गांव पंचायत के लिए चुने जायं उनमें १ और चुन लिये जायं और उनमें से प्रेस्काइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत के लिए १ आदमियों को नामिनेट कर देगी। इस तरह से ज्यादा अच्छे आदमी आ सकेंगे। पहले तो यही

[श्री कृपाशंकर]

था कि वहीं गांव सभा के मेम्बर लोग ही चुन दिया करते थे। लेकिन पिछ्ने तीन चार साल के तजुबें में जो खराबियां दिखलायी पड़ीं उनको दूर करने के लिये ही यह रखा गया है ताकि म्राइन्दा काम ठीक हो सके। इसलिये यह जो इसमें संशोधन पेश किया गया है वह उचित नहीं है श्रीर में इसका विरोध करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रष्ठाना (जिला सीतापुर) — श्रध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल हैं कि शायद विष्णुदयाल जी ने अपने इस संशोधन को संशोधित कर दिया था श्रोर उन्होंने को आपने के बाजा प्लेक्टेड शब्द रख दिया था। में तो इस समय एक दूसरी बात की तरफ घ्यान श्राक्षित करना चाहता हूं श्रोर वह यह है कि विष्णु दयाल जी ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को बात कही है श्रोर यह कहा कि प्रेसऋाइ उप्थारिटी द्वारा नामिनेट किये जाने के बाद जो विलेज रिपब्लिक श्राप बना रहे है उसका श्राधार ही नहीं रह जायगा। अगरचे श्राप नामिनेशन की बात यहां पर लाते है। मेरा यह ख्याल है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जहां तक एक्जीक्यूटिव श्रोर लेजिस्लेचर का सवाल है यह तो ठीक है कि चुने हुए नुमाइन्दे जनता के होते है, वह कानून बनाते है श्रीर एक्जीक्यूटिव उनको कार्य रूप में परिणित करती है लेकिन जहां तक कि न्याय प्रणालो की बात है में नहीं जानता कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणालो में कहां पर न्याय प्रणालो की बात है में नहीं जानता कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणालो में कहां पर न्याय प्रणालो चुनी हुई होती है? इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले जो सरकार ने एक जुडीशल रिफार्म्स कमेटी बैठाई थी उसने कुछ सिकारिश की थीं जिनका कि इस सदन में श्रकसर जिक हुशा है। उस श्रोर में माननीय सदस्यों का घ्यान श्राक्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है:——

"The Committee is of opinion that these defects are mainly due to the elective principle which has been introduced in the composition of these village courts. The Committee, however feels that the decentralisation of courts which was brought about by the Panchayat Raj Act, should not be scrapped altogether but should be given some trial. At the same time the Committee is definitely of the opinion that the elective system for constituting these Panchayati Adalats should go at once It is suggested that in place of the elective system the Panchayati Adalats should consist of panches nominated by the District Magistrate from within the Panchayati Adalat circle after such local enquiry through a gazetted officer as is considered necessary."

श्री ग्राध्यक्त-इसका थोड़ा सा खुलासा मुख्तसर में ग्राप हिन्दी में भी कह दीजिए।

श्री हरिक्चन्द्र श्रष्ठाना—वांचू कमेटी जिसने कि इस प्रक्षन पर विचार किया था कहा है कि यह तो सही है कि जहां तक कि अवालतों के विकेन्द्रीकरण का सवाल है पंचायती अवालतें बनायी जानी चाहिएं। मगर उसके अन्वर जो खामियां हैं, कमियां हैं वह इस वजह से हैं कि वह चुनी हुई पंचायतें है। अगर उस चुनाव को हटा कर कोई नामिनेशन का सिस्टम रख विया जाय और उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सुझाव विया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन पंचायतों को मनोनीत करे। मगर यहां जो संशोधन लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि गांव सभायें गांव पंचायतों को चुनेंगी और उसके अन्वर जितने सबस्य न्याय पंचायत के लिये चुने जाने वाले है, पांच या इससे कम या ज्यादा, उनको भी वह चुनेंगी। उसके बाद प्रेस्काइब्ड एथारिटी उनमें से उतने आदमी नामिनेट कर देगी न्याय पंचायत के लिये और बाकी गांव पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। तो इस तरह से माननीय सबस्य यह देखेंगे कि यहां पर

चनाव की पद्धति को अलग नहीं किया गया है यानी गांव सभा से चुने हुए मेम्बर गाँव पंचायत मे जायंगे स्रौर उन्हीं के चुने हुए मेल्बरों मे से प्रेस्क इब्ड एथारिटी को भ्रधिकार होगा कि न्याय पंचायत के लिए मेम्बरों को नामिनेट कर दे यानी चुने हुए सदस्य एक पेनल फार्स करेगे ग्रौर प्रेक्ताइव्ड एथ रिटी का ग्रधिकार मीमित कर दिया गया है, कि वह उन्हीं में से नामिनेट करे। उत्तको यह श्रिविकार नहीं दिया गया है कि किसी को भी गांव सभा में में चुन ले। गांव सभा के चुने हुए सदस्यों ने से ही उसको अधिकार है कि कुछ सदस्यों को न्याप पंचायत के लिए मनोनीत कर दे। इस तरह से यह जो नया क्लाज इस धारा के द्वारा लाया गया है उसके अन्दर चुनाव की प्रणाली भी रखी गई है श्रौर उसके साथ साथ जो खामियां या किम्या बतायी गई थीं, जिनकी तरफ बांछू कमेटी ने बहुत जोरों के साथ असहमति प्रगटकी है, उनको भी मलग कर दिया गया है। इस तरह से दोनों के मिलाने से जो कि एक भ्राटर्श रूप बन सकता था वह बनाया गया है। में समझता हूं कि जिस रूप में यह धारा है उसका संशोधन करने से उसका वह मतलब समाप्त हो जाता है। ग्रक्सर विरोधी दल के सदस्य वांछू कमेटी की दुहाई दिया करते ह और यह बहुत सही है, इसलिये जो संशोधन बिल में बारा है वही ठीक है और जो रांशोधन माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने रखा है उसका में विरोध करता है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय हिरइचंद्र जी ने एक ची अस.मने रखी। उन्होंने कोटेशन दिया श्रीर बतल या कि न्याय पंचायतों में जो दोष है वह इसिल ये हैं कि उनके सदस्य चुने हुये ह। मुझे श्रारचर्य होता है कि माननीय सदस्य एक तरफ चुने हुए सदस्यों का विरोध करते हे श्रीर दूसरी तरफ जो प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी है उसके द्वारा चुने हुए सदस्यों में से फिर सेलेक्शन करवाते हैं। यह एक श्रजीव जी चीज बन जाती है कि दोनों ची जों में से कौंन सी चीज सही है। में समझता हूं दि जो दोष श्रीर करण्यन का का रण दतलाया गया है वह चुनाव नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि प्रेस्काइब्ड स्थारिटी सेलेक्ट करेगी तो वह भी उन्हीं सबस्यों में से करेगी जो कि चुने हुए हे। तो मैं यह नहीं समझता कि यदि वह सबस्य उन्हीं चुने हुए मेम्बरों द्वारा जो कि उनको अच्छी तरह से जानते हैं श्रौर साथ के रहने वाल है उनकी अच्छाइयों श्रौर वुराइयों से भली भांति परिचित है तो उनमें क्या बात हो जाती है। उन्हीं सबस्यों को प्रेरकाइब्ड अथारिटी द्वारा प्राम सभा के रहने वालों पर थोग दिया जाता है तो क्या बात होती है? मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें भावना का अन्तर है। जो भावना मेरे संशोधन मे है वह अधिक बेहतर है बनिस्बत इसके कि उत्पर से सेलेक्ट करके गांव सभाओं पर थोप दिया जाय। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे श्रौर इसे मानने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे खेद हैं कि मै इसकी स्वीकार करने मे श्रसमर्थ हूं। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं।

श्री श्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A के रेखांकित श्रंश की पंक्ति ७ में शब्द "after" के बाद तथा पंक्ति ६ में शब्द "five" के पूर्व का शब्द समूह 'the prescribed authority has selected" के स्थान पर शब्द समूह 'the elected members have elected" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रोर अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थिगत हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रापकी श्राज्ञा से में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A में शब्द "Prescribed Authority" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"a committee consisting of the (a) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary, (c) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

यह अगर स्वीकृत हो गया उपाध्यक्ष महोदय, तो वह इस तर्ह से होगः--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the.."

"After the" के बाद इस तरह बदल जायगा

'a committee consisting of the (a) District Judge.....

उसके बाद वहीं है "has selected five persons or such Iseser number as aforesaid under section 43 for membership of the nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्काइब्ड अथारिटी जो इसमें लिखा है सेलेक्ट कमेटी मे जाने से पहले जब पहले इस सदन के सामने यह बिल पेश किया गया था, तो उस समय यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चर्चा की गयी थी कि जो प्रेस्काइब्ड अथारिटी होगी वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। सेलेक्ट कमेटीने उसको हटा दिया। मै चाहता हूं कि प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी को यहां पर डिफाइन कर दिया जाय कि वह क्या होगी। स्रौर मेरी उसने मंशा यह है कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी की खुद एक कमेटी हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज हों, वह चेयरमैन हों ग्रौर वहां के पंचायत राज अफसर हो वह सेकेट्री हों। उस न्याय पंचायत के क्षेत्र के अन्दर जितनी ग्राम सभायें होंगी उन सबके जो सभापति, यानी प्रधान होंगे वह उस कमेटी के मेम्बर होंगे इसका फैसला करने के लिये कि कौन से लोग न्याय पंचायत के मेम्बर बनाये जायं। श्रगर यह ५ श्रादमी छंटे चुने रखे जाते है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह नामजदगो का सवाल आ रहा है ; उनकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि पहले जिलों के अन्दर आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये जाते थे अब गांव पंचायत के अन्दर ४-४ आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकरेर किये जायेंगे जो अदालतों का फैसला करने वाल होंगे, उनमें श्रौर श्रानरेरी मैजिस्ट्रेटों में कोई फर्क नहीं होगा। केवल यही होगाकि यह भी उन्हीं ग्राम सभाग्रों द्वारा छुंटे हुर्व लोग होंगे, जिनको कहा गया है कि एलेक्टेड होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सेलेक्ट कमेटी ने खुद इस बात का फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वहां से हटा दिया है उसका नाम तो प्रेस्काइब्ड अथारिटी के अन्दर नहीं है लेकिन अन्देशा यह है कि इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी के नाम पर कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर कहीं उनके हाथों से नामिनेशन न करा दिया जाय। उपाध्यक्ष महीदय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो डेमोक्रेसी के दुश्मन है। प्रजातंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वह हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही है जो इसको चलने नहीं देना चाहते। ये छोटे हिटलर है। जिस तरह से हिटलर ने हिटलरशाही चलाई थी उसी तरह से ये लोग भी जिलों में हिटलरशाही चलाते है। कानपुर का ही केस ले लोजिये। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या हिटलरशाही नहीं चलाई है?

श्री उपाध्यक्ष-मै समझता हूं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मै तो डैमोक्रेसी के दुश्मन का नाम बतला रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो तजुरबा हो रहा है उसकी ज्याख्या कर रहा था। नमूना

मामने हो है कि इत प्रदेश के विरोधी दल के नेता जब कि आज सदन में पंचायत राज्य पर बहस हो रही है वह हमारे बोच मे नहीं है। उनमें कहा जाता है कि तुम मे बीच आफ पीस का खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष--में समझना हूं कि माननीय सदस्य का इशारा ही काफी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इशारा ही कर रहा हूं। हुनारा दिश्वास इन डिस्ट्रिक्ट मंजिरहेट पर में हटता जा रहा है ? इनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट जज को रख दिया जाय । कहा जा मकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज भातो हमारे हो अफलर है, उनको क्यों रक्खा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिन्ट्रेट को क्यों नहीं रक्खा जाता? उनके जो नमूने हे इसलिये उन पर से विद्यास हटता जा रही है। अगर पेंचायत राज्य की तरक्की करना है, उसकी आगे बढाना है तो इलेक्शन का जो सबसे अच्छा तरीका था, न्याय पंचायते जो हमारी है उनके पंचों को भी गांव सभा वाले ही इलेक्ट कर देने। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था बिल पेश करने वक्त का तजुरबा कहता है कि न्याय पंचायत के लोगों को उसमें से छाटा जाय जिनको गांव सभा वाले छाटे। तो थोड़ा सा डिस्कोशन प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को भी मिलना चाहिये जो उनको नामिनेट करेगी। इसलिये मे चाहता हूं कि प्रेस्काइच्ड अथारिटी जो एक कमेटी हो उसका चेत्रसम डिस्ट्क्ट जज हो, डिस्ट्क्ट पंचायत राज आफिसर उसका सेकेटरी हो और सब गांव मना के प्रयान उसके सदस्य हों। इतके मानी यह हुये कि डिस्ट्रिक्ट जज ग्रौर पंचायत राज ग्राफितर परमानेट मेम्बर्स होंगे ग्रौर जिस क्षेत्र में न्याय पंचायत बनेगी उस क्षेत्र की ग्राम मनाम्रों के जितने सभापित होंगे अलग अलग एरियाज मे वे कमेटी के मेम्बर्स होंगे। पांच एक्सट्रा जो छांटे जाये गे वे मिला कर ३० होंगे ग्रौर उन ३० मे से ५ ग्रादमी न्याय पंचायत के लिये मुकर्रर कर दिये जायं और उपाध्यक्ष महोदय इसका फैसला भी वही करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मं चाहता था कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी की सकाई यहां पर हो जाय और साफ साफ रख दिया जाय कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी क्या होगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो मालूम होता है कि माननीय मंत्री जो स्वयं ही नहीं रखना चाहते। इसीलिये उनका नाम हटा दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हे और डेनोकेसी को पनपने नहीं देना चाहते। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास काम भी बहुत हे और अधिकार भी उनके पास पहले से बहुत ज्यादा है और हम लोगों की दरबारदारी भी उनको बहुत करनी पड़ती है। लिहाजा यह काम नो डिस्ट्रिक्ट जज के लिये छोड़ देना चाहिये। जुडीशियल माइंड के होने से वह अदालतों में ऐसे ही आदिमयों को रक्खेगा जो जुडीशियल माइंड के हों और यह कहा जा सकेगा कि जो एक्जिक्युटिव है वह किसी तरह से इंटरिफ यर नहीं कर रही है। में उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मंजिस्ट्रेट्स को इनमें नहीं रक्खा जायगा और आगे भी यह कोशिश होगी कि वे दखल न दे सके। इन शब्दों के साथ में इसे पेश करता हूं और माननीय मंत्री जो के उत्तर के पश्चात् अगर कुछ और कहना होगा तो कहूंगा।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उपाध्यक्ष जो को इस प्रेस्त्राइब्ड ग्रयारिटो के शब्द से कुछ श्रम उत्पन्न हो गया है। प्रेस्त्राइब्ड ग्रयारिटो के सदा से यह मायने होते हैं कि प्रेस्त्राइब्ड बाई रूल्स। वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने ग्रायेगे ग्रौर संभव है कि प्रेस्त्राइब्ड ग्रयारिटो को पर मर्श दात्रो सिनित से राय करना होगा ग्रौर किसी ग्रन्य से भी राय करना होगा। तो उस समय ग्रापके स्वयं उस पर विचार करने का ग्रवस मिलेगा ग्रौर यह ग्रापके सामने ग्रायेगा कि प्रेस्त्राइब्ड ग्रयारिटो के किस प्रकार से काम होंगे। यह ग्रापने जो मुझाव दिया है यह बहुत ही विलम्ब-कारी ग्रौर व्यवसोल होगा। इनने कोई तथ्य नहीं है। उसने डिस्ट्रिक्ट जज का नाम लिया ग्रा कि उसकी राय से उसने काम किया जायगा। में इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज सिवाय जुडिशियरी काम को छोड़कर जिले की ग्रौर क्या जानकारी उसकी

^{*}वक्ताने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

[श्री रामल बन मिश्र]

रहती है। वह तो हमेशा मुक्रदमों को ही निर्दिष्ट पथ पर बँलेस कर सकता है श्रीर इसके श्रितिरक्त श्रीर कोई ज्ञान उसकी नहीं होता है। से इसकी दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरी किठनाई यह है कि प्रत्येक पंचायती श्रदालत में श्रगर यह सिमित बनायो जाय तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जल का श्रयना समय देना पड़ेगा श्रीर उसने बहुत व्यय होगा श्रीर दूसरे जिस दृष्टिकोण का उराध्याय जी नंतेत करते हैं क्या उस दृष्टिकोण से यह काम होगा। इसने बहुत सो श्रवने श्रायेगी। इसी कारण से यह अनुमान करता हूं कि 'प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी' शब्द से उनको भ्रन उत्पन्न हो गया है श्रीर इसी कारण से वह यह सशोधन लाये हैं श्रीर इसी कारण से "प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी' पर वह बहुत जोर देते है। में समझता हूं कि हमारे मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देगे कि 'प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी' के मायने होते हैं कि "प्रस्काइब्ड बाई रूल्स" श्रीर वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने श्रायेगे श्रीर उस समय उपाध्याय जो "प्रेस्काइब्ड श्रयारिटा" शब्द पर काफी चर्चा कर सकते है। यदि वह इस पर विचार करके देखेंगे तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि 'प्रेस्काइब्ड श्रयारटी" को किन किठनाइयों में श्रपना निर्णय देना होगा। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामस्त्दर पाण्डेय (जिला ब्राजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुन्ना है। यह जो पद्धति सरकार की ग्रोर से जारी की जाने वाली है कि न्याय पंचायत की नामजदंगी नियत अधिकारी द्वारा की जाय यह में समझता हूं कि लोकतंत्र के बिलकुल विपरीत है। श्रभी तक जो ग्रदालती पंचायते रही हं उनकी तारीफ सदन मे माननीय स्वशासन मंत्री के द्वारा बीसों बार हो चुकी हं ग्रौर तब जो पद्धति चुनाव की पहले थी उसको परिवर्तित करने के लिये कारण यही हो सकता है कि ग्रदालतों का इन्तजाम या प्रबन्ध या फैसला जनता की निगाह में **ब्रौर माननीय स्वशासन मंत्री की निगाह में खराब साबित हुआ। मं समझता हूं कि ब्रदालती** पंचायत एक ऐसी पंचायत रही है जहां कि पंच लोगों को सिक्रय रूप से श्रदालती केसेज का निर्णय करने में सफलता हुयो है। ग्राम पंचायतों का काम निष्क्रिय रहा है। जो पंचायत जनता की निगाह में या सरकार की निगाह में कामयादी हासिल करें उसके संबंध में इस प्रकार का संशोधन लाना साजिश करना होगा। जनता के प्रति जो पंच वफादार ग्रौर निष्पक्ष सावित हुये हं और किसी प्रकार की शिकायत उनकी जनता के बीच मे नहीं हुई है उन्हीं स्थानों की पूर्ति सरकार नियत अधिकारी के द्वारा कराये तो इसके मायने हो जाते हैं कि अभी तक चुनाव पद्धति बहुत खराब रही है। में उपाध्यक्ष महोदय, श्रापके द्वारा माननीय रामलखन जी से अपील करना चाहता हूं कि यह जनता की भावना की उपेक्षा होगी और उनका समादर नहीं होगा कि जो ब्रादमी इन्सपेक्टर या जो कलेक्टर की चापलूसी करेगा वही वहां पर श्रायेगा। मेरा विश्वात है कि जो आज नौकरशाही है वह ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देगी। ईमानदार तथा निष्पक्ष व्यक्ति न्याय पंचायत में नहीं जा सकेंगे। २,४ साल का मेरा कटु श्रनुभव यह साबित करता है कि करकार के अधिकारी उन्हीं लोगों की नामजदगी करेगे, जो जनता की उपेक्षा करते है। इस सिलसिले मे उधर के बैठे माननीय सबस्यों ने भी बीलों बार ऐसे प्रश्न किये हैं जिनसे यह साबित हुआ है कि नियत अधिकारी या इंसपेक्टर या पंचायत अफसर ने सदा उन बातों की उपेक्षा की है जो ग्रदालती पंचायतों के पंच या सरपंच या ग्राम सभा के सभापति कहते थे। ऐसी भ्रवस्था में उन्हीं भ्रधिकारियों को यह ग्रधिकार देना कि वे नामजदगी करें। इसके मानी होंगे कि अदालती पंचायत उन्हीं लोगों के हाथ की कठपुतली होगी जो कि इन अधिकारियों के चाहे हुये होंगे। यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि अवालती पंचायतों में भी, उतना तो नहीं लेकिन कुछ अप्टाचार अवश्य है और अप्टाचार छिपाने का एक ही तरीका है कि अधिकारियों की चापलूसी करे, दरबारदारी करे और जो ऐसा करता रहेगा उसकी कुर्सी रहेगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस धारा के मायने ही यह होते हैं कि सरकार के हुकुम की पाबन्दी, हुकुम चाहे गलत है। द सही हो, जिला पंचायत अफसर के हुकुम की पाबन्दी चाहे हुकुम गलत हो या सही मानना होगा। ग्रगर वह नहीं मानता है तो वह हटाया जा सकता है ग्रौर फिर उसकी जगह पर नियत ग्रिधिकारी ग्रपने मनोनुकूल ग्रादमी को नामजद करेगा। में समझता हूं कि इससे अष्टाचार कैलने की विशेष ग्राशंका है ग्रौर सही मानों में पंचायती ग्रदालतें जो निर्णय करना चाहती हैं उसमें रकावट होगी।

जिलाधीशों या नियत अधिकारियों के रवैये पर माननीय राम लखन जी या कुछ और माननीय सदस्य भले ही संतुष्ट हों लेकिन अधिकतर आपसी बातचीत में मालूम होता है कि उधर बैठे हुए सदस्य भी काफी नाराजगी जाहिर करते हैं उन अधिकारियों पर जिन्हें सरकार जनित्रय होने का जामा पहनाती है। नामजदगी की धारा हटाने से यह बिल जनता की निगाहों में ऊंचा आदर्श स्थापित करेगी। नहीं तो जनता जिस निगाह से अमदान में शरीक होती है, जिस दृष्टि-कोण से अदालती पंचायतों के फैसले को मानती है और बहती है कि पंचों का फैसला ईश्वर का फैसला है, में समझता हूं कि उसकी इस निगाह में अन्तर आवेगा और अमदान और निर्माण के कार्य में कभी आवेगी। अष्टाचार और चापलूसी का बोल बाला होगा।

इन पुरज़ोर शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नौकरशाही के हाथों में जनता को पीसने का मौका न दें। इस प्रदेश की जनता जो स्रधिकतर मूक है, उसके साथ खिलवाड़ न करें। उपाध्यक्ष महोदय, श्राप जानते हैं कि ग्राज के जिलाधीश इस प्रदेश में क्या कर रहे हैं।

कानपुर की घटना की में समझता हूं माननीय मंत्री जी को पूरी तरह जानकारी होगी। हमारे यहां दफा १०७ ग्रौर ११७ में गिरफ्तारियां बहुत होती है लेकिन गांवों में रहने वालों की ज्यादातर गिरफ्तारियां होती हैं जो कि दो दलों में बंटे होते हैं, जिनकी ग्रोर से ग्रंदेशा होता है कि वहां झगड़ा हो जायगा। माननीय राजनारायण सिंह जी जो जेल में बन्द है ग्रौर कानपुर के निवासी नहीं हैं, पंचायत राज संशोधन ऐसे बिल पर ग्रसेम्बली में हिस्सा लेना जरूरी हैं, उनको जेलखाने के द्वार पर ही १०७ का नोटिस दे दिया गया। ग्रगर ऐसे ग्रधिकारियों के हाथ में जिलों का प्रबन्ध ग्रौर न्याय पंचायतों का प्रबन्ध दे दिया जायगा तो में समझता हूं कि लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा ग्रौर सही मानों में जनता की राय की उपेक्षा होगी। में ग्रापके द्वारा उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इसमें हमारा हाथ बटायें ग्रौर माननीय उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। कहीं ऐसा न हो कि चन्द दिनों ग्रौर महीनों के बाद उधर के लोग वही कहने लगें जो ग्राज हम कह रहे हैं। इसलिये में ग्रापसे ग्रौर ग्रापके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के संबंध में जो हमारे साथी का संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला ग्राजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रभी जो पंडित रामसुन्दर जी पांडेय का भाषण हुन्ना तथा मकन मोहन जी उपाध्याय का भाषण हुन्ना, उनको मंने सुना। यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा तो में समझता हूं कि कातून बनाने का काम बहुत बेढंगा हो जायगा और इसको मंजूर कर लेने से कानून की गाड़ी नहीं चन सकेंगी। कानून का हमारे सामने एक ढांचा होता है श्रीर उसको बनाते समय यह देखा जाता है कि उसको कार्यान्वित किया जा सकेगा या नहीं। जो संशोधन इस समय रखा गया है वह इतना जबरदस्त संशोधन है कि उसके गांव पंचायत का रूप ही बदल जायगा श्रीर वह ऐसी चीज हो जायगी जिसकी उनको स्वयं भी इच्छा न होगी तथा उनको वह किसी प्रकार सहायता भी नहीं पहुंचा सकेगा।

इसमें संदेह नहीं कि इसमें एक विकात पड़ रही है। वह दिक्कत यह है कि कहीं भी प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी की डेफीनीशन नहीं की गयी है। यदि माननीय मंत्री जी प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी को डिफाइन कर दें तो में समझता हूं ज्यादा प्रच्छा होगा या रूल्स में जब वे बनाये जायं उनकी विषद व्याख्या कर दी जाय तो अच्छा होगा। अगर ऐसा कर दिया जायगा तो जो शक उत्रर के लोगों को हो रहा है कि अगर डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में

[श्रो पद्यनाथ सिंह]

इतनी पावर्स दे दी जायंगी तो उनका श्रक्ष्यूज होगा, यह उनका भय किसी हद तक कम हो जायगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी को इसी ऐक्ट मे श्रथवा रूल्स में डिफाइन कर दिया जाय तथा यह निर्णय उसके श्रधिकार का ध्यान रखते हुये किया जाय।

में इतना ब्रवश्य कह देना चाहता हूं कि चाहे कोई चेयरभैन श्रौर कोई सेकेट्री हो उसमे कोई ग्रन्तर नहीं पडता है। चेयरमैन चाहै डिस्ट्रिक्ट मिलस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है जैसा कि भय श्री रामसुन्दर जी और माननीय उपाध्याय जी ने जाहिर किया, क्योंकि जनरल सेकेट्री जो कुछ करता है ग्रधिकतर चेयरमैन उसको डिटो करता है। इसिनये चेयरमैन चाहे डिस्ट्बट जज हो या डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट हो उससे कोई अन्तर न पड़ेगा। जो कमेटी बनेगी मुमिकन है कोई रिलीफ दें दें लेकिन उससे बजाय दिक्कत कम होने के और भी बढ़ने की संभावना है। इससे कानून बड़ा कम्बरसम हो जायगा श्रीर जैसा कि सिम्पलीफाइंग ग्रौर कमाइज उसे होना चाहिये वह न बन सकेगा। में निवेदन करूंगा कि प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी को डिफाइन कर दिया जाय या जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको ऐसा कर दिया जाय 'एज प्रेस्काइब्ड बाई दी रूल्स'। इस ऐक्ट के संबंध में बार-बार डैमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है श्रौर यह प्लांड मालूम होता है कि श्री राजनारायण जी का नाम इस संबंध में जहां भी लिया जा सके ले लिया जाय। मेरे ख्याल मे इस हाउस का कीरम वड़ी मावधानी के साथ यूटीलाइज करना चाहिये। श्री राजनारायण सिंह की गिरफ्तारी का संबंध न तो डेमोकेसी की किसी व्याख्या से है श्रीर न वह इस ऐक्ट की किसी धारा के श्रन्तर्गत श्राता है। श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी की चर्चा इस सदन में पहले श्रा चुकी है। डेमोक्रेसी बनायी जाती है और उसके बनाने मे श्री राजनारायण जी तथा दूसरे माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ बैठे हुये है उनका बड़ा भारी हाथ है और होना चाहियें और डेमोक्रेसी के वनाने में यदि कोई सदस्य जरा भी अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो आरम्भ मे डेमोक्रेसी का पहला स्टेज कई जगह डिक्टेटिरयल रखा गया है और उसको डिक्टेंटरिशप की तरफ से ट्रीट करते है भ्रौर उसमें गिरफ्तारी क्या बड़ी-बड़ी बाते हो जाया करती है। तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की रूपरेखा के संबंध में हमारे दिमाग मे एक वन्पयूजन सा है श्रौर वह क्नफ्यूजन भी ऐसा है तभी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूप मे तो डिक्टेटरशिप डेमोर्केसी का पहला स्टेज है और उस डेमोक्रेसी के पहले स्टेज में यदि कोई खलल पैदा करता है तो वह एनिहिलेट कर दिया जाता है। तो यदि इन विचारों के ग्रन्तर्गत ग्राप विचार करे ग्रौर इस परिभाषा के ग्रन्तर्गत इस बात को देखे तो ग्राप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की दहाई देने वाले अपने कार्य से डेमोकेसी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि उसको पीछे ले जा रहे हैं। अपने ऐकान में वे जिस्टफाई नहीं करते है। इस प्वाइन्ट से में प्रोटेस्ट के तौर पर इस बात को कहता हूं कि यह संशोधन जो पेश किया गया है इसको डेमोक्रेसी की शान के अनुरूप होना चाहिये।

में तो काउन्टर प्रोटेस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि यहां न तो श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी से कोई संबंध है श्रौर न डेमोक्रेसी के किसी डेफिनिशन की कोई बात है। लेकिन फिर भी में यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी से जो भय दिलाया गया है उसको ध्यान में रखते हुये उसको इस समय या जिस समय रूल बने डिफाइन कर दिया जाय तो बहुत श्रच्छा है। ताकि किसी भी सेक्शन श्राफ पापुलेशन को यह भय न रहे कि जो पावर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं उसका एब्यूज होगा या इससे हमारा कल्याण नहीं होगा या पंचायत राज का उद्देश्य प्रतिपादित नहीं होगा। मेरा नम्न निवेदन यह है कि उस भय को ध्यान में रखते हुये इस ऐक्ट को बनाना चाहिये ग्रौर प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स जितने मिनिमाइज हो सकते हैं उतने मिनिमाइज होने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में एक कहावत है कि ग्रासमान से गिरा खजूर में ग्रटका' हमारे लायक दोस्त उपाध्याय जी ने बड़ी धूमधाम के साथ,

बड़ जोरों के साथ विरोध करते हुये अपना जो अप्रमेडमेट पेश किया है। उसके जिएये उन्होंने मेजिस्ट्रेट से हटा कर जज अरेर कुछ पंचायत अफसरों को खींच कर वहां खड़ा कर दिया जहां कि पहले सरकार थी।सरकार ने पहले रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेट करे लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाकर गवर्नमेट ने एक लीगल वे में बड़े सुन्दर ढंग से प्रेस्काइब्ड अथारिटी को रखा। में अपने लायक दोस्तां से कहना चाहता हूं कि जिस समय रूल बनाया जाय उस समय वे अपनी बुद्धि को अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डेमोकेसी को बड़ी बुहाई दी गयी है लेकिन जो डेमोकेमी के हामी है उनके कारनामें हमारे सामने इसी मेज पर मौजूद हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से दो चार लाइने पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--उसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण—-मान्यवर, मं कह रहा था कि पुंचरीना म्युनिसंपेलिटी में जो लोग कार्य कर रहे हं, वहां की हालत श्राप देखे कि वहां क्या हो रहा है। वहां की हालत बड़ी बुरी हं, पानी छिड़कने का न कोई इन्तजाम है, न सफाई का कोई इन्तजाम हे। जहां पर कि डेमोन्नेसी के हामी हमारे सोशिलस्ट भाई ही मीजूद हं, लेकिन वहां की बाते किसी को दिखलाई नहीं देतीं। तो में श्रापसे कहता हूं कि 'कहता सब मिले, गहता मिले न कोय' कहने के लिये तो सभी कहते हैं श्रीर कल माननीय नारायणदत्त जी व श्री मदनमोहन जो ने हिन्दुस्तान के तमाम सूबे का कोटेशन दिया लेकिन ट्रावनकोर का नाम किसी ने नहीं लिया कि वहां की हुकूमत केसा काम कर रही है। ट्र वेनकोर में हुकूमत कैसा काम कर रही है श्रीर कैसा एडिमिनिस्ट्रेशन वहां चल रहा है? हम यहां पर जो पंचायत राज बिल लाये हैं उस के द्वारा हम प्रैक्टिकल काम कर रहे ह श्रीर हमारी सरकार ने इस दिशा में देश भर में पहला कदम उठाया है श्रीर हम जन्ता को पावर देना चाहते हैं श्रीर राम-राज के उगते हुये पौधे को हम फलीभूत करना चाहते हैं श्रीर सुख उससे उत्पन्न करना चाहते हैं। हमे श्राशा है कि हमारे इस कार्य की दूसरे प्रदेश भी कापी करेंगे। यह कानून निहायत सुम्दर ढंग से लाया गया है, यह नहीं कि चाहे जो रख दिया हो जैसा कि उपाध्याय जी ने कह दिया कि जज को कमेटी बना कर चेयरमैन बना दिया जाय श्रीर पंचायत श्रफसर को उसका सेकेट्री बना दिया जाय। हमारी गवर्नमेट ने साफ लिख दिया है कि—

"Prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under secton 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उसमें साफ लिखा है कि आगे चलकर हम नहीं जानते कि किसको बनावेगे। वहां के लोगों को भी बना सकते हैं, वहां के जो मुख्य-मुख्य लोग हों या जो अच्छे सिविल्यिन हों उनमे से छांट कर हम आदमी रज सकते हैं बजाय इसके कि हम बाहर के किसी जज को या कलेक्टर को रखें। गांव के जो योग्य आदमी हों, बुड्ढे हों या करेक्टर के आदमी हों, जिनका मारल करेक्टर ऊंचा हो उन हो भी हम रख सकते हैं। इसलिये इस तरीके से जज वगरा यहां रख कर हाथ बांधना ठीक न होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालीन)--मं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलता रहूंगा क्योंकि राजा साहब ने प्वाइन्ट आफ आईर नहीं उठाया है, वह सवाल पूछना चाहते हैं। इस समय वह सवाल नहीं पूछ सकते जब तक मैं बोल रहा हूं। यह कोई इस वक्त क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमने अपने संविधान में भी जजों को सबसे अंचा स्थान दिया है और बहुत अधिक पावर दिया है इसलिये हम जजों को इस पालिटिक्स में घसीटना नहीं चाहते। उनका काम तो न्याय विभाग को देखना है; यह तो एक्जिक्यूटिव के कार्य है। हाईकोर्ट के और सुपरीम कोर्ट के जज तो हमारे कानून पर भी अपना फैसला दे सकते है इसलिये उनको घसीट कर

्र्यः दिवनाराप्रम

हीचड़ वाली नाली में न लाना चाहिये। हम चाहते हैं कि मुन्दर कानून बने उसमें प्रेस्काइड़ प्रथारिटी ही रावा जाय और जिसको चाह मौका देकर रख दिया जाय। डेमोकेसी की बात भी

अयोर्जाशन को भी अपनी पोजीशन को मैनटेन करना चाहिये, महज गाल बजाने से ही काम नहीं चन्ना है। ए-चुअली काम करने की भी जरूरन होती है। हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है वह बहुन मुन्दर ह और यह संशोधन ठीक वसा ही है कि जब हम जिलार्थश को पावर देना चाहने थे तो कह दिया कि जज को यह पावर दी जाय और पंचायत अफसर को उसका में अदेश बनाया जाय और जब हमने प्रस्काइन्ड अथारिटी रख दिया तो जजों की बात करने लगे। इस तरह से बेकार की बकवास से काम नहीं चलता है और म चाहता हूं कि वह इस मंशोधन को वापम ले ले।

श्री कारावर वसी (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, में यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे सदस्य जो भाषण दे उसको क्या कोई माननीय सदस्य इस सदन में बकवास कह सकते हैं:

श्री उपायस--मे समझता हूं कि मुझे इस समय इस पर कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं है ग्रीर इस मंबंध में कोई प्रश्न भी नहीं उठाया गया था।

श्रो जोराबर वर्मा--माननीय शिवनारायण जी ने स्रपने भाषण के स्रन्त में कहा था कि बकवाम से काम नहीं चलता, यह उनको नहीं कहना चाहिये।

राजा बीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, उनको इसे वापस लेना चाहिये, यह शब्द अनुचित हं।

श्री उपाध्यक्ष—मं समझता हूं कि जहां तक हो सके ऐसे शब्दों की एवायड करना वाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुन्रा हूं। यह जो न्याय पंचायतों के चुनाव करने का अधिकार मैजिस्ट्रेटों को दिया जा रहा है वह एक तरह से स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। श्राज जिस तरीके से इस पुस्तक में रखा गया हं कि न्याय पंचायत कैसे बनेगी उनके या जो पहले की श्रदालती पंचायते थीं उनके कामों के ग्रनुभव से यह कहा जा सकता है कि ये जो पचायते बनाई जायेंगी उनसे ब्राजकल की दुनिया में न्याय हो सकेगा यह हमको ब्रसम्भव मालूम हो रहा है। क्योंकि जो पंचायत गांव-गांव में वोटों द्वारा चुनकर ग्रदालती पंचायतें बनीं उनके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं उन सबको ग्रनुभव है कि उनका काम कंसा रहा हैं ग्रीर ये न्याय पंचायते कंसी थीं। बहुत से स्थानों पर तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हुन्ना कि प्रतिज्ञा लेते हुये पंचायत के मेम्बरों ने प्रतिज्ञा की कि हम अन्याय करेंगे, उन्होंने न्याय के स्थान पर पढ़ा कि हम ग्रन्याय करेगे और ठीक है उसी तरह से शिकायतें भी रही है स्रौर मै तो यहां तक कह सकता हूं कि देहातों में लोग स्राज न्याय पंचायतों से ऊब से गये हैं। गांव पंचायतें इसलिये बनाई गई थीं कि गांव में ही झगड़ों का निपटारा होगा और लोगों की ग्रदालतों तक जाने में कमी पड़ेगी और लोगों की परेशानी कम होगी लेकिन स्राज उसके विपरीत हुस्रा। गांवों में परेशानी इननी बढ़ गई हे कि लोग उन पंचायतों से ऊब गये। उन पंचायतों में इस तरह से किया गया कि जो मुकदमें दाखिल होते हें उनमें ग्रच्छी तरह से न्याय नहीं पा रहे हैं। उन मुकदमों का फैसला जिस तरह से अदालतों में होता है कि दो चार ओदमी आये और

मुठो बातों की गवाही दी, वह बात सही हो गई श्रौर उसी के मुताबिक फंसला हो गया। जैक वही बात श्रदालनी पंचायतों में होती है।

बहुत सी जगहों में तो म माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बतलाऊं यह सुनने में श्राया होर ऐसी शिकायने रही ह कि वहां के पंचायतों में जो न्याय होता था उसको बदल दिया जाना था। यह तो गांव के चुने हुये पंचायतों की हालत है। श्रव ये पंचायते जो मंजिस्ट्रेटों द्वारा चुनी जायगी वह कैसे कार्य करेगी श्रीर क्या करेगी इमका श्रन्दाजा माननीय सदस्य लगा सकते ह। जो गांवों के चुने प्रतिनिधि थे वे जानते थे कि वे जनता से चुन कर बैठे हुये हैं लेकिन पचायतों में बैठ कर श्रन्याय करते थे श्रव यह जो श्रिषकारी जनता के चुने हुये न होकर श्रिषकारियों द्वारा चुने हुये होगे वे किस तरह से न्याय करेगे। इन सारी चीजों को देखते हुये में तो कहता ह कि गांवों में एक-एक बात पर थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद बैर साधने के लिये बहुत से १०७ के मुकदमे दाखिल हो जाते हं। जहां से थोड़ी सी रिपोर्ट हुई वहीं से देखिये पचास श्रादमी, सौ श्रादमी श्रदालतों में परेशान हो रहे ह। तो यह हालत हमारे गांवों की श्रोर गांव पचायतों की है। श्रभी-श्रभी सदन के सामने हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कानपुर का जिक्र किया। उस जिक्र के सिलसिले में में श्रापके सामने बतला देना चाहता हूं कि १०७ का मुकदमा उस वक्त चलाया जाता है जब कि दो फरीकों में झगड़ा होने का श्रन्देशा हो। उस वक्त १०७ के मुकदमें की नोटिस दी जाय श्रोर उस नोटिस के बाद जब श्रादमी फिर किसी प्रकार श्रमनोग्रमान में देखल करेता है तब वह बन्द किया जाता है। लेकिन राजनारायण जो जलखाने में बन्द थे.....।

श्री उपाध्यक्ष—मं समझता हूं कि उस मामले का यहां पर हवाला देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—मं उसका हवाला नहीं दे रहा था। मं बतला रहा था कि कलेक्टर द्वारा जो श्रादमी चुने जायगे वह कैसे काम करेगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों के चुने हुये पंच जो श्रब एक नियत श्रिधकारी द्वारा चुने जायंगे वह कैसे न्याय करेगे। वह तो सोचेगे कि हम तो सरकार द्वारा चुने हुये पंच ह, जंसे भी हो हमको न्याय करना है श्रीर जिस तरह से भी हो गांव के लोगो को फांसना है। उपाध्याय जी ने यह रक्खा है कि हर गांव के जो सभापित हों उनकी एक कमेटी बनायी जाय श्रीर पंचायत राज श्राफिसर उसका सेकेटरी बनाया जाय। श्रीर डि.न्ट्रक्ट जज उस कमेटी का चेयरमंन बन य, जाय। हब उस कमेटी के द्वारा न्याय पंचायत बनाई जाय। ऐसी हालत मे गांव के जो सभापित होंगे वह गांव के प्रत्येक व्यक्तियों के विचारों से परिचित होंगे श्रीर यह भी जानते होंगे कि कीन-कीन लोग ईमानदार है। ऐसी एक नियत श्रिधकारी कोर्ट, वन जायगी इस तरह से ईमानदारी से फैसला करने वाले श्रादमियों को चुनेगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मे उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री द्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—ग्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने गौर से उपाध्याय जी के भाषण को सुना । उनके भाषण के भीतर मुझे ऐसी भावना दिखाई पड़ी जिससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इसके ग्रन्दर कुछ रोष ग्रौर खफगी है जिसकी वजह से यह संशोधन ग्राया है ग्रन्यथा ऐसा ग्रव्यावहारिक संशोधन कभी नहीं ग्राता। ग्रापने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को छोटा हिटलर बना दिया। कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय मे व्यक्तिगत रूप से कुछ बुरी भावना हो सकती है लेकिन यह कह देना, उपाध्याय जी ऐसे जिम्मेदार ग्रादमी की तरफ से कि सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जितने हैं; जिनकी संख्या हमारे जिले मे कम से

[श्री द्रजनपण मिश्र]

कम ८१ तो ह ही: मबकं सब छोटे हिटलर ह ग्रीर बड़े गेर जिम्मेदार ह ग्रार सभी बड़ा गलत काम कर रहे हे, उनको नष्ट कर दिया जाय. म समझता ह कि यह श्रत्यन्त गर जिम्मेदारी की बात है।

न्हीं बात यह कि यहां बारम्बार माननीय नेता विरोधी दल के मामले की इस मामल में धर्मीटने की कोटिश की गई स्रोर कानपुर के काड का हवाला दिया गया। म कहना चाहना हू स्रत्यन्त नम्रता के साथ स्रौर बड़े स्रदब के साथ कि यह घटना जो कानपुर में हुई हं......।

श्री उपाध्यक्ष—म माननीय सदस्य से कह देना चाहता कि उस घटना का यहा पर जिक्र न किया जाय।

श्री वृज्ञभ्यण मिश्र— मं यह कह रहा था कि जो कानपुर में घटना हुई ह वह ११ अप्रंत का पहले ही मिर्जापुर में हो गई होती। जब कि माननीय चरण मिह वहा गये थे उनके साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो सल्क किया. मुझे दुःख के माथ कहना पड़ना ह कि यह घटना वही हो गई होती। जो उन्होंने वहा श्राचरण किया था मं उसके देशेरे में नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार उन्होंने एक दूर शान्त बगीचे में बैठी हुई सभा पर एक भीड़ लेकर श्राक्रमण किया, माइकोफोन छीनने की कोशिश की श्रीर सभा के सर पर २० गज के फासले पर श्रपना माइकोफोन लगाकर बाधा उत्पन्न की। बराबर शान्ति भंग की ग्रवस्था उत्पन्न की, यह काम ऐसा था कि वहां कोई घटना हो सकती थां, किन्तु चौधरी साहब की सहनशोलता से वह दल गयी।

श्री उपाध्यक्ष—मं माननीय सदस्य से यह कह देना चाहता हूं कि इस घटना का इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री वृज भूषण मिश्र— क्योंकि यहां पर कानपुर का उल्लेख किया गया इमिलिये कहना चाहता हू । श्रापकी श्राज्ञा से नहीं कहूंगा । तो में कह रहा था कि मिर्जापुर का जो कांड हुआ उससे में समझता हूं कि श्री राजनारायण सिंह जी ने नसीहत कोई नहीं ली उसका नतीजा यह हुआ कि कानपुर में एक दुःखद स्थिति उनको भोगनी पड़ी। इसके बाद में संशोधन के विषय में कहता हूं। स्रापन कहा है कि वहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बजाय जजु साहब उसके चेयरमैन हों स्रौर वह कमेटी बनावे। हर गांव सभा मे, जहां पंचों का चुनाव करना हो वहां के सब सभापित लिये जावे और वे लोग बंठ करके अपने हल्के के पंचो को चुना करे। इस प्रकार बराबर सिलिसिला जारी रहे। सोचने की बात है कि हमारे सूबे मे ३६,००० ग्राम सभाये ह श्रौर ग्रदालती पचायते करीब द हजार, ६ हजार के हैं तो इतनी ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये इतनी सब कमेटीज बने और रोज-रोज उनका संगठन हो श्रीर रोज-रोज चुनाव करे, यह कितना विलम्बकारी, श्रव्यावहारिक श्रौर खर्चीला कोर्स है। यह बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिस पर अमल नहीं हो सकता। तो यह ऐसे क्यों थे और अव्याव-हारिक सुझाव दिये हे किये कवापि मानने लायक नहीं है। यह कहना कि जज साहब, जिनको श्राप कहते है, अच्छा ही अच्छा करेगे ठीक नहीं उनमें भी ऐसे आदमी हो सकते हे जो खराबी कर सकते ह। तो यह कोई गारन्टी नहीं है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मिजिस्ट्रेट हं सब खराब है और जज साहब आ जायेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा चुनाव करेंगे यह बात ठीक नहीं है। हर काम उसूल से होना चाहिये। इसलिये में कहूगा कि म्रापका जो संशोधन है श्रव्यावहारिक है और मानने लायक नहीं है। कोई कानून व्यक्तियों पर ग्राधारित नहीं होना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्यों के भाषण हो चुके हैं। मै चन्द बातें जो कि सुझाव के रूप में हैं इस सदन के सामने पेदा करना चाहता हूं। मै बताना चाहता हूं कि हमारे गांवों की वस्तुस्थिति माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है श्रौर कानून की व्यवस्था जो इस सदन में बनायी जा रही है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनायी जा रही है । हमे यह देखना है कि हमारे गांवों के विकास का स्तर कहां है श्रौर इस प्रकार स्तर को देखते हुए जो गांवों की स्राज नई व्यवस्था हम करने जा रहे है उसमें हमारे ग्रामीण भाई कहां तक सहायक होंगे और किस हद तक सफलता प्राप्त कर सकते है। अगर इन वातों को हम नजरश्रन्दाज कर देते है तो मै समझता हूं कि जिस कानून की व्यवस्था हम बनाने जा रहे है शायद वह हमारे गांवों के जीवन को व्यवस्थित रूप से विकास के पद पर श्रागे बढ़ाने में उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि उसको होना चाहिये। मे यह बताना चाहता हूं कि जो यह मौजूदा प्राविजन है उसके ग्रन्दर प्रेस्काइब्ड भ्रथारिटी का जिक ग्रवस्य किया गया है । में समझता हूं कि इस प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को केवल एक वैकुश्रम मे हमें नहीं छोड़ना है, हमे रियलिटी के साथ ग्रेपिल करना है, ग्रगर कोई मुक्किल बात इसमें है तो उसको ग्रवक्य इस सदन मे टेकिल किया जाना चाहिये श्रौर इस प्रेस्काइब्ड श्रथ रिटं को श्रवस्य डिफाइन कर देना चाहिये। श्रगर प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी की सही ग्रौर सच्ची तस्वीर इस सदन में पहले रख दी गई होती तो म्राज इतने लम्बे-लम्बे वक्तव्यों की जरूरत कतई नहीं होती ग्रौर में यह समझता हूं कि ग्रगर इस मसले को ठीक से सही कर दिया गया तो जितनी ग्रड़चनें ग्राज हुमे नजर श्रा रही है उतनी श्रवश्य हमें दिखाई नहीं देंगी।

इसके अतिरिक्त में यह बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी सरकारी अहलकारान है, जिनका सम्पर्क गांवों की जनता से है उनको गांव पंचायतों के संगठन से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग इसमें शक करते हैं श्रौर समझते हैं कि सरकार का इसमें वड़ा भारी इंटरेस्ट हैं श्रौर चाहते हैं कि गांवों की संस्थाश्रों का सफल संचालन हो, म उनसे एकमत नहीं रखता। इसलिये गांवों की संस्थाग्रों के उत्थान का ग्रौर उनके विकास का उन लोगों के हवाले कर देना जिनकी सहानुभूति गांवों की जनता मे नहीं है बल्कि जो गांवों की संस्थान्त्रों को ग्रपने ऐडिमिनिस्ट्रेशन के लिये श्रीर ग्रपने इल गाटेन गेन्स के लिये एक श्रमिशाप समझते हैं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। जहां तक कि सरकारी श्रहलकारान का प्रक्त है में समझता हूं कि हम जो कोई भी मशीनरी गांवों की संस्थाओं को दृढ़ बनाने के लिये इस कानून के जरिये बनाना चाहते है उसमें नान-भ्राफ़िशल्स का ग्रधिक हाथ होना चाहिये ग्रौर सरकारी नौकरों का बहुत कम हाथ उसमे होना चाहिये। इसलिये मै यह समझता हूं कि जो कोई भी प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी हो वह कोई सरकारी ग्रहलकार जो कि जिले का हो, चाहे वह डिप्टी कमिक्नर साहबे हों या उनके मातहत वाले कोई ग्रफसर हों उनको नहीं होना चाहिये क्योंकि वे लोग ब्रिटिश कोर्ट श्राफ जस्टिस के सिस्टम से परिचित हैं जो कि एक एक्सप्लायटेशन का सिस्टम था श्रीर ब्राज भी श्रगर हम उस सिस्टम को इस मुल्क में चालू रखते हैं या फिर से हम ग्रपने गांवों में उस सिस्टम को लागू करते है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सिस्टम हमारे गांवों के उत्थान के लिये या उनके विकास के लिये एक ग्रभिशाप साबित होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस जमाने में खड़ी हुई थी और ब्रिटिश पालियामेंट में ग्रंग्रेजों के बड़े-बड़े नेता जो पालियामेंट के मेम्बर थे उन्होंने इस बात की वलीलें दी है और तकरीरें की है कि ब्रिटिश सिस्टम प्राफ जिस्टस भारतवर्ष को तबाह किये डाल रहा है धौर वहां की जनता उससे त्राहि-त्राहि कर रही है। वे चाहते थे कि इस सिस्टम को इस मुल्क से हटा विया जाय। जब कि उस जमाने में इस बात को महसूस किया जाता था तो में समझता

[चन्द्र मिह रावत]

हूं कि ग्राज वह समय ग्रा गया है जब कि हमें उस कमी को दूर करना है। इसलिये गांबों के लिये जो कानून हम ग्राज बनाने जा रहे है उसकी व्यवस्था इतनी सिम्पिल होनी चाहिये कि गांव के लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सके। ग्रगर इसकी दफायें इतनी काम्पलीकेटेड ग्रौर इतनी टेढ़ी है कि उनका पढ़े लिखे लोग भी कई किस्म का इंटरप्रेटेशन लगायें तो में समझता हूं कि उससे हमारे गांव की जनता का कोई फायदा नहीं हो सकता।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों की श्रोर से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा ग्रार मुझे कतई उसमें कोई हिचिकचाहट महसूस नहीं होती क्योंकि मं ग्रपनी उस भावना से प्रेरित होकर कह रहा हूं जिससे गांवों का भला हो सकता है कि जहां तक हो नके गांवों के ग्रन्दर इलेक्शन के जिरिये ही इन संस्थाग्रों को रखने में गांवों की जिन्दगी का सुधार किया जा सकता है भ्रौर जितने भी नामीनेटेड मेम्बर्स होंगे वह करप्शन का एक जरिया होंगे ग्रीर जहां तक गांव के लोग ग्राज तक इस करण्डान, बेईमानी ग्रार इम बीमारी से बचे हुये हे वह भविष्य में इन सब बीमारियों के शिकार होने लगेंगे और गांव की जिन्दगी और ज्यादा करण्ट हो जायगी। जब गांव के पंचों की पता चलेगा कि उनका नामीनेशन पांच साल के लिये हुआ है और उन्हें कोई निकाल नहीं मकता है तो में ग्रापको विज्वास दिलाता हूं कि हमें विज्वास है कि ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट्स को जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने बनाया था उसी प्रकार की प्रणाली से गांव का मंगठन छिन्न-भिन्न हो जायगा ग्रौर सरकार के प्रति जो रही-सही श्रद्धा गांवों में है वह मिट जायगी ग्रौर इसके साथ ही साथ घूसखोरी का राज्य फैलने लगेगा।

मं चाहता हूं कि इस प्रकार की ब्यवस्था कर दी जाय जिससे बेईमानों को प्रोत्साहन न मिल सके ग्रौर उनके ग्रन्दर यह विश्वास न हो कि बावजूद लोगों की नाराजगी के ५ साल तक वह जरूर रहेंगे ग्रौर उनको कोई हटा नहीं सकता है। जहां वह घूसखोरी करना चाहते है वहां वह सरकारी ग्रहलकारान को घो के कनस्तर घून में देकर ग्रिपने को ५ साल तक कायम रखने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें सुधार हो जायगा ग्रगर उनको यह विश्वास हो जायगा कि उनको लोगों के नाराज होने पर हटाया जा मकता है। जहां भ्राज सैकड़ों शिकायतें माननीय मंत्री जी तक पहुंचती है कि घूसखोरी हो रही है वह सब दूर हो जायंगी। इसलिये में समझता हूं कि हमें ग्रवस्य इन सब झगड़ों को दूर रखते हुये, पार्टी पोलिटिक्स के नुक्तेनजर को ग्रेलग रखते हुये, केवल गांवों की विकास की भावना से प्रेरित होकर और गांवों के फायदे की दृष्टिकीण में रख कर, इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने के लिये इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी चाहिये जो बहुत ही सीधीसादी हो ग्रीर गांव के लोग उसको श्रासानी से समझ सकें ग्रौर उसको ग्रमल में भी ला सकें ग्रौर उससे कोई करण्यान करने में प्रोत्साहन न मिले श्रौर करण्शन की कोई गुंजायश न हो श्रौर उनके श्रन्दर विश्वास न हो कि वह बुरे तरीके से भी श्रपनी जगह पर कायम रह सकते हैं बावजूद गांव के लोग मैजारिटी में उनके खिलाफ श्रावाज उठाते हैं।

श्री भगवतीत्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—-उपाध्यक्ष महोदय, में क्लोजर मूब करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, में इसका विरोध करता हूं, ग्रभी बहुत कम बहस हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--बहस तो काफी हो चुकी है। प्रक्त यह है कि......

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)-- प्वाइंट श्राफ श्राईर सर, कोई क्लोजर का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया है। श्रीमन्,

श्री उपाध्यक्ष-प्रस्ताव तो उपस्थित किया गया है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मै ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि श्रव प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-प्रश्न यह है कि ग्रब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुग्रा—

पक्ष में--- ५७

विपक्ष में--१३।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्राग्यूंमेंट्स उघर से पेश कि गये हैं मेरे संशोधन के खिलाफ, मै समझता हूं कि उनका जवाब देना मेरे लिये बहुत ग्रावश्यक हो गया है। माननीय रामलखन जो ने सबसे पहले यह कहा कि साहब, डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, वह डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ जानता हो नहीं है। इसीलिये तो हम चाहते थे कि पालिटिक्स वाले को नहीं होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो ऐसी पालिटिका जानता है कि चाहे जिसको लड़वा दे, चाहे जो करा दे।

श्री रामल वन मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैने पालिटिक्स का नाम नहीं लिया या डिस्ट्रिक्ट की जानकारी की बात कही थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—ठीक है, लेकिन जानकारी की श्रावश्यकता ही नहीं है। जिस न्याय पंचायत क्षेत्र के श्रन्दर वह नामजदगी करेगा वहां के लोगों की जानकारी वहां के ग्राम सभा के सभापित को होगी, वह बतायेगा, सरपंच बतायेगा, पंचायत राज इंस्पेक्टर्स बतायेगे। जज तो यह देखेगा कि यह श्रादमी ठीक है या नहीं, न्याय कर सकता है या नहीं, श्रदालती काम कुछ चला सकता है या नहीं, इस बात का फैसला डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। तो यह कोई श्राग्मेंट नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट के बारे मे कुछ जानता नहीं इसलिये वह न रखा जाय। में यह भी कहता हूं कि श्रगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखा जाता है तो वह भी इलाके की खबर नहीं जानता, वह भी दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इसलिये में समझता हूं कि यह तो कोई दलील इस बात की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्काइब्ड उप-ग्रथारिटी के जरिये से ये जो नामिनेटेड पंच मुकरंर किये जायंगे, हमारा पुराना तजुर्बा है, पिछली मर्तबा चुनाव हो रहा था, इसी हाउस का एलेक्शन था, उपाध्यक्ष महोदय, इन सरपंचों से लोगों ने जा जाकर यह कहा कि तुम तो सरकारी ग्रफसर हो, तुम तो सरपंच हो, सरकार के ग्रफसर हो, तुम्हें तो कांग्रेस को बोट देना ही पड़ेगा। तो यह तो तब कहा जब कि एलेक्टेड थे वह ग्रौर श्रव जब कि एलेक्टेड निकाल कर नामिनेटेड होंगे, प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी के जरिये से पंचों की नामजदगी होगी तब तो फिर पंचायत राज इंसपेक्टमं की पूरी बादशाहत हो गई। वह जाकर अनसे कहेंगे कि साहब, देखिये फलां श्रफसर ने श्रापको मुकरंर किया है, ग्रव तो आप बिल्कुल सरकारी ग्रादमी हो। ग्रगर बोट का प्रश्न ग्रायेगा तो वह उनसे कहेंगे कि तुम फलां ग्रादमी को बोट हो। हमारा हो ग्रह ऐसा तजुर्बा कहता है कि ्री महत्र में इन उपाध्याय]

यह तो पंचायन राज इंसपेक्टमं है वह और जिले के मन्दर सत्यानाश करते हैं इन पंचायनों का। यह कभी ग्राम सभामों ये नहीं जाते हैं, और जगह जाते होंगे, मुझे दूसरी जगहों का तजुवां नहीं है, पर मेरे जिले के अन्दर जो पंचायत राज इंसपेक्टमं ह उनका काम यह है कि अवालती पंचाय. जब बैठती है तो उसके पास बैठे तहने ह। ग्राम सभामों में वह नहीं जाते ह। ग्राम के विकास में इन्हें ज्यादा इन्टरेन्ड नहीं ह। इनका तो इसी में इन्टरेस्ट होता है कि गांव पंचायत में कोई सकदा प्याप्त किये मजा कराये और किसे छुड़ाये। यह भी हमारा तजुर्बा है कि पंचायन के इन्दरेस्ट ने किया जायगा अगर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट किया कारा किया अधिकारों को प्रकार है कि अब उसकी स्वराज्य मिल गया है, यह तो तुक्त राज्य हो गया है, यह तो तुक्त राज्य हो गया है, यह राज्य उसका न रह कर प्रेस्काइब्ड आथारिटी का राज्य हो जारा।

गाननीय पद्मनाथ सिंह जी ने जो मेरा मकसद था उसको ज्यादा साफ किया कि प्रार प्रेस्ट्राइव्ड श्राथारिटी की डेफीनीशन हो जाती तो पता चल जाता कि प्रेम्ट्राइट्ड प्राथारिटी की डेफीनीशन हो जाती तो पता चल जाता कि प्रेम्ट्राइट्ड प्राथारिटी कींन होगा। हमें शक है इस बात का कि यहां पर जो प्रेस्ट्राइट्ड श्राथारिटी लिखा गया है, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मिजस्ट्रेट न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो हो। हमारे इस सदन में कांग्रेस का बहुमत है। तो कहीं ऐसा ही न हो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही लाकर प्रेस्त्राइब्ड श्रयारिटी रम्ब दिया जाय। हमें इस बात का शक है।

जहां तक माननीय शिवनारायण जी का सवाल है मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि उन्होंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जज का नाम सुना श्रोर जज पर ही कहते रहे। कहने लगे कि वकवास हो रही है। जैसे वह बकवास करते है वैसे दूसरों के लिये समझते है कि वकवास करते है। लेकिन में उनके रास्ते में रोड़ा नहीं डालना चाहता। वह किसी उम्मीद में है। उनकी वह उम्मीद कायम रहे श्रोर उनको मिलेगी। इन्तजार का फायदा मिलता ही है। इसलिये में उनके लिए कुछ नहीं कहन। चाहता।

जपाध्यक्ष महोदय, एक बात ग्रौर कह देना चाहता हूं। माननीय मिश्र जी ने बेबुनियाद ग्रौर न मालूम कितने इसी प्रकार के शब्द कह डाले इस संशोधन पर, वे शब्द मुझे याद ही न हैं। ग्रा रहे हैं। लेकिन उहों। एक महत्वपूर्ण बात कह डाली जिस की तलाश में ही में था। हम सोच रहे थे कि राजनारायण जी को तंग करने का क्या कारण है। क्यों राजनारायण जी को जेल में बिना किसी ग्रपराध के बन्द किया जा रहा है? श्रव पता चला जब कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि मिर्जापुर में माननीय राजनारायण जी की ग्रौर माननीय चरणसिंह जी की लड़ाई हो गयी थी। वहां पर माननीय चरण सिंह जी की नहीं चली। उपाध्यक्ष महादय, चूंकि इसका जिक उन्होंने कर दिया इसलिए में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष-मैने तो उनको भी मना कर दिया था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—पाप तो खुल ही जाता है। श्रब पता लगा कि माननीय राजनारायण जी को क्यों तंग किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि माननीय चरणसिंह...

श्री उपाध्यक्ष—यह बात नामुनासिब होगी। इस पर माननीय सदस्य कुछ न कहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो कुछ ग्रौर बाते माननीय व्रजभूपण जी ने कहीं मेरी समझ में नहीं श्रायी कि कैसे इस पर नहीं लागू हो सकता। उन्होंने कोई ग्रागूमेट नहीं दिया। यह तो कह दिया यह तो लगता ही नहीं हूं। प्रेस्काइड्ड ग्रथारिटी कोई व्यक्ति होगा। जब डेफिनीशन होगी जब रूत्स बनेंगे तो प्रेस्काइड्ड ग्रथारिटी किसी को बनाया ही जायगा। में समझता हूं कि बजाय इसके कि रूत्स में यह बात रखी जाय, कि प्रेस्काइड्ड ग्राथारिटी क्या चीज है कम से कम जहां तक गांव पंचायतों में मेम्बरों को नामिनेट करने का सवाल है उस मौके पर प्रेस्काइड्ड ग्राथारिटी को हटा दिया जाय। मैं तो प्रेस्काइड्ड ग्राथारिटी की डेफिनीशन भी नहीं चाहता। में तो इस प्रेस्काइड्ड ग्रथारिटी को हटाना ही चाहता हूं। इसकी जगह में चाहता। हूं कि एक कमेटी रखी जाय जिसके चेयरमंन जज हों, जिसका सेकेटरी पंचायत राज इंस्पेक्टर हो ग्रौर जिसके मेम्बर गांव सभाग्रों के सभापित हों।

माननीय शिवनारायण जी का भाषण डेमोक्रेसी पर भी सुन लिया। मैं कहता हूं कि यही डेमोक्रेसी है। ग्रसली यही जड़ है जहां से डेमोक्रेसी पनपने वाली है। जो हा बोट देने वाले हैं, जिनकी हम यहां पर सेवा करने आये हैं जिस जनता ने हमें यहां भेजा है कि हम कानून बनायें, उसी जनता को हम उसके श्रीवकारों से वंचित करना चाइने हैं। यही डेमोक्रेसी हैं? हम ऐसे श्रीवकार नहीं देना चाहते कि जिन्होंने हमको यहां छंटकर मेज दिया उस जनता के श्रीवकारों पर हम श्राक्षेप करे। एक प्रेस्काइब्ड श्रिवारिटी व ला

भीर में तो चाहता हूं कि यह हट जाना चाहिये श्रीर ग्रगर नहीं हटता है वहीं ऐसे लोग होने चाहिये जिन पर किसी राजनीति का श्रसर न हो, पोलिटि-स पर जिनका कोई ग्रसर न हो। वे ही लग उनको मुकर्रर कर सकते हैं।

इत चन्द शब्दों के साथ मुझे ब्राशा है कि माननीय मंत्री जी, जिनको मैने ब्रभी तक सुना नहीं, इनको सुनने के बा. जो उचित बात होगी वह कहेंगे और जो उचित होगा वह स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जितनी वहस हुई, उसमें बहुत सा तो इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। में इस समय यह मुनासिब नहीं समझता कि जबिक एक संशोधन पर विचार हो रहा हो, किसी एक ऐसे प्रक्त को लाया जाय और उसको तय करना कि वह सही हो रहा है या गलत, जबिक उस पर बहस नहीं है और जबिक न कोई उसका नोटिस है और न उसके हक में या उसके खिलाफ कोई अवसर है। ऐसी जगह या नाम लेकर कुछ कहना मुझे ग्रलत मालूम होता है और इसलिये में उसका जवाब नहीं देना चाहता। उसका सही अवसर होगा, जब वह मामला आये, जब उस पर विचार हो और जो उसके हक में या खिलाफ फैसला हो। इसलिये राजनारायण जो का या कानपुर के डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेट का नाम लेना में बिल्कुल गलत समझता हूं और न में इसके सम्बन्ध में कोई राय देना चाहता हूं या जिक करना चाहता हूं, या यह समझता हूं कि इसमें जो राजनारायण जी का या डिस्ट्रिक्ट मंजिस्ट्रेट का नाम लिया गया....

श्री मदनमोहन उपाध्याय-मिर्जापुर के बारे में क्या खयाल है?

श्री मोहनलाल गौतम---मिर्जापुर का तो एक खास वाक्रया था, उसके सम्बन्ध में जो कहा गया श्रीर उत्ती के कांटिनुएशन में जो गलती चली जा रही है, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखती, उन बातों पर मैं श्रपने विवार इस समय प्रकट करना नहीं चाहता।

^{*} बस्ता ने भाषण का पुनर्वीञ्चण नहीं स्टिया ।

[श्री मो [तनान गोतम]

यव बहुन से डेमोक्रेसी के श्राँर दूसरे सिद्धान्त कहे गये। इस वक्त जबिक परिवर्तन का मंशोधन माननीय विष्णुवयाल जी का था, उसमे एक सिद्धान्त की बात थी कि न्याय पंचायन के पंच नामजद हों या चुने जायं। चुने जायं तो प्रतिनिधियों द्वारा चुने ज्ञायं। वह एक सिद्धान्त की बात हो सकती थी। लेकिन श्रव सिद्धान्त की बात कोई नहीं। सवाल यह है कि नामजद भी किये जायं अपवाइंट किये जायं, सेलेक्ट किये जायं, नेजिन कौन करें, यह बहस है। इसलिये जितनी सिद्धान्त वर्गरा, या डेमोक्रेसी की बाते कही गई वह भी इस समय बेकार है श्रौर उनका उत्तर देने की भी मुझे श्राव-रयकना प्रतीन नहीं होती।

ग्रव प्रश्न यह हैं कि जो सदनमोहन जी ने एक प्रेस्काइब्ड को डिफाइन करने की कोशिश की हे वह क्या है:

"a committee coasisting of the (a) District Judge who shall be the Character in the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary (c) all the Prauliums of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने सरकारी ग्रफसरों की बुराई की, उन्होंने वृद ही ग्रपने ग्राप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ग्रफसर को सेन्नेटरी बना कर उसका जवाब दे दिया ग्रार उन पर विश्वाम प्रकट करके कह दिया कि जितनी उन्होंने दलीले दी थीं वह सब बेकार थीं। इंसपेक्टरों की बुराई की गयी। हो सकता था कि किसी खास क्षेत्र की जलवायु ऐसी हो कि वहां के रहने वालों पर कोई खास ग्रसर पड़ता हो, लेकिन मं कह सकता हूं कि पंचायत राज ग्रफसर सिर्फ न्याय पंचायतों पर बंठ कर ही ग्रपना काम नहीं करते। उनको ग्रीर बहुत से काम करने पड़ते हं, उनकी रिपोर्टे ग्राती है, ग्रीर जब सेन्नेटरी होगा तो वह इस्पेक्टरों की बात मानेगा हो। तो जितनी बाते इंस्पेक्टरों वग्ररह की वही गयीं उनका जवाब स्वयं दे दिया गया ग्रीर उसके ग्रलावा जो बाने कही गयीं वह बहम के तौर पर कह रहे हं।

तो इसमें ये चीजें जो इधर-उधर की है। ग्रसल सवाल यह है कि जो कमेटी माननीय उपाध्याय जी ने इसमें बनायी है उसका क्या रूप है। उसका रूप यह है कि अगर द,४०० न्याय पंचायतें हे तो उसके अनुसार द,४०० कमेटियां श्रलग-प्रलग हुई ग्रौर हर गांव सभा का सभावति उसका मेम्बर होगा। ऋगर ६५, ७० या ७५ हजार गांव सभाये हों तो ६५ हजार गांव सभाग्रों के सभापति इन ८,४०० प्रेस्काइब्ड प्रथारिटीज की सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर होंगे। ग्रब ग्रन्दाजा कीजिये कि जब जब वेकेन्सी होगी तत्र तब यह प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी बँठेगी ग्रौर ये ६५,००० ग्रादिमयों की **८,४०० कमेटीज जो होंगी वे समय समय पर बंठा करेगी। इसका हिसाब लगाइये** कि इसमें क्या खर्च बैठेगा। एक न्याय पंचायत के लिये एक कमेटी हुई जिसमे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमंन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ग्राफिसर सेन्नेटरी हं ग्रौर जितने सभापित है, वे मेम्बर है। जब उन्होंने न्याय पंचायतों को चुन लिया तो वह कमेटी खत्म हो गई स्रोर दूसरी कमेटी शुरू हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयर्मन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य ग्राफिसर सेकेटरी है ग्रीर सब सभापति सेम्बर्स है। ग्रगर न्याय पंचायतों मे १५ से २५ तक मेम्बर रक्खे जायं तो जब कभी कोई वेकेन्सी होगी तो सब सभापति आया करेगे श्रीर उन सबको भत्ता मिला करेगा। ब्रेन्दाजा नहीं कर सकते कि जितना बजट पंचायत राज्य को मिलेगा वह प्रस्काइब्ड ग्रथारिटी के भत्ते में ही समाप्त हो जायगा या कुछ बाकी भी रहेगा। इतने ग़लत तरीके का यह सुझाव है जिसको में नहीं समझ सकता। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय उपाध्याय जी इसकी बापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्यण्य— गैने प्रेस्क ब्ह प्रश्निति ही कोई परिभाषा नहीं है की है। जहां तक पंचों के मुकर्रर करने का सवाल है उसी स्था से मने इस संशोधन को रक्खा है। माननीय मंत्री जी यह ग़लत सजझे कि नने प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी को कोई परिभाषा की है। ५ पंचों को जुंरर करने के लिये यह करेटी बनेगी, फिर वह खत्म हो जायगी।

श्री मोहनलाल गाँतम—मं नहीं समझता कि मेने समझने ने कोई सलती की है। वं लोग चुन लिये जायंगे यह ठीक है लेकिन जब कोई वेकेन्सी होती तो द,४०० न्याय-पंचायतों में जो २०-२० या २४-२४ श्रादमी होंगे जो दो लाख से ज्यादा होंगे, जो महस्य होंगे न्याय पंचायतों के, उनकी मीटिंग्स हुग्रा करेगी श्रीर उसने उिस्ट्रिक्ट जज चेयरमंन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य श्राफिसर सेकेटरी श्रीर उस क्षेत्र वी ग्रास सभाग्रों के सभापति उसके सदस्य होगे। ये सब दैठ कर उस वेकेन्सी के लिये फिर मेम्बर चुनेगे। लिहाजा में शलत नहीं समझा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह हे कि खंड १४ में प्रस्ताब्रित धारा 12-A में सब्द "Prescribed authority" के स्थान पर निम्नोलिखत शब्द रख विये जाये

"a committee consisting of the (a) District Ledge v'o hell be the Crairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Sucretary, (c) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और ग्रस्दीकृत हुन्ना:)

* महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मं श्रापकी श्राज्ञा से ग्रपने संशोधन को इस संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ के श्रन्तर्गत 12-A के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

12-A. For the purpose of electing members of a Caun Puncha, and the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as aforeasid under section 43 for membership of the Nyaya Pancha, at shall be members of the Gaon Panchayat.

*श्री मोहनलाल गौतम—यह संशोधन इतना लम्बा है कि मेरी सपक्ष मे धभी नहीं ग्राया है, इसलिये मेरे लिये उस पर राय देना कठिन होगा।

महाराजकुमार बालेंग्दुशाह—म उसकी काथी धादके पास भेज देता हूं। जहां तक इस संशोधन का तात्पर्य हं उसमे ग्रीर जो माननीय धंरी महोदय ने इस धारा में प्राविजन कर रखा है उसमे दो विशेष ग्रन्तर है। माननीय मंत्री महोदय की इच्छा यह है कि प्रेस्ताइब्ड ग्रथारिटी के द्वारा न्याय पंच की निष्टुक्ति हो। उसमें मंने ग्रापित उठायी है ग्रीर मंने यह सुझाव पेश किया है कि वजाय प्रेस्ताइब्ड ग्रथारिटी के द्वारा इनकी नियुक्त करने से यह उचित होगा कि जिन सदस्यों को गांव सभा में न्याय पंचायत के लिये छूट हो वह स्वयं श्रापस में बैठकर पंचों का चुनाव करें यानी जैसा कि मंत्री महोदय के विचार के ग्रनुसार एतें काल हो रहा है तो मेरा सुझाव यह है कि उस एलेक्शन से इन्डाइरेक्ट एलेक्शन किया जाय।

दूसरा श्चन्तर यह है कि बह एक कंप्रोमाइज की शक्ल माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी है क्योंकि मंत्री महोदय श्रभी तक पंचायत राज के सम्बन्ध में उतना

^{*}बस्ता ने भारण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महरा :कुमा वा नेन्दु गह]

विश्वास उत्पन्न नहीं हुन्रा है, इसलिये कि माननीय मंत्री महोदय बराबर यह कहते हैं कि ग्रभी तक ग्राम जनता इस योग्य नहीं है कि उनके हाथ में उनके चुनाव को छोड़ दिया जाय । मेरी राय में ग्रगर उनके चुनाव को उनके हाथ में छोड़ दिया जाय तो सम्भवतः वह पूरे मेम्बर चुने जा सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मंने ऐसा कभी नहीं कहा श्रौर इस कम में जो दलील होगी वह बेकार होगी।

महाराजकुनार बालेन्दुशाह—यदि माननीय मंत्री महोदय ने इसको नहीं कहा है तो मं उसको वापस लेता हूं। किन्तु इस विधेयक को पढ़ कर यह स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री महोदय को ग्राम जनता पर भरोसा नहीं है। यहां पर मने यह कम्प्रोमाइज का फार्मूला पेश किया है श्रीर मेरी यह मंशा है कि यदि किसी कारण मंत्री महोदय या उनका विभाग

श्री शिवनारायण—प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, नम्बर ४६ पर श्री विष्णुदयाल जी का जो संशोधन है वह बिल्कुल ऐसा ही है।

श्री उपाध्यक्ष-वह तो संजूर नहीं हुन्ना है।

श्री शिवनारायण—वह तो वैसा ही है श्रीर ग्रभी पेश भी नहीं हुन्रा है।

श्री उपाध्यक्ष—मं समझता हूं यह सक्टीटचूशन के लिये प्रस्ताव है।

श्री शिवनारायण-देवारा किस तरह पेश हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष-इतना ही नहीं है। दूसरी चीज भी रखने के लिये यह है।

महाराज हुमार बालेग्डु ग्राह—माननीय शिवनारायण जी ने जो प्वाइंट स्राफ भ्राइंर रेज किया है उसका सुक्ष्म उत्तर देने की मैं स्नावश्यकता समझता हं।

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है।

महाराजकुनार बलेन्दुशाह्—जैसा मं कह रहा था मेरे सुझाव में एक कप्त्रोमाईज फार्म्ला पेश किया गया है जो कि श्री तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन में नहीं है वह यह कि जिन पंचों का चुनाव गांव सभा से नियुक्त गांव पंचायत करे उसको माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्ताइब्ड अयोरिटी कनफर्म और एप्र्व करे तब चुनाव मामा जाय। इसलिये मं माननीय शिवनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे श्राराम से बैठें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि प्रश्न केवल एक ही है थी! वह है सिद्धान्त का थ्रौर वह यह कि उनकी नियुक्ति हो या चुनाव द्वारा पंच बनाये जायं। में यह मानता हूं कि जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने पेश किया है वह एक जिर्या ह कि प्रस्काइब्ड ग्रथारिटी किस तरह की बने। इतना उसमें भी है कि नियुक्ति की प्रथा श्रपनायी जायगी। में समझता हूं कि उससे श्रिक खन्तर नहीं श्राता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे या डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त करे या पंचायत श्रा फेसर नियुक्त कराये या चाहे माननीय मंत्री जी हो स्वयं 'नियुक्त क्यों न करें, में समझता हूं सब एक ही श्रेणी के हैं। प्रश्न यह है कि सिद्धान्त रूप में से पंचों की नियुक्ति होना उचित है या ग्रमुचित या सिद्धान्त रूप से चुनाव होना उचित है

या अनुचित । मेरा जहां तक मत है में इस दृढ़ विश्वास का हूं कि यदि पंचायत राज सफल बनाने की वास्तविक कोशिश है और यदि यह इच्छा है कि जनता में पंचायत राज जैसा एक इस्टी ध्यान बने तो उसके बीच में कोई ऐसी चीज न होनी चाहिये जो सरकार द्वारा थोपी जाय। में तो यह मानता हूं कि जनता को पूर्ण रूप से अधिकार देने चाहिये और अगर यह संभव न हो सके तो जितना भी हो सके कम रिजर्वेशन के साथ उसको वे अधिकार दिये जाने चाहिये। जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जो को जहां तक हो सके अधिक से अधिक अधिकार जनता को देने चाहिये ताकि जनता उसमें भाग ले सके और जनता का यह इंस्टी ध्यूशन सफल हो।

पंचों के चुनाव के सम्बन्ध में एक दात मुख्य रूप से ग्रौर हमेशा कही जाती है स्त्रीर हमेशा एक ही दलील दी जाती है कि कहीं भी यह प्रथा नहीं पायी जाती है कि पंच ग्रथवा जुडिशियरी इलेक्टेड हो। बहुत नुब हद तक यह बात सही है। मन्त्री महोदय को मालूम है कि हाईकोर्ट श्राफ पालियामेर है, हालांकि उसकी बैठक कभी कभी होती है, वह इलेक्टेड बाडी है। लेकि वह डलेक्टेड बाडी होने के बावजूद भी जुडिशयरी का हाइएस्ट अंग माना जाता है मगर इसके होते हुए भी मै यह मानने के लिये तैयार हूं कि जहां तक हो सके जुडीशियरे इलेक्टेड नहीं होनी चािये। इस बात का जिक्र करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह में अपने है विरुद्ध बात कह रहा हूं। किन्तु में समझना ह कि यह बात नहीं है और जुड़ी केयरा के ऐक्ट न होन भारक है। मुख्य के रेण है और वह यह है कि जो व्यक्ति कल एक लिटिगेट की हैसियत से उस जुडिहिंगरी के सार ने जायेगा उस व्यक्ति का चुना हुया वह रंच न हो। यानी जहां तक हो एके सम्भावना को बचाया जाय कि कल उसी पंच के सामने वही व्यक्ति एक लिटिगेट की सूरत मे श्रावे। जो सुझाव मैने मानतीय मंत्री महोदय के सामने रखा है उससे यह सम्भावना बहुत हद तक दूर हो जाती है। मेरे सुझाव के ब्रतुसार केंदल मात्र ३० या ३५ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके द्वारा पंचों का चुनाब होगा। हो सकता है कि इनका मामला इन पंचों के सामने आवे और ऐसी अवस्था में जो कहा जाता है कि उसके खिलाफ वे जायं, किन्तु में समझताहूं कि ग्रगर ३० या ३५ व्यक्तियों के मामल के ग्राने को सम्भावना के कारण ग्रादि हम इत्र नियुक्ति के सिद्धांत को श्रपनाये तो वह एक बहुत हो गलत जात है। जहां तक में देख सकता हूं इन डाइरेक्ट एलेक्शन के द्वारा पंचों का चुनाव करने में न केवल जनता का उन गंचों के ऊपर विश्वास होगा बल्कि साथ ही साथ वह इंड्यरिणाम भी दूर हो जायगा जो कि एक नामिनटेंड व्यक्ति और इस जनतांत्रिक राज्य द्वारा छांटे हुए लोगों के बोच में काम कराने की चेष्टा की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदप, इस सम्बन्ध में हमारा यह भी कहना श्रावश्यक है कि यि मंत्री महोदय मेरे इस कम्मोमाइम फार्म ले को नहीं माने व्योंकि इसको मानने न मानने को तो उनको श्राविकार है, हमें के बल सुझाव देने का हो प्रधिकार है। तो में यह कहता हूं कि यह मंत्री महोदय इस फ.मूंले को स्वीकार करते हैं तो जहां तक में देख सकता हूं उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निय्वित करने के लिए कोई विशेष कारण है। एक कारण जो मेंने कहा कि एनेक्शन को खिलाफ बारम्बार कहा जाता है और केवल यही कारण है कि यह मंग्रीधन श्राया और एनेक्शन की बुराई बतलायो गयी। जुडिशिश्ररी का एलेक्ट होना ठीक नहीं है इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। एक श्रीर कारण बतलाया गया है कि यदि उनको यह श्रीधकार दे दिया जाय तो सम्भव है कि अनुचित व्यक्ति में ब वन जाब। तो जो मेंने मंत्री महोदय की सेवा में कम्प्रोमाइज संशोधन प्रस्तुत किया है उससे ये दोनों श्रापत्तियां दूर होती है। जुडिशिश्ररी का एनेक्ट होना तो में मानता हूं कि अनुचित है किन्तु जिस रूप में श्रव पंच गण एलेक्ट होंगे उस रूप में नुडिशियरी के एलेक्ट होने की बुरायी दूर हो जाय और जहां तक सम्भव है बुरे लोग पंचों में से छट जायं। यह श्रीधकार प्रस्काइब्ब अथारिटी के हाथ में देने से जो पंचों के चुनाव में माननीय मंत्री महोदय को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है वह इस कम्प्रोमाइज फार्मू ले से काफ़ो हद तक हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

ात चच्च स्याने दुश्यही

माननी प्रमान है है है ने की मही भार की विरोध करने हुए किसी व्यक्ति ने अपने भावण में
नार शित्र ना को लिए हैं हो साहिए कि एता निया है सके जजेज की पोलिटिक्स से दूर रखा
पार कि ना को रिवार के एक किस प्राथार पर उन्होंने कहा। क्या इससे में यह तमम् कि
रह पर का पार कि लिए का एक यहाँ व बनाया जा रहा है ? में तो समझता था कि पंचापन
राज का का का का है कि है है कि नहीं है । किन्तु एक सदस्य का अोग
रह है नहीं वंदा के कामा था ऐसा कहना कि जजों की पंचायत राज की पालिटिक्स से दूर
राज विश्व के कामा था ऐसा कहना कि जजों की पंचायत राज की पालिटिक्स से दूर
राज विश्व के का का लिए का की पालिटिक्स से पालिटिक्स को बात है । यदि इस समय नहीं नो
कि हिए में को का निवार के हैं कि का पाले हैं कि वंदा की पालिटिक्स को बात है । यदि इस समय नहीं नो
कि हिए में का कि लिए की हैं दिनका पह मुख्य कर्ताच्य मौर सिद्धांत है कि जहां तक हो सके
पद्म पर पाले के का निवार में से सहस्य की स्वार की में हो में रित होकर कुछ कह रहा है
जीर समय के कि पत्र की से विचार से सहस्यत नहीं किन्तु यह कहना कि जनतंत्र राज्य से
से यह रहा करना कि वह गंदों को नियुक्त करके उन पर विश्वास करेगी, म

म उन नात्व ने जुड़ उस बात की भी चर्चा कहंगा कि हम इन न्याय पंचायतों में क्या जात कारी है। यहां ना दुर्माग्यादा मंत्री महोदय के सामने एक तुच्छ व्यक्ति हूं परन्तु म इस नावत्व रे या ने उन ने ला विचार रखता है। मंत्री जी के विधेयक की पढ़ते समय यह अवस्य प्रश्ति है। जो के विधेयक की पढ़ते समय यह अवस्य प्रश्ति है। जो की कि जहां का है कि जहां ना कम्याय नंचायतों का सम्बन्ध है मंत्री महोदय उनकी त्याय की कि जहां ना प्रश्ति काएग तंग समझते ह यानी जैसे एक सुत्रीम कोई है उसके नीचे हाईकोई हु छोर जिस प्रश्ति वाही बगोड़ी कोई घाफ जूड़ी केचर होता है उसी तरह से मंत्री महोदय ने इन पंचायतों के रेड निनिस्ट्रेशन आफ जिस्स की अंग माना है। हो सकता है कि उनका विचार सही हो होरा यह भी नहीं हो कि नंगी महोदय अपने पिछले तीन या चार साल के अनुभव के अनुनन वह विभेग्न लाये हैं। और पेरा अनुभव पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में कम हो

(इन सन्द ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

परन्न जो मुख भी मेरा अनुभव है उसका भी इस सदन में जिक्र कर देना उचित बन नम्या इं किन्तु इस बिखर में मे यदि घांड से नहीं तो गौरव से कहता हूं कि सूबे हे बंबायपर जो देश सन की जो प्रणाची चलाबी गयी उससे पहले ही टेहरी गढ़वाल में पंचायत राज चलाया गा श्रीर हालांकि जैसा कि होता ही है उस समय के बाताबरण ने और डा समय के वाताबरण में बहुत अन्तर है फिर भी म इन्न दिल को कर देना च हना हं कि वहां की न्याय पंचायतों की जो भावना थी ग्रीर जो प्राइडियन या अपदर्श था उसने इस विधेयक की जो भावना है वह बिलकुल विभिन्न है इतन को कहा हो जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह पंचायत राज की न्याय पंचायने होई कोर्ट नहीं है कचहरी नहीं है। वह तो ऐसी संस्थायें है जहां पर दो व्यक्ति चाहे भाई-भाई ह वर्शे न हों, अगर उनने झाड़ा हो जाय तो वह जा कर फैसला नहीं मांगते। वह चाहने हैं कि वहां जनसोता, राजीनामा या कम्प्रोमाइज हो जाय, चाहे वह क़ानून के प्रनुसार गलत हो क्यों न हों. वह एक रेडो इन्ट रफ फैसला चाहते है चाहे वह कैसा भी हो लेकिन दोनों को वन्तुष्ट करने वाला हो। जो रीति मंत्री महोदय ने इसमें अपनायी है जिसके अनुसार फार्ने निटीज फाफ कोर्ट पोनीज्योर अपनाया गया है, जिसके अनुसार राइट आफ अपील दी गरी है उमी स्वष्ट रूप में प्रतीन होता है कि कुछ दिनों पश्चात्, कल नहीं, स ल भर पश्चात् नहीं, १० साल पत्रचान् यह न्याय पंचायतें मंत्री महोदय के हाथ से निकल कर माननीय न्याय कंत्री के हाथ में दे दी जायेंगी श्रीर में समझता हूं यदि ऐसा होगा तो यह पंचायत राज्य के हित

के लिये बहुत बुरी बात होगी। मेरा तो यह विश्वास है कि न्याय पंचायत पंचायत राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रंश है और न्याय पंचायतों से यह आशा करना कि जिस रफ्तार से हम यहां कानून बनाते जाते हे और उन कानूनों का वहां वे इंटरप्रिटेशन करें या उन कानूनों के प्रमीज्योर में फंसकर ऐकेडेमिक और लिटरेरी जजमेंट दे यह हमारी तरफ ने पूर्वता होगी। बारम्बार मेरी यही सिफारिश होगी कि हमारा यह कहना और यह सोचना अनुचित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह पंच बनने के योग्य नहीं है। पढ़ना और जनता का विश्वास प्राप्त होना यह दोनों वातें ऐसी नहीं है जो साथ-साथ नहीं पायो जा सकतीं। यह कुछ हद तक पाया जाता है कि व्यक्ति पढ़ा न हो फिर भी जनता पूर्ण हम से अन्वविश्वास तक करने के लिये तैयार हो। ऐसा व्यक्ति में पूछता हूं कि जिस रूप से न्याय पंचायत की प्रणालों बनी है अनपढ़ा हो किन्तु जनप्रिय, जनता का विश्वास प्राप्त व्यक्ति न्याय पंचायत में बंचित रखा जाय, जानबूझकर नहीं किन्तु एक ऐसी रोति अपनाकर जिसकी वजह से उसका वहां श्राना असम्भव हो जाय में समझता हूं गलन है।

मं स्रव स्रिश्चिक न कह कर यह स्राह्मा करता हूं कि मैंने जो कम्प्रोमाइज का सजेशन दिया है उसको स्वीकार करेगे लेकिन मुझं शुबहा है कि मंत्री महोदय के कुछ विशेष कारण है जिनसे वह चाहेगे कि वह स्वीकार न किया जाय। में नहीं जानता कि ये कारण क्या है। हो सकता है कि उनको बात वजनी हो तो भी में कहूंगा कि वे कारण इतने वजनी कभी नहीं हो सकते जितना भार मंत्री महोदय ने लिया है कि पंचायत राज को जनता का एक इंस्टोट्यूशन बनाये न कि सरकार द्वारा जनता के बीच एक इंस्टीट्यूशन रखा गया हो जिसको जनता चाहे माने या न माने जनता को मानना ही पड़ेगा।

*श्री सुरेश प्रकाश सिह—-ग्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राज्ञा से भवन के सामने उपस्थित संशोधन के समर्थ न में तुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि सरकार द्वारा बैठायी गयी कमेटी जिसमें रिपोर्ट इस श्रमेडिंग बिल पर दी थी उसमें में हं श्रीर करीब साल भर से नैनीताल से में इस सेलेक्शन श्रीर एलेक्शन के चक्कर में था श्रीर मुझे कोई सल्युशन न मिल रहा था। पंचायत राज के श्रालोचक जितने थे उनका यह कहना था कि जुडीशियरी एलेक्टेड नहीं होनी चाहिए श्रौर श्रगर कोई चीज पंचायत राज्य में एलेक्टेट न हो ग्रीर हर चोज एप्वाइंटेड हो तो वह पंचायत राज्य की जान निकाल देता था, पंचायतराज नुख रह नहीं जाता था भ्रौर इसी चक्कर में हम लोग पड़े हुए थे भ्रौर साल्युशन निकालना चाहते ये। सरकार ने उन ग्रालोचकों के प्वाइन्ट्स को कुछ मीट करना चाहा ग्रौर एक प्रकार का कम्प्रोमाइज सामने रक्खा गया कि यह सेलेक्शन ग्रौर एलेक्शन दोनों इसमे हो ग्रौर यह किया गया कि ३५ ग्रादमी या ४० ग्रादमी जितनों की गांव पंचायत मे ग्रावश्यकता हो उनसे ५ ग्रादनो ग्राधिक चुने जायं ग्रौर उसके प्रेस्काइब्ड एथारिटी यानी डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट उनका एप्याइन्टमेंट करे । मुझे खेद है श्रीमन्, कि उस समय जबकि यह लिखा हुआ था कि प्रेस्काइब्ड एयारिटो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगी ग्रौर वह ३५ ग्रादिमयों मे से ५ को एप्वाइन्ट करेगा, उस वक्त हमारे सामने एक स्पष्ट चीज थी। हो सकता था कि भवन इसकी पसन्द न करता कि डिस्ट्रिस्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिक।र क्यों दिया गया परन्तु एक स्पष्ट चीज हमारे सामने थी । अब श्रोमन् दूतरे रूप में यह विधेयक हमारे सामने आया है जिसमें एक स्पष्ट चीज को निकाल कर एक अस्पष्ट चीज को सामने लाया गया है कि प्रेस्काइब्ड एथारिटी उनको एप्वाइन्ट करेगी ।

श्रीमन्, मुझे ग्रापत्ति यह है कि मै यह नहीं समझ सका कि ग्राखिर प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी ग्राखिर कौन होगी, कहां से ग्रायेगी ग्रीर वह कौन सी चिड़िया है ग्रीर वह किस श्रासमान से ग्रायेगी। या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो प्रेस्काइब्ड एयारिटी या एस०डी०ग्रो० हो,

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तहसीलदार हो और ईश्वर न करे कि कहीं थानेदार साहब हो जायं। तो मेरी समझ में नहीं म्राता कि कोई भो इनमें से प्रेस्काइब्ड एयारिटी हो उसको इस बात की कैसे जानकारी हो सकती है कि इस गांव के सुरेश प्रकाश सिंह किस तरह के म्रादमी है। यह बात उनको कैसे मालूम हो सकतो है? इसके लिये म्रात्वायं हो जाता है श्रीमन्, कि किसी से वह सलाह—मिवरा करें। ग्रार किसी एम० एल० ए० से सलाह—मिवरा करते हैं तो यह उचित नहीं मालूम होता है, ग्रार ग्रान दोस्तों से सलाह—मिश्वरा करते हैं तो वह भी उचित नहीं मालूम होता इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि एस०डी०ग्रो० साहब तहसीलदार साहब से रिपोर्ट मांगें ग्रीर फिर तहसीलदार साहब थानेदार साहब से रिपोर्ट मांगें कि इन ३५ ग्रादिमयों में कौन से ५ ग्रादमों भले हैं।

अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी बात श्रीर भी श्रनुचित हो सकती है। वह यह है कि हम लोग परेशान किये जाते हे कि साहब चिलये आप सिफारिश कर दीजिये चलकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब से बर्ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब क्या जानेगे कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। उनको क्या मालूम कि कहां की कैसी परिस्थितियां है। इसलिये श्रीमन्, श्रगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रक्ला जाता है तो फिर प्रेस्काइब्ड एथारिटी कौन होगा?

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अच्छा यह होगा कि प्रेस्काइब्ड एथारिटी वहीं हो जो कि उस गांव का हो, जो उसी क्षेत्र का हो और जो तजुर्बे कार हो। जैसे अगर कोई बुड्ढा हो जाय तो वह तजुर्बेकार होगा और वह जानता होगा कि यहां ३५ आदिमयों में कौन किस तरह का व्यक्ति है। परन्तु श्रीमन्, यह सुझाव भी उतना हो अनवर्के बिल है जैसा कि अभी एक संशोधन के लिये कहा गया। क्योंकि किर उसमें कैसे छांटा जाता कि कौन सा बुड्ढा जानकार है। फिर उसमें उन्न की भी क्वालीफिकेशन रक्खी जाती कि ७० वर्ष का हो या ६० वर्ष का हो या ४५ वर्ष का हो मुमिकन था कि कहीं उस उस्न का बुड्ढा न मिलता यह भी उसमें एक दिक्कत पड़ती इसलिए श्रीमन्, यह भी उतना ही अनवर्के बिल है जितने कि यहां पर और भी कई संशोधन आ चुके हैं।

मुझे खुशी है श्रीमन्, और में समझता हूं कि इस भवन को कृतज्ञ होना चाहिये श्री बालेन्द्रशाह जो का कि उन्होंने एक ऐसा साल्युशन निकाला है जोकि उन आलोचकों के प्वाइन्ट्स को भी मीट करता है और सरकार के प्वाइंट को भी मीट करता है। यह एक किस्म से कम्प्रोमाइजिंग फारमुला रक्खा गया है जिसमें सेलेक्शन भी है, एलेक्शन भी है। यानी डाइरेक्ट एलेक्शन हो करके इनडाइरेक्ट एलेक्शन है श्रौर उसके बाद फिर प्रेस्काइब्ड एथा-रिटी के द्वारा सेलेक्शन भी हो जाता है। उन्होंने यह कहा कि गांव सभा द्वारा चुने हुए गांव पंचायत के लोग अपने में से न्याय पंचायत के लिए प्र आदिमियों को चुन लेंगे और उनका कन्फरमेशन प्रेस्काइडड एथारिटी करेगी। तो जब ५ ग्रादमी चुन लिये जायेंगे वह कन्फरमेशन के लिए प्रेस्काइब्ड एथारिटो के पास जायेगे उस वक्त प्रेस्काइब्ड एथारिटी के लिए ब्रासान हो जायगा कि वह पता लगा लें कि यह ५ ग्रादमी जो चुने हुए हं ३५ ग्रादमियों में से वह किस तरह के हैं। वैसे ३५ ब्रादिमयों में से ५ ब्रादिमयों को चुनने से सारी जिम्मेदारी सरकार पर ब्रा जायगी ग्रीर ग्रगर कहीं काम खराब हुग्रा तो जनता कहेगी कि हम क्या करें, इनको सरकार ने हमारे ऊपर लादा था। सरकार द्वारा यह जो लादे गये पंच है हमारे अपर ग्रन्याय कर रहे है। तो क्यों न ऐसा किया जाय कि इन लोगों को चुनने का भार गांव वालों पर छोड़ दें कि जिसको वे पसन्द कर चून लें। ५,७ साल हो गये पिछले चुनाव को लोग देख चुके है कि उन्होंने जो गलितयां की कितनी तकलीफ हुयी। लोग जान चुके हैं कि अगर उन्हीं गलत आदिमयों की चुना गया तो नुकसान होगा और फिर ऐसा करें तो कम से कम और हम सरकार के साथी जो हं वह यह कहेंगे कि एक अमल का मौक मिला तुमने गलत आदमी को चुना। फिर मौका दे दिया फिर गलत आदमी को चुना तो सरकार क्या करे। तो श्रीमन्, अगर प्रेस्काइडड अवारिटी ५ आदिमयों को चुनती

है और मुझे ग्राशंका है कि ग्रवश्य यह बात होगी कि पांच ग्राहमी ग्रनुचित ले लिये जायेगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए ३५ ग्राहमियों के ब्लाक में से हर एक की जानकारी रखना कित है। तो बड़ो भारी रेस्पासिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की है और फिर गांव वाले कहने लग जायेंगे कि सरकार ने हमारे ऊपर ५ ग्राहमियों को लाद दिया है जो ग्रन्याय करते हैं ग्रात्याचार करते हैं। तो श्रोमन, जो मुझाव इस समय इस संशोधन द्वारा लाया गया है उसमें तो यह है कि ३५ का चुनाव गांव वाले करेगे। फिर यह ३५ बैठकर ५ ग्राहमियों को चुन लेंगे ग्रीर इन ५ का कनफरमेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट....

श्री श्रध्यक्ष--यह ३५ में से ५ तो नहीं होंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—इन्हीं में से होंगे।

श्री ग्रध्यक्ष--गांव सभा चुनेगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—-गांव सभा चुनेगी ३० या ३५ को श्रीर वही श्रपने में से ५ को चुन ले।

श्री ग्रध्यक्ष--यह नहीं है। मेरे पास जो मंशोधन है उसमे यह है कि--

"the members prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha from amongst themselves"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--ग्रध्यक्ष महोदय, यदि ग्राज्ञा हो तो स्पष्ट कर दूं। जो संशोधन दिया था उसको थोड़े में परिवर्तित करके पेश किया था।

श्री ग्रध्यक्ष--उसका करेक्ट फार्म मेरे पास भेज दीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो श्रीमन्, इस संशोधन का सुझाव यह है कि ३०,३४ सदस्य चुने जायेंगे गांव सभा द्वारा श्रीर वे श्रपने में से ४ को चुन लें ग्राम पंचायत के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटो। जिम्नेदारी फिर गांव दालों पर है। ठीक इसी प्रकार धमकी से या नाजायज दबाव से इन ४ में कोई श्रनुचित व्यक्ति तो नहीं श्राया है इसकी छटनी इस संशोधन में रखी गयी है। श्रीमन्, में श्रापके द्वारा निवेदन करूंगा सरकार से....

श्री ग्रध्यक्ष — में यह जानना चाहूंगा कि उसमें ग्रौर श्री विष्णुदयाल वर्मा के संशोधन में क्या फर्क रहा। उसमें भी तो यह था कि 'elected members have elected' ग्रौर 'co-opted' वर्ड नहीं था। इलेक्टेड मेम्बर्स ने ५ को चुना क्या यही उसमें था?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---उसमें कोग्राप्शन था।

श्री ग्रध्यक्ष--कोम्राप्तान उसमे नही था ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उनके श्रमेडमेट मे जो ४ है वही हो जाते पंचायत के मेम्बर ग्रीर इसमे जब तक कि कनफर्नेशन बाई प्रेस्काइब्ड ग्रथ।रिटी न हो तब तक वे पांच भी नहीं हो सकते।

श्री ग्रध्यक्ष नयह भी है इसमे ? ठीक है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो इसलिये श्रीमन्, में निवेदन कर रहा था ग्रापके द्वारा सरकार के सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठ जाती है। जिम्मेदारी फिर उन्हीं गांव वालों पर पड़ती है जो कि ग्रसलियत में पड़नी चाहिये थी ग्रौर हमारे पास चेक भी है कि कोई अनुचित व्यक्ति न ग्राजाय ग्रौर वह यह है कि प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी द्वासायह ५ व्यक्ति कनफर्म [श्री सुरेश प्रकाश सिंह]
किये जायं। इसिलए श्रीमन्, मं समझता हूं कि सरकार को यह एक बहुत ग्रच्छा
साल्यूशन मिला है जो काम्श्रोमाइज भी चाहता है ग्रीर जितनी उलझने ग्रीर जितने झंझट
इस प्रश्न पर उनके सामने थे उनको देखते हुए में ग्राशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को
मान लेगी जोकि माननीय बालेन्दुशाह जी ने पेश किया है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मानतीय श्रध्यक्ष महोदय, मैने बड़े ध्यान से माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन को देखा श्रीर मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संशोधन उन लम्बे प्रयत्नों की एक सीढ़ी है जो जिस मंशा से पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है, उसकी संबोटाज करना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं। दरअसल में अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय श्रदालत का सम्बन्ध है आज प्रातः काल से इन दो सिद्धांतों में टक्कर हो रही है। कुछ लोग यह कहा करते हैं कि पंचायत श्रदालतों को एक चुनाव का श्रखाड़ा बना करके, उनको मखौल बना करके श्रन्ततोगत्वा खत्म कर देने की बात है। कुछ लोगों का यह ख्याल है, और वह सौभाग्य से जो इधर बैठते हैं उनका है कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसे जहां तक सम्भव हो सके चुनाव के श्रखाड़े से दूर रखा जाय और माननीय बालेन्दु शाह जी के इस संशोधन से तो चुनाव काएक दूनरा श्रखाड़ा भी खुलता है कि जो गांव सभा के चुने हुए सदस्य हों वे फिर श्रापस में बैठ कर सदस्यों का चुनाव करें। यानी एक चुनाव तो यह हो कि गांव सभा के सदस्य चुने जायं श्रीर उनके साथ-साथ उसमे कुछ संख्या न्याय पंचायती श्रदालत के सदस्यों की भी हो श्रीर दूसरा श्रखाड़ा यह हो कि वे वैठ कर जो संख्या न्याय पंचायत श्रदालत की हो उसकी चुनें।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--में माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि एक दूसरा ग्रखाड़ा पहले ही उप-प्रधान के चुनाव में बनाया जा चुका है?

श्री रामनरेश शुक्ल--ग्रध्यक्ष महोदय, में इसके पहले भी कुछ कह सकता कि में पहले ग्रलाड़े को भी पसन्द नहीं करता, लेकिन यह कि दूसरा ग्रलाड़ा भी खोल दिया जाय पहले म्रलाड़े के कारण यह कहां तक उचित होगा यह प्रश्न इस समय विचारणीय है और इसलिये विचारणीय है कि ग्रगर जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मर्तबा अपनी राय दी थी कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसमें चुनाव का होना बहुत ठीक नहीं होता, तो मौजूदा सरकार ने अपनी हाइयस्ट जुडिशियरी की राय को भ्रौर जनता की भावनाओं का, दोनों का समन्वय किया है। ग्रौर फिर ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर सिद्धांत के प्रश्न को म्रालग रख दिया जाय तो माननीय सुरेश प्रकाश जी का यह तर्क मेरी समझ में कम से कम नहीं ग्राता है कि यदि न्याय ग्रदालतों में कोई बुराई होगी तो हम गांव में जाकर यह कह सकेंगे कि इसमें हमारा क्या दोष है, यह तो तुमने ही चुना है और तुम्हीं इसके जिम्मेदार हो। ग्रध्यक्ष महोदय, प्रश्न ग्राज यह सामने नहीं है ग्रौर न किसी कानून बनाने वाली संस्था के सामने होना चाहिये कि जिम्मेदारी किसके कंथों पर डाली जाय, बिल्क प्रश्न यह होना चाहिये कि क़ानून ऐसा बने कि जिससे समाज के ज्यादा से ज्यादा ग्रादमियों को लाभ हो श्रौर ज्यादा से ज्यादा श्रादमियों को संतोष हो। तो यह तर्क जो माननीय सुरेश प्रकाश जी ने दिया ह यह सम्भव है कि उन्हें अपने क्षेत्र की बात याद आती होगी कि हर एक को प्रसम्भ करने को कोशिश की जाय चाहे वह सही हो या ग्रलत हो और अपने को यह साबित करने का प्रयत्न किया जाय कि मैंने तो ठीक ही किया, जो कुछ गलत किया वह सरकार ने किया और अगर सरकार पर भी वह दोष नहीं साबित कर सके तो फिर यह कहा जाय कि भगवान ने किया। तो यह तर्क कम से कम कानून बनाने वाले सज्जनों को नहीं करना चाहिये।

^{*}बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

एक हमारे लिये रास्ता खुल जायगा श्रौर न्याय श्रदालतों में गड़बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि तुम्हीं ने तो उनको चुना है। श्रव फिर से उनको चुनों। श्रध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थित यह है कि तजुबें से यह ज्ञात हुश्रा, श्रनुभव से यह पता चला कि जहां पर चुनाव हुये पंचायती श्रदालतों के वहां पर उस हद्द तक लाभ नहीं हो पाया जिस हद्द तक कि सरकार की मंशा थी। इस श्रनुभव के श्राधार पर श्रौर जो श्रपनी जुडीशियरी के बड़े-बड़े विद्वान् है उनकी राय जानकर यह निश्चय किया गया कि किसी तरह से चुनाव श्रौर न्याय दोनों का समन्वय किया जाय तो श्रच्छा हो।

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी राय में विरोधी दल के उस तरफ बैठने वालों ने इस मनोभावना को पहचानने की कोशिश नहीं की है और कहीं इशारा यह होता है कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी का पता कैसे चलेगा, कैसे नामजदगी की जायगी, कैसे पता चलेगा कि कौन ग्रच्छा है ग्रौर कौन बुरा है ग्रौर यहां तक कि यह ग्रंदाजा लगाना ग्रौर सब से ज्यादा जो फोबिया या भूत सवार है वह यह है कि एम० एल० ए० महोदय से राय ली जायगी। ग्रगर वह सही राय देते है तो इसमें क्या बुराई है ग्रौर वह भी राय उसी जगह पर देंगे जहां देना उचित होगा। एम० एल० एज०, जहां तक इस तरफ के बैठने वाले हैं वह ग्रपनी ग्रादत को जानते हैं। दूसरी तरफ के एम० एल० एज० यदि राय नहीं दे पाते हैं तो शिकायतन राय जरूर दे देते हैं। राय देने ग्रौर शिकायतन राय देने में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता है। किसी चीज को करने के लिये शिकायतन या प्रदर्शन करके करवाना, यह भी राय देने का एक रास्ता है, जहां तक मंने समझा है। यही बात उस तरफ लगाई जाती है जिसका कोई सबूत ग्रौर प्रमाण विरोधी दल नहीं दे सका है सिवाय इसके कि यहां या बाहर कह दिया। लेकिन इस बात का सबूत उनके कार्यों ग्रौर भाषणों से सदैव मिलता है कि उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है शिकायत के ग्राधार पर।

में, श्री सुरेश प्रकाश जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि उन्हें सरकार की तारीफ करना चाहिये भ्रौर इस सरकार को चलाने वाली पार्टी की तारीफ करनी चाहिये, जिसमे हिम्मत है कि वह जिम्मेदारी भ्रपने कंधों पर लेना चाहती है। नामजदगी हम करना चाहते है, इसलिये नहीं कि ब्राप सोचें कि कोई मतलब निकालना चाहते है । जैसा कि कहा गया है कि नामजदगी इसलिये करना चाहते हैं कि इन न्याय पंचायतों में जिनमें चुने हुये लोग श्राये हैं, उनसे उस हद्द तक लाभ नहीं हो सका है जिस हद्द तक कि होना चाहिये था। यह सही है कि इन पंचायती ग्रदा-लतों में चुनाव के कारण दलबन्दी हुई श्रीर उसके कारण हारी हुई पार्टी की जीती हुई पार्टी ने न्याय नहीं दिया। ऐसी सूचना सरकार के पास आयी है। इसलिये जरूरी था कि कोई न कोई बंघन डाला जाय, कोई न कोई रुकावट डाली जाय। यह रुकावट सरकार ने डाली है। में यह कहने के लिये तैयार हूं कि यदि यह संशोधन जो माननीय बालेन्द्र शाह जी का है, मान लिया जाय या ग्रीर भी संशोधन जो हो चुके है या ग्रागे ग्रायेंगे, उनको मान लिया जाय तो जिस मंशा से संशोधन किया जा रहा है उसका प्रमाण ही निकल जायगा। यह हवा फैलाना ग्रौर इस प्रकार से ब्राच्यक्ष महोदय, काल्पनिक चीजों का चित्रण करना कि प्रेस्काइब्ड ग्रथ।रिटी कौन होगी श्रौर होगी तो डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट होगी। ग्रभी इसका कोई भी रूप नहीं दिया गया है लेकिन एक कल्पित लक्ष्य बना कर ऐसी बातें कही गईं है जिनका कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि मै इतना ही कहूंगा कि हमारे विरोधी दल के कुछ सदस्यों को फोबिया हो गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से और वह सही है ग्रध्यक्ष महोदय, उनका फोबिया जो है उसकी वजह से वह हर जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की शिकायत करते हैं, वह उनके हित में जाता है क्योंकि ग्राज शासन की जो सब से छोटी इकाई है प्रान्त की, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ग्रारम्भ होती है श्रीर जो शासन को हिलाना या गिराना चाहते हैं, उन्हें जरूरत इस बात की होती है छोटी सी छोटी इकाई से ले कर बड़ी से बड़ी इकाई पर हमला करें। लेकिन जो इस शासन को चलाना चाहते है, समाज की सहायता करना चाहते हैं, उसे ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस चीज को जानते हुये भी, समझते हुये भी....

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—प्वाइंट श्राफ श्रार्डर, सर । श्रीमन्, मै श्राप की इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि भाषण में जिस चीज का जिक्र भी न किया गया हो उस चीज को श्रपने से समझ कर उसका जवाब देना क्या ठीक है किसी माननीय सदस्य के लिये?

श्री ग्रध्यक्ष—यह तो ग्राप बहुत गोल बात कह रहे हैं। मैं इसमें क्या व्यवस्था दूं? जरा साफ़ कीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये न तो मैने श्रौर न बालेन्दु शाह जी ने कुछ कहा है । तो उसको मान करके कि कहा होगा या कहा है या उसको ऐसा समझ कर, यह जो कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फोबिया या श्रौर क्या-क्या माननीय सदस्य ने कहा, यह क्या उचित है ?

श्री ग्रध्यक्ष—नहीं-नहीं। इसका तो ग्राप ने जिन्न किया है कि पहले यह बात तय हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेसस्नाइड्ड ग्रथारिटी होगा। कई दफा ग्राप के भाषण में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिन्न ग्राया था।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप ने बड़ी कृपा कर के यह व्यवस्था दी ग्रीर में ग्राप से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सुरेश प्रकाश जी तो इस हद तक गये है कि जो ग्रमेंडमेट हो गये है उन भाषणों का भी जिन्न किया है। ग्रगर वह चाहेगे तो उन्हीं के भाषण को ले कर में दिखा दूंगा।

तो में, अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि यह कम्प्लीकेशन पैदा करना है ग्रौर जटिलता लाना है। जहां तक पंचायतों की व्यवस्था का सवाल है, ग्रध्यक्ष महोदय, मैने ऐसा समझा है कि उसमें बड़ी सरलता श्रौर सिशाई होनी चाहिये। जटिलता उसमें नहीं म्रानी चाहिये, गुर्त्थियां नहीं डालनी चाहिये। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह एक गुत्थी और एक गांठ और डालता है कि एक चुनाव हो, दो चुनाव हो और फिर उसके बाद प्रेंस्काइब्ड प्रथारिटी चल कर उस पर प्रपनी मोहर लगावे। जब प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी को मोहर लगाना ही है भ्रौर जब उसमे कोई बन्धन नहीं लगाया जा रहा है कि कितने भ्रादिमयों को वह निकाल सकता है तो प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी चाहे तो सब को निकाल सकती है। उनके संशो-घन से जहां तक मैं समझता हूं ग्रगर वह मान भी लिया जाय तो उससे क्या फायदा होगा। बात को ग्रंगर मान लिया जाय कि किसी एक ढंग से शासन चलाने का कोई प्रयत्न करेगा तो जो कोई भी चुना हुया होगा, पांच के पांचों जो चुने हुये होंगे उनको वह प्रेस्काइ इंड प्रथारिटी निकाल सकती है । तो फिर यह समय क्यों वर्बाद किया जाय। इतना समय नष्ट किया जाय द्यौर किर साथ-साथ वह प्रेस्काइब्ड द्रथारिटी भी ग्रपनी जगह पर रहे, श्रपनी पूरी ताक़त के साथ, इससे क्या फायदा होगा। इस तर्क को तो मैं मान सकता हूं कि प्रेस्काइ इ अथारिटी को हटा दिया जाय श्रौर चुनाव रक्खा जाय, यह बात तो समझ में श्राती है लेकिन यह क्या बीच मे कि ऐसा न हो तो ऐसा किया जाय, दस-बीस चीजों को मिला कर के एक प्रेस्क्राइब्ड ग्रथारिटी बने, यह एक हा व-पाच की सी चीज है और कुछ समझ में नहीं म्राती। शायद उस म्रार्गमेंट से कुछ मतलब समझ में ब्राता है जो कभी-कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि प्रेस्काइब्ड प्रथा-रिटी नहीं रहनी चाहिये। ठीक है, उनका एक तर्क है, उनका एक निशाना है, एक रास्ता है, जो चीज वह चाहते हैं वह समझ में भ्राती है। यह दूसरी बात है कि वह ग्रेलत है या सही लेकिन वह अपनी चीज रखते है और वह समझ में आती है परन्तु यह क्या है, यह कौन सा मुख्बा बन रहा है, क्या चीज है, जैसे सब दलों को मिला कर एक संयुक्त दल बन गया, २५ रास्तों को ले कर एक रास्ता बन गया है....

श्री श्रध्यक्ष—में माननीय सदस्य से कहूंगा कि पार्टियों के संबंध में बार-बार जिन्न लाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मैंने टोका नहीं कई मतंबा इशारतन श्राप ने दूसरों पर मोटिव भी एस्काइब किया है कि यह नियत होगी। श्रव उनकी तरफ से नियत तो स्पष्ट मालूम नहीं होती है श्रौर श्राप नियत को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह उचित नहीं है क्योंकि इससे भाषण में गर्मी पैदा हो जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कुछ इशारा किया गया था इसिलये मंने भी थोड़ा सा इशारा किया है, ज्यादा नहीं। में इसको यहीं छोड़ देता हूं और केवल इतना कहंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है और यह एक कम्प्लीकेशन पैदा करता है। एक प्रयत्न जो इस तरफ से हो रहा है कि न्याय को ज्यादातर जितना सम्भव हो सके चुनाव से म्रलग रक्ला जाय क्योंकि हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध म्रधिकार है कि वह न्याय पा सके, उस प्रयत्न में यह एक उलझन पैदा करता है। यदि चुनाव के कारण गड़बड़ी हो जाती है तो उसको ग्रलग करना चाहिये । जहां तक नामजदगी का प्रक्न है अगर नामजदगी भ्रच्छी चीज नहीं है लिहाजा उसकी हटा देना चाहिये भ्रौर चुनाव किसी हद तक श्राना में ग्राप के द्वारा, ग्रध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रगर इस तर्क का विस्तार ज्यादा दूर तक ग्रौर पूरे तौर पर किया जाय तो कभी यह भी कहा जा सकता है कि मुंसिफ का मेलेक्शन नहीं होना चाहिये, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये भीर जुडीशियरी का प्रत्येक व्यक्ति चुना हुआ होना चाहिए क्योंकि कोई न कोई पार्टी सरकार में रहेगी ग्रौर कुछ न कुछ हाथ उन लोगों की नियुक्ति में सरकार का रहता ह है। तो ग्रगर यह तर्क सिद्धांततः मान लिया जाय कि नामजदगी बिल्कुल ग़लत चीज है, चुनाव ही एक चीज है, जो लिया जाय न्याय के सम्बन्ध में, तो यह तर्क भी, विस्तार करने पर ग्रा जायगा। इससे बड़ी भयंकर परिस्थित उत्पन्न हो सकती है। मै ग्राप के द्वारा ग्रन्त में यह प्रार्थना करूंगा कि न्याय को एक दम चुनाव से अलग रखा जाय। श्रीर में तो माननीय मंत्री जी से श्राप के द्वारा यह कहंगा कि ब्रगर बीच में यह भी मालूम हो कि यह जो श्रवाड़ा एक चुनाव का हो गया उसमें भी गड़बड़ी हो रही है तो उसमें भी संशोधन लाया जाय और उसको भी समाप्त कर दिया जाय क्योंकि न्याय मिले इस समाज को, यह समाज की मांग है। में समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा समाज को न्याय मिलने वाला नहीं है।

श्री श्रब्दुल मुईज खां--मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रब प्रश्न उपस्थित किया जाय। कई सदस्य-श्रभी इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते है।

श्री ग्रध्यक्ष—श्रौर लोग भी बोलना चाहते है तो दो एक भाषणों के बाद यह प्रश्न लिया जायेगा।

गेंदा सिह--माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मै माननीय बालेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं, ऋौर मजबूरी मेरी यह है कि यदि हम समर्थन न करें तो माननीय राम नरेश जी ने जो पहले से इसके लिये नक्शा बना रखा है जिसमे प्रेस्क्राइब्ड श्रथारिटी के ऊपर कोई भेद नहीं है यह बहुत खराब बात है। क्योंकि अगर माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी के संशोधन को माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने स्वीकार करने की मेहरबानी की होती या माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार करने की माननीय राम नरेश जी ने मेहरबानी की होती तो में समझता हूं कि माननीय बालेन्द्रुशाह जी को इस संशोधन को पेश करने की ग्रावश्यकता ही नहीं होती। लेकिन चूंकि उन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने की उन्होंने कृपा नहीं की इसलिये माननीय बालेन्दु शाह जी के संशोधन को लाने की श्रावश्यकता पड़ी । में समझता हूं कि माननीय विष्णुदयाल जी का संशोधन और माननीय मदनमोहन जी का संशोधन जब श्राया तो उस समय चाहे माननीय राम नरेश जी खामीश रहे हों लेकिन यह उनकी इच्छा थी कि वह दोनों संशोधन खराब हैं । वह दोनों संशोधन उनके उद्देश्य से विपरीत जाते है । इसलिये दोनो भ्रस्वीकार कर दिये जायं। ग्रौर जब वह ग्रस्वीकृत हो गये तो यह जो हल्के दरजे का चेक लगता है प्रेस्काइब्ड ग्रथा-रिटो पर उसको वह ड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कह रहे हैं कि जो संशोधन हम लोग रखते है कि चुनाव द्वारा ही न्याय पंचायतों का निर्माण हो उसे तो वह कहते हैं कि वह बात कुछ समझ में भ्राने वाली है। लेकिन माननीय बालेन्द्रशाह जी की बात समझ में ग्राने वाली नहीं है। माननीय राम नरेश जी ने यह भी कहा कि हमारी बात सही है या गलत उस पर वह राय नहीं देना चाहते। तो सीधी ्श्री गेडा सिह्

बात यह है कि न्याय पंचायतों का चुनाव किया जाय इसको तो वह नलत कहेगे ही लेकिन उसमें हल्के दरजे की बात जो मानतीय दालेन्दुशाह जी ने पेश की है उसको भी कह दिया कि यह भी रालत हैं। इसियों ग्रव म मानतीय दालेन्दुशाह जी के इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। म जानता हूं कि कोई चेळ नहीं चाहते मानतीय राम नरेश जी इस न्याय पंचायत के बनाने वालों के ऊपर, उनको दड़ा मोह है डिस्ट्रिक्ट मिजिस्ट्रेटों पर । उनके बारे में मुझे ग्रधिक कहने की जहरत नहीं माल्म होती है लेकिन प्रेस्त्राइव्ड ग्रथारिटी में कुछ चर्चा उनकी हो। गयी है ग्रोर ग्रस्ता तक उम तरह में इस दान का कोई जिल नहीं हुन्ना कि प्रेस्त्राइव्ड ग्रथारिटी में जिलाधीश महोदयों का क्या स्थान होगा? वह होगे या नहीं? मुख ऐसा में समझता हूं कि मौन हो जाना भी

ना माफ बात कह दा कि बस सब न अण्या क्यार आ न्हार १००० वर्ग साम उत्तर उम छाटा इकाई, जिलाधील महोदय ह जिल पर, उन्होंने भरोमा नहीं किया तो वह शामन उत्तर जायना । इमिलये प्राननीय राम नरेश जी का जो ग्रनुभव है ५-६ वर्ष का, उस में उन्होंने यह समझा है ि ग्रव में बढ़िया इलाज यह है कि इस न्याय के ऊपर हमला करो।

जो हमारा संविधान है, वह कह रहा है कि न्याय को ज्यादा से ज्यादा एग्जिक्यूटिव ने ग्रलग करो. बल्कि सोलहों स्नाना स्नलग कर देने को उसमें कहा गया है हम देख रहे हैं कि उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है । उसमें उत्टा चलने की बान माननीय रामनरेश जी सीच रहे ह कि बजाय इसके कि न्याय विभाग को शासन से ग्रलग किया जाय वह यह फैसला करना चाहते हैं कि न्याय के ऊपर पूरा क़ब्जा कर लेना चाहि । वह कहने हे कि चुनी हुई न्याय की शाखाएं हों यह बड़ी खराब बात है। में उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं श्रौर जानना चाहता हूं कि कौन सी न्याय की शाला ऐसी है कि जो चुनी हुई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है? माननी सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति कीन करता है? कोई ग्रासमान से नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपनि महोदय करते ह । श्रीर राष्ट्रपित महोदय को मालूम होता है हम नहीं चुनते, कोई खुदा मियां उनका चुनाव करते ह या श्रदृष्य शक्ति करती है। तो हम जब करते हैं तो हम भी चुने हुए है ग्रौर हमारे द्वारा नियुितयां जो उनकी होती हे तो उनके द्वारा जो नियुक्तियां हुई जजों की तो म समझना हूं कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मने निवेदन किया चुने हुये लोगों ने ही की ग्रौर इसी प्रकार में हाई कोर्ट के जजों की ग्रौर दूसर जजों की नियुक्तियां भी चुने हुये लोगों के द्वारा होती है । जिसको माननीय राम नरेश जी इकाई कह रहे है जिला की, तो मै कहता हूं कि गांव की दब पहली मीड़ी पंचायत होती है। ग्रगर वह भी चुनी हुई हो तो ग्रौर भी ग्रच्छा है। ग्रगर चुनी हुई न हो, तो क्या हो । अगर न्याय विभाग का कोई अधिकारी उस न्याय पंचायत के चुनने में हाथ डाले तो जिम तरह में कुछ लोग लाल कपड़ा देख कर भड़कते है उसी तरह से माननीय राम-नरेश जी भड़कते हे. कि न हीं, कभी नहीं, न्याय विभाग वालों को इस न्याय पंचायत से छुब्राछ्त नहीं होनी चाहिये। अगर नहीं होनी चाहिये तो मं साफ तौर से इस बात को कहना चाहता है कि मरकार चाहती है कि जो उनकी न्याय पंचायतों में एक म्राना, दो म्राना इंडिपेडेस बाक़ी रहे गयी है वह भी न रह जाय। में जानता हूं कि सरकार को उसमें कुछ लुक्क भी आता ही है। वह ना मजा लेना चाहनी है इसमें । सरकार कभी इसको नहीं चाहती कि शासन स्रौर न्याय में पृथ करण हो। महास में न्याय को शासन से अलग करने का फैसला मद्रास सरकार ने ले निया उम जमाने में जिस जमाने में मद्रास में स्राग लगी हुई थी ।

श्री ग्रध्यक्ष——ग्राप कुछ ग्रसंगत से हो रहे हैं। जरा संशोधन पर ग्रा जाइये। श्री गेदा सिह——ग्रध्यक्ष महोदय, में तो बिल्कुल संशोधन पर ही ग्रपनी बाते कहना चाहता हूं ग्रीर ग्रापकी ग्राजा पालन कहंगा लेकिन माननीय राम नरेश जी की बिदमत में जरा यह बात ग्रजं कर देना चाहता था..... श्री ग्रध्यक्ष--ग्राप ने विषयान्तर यह कर दिया कि न्याय स शासन को ग्रलग करने के नियं ग्राप ने महास का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया तो यह बहुत ब ़ी दास्तान हो जायगी। न्याय से जो कुछ संबंधित बाते हों वह ग्राप कहें लेकिन महास का जो ग्राप किस्सा सुना रहे हैं वह जरा विषयान्तर हो रहा है।

श्री गेदा सिह--ग्रध्यक्ष महोदय, मै मद्रास का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर बाहता हं कि जिस वक्त न्याय पंचायतों के प्र-न पर विचार किया जाय कि उनका क्या ढांचा हो हमारी सरकार को जरा उस पर गौर करना चाहिये। मै फिर यही कहुंगा कि इस न्याय को हम पहली सीढ़ी बना रहे है। इसमे जितनी भी स्वतंत्रता हो सके न्याय करेने की उसके लिये हमें विधेयक में गुंजायश रखनी चाहिये। हम देखते है कि जो भी प्रेस्क्राइःड ग्रथारिटी बनेगी उम संबंध में ग्रब तक माननीय स्वशासन मंत्री या किसी माननीय सदस्य की ग्रोर से यह बात नहीं कही गई कि इसमें न्याय विभाग वालों का भी हाथ होगा। अगर न्याय विभाग वालों का हाथ नहीं होता है तो इसके स्पध्ट अर्थ यह होंगे शासन के चंगुल मे पूरे तौर से न्याय पंचायतों को दें देना। शासन की जो मुसीबत है, उस मुसीबत को कहने की बात बहुत मर्तबा स्राती ह स्रौर जिस तरह से हम अ। पको परेशान करते है अपनी तकलीफे सुना कर वह केवल शासन की वजह से ग्राप को सुनाने की जरूरत पड़ती है। तो फिर उस शासन के हाथ में पूरे तौर से साढ़े ग्राठ हजार जो न्याय पंचायते बनेगी उनको दे देना यह कभी वर्दाक्त करने की बात नही है। सरकार ताकत में है। सरकार जिस तरह से अपने को महफूज समझेगी या अपने दिल की बात सोच कर महफूज करना सोचेगी करेगी और उसके लिये जिस तरह से नक्शा बनायेगी वह ठीक है और उसके लिये गांव सभाश्रों को वह जिस तरह से अपने साथ ले जाने की कोशिश करे वह मुनासिब हो सकता है और उसके लिये वह कोशिश कर सकती है लेकिन न्याय के नाम पर और संविधान के नाम पर और अपने पुराने प्रस्तावों के नाम पर अगर इन न्याय पंचायतों को शासन के चंगुल में न दिया जाय तो यही उचित है।

यह माननीय बालेन्द्रशाह जी का जो प्रस्ताव है वह पूरे तौर से शासन के चंगुल से न्याय पंचायतों को नहीं छु, ड़ाता, थोड़ा सा चेक करता है श्रौर उस थोड़े से चेक को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मजबूरी होगी इस असंतीधन को स्वीकार कर देने के बाद यह ग्राप के सामने कहना पड़ेगा कि यह पूरी धारा ही निकाल दी जाय। क्योंकि इस धारा के रखने से में समझता हूं कि पंचायतों की प्रतिष्ठा में कमी हो हो। में इस बात को मानता हूं कि पचायतों मे प्रतिष्ठा के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी रहा है और उसके सुधारने की जरूरत है लेकिन यह जो तरीका श्रपनाया जा रहा है यह उन पंचायतों को बजाय सुधारने के ग्रौर भ्रष्ट करूंगा। म इस लम्बन्ध में माननी । स्वशासन मंत्री ,से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यह हमारे लिये नहीं बल्कि जैसा कि मैने कहा कि सविधान के नाम पर, त्याय के नाम पर श्रौर समाज के नाम पर भ्रागे के लिये लोग ऐसा सबक़ न सीखे कि भ्रगर हम यहां पर बैठ जायं ग्रीर यहां पर जिस मर्यादा का ध्यान हमको रखना चाहिये उसको भूल जायं तो वही कठिनाई हो जायेगी। इन सब चीजों पर ध्यान रख कर श्राप माननीय बालेन्द्रुशाह के संशोधन को स्वीकार कर ले। श्रनर ग्राप ने विष्णुदयाल जी के संशोधन को ग्रस्वीकार किया होता तो मुझे बालेन्द्रशाह जी के सशोधन का समर्थन करने की जरूरत नहीं पड़ती श्रीर वह संशोधन यहां पर श्राता भी नहीं, लेकिन जब पेट भर खाने को अच्छा नहीं मिलता है तो हम सत्तू ही खोने के लिये तैयार हे। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह हमारे सत्तू के समान है लेकिन फिर भी मजबूर हे कि उसको ही खाकर कुछ शान्ति प्राप्त कर ले।

श्री श्रब्दुल मुईज खां—श्रीमान् जी, में प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे साथी माननीय बालेन्दुशाह ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसके बारे में मुझे यह बात समझ में नहीं श्रायी कि इससे पहले जो संशोधन यह सदन श्रस्वीकार कर चुका है यानी यह कि एलेक्टेड मेम्बर के जिरये से न्याय पंचायत के वे ५ सदस्य चुने जायं। इस बात का सदन जब श्रस्वीकार कर चुका है तो उसके बचने के लिये श्राप का संशोधन श्राउट श्राफ श्रार्डर न हो जाय

[श्री ग्रब्दुल मुईज खां]

उमके बाद इस शब्दावली से प्रेस्काइ ड ग्रथारिटी में कंन्फर्म क 'ाने की बात कही गयी। यह एक बात कही गयी जिसकी वजह से वह भाउट म्राफ भ्रांडर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस मशोधन का समर्थन किया उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह मालूम हो सके कि वह इस पोर्शन के लिये जिस्टिफिकेशन हो सकता है। में उनकी बातों को समझने में ग्रसमर्थ रहा। मेरा ख्याल है कि जो बात इस संशोधन में रखी जा रही है बजाय इसके कि इस कानून में कोई ग्रासानी हो इससे ग्रोर ज्यादा ग्रइचन पैदा हो जायगी भौर वह यह है कि जब कोई पंचायत का सदस्य चुन कर ग्रायेगा उनके साथ कुछ ग्रौर सदस्य भी चुने जायंगे। वह ग्रापस में बैठ कर ५,४ या जितने भी सदस्य न्याय पंचायत के लिये चुने होंगे, चुनेगे। इस चुनाव को ग्रगर प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी ने मंजूर नहीं किया तो उस वक्त क्या तरीक़ा ग्रब्तियार किया जायगा। इसके लिये कोई बात इस संशोधन में नहीं रखी जा रही है। इससे जाहिर है कि ऐसी बहुत सी सूरते पैदा हो सकती है। यह जो पंचायत राज का तरीका है ग्रौर उसमें जो यह न्याय पंचायत के जिरये मुधार की बात रखी जा रही है उसके सुधार होने की गुंजाइश कम हो जायगी। इस-लिये में उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त ग्रपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करेगे।

श्री ग्रध्यक्ष-प्रश्न यह है कि ग्रब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुग्रा।)

ैमहाराजकुमार बालेन्दु शाह—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों से **ग्रौर** जिस जोश के साथ ग्राज माननीय रामनरेश जी ने इस सदन में भाषण दिया उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यदि प्रेस्काइ ड प्रथारिटी के हाथ से पंचों की नियुक्ति हटा दी जाय तो उससे सरकार को कोई विशेष ग्रापत्ति पहुंचेगी। मैंने तो ग्रपने भाषण में शुरू में यह कह दिया था कि हमको ग्रीर जो ग्राम जनता को, ग्रापत्ति पचों के चुनाव के संबंध में बतायी गयी उसका एक हल, भीर उस समस्या को हल करने के लिये एक तरीका मैने सामने रखा था। जहां तक रामनरेश जी ने मेरे कम्प्रोमाइज के फार्मूले को ऋिटिसाइज किया है ग्रौर उनके विचारों के ग्रनुसार एक कम्प्रेमाइज को पेश करना एक ग्रलत बात है उनके वहां पर ग्रौर मेरे यहां पर होने का ही यह कारण है। बहुमत के ग्रहंकार में मस्त होकर बहमत के जरिये से अपनी इच्छा के अनुसार और मनमानी करने का अभ्यासी होने के बाद यह चेष्टा कि वे सही रूप में समस्या को हल करने का उपाय पेश करे, चाहे कोई कम्प्रोमाइज ही पेश क्यों न करे। में यह मानता हूं कि श्री रामनरेश जी के लिये यह एक कठिन समस्या है और वह उसको सुलझा नहीं पायेंगे । जो खास प्रश्न था उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ ब्रिधिक नहीं कहा । उन्होने न्याय-न्याय की बहुत ब्रिधिक दुहाई दी मै माननीय राम नरेश जी से पूछंगा कि वह न्याय क्या है जिसकी इस सदन में उन्होंने इतने जोरदार शब्दों में चर्चा की है। मेरी हमेशा यह कोशिश होती है कि किसी के खिलाफ ग्रधिक न कहा जाय लेकिन यह पूंछना ही पड़ता है कि क्या रामनरेश जी न्याय का अर्थ यही समझते है जैसी कि जिलों में घटनाएं हो रही है। क्या कानपुर की घटना उनके विचार से न्याय संगत हो सकती है? कानपुर ही क्यों टेहरी-गढ़वाल या और कोई जिला ही ले लीजिये वहां भी यही होता है। मैं पूंछता हूं कि क्या श्राप हरएक पंचायत में इसी प्रकार का न्याय प्रचलित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि हम न्याय पंचायतों का चुनाव कराते है तो फिर यह भी मांग आयोगी कि हाईकोर्ट के जजों का भी चुनाव हो । समझ में नहीं आया कि उन्होंने यह तत्व कहां से पाया। मुझे दु:ख हुआ हालांकि उनका भाषण बहुत अच्छा था लेकिन वह तत्विवहीन था शुरू से अन्त तक और किसी तत्व को पेश करने का भी प्रयत्न किया तो उन्होंने काल्पनिक रूप से ही किया। ट्रेजरी बेचेज की ओर बैठकर और उसके एक प्रमुख होने के नाते

ये बात उन्हें शोभा नहीं देतीं। श्रध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड हो या न हो उसके संबंध में में शुरू में ही बहुत कुछ कह चुका हूं लेकिन इस सम्बन्ध में में यह श्रीर कहना चाहूंगा कि जब एक तरफ यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड न हो उसके साथ हो साथ दूसरा प्रश्न यह भी है कि जुडिशियरी ऐक्जीक्यूटिव से जहां तक हो सके अलग हो। इस सम्बन्ध में में यहां तक कहूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज की नियुक्त ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा होती है तो मे पूछ्रूंगा कि क्या राम नरेश जी को यह मालूम है कि हाई कोर्ट के जजेज भी ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा प्रभावित हो जाते है। श्रीर जो हाईकोर्ट के जजेज प्रभावित हो सकते हैं

श्री मोहन लाल गौतम--मेरे स्थाल में माननीय हाईकोर्ट को इस प्रकार से किटिसाइज करना उचित नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष--ग्राप हाईकोर्ट के जजेज का नाम न लें क्योंकि एज ए होल हाईकोर्ट पर रिक्लेक्शन पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्द्रुशाह--ग्रध्यक्ष महोदय, ठीक है। ग्रध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा था कि हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि न्यायालयों के जजेज ऐक्जीक्यूटिव से प्रभावित होते है चाहे वह किसी भी श्रेणी का न्यायालय क्यों न हो ग्रौर जबकि उच्च श्रेणी के न्यायालयों पर प्रभाव पड़ सकता है तो में पूछ्रांगा कि एक प्रेस्काइब्ड अथारिटी द्वारा नियुक्त किये गये साधारण, गरीब ग्रीर देहात में रहने वाले पंचों के ऊपर किस प्रकार से ऐक्जीक्यूटिव का प्रभाव न पड़ेगा। ग्रब प्रश्न यह उठता है कि यह शुबहा ही क्यों रक्खा जाय कि ग्राखिर प्रभाव पड़ ही जायगा । यह हमारा ग्रनुभव है ग्रीर हालांकि श्री राम नरेश जी यहां इस सदन में कुछ कह दें लेकिन मेरा विश्वास है कि उनका भी यही अनुभव है कि भ्राजकल के न्यायालय उतने उच्च नहीं हैं, उतने निष्पक्ष नहीं है जितनी कि उनसे ग्राशा की जाती है ग्रौर जबकि ये न्यायालय इतने निष्पक्ष नहीं पाये जाते हालांकि उनके जजेज की नियुक्ति के समय एक्जीक्यूटिव बहुत विचार करती है और योग्य व्यक्तियों को ही केवल नियुक्त करती है फिर भी उनकी निष्पक्षता में शबहा जाहिर किया जा सकता है। फिर मै पूंछता हूं कि इन पंचों की नियुक्ति के पश्चात् यह कैसे स्राशा की जायगी कि वे इस प्रेस्काइब्ड स्रथारिटी के प्रभाव से ऊपर उठ पायेंगे स्रौर वे पंच किसी डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट या किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भ्राफिसर या डिस्ट्रिक्ट पंचायत-राज श्राफिसर के संकेत से दूर रह सकेंगे। श्रध्यक्ष महोदय, में इस सम्बन्ध में श्रापके द्वारा यह भी प्रकट करना चाहता हूं हालांकि इसका जिक्र पहले होना चाहिये था फिर भी 'बेटर लेट दैन नेवर' इस विधेयक को इस रूप में पेश करके माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन का श्रपमान किया है। इस सदन में मे स्पष्ट रूप से दिखलायी देता है कि श्रापका बहुमत है श्रीर उसके जोर पर इस सदन से यह स्राज्ञा करना कि वह इस संज्ञोधन विधेयक को पारित करे जब कि प्रेस्काइब्ड भ्रयारिटी सरीखे शब्द की, इंस्टीट्यूशन की कोई परिभाषा नहीं दो गयी है, परिभाषा ग्रध्यक्ष महोदय तभी हो सकती थी जबिक कम से कम इस चीज का रुख माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में क्रिस्टलाइज हो जाय । मुझे दुख है कि इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी क्या होगी यह हमें नहीं बतलाया गया है और न हमको किसी प्रकार का संकेत ही दिया गया है कि अगर यह चीज नहीं होगी तो यह होगी। यानी जहां तक कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रैट के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट कर दिया जाय, किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं किया गया है।

श्री ग्रध्यक्ष—ग्रभी ग्राप कुछ देर तक ग्रपना भाषण जारी रखना चाहते है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां, ग्रभी मैं कुछ देर बोलूंगा
श्री ग्रध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि कल ग्राप ग्रपना भाषण जारी रखेंगे।

कांतपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री ग्रध्यक्ष-मुझे सदन को कुछ सूचना देनी है।

स्यायी समितियों के लिए नामजदगी करीब-करीब सब की भ्रा चुकी है लेकिन पांच के विषय में मुझे मालूम हुआ है कि उनकी नामजदगी पूरी नहीं हुयी है या शायद बिलकुल ही नहीं हुयी है। वे ये हे—यातायात कमेटी, श्रावकारी कमेटी, शरणार्थी कमेटी भीर खाद वितरण कमेटी तथा जेल, तो इसलिए कि चूंकि इनकी कतई न मजदगी नहीं हुयी है, में दूसरी तारीख उनके लिये मुकर्रर करता हूं। ७ मई, ३ बजे तक नामजदगी की तारीख होगी और द मई को १ बजे तक उनकी सूक्ष्म परीक्षा होगी। ११ मई नाम वापस लेने की तिथि होगी। कुछ नाम वापसी पर भी भ्रगर चुनाव की भ्रावक्यकता पड़ी तो १५ तारीख को चुनाव होगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १ मिनट पर ग्रगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थिगत हो गया ।)

लखनऊ : ४ मई, १६५४ । कैलासचन्द्र भटनागर, सचिव, विघान सभा, उत्तर प्रदेश ।

न-त्री क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर ।)

मची

8	लाल गंज डंडवा	कच्ची सड़दः	X	मील
Ş	घनघटा विश्वनाथपुर	"	ሂ	17
ş	दुधारा यस्ती	77	ጸ	17
ሄ	तालपुरवा नासी	77	5	"
ሂ	बिसकोहर पटना	27	3	27
Ę	हरैया सेमरा	" _	E	77
9	डुबोलिया कप्टेन गंज	11	5	77
5	घनघटा सिरसी	प्राम सङ्क	Ę	,,
3	बसखोड करही	77	હ	**
१०	रुदौली मानपुर	27	5	"
११	उसका लोहांस	"	Ę	"
१२	विर्धीपुर तिवड़ा	73	Ę	77
१३	चांदापुर ग्रहरोलिया	"	Ę	77
१४	डुमरिया गंज महवार	77	હ	"
१५	नितहापुर रजवापुर	n	9	**
			<i>e</i> 9	मील

उत्तर प्रदेश विधान समा

बुधवार, ५ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रध्यक्ष, श्री ग्रात्माराम गोविन्द खेर, की ग्रध्यक्षता में ग्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

श्रंसमान सिंह, ग्रक्षयवर सिंह, श्री ग्रनन्तस्वरूप सिंह, श्री प्रब्दुल मुईज खां, श्री ग्रब्दुल रऊफ खां, श्री ग्रमतनाथ मिश्र, श्री प्रली जहीर, श्री मैयद ग्रवधशरण वर्मा, श्री ग्रशरफ ग्रली खां, श्री ग्राशालता व्यास, श्रीमती इरतजा हुसैन, श्री इस्तफा हुसैन, श्री उदयभान सिंह, श्री उमाशंकर, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री उम्मेद सिंह, श्री उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री ऐजाज रसूल, श्री ग्रोंकार सिंह, श्री कन्हैया लाल, श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री कमाल ग्रहमद रिजवी, श्री करनसिंह, श्री कल्याण राय, श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री कालीचरण टंडन, श्री किन्दर लाल, श्री किशनस्वरूप भटनागर, श्री कंवरकृष्ण वर्मा, श्री कृपाशंकर, श्रो

कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री कृष्णशरण स्रार्य, श्री केवलसिंह, श्री केशभान राय. श्री केशवगुप्त, श्री केशव पांडेय, श्री कैलाशप्रकाश, श्री खुशीराम, श्री गंगाधर, श्री गंगाधर जाटव. श्रो गंगाप्रसाद, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री गणेश प्रसाद पांडेय, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्री गुप्तारसिंह, श्री गुरुप्रसाद पांडेय, श्री गुरुप्रसाद सिंह, श्री गुलजार, श्री गेंदासिंह, श्री गोपीनाथ दोक्षित, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री गौरीराम, श्री घनश्यामदास, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्री चन्द्रवती, श्रीमती चन्द्रसिंह रावत, श्री चन्द्रहास, श्री चरणसिंह, श्री चिरंजीलाल पालीवाल. श्री

चन्नी लाल सगर, श्री छेंदालाल चौधरी, श्री जगतनारायण, श्री जगदीश प्रसाद. श्री जगदीश सरन रस्तोगी, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगन्नाथ बस्ता दास, श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री जगपति सिंह, श्री जगमोहन सिंह नेगी, श्री जटाशंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री जयराम वर्मा, श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री जवाहरलाल, श्री जुगलकिशोर, श्री जोरावर वर्मा, श्री झारखंडे राय, श्री टोकाराम, श्री डल्ला राम, श्री डालचंद, श्री त्रलसीराम, श्री तुला राम, श्रो तुला राम रावत, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री तेजबहादुर, श्री तेजासिंह, श्री त्रिलोकीनाथ कौल, श्री दयालदास भगत, श्री दर्शनराम, श्रो दीनदयालु शर्मा, श्री दीनदयालु शास्त्री, श्री दोपनारायण वर्मा, श्री देवकीनन्दन विभव, श्री देवदत्त मिश्र, श्री देवराम, श्रो द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री घनुषधारी पांडेय, श्री धर्मसिंह, श्री नत्थुसिंह, श्री नरदेव शास्त्री, श्री नरोत्तम सिंह, श्री नवलिकशोर, श्री

नागेश्वर द्विवेदी, श्री नाजिम ग्रली, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री नारायण दास, श्री नारायण दीन वाल्मीकि, श्री नेकराम शर्मा, श्री नेत्रपाल सिंह, श्री नौरंगलाल, श्री पदमनाथ सिंह, श्री परमेश्वरी राम, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री पहलवान सिंह चौधरी, श्री पातीराम, श्री पुत्तुलाल, श्री पूहन राम, श्री पुलिनविहारी बनर्जी, शी प्रकाशवती सूद, श्रीम ' प्रतिपाल सिंह, श्री प्रभाकर शुक्ल, श्री प्रभुदयाल, श्री प्रेमिकशन खन्ना, श्री फज्जलुल हक़, श्रो फतेह सिंह राणा, श्री बद्रीनारायण मिश्र, श्री बनारसी दास, श्री बलदेव सिंह, श्री बलदेव सिंह ग्रार्य, श्री बलवन्त सिंह, श्री । बशोर ग्रहमद हकीम, श्री ' बसन्त लाल, श्रो वसन्त लाल शर्मा, श्री बाबनन्दन, श्री । वाबू लाल कुमुमेश, श्री बाबू लाल मतिल, श्री बालेन्दु शाह, महाराजकमार विशम्बर सिंह, श्री बेचन राम, श्री बेचन राम गुप्त, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री भगवती प्रसाद दुबे, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी । भगवान दीन वाल्मीकि, श्री भगवान सहाय, श्री भोमसेन, श्री भुवरजी, श्री

उपस्थित सदस्यों की

भपाल मिह खाती, श्री भगनाथ चतुर्वदी. श्री भौलामिह पादव, श्री मकसूद ग्रालन वा. श्री मथरा प्रसाट त्रिपाठी. श्री मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री मदनगोपाल दद्द, श्रो मदनमोहन उपाध्याय, श्री मन्नीलाल गुरुदेव, श्री मलखान सिंह, श्री महमुद ग्रली खां, श्री (रामपुर) महम्द ग्रली खां. श्री (सहारनपुर) महाबीर सिंह. श्री महीलाल, श्री मान्धाता सिंह, श्री मिजाजी लाल, श्री मिहरबान सिह, श्री मुञ्जूलाल, श्री मुरलीधर कुरील, श्री मुश्ताक ग्रली खां, श्री मुहम्मद ग्रब्दुल लतीफ, श्री मुहम्मद ग्रब्दु समद, श्री मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज मुहम्मद तक़ी हादी, श्री मुहम्मद नसीर, श्री मुहम्मद मंजूरल नबी, श्री मुहम्मद बाहिद नाखरी, श्री मोहन लाल, श्री मोहन लाल गौतम, श्री मोहन सिंह, श्री मोहन सिंह शाक्य, श्री यमुना सिंह, श्री यशोदा देवी, श्रीमती रघुनाथ प्रसाद, श्री रघुराज सिंह, श्री रघुवीर सिंह, श्री रमें वन्द्र शर्मा, श्री रमेश वर्मा, श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा राजिकशोर राव, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राजवंशी, श्री राजाराम किसान, श्री राजाराम मिश्र, श्री राजाराम शर्भा, श्रो

राजेन्द्र दत्त, श्री राधाकृष्ण ग्रग्नवाल, श्री राधा मोहन सिंह, श्री राम ग्रधार तिवारी, श्रो राम ग्रधीन सिंह यादव, श्री राम ग्रवध सिंह, श्री रामकिकर, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री राम गुलाम सिंह, श्री रामचन्द्र विकल, श्री रामजो लाल सहायक, श्री रामजा सहाय, श्री रामदाम ग्रार्य, श्री रामदास रविदास, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री रामनरेश शुक्ल, श्री राम नारायण त्रिपाठी, श्री राम प्रसाद, श्री राम प्रसाद नौटियाल, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री रामबली मिश्र, श्री रामभजन, श्री राममूर्ति, श्री राम रतन प्रसाद, श्रो रामराज शुक्ल, श्री राम लखन, श्री राम लखन मिश्र, श्री राम लाल, श्री राम वचन यादव, श्री राम शंकर द्विवेदी, श्री राम शंकर रविवासी, श्री राम सनेही भारतीय, श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री राम सुन्दर राम, श्री राम मुभग वर्मा, श्री राम सुमेर, श्रो राम स्वरूप गुप्त, श्री राम स्वरूप भारतीय, श्री राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री रामहरख यादव, श्री रामहेत सिंह, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री लक्ष्मण राव कदम, श्री लक्ष्मीदेवी, श्रीमती लक्ष्मी शंकर यादव, श्रो

लाल बहादुर सिंह, श्री नाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री लुत्फ ग्रली खां, श्री लेखराज सिंह, श्री वंशनारायण सिंह, श्री वंशीदास धनगर, श्री वसी नक्तवी, श्री वासूदेवप्रसाद मिश्र, श्री विजयशंकर प्रसाद, श्री विद्यावती राठौर, श्रीमती विष्णु दयाल वर्मा, श्री विष्णु शरग दुब्लिश, श्री वीरसेन, श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री बोरेन्द्रपति यादव, श्री बोरेन्द्र वर्मा, श्री वीरेन्द्र शाह, राजा द्रजरानी मिश्र, श्रीमती द्रजवासी लाल, श्री व्रजबिहारी मिश्र, श्री वजिंबहारी मेहरोत्रा, श्री शंकर लाल, श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री शांति प्रपन्न शर्मा, श्री शिवकुमार मिश्र, श्री शिवनारायण, श्री शिवप्रसाद, श्री शिवमंगल सिंह कपूर, श्री शिवराज सिंह यादव, श्री शिवराम पांडेय, श्री शिववचन राव, श्रो शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री शिवस्वरूप सिंह, श्री शुकदेव प्रसाद, श्री शुगन चन्द, श्री श्याम मनोहर मिश्र, श्री

श्याम लाल, श्री श्रीचन्द, श्री श्रीनाथ राम, श्री सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती संग्राम सिंह, श्री सिच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती सत्य सिंह राणा, श्री सावित्री देवी, श्रीमती सियाराम गंगवार, श्री सियाराम चौधरी, श्री सीताराम, डाक्टर सीताराम शुक्ल, श्री सूखी राम भारतीय, श्री सुन्दर दास, श्री दीवान सुन्दर लाल, श्री सुरुजू राम, श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री सूर्य्यबली पांडेय, श्री सेवाराम, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री हबीबुर्रहमान ग्रंसारी, श्री हबीबुर्रहमान आजमी, श्री हबीबुर्रहमान खा हकीम, श्री हमीद खां, श्री हरखयाल सिंह, श्री हरगोविंद पन्त, श्री हरगोविंद सिंह, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री हरदेव सिंह, श्री हरि प्रसाद, श्री हरिश्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री हरिवचन्द्र वाजपेई, श्री हर्रिसह, श्री हुकुम सिंह, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रक्न

कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल-व्यवस्था

*१-शि दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--वया यह सही है कि सरकार तीन वर्ष पूर्व कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल देने का वायदा किया था? प्रश्नोहार १७६

ह्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी नहीं

"२--श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि इस जल व्यवस्था मे कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान था ?

श्री मोहन लाल गौतम -- इस कालोनी की कोई पृथक् योजना नहीं है बिल्क कनखल की जल योजना ही में यह सिम्मिलित है। १९५२ में इस योजना का ग्रनुमानित व्यय ४ लाख रुपया था।

*३--श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि यह जल योजना कब तक ग्रमल मे श्राजायेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—१६५६-५७ तक इस योजना के पूर्ण होने की ग्राशा है। श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि स्वयं मुख्य मंत्री जी ने सन् ५१ में इसका वादा किया था ?

श्री मोहन लाल गौतम-इसकी सूचना चाहिए।

श्री दीन दयालु शास्त्री—क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के पास मुख्य मंत्री जी ने यह बात लिख कर भेजी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्नकर्ता इस बात के बारे मे ज्यादा जान सकते हे मेरी फाइल पर इसकी नकल नहीं है।

श्री दीन दयालु शास्त्री—-क्या मंत्री जी को पता है कि इस मई के महीने में ही वहां नल लगने जा रहा है ? में ग्राज ही हरिद्वार से ग्राया हूं ग्रीर वहां नल लग रहा है । क्या उन को मालूम है कि यह जल-योजना वहां ग्राजकल होने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—एक हैंडपम्प वहां लगाया जा रहा है ग्रोर उसकी सफलता पर ग्रागे विचार होगा कि यह ग्रस्थायी प्रबन्ध ठीक है या नहीं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती) —कृष्णनगर कालोनी की क्या जनसंख्या है?

श्री मोहन लाल गौतम--सूचना चाहिये।

प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल

*४--श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर) (श्रनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १६५३ में जो उत्तर प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल हुयों थी उसे सरकारी नोटीफिकेशन नं० ६०६६ (एल)-(३)/१८-३६५(एल)/४५ तिथि १० दिसम्बर, १६४७ के ग्रन्तगंत गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं, ऐसी कोई प्रदेशव्यापी घोषणा नहीं की गयी।
*५—श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)—[१८ मई, १६५४ के लिए प्रश्न संख्या
६४ के ब्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य की पंचायतों के लेखों की ग्राडिट-व्यवस्था

*६-श्री धर्मासह (जिला बुलन्दशहर)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों के धन को ख्राडिट करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री सोहन लाल गौतम--जी नही। पंचायतों के धन को श्राडिट करने का कोई प्रबन्ध नहीं है, परन्तु पंचायनों के लेखो के श्राडिट की व्यवस्था इस वर्ष की जा रही है।

* 3--श्री धर्मीमह --क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेगे कि मेरठ रीजन में कितने वर्षों ने पंचायन का धन ग्राडिट नहीं हुन्ना है ?

श्री मोहन लग्ल गौतम--प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री धर्म सिंह—क्या यह सत्य है कि पुराने पंचायत राज ऐक्ट ने रंचायतो को ग्राडिट करने की व्यवस्था थी ?

श्री मोहन लाल गौतम--कानून मे इसका प्राविजन ह।

श्री धर्ममह -- यदि कानून मे व्यवस्था थी तो उनको म्राडिट करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम--उस मेशीनरी को कायम करने मे कुछ श्रायिक विक्कते थी श्रार वजट का प्राविजन नहीं था, इसीलिए नही हो सका।

श्री बलवन्त स्टिह--सरकार जो पंचायतो के आडिट की व्यवस्था कर रही ह उनका खर्च कौन बरदाक्त करेगा ?

श्री मोहन लान्स गाँतम--इसका जिक्र बजट पेपर्स मे हैं, माननीय सदस्य उसे पढ़लें।

श्री धर्म सिंह—क्या मानर्नाय मंत्री जी कृपा करके बतायेगे कि नये ऐक्ट के स्रनुसार जबकि सूबे में बहुत सी पंचायते ह तो किस प्रकार स्राडिट करने का प्रबंध करेगे?

श्री मोहन लाल गाँतम—जिस व्यवस्था पर विचार हो रहा है उसमे इसका भी ध्यान रखा जायगा ।

बलिया में पंचायत-मंत्रियों को वेतन मिलने में विलम्ब

" = -श्री गंगा प्रसाद सिह (जिला विलया) (श्रनुपस्थित) - - क्या सरकार को ज्ञात हं कि बिलया जिले को कुछ पंचायतों के मंत्रियों को लगातार कई माह मे वेतन नहीं मिल रहा है?

श्री मोहन लाल गौतम—बिलया जिले में केवल दो पंचायत मंत्रियों के ग्रतिरिक्त सबका बेतन फरवरी, १६५४ तक समयानुसार दे दिया गया है।

देवरिया जिले मे दुदेही अदालत पंचायत के सरपंच की मुश्रत्तली

*६--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया) (श्रनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की दुदेही श्रदालत पंचायत के सरपंच मुश्रत्तल किये गये थे? ग्रगर हां तो किस केस मे ?

श्री मोहन लाल गौतम-जो हां। सरकार बनाम श्री एस० एम० श्रीवास्तव पंचायत निरीक्षक के मुकदमें मे।

*१०-श्री राम सुभग वर्मा (ब्रनुपस्थित)--क्या सरंपंच मुकदमे से निर्दोष बरी हो गये ? यदि हां, तो क्या उनको सरपंची का चार्ज मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—मुकदमें में सरपंच को ग्रवश्य वरी कर दिया गया है, किन्तु उन्हें पदारूढ़ नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनके विरुद्ध वभागिक कार्यवाही चल रही है।

*११--श्री राम सुभग वर्मा (ब्रन्पस्थित)--क्या सरकार को पता है कि इस स्नाशय का प्रार्थना-पत्र विभागीय दफ्तर तथा सरकार के पास भी जाया है?

श्री मोहन लाल गौतम-जो हां।

फर्वलाबाद-फनेहगढ़ में वाटर-वर्क्स योजना तथा पृथक्-पथक् म्युिसिपैजिटियां बनाने की मांग

* १२--श्री पाती राम (जिला फर्सव वाद)--क्या अर्र बाबाद फतेहगढ़ की मिनीजुनी म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग करने के वास्ते वहां की जनता की तरफ में कोई मांग मरकार में की गर्या है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*१३—श्री पाली राम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स योजना कव तक ब्रारम्भ हो सकेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—योजना का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है परन्तु जलवितरण की निश्चित तिथि श्रभी निर्धारित नहीं की जा सकती ।

श्री पाती रान--क्या सरकार प्रारंभिक योजना का स्पट्शकरण करेगी ?

श्री मोह्न लाल गौतम—सन् १६५२-५३ मे ५० हजार रुपया लोन दिया जा चुका है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती) —क्यः मरकार कृषा करके उद्दारायेगी कि म्युनिसि-पलिटी ने उममे कितना हिस्सा विया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--ग्राम तौर पर वाटर-वर्क्स पर बहुन थोड़ी-सी न्युनिसिय-लिटियां हे, जो ग्रपना हिस्सा दिया करती ह, लोन गवर्नमेट का ही होता है।

*१४—श्री पाती राम—[१६ मई, १६५४ के लिये प्रकृत संख्या = ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

*१५-१७--श्री किञन स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)--[१६ मई, १६४४ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में टी० बी० के टीके

*१८--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जैंतपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में १९५३ में कितने टी० बी० के टीके लगाये गए?

ग्रन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—जीतपुर जिले में २३,३७० ध्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये टीके केवल कस्बों में लगाये गए हं या गांवों में भी .

श्री बनारसी दास—यह कस्बों ग्रौर गांवों दोनों ही में लगाये गये हैं। मड़ियाहूं के ग्रन्तर्गत सीनापुर ग्राम में महिला चिकिःसालय की मांग

*१६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं के ग्रन्तर्गत सीतापुर ग्राम की जनता ने महिला चिकित्सालय के लिए मांग की है श्रीर उसके लिये इमारत देने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास-जी हां । प्रक्त विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कब नक यह प्रश्न विचाराधीन रखा जायगा ?

श्री बनारसी दास--इमी वर्षके ग्रन्दर इस पर निर्णय हो जायगा।

होमियोपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री

*२०—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम्यो-पैथिक डाक्टरों की रिजस्ट्री की जाने वाली है? यदि हां, तो कब से?

श्री बनारसी दास—जी हां। होमियोवैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री का काम की ह

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कब्ट करेंगे कि उनके पास कोई ऐसे श्रांकड़े हैं कि प्रदेश में क्वालिफाइड होमियोपैथिक डाक्टर्स कितने है?

श्री बनारसी दास—इस बक्त तो कोई स्रांकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बस्ती जिले में बी० सी० जी० के टीके

*२१—-श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका बस्ती जिलें में लग रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० की एक टोली ने बस्ती जिले में १५ जुलाई से २६ नवम्बर, १६५२ तक कार्य किया।

*२२—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले के किन-किन तहसीलों में बी० सी० जी० का टीका लगाया गया है?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० का कार्य जिले की पांचीं तहसीलों में किया गया श्रीर जितने श्रादिमयों की जाच की गई तथा टीके लगाये गये उनकी संख्या नीचे दी जाती है:

ऋ० सं० तहसील का नाम			जांच किये गये	टीके लगाये गये	
१	सदर तहसील		२४,७४०	८,४१४	
२	बांसी	• •	११,८०१	३,२४१	
₹	हरैया	• •	3,986	१,५२३	
8	खलीला बा ब	• •	१०,५७४	३,०००	
K	डुमरियागं ज	• •	४,८७१	१,६९६	

*२३—श्री रग्मसुन्दर राम—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दीका लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपर्युक्त जिले में कुल कितनी है ?

श्री बनारसी दास—कुल ५७,७५४ व्यक्तियों की जांच की गई, उसमें से १७,८७७ व्यक्तियों को, जिनको बी० सी० जी० के टीके की ग्रावश्यकता थी, टीके लगायें गये।

श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका किस ग्राधार पर बस्ती जिले में लगाया जा रहा था ग्रीर किन कारणों से बन्द कर दिया गया?

श्री बनारसी दास—इसका कारण यही था कि समस्त प्रदेश में ही इसकी श्रावश्यकता मह्मूस की गयी कि टी० बी० की बीमारी बढ़ती चली जाती है इसिल ए उसकी रोक-थाम करने के लिये वहां जांच की जाय श्रीर टीके लगाये जायं। इसी लिये वहां पर टीके लगाने का कार्य श्रारम्भ किया गया, लेकिन सूबे में बी० सी० जी० की जो यूनिट्स है वह तो चलती-फिरती ही मभी जगह काम करती हैं।

श्री त्रीरेन्द्र व $\mathbf{H}^{[-]}$ —क्या माननीय मंत्री जी बताने का कव्ट करेंगे कि बस्ती जिले की इस यूनिट पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की ग्रावश्यकता है।

श्री र (मचन्द्र विकल--क्या म (ननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वतलाने का कब्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का परीक्षण टी० बी रोकने में सफल रहा है या ग्रसफल?

श्री बनारसी दास--सफल रहा है।

श्री चन्द्रोंतह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ऐसी भी रिपोर्ट आयी है कि जो टीके लगे वह फूल गये और उससे लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और सेप्टिक हो गया?

श्री बनारसी दास--सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—न्हया माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में बी० सी० जी० के टीकों की यूनिट्स प्रोवाइडेंड हैं?

श्री बनारसी दास—इसकी यूनिट्स कहीं भी निश्चित रूप से नहीं है बल्कि जितनी यूनिट्स हैं वह सभी जिलों में बारी बारी से भेजी गयी

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती) — क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलावेंगे कि बस्ती जिले की विभिन्न पांचों तहसीलों में जो टीके लगाने की संख्या दी गई है उसमें क्यों ग्रन्तर है ?

श्री बनारसी दास—इसका कारण यह है कि जब टोके लगाने के लिये वहां पर जाते हैं तो वह जनता के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। जितने ज्यादा श्रादमी जांच करने के लिये मिल सकते हैं उतने ज्यादा टीके लगाये जा सकते हैं। इसके श्रलावा तहसीलों के श्रन्दर यह भी देखना पड़ता है कि जांच के फलस्वरूप उसमें निगेटिव कितने हैं श्रौर पाजिटिव कितने हैं श्रौर टीका कितने श्रादियों के लगना है। इसलिये श्रन्तर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का कार्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पंच-वर्षीय योजना के साथ ही सम्पन्न हो जायना ? श्री बनारसी दास—लगभग सभी जिलों के ग्रन्दर बी॰ सी॰ जी॰ के टीके लगेगे इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि तमाम जिलों में इतनी बड़ी तादाद मे बी॰ सी॰ जी॰ की युनिट्स बढ़ा दी जायंगी कि सभी जगह एक ही साथ कार्य हो जाय।

श्री राम दास स्रार्थ (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को बी० सी० जी० के टीके लग चुके हैं उनको फिर इस टीके की ग्राव-ज्यकता नहीं होगी, ग्रगर होगी तो कितने दिनों बाद?

श्री बनारसी दास—-ग्रामतौर से विशेषज्ञों का यही मत है कि जिनको टीका लग जाता है फिर उन्हें क्षय रोग नहीं होता है।

*२४-२६-श्री राम सुन्दर पाडेय (जिला ग्राजमगढ) — [१६ मई, १६४४ के ल्ये स्यगित किये गये।]

*२७—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[१६ मई १६४४ हे लिये स्थिति किया गया।]

श्रस्पताल के कार्य काल में मेडिकल श्रफसरों को बाहर न जाने का श्रादेश

*२८—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्डेखाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि डी॰ एम॰ एच॰ एस॰ यू॰ पी॰ ने दिनांक, २१ जून, १६४६ ई॰ को एक पत्र द्वारा प्रान्त के सभी सिविल सर्जनों को ग्रादेश दिया है कि किसी भी ग्रवस्था मे कोई मेडिकल ग्राफिसर ग्रस्य-ताल के काम के घंटों में किसी भी रोगी का किसी भी दशा मे ग्रस्पताल के बाहर इलाज करने नहीं जा सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उप पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' स्रागे पृष्ठ २३६ पर।)

*२६--श्री मथुर। प्रसाद त्रिपाठी--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सब है कि उपर्युक्त परिपत्र को रिवाइज किया गया है? यदि हां, तो कब ? श्रौर क्या उसकी प्रतिनिध सरकार मेज पर रक्खेगी?

श्री बनारसी दास—संशोधित परिपत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' श्रागे पुष्ठ २३७-२३६ पर ।)

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिपन्न दिनांक ६ जनवरी, १६५० की प्रतिलिपि जिला फर्रुखाबाद के सिविल सर्जन के पास भी भेजी गयी थी? यदि हां, तो कब?

श्री बनारसी दास—वह तो सभी सिविल सर्जनों के पास भेजी गयी थी। जिस तिथि का ग्राप ने जिन्न किया उसी पर उनको भी भेजी गई।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रगर कोई कालरा का मरीज है और उसको डाक्टर पहले से श्रटेंड नहीं करता है, तो वह वर्किः। श्रावर्स में उसको श्रटेंट कर सकता है या नहीं?

श्री बनारसी दास—उस सर्क्यूलर के श्रनुसार वर्षिण श्रावर्स में विशेष परिस्थितियों में बाहर जाने की श्रनुमित दी गई है श्रीर उसमें यह भी है कि श्रगर कोई मरीज का एक्सीडेंट हो गया है या किसी विशेष परिस्थितिवश उसको लाया नहीं जा सकता तो यह डाक्टर की मर्जी के ऊपर है कि मरीजों को देखने के लिये श्राफ़िस श्रावर्स में जाना चाहिये या नहीं।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छुटनी

*३०—श्री झारखंडे राय (जिला ग्राजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि बाद्य विभाग से ग्रब तक कुल कितने कर्मचारी छांटे जा चुके हैं?

श्री बनारसी दास--- ५,०६३।

*३१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन निकाले गये कर्मचारियों में कितने लोगों को नियुक्ति मिल गयी है?

श्री बनारसी दास---२०३।

*३२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कर्मचारी बाक़ी रह गये हे उनको पुनः कहीं नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास—सरकार के समक्ष ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने छटनी में ग्राये हुये इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह ग्रादेश ग्रवदय जारी किये हं कि जहां तक सम्भव हो सरकारी विभागों में होने वाली ग्रस्थायी ग्रौर स्थायी नियुक्तियों में इनमें से योग्य कर्मचारियों को प्राथम्य दिया जाये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि यह छटनी किस स्राधार पर हुई है स्रौर किन नियमों के मातहत हुई ?

श्री बनारसी दास—्योंिक डीराशानिंग हो गया है श्रीर इसलिये श्रावश्यकता कम हो गई। रिट्रेच करने की जरूरत पड़ी, इसलिये रिट्रेंचमेट किया गया श्रीर इसके लिये तीन श्रीणयां बनाई गई। तो कुछ लोग तो ए में श्राये, कुछ बी में रखे गये। जिनका कार्य श्रच्छा नहीं था, जिनकी इन्टेग्नेटी डाउटफुल थी उनको सी में रखा गया। सी वालों को पहले निकाला गया श्रीर जैसे जैसे छटनी होती चली गयी रिट्रेच किये गये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि २०३ की जो नियुक्तियां हुई है वे श्रधिकतर जो विभाग के बड़े श्रधिकारी थे या जो पोजीशन पर थे उन्हीं की हुई है ?

श्री बनारसी दास—यह तो प्रश्न नहीं होता। उसमे ज्यादातर नियुक्तियां नान-गलटेड लोगों की है ग्रौर इसके लिये जो विभागीय सूची तैयार की गयी थी वह सभी हैड्स ग्राफ डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई है ग्रौर एमप्लायमेंट एक्सचेंज को भेज दी गई हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि साद्य विभाग टूटने वाला है और कर्मचारी बेकार होने वाले हैं?

श्री बनारसी दास—श्रभी कोई ऐसा निश्चय नहीं है ग्रौर बाक़ी जैसी। हियति है उससे ग्रन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि खाद्य विभाग के ८,०६३ धार्बमियों के छटने के बाद कितने आदमी शेष होंगे ?

श्री बनारसी दास—इस समय कुल कर्मचारियों की संख्या जो आफिस में रह गये हं वह ४,६६६ हैं।

श्री रामचन्द्र विकल-क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि खाद्य विभाग के मुक्त कर्मचारी जो श्रपने घरों पर बैठे हुये हैं श्राइन्दा सर्विस के समय उनकी श्रवस्था पर प्रतिबन्य नहीं रहेगा?

श्री बनारसी दास—जी हां। जो लोग रिट्रेंच किये गये हैं उनको प्रवस्था

के समय में अपवाद मिल जायगा।

श्री धर्मसिह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों की छटनी हुई है उनमें कितने गजटेड ग्राफ़िसर्स हैं ?

श्री बनारसी दास-११८ गजटेड श्राफ़िसर्स हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायतें श्रायी हैं कि सरकार के ब्रादेशों का पूरा पालन नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस प्रकार की शिकायतें श्रवश्य मिलीं कि सरकार के ग्रादेशों के बावजूद भी बहुत से विभागाध्यक्ष ग्रपनी मनमानी करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्री बनारसी दास-पुनः ग्रादेश जारी किये गये हैं।

श्री द्वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन २०३ श्रादिमयों की नियुक्ति हुई है वह केवल सीनियारिटी के श्राधार पर हुई है या कोई दूसरा नियम भी बरता गया है?

श्री बनारसी दास—इसका कोई प्रश्न नहीं है। जैसी सूची तैयार की गयी है उसके ग्रनुसार जिनको रखना था उनको सामने बुलाया गया ग्रौर जिनको उन्होंने उचित समझा उनको रक्खा।

*३३-३४-श्रो देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--[२ जून, १६४४ के लिये स्वितिन किये गये।]

*३६-३८--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालीन)--[१६ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

*३६-४१--श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--[१६ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

*४२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बहायूं)—[२१ मई, १६५४ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी योजना

*४३—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या रूरल हार्डीसंग कंडीशंस को सुधारने की प्रदेशीय सरकार की कोई योजना चालू है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम—रूरल हार्डीसंग सबंधी कोई सरकारी योजना चालू नहीं

श्री दिवराज सिंह यादव—क्या माननीय मंत्री बताने की कृषा करेंगे कि प्रदेशीय मरकार लो कास्ट हाउसिंग सम्बन्धी कोई रिसर्च करा रही हूँ ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस प्रकार को एक नुमायश दिल्ली म हुई थी श्रौर उससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है।

*४४--श्री पुद्दन राम (जिला बस्ती)--[१६ भई, १६५४ के लिने स्थिगित किया गर्मा।]

पंचायत घरों के लिए 'ग्रावाज' रेडियो

*४५--श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र (जिला हरदोई)--क्या यह सही ह कि सरकार ने प्रान्त की सभी ग्राम सभाग्रों के पास यह ग्रादेश भेजा है कि वह केवल 'श्रावाजं रेडियो ही पंचायत घरों के लिये खरीदे ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नही।

*४६-४७--श्री इसराहल हक़ (जिला आगरा)--[१६ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

वैद्यों ग्रौर हकीमों का रजिस्ट्रेशन

*४८--श्री त्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (ग्रनुपाण्यत)--क्या यह सच है कि वैद्यो और हकीमो के रजिस्ट्रेशन करने की ग्रविध ७-३-४३ तक ही थी ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। वैद्य एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन श्रव भी होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय-- क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेगे कि रिजस्ट्रेशन करने की क्या पद्धति है ?

श्री बनारसी दास——बोर्ड श्राफ इंडियन मेडिसिन के श्रधीन जो लोग डिग्री प्राप्त करते है परमानेट संस्थाओं मे, उनका रिजस्ट्रेशन इस वक्त होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि रिजस्ट्रेशन की कुछ कीस भी ली जाती है?

श्री बनारसी दास--जी हां, वह सही है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--रिजस्ट्रेशन कब तक होता रहेगा?

श्री बनारसी दास-जब तक वैद्य लंग पढ़कर ग्राते रहेगे, तज तक होता रहेगा।

गंगा नदी में जबहीं घाट पर नाव-दुर्घटना

*४६—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बिलया) (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि ब्रह्मपुर मेले के सिलसिले में बिलया जिले के जबहीं (सपहीं) घाट पर गंगा नवी में पार करते हुए एक बड़ी नाव डूब गयी और उसमें क़रीब १०० ग्रावमी डूब कर मर गये?

श्री मोहन लाल गौतम—बह्मपुर मेला विहार प्रदेश के शाहाबाद जिले के पुलिस याना बह्मपुर के क्षेत्र में लगता है और प्रश्न में उल्लिखित नाव डूबने की दुर्घटना उसी क्षेत्र में हुई थी। इस सरकार के पास उक्त दुर्घटना का कोई विवरण नहीं है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४८ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा ।

*५०-श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार बिलया जिले के जबही (सपहीं) घाट की घटना की जांच के लिये कोई कमेटी बनाने की कृपा करेगी ताकि इसके बारे में सारी बाते जाहिर हो सकें?

श्री मोहन लाल गौतम—चूंकि नाव दुर्घटना इस प्रदेश मे नहीं घटी थी इस कारण इस सरकार द्वारा किसी जांच समिति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

*५१—श्री शिव राज सिंह यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष स्वास्थ्य विभाग के स्रघीन कितना रुपया देहाती क्षेत्र में पीने के पानी के सम्बन्ध में खर्च किया गया?

श्री बनारसी दास-गत वर्ष राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने १,०३,७०० की रक्तम राज्य कं ग्रामीण क्षेत्रों मे पीने के पानी की योजनात्रों के हेतु अनुदान के रूप में दिया।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिये सरकारी योजनाये क्या है श्रीर उसमें श्रनुदान देने का क्या तरीक़ा है?

श्री बनारसी दास—जैसा कि ग्रभी जिन्न किया गया, बजट मे इसका प्राविजन है, स्टेट हेल्य बोर्ड की तरफ से कि जहां प्लॉनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पीने के पानी की कमी की सूचना श्राती है वहां पर इसकी ग्रांट दी जाती है ग्रौर स्थानीय लोगों को भी कुछ रुपया देना पड़ता है। जहां पर ऐसा होता है वहीं मंजूर करते हैं।

श्री गंगा घर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल, टेहरी श्रौर श्रल्मोड़ा में कितना रुपया पानी के लिए दिया गया है?

श्री बनारसी दास-इसके लिये तो पहले से न टिस की श्रावश्यकता है।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में बहुत सी दरख्वास्तें हरिजनों की उनके पीने के पानी के सम्बन्ध में पड़ी हुई है श्रौर वे पास के तालाबों से पानी पी रहे हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां, हो सकता है कि स्रभी जो उत्तर दिया गया है इसके स्रति-रिक्त हरिजन सहायक विभाग की तरफ से भी कुन्नों के लिये १ लाख ७० हजार रुपये का प्राविजन किया गया है। मुमकिन है कि हरिजन सहायक विभाग की तरफ से हो। इसके स्रतिरिक्त कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया और नेशनल एक्सटेंशन सिवस के स्रन्तर्गत भी पानी के कुंसों की स्यवस्था की गई है।

श्री चन्द्रसिंह रावत क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितना रुपया पीने के पानी के लिये मंजूर हुआ था वह पूरा यूटिलाइज हुआ ?

श्री बनारसी दास—जितना रुपया रखा गया है उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना ग्रभी बाक़ी है इसके लिये तो पहले आंकड़े इकट्टा करने के बाद सूचना दी जा सकती है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार ने कोई डेड लाइन मुक़र्रर कर दी है कि उस वक्त तक वह तमाम स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीने का इन्तजाम कर देगी?

श्री बनारसी दास—वह तो जिस साल के लिये रुपया रखा जाता है उसमें माशा की जाती है कि पूरा खर्च हो।

एटा-गंज इंडवाणा सड्क का सुधार

*४२—श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा) (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से गंजडुंडवाणा को जो सड़क जाती है वह बहुत खराब है? उसकी बनवाने के लिये सरकार विचार कर रही है या नहीं?

श्री मोहन लाल गौतम—एटा-गंजडु डवाणा सड़क की दशा शोचनीय होने के कारण जिला बोर्ड ने इसके १३ मील को बनवाने का ठेका मार्च, १६५४ में स्वीकृत कर दिया है। कार्य पूरा होने की ६ मास के ग्रन्दर ग्राशा की जाती है।

भेड़िया बालक राम् के लिये बलरामपुर ग्रह्मताल, लखनऊ में प्रबन्ध

*५३—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रत्मोड़ः)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामू नामक भेड़िया बालक के लिये, जो बलरामपुर श्रस्पताल लखनऊ में है, सुरक्षा का कोई खास प्रबन्ध वह कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५४-श्री मदनमोहन उपाध्याय-क्या यह सही है कि इस भेड़िया बालक के सम्बन्ध में संसार के ग्रन्थ देशों से भी पूछ-तांछ हो रही है।

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह खास प्रबंध इस भेड़िये के लड़के के लिये क्या है ?

श्री बतारसी दास—उस भेड़िये के बच्चे को स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर ४ में रखा गया है श्रौर उसका उपचार होता है । उसके ऊपर दो वार्ड ब्वायज श्रौर रख दिये गये हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रामु लड़के के बारे में विदेशों से जो पूछतांछ हो रही है वह क्या है?

श्री बनारसी दास-पूछतांछ इस सम्बन्ध में है कि वह कैसे रहता है, क्या पशुग्रो के समान रहता है ग्रौर किस प्रकार से उसकी ग्रवस्था में सुधार हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस लड़के के खर्चे के लिये विदेश से भी कुछ रुपया श्राया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, रुपये ग्राने की कोई सूचना नही है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—क्या यह सही है कि रामू को भाषा सिखाने के लिये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है?

श्री बनारसी दास-जी ग्रभी तक कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि विदेशी लोग राम् भेड़िये के लड़के को ले जाने के लिये वार्ड क्यायज को घूस देने का षडयंत्र कर रहे थे?

श्री बनारसी दास-इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार है अब तक इस लड़के के ऊपर अपने कोष से कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री बनारसी दास—ग्रभी तक जितना रुपया खर्च हुन्ना है उसकी पूरी सूचना सरकार के पाम नहीं ग्राई है।

श्री सदनसोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेडिये के लड़के रामू को देखने के लिये क्या ग्रस्पताल में कोई टिकिट लगाया गया है ?

श्री वनारसी दास-जी नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामू की

श्री बन रसी दास—ग्रब वह चलने लगा है ग्रौर थोड़ा २ बोलता भी है। न नपुर तहमील, थाना खेरीघाट के पास चिकि सालय भवन का निर्माण

*५५—श्री वसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—न्या सरकार कृपा कर बनायेगी कि बहराइच जिले के ब्रन्तर्गत नानपारा तहसील में थाना खैरीघाट के सन्निकट कोई हास्पिटल भदन का निर्माण किया जा रहा है?

श्री बनारसी दास-जी हां।

*५६—श्री बसन्त लाल शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त कार्य के लिये कितनी धनराशि कब से स्वीकृत है ?

श्री बनारसी दास——३६,७०० ६० की धनराशि १६४६ में स्वीकृति हुई थी। ग्रब दूसरा तखमीना ४२,७०० ६० का स्वीकार हुआ है।

श्री वसन्त लाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का कॉस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ है और कितना हो चुका है ?

श्री वन रमी दास—इसका कंस्ट्रकान तो काफी हो चुका है ग्रौर ग्राशा यह है कि इस साल के ग्रन्त तक पूरा हो जायगा। देरी ग्रवश्य हुई है। सन् १९४६ ई० में रुपया मंजूर हुन्ना लेकिन कार्य जल्दी शुरू नहीं हो पाया ग्रौर बाद में दुबारा तखमीना मांगना पड़ा।

श्री दीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की क्रुपा करेंगे कि यह ग्रस्पताल कितने बेड्स का है?

श्री बन रसी दास—यह जो डिस्पेंसरीज का माडल है उसके ग्रनुसार है, वहां पर प्रायः ६ बेड्स का प्रावीजन होता है।

कानपर शहर में ईंधन सप्लाई के टेण्डर

*५७--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत श्रक्तूबर में कानपुर शहर को ईंधन सप्लाई करने के लिये कंजरवेटर ने टेण्डर मांगे थे?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*४६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसका टेंडर स्वीकार किया गया, श्रीर क्यों ?

श्री बनारसी दास-श्री महेन्द्र सेन का टेडर स्वीकार किया गया था, क्योंकि उनका टेडर १ ६० ३ ग्राने का था जो सबसे नीचे दरों का था।

श्री बृह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि इस समय कानपुर में ईंघन सप्लाई का काम कौन कर रहा है?

श्री बनारसी दास-प्राविशियल मार्केटिंग फ़ेंडरेशन ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि इस फ़ेडरेशन को शुरू में काम एक रुपया तीन ब्राने के हिसाब से दिया गया था, बाद को बगैर सूचना एक रुपया, पांच ब्राने रेट कर दिया गया?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है कि एक रुपया पांच ग्राने कर दिया गया, लेकिन यह सही नहीं है कि सूचना नहीं दी गयी।

श्री वासुदेव प्रसाद सिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि एक रूपया, पांच ब्राने के टेंडर बहुत से लोगों ने दिये थे, उनके टेंडर ब्रस्वीकार कर दिये गये हैं और फ़ेडरेशन को दिये गये हैं?

श्री बनारसी दास-जिस वक्त टेंडर इन्वाइट किये गये थे तो एक रुपया तीन झाने का लोएस्ट था, यह सही है कि कुछ लोगों ने एक रुपया पांच झाने भी दिये। लेकिन जिसका लोएस्ट था उन्होंने लकड़ी सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था, तब कोग्रापरेटिव फ़ेडरेशन को मुक़र्रर किया गया था और दूसरे लोग एक रुपया तीन झाने की दर पर उपलब्ध नहीं थे।

*५६-६०--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--[१६ मई,१६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की ग्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना

श्री श्रध्यक्ष—माननीय उपाध्याय जी ने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कहा का कि विशेषाधिकार का प्रश्न वह उठाना चाहते हैं। उन्होंने लिखकर उसके कारण भी बताये हे श्रीर उठाने की श्रनुज्ञा मांगी है कि श्राज वह उसे उठा सकें। मेरे सचिव के पास कोई ११ बजे से दस बारह मिनट पहले उनका खत श्राया है। बहुत लम्बा खत है श्रीर वह पहुंचा मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट पहले यहां श्राने के, तो उसकी नक़ल में श्रभी माननीय मंत्री जी को दे नहीं सका हूं श्रीर में भी पढ़ नहीं सका हूं, क्योंकि में ११ बजे के क़रीब ५ मिनट पहले श्रपने कमरे में श्राया। इसलिये में इसको कल पढ़ने के बाद इसके ऊपर निर्णय दूंगा कि क्या उसे श्राप सदन में उठा सकते है।

इलाहाबाद युनिर्वासटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मं इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९४४, पुरःस्थापित करता हूं।

(बेखिये नत्थी 'ग' भ्रागे पृष्ठ २४०-२६ पर।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४ † खण्ड १४ (ऋमागत)

श्री ग्र॰प्रक्ष—ग्रब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैमा कि वह संयुक्त प्रवर ममिति द्वारा संशोधित हुग्रा है, विचार जारी रहेगा।

महाराज्ञ मार खाले दुराह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के दिरोध में केवल दो आपित्तयां उठाई गई। माननीय अब्दुल मुईज खां ने यह आपित उठाई कि जो मेरा नंशोधन है वह एक आपटर थाट के रूप में है और इस आपित्त के कारण उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि क्योंकि यह एक आपटर थाट है इसलिये इसको अस्वीकार करना चाहिये। माननीय अब्दुल मुईज खां एक बंडिंग लाइयर है और एक बंडिंग लाइयर की भांति उन्होंने यह रखने की चेट्टा की है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि मेरा संशोधन एक आपटर याट है नो कहां तक संशोधन के तत्व पर इसका असर पड़ता है और कहां तक केवल एक आपटर याट होने की वजह से ही वह एक अनुचित संशोधन हो जाता है, इस पर कुछ न कहकर में इस विषय पर निर्णय देने के लिये मदन के सदस्यों और आपके अपर ही इसको छोड़ता हूं।

दूसरो ग्रापित साननीय राम नरेश शुक्ल जी ने उठायी थी ग्रौर उनका कहना यह था कि यदि कोई एक रिचोत्यूशनरी कदम या मुझाव दिया जाय, चाहे वह कितना ही ग़लत क्यों न हो. चाहे वह कितना ही इम्प्रेक्टिकल (ग्रव्यवहारिक) क्यों न हो, किन्तु यदि कोई ऐसा संशोधन पेश किया ज न तो उसको माननीय राम नरेश शुक्ल जी समझने के लिये तैयार है, किन्तु यदि एक ऐसा संशोधन पेश किया जाय जो कि प्रैक्टिकल रूप मे एक प्रकार का कम्प्रोमाइज पेश करता हो तो उसको वे स्वीकार करने के लिये कभी भी तैयार न होंगे। माननीय राम नरेश जी की जो ग्रापित है..............

श्री श्रब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट श्राफ श्रार्डर सर, श्रीमन् इस अमेडमेट मे जो सेक्शन ४३ श्राफ दि प्रिसिपल ऐक्ट का जिल्ल किया गया है तो सेक्शन ४३ श्राफ दि प्रिसिपल ऐक्ट में तो किसी नामिनेशन की बात नहीं है जैसा कि इस अमेडमेंट में हैं। वहां तो मीथे गांव सभा एलेक्ट करेगी पंचायती श्रदालत में पंचों को। इसलिये यहां सेक्शन ४३ श्राफ दी प्रिसिपल ऐक्ट तो उससे श्रसंगत हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—श्रध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध मे मै श्रापके सम्मुख यह निवेदन कर दं.....

श्रो ब्रध्यक्ष-मं ब्रभी जरा देख लूं कि ब्रापत्ति क्या है।

श्री ग्रन्दुल पुईज खाँ, ग्राप ग्रपनी ग्रापत्ति दोहरा दीजिये।

(कुछ ठहर कर)

श्री श्रब्दल मुईज खां—श्रीमन्, प्रिंसिपल ऐक्ट जो है ग्रगर उसकी धारा ४३ जैसा इस ग्रमेंडमेंट में लिखा है।

श्री ग्रध्यक्ष-वह पढ़ कर ग्राप सुना दें, ग्रापके पास है?

श्री ग्रद्ल मुईज खां—वह इस प्रकार है—"Every Gaon Sabha in a circle shall c'ect five adults of prescribed qualification" इतने ही से काम चल जायगा। वहां तक गांव सभा पंचायती श्रदालत के सदस्यों को चुनेगी श्रीर हम जिस खंड को इस वक्त ले रहे

^{*}संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है। †४ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

हं ग्रीर जिस पर पर अमेंडमेट है, पूरा अमेडमेट जिस पर ब्राधारित है वह यह है कि एलेक्शन के बाद नामिनेशन होगा। तो अगर "४३ ब्राफ दी प्रिसिपल ऐक्ट" इसमे कायम रहा अमेडमेट मे. नो पूरा खंड असंगत हो जाता है।

महारा नकुमार बालेन्दुशाह—मध्यक्ष महोदय, जो म्रापित श्री म्रब्दुल मुईज खां माहब ने की है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि पहले तो जो माननीय मंत्री महोदय का ड्राफ्ट है उसमे केवल प्रिंसिपल ऐक्ट बढ़ाया है। लेकिन जहां तक मुईज खां साहब की भ्रापित है में उनका और ग्रापका ध्यान इस श्रीर म्राकॉबत करना चाहता हूं कि सेक्शन ३३ श्राफ दी श्रमेंडिंग बिल जो है उसमें सेक्शन ४३ ग्राफ दि प्रिंसिपल ऐस्ट के संबंध में संशोधन पेश किया है। ३३ खंड में मंग्रध में भी मैने एक नंशोधन पेश किया है जो कि दर्तमान मंशोधन के मनुकुल है।

श्री श्रब्दुल मुईज खां--जैसा श्रभं बालेन्दु इतह जी ने करमाया, संशोधन ने सेवदन ४३ श्राफ दि ऐक्ट है "श्राफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" नहीं है। श्रगर श्राप "श्राफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" की शब्दावली से श्रमेडमेट पास हो जायगा तो इसके मानी यह हो जायंगे कि 'सेक्शन ४३ श्राफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट'।

श्री ग्रध्यक्ष--वह तो कह रहे हैं कि उन्होंने खंड ३३ में भी एक संशोधन दिया है जो इस संशोधन के श्रनुरूप है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—ग्रध्यक्ष महोदय, जो मुईज साहब की ग्रापित है वह यह है कि 'प्रिंसिपल ऐक्ट' होने की वजह से जो ग्रोरिजिनल ऐक्ट में है, उसका संशोधन होगा ग्रमिंडग बिल में। तो रेफरेंस जो प्रिंसिपल ऐक्ट का हो गया प्रिंसिपल ऐक्ट की भाषा इनकारपोरेट हो गयी। जो संशोधन में है वह सेक्शन ४३ है। सेक्शन ४३ जैसा होगा वह ग्रप्लाई किया जायगा। इसलिये प्रिंसिपल ऐक्ट ग्रगर न हो तो उनकी ग्रापित नहीं रहेगी। इसलिये ग्रगर इस विषय को लिया जाय तो मेरी प्रार्थना है कि 'ग्राफ दि प्रिंमिपल ऐक्ट" हटा दिया जाय। इसको हटाने के बाद ठीक हो सकेगा। तब इस पर गौर किया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष—विघेयक में यह दिया हुन्रा ह--

"has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43"

४३ घारा किस ऐक्ट की है?

श्रो मोहन लाल गौतम—सेक्शन ४३ जब यहां श्राया तो सेक्शन ४३ जैसे श्रमेंडेड होगा वह मी एप्लाई हो जायगा श्रोर श्रमेंडेड का मतलब यह है कि पांच, तीन, दो या एक जो भी होगा, वह ४३ में इन्क्लूड हो जायगा, ऐज श्रमेंडेड और यह प्रिसिपल ऐक्ट में फिर इन्क्लूड नहीं होगा, बिल्क उसकी भाषा इनकारपोरेट हो जायगी।

श्री ग्रध्यक्ष-माननीय बालेन्दुशाह जी को ग्रब तो इसमे कोई ग्रापत्ति नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां, कोई ब्रापित नहीं है। जैसा में कह रहा था अब्बुल मुईज खां जी की जो पहली श्रापित है उसके सम्बन्ध में में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो रामनरेश जी शुक्ल ने कम्प्रोमाइज के सम्बन्ध में कहा उसके संबंध में एक यह "एनकडोट" पेश करना चाहता हूं। एक समय ऐसा हुआ कि एक नेरो बिज में जहां दो गाड़ियां इक्ट्रिश पास नहीं कर सकती थीं एकाएक दो दिशाओं से दो गाड़ियां आ पहुंची। एक तो उनमें बड़ी ट्रक थी और दूसरी छोटी सी गाड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि पुल पर ट्राफिक जाम हो गया। बड़ी गाड़ी वाला अपनी बड़ी गाड़ी के श्रहंकार और जोश में चिल्लाकर कहने लगा "आई नेवर बंक फ़ार ए

[महाराज बुमार बालेन्दु शाह]

फूल" (मैं किसी बेवकूफ की खातिर गाड़ी पीछे कभी नहीं हटाता।) छोटी गाड़ी वाले ने जवाब दिया "ग्राई ग्रालवेज इ" (में हमेशा हटा लेता हूं।) ग्रीर उसने गाड़ी बैक कर ली। यही हाल यहां पर है। इस बहुमत की गवर्नमेंट का सोमना हमें करना है। "फूल" का उदाहरण में उसी रूप में पेश नहीं करता, लेकिन जब यह प्रतीत होता है कि बात चाहे ठीक हो या गलत हो उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो एक प्रकार से जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि चाहे यह सत्त हो इस को स्वीकार कराने की कोशिश हमारी तरफ से है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना कहेंगा कि वह इस कम्प्रोमाइज के फार्मुले को सत्तू के समान ही समझें। जो सिमली उन्होंने दी है मे भी उससे सहमत हं और में भी यह चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के पंचीं का चुनाव खुल्लमखुल्ला हो। उसमें किसी प्रकार से भी न किसी प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी का, न माननीय मन्त्री महोदय का ग्रौर न किसी का भी प्रभाव उसके अपर पड़े। कोई भी बाधा किसी तरह के उनके काम न पड़े भौर न कोई किसी प्रकार की ग्रहचन उसमें डालने की कोशिश करे। यह जो फार्मुला हमारी तरफ से दिया गया है वह ऐसा है कि सरकार की जो यह इच्छा है कि उसमें किसी हद तक न्याय पंचायत की निगरानी रहे तो वह भी हल हो जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राम नरेश जी ने कहा था कि प्रेस्का-इब्ड प्रयारिटी के द्वारा एलेक्शन कराने में फायदा है, किन्तु चुने हुये न्याय पंचों के द्वारा स्वीकार करने में बहुत अन्तर है इसलिये कि मनमानी नहीं हो पायेगी। किसी प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी की बात को ग्रस्वीकार करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को हिम्मत ग्रीर करेज दिखाना पड़ेगा। यदि जैसाकि में समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ऐसी हिम्मत रखते हैं ग्रौर ऐसा करेज उनमें होगा तो फिर उनके सामने इस सुझाव से कोई ग्रापित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत के लिये चुन लिया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय या प्रेस्काइब्ड ग्रथा-रिटी उसको डिसएप्रुव कर सकती हैं। जहां तक इसका प्रेक्टिकल सवाल है उसमें कोई ऐसी समस्या दिलाई नहीं देती जिससे माननीय मंत्री महोदय के सामने कोई बड़ी बाधा रास्ते में दिलाई पड़ती हो। इसलिये में प्रधिक न कह कर प्रन्त में यह कहुंगा हालांकि माननीय राम नरेश जो इस बात से सहमत हैं कि गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत बने, किन्तु यह सम्भव है कि रामनरेश जी की भावना भिन्न हो सकती है। रामनरेश जी सही हों या में सही हूं यह एक ग्रसंगत बात है। जहां तक में समझता हूं इस सम्बन्ध में वही न्याय हमको मानना चाहिये, जिसको जनता न्याय समझे। हमारे बीच में यदि चोरी हो तो उस ब्रादमी को न्याय मिले। हम विशेषरूप से चाहते हैं कि यह सम्भव हो कि यदि गाव में किसी प्रकार की चोरी हो जाय ग्रौर उसके सम्बन्ध में जनता वर्तमान कायदे के ग्रनुसार उसको कोई उतना ग्रपराध गम्भीर न समझे तो हमको इस पर एतराज नहीं होना चाहिये । न्याय पंचायत जनता के बीच में न्याय पहुंचाने के लिये स्थापित की जा रही है न कि माननीय मन्त्री महोदय या माननीय रामनरेश जी के या मेरे विचार के ग्रन-सार जो न्याय हो उसको प्रचलित करने के लिये। इसलिये ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा यह विश्वास है कि मेरे संशोधन से माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर कोई ब्राधात नहीं पहुंचता है ग्रौर हालांकि मुझे यह संशोधन मजबूरी की हालत में पेश करना पड़ा किन्तु 'सम थिंग इज बैटर दैन नियग' के अनुसार मेने इसको पेश किया है और मेरा विश्वास है कि यदि वह इसको स्वीकार कर लेते है तो इससे जनता के बीच में न्याय पंचायतों की प्रशंसा बढ़ेगी। न्याय पंचायतों के ऊपर उनका विश्वास ग्रोर भरोसा बढ़ेगा। यदि इसको माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार नहीं करते है ग्रौर जिद में प्राकर अपने द्वारा ही नियुक्त किये गये पंचों को जनता के बीच में स्थापित करते हैं जो कि एक प्रकार से उनकी ही सरकार स्थापित होती है तो मुझे भय है कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर माननीय मंत्री महोदय को और मुझे पूरा फाउन्डर होने का अन्देशा है।

*श्री मोहनलाल गौतम—श्री बालेन्दुशाह ने मुझे यह कहा कि मैंने इस विधेयक को यहां पर रख कर सदन का प्रपमान किया है तो उस वक्त मुझे खयाल ग्राया कि कैसे ग्रपमान हुग्रा ग्रीर क्या हुग्रा। क्योंकि मेरे दिमारा में यह नहीं था, लेकिन में यह ज़रूर समझ गया कि जिस माननीय सदस्य के दिमारा में इस विधेयक को रखने से ग्रपमान होता हो उन्होंने स्वयं इस पर

^{*}बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस्तखत किये, जब कि यह विधेयक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से इस सदन में श्राया तो उन्होंने ही इस मदन का श्रपमान किया। सवाल यह है कि मेरे दिमारा में तो सदन का श्रपमान नहीं था, लेकिन जिस माननीय सदस्य ने सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से इस पर दस्तखत किये श्रौर यह कहा कि प्रवर समिति के कुछ निर्ण में में वह श्रपने संशोधन लाने के श्रधिकार को सुरक्षित रखते हैं, श्रर्थात् इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि विधेयक सदन में न रखा जाय बल्कि यह कहा कि रखा जाय श्रौर वह उसमें संशोधन पेश कर सकें। तो उनके श्रव के स्टेट पेंट के हिसाब से क्या प्रायश्चित वह करें, यह वह खुद जानें। कम से कम मेंने सदन का श्रपमान करने के लिये विधेयक यहां नहीं रखा।

बहस कुछ इधर उधर हो गई। जो लोग यह समझते थे कि इलेक्शन ठीक है श्रौर जब उघर का ग्रमेंडमेंट नामंजूर हो गया तो माननीय गेंदा सिंह जी ने ग्रौर कुछ ग्रौर माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहस करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन इसमें भी हो। इसका तो मतलब यह है कि ग्रयारिटी ग्रभी प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी रहे चाहे उसके नामीनेट करने की बात हो या करफर्म या एप्रव करने की हो। बालेन्द्रशाह जी का संशोधन सिर्फ रिकमेंडेशन की हैसियत रखता है। प्रैस्काइ ब्ह प्रयारिटी को कन्फ़र्म या एप्रव करने का ग्रधिकार है, चाहे वह माने या न माने । यहां इलेकान नहीं है, यहां सिर्फ रिकमेंडेशन है क्योंकि ग्रगर रिकमेंडेशन कन्फर्म नहीं होगी तो वह मानी नहीं जायगी। प्रब सवाल यह है कि क्या भ्राप भ्रपने पंचों को इस हैसियत में डालना चाहेंगे कि उनके चुने हुये को प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी नामंजुर कर दें। ग्रगर उसने नामंजुर कर दिया ग्रौर कोई पंचायत गुस्से में प्राकर यह कहे कि हमने इन ५ ग्रादिमयों को रिकमेंड किया श्रीर चुंकि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी ने नामंजूर कर दिया तो हम दूसरी सिफ़ारिश नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति के लिये बालेन्द्रशाह जी की स्कीम में कोई प्रावीजन नहीं है। इसलिये वह वक्तबिल नहीं है। में पंचों को इस पोजीशन में नहीं डालना चाहता कि प्रेस्काइ ड प्रथारिटी उनकी रिकर्मेंडेशन को नामंजर कर दे। कोई भी स्कीम पूरी होनी चाहिये। बीच की चीज, जिसे कि गोल्डन रूल समझा जाता है, उसमें गड़बड़ होने का अन्देशा रहता है। पंचों ने सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया, लेकिन प्रेस्काइन्ड ग्रथारिटी ने नामंजुर कर दिया तो डेडलाक हो गया, तो फिर पंचायती ग्रदालत कैसे बनेगी ? प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी उनकी स्कीम में फ़ाइनल है प्रयात ग्रन्तिम ग्राज्ञा उसकी चलेगी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रेस्काइब्ड ग्रथ। रिटः साफ नहीं है। मे उनसे निवेदन करूंगा कि इस ऐक्ट में एक तालिका दी हुई है और प्रेस्काइब्ड अथारिटी जगह जगह पर म्रलहदा-म्रलहदा है। म्रांडिट करने के लिये, इंस्पेक्शन करने के लिये, म्रलहदा होगी, इसी तरह है। माननीय सदस्य इस तालिका को देख सकते है। भ्रब कई साहेबान कहने लगे कि थाने-बार प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी हो जायगा। ग्रगर ऐसा होगा तो बालेन्द्शाह जी की स्कीम में वही थानेदार प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी रहेगा भ्रौर वही फ़ाइनल वर्ड होगा। इसलिये प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के बारे में भ्रधिक बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बालेन्द्शाह जी ने प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को माना है भौर माना ही नहीं है बल्कि उतना ही माना है जितना कि मैने माना है। उन्होंने कहा कि यह एक समझौता है, लेकिन यह समझौता ही नहीं इसमें दोनों की ग्रन्छी बातों को तो छोड़ दिया गया है और गलत बातों को ले लिया गया है और इस तरह से यह समझौता पेश किया गया है। इसलिये मुझे यह मंजूर नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जहां तक ग्रपमान का सवाल है मेरा विचार यह है कि सदन के सामने जो विधेयक पेश हुग्रा है, उसमें मुख्य बात प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी की है जिसकी परिभाषा भी इस विधेयक में नहीं है ग्रौर उस पर यह विधेयक बहुत हद तक निर्भर है। ऐसी हालत में भी सरकार बहुमत के जोर से एक प्रकार से हम लोगों से सफ़ेद काग्रज पर दस्तखत करा लेना चाहती है। यह सदन का एक प्रकार से ग्रपमान है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह सफाई नहीं है। ग्रापन कोई नोट ग्राफ डीसेंट भी नहीं विया, दस्तखत कर दिये ग्रौर कहा कि पेश कर वो। मैंने उनके कहने से पेश कर दिया, इसमें मैंने क्या ग्रयमान कर दिया ?

र्धः प्रध्यक्ष-यह बहस नहीं है । उनको जो पर्सनल ऐक्सम्लेनेशन देना था. उन्होंने दे दिया ग्रब उसका परिचाय माननीय सदस्यों के हृदयों पर जो कुछ होना है होगा।

प्रश्न यह है कि खंड १४ के अन्तर्गत प्रस्तायित धारा "12-A" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"12-A. For the purpose of electing numbers of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five tool? In hy lesser number is fixed in any case as shall exceed by such numbers the number prescribed under sub-section (2) of section 12, but only such of them as rem in after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as alloresald under section -3 for membership of the Nyaya Panchayat, and approved and confirmed by the Prescribed Authority, shall be members of the Chen Panchayat."

(प्रक्त उपस्थित किया गया श्रीर कृश्रा।)

श्री तेज प्रताप निर् (जिला हमीरपुर)—ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, मै समझता हं कि.....

भी मोहत लाल गैहम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पहले यह फैसला हो जाना चाहिये कि जब मेम्बर्स के इलेक्ट होने का एक ग्रमेंडमेंट गिर चुका है तो क्या फिर पेश किया जा सकता है। सदन जिस चीज को अस्वीकार कर चुका है माननीय तेज नारायण जी का संशोधन उसको कवर शरता है।

श्री ग्रध्यक्ष-श्री तेज प्रताप सिंह जी ग्राप बतायें कि इसमें फर्क क्या है ?

श्री तेज प्रताप सिंह—विष्णुदयाल जी का संशोधन तो सिर्फ यह था कि वे इलेक्टेड हों लेकिन उसमें यह निश्चित नहीं था कि कहां से इलेक्टेड हों, परन्तु मेरे संशोधन में यह है "from amongst themselves."।

श्री स्रध्यक्ष--इसमें थोड़ा सा अन्तर जरूर हैं। इसके पेश करने की में इजाजत देता हूं।

श्री मोहन लाल गैतिस — श्रध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि जिस समय संशोधन पेश किया गया था उस समय ही श्रमेंडमेंट पर श्रमेंडमेंट पेश कर दिया जाता। इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है श्रीर इस तरह से एक एक लफ्ज बढ़ा कर श्रलग श्रलग श्रमेंडमेंट पेश करने की इजाजत श्रापने दे दी तब तो सदन का बहुत समय लगेगा। तो में प्रार्थना करता हूं कि श्राप इस पर श्रपनी व्यवस्था दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष—यह तो उस वक्त प्वाइंट ग्राउट नहीं हुग्रा । यह तो एजेंडे पर भी था । ग्रगर उस वक्त यह सुझाव श्रा जाता तो में इस तरह की बात स्वीकार कर लेता ।

श्री मोहन लाल गौतम—तो ग्रागे के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाय, तो ठीक है।

श्री ग्रध्यक्ष—हां , ग्रागे के लिये हो जायगी ।

श्री तेज जतांप लिह— बादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी भ्राज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा "12 - A" की पंक्ति ७ में शब्द "after" तथा पंक्ति ६ में शब्द "for" के बीच के शब्द हटाकर निम्नलिखित रख दिये जायं— "They have elected five persons or such lesser number as aforesaid from amongst themselves."

यह जो संशोधन साननीय मंत्री जी इस सदन के सामने लाये है नै समझता हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इसमें खासतौर से न्याय पंचायतों के संगठन के बारे में एक नया प्रोविजन रखा गया है। ग्राम सभाश्रों, ग्राम राज्य की जो कल्पना की गयी है उसके हो ही ग्रंग हं। एक तो ग्राम पंचायतों का श्रौर दूसरा न्याय पंचायतों का। इसीलिये यह एक विशेष महत्व रखता है जब उसके संगठन के बारे में हम कोई तब्दोली करते है ग्रौर इस महत्वपूर्ण मनले में

श्री ग्रध्यक्ष—एक बात में इस संशोधन में देखता हूं जो महाराज कुमार बालेन्द्रशाह जी के संशोधन में भी थी "Those persons elected by the Gaon Sabha have from morgst themselves elected five persons or such lesser number" तो इन शब्दों में ग्रीर उसमें क्या ग्रन्तर है?

श्री तेज प्रनास सिंह अध्यक्ष महोदय, उनके संशोधन में था "and approved and confirmed by the prescribed authority."

श्री ग्रय्य — लेकिन वह प्रिसपल तो उसमे ग्रा चुका है "those persons elected by the gaon sabha"। जब यह चीज पहले ग्रा चुकी है तो फिर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री तेज प्रनाप सिंह—श्रीमन् उसमें है कि "and approved and confirmed by the prescribed authority 1"

श्री अध्यक्ष --तो श्राप उस सिद्धांत को हटा देते हे ?

श्री तेज प्रताप सिंह-- जी हां।

श्री ग्रध्यक्ष—तो ग्राप मुस्तसर ही बोलें इस पर ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिये क्योंकि यह स्वल्प संशोधन है।

श्री तेज प्रताप सिह—तो यह जो दंलील दी गयी है, में समझता हूं कि खासतौर पर इस एलेक्शन से पार्टीबन्दी बढ़ेंगी। मैं समझता हूं कि पार्टीबन्दी के इस युग में डेमीकेसी का प्रोसेस रोका नहीं जा सकता और हम सबको इस बात का भान होगा कि हर गाँव में पार्टीबंदी है। तो यह तर्क पेश करके ग्रगर इस तरह का तर्क करें कि पार्टीबंदी इस नामिनेशन से खत्म हो जायगी, यह नहीं होगा । दूसरे जो हम नामिनेशन करने की व्यवस्था लाते हैं तो इस संशोध य के द्वारा यह प्रेंस्काइब्ड श्रथारिटी ग्राती है तो भ्राखिर नामिनेशन किस प्रकार हो। नामिनेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा हो जो इतना महान हो, जो जेनरल विल रेप्रेजेंट करता हो। तब यह माना जा सकता है कि वह ग्रामीण जनता की भावनाम्नों को ध्यान मे रखते हुए एक सही बात करता है और उससे फिर कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो काम करता है वह सब के हित में करता है और वह इतना महान् है तो इसमें कोई ग्रापत्तिनहीं हो सकती। लेकिन श्राज जो समाज का नैतिक स्तर गिरा हुआ है उसको सभी स्वीकार करते है और तब हमारे लिए यह प्रक्त उठता है कि ऐने समय में जब कि हमारा नैतिक चरित्र इतना ऊंचा नहीं है तब हम ग्रांखिर क्या व्यवस्था करें। तब ऐसा प्रश्न ग्राता है कि हम उन्हें ग्राम समाजों पर, उन्हीं प्रामीण भाइयों पर यह जिम्मेदारी छोड़ें कि वह अपना कान स्वयं करे जिससे उनका स्तर ग्रपने ग्राप ऊंचा होगा । जब उनकी जिम्मेशरियां उन पर होंगी तभी उनका चरित्र निर्माण हो सकता है, ग्रन्यथा श्रगर बाहर से कोई व्यवस्था कायम की जाय तो यह हो नहीं सकता है। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि प्रेस्त्राइब्ड ग्रथारिटी द्वारा जिन व्यक्तियों का नामिनेशन होगा वे सही न्याय कर सकेंगे या नहीं, इस विषय में दोनों पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जितने भी व्यक्ति उस पेनल में चुने जायंगे तो यह स्वाभाविक है कि सभी में यह महत्वाकांक्षा होना लाजमी है ग्रौर वह होती है कि मै न्याय पंचायत में जाकर काम करूं और यह प्रकट भी होगा कि ५ या उससे कम जो संख्या होगी वही न्याय पंचायतों में काम करेगी। तो इससे यह भावना पैदा होती है कि सभी इस कमेटी में जाना चाहते हैं भौर उसके लिए दौड़ धूप शुरू हो जाती है। आज के नैतिक स्तर से यह जाहिर है कि दौड़ धूप

[बो तेज्ञताप सिर्]

ग्रौर एत्रोचेज जहर होगीं ग्रौर उससे उन्हीं का स्तर नहीं गिरेगा वित्क उन जिम्मेदार व्यक्तियो का भी स्तर गिरने का भय है, जो ऐसी कोशिश करने के लिए मजबूर होंगे। जबकि हम ऐसे मंकट के ममय मे गुजर रहे है तब तो नैतिक स्तर ऊंचा करने की श्रौर भी श्रधिक श्रावश्यकता है श्रौर हमें ऐसी प्रणाली को मौका न देना चाहिए जिस से हमारे जन-समाज श्रौर विशेष कर ग्राम-समाज उसमे बंचिन रहें ग्रौर उसका स्तर निरन्तर गिरता चला जाय । बार बार हमारे नेताग्रों ने यह बान कही है कि हमें किमी दूसरे पर निर्भर न रहना चाहिये, श्रौर किसी का भरोसा न करना चाहिए. ग्रपने पैरों पर खडा होना चाहिए। उन्हीं भावनाग्रों से प्रेरित हो कर मैने यह संशोधन रखा है ग्रीर ग्राजा है कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। माननीय सदस्यों ने जिम पंचायन राज्य ऐक्ट को पास किया था वह निस्संदे सराहनीय है और वह इतिहास में एक विशेष स्थान रखना है। यह भी मत्य है कि समय बदलने पर कुछ चीजों में संशोधन करने की भी भ्रावश्यकता होती है लेकिन उनमें रहोबदल करते समय हमें इस बात का ध्यान भ्रवश्य रखना चाहिए कि हम जिन लोगों को यह शक्ति दे रहे है भ्रौर जिनमे यर प्रणाली कायम करने जा रहे है उनके नैतिक स्तर में इस से गिरावट तो न होगी श्रौर उनकी स्वावलम्बन का भावना तो खत्म न होगी । इसलिए इम बिल में सबसे भ्रावश्यक ग्रौर सब से महत्वपूर्ण यही धारा थी, जिस पर में चाहता था कि माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करूं। हमें उन में इस म्बावलम्बन को बढ़ाना चाहिए, उनमें वह जोश श्रौर जीवन पैदा करना चाहिए श्रौर उन्हें वह शक्ति देनी चाहिए कि जिससे वह लोग त्याय पंचायतों श्रौर दूसरी चीजों में श्रागे बढ़ें श्रौर वह वहां की जनता के विश्वासपात्र बन सके। हम कोई प्रेस्काइन्ड प्रथारिटी जैसी कोई चीज लांद देते है, प्रेस्काइब्ड प्रयारिटी किसी व्यक्ति पर ग्राक्षेप श्रवश्य नहीं है, सब जगह ग्रच्छे बरे हो सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत की बात सामने रखते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस दौड़ धूप भौर नैतिक गिरावट को रोकने का यही एक साधन है। कोई व्यक्ति जो महत्वाकांका रखता हो उसके लिए यह जरूरी है कि वह लोगों में जाय ग्रौर विश्वास हासिल करे ग्रौर तब ग्रागे बढ़ सके। इस कारण में मंत्री जी से विशेष रूप से ग्रनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करके इस संशोधन को वापस कर लें। हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है जब हमारे गांवों में पंचायतें हुआ करती थीं। लोग कहते हैं कि जुडीशियरी की एलेक्टेड नहीं होना चाहिये। हमारे यहां गांवों में एलेक्शन तो दूर रहा हमेशा आपस में फैसले हुआ करते है। गांवों में ऐसे स्थान ग्रब तक मौजूद है जहां पर लोग इकट्ठें हो कर छोटे मोटे मसलों पर विचार करके फैसला किया करते हैं। इस ऐतिहासिक सत्य को घ्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो भ्रपना संसार में एक विशिष्ट स्थान रखता है उसमें हमारी प्रणालियों को भी प्रश्रय मिले उन्हीं जड़ों में पानी डालना चाहिये जिससे वह पौघा मजबूत हो जिससे हम बाहर की श्रोर न देखें कि बाहर कौन सी प्रणालियां चलाई गयीं। हमें ग्रपने यहां की प्रणालियों पर घ्यान देना चाहिए. उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके उन्हीं पर मजबूती से कार्य करने की जरूरत है इस मूलभूत सिद्धांत को हमें छोड़ना नहीं चाहिये। इसलिए में माननीय मंत्री जी से ग्रन्रोघ करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोदय, जो बात मेने उठायी थी उस बात की सफाई ग्रभी तक नहीं हो पायो। वह यह कि विष्णुदयाल जी ने कहा था कि वे मेम्बर चुन ले ग्रीर ग्रापने कहा कि ग्रपने में से ही चुन लें। विषेपक की जो यह घारा है वह कहती है कि गांव पंचायतों के कुछ मेम्बर होंगे। गांव सभाग्रों की तरफ से न्याय पंचायतों के लिये जितने सदस्य चुन जायंगे वह दोनों की संख्या मिलाकर चुने जायंगे ग्रौर उसमें जितनी न्याय पंचायत के लिए संख्या होगी जब प्रेस्काइन्ड ग्रथारिटी उनको छांट देगी तो बाकी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। मान लीजिये कि २१ ग्रौर ३ गांव पंचायत श्रौर न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाने वाले है तो २४ चुने जायंगे ग्रौर उनमें से तीन छंटने के बाद ही २१ रहेंगे। जब तक २४ नहीं चुने जायेंगे तब तक २१ कैसे रहेंगे तो एमंग्स्ट दंमसेल्ब्ज उसमें इम्प्लाइड है ग्रौर उसके बिना तो स्कीम ही वर्क नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष-यह प्रस्तुत संशोधन की वैधानिकता के ऊपर दूसरा तर्क माननीय स्वरासन मत्री ने उपस्थित किया है उसमें काफी बल हैं।

श्री नेजश्रताप सिह—ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे ग्रौर विष्णुदयाल जी के संशोधन मं फर्क है। म नहीं चाहता कि उस पर कोई बंधन रहे। मं यह चाहता हूं कि ग्रपने में से वे बुद चुन ले ग्रौर विष्णुदयाल जी का जो संशोधन था उसमें था कि एलेक्ट कर दे।

श्री ग्रध्यक्ष—उसमे इसमे कोई ग्रन्तर नहीं होता । उनका खयाल यह है कि ग्रादमी द्वाट निये जायेगे जो चुने हुए सदस्यों में से ही होंगे ।

श्री नज प्रताप सिह-वह एमंग्स्ट देमसेल्ब्ज नहीं होंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष—उन्हे ग्रपने में से ही लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रागे यह दिया है कि बाकी जो बचेगे वह गांव सभा की चुनी हुयी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। उनका यह कहना तकंयंगत मालूम होता है ग्रौर परिणाम में दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं है। इसलिए में इसको ग्रबंध करार देता हूं क्योंकि ग्रापने उसका कोई उत्तर ठीक दिया नहीं।

श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राज्ञा से निम्निनिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

'खण्ड १४ में प्रस्तावित घारा 12-A निकाल वी जाय।"

ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें कई धारायें है ग्रौर एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि म इस खंड का विरोध कर रहा हूं लेकिन चूंकि कई धाराग्रों से इसका सम्बन्ध हूं इसीलिए मने यह संशोधन किया है कल से कई बार इस न्याय पंचायत के बनाने के सम्बन्ध में विचार विनिमय हुन्ना हूं। कुछ ऐसे फारमूले भी लाये गये जिनको कम्प्रोमाइजिंग कहा जा सकता है...

श्री ग्रध्यक्ष—ग्राप 'कम्प्रोमाइज फार्मूला' शब्द तो कहें लेकिन 'कम्प्रोमाइजिंग' शब्द न कहें क्योंकि उसका ग्रर्थ जरा ग्रापत्तिजनक हो जाता है।

श्री गेदा सिंह-सुलह करने की कोशिश तो की गयी थी लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने मानने से इन्कार कर दिया। इसलिए मजबूर हो करके हमको कहना पड़ रहा है कि इस खंड को यहां से निकाल दिया जाय। में समझता हूं कि इस खंड को निकाल देने से कछ कठिनाइयां सामने ग्रा सकती हं लेकिन जितनी कठिनाइयां इसके रहने से ग्रायेंगी उससे कम कठिनाइयां इसके निकाल देने से आयेंगी। न्याय पंचायत के सम्बन्ध में मेने कल भी कुछ निवेदन किया था और में ब्राज भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि न्याय का स्थान ग्रगर ऐने लोगों से ब्रख्नुता रखा जाय जिनका शासन से सम्बन्ध है तो यह ज्यादा ब्रच्छा होगा, जनता के लिए, सरकार के लिए और जिनके ऊपर इन्साफ का बोझ होता है उनके लिए या को इन्साफ कराने के लिये जाते हैं न्यायाधीशों के पास, इन सब के लिए अच्छा होगा और बहुत सोचने समझने के बाद हमारे संविधान में इस बात की गुंजाइश की गयी थी कि जितना भी जल्दी हो सके न्याय और शासन को पृथक कर दिया जाय। उसके अनुसार हमारे प्रदेश में भी चाहै वह नाममात्र को ही कहा जाय-फिर भी यत्न तो किया गया है कि न्याय और शासन को प्यक प्यक किया जाय सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पंचायत के कानून पर संशोधन करने के लिये एक कमेटी बैठी। उस कमेटी में ऐसे माननीय सबस्य हं जिनकी बुद्धि पर हम भी भरोसा कर सकते हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ लेने के बाद जो अपनी राय कायम की, मं नहीं समझता कि उस राय को बदल देने का क्या कारण सरकार के पास है। में समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इस बात पर स्राज जरूर प्रकाश डालेंगे। मेरा उनसे यह बहुत नम्र निवेदन है, आरजू है कि जिस कमेटी के चेयरमैन वे थे उस कमेटी में उन्होंने कभी इस प्रकार की राय नहीं दी कि न्याय पंचायतों का गठन इस प्रकार से होना

[श्री गेंदा सिंह]

चाहिए जैसा कि विघेयक में हे श्रौर न किसी माननीय सदस्य ने उसमें से श्रपनी ऐसी राय जाहिर की कि न्याय पंचायतों का इस प्रकार संगठन होना चाहिये। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की की को लेक उसका के कि स्वयंत्रक.

सामन भाषा 📑 उसका होता है कि उसने उस पर भी अपनी सम्मित दी और यह कहा कि जो यह सोचा जा रहा है कि न्याय पंचायतों को नामजद किया जाय यह गलत बात है। उन्होंने एक मत से यह कहा कि जो इस समय प्रया प्रचलित है गांव सभाग्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की वही प्रथा प्रचलित रहती चाहिये। माननीय वजिवहारी मिश्र, माननीय स्वशासन मंत्री जी ग्रौर भी माननीय सदस्य उस तरफ के रहने वाले ग्रौर माननीय मललान सिंह जी ग्रौर बड़े बड़े ऐसे लोग उस कमेटी मे में रहे है जिन पर में समझता हूं कि कम से कम इस पंचायत की रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध मे में उंगली नहीं उठा सकता । उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इस पर विचार किया है और इस रिपोर्ट को लिखा है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आ जाने के बाद सरकार को कुछ होश माया या बेहोशी हुयी, दोनों बातें कही जा सकती है। सरकार को यह खबर थी कि यह जो कमेटी बनी है उस कमेटी की ऐसी रिपोर्ट श्रायेगी जिससे वह इन पंचायतों को जिस प्रकार चाहे घूमने वाली बना सकती है। मगर यह रिपोर्ट दूसरे प्रकार की ग्रा गयी। इस तरह से, पूरी तरह से एक्सपोज्जर हमने कभी सरकार को होते हुए नहीं देखा । कम से कम इस ग्रसेम्बली के मेम्बरी के जीवन मे। जिस प्रकार इस सरकार का श्रस्पष्ट रूप जो है वह इस विधेयक द्वारा दिखायी दे रहा है। इस विधेयक के लाने से, मुझे कुछ ऐसा लगता है ग्रध्यक्ष महोदय, कि इस विघेयक का सम्बन्ध शायद जिला बोर्डों के चुनाव से भी है। हालांकि इस विघे-यक में कहीं जिला बोर्डों से सम्बन्ध रखने की बात नहीं की गयी है। जिला बोर्डी का ग्रब तक जो चुनाव होता या वह प्रत्यक्ष चुनाव होता या । लेकिन ग्रब सुनता हूं कि जिला बोर्डों के चुनाव का इन पंचायतों के चुनाय से सम्बन्ध होगा श्रोर जिला बोर्डो का चुनाव श्रप्रत्यक्ष रूप से होगा तो मुझे कुछ ऐसा संदेह होता है कि इन पंचायतों को सरकार ऐसा बनाना चाहती है कि इसी बुनियाद पर फिर जिला बोर्ड भी ऐसे ही बनें जैसी की सरकार की इच्छा हो, या होगी। श्रब मे न्याय पंचायतों के बारे में इस समय कह रहा हूं कि सारे विधेयक के देखने के बाद ऐसा लगता है कि साधारण तौर पर एक भ्रादमी को शिकायत हो सकती है कि क्या जिला बोर्डों के चुनाव को दृष्टि में रख कर तो ऐसा भेद नहीं किया जा रहा है। जहां कहीं भी हो

श्री ग्रध्यक्ष—इस विघेयक में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में तो कुछ है नहीं। श्राप कल्पना करके हमला कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—में कल्पना की दुनिया में तो नहीं रहना चाहता । में भी जो सामने हैं उसी को देखना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी इस तरह की कल्पना होती हैं जिसको मंने कह दिया। तो में यह जानना चाहूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी से कि श्राखिर उस कमेटी की रिपोर्ट से क्यों नाराज हो गये श्रीर उनकी बेशकीमत राय जो हमारे सामने इस सदन में श्रा रही हैं उससे उन बेचारे माननीय सदस्यों को जो उनकी कमेटी के मेम्बर थे क्यों नहीं लाम उठाने दिया। यह उनके साथ बड़ा भारी श्रन्याय हैं कि जो मत इतना कीमती समझते हैं माननीय स्वशासन मंत्रीजी श्रीर श्रपना मत यहां देते हैं लेकिन वही मत कमेटी में नहीं दिया। श्राज वह माननीय सदस्य को बड़ी कठिनाई होती है कि माननीय स्वशासन मंत्री जो जब इस प्रकार का मत सदन में दे रहे हैं तो वे बेचारे भी बड़े धर्म संकट में हैं कि वे क्या करें। जिन्होंने कमेटी में दूसरी राय दी थी। माननीय क्रज विहारी जी मिश्र को में जब कहता हूं कि श्रापने इतनी जल्दी क्यों राय बदल दी, वह तो बड़े बुजुर्ग श्रीर गमभीर श्रादमी हैं, मैं उनसे श्रच्छी तरह परिचित हूं, उनके सामने तो मैं बच्चा हूं श्रीर माननीय मिश्र जी मुझको बच्चा समझ कर एक खिलौना वे देते हैं, कभी वह मुझको समझाने की कोशिश नहीं करते। तो श्रब मैं कम से कम समझने का हकदार हूं श्रीर वह माननीय सदस्य भी समझने के हकदार है कि उनके साथ उस कमेटी

में क्यों ग्रन्याय किया गया । में समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पढ़ी होगी । यह माधारणतौर पर हमें विश्वास है कि चूंकि वे इस कमेटी के चेयरमें न रहे हूं इसलिए वे इसके एक एक पैरा से वाकिफ होंगे । इसमें २६ वें पन्ने से न्याय पंचायत पर जो मत प्रकट हुए हूं शुरू हुये हूं श्रीर काफी दूर तक इस पर विचार किया गया श्रीर ४२, ४३ पेज तक विचार किया गया है श्रीर ऐसे लफ्ज इसमें लिखे गए हूं कि एक बार में माननीय मदस्यों से चाहूंगा कि कम से कम इन थोड़े से पन्नों को जरूर पढ़ ले । इन ५-७ पन्नों को पढ़ने के बाद किर हम लोगों को दलील देने के लिए कोई बात नहीं रह जाती । इसको मेने बड़े गौर में पढ़ा है श्रीर में समझता हूं कि एक बार श्रगर गौर से कोई माननीय सदस्य इसको पढ़ जांय तो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो कुछ भी यहां कहा वह उसे स्वीकार नहीं करेगा श्रीर यह समझेगा कि माननीय स्वशासन मंत्री किसी एक कारण से यहां इस तरह की बात कह रहे है । इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको पढ़ने के बाद श्रपना मत स्थिर करेंगे कि जो न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में इस समय सोचा जा रहा है वह ग़लत सोचा जा रहा है । इसमें, माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्राज्ञा चाहूंगा कुछ पढ़ने के लिये।

श्री श्रध्यक्ष--उसका जो ग्रंतिम फैसला है उतना ही हिस्सा श्राप पढ़ कर सुना दें। ग्रगर पूरी किताब पढ़ना शुरू कर दे तो में इजाजत नहीं दूंगा। श्राप श्राग्सेंटस तो दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह—पूरी किताब तो में नहीं पढ़ूंगा ग्रध्यक्ष महोदय । मे ३७ वें पेज पर २० वे पैराग्राफ से कुछ पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है:—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be any alternative."

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरी गुजारिश है कि यहां की जबात तो हिन्दी हो गयी है। रिपोर्ट हिन्दी शें भी है।

श्री ग्रध्यक्ष-ग्रापके पास हिन्दी में रिपोर्ट नहीं है ?

श्रो गदा सिंह—जी नहीं, श्रध्यक्ष महोदय, भला में ऐसी गल्ती करता ? मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी को पढ़ने में। तो इसमें हैं:—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be no alternative to create the people's tribunals in the rural areas.

"The burden of responsibility fully laid on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gained of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more likely to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayat for themselves."

में समझता हूं कि इन शब्दों को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जरूर देखा होगा। जब इस प्रकार की राय कमेटी ने सर्वसम्मति से दी है तो क्या बात है कि इस वक्त वह राय बदली जाय। न्याय पंचायतों को एक शासन के बिल्कुल जुऐ के नीचे डाल देना उचित नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं और कई माननीय सदस्यों ने संदेह भी प्रकट किया है और वह सफाई चाहते है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी क्या होगी। प्रेसस्काइब्ड अथारिटी के लिये यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटस के संबंध में लोगों की रूचि नहीं मालूम होती कि उनको रखा जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट से एक बात कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटस की इस तरह की एक साजिश है कि न्याय पंचायतों को उनके हाथ से बनवाया जाय।

[श्री गेंदा सिंह]

श्री ग्रध्यक्ष--प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी के सिलसिले में जो ग्राप श्रारगूमेंट्स दे चुके हैं उनको रिपोट यानी दुहरा न करके केवल संकेत मात्र से कह दें।

श्री गेंदा सिह--ग्रध्यक्ष महोदय, में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इसका कोई श्राकार नहीं है तो हमें श्रंधेरे में टटोलना पड़ता है श्रौर उसमें श्रंधेरे में टटोलने से हमारे सामने बड़े लोग मा जाते है मौर उनके सबंध में चर्चा जरूर करना पड़ती है । जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रखना है तो साफ साफ इस बात को कह दिया जाय तो मै समझता हूं कि विरोध कम हो जायगा । हालांकि इस न्याय पंचायत का सही रूप सामने नहीं ग्रा सकता है ग्रीर न्याय के नाम पर में समझता हूं कि शासन का जो भ्राजकल सबसे बड़ा मजबूत एक खम्भा समझा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसे ग्रन्याय करने का ग्रवसर मिल जाता है । उसको शासन के चलाने की परवाह हमेशा है ग्रगर में यह भी कहं तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी कि जो दल इस समय शासनारू ह है, उस दल को वह किस तरह से प्रसन्न कर सके श्रीर श्रागे भी रखने के लिये कामयाब हो सके. जिसकी वजह से उसकी नौकरी पक्की होने वाली है, तरक्की मिलने वाली है। उसी की चिन्ता श्रविक होगी । उसे वह प्रसन्न करने के लिये ऐसे काम कर सकता है जिनका इंसाफ से बिल्कुल उल्टा सम्बन्ध हो, न्याय के नाम को कलंकित करना हो । मैने देखा है श्रपने यहां की जुडीशियरी को वहां पर शासन से संबंध रखने वाले श्रधिकारियों ने जो श्राजकल है पावर में, उस दल के विरोधियों को दबाने की भरसक कोशिश की है । यहां तक कि उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि वह न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है । उसकी न्याय की बात को सब से अधिक दृष्टि में रखना चाहिये बल्कि उसको पार्टी पालिटिक्स और झगड़ों में नहीं जाना चाहिये। इस बात को घ्यान में न रख कर तरक्की देने वाले को प्रसन्न करने के लिये ऐसे ऐसे काम किये जिसके बिल्कुल उल्टा काम जर्जों ने कर दिया । मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि इस सरकार के विरोधियों को उन्होंने नीचा दिखाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन हम घन्यवाद देंगे श्रपने देश की जुडिशियरी की, उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायलय की कि उसने उनकी हिफाजत की श्रौर श्रगर उसने हिफाजत न की होती तो जिसको हम प्रेस्काइन्ड श्रथारिटी बनाने जा रहे हैं, उसके जरिये जहां पर न्याय हो रहा है, उससे बड़ा डिमोक्रेसी की मर्यादा को धब्बा लग जाता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्रापसे यह कहने के लिये माफी चाहूंगा कि मे श्रपने को रिकंसाइल करने के लिये तैयार नहीं हूं कानपुर के मसले में ।

श्री श्रध्यक्ष—में समझता हूं कि वह सदन में न श्रावे तो श्रच्छा है। संशोधन ऐसा नहीं है कि जिसमें श्राइन्दा उठने वाले विषयों पर सदस्य बहस कर सकें या, उन सब विषयों को यहां पर से श्रावें।

श्री गेंदा सिह—में छोड़े देता हूं उसको, लेकिन में यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि क्या हमारे दिल के ऊपर कोई चोट नहीं लगती है ? श्रौर फिर हमसे यह श्राशा करना कि हम प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर भी चुप-चाप इस कानून को पास करा लेने दें ? यह दुराशा है श्रौर हमसे ऐसी श्राशा नहीं करनी चाहिये । हम पूरी मुखालिफत इस संड के सम्बन्ध में करना चाहते हैं श्रौर हम श्रपनी फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में न्याय के काम में शासन के लोगों को हाथ डालने से रोकना चाहते हैं श्रौर

द्भार त्याय के काम में शासन वालों को हाथ डालने से नहीं रोका जाता तो में समझता हूं देश की जो आजादी है—हम डेमोकैसी में आजादी समझते हूं—वह खतरे में पड जायगी। आज डेमोकैसी खतरे में है और आज जो शासन वालों की प्रवृत्ति हो रही है वह यह है कि चाहे जिस तरह से हो सके अपने तरक्की देने वालों को, अपने रखने वालों को, जिनके हाथ मे उनकी चोटी है, उनको प्रसन्न किया जाय। में उस पर कतई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मौजूद नहीं थे, माननीय अज्ञूषण जो ने राजनारायण जी के सम्बन्ध में मिर्जापुर की चर्चा की। आप अगर स्वयं पता लगावे तो आप को मालूम होगा कि मिर्जापुर का बदला राजनारायण जी से कानपुर में लिया जा रहा है।

श्री श्रध्यक्ष—में ममझता हूं कि दो गलतियां एक सही बात नहीं हो सकती। श्रुगर उन्होंने गलती की, ऐसा कुछ मान भी लें, तो मैं तो श्रापको वही गलती नहीं करने दूंगा।

श्रो गेदा सिह--में ब्रापके नोटिस में केवल लाना चाहता था। ब्रापके नोटिस में ला करके बन्द कर देना चाहता हु, उसकी चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन में सिर्फ इतना जरूर कहना चाहगा कि जिन लोगों के हाथ मे शासन की बागडोर है, शासन चलाने का भार है, उनके हाथ में इस काम को न दिया जाय। श्रब स्वशासन मंत्री कह सकते है कि शासन चलाने का भार तो उनके हाथ में भी है, लेकिन एक बात में उनसे नम्रता पूर्वक कह देना चाहता है कि जहां शासन चलाने का एक तरफ भार मिला है, तो हम है प्रजातंत्र की भावना से ब्रोतप्रोत उनको देश की जनता ने शासा चलाने का भार सौप रखा है स्नौर उसका भावना को हम प्रतिष्ठा करते है ग्रौर उनको इसलिये हक है कि वह शासन करें। उसी प्रकार से जनता द्वारा हम और माननीय स्वाशासन मंत्री जी और सभी सदस्यों नेशिल कर राष्ट्रपति का भी चुनाव किया है। राष्ट्रपति का जनता द्वारा उस स्थान पर प्रतिष्ठित होने के बाद उन्होने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है ग्रौर हमारी उस पर श्रद्धा है, हमारा उस पर पूरा विख्वास है । हम सझते हं कि जो कुछ वह करता है, न्याय करता है । हो सकता है कि वह भूल कर रहा हो । मनुष्य के जीवन में भूल भी शामिल है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, इन्सान भूल कर सकता है। इसलिये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाय या हाईकोर्ट का जज हो जाय, उससे में यह नहीं कह सकता कि वह कभी भूल कर ही नहीं सकता । लेकिन हमारे मन मे उसके प्रति कभी यह शंका नहीं उठती कि उसकी नीयत में खराबी है, वह कोई श्रन्य उद्देश्य श्रपने सामने रखकर कोई काम करता है। तो श्राखिर वह तो चुने हुऐ लोगों से नियुक्त किये जाते है, क्या में पूछ सकता ह कि जितने लोग ये प्रेस्काइव्ड प्रथारिटी द्वारा नियुक्त किये जायेगे उनकी निजी तौर पर जानकारी माननीय स्वशासन मंत्री जी को हो सकती है क्या उन्हें भी जनता ने सीधे सीधे शासन करने के तिये ग्रधिकार दे रखा है ? किस डिस्ट्रिक्ट में जिस्ट्रेट को जनता ने श्रपनी तरफ से ग्रधिकार दिया है कि वह शासन करे ? माननीय स्वशासन मंत्री जी उसे नियुक्त करते है या पिब्लक सर्विस कमीशन नियुक्त करता है । तो इस तरह से यह बड़ी पेचीदी चीज है ग्रौर फिर संविधान हमारा यह कहता है कि हम गांव की इकाई को जितना भी श्रधिक से ग्रधिक हो सके बलवान बनायें, संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि पंचायते बनाई जायं, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि पंचायत बनावो, उत्पादन बढ़ाने के लिए । श्राज पंचायतों में खराबियां भी है, मैं भी कहता हूं कि है, न्याय पंचायतों ने ऐसे काम भी किये जिनसे शिकायत हो सकती है। ग्रध्यक्ष महोदय, मै तो बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस बात को कि ग्राज न्याय पंचायतों के सारे काम ग्रगर विश्लेषण किया जाय बारीकी के साथ तो बहुत कम पंच हमारे सामने ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कि ईमानदारी से जैसा चाहिए वैसा काम किया हो। लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि जब कोई दूसरा श्रालटरनेटिव नहीं है तो वैसी हालत में हमको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है । महात्मा गांधी ने तो, १८ वर्ष की उम्र से कहा या कि कांस्टीटुएंट ग्रसेम्बली बनेगी श्रौर उसी के द्वारा, वह जो कुछ करेगी, होगा, यहां तो २१ वर्ष की बात है । २१ वर्ष वाले लोग अपने अपर शासन करने वालों को चुन नहीं सकते, सारा बोझ सरकार ग्रपने अपर लेना चाहती है । सरकार भी अपने १२, १४ ब्रादिमयों का मंत्रिमंडल जो यहां पर बैठा हुआ है, वह अपने को किस बुनियाब पर रखना चाहता है । में उससे दरस्वास्त करना चाहता हूं कि वह क्यों ऐसी भूल कर

िश्री गेंदा मिहें रही हैं । हालांकि बेरा कुछ उसमें बिगड़ता नहीं है। हम तो जहां पर बैठे हुए है, वहां बैठकर यह चाहने ही है. हमारा तो काम ही यह है कि इस सरकार को अपदस्थ किया जाय और उसके लिए इस सरकार को जितनी जल्दी अविश्वासपात्र बनाया जा सके बनाया जाय । मैं सरकार से कहना चाहना है कि जितने अविश्वास का पात्र सरकार पिछले चार पांच वर्षों में इन पंचायतों की कार्चवाहियों से नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा श्रविश्वास का पात्र श्रगले तीन चार वर्षों में अपनी इस कार्यवाही के द्वारा जिसके द्वारा कि वह पंचायतों को श्रौर खास तौर से न्याय पंचायनों को इस प्रकार से बना रही है बनेगी श्रीर में ऐसा भी समझता हूं कि हम में से बहुत कम ग्रादमी चार पांच वर्षों में मरने वाले हैं, हम इन चार पांच वर्षों में देखेंगे कि इसकी ग्रौर यदि फिर कोई कमेटी माननीय स्वशासन मन्त्री जी बैठायेंगे, श्रपने इस विधेयक के मुताबिक काम करने के बाद, तो उस कमेटी द्वारा हमारी इस बात को उस समय एक एक ग्रक्षर मान लेने को तैयार होंगे ' जो न्याय पंचायत भ्राज बनाने जा रहे है वह जनता के लिए उत्तरदायी न होगी, वह उत्तर-दायां होती कान्द्र में के लिए या जिसको वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी बनावेंगे उसके लिए । मै उनमे दरस्वास्त करना चाहता हूं कि उनकी पंचायत की मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है कि जिस मशीतरी के जरिये वह इन न्याय पंचायतों को बना लें। पंचायत में ऊपर पूरी तरह से रेवेन्य डिपार्टमेंट का रोब गालिब है श्रीर इन पंचायतों के बनाने में पूरी तरह से रेवेन्य डिपार्टमेंट का हाथ होगा । वह रेटेन्य डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहा है, हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, गांवों के रहने वाले हैं, उसकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, और वह बात सामने श्रायेगी। श्राज वह रेवेत्य डिपार्टमेंट का कलेक्शन श्रमीन श्रौर कुर्क ग्रमीन कानूनगो श्रौर तहसीलदार श्रौर डिप्टी तक मालगुजारी की वसूली में जो नंगा नाच कर रहे हैं, उसकी पूरी खबर अगर सरकार को न हो तो सरकार डबेगी । फिर उसका हाथ होगा । वहीं डिप्टी कलेक्टर, वही तहसीलदार न्याय पंचायत का बनाने वाला होगा। पंचायत राज विभाग ग्रलग तमाशा देखता रहेगा। पंचायत राज विभाग को हाथ मलने पड़ेगें दो वर्ष के बाद कि हमने बड़ी भूल की। पर से उत्तरदायित्व हटा कर ऐसे कुछ थोड़े से लोगों पर उत्तरदायित्व डोल दिया जिनके सामने यह न्याय पंचायत घटने टेक रही है। माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि नहीं उनका कोई गांवों से मतलब ही नहीं होगा, वह बिलकुल निष्पक्ष होंगें। एक मर्तबा वह पंचायत बना देंगे फिर उसके बाद उनको दखल डेने की क्या आवश्यकता होगी ? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लेखपाल साहब, कानुनगो साहब और दूसरे और साहबान का रोज का संबंध गांवों से है। उन कामों में वह राज दखल टेगें । वह हर न्याय पंचायत मेम्बर को धमकायेंगे कि तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में है । इस बार किया तो किया लेकिन ग्रगर ग्रब से ग्रगर गलती की, में गलती शब्द का प्रयोग कर रहा हं, उनकी निगाह में गलती, किसी दूसरे मानी में होगी, ग्रसली गलती के लिए वह कभी झगड़ा नहीं करेंगे, फिर ब्रागे ब्रापको हम नहीं चुनने देगें ब्रौर मनुष्य की कमजोरी होती है पद, मर्यादा प्रतिष्ठा चाहता है वह । उस प्रतिष्ठा के लिए मैं समझता हूं कि पंचायतों में लोग जायेंगे। जंसा कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने ग्रौर ग्रौर लोगों ने कहा कि वह तो फिर वह करेंगे क्या ? जनता की सेवा करने की बात नहीं सोचेगें। वह दूसरी बात सोचेगे। वह सोचेगें कि जिस तरह से भी हो प्रेस्काइःड ब्रायारिटी को खुश करें और प्रेस्काइब्ड ब्रायारिटी कैसे प्रसन्न होगी, भगवान् जाने।

श्री राम नरेझ शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—ग्रगर ग्राप ही, प्रेस्काइब्ड श्राथारिटी हो गये तब

श्री गेंदा सिंह—श्रध्यक्ष महोदय, जिसके हाथ में बिना लगाम पावर चली जायगी वही खराब हो जायगा। में माननीय राम नरेश जी से कभी इसके लिए दरस्वास्त नहीं करूंगा। श्रगर माननीय राम नरेश जी मुझे ऐसी ताकत दें तो पहले यह सोच लें कि गेंदा सिंह को भी चौपट कर देना है, बरबाद कर देना है। में चाहता हूं कि लगाम लगायी हुई ताकत हमको मिले, में तो यह समझता हूं कि इस सरकार पर जरा ढीली लगाम है जिससे सरकार ऐसे गड़बड़ भी करती

हे कि प्रपोजीशन के लीडर को ही बन्द कर दिया प्रगर हमारे पास कड़ी लगाम होती तो हम कुछ सरकार को भी रोक पाते । बगर लगाम किसी को शक्ति देना खनरे से खाली नहीं है इसीलिए में दरख्वास्त कर रहा हूं कि सेलेक्ट कमेटी में दस मर्तबा दरख्वास्त किया और यहां भी कर रहा हूं और एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं चेतावनी लपज इस्तेमाल करन के लिए म आफी बाहूंगा, डर मुझे इस बात का है कि इस न्याय पंचायत से ग्राहित होवे जो इम कमेटी ने समझा है बिलकुल उसकी राय से में सहमत हूं और उसकी राय को मानने के लिए में इल सदन से दरख्वास्त करता हूं । जिस नतीजे पर कमेटी पहुंची उसे ग्रलग कहीं कोई राय हम कायम नहीं कर सकते । इस कमेटी के सदस्यों ने बड़ी मेहनत की थी, सात ग्राठ दिन नंनीताल में देंठ कर । बहुत से लोगों की राये और रिपोर्ट पढ़ीं गई और उसके बाद सभी लोगों ने राय दी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिये में फिर एक मर्तबे माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि ग्रगर उन की मेहरबानी न हो और न्याय पंचायत हमारे मन के माफिक नहीं बन सकरें। तो वह बनायी ही न जाय यहीं ग्रच्छा है । लेकिन में यह दरख्वास्त करके उम्मीद करता हूं कि इस पर वह विचार करेंगे और इस रिपोर्ट को फिर एक बार पढ़कर उसी के ग्रनुसार न्याय पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे ।

श्री मोहन लाल गातम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जितनो दलीचे इत वक्त दी गई वे सब पहले दी जा चुकी हैं जौर काफी बहस उनपर हो चुकी है। कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो नई हो और जिसका में उत्तर दूं। इसलिये मुझे श्रकसोस है कि में इस संद्रीधन की स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री व्रजिवहारी मिश्र (जिला ग्राजमगढ़)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय गेदा सिंह जी ने ग्रपने भाषण में मेरा खास तौर से जिक किया ग्रीर यह कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है सदन के समक्ष उसमें इस बात का जिक कहीं नहीं किया गया कि ग्रदालती पंचायतें किस प्रकार से चुनी जायंगी। इसीलिये माननीय गेंदा सिंह जी ने यह संशोधन देश किया कि खंड १४ की प्रस्तावित धारा १२—ए निकाल दी जाय। माननीय गेंदा सिंह जी से में विनम्न निवेदन करूंगा कि में उनकी बड़ी इज्जित करता हूं ग्रीर यह भी जानता हूं कि उस पक्ष के टैठने वाले सदस्यों में माननीय गेंदा सिंह जी का प्रमुख स्थान है ग्रीर वह जो बातें कहते हैं बहुत हां उचित ग्रीर रीजनेवल होती हं, में उनका ध्यान ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके द्वारा जे रिपोर्ट है उसके सफे ३४ व ३५ के पैरा १४ ग्रीर १५ की ग्रीर ग्राक्षित करना चाहता हूं। धारा १४ में लिखा हुगा है—

"The constitution of Nyaya Panchayats was the most controversial subject and during the course of prolonged discussion the concensus of opinion in the Committee swayed time and again from one stand point to the other. The main plank of criticism against the Nyaya Panchayats wasthat no elected judiciary could function honestly and efficiently."

श्री ग्रध्यक्ष—म्राप उतना ही हिस्सा पढ़िये जितना ग्रावश्यक हो, उसके पहले का हिस्सा न पढ़िये ।

श्री व्रज विहारी मिश्र—में उतना ही पढ़ रहा हूं जितना ग्रावरवक है ग्रौर जिसकी ग्रोर में माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान ग्राकित करना चाहता हूं। १४ में यह लिखा हुग्रा है कि कमेटी का ध्यान न्याय पंचायतों की ग्रोर गया था कि इन न्याय पंचायतों का कांस्टिट्य्वान कैसा हो इस पर हमने सविस्तार विचार किया था। ग्राया चुना हुग्रा हो या जैसा इस विष्में प्रस्तुत किया गया है वैसा हो। श्रव में माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान पैरा १५ की ग्रोर दिलाना चाहता हूं उसमें साफ तौर से लिखा हुग्रा है——

"Section 43 of the draft Bill contained a proposal that while electing the Gaon Panchayat the Gaon Sabha should elect five more than the required number. The District Magistrate could appoint any five from

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

out of the total number of persons elected by the Gaon Sabha to be Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat. It was argued, in support of this proposal that in this manner the persons appointed to be members of the Nyaya Panchayat would not only enjoy the confidence of the Gaon Sabha but in this process the District Magistrate could select suitable persons; some having experience while others possessing the required educational qualification."

इसका मतलब यह है कि कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया था । माननीय गेवा सिंह जी तथा उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से में प्रार्थना करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात दी हुई है ग्रीर उसने इसको "रूल ग्राउट" नहीं कर दिया है । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मं ग्रापके द्वारा एक ग्रीर बात के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी तथा ग्रन्य माननीय मदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्वाईंट सेलेक्ट कमेटी उसीमें मुझे सौभाग्य प्राप्त था माननीय गेंदा सिंह जी के साथ बैठने का । उसमें भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था ।

श्री ग्रध्यक्ष — सेलेक्ट कमेटी के ग्रन्दर क्या हुन्ना उसकी यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र--मं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। केवल इतना बतलाना चाहता हं कि इस पर भी विचार किया गया था । माननीय ब्रध्यक्ष महोदय यह हम सवका तजुर्बा है क्योंकि हम सब गांव के रहने वाले है कि पंचायतों के बारे में अजीब समस्या उपस्थित हो गई थी । एक सेक्शन तो यह कहता था कि न्याय पंचायतों को बन्द कर दिया जाय और दूसरा सेक्शन कहता था कि पंचायतें रहेनी चाहिये । ५-६ वर्ष तक हमने पंचायतों का तजुर्बा भी किया है । मालुम यह होता है कि माननीय गैंदा सिंह जी और उनकी विचारधारा के अन्य सदस्य इस विधेयक को कुछ सन्देह की दृष्टि से देखते हैं श्रौर वे समझते है कि यह जो विघेयक लाया जा रहा है उससे गवर्न मेंट का इरादा पंचायतों पर ब्रधिकार करने का है, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सन्देह की दृष्टि से इस विघेयक को न देखें, बल्कि हमने जो "वाया मीडिया" निकाला है वह बहुत सोच समझ कर निकाला है कि इलेक्शन-कम-सिलेक्शन से न्याय पंचायते बनाई जाये, क्योंकि इलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां त्राती है और सिर्फ सिलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां त्राती है। इसलिये हमने इलेक्शन-कम-सिलेक्शन को रख कर ट्रायल करने का विचार किया है। बहुत प्रच्छे प्रच्छे लोगों का यह विचार था कि ब्रदालती पंचायतों को समान्त कर दिया जाय, इसलिये ट्रायल के तौर पर ग्रध्यक्ष महोदय, हमने यह संशोधन रक्ला है । में समझता हूं कि इसको सन्देह की बृष्टि से न देखा जाय, इस वृष्टि से देखें कि हम इसका ट्रायल करना चाहते है । हमें श्राशा है कि यह जो प्रस्तावित संशोधन है यह ग्रदालती पंचायतों के कार्य को सफल बनायेगा । इन शब्दों के साथ में त्राशा करूंगा कि माननोय गेंदा सिंह जी श्रपने संशोधन की वापस ले लेगे।

श्रो सीताराम शुक्ल—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैने माननीय गेंदा सिंह जी के व्याख्यान को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना ग्रौर श्रापने चन्द बातें उसमें फरमायी है। उसके उत्तर में में भी श्रपने विचार व्यक्त करूंगा। श्रापने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि श्रगर सब—कमेटी की रिपोर्ट ग्राप पढ़ लें, तो हमारे मिनिस्टर साहब पढ़ लें, तो हमको ग्रौर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सब-कमेटी बनायी जाती है, ताकि काम ग्रासानी से चले। यह जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट सब-कमेटी दे उसको मान लिया जाय ग्रौर ग्रगर उसकी सब बातों को मान लिया जाय, तो फिर हाउस की क्या जरूरत है। क्या ग्राप यह समझते हैं कि माननीय मन्त्री भी ने रिपोर्ट को बिना पढ़े ही ग्रापकी बात का जवाब दे दिया है। उस पर विचार किया है ग्रीर विचार करने के बाद जो ठीक समझा, उसी को यहां हाउस में पेश किया है। नामिनेशन

में पक्तपात की कुछ शिकायतें हो सकती हैं ग्रीर श्री गेंदा सिंह जी को भी वही शिकायतें हैं उन्होंने वही एतराज किये हैं। यह सब एतराज ठीक है। मगर जो रास्ता स्रापने बतलाया है वह तो ग्रीर भी खतरनाक है। क्योंकि पहले ग्रदालत के पंचीं का चुनाव करने का पूरा ग्रधिकार हमारी सरकार ने जनता को दिया था कि जिसको चाहें, लोग चुनें ग्रौर उसका फैसला करें। चेनाव ठीक हो श्रौर सबका फायदा हो श्रौर चुने हुने हमारे सदस्य हों, किन्तु वह सफल नहीं हुँ आ। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि पंचों को जनता चुने और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ६५ फीसदी पंचों की शिकायतें हैं। यह तर्क के विरुद्ध बात है। मेरी गुजारिश यह है कि हर प्रकार में कुछ न जुछ यह दिक्कत पड़ती है इसलिए जिसमें कम खराबी हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरी गुजारिश यह है कि चुनाव का क्षेत्र बड़ा हुआ करता है तो उसमें बुरा ब्रादमी एलेक्ट नहीं हुआ करता है। क्योंकि लोग खुद तो चाहते हैं कि हम तो गलती करें, ग्रौर उनकी गलती श्रोवरलुक कर दी जाय, लेकिन उनका नेता गलती न करे। मसलन एक म्रादमी खुद तो शराब पीता है लेकिन वह यह भी चाहता है कि उसका लड़का शराब न पिये। इसलिए ग्रपना नेता चुनते वक्त वह ग्रच्छे ग्रादमी को वोट देते है किन्तु छोटी जगह में थर्ड क्लास का भ्रादमी ग्रपना प्रभाव जमा लेता है, क्योंकि उसकी गुन्डागीरी उस थोड़े से क्षेत्र में चल सकती है, लेकिन सारे क्षेत्र में वह नहीं चल सकती है। मेरी गुजारिश यह है कि बड़े क्षेत्र के चुनाव में भ्रच्छा भ्रादमी ही चुना जा सकता है, क्योंकि भ्रच्छे भ्रादमी की तारीक हुआ करती है किन्तु बरे ब्रादमी की धमकी नहीं चलती। किन्तु छोटे स्थानीय चुनाव में भले ब्रादमी के लिए वहीं दिक्कत ब्राकर पड़ेगी। भला ब्रादमी जो होता है, वह किसी पार्टी में नहीं पड़ता है, ब्रौर थर्ड क्लास ग्रादमी जो होता है, वह बहुत ग्रसानी से पार्टी बना लेता है ग्रौर उसको ग्रगर किसी की गवाही की जरूरत पड़ती है तो श्रासानी से उसकी गवाही गुजर जाती है, क्योंकि श्राइन्दा के लिए, उसके काम वह ग्रा सकता है। ग्रच्छा ग्रादमी ग्रगर गरीब है, तो वह तकलीफ में ही रहता है, मगर किसी से कुछ मांगता नहीं, उसका भगवान पर भरोसा रहता है, ग्रौर वह यही कहता है कि "हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रिहये।" श्रीर ग्रुपने ऊपर तकलीफ सहन करता रहता है। वह गलती भी कम करता है ग्रीर सब का काम करने को को शिक्ष करता है और पार्टीबाजी में वह नहीं पड़ता है और न यह कहता है कि हमने तुम्हारा काम कर दिया तुम हमारा काम करो । भला ब्रादमी कहीं पर जाता भी नहीं है वह किसी मुकदमेंवाजी में भी नहीं पड़ता है, यदि उससे गलती हो जाती है तो वह भ्रदालत में कबुल कर लेता है। झूठ बोल कर अथवा झूठी गवाही देकर बचने की कोशिश नहीं करता। नतीजा यह होता है कि सत्य-पथ पर चलने के कारण खुद तो प्रसन्न रहता है स्रौर प्रतिष्ठा भी पाता है परन्तु पार्टी नहीं बना पाता । नतीजा इसका यह हुआ कि भले आदमी चुनाव से हट गये कि कौन झंझट में पड़े। नामजदगी में क्या दिक्कतें हं, वह श्रापने खुद फरमाया है। मेरी गुजारिश है कि इसे तोलना यह होगा कि किसमें कम बुराइयां है। इसलिए हमारी सरकार ने बीच का रास्ता ग्रस्तियार किया है। चुनाव की खूबी भी उसके ग्रन्दर है ग्रौर नामजदगी की खूबियां भी उसके अन्दर मौजूद हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने छानबीन कर और समझ बुझ कर इस चीज को निकाला है और उसे आप कहते हैं कि हटा दिया जाय। इस पर तो ग्रापको घन्यवाद देना चाहिए था। इसी सिलसिले में मैं यह भी प्रर्ज कर दूं कि यदि ग्रनुभव से इस प्रणाली में भी परिवर्तन की स्रावश्यकता हुई । परिवर्तन हो सकता है, फैसला बदला जा सकता है ग्रौर मुल्कों में भी चुनाव होता है। ग्रमिरिका में तो जजेज भी चुने जाते हैं, बोट से। लेकिन वहां और यहां में फर्क है कि वह विकसित कन्द्री है। वहां की माली हालत भ्रच्छी है। में जानता हूं, इंगलैन्ड की बात है कि वहां चुनाव हो रहा था। पब्लिक ने विरोधी दन के नेता को हट किया जब वह बोले। तो मेजारिटी पार्टी के लीडर ने कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, यह क्या बात है कि विरोधी दल को बोलने भी नहीं दिया जाता। वहां जो चीज श्रापने फरमायी, वह हो सकती है। लेकिन देश में नया तजुर्बा है, यहां तो विकिग कमेटी श्रीर माननीय मन्त्री बुन्द भी नामजद किये जाते हैं तब पंचीं को क्यों न नामजद किया जाय । **भा**पने नीयत पर आक्षेप कर दिया, शिकायत कर दी। यह वाजे रहे आपको कि

[श्रां सीत राम गुरल]

धोखाधड़ी या चालबाजी से ग्रयवा कानून बनाकर कोई सरकार रह नहां सकती । ग्रगर हमारी मरकार क करेक्टर ग्रच्छा नहीं होगा, हममे मूझ बूझ ग्रौर त्याग नहीं होगा, तो कानून कायदा किमी को बहुत दिन नहीं बचा सकता है। ग्रापन देखा कि पूर्वी बंगाल मे मुस्लिम लोग, जो पादर मे थी। पटरा हो गयी। हमारे चुनाव भी ग्रापने कानपुर ग्रौर बहराइच के देखे। हम ग्रागे बढ़ते जा रहे ह। ग्रभी तो इब्तदाये इक्क है। शुरू मे हमारे साथ कुछ परेशानियां थीं। जरा हमको जनता का खाना, कपड़ा, मकान का प्रक्रन हल करने दीजिये। किर ग्राप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रौर खुद ही बिल लाया जायगा ग्रौर जनना को पूरा ग्राख्तियार दिया जायगा। इन शब्दों के साथ में उनके सम्बोधन का विरोध करता हं।

राजा दीरेन्द्रगाह (जिला जालौन)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मंश्री गेदा सिंह जी के अस्ताव का समर्थन करता हूं। मं श्रापकी श्राज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि पहने ऐक्ट में जो धारा थी, उसे हम रखना चाहते हूं श्रोर इसको निकाल दिया जाय, इस प्रस्ताव का मं समर्थन करता हूं। श्रीयन्, सबसे पहले, तो मं यहां जो श्रभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में बोल रहेथे, उसके बारे में कुछ कहूंगा श्रीर उत्तके बाद मं इस व्याख्या में श्राना चाहता हूं कि यह घारा रखी जाय। श्रभी हमारे पूज्यनी. मिश्रजी महाराज ने १४, १५ पढ़कर मुनाया। मं श्रदब के यह कहना चाहता हूं कि देखा यह जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट में श्राखिरी बात क्या तय हुई, यह चीज महत्व की होती है। बीच की बातों का जिक्र करना उनकी कमजोरा को बतलाता है। श्राखिरी में जो रिपोर्ट सब लोगों ने मिलकर दी, वह यह दी कि न्याय पंचायत का चुनाव सेंडेंब्रान हा। नहीं हो। च हिये। गेदासिंह जो ने इसको गढ नहीं दिया बिल्क उस कमेटी में श्रापके सदस्यों का ही बहुमत था। इसलिए उनका कहना ठीक नहीं है।

दूसरी बात शुक्ल जी ने कही कि रिपोर्ट श्रंग्रेजी में क्यों पढ़ी जाती है। में श्रापके जिय से उन्हें बतला देना चाहता हूं कि इसमें हम लोगों का दोष नहीं है हमको तो इसमें खुशी होती है कि हम सब काम हिन्दी में किया करें, लेकिन यह तो उन्हीं की सरकार का काम है कि प्रस्ताय के पास होने के बाद भी अंग्रेजी में रिपोर्ट दी जाती है, श्रंग्रेजी में पत्र व्यवहार किया जाता है श्रोर इस प्रकार से श्रंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए माननीय शुक्ल जी ने जो कुछ श्रंग्रेजी के बारे में कहा में उसकी सकाई इस प्रकार से दे देना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, जहां तक यह सवाल है कि न्याय पंचायतों में पंचों का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने जोरदार शब्दों में यह कहा कि चुनी हुई पंचायतें न्याय का काम नहीं कर सकतीं। चुनी हुई जुड शियरी नहीं हो सकती। में उनसे इस बात में सद्मत हूं लेकिन जो कांग्रेस सरकार बनी श्रीर उसने जिस वक्त पंचायत राज कायम किया, जिसका बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया श्रीर देश भर में प्रचार किया गया कि उन्होंने बड़ा श्रच्छा कार्य किया है।....

(इस समय ? बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुन्ना न्नौर २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष , श्री हर गोविन्द पन्त की म्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः म्नारम्भ हुई।)

राजा बीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय गेंदा सिंह जो के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा था। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस बहुत दिनों से इस बात का नारा लगाये हुए थी, और कहती थी कि जुरेशियरी और एकजीर्द्राटव को अलग-अलग किया जाय। हमें खुशी है, कि हमारी सरकार ने इस ओर एक कदम उटाया भी और जुरेशियल मैजिस्ट्रेट बनाये गये। लेकिन श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह करने के बाद अब इस बिल में हम देखते हैं सो बिलकुल उसका उल्टा है, यानी न्याय पंचायतों का एप्वाइन्टमेंट एक्जीक्यूटिव के हाथ में देना चाहते हैं और नारा यह लगाया जाना है। श्रीमन्, हमारे माननीय श्री राम नरेश शुक्ल जी ने बड़े जोरों से कहा कि श्रगर इस बिल का १२-ए निकाल दिया जान तो . . .

श्री रामनरेश शुक्ल--ग्रान ए प्याइन्ट ग्राफ ग्रार्टर, सर। म तो ग्राज इस ग्रमेंडमेंट के ऊपर बोला भी नहीं। क्या माननीय सदस्य कल के भारणो का हवाला दे सकते है जो दूसरे ग्रमेंडमेंट के ऊपर हो?

राजा बीरेन्द्र श १ह--जव यह बिल पेश है,को जो भी कांग्रेम पार्टी के मुख्य सदस्य इस मम्बन्ध में कहेंगे, उनकी मुख्य-मुख्य बाते तो श्रीमन् कर्ती ही रहेंगे। इसी वजह में श्रीमन्, में यह कहना चाहता हूं कि माननीय शुक्त जी ने इस धारा की इस बिल की जान बतलायी ग्रीर यह कहा कि अगर यह निकाल दी जाय. तो इस दिल की जान ही निकल जायनी। श्रीमन, में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने भ्रगर इसी उद्देश्य में यह गाप पंचापन मंशीधन बिल प्रम्तुत किया है नव तो मुझे बड़ा दुख है। हम लोग न रझने थे कि जिम तरह ग्रामों मे यह रिपब्लिक कायमें करने के समय हमारी कांग्रेस का दात्रा का और यह नारा लगानी थी कि हमने देहाती क्षेत्रों मे उनको स्वयं इन्तजाम करने के लिए ज्ञियकार दिया और एलेक्सन करने की एक ऐसी ब्रजीब प्रणाली निकाली, जो देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से किसी भी जगह इतना बड़ा एलेक्शन नहीं हुन्ना, जैसा कि हमने अपने यहां कराया। इस सम्बन्ध में बड़े बड़े नारे लगाये गये और एडवरटीजमेट कराये गये। श्रीमन्, म श्रापके जरिष्टे बनलाना चाहता हं कि सरकार जो यह संशोधन लायी है, उसको पाम कराने के बाद वही बड़ो गनती करेगी, जो पहले सरकार यह समझती थी कि न्याय पंचायते कायम करके रिपब्लिक यानी देशनों मे स्वयं इन्तजाम करने की जो एक शक्ति दी है, जो हमने उनको एक चीज दो हे, उसको वापम लिये जाने की सब से पहली चीज होगी। ग्रगर ग्राप यह प्रस्ताय पास करने ह, तो म यह कहता हं श्रीमन, कि सरकार को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ग्रोर जब मायह कहता हं तो इसका मतलब यह नहीं है वि सरकार इस वात को नहीं सोचनी होगी। सरकार भी चाहती है कि देहाती क्षेत्र के लोगों पर उसका प्रभाव पड़े ग्रौर वहां के लोगों से ग्रच्छी तरह से प्रबन्ध करने का विचार पैदा हो। लेकिन में यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह में मेरे भाई गेदा सिंह जी ने इसका समर्थन किया और जो प्वोइन्ट्स रखे, उनको में टोहराना नहीं चाहता, लेकिन में समझता हूं कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, और इसका उदाहरण यह है कि जब मन्त्री जी का उत्तर देने का समय भ्राया तो उन्होंने यहाँ पार्तियानेट्री सेकेटरी को भेज दिया भ्रौर वह इस वजह से क्योंकि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि वह कह सके, शीर एक भी दलील दे सके, श्रौर श्रगर पार्टी व्हिप उठा लिया जाय श्रौर उधर के सदस्यों से राय ली जाय, तो वह हमारे संशोधन से मुत्तफिक होंगे। म बतलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि मन्त्री जी ने कह दिया स्रौर बहुत से प्वाइन्ट जो पहले संशोधन में रखे गये थे उन्हों की स्राड़ लेकर वही प्वाइन्ट्स रख दिये ग्रीर कह दिया कि मुझे ग्रीर कुछ कहना नहीं है। जद ग्राप जनता के हाथ में पावर देने की बात करते है ग्रार डेमोक्सेश की हिमायत करते है तो डेमोक्रेश के माने यह है कि स्रापको हर एक को बात सुनना चाहिए चाहे वह किसी दल मे हो, जिन्होने स्रापको बोट दिया है, वह जनता, सदस्य क्षमा करे, अप के न्याय को मानने वाली नहों है। बार बार कहा जाता है कि चुनाव में यह हुआ और चुनाव हमारे पक्ष में हुआ। यह मुमक्षिन हो सकता है कि एक दो जगह ग्राप जीत गर्ये हों, लेकिन ग्रब ग्रापके कारनामें ऐसे हो रहे है कि प्राप का नामालूम क्या हाल होगा, यह भगवान ही जाने । जब देश भर मे तमाम लोगों की मांग ह कि जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से भ्रलग रखा जाय, तो किस तरह से इस विल मे इस चीज को यह इस तरीके से रखा जा रहा है? मैं समझता हूं कि कहीं भी इस तरह की चीज किसी बिल में न रखी गयी होगी कि जिसमे एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम जुड़ीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलगकरते है, भ्रौर एक तरफ एक्जीक्यूटिव द्वारा इस जुडीशियरी का नामिनेशन कराते हे । ऐसी खराब चीज को सरकार यहां रखना चाहती है, यह चीज हमारी समझ मे नहीं ग्राती है। श्रीमन्, देखेगे कि "प्रेस्काइब्ड ग्रंथारिटी" रख दिया गया है, ग्रौर कहीं पर निश्चय नहीं किया गया र कि उसका क्या रूप होगा। कहा जाता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, या कोई कमेटी बनेगी, इस तरह की नाना प्रकार की मनगढ़न्त लगायी जा रही है। जब यह इतनी अप्तम चीज है, तो सरकार ने क्यों ग्रपनी तरफ से प्रस्ताव ला कर साफ नहीं कर दिया कि

राजा वीरेन्द्रशाह]

"प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी" यह होगी। ग्रगर किसी एक्जीक्यूटिव श्राफिसर को रखना है. तो हमे उसका घोर विरोध है। कभी एक्सपेरिमेट के लिए बिल नहीं बनाया जाता। आपने नैकनियती से जैसे पहले रखा था, उसके मुताबिक ही श्रगर रखते तब भी ठीक था। म यह मानता हं कि श्रदालतों में कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ लोगों ने गलतियां कीं, लेकिन ज्यादातर जो रिपोर्ट है वह यही है कि इन ग्राम सभाग्रों ने जो कार्य किये है, वे प्रशंसनीय हे ग्रौर उसके लिए सरकार बड़े गर्व के साथ कहती है, श्रौर कहना चाहिए क्योंकि नये नये कामों की, जो उनको साप गये थे. देखते हुए उन्होंने बहुत उम्दा कार्य किये। अब अगर कुछ गलनियां हो गयीं हों, तो उसके लिए यह रखना कि चुनाव कलेक्टर द्वारा कराये जायं, प्रेस्काइव्ड अथारिटी के प्रधीन चुनाव हो तो यह निहायत गलत है। जहां ३० मेम्बर चुनने है, तो ३५ चुने जायं। म श्रीमन्. इसको चुनाव नहीं मानता इसलिए कि इसमे वे एलिमेट खड़े हो जायेगे, जिनको गांव वाले चुनना नहीं चाहते श्रौर जो चालाक किस्म के श्रादमी होंगे, वह में किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कहता सभी पार्टी के इस तरह के व्यक्ति किसी न किसी तरह चने जाने के लिए उपाय निकालेंगे, भ्रौर चने जायेंगे, श्रौर फिर प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी से कोशिश करेंगे कि वह चुनकर भ्रा जाय भौर भ्रा जायेगे। मुझे श्रफसोस है कि उन चालाक भ्रादिमयों के सिवा कोई ग्रौर मेम्बर हो नहीं सकता जो सही रूप से पंच हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार मे बाइब करके या किसी भी प्रकार प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को वे लोग मजबूर करेगे कि उनको चना जाय ग्रीर जब वे चनकर ग्रा जायेंगे, तो गांव सभा के काम को खराब कर देंगे। सरकार ने इस चुनाव के सम्बन्ध मे जो सदसे बड़ी गलती की है, वह यही तो है कि चुनाव को प्रेस्त्राइन्ड श्रथारिटी के ऊपर छोड़ा है। अगर चुनाव हो जैसा होता है तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि चुनाव में खड़े हो जायं, जिन पर गांव वाले भरोसा नहीं रखते है और गांव सभा के कामों मे गड़बड़ियां करते है। लेकिन अगर सरकार यह मौका जो दे रही है, देती है, तो वह गलत लोग भ्रा जायेंगे। भ्रगर भ्रापका प्रस्ताव जैसा है रहता है तो मुझे भय है कि वही लोग चुनकर ग्रा जायेगे, जिनको गांव वाले नहीं चाहते । लेकिन सरकार तो बहरी है, हमारी बातों की सुनवाई तो वहां हो नहीं पाती, वर्ना मै तो यह कहूंगा कि सरकार इसको इस वक्त मुल्तवी कर दे भीर उस वक्त तक के लिए मुन्तवी कर दे इस पर उस वक्त तक विचार न करे जब तक कि सरकार प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी की डेंफिनीशन को न सुना दे। श्रगर ऐसा हो जाय, तो मं सरकार के प्रस्ताव का विरोध नहीं करूंगा, वर्ना मै समझता हं कि वे सभी लोग जो गांवों का हित चाहते है इसका विरोध करेगे श्रीर में तो इसका घोर विरोध करता ही हं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुम्रा हूं। इस संशोधन पर जो भाषण इस सदन में हुये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना ग्रीर मुझे बड़ा दु ख हुम्रा जब मेने यह देखा कि माननीय गेदा सिंह जी के भाषण में ग्रागमेट्स तो कम थे, लेकिन नाराजगी का ग्रंश ज्यादा था। मैं नहीं जानता कि कौन से ऐसे वाक्रयात पिछले दो चार दिनों में हो गये हैं जिनकी वजह से उनमें नाराजगी ज्यादा बढ़ गयी। नाराजगी जब होती है तो बैलेन्स ग्राफ माइंड जो होता है वह ठीक नहीं हो पाता है, इसलिये उस समय जो बात कही जाती है वह रीजनेबिल नहीं होती है।

यह एक बहुत छोटा सा प्रश्न है श्रीमन्, कि न्याय पंचायते किस प्रकार से बनाई जायं। पंचों का चुनाव किया जाय या उनकी नामजबगी की जाय, यह छोटा सा सवाल है। तो ग्रगर जो पिछले ग्रमडमेंट्स थे जिनको हाउस ने पास नहीं किया उनको देखा जाय तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस भवन का ग्रधिकांश मत इसी पक्ष में है कि न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं होना चाहिये, बिल्क वह किसी तरीके से नामजबगी की शक्ल मे बनाई ज य। ऐसी हालत मे मे माननीय गेदा सिंह जो का ध्यान इस तरफ ग्राक्षित करूंगा कि प्रश्न यह है कि चार स.ल की जो न्याय पंचायतों की विकंग थी उनके सम्बन्ध मे ग्राज इस प्रदेश में दो मत है। काफी संख्या मे ऐसे लोग है जिनका मत यह है कि न्याय पंचायतें जिस उद्देश्य के लिये बनाई गई थीं वह पूरा नहीं

ः रहीं मौक़ा दिया जाय ग्रौर कमियां जो थीं उनको दूर किया जाय।

माननीय गेंदा सिंह जी ने सब से बड़ी श्रापत्ति इस बात पर उठायी कि पंचायत राज ग्रमेंड मेंट ऐक्ट की जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में, मेम्बर सरहबान ने यह कहा कि न्याय पंचायत चनी हुई होनी चाहिये, इसलिये उनको इसको बड़ी शिकायत थी कि क्या वजह हुई कि मेम्बर साहबान ने ग्रपने ख्यालात बदल दिये। मै समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी हर मेम्बर को इतना श्रधिकार तो देंगे ही कि वह किसी भी स्टेज पर ग्रगर ग्रपने ख्यालात बदलना चाहे तब बदल सकता है ग्रगर वह यह समझ जाय कि जो बात मने ग्रान से कुछ दिन पेरतर वही थी वह ग्रव उसके ख्याल में ठीक नहीं है तो मै समझता हूं कि उसको इतना ग्रधिकार है कि ग्रपनी राय को बदल सकता है। इस रिपोर्ट के जो १४-१५ पैराग्राफ हं उसमें साफ तौर से दिया है भ्रौर इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुन्ना है कि न्याय पंचायतों का यह इशु बड़ा कन्ट्रोवर्शल है। अपर कभी भी एक मत नहीं हो पाय, कभी श्रोपीनियन इस साइड में थी श्रौर कभी श्रोपीनियन उस साइड में थी। काफी तादाद में ऐसे लोग थे जिनका मत था कि चनाव नहीं होना चाहिये क्योंकि चुनाव में गांव के जो प्रभावशाली लोग होंगे, चाहें वह ग्रच्छे हों या ग्रच्छे नहीं हों वह किसी न किसी तरीके से बहुमत को ग्रपनी ग्रोर कर लेंगे जिसकी वजह से ठीक ग्रौर ग्रच्छे ग्रादमी पंच बनने से वंचित रह जायंगे। यह भी इसमें एक मत था। इसके अन्दर यह भी कहा गया कि जो पांच ग्रादमी चुने जायं उनका नामिनेशन हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेशन करे लेकिन जो हमारे सामने बिल है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहीं भी जित्र नहीं है बल्कि उसके श्रन्दर प्रेस्का-इग्रड ग्रथारिटी की बात है। इस िलसिले में डेमोकेसी की भी दुहाई दी गई। इस मामले में यह भी दहाई दी गई कि जुड़ीशियरी और एव्जीक्यूटिव को एक साथ नहीं होना चाहिये और भी न मालूम कितने इशु इसके अन्दर इकट्ठे कर दिये गये। अब देखना यह है कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी का स्याल है इस क्लाज को बिल्कुल हटा दिया जाय तो मैं भी पिछली चीज जो शुक्ल जी ने कहीं थी इस बिल के जो सब से बड़ा श्राधार है, वह निकल जाता है श्रीर जो इस बिल की श्रात्मा है उसका क्तई हनन होता है। प्रश्न यह है कि हम गांव की स्थित को जानते है श्रीर गांव के अन्दर चुनाव की हालत भी हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव जो होगा वह हाथ उठा कर होगा। इस भवन में इस किस्म के भी संशोधन श्राये कि चुनाव बैलट से होना चाहिये, जो कि पास नहीं हो सके। तो जब हाथ उठा कर चुनाव होगा तो जो गांव के प्रभावशाली श्रादमी होंगे, ४-५ की संख्या में वह गांव के बदमाशों की सहायता, ग्रपने दबाब या ग्रातंक से गांव वालों के ऊपर हावी हो जायंगे। तो ऐसी स्थिति में यह समझना कि चुनाव से हम ग्रच्छे, ईमानदार भ्रादमी चुन पायेंगे, मै समझता हूं कि बड़े संदेह की बात है श्रौर फिर जो तरीका रखा गया है उसमें यह है कि अगर ३० अप्रदमी गांव सभा के मेम्बर होंगे तो ३५ अप्रदमी चुनें जायेंगे सो जहां तक चुनने का सवाल है यह सभी ही चुने होंगे क्योंकि जो ३५ ग्रादमी चुने जायंगे उनमें से ही ५ मादमी प्रेस्काइःड ग्रथारिटी छांटेगी। वे ५ म्रादमी भी चुने हुए होंगे जो कि गांव के वोटर्स द्वारा छांटे जायेंगे ग्रौर जिनको उनका विश्वास प्राप्त होगा तो वहां तक तो डेमाऋसी ठीक है। स्रव सवाल यह आता कि प्रेस्काइब्ड स्थ्यारिटी क्या होगी। इसके मन्दर एक बहुत दिक्क़त की बात है क्योंकि प्रेस्काइःड श्रथारिटी इतनी जगह आयी है बिल के अन्दर, और हर जगह उसके अलग अलग माने है और इस कारण बड़ा कनपयुजन है यह भी भय है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अथारिटी दे दी गई तो तमाम मामला चौपट हो जायगा और इस सिलसिले में जो भ्रापत्ति माननीय गेंदा सिंह जी को जो थी वह यह थी कि श्राज कल के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनका एक पेशा है श्रौर वह यह है कि जो दल शासना-रूढ़ है उसको किस तरह से खुद्रा किया जाय श्रौर खुद्रा करने का कारण उन्होंने यह बताया है कि चूंकि उनका प्रोमोशन, नौकरों, तरक्की उनके हाथ में है। तो मै गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का शासन किसी भी समय क्यों न हो एक्जीक्यूटिव अपनी जगह होगी। तो ग्रगर उनका यह विचार है चूंकि कांग्रेस शक्तिशाली है, कांग्रेस को खुश करने में

[श्री नबल किशोर]

ही डि स्टिक्ट मैजिस्ट्रेट का समय कटता है तो उसका सुधार समझ में श्राता नहीं है। कल को श्रगर गेंदा सिंह जी पावर में ब्रा जायं तो उनको खुश करना उनका काम हो जायगा । यह कोई दलील नहीं है। ग्रगर गेंदा सिंह जी यह कहें कि एक्जीक्यूटिव में कुछ किमयां है ग्रौर उनको दर करने की कोशिश की जाय तो ठीक है। वर्ना में उनको यह विश्वःस दिलाना चाहता है कि कोई भी पार्टी शक्ति में आये एक्ज़ीक्यूटिव हमेशा कायम रहेगी और जो पार्टी पावर में होगी उसके आर्डर्स व पालिसी को मानेगी और अप जीशन की स्वीट विल पर काम नहीं कर सकती। ऐसा समय कभी ग्राने वाला नहीं है। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस की यह नीत भ्रवक्य रही है कि जुड़ोशियरी भ्रौर एक्जीक्युटिव की सैंपरेट किया जायगा भ्रौर जहां तक मंने दिल को पढ़ा है मेने कहीं यह नहीं पढ़ा कि एक्जीक्युटिव जुडीशियरी को न मीनेट करेगी। माननीय रेंदा सिंह जी को यह भय हो गया है कि प्रेस्काइ ड प्रथारिटी डिस्ट्क्ट मंजिस्ट्रेट हो बनने वाला है। लेकिन जब शुक्ल जी ने कहा कि नहीं माननीय गेंदा सिंह जी भी प्रेस्काइ ड प्रथारिटी बन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता जिसमें कोई लगाम न हो। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लगाम सरकार पर ढीली है। यदि ढीली न होती तब ग्राज नेता विरोधी दल जेल में न होते। उनकी लगाम ढीली है या नहीं सो तो में नहीं जानता, मेरा तो ख़्याल है कि वह यथाशक्ति कड़ी रखने की ही कोशिश में रहते हैं। मगर में उनको यह अवश्य कहना चाहता हं कि सरकार की लगाम ढीली हो या न हो, उनकी श्रपनी पार्टी की लगाम श्रवश्य ढीली है और ग्रेगर ऐसा न होता तो माननीय नेता विरोधी दल ग्रीर उनकी पार्टी कानपुर में यह सब न करते ग्रौर न वह ग्राज जेल में होते. में श्रीमन् एक्जीक्युटिव ग्रौर जूडे शियरी के सेपेरेशन की बात कह रहा था । जहां तक मैं समझता हूं पहले यह होता था कि जो एस० डी० एम० होता था वहीं चालान करता था ग्रौर वही ट्राप्ल करता था। तो एक्जीक्यूटिव ग्रौर जुडीशियरी को कन्फ्यूज न किया जाय। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि प्रेस्त्राइट्ड ग्रथारिटी के माने क्या हैं। तो इसके मानी यह है कि सरकार जिसको भी अमुक कार्य करने की उस समय के लिए शक्ति तथा अधिकार दे दें। वह एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और कोई कमेटी भी। उनकी यह एक कंडीशनल बात है कि अगर प्रेस्काइन्ड अयारिटी डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट हुई तब तो उनका श्रापोजीशन है और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न हो कर कोई और हुआ तब शायद उनका अपो-जीशन नहीं होगा। तो इसके माने यह हैं कि बुनियादी तौर से उनको इस बात पर कोई विशेष श्रापत्ति नहीं है। यह भी कहा गया कि पिछले ५-६ सालों में सरकार इतनी ज्यादा श्रनपापूलर नहीं हुई जितनी कि अन्दाजा है कि अगर यह कानून बन गया तो हो जायगी। तो माननीय गेंदा सिंह जी की सहानुभूति के लिये में उनको बहुत धन्यवाद देता हूं हालांकि में समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा डिप्लोमेंसी की बात उन्होंने नहीं कही। उनके लिये तो यह बड़ा ग्रच्छा है कि सरकार जितनी जल्दी ग्रनपापुलर हो उतनी ही जल्दी उनका काम बने। तो इसकी फ़िक्र न करें, सरकार को खुद फ़िक्र है और वह यह जानती है कि उसकी क्या पोजीशन है और क्या होनी चाहिये ।

श्राखिर में जो बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि एलेक्टेड जुडीशियरी ग्रमरीका में होती है, श्रीमन्, यह वड़ा श्रच्छा लगता है, में भी चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ग्रमरीका बन जाय ग्रीर ग्रगर उससे ऊंचा उठ जाय तो बहुत श्रच्छा है, लेकिन ऐसे मुल्क की मिसाल देना जहां सिदयों से डेमोक्रेसी रही है, जो डेमोक्रेसी में पले हैं, ऐसे देश के मुकाबिले में जिसकी ग्राजादी को ग्रभी ६ साल भी हुये हों श्रौर जहां श्राज भी ६६ फीसदी इन्सान श्रनपढ़ हो, जहां इस तरह का जाति पांति का भेद भाव हो, मेरी समझ में कुछ बहुत उचित नहीं है। में यह बात मान सकता हूं कि ग्रगर जुडीशियरी चुनी जाय तो कोई ज्यादा ग्रापित की बात नहीं है मगर जिस स्थित से हम गुजर रहे हैं ग्रौर जो स्थित हमारे देश की है मुझे पूर्ण विश्व स है कि उसमें ऐसा करने से बजाय इसके कि न्याय हो श्रन्थाय ही श्रधिक होगा। श्राज कल जिन्हें पंचायतों का श्रनुभव है, श्रौर में समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को पंचायतों का श्रनुभव बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका ग्रामीण जीवन से बहुत ज्यादा सम्पर्क है, वे स्वयं भी जानते होंगे कि ग्राज कल की जो पंचायतें

बेनी हुई हैं उनमें कितना अन्याय होता है। जब चुन कर लोग आयेगे तो यह स्वाभाविक है कि जो बोट देगे उनका असर उनके ऊपर थोड़ा बहुत जरूर होगा। प्रेस्काइःड अथारिटी से जितना भय उनको है उतना भय मुझे नहीं है। हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे सूबे मे

भ्रौर एक्जीक्यूटिव को आगे बढ़ाने वाला नहीं हैं। एक्जीक्यूटिव के ऊपर आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई किमयां है तो उनको आप दूर करें लेकिन उसके ऊपर आप ट्रस्ट न करे इससे में समझता हूं कि शासन का चलना एक असम्भव सा हो जायगा। इन सब बातों के कहने के वाद मुझे यह आशा है कि माननीय गेंदा सिंह जी वस्तु स्थिति पर अधिक ध्यान देगे और भावनाओं के अन्दर न बह कर अपने इस संशोधन को वापस लेगे।

"श्री देवकी नन्दन विभय (जिला श्रागरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मंने जब माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन श्रीर उनके भाषण को मुना तो मुझे एक ही बात विदित हुई कि उनकी कुछ संदेह श्रीर शंकाये करने की जो श्रादत है वह बढ़ती जा रही है श्रीर मुझे श्रफ्सोस है कि कहीं वह स्रागे चल कर श्रपनी छाया से ही शंका न करने लग जायं। न्याय पंचायत के संबंध में जो उनका संशोधन है वह न तो इस बात का हामी है कि एक्जीक्यूटिव श्रीर जुडि शियरी को पथक करना चाहिये क्योंकि ग्राम पंचायतों में जुई शियरी श्रीर एक्जीक्यूटिव की वह ही स्थित है जो कि प्रदेश में प्रान्तीय धारा श्रीर हाईकोर्ट या न्यायालयों की है। श्राप चाहने हैं कि गांव की जुई शियरी का चुनाव वहां की पंचायतों के हारा हो। श्राप इस तरह से यह श्रनुमान करते ह कि जो वहां पंचायते बनेंगी वह वहां की जो सभाये होंगी वह स्वतंत्र होंगी। श्राप चाहते हें कि ग्राम सभा के ३५ श्रादमी जो हैं वह ५ श्रावमियों को चुनेंग तो क्या श्राप यह श्रनुभव नहीं करते है कि उनका उन पर प्रभाव होगा श्रीर पंचायतों में पार्टी बंदी जरूर होगी, जहां एक दल हावी हैं, क्या उसके हाथ में न्याय पंचायत के निर्णय करने का श्रिषकार नहीं पहुंच जायगा? तो क्या श्राप चाहते हैं कि गांवों में जो पार्टी बन्दी हैं उसके सिर पर न्याय श्राप खें श्रीर दूसरे लोगों को न्याय श्राप्त नहीं जो माइ नोरिटी में हैं। मेरे ख्याल से यह जो बाया मीडिया इलेक्शन श्रीर नामिनेशन का रखा गथा है, वर्तमान परिस्थित में मेरे ख्याल से इससे श्रच्छ। श्रीर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है।

इतने बड़े देश में , श्राप के प्रदेश में जहां कि क़रीब ६ हजार पंचायतों का निर्माण न्याय के लिये होता है श्रीर जहां लाखों मामले उन पंचायतों के सामने श्राते हैं, उतना बड़ा प्रयोग, में समझता हूं कि बहुत कम दूसरे देशों में इस प्रकार का होता है, वह, श्राप हे प्रदेश मे हो रहा है श्रीर केवल ५—६ साल के ही श्रनुभव से हमें मालूम हुश्रा कि इसमें श्रभी इस तरीके के कुछ नियंत्रण करने की श्रावश्यकता है, जिससे एक माइनोरिटी के दल को या कुछ दल जो माइनोरिटी मे श्राये हे, उनकी भी रक्षा हो सके।

श्रपनी प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी के श्रिविकार में केवल यह रखा गया है कि जो ३५ श्रादमी श्राप ग्राम सभा के लिये चुनें उनमें से ५ योग्य श्रादिमयों को वह चुन ले। यह भी सम्भव हो सकता है कि कहीं कहीं श्रच्छे श्रादमी न श्राये। लेकिन यह एक एक्सपैरीमेंट हैं जो श्रापको करना है। वर्तमान परिस्थित में श्राप के सामने चल रही है श्रौर गांवों में जो हमे सुधार करना है, उनमें शिक्षा का प्रचार करना है, उनमें जो पार्टीबन्दी है उसको मिटाने के लिये जनतांत्रिक भावना को जाग्रत करना है मेरा ख्याल यह हैं कि कुछ समय में वह समय श्रा सकता है जब कि हम वहां की जुडीवियरी को बिल्कुल चुनाव पर ही छोड़ दें लेकिन वर्तमान परिस्थित में यह सम्भव नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह संशोधन रखा है, में समझता हूं कि कानपुर की घटना उनके दिमाग को उस समय प्रभावित कर रही थी। लेकिन कानपुर में क्या हुग्रा, उसका उल्लेख में यहां पर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसकी इस समय कोई श्रावश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय हम यह कानून बनायेंगे उस समय हमें इस तरह की परिस्थि तयों से ऊंचे उठने की ग्रावश्यकता

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वी अण नहीं किया।

[देवकी नन्त विभव]

हैं। माननीय गेदा सिंह जी से म स्राग्रह करूंगा कि वह गांवों की परिस्थितियों को समझे स्राँर दें में कि कहीं वह स्रपने मंशोधन से वह परिस्थित तो पेदा नहीं कर रहे है कि गावों में ये न्याय पंचायने उत्थी इन का एक साधन बन जायं। स्रगर माननीय गेदा सिंह जी गये होंगे गांव में, मुझे जाने का मौका मिला ह स्रौर गेदा सिंह जी का तो काफी गांव से परिचय रहता है, क्या यह बात नहीं है कि स्राज गांव मे पार्टी-बन्दियां ह स्रौर उनके कारण ग्राम सभास्रों के कार्य का संचालन करना कठिन हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे ख्याल से जहां वह एक तरफ इस सिद्धांत को कहते हैं कि जुड़ीशियरी स्रौर एकजीक्यूटिव का एक दूसरे पर प्रभाव न पड़े, उनको पृथक होना चाहिये. वहां में यह समझता हं कि ग्राम की एकजीक्यूटिव यानी ग्राम की पंचायतों द्वारा निर्वाचित वहां की न्याय पंचायतों के इस उसूल से वह मेरे ख्याल से स्रपने ही उस उसूल को काट रहे हे जिनको वह पेश करना चाहते है।

म तो, जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, माननीय स्वशासन मंत्री की स्रोर से, उसका समर्थन करता हूं क्रोर साथ ही स्राशा करता हूं कि माननीय गेदा सिंह जी स्रपने संशोधन को वापम कर लें।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रपने ग्रादरणीय मित्र माननीय गेदा मिह जी के संजीधन पर मेने संयुक्त दल के माननीय सदस्य राजा वीरेन्द्रज्ञाह का जो भाषण मुना उससे म कुछ स्तंभित हुग्रा। वह बड़े तैं के साथ, ग्रावेश के साथ यह कहते ह कि सरकार के पास, कांग्रेम पार्टी के पास को उत्तर नहीं ग्रौर यही कारण है कि शायद माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सदन मे उपस्थित नहीं है। ऐसा लगता है कि जमींदारी उन्मूलन विवान के द्वारा कांग्रेस ने उस वर्ग को जो जवाब दिया है, उसकी तिलमिलाहट से माननीय वीरेन्द्रशाह, या उसकी झुंझलाहट मे इस प्रकार की बात कह देते हैं। यह बात उनके जैसे गम्भीर व्यक्ति के लिये शोभाजनक नहीं है। उनको यह स्वीकार करना चाहिये कि पंचायत राज विभाग कांग्रेस की मृध्टि है ग्रौर शायद ही कोई दल या व्यक्ति इस प्रकार का हो जो ग्रपनी सृष्टि को विकृत या ग्रमुन्दर करना चाहे। किन्तु इसके विपरीत यदि माननीय वीरेन्द्रशाह को पंचायत राज विभाग से गुरेज्ञ हो या उसके प्रति उनको कोई इर्ष्या या द्वेष हो, तो यह स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा की प्रतिक्रिया पंचायतराज विभाग है, नहीं तो ग्रगर वह ग्राज इस व्यवस्था को ठीक ठीक उसी प्रवृत्ति के ग्रनुकूल नहीं ला पाते हों ग्रौर उसको ग्रमफल बनाने मे छद्म हप मे नाना प्रकार की प्रवचनान्नों द्वारा ग्रसफल करना चाहते हों, तो में माननीय वीरेन्द्रशाह से कहना चाहूंगा कि वह ग्रपने इस प्रयास मे ग्रसफल होंगे।

हमारे सदन के सामने आज विरोधी दल के नेताओं ने जिस प्रकार विवाद किया उससे ऐसा लगता है कि वह संदेह और अविद्वास के शिकार है। न्याय की बात कहते समय वह सिद्धा-न्ततः न्याय को भूल जाते ह। उसके न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा लती है और जब उस न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा ले लेती है तब यदि उन्हें असंतोध होता हो न्याय से तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वर्गा प्रेस्काइ इ अथारिटी जिसको वह जानते नहीं कि क्या होने वाली है, क्या होगी, उसके सम्बन्ध में पहले से ही इस प्रकार की भूमिका बांधना, वही जैसा मने कहा, संदेह और अविद्यास का शिकार होना है। में उनको विद्यास दिलाता हूं और यह आश्यासन दिलाता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था को अधिक से अधिक सुन्दरतम और सफलतम बनाने के लिये कोई ऐसा कार्य नहीं जिस कार्य को करने में हमारो कांग्रेस पार्टी जरा भी हिचक करेगी। बजट के समय जिन लोगों ने इस पक्ष के भाषणों को सुना होगा पंचायत राज व्यवस्था के अपर उनको यह स्मरण होना चाहिये कि उन्होंने बराबर न्याय पंचायतों की भूरि भूरि नित्वा की और यह कहा कि सरकार का यह प्रयास सम्पूर्ण असफल हुआ और आज भी जहां वह एक तरफ निर्वाचन की दुहाई देते हे और गांव सभाओं के अधिकार की दुहाई देते है वहीं वह दूसरी तरफ गांव सभाओं के अधिकारों के ही अपर कुटाराधात करते है।

^{*} वनताने भाषण का पुनर्याक्षण नहीं किया।

राजा वीरन्द्र झाह—गलत कहते हं स्राप।

श्री देवदत्त मिश्र--ठीक है। गलत ग्रीर सही तो भविष्य बतायेगा।

तो मैं जो कह रहा था कि गांव सभाश्रों के जो ग्रधिकार है उनके ऊपर श्रापको विश्वास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह-शीमन्, मे एक सवाल पूछना चाहता हूं। श्री दव दत्त सिश्र-मे यील्ड नहीं करता।

उनके न्याय के ऊपर श्रापको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो श्राप कभी जो गांव सभायें उन व्यक्तियों को चुनेंगी जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्काइब्ड ग्रयारिटी नामजद करेगी तो यह कैसे मान लिया जाय कि गांव सभायें श्रवांखित व्यक्तियों का निर्वाचन करेंगे। जो गांव सभा प्रपने संगठन के लिये विशब्द व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं कर सकती उससे यह श्राशा करना कि वह दूसरे संगठन के लिये उचित व्यक्तियों का चुनाव करेगी, यह कैसी आज्ञा है ? इसलिये मैने जैसा कहा आज विरोधी दल को गांव सभाओं के न्याय के ऊपर गांव सभाग्रों के श्रिधिकार विवेचन के ऊपर सचमच में विश्वास नहीं है ग्रीर या कोई दूसरा निहित उद्देश्य उसके भीतर है जिसकी वजह से वह इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। माननीय बालेन्द्रशाह जी ने जो संशोधन रखा उसको उन्होंने एक कम्प्रोमाडज फार्म् ला बताया किन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो कम्प्रोमाइज फार्म ला तो जो इसमें रखा गया है वही श्रसल में एक कम्प्रोमाइज फार्म् ला है निर्वाचन ग्रौर नामजंदगी के बीच में। हम प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को स्वच्छन्द नहीं छोड़ते कि वह जिसे चाहे नामजद कर दें, बिन्क उसे हम गांव सभा के विश्वास-पात्र व्यक्तियों में से किन्हीं पांच को चनने का केवल श्रधिकार देते हैं। तो इसलिये जैसा कि न्याय पंचायतों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाघीशों से लेकर नीचे के जिलाधीशों तक ने न्याय पंचायतों के संगठन के ऊपर यह सन्देह प्रकट किया कि चुनाव के द्वारा जिन पंचायतों का संगठन होगा मानव स्वभाव की दुर्बलता से हर व्यक्ति संकात होता है इसलिये बहुमत के द्वारा चुने गये व्यक्ति यदि बहुमत का लिहाज करें तो यह श्रस्वाभाविक नहीं होगा ग्रौर जैसा कि मैने कहा यह तो मानव स्वभाव सुलभ दुर्बलता है। इसलिए जो इसमें एक त्रुटि थी, उसको दूर करने के लिए यह एक इतना सुन्दर फार्मुला निकाला गया कि उनको, जो न्याय पंचायत के संदस्य हैं, उनको गांव सभा का विश्वास भी प्राप्त हो श्रौर साथ ही साथ लिहाज का भी सवाल उनके सामने न रहे। क्योंकि उन्होंने चालीस की जगह पैतालीस या तीम की जगह पैतीस ब्रादिमयों को चुना, गांव पंचायत के सदस्यों के रूप में। ब्रब उनमें से पांच व्यक्ति न्याय पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। उनके अपर सीधा लिहाज कोई नहीं होता है कि हमने भ्राप को न्याय पंचायत का सदस्य चुना इसलिए हमारी बात भ्रापको माननी चाहिए। इससे मुन्दर बीच का रास्ता हो नहीं सकता था।

इस प्रश्न पर एक्जीक्यूटिव श्रौर जूर्ड शियरी की बात पैदा हुई। इस सम्बन्ध में उन्होंने पंचायत राज की भावना को ही नहीं समझा। पंचायत राज की भावना इस एक्जीक्यटिव श्रौर जूडिशियरी की भावना से सर्वथा स्वतन्त्र है। पंचायत राज की भावना में यह निहित है कि ज्यादातर न्याय पंचायतों का उद्देश्य होगा कि वस्तु स्थिति को समझ कर घटनाक्रम को जानक र दोनों पक्षों को श्रापस में एक दूसरे के नजदीक ले श्रायों। वह हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, सेशन कोर्ट, श्रौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दृष्टि से न्याय पंचायतों को देखते है। भगवान, इस दृष्टि से न्याय पंचायतों को देखते है। भगवान, इस दृष्टि से न्याय पंचायतों को बचाय रखें। इसी में कल्याण है। इसलिए एक्जीक्यूटिव श्रौर जुडीशियरी वाली बात यहां है नहीं।

कानपुर की घटना का उल्लेख हमारे कतिपय माननीय सदस्यों ने किया श्रौर माननीय गेंदा सिंह जी ने, जिनको में इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, जिस भाव के साथ इस घटना का उल्लेख श्री देवदत्त मिश्र]

किया, उससे मुझे ग्रत्यन्त खेद है। मैं बड़े ग्रदब के साथ उनसे यह पूंछ्गा कि लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा में ग्रपने को ग्रग्रणी मानने वाल माननीय गेंदा सिंह जी किसी ऐसे व्यक्ति को के किसी कारण समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर है, क्या इस बात की इजाजत देंगे कि वह कानून के ग्रपने हाथ में ले लें, ग्रौर इस प्रकार जो कानून को ग्रपने हाथ में ले लेता है, क्या वह व्यक्ति लोकतन्त्र का प्रतिष्ठाता माना जा सकता है? मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, किन्तु में स्वयं उस दिन ग्रौर उसके पहले प्रायः एक पक्ष तक कानपुर में रहा।

राजा वीरेन्द्र शाह--मै पूछना चाहता हूं कि यह संगत है ?

श्री देवदत्त मिश्र—-यह गेंदा सिंह जी और ग्रन्य लोगों से पूछिये। उस वक्त ग्राण्के न्याय बुद्धि कहां गयी थी?

श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि माननीय सदस्य को उस घटना के ऊपर ग्रिक कहने की ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने तो पहले ही कहा कि में डिटेन्स्म में नहीं जाता। श्रभी श्राप ही की उपस्थित में इसका जिक किया गया श्रीर इसके पहले श्रध्यक्ष महोदय की उपस्थित में भी जिक्र किया गया। मै तो एक पासिंग वे मे जा रहा हूं। मैने जैसा कहा कि लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी सम्माननीय व्यक्ति हो, उसको यह श्रधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह कानून श्रीर व्यवस्था को श्रपने हाथ मे ने। कानून श्रीर व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए जो व्यक्ति श्रपने कर्त्तव्य स्थान पर तैनात किये हुए हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिस दिन उस व्यक्ति को बचाने की चेष्टा की जायगी, उस दिन हमारे देश से लोकतन्त्र मिट जायेगा।

हमारे गेंदा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य ऐक्ट कमेटी की रिपोर्ट का जित्र करने हुए जो ग्रंश उद्धृत किया था, में उसी ग्रंश को पढ़ कर उनसे दरस्वास्त करूंगा कि वह ग्रपने संशोधन को वापस लें लें। वह ग्रंश इस प्रकार हैं:—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perlers aid not fully appreciate that there could be no alternative to create the pecple's tribunals in the rural areas. The burden of responsibility fully a d on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gauge of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more they to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayats for themselves."

माननीय गेंदा सिंह जी ने इस ग्रंश के द्वारा, इस बात को बतलाया कि गांव सभाये, इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वे इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें, जिससे न्याय पंजायतों का संगठन सुन्दर ग्रौर इस प्रकार का हो सके, जिससे हमारी न्याय पंचायतों का कार्य चल सके। इस भावना के अन्तर्गत जैसा मैंने पहले कहा था, चूंकि गांव सभाग्रों के ऊपर यह उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है कि ५ व्यक्ति वे चुनेंगे ग्रौर जो प्रेस्त्राइब्ड श्रथारिटी होगी, वह इस प्रथा को सफल बनाने के लिए होगी, वह इस प्रथा को सफल बनाने के लिए होगी, वह इस बात को घ्यान में रक्खेगी, कि ऐसे व्यक्ति चुने जायं, जो न्याय पंचायतों के लिए उपयुक्त हों। हमें ऐसी ही स्वस्थ परम्परायें डालनी चाहिए, अविश्वास ग्रौर सन्देह से दूर हो कर इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि प्रेस्त्राइब्ड ग्रथारिटी ने जिन व्यक्तियों की टुष्टि में रख कर न्याय पंचायतों के लिए गांव सभाग्रों ने सदस्यों को चुना है, उनको ही वह नामजद करे, इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने की जरूरत हैं। हमारी डेमोक्रेसी, ग्रभी शिश्वकाल में हैं। इस शिश्व ग्रौर यौवनकाल में जब तक इस प्रकार की परम्परायें, नहीं डाली जायेंगी, तब तक डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती। ये परम्परारें

विस्वास के ब्राधार पर होनी चाहिये। तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से ब्रपील करना चाहता हं कि वह इस बात का विश्वास करें कि पंचायत राज्य व्यवस्था को हम दोनों ही मिल कर, ्रिक हुद्गरे के विद्वास और स्योग की भावना से सफल बना सकते हैं। एक बात माननीय गेंदा सिंह जी अपने भाषण में शायद आवेश में कह गये, क्योंकि उनका जैसा गम्भीर व्यक्ति हेमी दात नहीं कह सकता कि सरकार के ऊपर अविश्वास पैदा करना ही हमारा काम है। यह डेमोक्नेसी को निगेटिव करना है। जो भी सरकार इन पार्टी होती है, डेमोक्नेसी का यह उमूल है कि जितने दल होते हैं, वे सब दल मिल कर इस बात का प्रयत्ने करते हैं कि उसके द्वारा जो स्कोम्स ग्रौर जो प्लान्स उनके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं, उनको सपोर्ट करें, ग्रापका सहयोग प्राप्त करके, उनको वर्क भ्राउट किया जाय। उनके लिए भ्रापका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। किन्तू जब दिरोधी दल इस बात से दूर हटकर केवल पावर की तलाश में रहता है, तब वह इस प्रकार का काम करता है और गाहे बगाहे, समय वे समय वह केवल सरकार के प्रति भ्रविश्वास पैदा करने का काम करता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि ऐसा करने से वह उसी डाल को काट रहा है, जिस पर वह स्वयं बैठा है। वह लोकतन्त्र की श ख को काट रहा है। इसी प्रकार से वह उन पद्धतियों को जो फासस्टि हैं, श्रौर एकतन्त्रीय पद्धति हैं, उनको इस प्रकार के व्यवहार से अवसर देता है कि वह लोकतन्त्र की जगह आकर उसके स्थान को ग्रहण करें। इमिलये, में माननीय गेंदा सिंह जी से एक सदस्य की हैसियत से यह श्रपील करूंगा कि वह श्रपना यह कर्तव्य भूल जायं कि उनका कर्तव्य केवल सरकार के प्रति ग्रविश्वास पैदा करना है। ऐसा करके वह अपने उसलों के प्रति वफादारी नहीं करते हैं।

एक बात ग्रौर कहकर मैं ग्रपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय वीरेन्द्र शाह ने कहा कि हमारे कारनामे यानी कांग्रेस के कारनामे जो हैं, उनको याद रखें। कम से कम वीरेन्द्र शाह जी को तो यह बात नहीं कहनी चाहिए, इसिलए कि कांग्रेस ही ऐसी जमात हैं कि जिस जमात में, चूंकि वह राष्ट्रीय जमात है, जिसमें ग्राप जैसे वर्ग के लोगों को भी प्रथ्य ग्रौर ग्राश्रय मिल सकता है ग्रौर जिसके साथ ग्राप ग्राज विरोध की भावना का ग्राश्रय लेकर विरोध किया करते हैं, ग्रौर कन्धे से कन्धा मिलाकर विरोध करते हैं, जिस दिन वह सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गावर में ग्रायेंगे, उस दिन हमारे कारनामें ग्रापको स्मरण ग्रायेंगे। में ग्रन्त में फिर इन शब्दों के साथ ग्रपने माननीय मित्र गेंदा सिंह जी से ग्रपील करूंगा कि वह ग्रपने संशोधन को वापस लेकर पंचायत राज की व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग दें।

श्री नियार स चौधरी (जिला बहराइच) ां क्लोजर मूव करता ं कि श्रब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—में श्री गजेन्द्र सिंह को ग्रवसर ग्रौर देता हूं, तब फिर इसके बाद इस प्रस्ताव पर राय ने लुंगा ।

श्री एजेन्द्र स्टिह (जिला इटावा)—मै ग्रापको धन्यवाद देता हूं कि ग्रापने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्राज्ञा से में श्री गेंदा सिंह जो के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्रा हूं। माननीय गेंदा सिंह का संशोधन इस बात को कहता है कि दफा १२-ए निकाल दी जाय। मैं ग्रापकी ग्राज्ञा से उस धारा को पढ़ना चाहता है:—

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Guon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number the number prescribed under sub-section(2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

[श्री गजेन्द्र सिंह]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरहाल भारा १२-ए को निकाल देने का मन्शा यह है कि न्याय पंचायत का चुनाव सीधे गांव सभा द्वारा किया जाय, जैसा कि ग्रभी तक होता रहा है। श्रगर इस धारा को नहीं निकाला जाता है, तो उसका मन्शा यह होगा कि गांव सभा के लोग गांव पंचायत को चुनेगे, श्रौर गांव पंचायत के मेम्बरों में से जो २५ या ३० होगे, उसमें में प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी जो कि सरकार द्वारा नियुक्त की जायगी, चाहे वह डी० एम० हो या ए० डी० एम०, हो, वह उनमें से ५ श्राविमयों को सेलेक्ट करेगा, जो कि न्याय पंचायत के मेम्बर होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर यहां काफी वाद-विवाद किया गया है। माननीय देवदत्त जी ने हमें नसीहत दी कि कोई श्रादमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, श्रग्य वह कानून हाथ में लेगा, तो उसे सजा दी जायगी। में इससे सहमत हूं श्रौर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन में उनसे यह पूछगा कि यह सिद्धांत क्या श्रपोजीशन पर ही एप्लाई होता है, या कभी इसे उनके मेम्बर्स पर भी एप्लाई किया गया है। क्या वह भूल गये कि पालीवाल जी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने श्रलीगढ़ में एक सिपाही को बेत मारा था? क्यो नहीं उनको देवदत्त जी ने मिनिस्टरी से उसी समय निकाल दिया श्रौर जेल भेज दिया. जैसे कि श्री राजनारायण जी को जेल में डाल दिया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—म्रान ए प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर । ग्रगर यह गर्मी पंचायत राज से ग्रलहदा रहे तो ग्रच्छा हे ।

श्री उपाध्यक्ष--काफी जवाब दे चुके हे, ग्रब संशोधन पर ग्रा जावे।

श्री गजेन्द्र सिह—मं चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को बराबर लागू किया जाय श्रोर राज-नारायणजी के मामले में तो श्रागे चलकर कोर्ट तय करेगा कि कानपुर का डी० एम० गन्ती पर या या राजनारायण जी थे। यह बात उधर से उठायी गयी थी, इसलिए उत्तर देना श्रावश्यक था।

माननीय देवदत्त जी ने कहा कि विरोधी दल के लोगों का गांव सभा पर विश्वास नहीं है कि ठोक श्रादमी चुन सकेगे। में उनसे कहना चाहता हूं कि हमे गांव सभाशों पर पूरा विश्वास है और इसीलिए हमने यह रखा है कि गांव सभा ही श्रपनी गांव पंचायत और न्याय-पंचायत को चुनें। लेकिन यदि देवदत्त जी को गांव सभा का विश्वास होता, तो वह प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी के द्वारा न्याय पंचायत के मेम्बरों के सेलेक्ट होने की बात को सपोर्ट न करते। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि जनता को मौका दिया गया श्रदालती पंचायतों के चुनने का, पर उसका नतीजा श्रच्छा नहीं निकला। उनको याद हो, तो पहले, जो पंचायते, ब्रिटिश रंजीम में कलेक्टर नामिनेट करता था। उन ने तो इनका काम श्रवश्य श्रच्छा था, तो फिर श्राप श्रव क्या प्रेस्काइब्ड श्रयारिटी से नामिनेट कराते हैं? उन्होंने कानपुर के चुनाव का भी जिक किया श्रौर कहा कि उनकी पार्टी कानपुर में चुनाव जीती। लेकिन में उनसे यह पूछना चाहत हूं कि उनकी पार्टी कानपुर में कैसे चुनाव जीती। श्रापने श्रपोजीशन लोडर को जेल में बन्द किया। श्रापने राजाराम जी शास्त्री के पोलिंग एजेन्ट्स को जेल में बन्द किया। श्रापने वहां पुलिस का श्रातंक छ। दिया। में माननीय सदस्य की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोले। बाहर की बातों पर न बोलें। कानपुर का काफी उत्तर वह दे चुके है।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नवलिकशोर जी ने कहा वि चुनाव द्वारा श्रच्छे श्रादमी चुने बायेंगे, यह मुश्किल है। में उनसे कहूंगा कि श्रगर चुनाव द्वारा स्थाय पंचायतों के लिए श्रच्छे श्रादमी नहीं चुने जायेंगे, तो गांव पंचायतों में भी चुनाव द्वारा श्रच्छे श्रादमी नहीं चुने जायेंगे, श्रौर चुनाव के द्वारा हम लोग जो श्रसेम्बली के सदस्य एम० एल० एअ है, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेगे, और इस तरह से संसद के सदस्य भी जो चुनाव द्वारा चुने जायेगे, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेगे, और इस तरह से चुनाव का सिस्टम ही बेकार हो जाता ह अंर डेमोक्रेमी भी फिर ठीक चीज न होगी। अगर आप चुनाव का सिस्टम पालियामेट अमेम्बली, गांव पंचायत सभी एग रखना चाहते हे, तो आर को जनता पर तो विद्यास करना ही होगा, कि वह ठीक आदिमयों को चुनकर भेजे और अगर वह ठीक आदिमयों को नहीं भेजती है, तो उसकी उसका खिमयाजा भुगतना ही होगा। यह केसे हो सकता है कि जनता असेम्बली के मेम्बरों को अच्छा चुन लेगी, पालियामेट के सदस्यों को अच्छा चुन लेगी, गांव पंचायतों के मदस्यों को अच्छा चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायतों के नदस्यों को वह अच्छा नहीं चुन सकेगी। यह दलील नमझ में नहीं आती कि जनता सब को ठीक चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायत के मदस्यों को ठीक से नहीं चुन सकेगी।

यह भी कहा गया कि एक्जीक्युटिव ग्राफिसर रहेगे, ग्रौर उनको पावर दी जायगी। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया ग्रापने कलेक्टर को जहां भी पात्रर दे रखी ह, वही श्राप देख ले, कि कसा काम हो रहा है। प्रपोजीशन की ग्रोर से विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सरकार का जो ख्याल है, कि छोटे-छोटे लोग पंचायतो में जो होते ह, उनको पावर न दी जाय, उसका हम विरोध करते है, सरकार उनकी पावर को स्नेच करना चाहती है। मालुम होता है कि नरकार को जनता पर विञ्वास नहीं रह गया है और वह जनता को नीचे स्तर का समझकर बड़े-बड़े श्रकतरों को तमाम पावर देना चाहती है। यहां तक किया जाना है कि मन्त्री महोदय जाते हे त्रोर जिलाधीशं के कान में कह देते हैं कि हमारी पाटी को सपोर्ट करो। हमारे यहां मिनिस्टर साहब गये थे, और उन्होंने वहां ऐसी चीजे थेश क कि जिनके बारे में में सदन के सामने क्या कहूं। में श्रीमन्, ग्रापके द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी कौन होगी, इस चीज को साफ होना चाहिए था, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने इस विषय में हमे बिलकुल ग्रंधेरे मे ही रखा है। जब माननीय गेदा सिंह जी ने कहा था कि क्या वह प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजि ट्रेट होगा, तो उस बात का मन्त्री महोदय ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया। में समझता हूं कि प्रेस्ऋाइब्ड अथारिटी चाहे डी० एम० बनाया जाय या कोई भी अफसर बनाया जाय, लेकिन इस तरह से बनायी गयी ग्रथारिटी की कोई भी इन पंचायतों के बारे मे जानकारी नहीं होगी कि कौन कैसा है और जो डिटेल की वहां की बाते ह वह किसी भी जिलाधीश या प्लानिंग ब्राफिसर को नहीं मालूम हो सकती है और ऐसी सूरत में वह अपने निजी लोगों पर ही ब्राधारित रहेगे ब्रौर पंचायत राज इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर ही काम करेगे, ब्रौर इस तरह से जो मन्ता इस बिल की है, वही खत्म हो जायगी श्रौर जो करप्तन श्रौर भ्रध्टाचार है, वह इसी तरह से वहां कायम रहेगा। जरा सोचने की बात यह है कि इस तरह से पंचायत इन्स्पेक्टर, तहसीलदार या सुपरिन्टेडेंट, एस० डी० एम० द्वारा सजेस्ट किये हुए भ्रादमी कहां तक न्याय-पंचायतों का काम ईमानदारी से करेगे, और कहां तक ईमानदार श्रादमी सजेस्ट किये जायेगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन क ना चाहता हैं कि इस संशोधन को स्वीकार करा के हम पंचायत राज का जो उद्देश्य है उसको समाप्त करना चाहते है। वह चाहते है कि उनके द्वारा निर्धारित लोगों के पास चारों तरफ से लोग जायं ग्रौर बहुत ぶड़ी तादाद मे लोग इन तहमीलदारों, प्लानिंग भ्राफिसर्स, पंचायत इन्स्पेक्टर्स को धेरे रहे भ्रौर इस बात की कोजिश करेंगे कि हमको पंच बनाया जाय। जैंसा कि माननीय उपाध्यक्ष देखा जाता है कि गवर्नमेट ने ब्रानरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने के लिये कमेटी बनायी, श्रौर उन कर्मचारियों के पास किस तरह मे लोग दौड़-दौड़ कर ग्राते हे ग्रौर ग्रपनी सिफारिश कर ते हे ग्रौर चाहते है कि हमको श्रानरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय। तो इस तरह से बौड़ थूप करके, पैसा खर्च करके लोग ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट बनेगे, वे कहां तक न्याय कर सकेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संशोधन को लाकर माननीय मन्त्री महोदय, करण्यान बढ़ाना चाहते है और व चाहते ह कि जो चापलूसी कर सके, उनके हाथों मे यह पावर जाय। एक तरफ तो वे पंचायतराज कायम करना चाहते है ग्रौर दूसरी तरफ ग्रपने को शक्तिशाली भी बनाना चाहते हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटीज

[श्री ग्जेंन्द्र निंह]

व टाउन एरियाज के जो एलेक्शन हुए हैं, उनके नतीजे से उनको खतरा हो गया है, इस एलेक्शन से उनको घबराहट हो गयी है, ट्रायनकोर के नतीजे से उनको घबराहट है, और अपनी घबराहट का उन्होंने प्रक्रीन किया है। माननीय विभव जी ने कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी का विरोध बढ़ना जाना है। से माननीय विभव जी से कहता हूं कि अगर उनका विरोध बढ़ता जाता है, तो जिस तरह से कानपुर के डी० एप० ने श्री राजनारायण जी को बन्द कर दिया है, उसी तरह से उनको भी बन्द कर बा दीजिये। माननीय विभव जी ने यह भी कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी की गांवों की परिस्थित का ज्ञान नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं आपके द्वारा माननीय विभव जी से कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी गांव के ही रहने वाले है और आप शहर में रहने हे और शहर में रह कर आपक. गांवों का उतना तजुर्वा नहीं है, जितना गेंदा सिंह जी को है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन न्याय पंचायतों के सेलेक्शन का काम प्रेस्क:इंड अथारिटी के हाथ में द दिया गया तो न्याय पंचायतों की वही हालत हो जायगी, जो अंग्रेजी राज्य में उस समय के अदालती पंचायतों की थी।

माननीय उपाध्यक्ष रहोदय, मेरा श्रपना विश्वास है कि श्रगर प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी हारा ये न्याय पंचायतें च्नी अत्येंगी, तो उनका नतीजा यही होगा कि जहां सरकार मजबत दनेगी, उसके साथ ही साथ तरकार के प्रति ग्राम जनता में नफरत का भाव भी पैदा हो जायगा। इसिनए माननीय गेंदा निह जी ने जो संशोधन पेश किया उससे माननीय मन्त्री जी की स्वयं वयत होती है। वे अपने सिर पर क्यों कलंक लेना चाहते हैं? वे क्यों डी० एम० को बदनाम करना चाहते हैं? वे क्यों प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के हाथ में यह राइट देकर उसे भी बदनाम करना चाहते हैं? इस तरह से इ डाइरेक्ट वे में उनकी भी बदनामी होगी। ग्रगर वे समझते हैं कि इस तरह से प्रेक्षाइब्ड ग्रथारिटी के हाथ में सेलेक्शन का राइट देकर वे उसते वय जारें ोे तो में श्रापके द्वारा माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि वे उस से बच नहीं सकते हैं। उसका ग्रसर इंग्डाइरेक्ट वे में उनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इन तमाम शब्दों के साथ माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि न्याय के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर जनता को इन्तजाम करने का पूरा ग्रधिकार दीजिये। चाहे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, चाहे न्याय पंचायतों का चुनाव हो, लेकिन हर हालत में उनको पूरा ग्रधिकार देना चाहिए । श्रगर वे कुछ गल ती भी करें, तो गलती के बाद धीरे-धीरे काम करना सीख सकेंगे। हर व्यक्ति गलती करता है, हर संस्था गलती करती है श्रीर हर सरकार भी गलती करती है। इन शब्दों के साथ में मानूतीय मन्त्री जी से निवेदन करता हुं कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लें।

महाराज्ञ प्रारं याले स्माहित्य ह—माननीय उपाध्यक्ष महोवय, मै आपसे कुछ प्रार्थना क ना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोवय, कभी-कभी ऐसी खुशी का अवसर प्राप्त होता है और हमारे लिये खुशी की बात है कि इस समय दोनों मन्त्री महोवय, यहां इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि बे हमारे सामने अपने विचार प्रकट करें।

श्रो उपाध्यक्ष—यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि ग्रब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

श्री गेंदर सिंह — माननीय उपाध्यक्ष महोवय, में ग्राशा करता था कि जो शुग्रहा या संवेह मेरे दिमाग में उत्पन्न हो गया है श्रौर मेंने उसको स्पष्ट रूप से माननीय स्वशासन मंत्री के सामने रख विया था, उस पर कुछ प्रकाश पड़ेगा श्रौर हो सकता था कि उस पर कुछ रोशनी - इने के बाद में कुछ सोचता समझता श्रौर शायद श्रपने मित्रों की बात जैसा कि माननीय देवदत्त जी ने कहा, माननीय द्रज विहारी जी जो हमारे श्रुजुर्ग है उन्होंने भी कहा, तथा श्रौर माननीय

मदम्यों ने भी कहा कि हम प्रयने संशोधन को बापस ने ले। मुने बड़ी प्रतक्ता होती ग्रगर उन्यां बात को मान कर प्रयन संशोधन को वापस कर लेता। मुमें प्रफसोल है कि माननीय स्वशासन मंत्री ने प्रयने विज्ञार बतलाने की मेहरबानी नहीं जी। उल्टे जो माननीय सदस्यों ने भायण कि उन्होंने हमारे संदेहों को दूर करने के बजाय उन संदेहों को ग्रौर भी पुष्ट करने की कोशिश की। में सदसे पहले उन्हों यह कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस रिपोर्ट के म्-१० पन्नों को पढ़ने की मेहरबानी की। ग्रगर माननीय सदस्यों ने एक घंटे के समय का ठीक उपयोग किया होना तो में समझता हूं मुझे कि किसी बात के कहने की ग्रावश्यकता नहीं पढ़ती। यह रिपोर्ट बहुन विचार विनिमय के साथ ग्रौर बड़ी गंभीरता के साथ लिखी गयी है। इसके ग्रितिरक्त म ग्रौर कोई बात लोगों को याद भी नहीं विलाना च हता हूं लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि मुझे उस तरफ के लोगों को याद दिलाने की जरूरत होती है। इसलिए कि जिन माननीय सदस्यों ने लंच ग्रावर के बाद भाषण किये उनसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बरावर इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी इसको देखा नहीं। माननीय एक िहारी मिश्र जी ने एक पैराग्रफ की तरफ जाने को कहा था। में उनका ध्यान इस रिपोर्ट के खार-खास ग्रंशों की तरफ दिलाना चाहना हं। यहां पहल ही भूमिका में जहां पर न्याय पंचायत हुए हुयी है उन्तीसवे पेज में यह बान लिखी हुयी है, में उस तरफ माननीय मिश्र की का ध्यान ले जाना चाहता हूं—

"In the of the shortenings, land of experience and training and results of the shortening of rollions of suspicious eyes the Adalti in the characteristic end blinking of rollions of suspicious eyes the Adalti in the characteristic end by disposing of over 9 lakhs of a session inch only two percent, revisions were allowed. Any machines with the odd natration of justice embellished and studded with legest a principle of any country would have been proud of such an achievement I not ghouse the expense involved in its maintenance would have been problibility for a country of poverty-stricken millions."

यह तो मान-ीय मिश्र जी ने पंचायतों की तारीफ में कहा। इसके बाद फिर ते सरे पैरा गफ में कुछ जस्टिस की तरफ यानी जिस तरह से न्याय किया जाय इस पर कुछ विशेष कहने की कृपा की हैं। इसमें उन्होंने कहाः—

"In simple language and briefy however the act of giving to every orhis due may be contact as justice. It must be levich, full, but and contable, hold necessarily be based on trath and reighteousness should be evaluated must appear to be upright.

यानी यह कि वह केवल थ्योरी में त हो बिल्क वह दिखायी भी दे वह सही चीज है तो क्या प्रेस्काइटड ग्रथारिटी के नामजबगी से इसमें खबसूरती दिखायी देगी फिर इसके बाद वेलफेयर स्टेट में कैसा जिस्टस हो इस पर भी उन्होंने एक राय कायम की है श्रौर में समझता हूं कि कमेटी ने बहुत मुनासिब राय कायम की है। वह कहते यह है कि:—

"Justice in a Welfire State must no. only be done but even the weaker and the poorest must have the faith and confidence that it shall be done to him. The basis of a Welfare State lies in the secure and a consistent enjoyment by the people, in an ever increasing manner of the rights conferred upon them by the laws of the land."

स्रब में नहीं समझता कि किस तरह प्रेस्काइब्ड स्रथारिटी को यह स्रधिकार देकर हम जनता को स्रधिकार दे रहें हैं और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। में स्रौर बातों जो छोड़कर जो इसका स्रंतिम पैरा है उसे माननीय सिश्र की की रोवा से स्रौर माननीय सदन की सेवा में रखना चाहता हूं और इसे देखने के बाद फिर में समझता हूं कि शायद माननीय सदन को स्रपनी राय बदलने को राजी किया जा सके स्रौर माननीय मिश्र जो को स्रगर वह

[ओ गेंदा सिंह]

विस्मृत हो गया रिपोर्ट की बातें तो फिर उनको स्मरण दिलाकर में चाहूंगा कि वह हमारा साथ दें और सरकार को कहें कि सरकार भी श्रपनी राय बदले । छःवीसवें पैरा में यह कहा गया है—

यह तो सीकेट बोर्टिंग पर है, लेकिन ग्राखिरी हिस्सा उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने इसका पढ़ा उसमें स्पष्टरूप से यह बात कही गयी है कि कमेटी इस राय की है कि किसी दूसरी प्रथा को चाहे वह नामिनेशन हो, चाहे वह कोई प्रथा हो उसको पेश करने के लिये वह तैयार नहीं है—लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ग्रगर किसी को उसने समझा है तो गांव सभा द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव को । इस कमेटी में उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य रहे हैं उनके नाम में जरूर यहां रख देना चाहूंगा अमें कि वह माननीय सदस्य ऐसी स्टैंडिंग के हैं जिससे में समझता हूं कि उनके नाम सुनने से माननीय सदस्यों का भी शायद इस रिपोर्ट को पढ़ने का जा चाहेगा और मैंने जो उनके सामने यह दरख्वास्त की है, जो उद्धरण पेश किये है उस पर शायद उनको राय बदलने का मौका मिले।

1.	Sri.	Mohan Lal Gautam, Minister for Local Seif-Go-	
		vernment	Chairman
2.	Sri.	Malkhan Singh M. L. A	Member
		Brij Behari Misra, M. L. A.	Member
		Ishwari Prasad, M. A., D. Litt., M. L. C.	Member
		Suresh Prakash Singh, M. L. A	Member
		Mahant Jagannath Bux Das. M. L. A.	Member
		Shiv Saran Lal Srivastava, M. L. A.	Member
		Kalika Singh, M. L. A	Member
		S. N. Katju, M. L. A.	Member
10.	Sri		Member
		J. K. Tandon, Secretary Legislative Department	
		K. N. Singh, Secretary Local Self Government De-	
	D. 1		Member
13.	Sti	G. S. Chooramani, Joint Director of Panchayats	Member
15.	O11	5. 5. Choolamani, Joint Director of Landing and	Secretary.

यह १३ माननी । सदस्य इस कमेटी के मेम्बर रहे हैं। में इन १३ माननी । सहस्यों को निजी तौर ते कुछ जनता हूं। लेकिन श्री जे० के० टंडन जो इस कनेटी के सेकेटरी हं उनका नाम जब में पाता हूं तो अधिक मजबूत हो जाता हूं। इसके अलावा डाइरेक्टर साहब श्री चूरामनी के नाम से मझे कुछ और मजबूती मिलती है। लेकिन सबसे अधिक मजबूती तो तब मिलती हैं जबिक माननीय स्वशासन मंत्री जो जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे उनकी भी राय कुछ दूसरी नहीं है। उनकी राय भी यही है जोकि मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखी। माननीय चेयरमैन साहब, जो इस समय हमारे सामने माननीय स्वशासन मंत्री जी की शक्त में हैं उनकी राय में समझता हूं कि इस कमेटी में बहुत मजबूत राय होगी। वो और आदमियों की राय ने सबसे ज्यादा काम किया होगा। एक तो माननीय टंडन जी जोकि इस सवन के कान्नी सलाहकार है, उनको में निजी तौर से भी जानता हूं, वह एक बिन्दी हटाने में भी उपाध्यक्ष महोदय, घंटों सोचते है। अगर किसी विषयक में एक कामा और फुलस्टाफ हटाने

की भी बात कही जाय, यह मामूली बात नहीं है कि वह उसपर राजी हो जायं। अगर माननीय टंडन जी के दस्ताबत से यह रिपोर्ट शाया हुयी है तो मं तो उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल उर्ज़ल पड़ा। नहीं मालम के न सा जब उस बेचार पर हुआ जिसके बाद उन्होंने इस बिल को फिर से दूसरे प्रकार से ड्रापट कर दिया। में जब किसी वक्त सोचता हूं तो यह महसूस करता हूं की श्री टंडन के ऊपर भारी जब किया गया होगा और उससे में परेशान हो जाता हूं कि कैसे उस भले ग्रादमी ने कबूल किया होगा। इसके ग्रालावा माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कैसे कब्ल किया, इसे सोचकर उनसे हमारी पूरी हमदर्वी है। उनकी जो ग्रवस्था हुयी होगी इस बिल को कबूल करने में इस रिपोर्ट को लिखने के बाद जबिक इस बिल में उपाध्यक्ष महोदय इसका जिक्क है खंड ४३ में, पंचों के चुनाव के सं न्ध में कि हम इस बार को नहीं मान स ते। यह ड्राप बिल में जो बात आयी है इसको स्वीकार नहीं कर सकते, यह लिखा हुआ है। तो में नहीं समझता कि क्या गुजरी होगी माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऊपर। श्रीर इसीलिए में हमदर्वी का इजहार करता हूं। अब रें किन शब्दों में कहूं, हां यह बात तो ठीक है, जो माननीय अपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्द नहीं है। वाकई में ठेट देहाती ग्रादमी हूं। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्द नहीं है। वाकई में ठेट देहाती ग्रादमी हूं। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्द कित होता तो में श्राज गवर्नमेंट को उन

जुला लिया करेंगे। में यह कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में मेने शुरू में यह कहा हैं, कि इस शासन विभाग के लंभों की जो मोटे-मोटे है उन केसाथ इसको बांघ दिया जाय। ग्रगर बांघ दिया गया तो यह खंभे इन्हें ले जा करके ग्रज्छी जगह न डालेंगे। न्याय विभाग वालों को ले जा कर गड़ढ़े में डाल देंगे। मैने शुरू में कहा था, बार-बार क्या दोहराऊं, कि न्याय विभाग का जिसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध गांवों के छोटे-छोटे मामलों से है इसका इस तरह से शासन के साथ गठबन्धन कर देना य श्रन्याय करना है, कोई न्याय नहीं पायेगा और रही बात माननीय देवदत्त जी की कि सरकार के ऊपर हमारा श्रविश्वास बढ़ता जा रहा है। में यह कहता हूं कि सरकार के प्रति जितना भी श्रिधिक से ग्रिधिक ग्रिविश्वास फैलाया जा सके यह हमारा काम है। लेकिन हम जानते है कि जो लोग कांग्रेस के भीतर रहे हों और कुछ भी गांधो जी की छाप उनके जीवन पर एक ग्राना, एक पाई, २ पाई है तो उनका कर्त्तव्य ग्रपने विरोधी को नीचे गिराना ही नहीं है, बल्कि ग्रन्देशा है कि कम खतरे से ग्रागाह करना भी कर्तव्य समझे, मेने शुरू में ही यह वात कही थी कि हमारा काम यह जरूर है, इससे इन्कार नहीं करते। अगर वह काम हमारा न होता तो हम भी माननीय गौतम जी के साथ होते। माननीय स्वशासन मंत्री जी जो है उनके पीछे रहने का तो ग्रवसर कभी मिला ही था काफी दिनों तक और जिस वक्त यह हमसे जुदा हुए उस वक्त बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट का वर्णन नहीं कर सकता। ग्राज माननीय मंत्री जी जिसमें विश्वास करते है उसमें हम नहीं विश्वास करते। फिर भी हमारा यह काम नहीं है कि हम हर मामले में स्वशासन मन्न जी या इस शासन का जो भार चला रही है, सरकार को उसे प्रत्येक मामले में बदनाम किया करें। हर म.भले में जो सही सलाह दी जा सकती है वह न दें। डेमोक्रेसी में श्रपोजीशन का काम में उन माननीय सदस्यों से सीलना चाहता हूं जो हमको यह सिखाते है। हम कहते है कि अपोजीशन का क्या काम है, विरोधी-दल का क्या काम है। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रखना है और डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो भाषण करना जरूरी होगा श्रौर जिन माननीय सदस्यों को भाषण पर विश्वास न हो वे बाहर चल करके जरा तन वार पर हाथ रखे क्योंकि सरकार को बदलने का 'रीन या तो भाषण है नहीं तो तलवार है। उसके भ्रलावा दूसरा तो कुछ नहीं। और तीसरा तरीका विनोबा-भावें जी का सेवा करने का है जिसमें माननीय सदस्य जो उलाहना देते हैं हमारे भाषण का छनको विश्वास ही नहीं है। हम कहेंगे कि जरा बिनोवा जी के पीछे तो चलिये तो उसके पीछे जाने को तैयार नहीं तलवार उठाने को तैयार नहीं, भाषण पसन्द नहीं। फिर करते क्या ? तो में बापुसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा विश्वास डेमोकेसी में है प्रजातंत्र में है और उस मजातंत्र में विश्वास रखते हुए हम यह सोचते हैं कि हर आदमी को उचित मौका रहना चाहिये

|श्री गेंदा सिंह]

कि वह न्याय पा सके। हम जब यह संदेह करते हैं कि सरकार, शासनाधिकारी जो हैं वे न्याय के कामों में दखल देते हैं और न्याय के कामों में दखल दिया करते हैं, सरकार के विरोधियों को कचलने के लिए, श्रपनी क्चेंघ्टा को पूरा करने के लिए, तो में क्या गलत कहता हूं ? में उदाहरण स्वरूप ग्रगर ग्रपने ही को रखूं तो क्या इससे सरकार इन्कार करेगी कि जिसको सरकार ने नियक्त किया, जिसका सरकार के साथ बहुत नजदीक का सम्बन्ध या उसने उपाध्यक्ष महोदय, मझें दो वर्ष की सजा दे दी। ऐसा समझ कर सजा दी कि दो वर्ष की सजा के बाद यह श्रयोग्य हो जायगा इस ग्रसेम्वली का सदस्य बनने के लिए । लेकिन जिस वक्त मेंने उसी हक्म के खिलाफ श्रपील की श्रौर जिसका शासन से जरा दूर का सम्बन्ध है उस जुडिशियरी ने फैसला दे दिया कि यह बेक़मुर है। ग्रब उस जडीशियल मैजिस्ट्रेट को मैं क्या कहं, जिसने दो वर्ष की हमको सजा दी । वह कन्फर्र्ड नहीं था । उसको जुडीशियल मैजिस्ट्रेटी करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि धगर दो वर्ष की सजा गेंदा सिंह और उनके साथी को देते हैं तो बड़ी पक्की नौकरी उसकी हो जायगी श्रौर फिर जो यह श्रसेम्बली में जा कर सरफ र के सामने दो बातें जनता की कह लेता है वह कहने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन उस जुडीशियरी ने, जिस पर हमें गर्व है, उसने हमें रिहा कर दिया श्रौर में कहता हूं कि सरकार श्रपील में क्यों नहीं श्रायी, जरा हाई कोर्ट में ज ती तो में इंखता कि सरकार की क्या गति वहां बनती। इसलिए में कहता हूं कि सरकार न्याय के काम में बिल्कुल गुलाम न बना दे उनको। यह तो बड़े पैमाने पर है। मैं कहता कि छोटे पैमाने पर गांव-गांव में पार्टीबन्दी है, उस पार्टीबंदी को हम एक स्वस्थ रूप देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि गांवों में पार्टीबन्दी होगी, कोई दुनियां की ऐसी ताकत नहीं जो उस पार्टीबन्दो को रोक सके। भ्रगर उस पार्टीबन्दी को रोका नहीं जा सकता तो क्यों न उसे एक स्वस्थ्य रूप दिया जाय, जिससे कि वह गांवों को नर्क न बनाये बल्क उनको तरको की तरफ ले जाये। ग्राज जो कानून सरकार बना रही है उसके मुताबिक गांवों का क्या स्वरूप होगा । प्रेस्क्राइब्ड श्रयारिटी न्याय नं व।यत बनायेगी श्रौर न्याय पंचायत बनाने के बाद जिनको जी में भ्रायेगा उनको वह सतायेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से सजा दिलायेंगे और जो में उदाहरण स्वरूप श्रापसे कहता हूं कि मैंने ऐसा हुक्म कभी नहीं देखा कि एक मैजिस्ट्रेट एक श्रादमी को जमानत के लि ने ऐसा हुक्म दे और यह कहे कि तुमको कानपुर के किसी इन्कमटैक्स देने वाले को ही लाना पड़ेगा, उसी की जमानत हम मानेंगे, यह माननीय राजनारायण जी को एक मैजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—प्रोपेगेंडा करने की बात दूसरी है।

श्री गंदा सिंह—सभी को प्रोपेगेंडा करने का श्रिधकार है श्रौर हमें भी है। माननीय सबस्य भी करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो करती है उसका हम सभी चित्रण करना खाहते हैं श्रौर में समझता हूं कि यह हमारा श्रिधकार है। श्रगर हमारे श्रिधकार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोक दें तो में समझता हूं कि यह हमारे साथ श्रन्याय होगा, श्रौर किसी माननीय संदस्य को इस तरह से रोकने का श्रिधकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में सदत में चर्चा हो चुकी है, उसके विषय में फैसला भी हो चुका है श्रीर तरीका भी बताया गया है कि किस तरह से काम किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो उनके विवाद में संबंधित चीजें है उन्हों पर बातचीत होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—में ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नवल किशोर जी ने श्रौर दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर काफी रोशनी डाली, काफी बदनाम करने की कोशिश की माननीय राजनाइ यण जी को श्रौर इस बहाने से वे बदनाम कर लें श्रौर श्राप हमको श्रपनी श्रोजाञ्चन को साफ करने का मौका न दें यह हमारे साथ श्रन्याय होगा, में तो कहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के साथ हो क्या रहा हूं ? में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि इसी तरह के लोगों को श्राप प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी बनावे जा रहे हैं। श्रगर सरकार को साहल हो तो कह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी में नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट

मंजिस्ट्रें ने प्रेस्काइ ड प्रथारिटी होंगे। इस रिपोर्ट में यह बहुत स्पष्ट लिखी हुई बात है कि १७ जिला मंजिस्ट्रेटों ने नामिनेशन के लिये सिफारिश की कि नामिनेशन किये जायं न्याय पंचायत के लिये।

एक सदस्य-लेकिन वह माइनारिटी में है।

श्री गैंदा सिंह—माइनारिटी में होते हुये उन्हों की चल रही है। कलक्टरों में सभी नालायक थोड़े ही है, उनमें भी लायक होंगे और उन्होंने कहा होगा कि न्याय पंचायतें चुनी जायं, लेकिन जो कलक्टर पथ-अष्ट है, जो बुद्धि-अष्ट है उनकी चल गयी और सरकार ने उनकी राय की ही पसन्द किया और जो १३ सब से बिंह्या राय देने वाले इस कमेटी में बैठे थे उनकी राय कट गयी। इस तरह से यह पंचायतें भी अष्ट होने जा रही है। यह बुद्धि अष्ट १७ डिस्ट्रिक्ट मैंजि ट्रेटों की राय थी कि पंचायतें नामिनेटड हों और बाकी ३४ कलेक्टरों की यह राय नहीं थी। वह १७ कानपुर के राठौर जैसे थे। लेकिन उन १७ कलेक्टरों की बन गयी जो पथभ्य अष्ट और बुद्धि अप्ट थे और सरकार भी उनके पीछे चली गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि स्रब भी सरकार चेते स्रौर सारे माननीस सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह इस गुस्से में काम न करें। नाराज होने का कारण मुझे तो हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिस घर के बुजुर्ग को जेलखाने में बन्द कर दिया गया हो स्रौर इस पर भी हमें चिढ़ाया जाता है, हमसे सवाल होता है कि तुम्हारे नेता कहां है तो मुझे गुस्सा नहीं होगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष-मं फिर माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मं नाराज भी हूं श्रीर हमें तकलीफ है। हमारे घर कां जो बुजुर्ग है जिसे हमने बुजुर्ग का दर्जा दे रखा है श्रीर में किसी सरकार के लिये समझता हूं उचित नहीं है कि वह इतने बड़े प्रबल मत श्रीर इतनी बड़ी शक्ति में होने के बाद एक व्यक्ति से चाहे कि उसको जेलखाने में रखकर हुकुमत करेगी।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, मै यह जानना चाहूंगा कि चेयर से रूलिंग होने के बाद यह बात असंगत है, माननीय सदस्य का परिसस्ट करना क्या मुनासिब है ?

श्री गेंदा सिह-चेयर से कोई रूलिंग नहीं हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष—ग्रगर रूलिंग नहीं हुयी है तो भी में माननीय सदस्य को सलाह वे चुका हूं। मेरी सलाह को न मानना कहां तक उचित है यह में माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मै ग्रापकी सलाह की रूलिंग से भी ग्रधिक प्रतिष्ठा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं।

श्री ग्रेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यदि में थोड़े से में जवाब न दे दूं, तो हमें बदनाम होने का डर है, श्रीर हमें बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। मेरे दिल में नाराजी है, लेकिन में विषयक पर नाराज होकर नहीं शेल रहा हूं। जिस दिन से यह पचायत राज विषयक श्राया मैने श्रपना सारा काम छोड़ रक्जा है श्रीर उस दिन से मैने इसको विधिवत् ढने की कीशिश की है। में पंचायत राज विभाग के श्रिवकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे लिए बड़ी सुविधा दे दी थी, कि हम पंचायतों के बारे में श्रासानी से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर सकें। आज भी बहस होने के पहले उन्होंने हमें एक छोटी सी पुस्तिका दी, जिससे हमारी जानकारी श्रीर भी बढ़ गयी। हम नाराजगी में इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्क बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं।

[श्री: गेदा सिंह]

हम सरकार के उन विरोधियों में से ह, जो सरकार को हटाना चाहते ह, लेकिन सरकार को इसलिए हटाना नहीं चाहते है कि गलत या सही हर मामले मे हम सरकार की ग्रानीचना किया करें। सरकार गलती करने जा रही है, इससे हम उसकी आगाह करना चाहते है। धगर सरकार धागाह होना चाहे, तो हो जाय। लेकिन नहीं होना चाहे, तो भी हम तो प्रपना कर्तव्य-पालन कर रहे है, ब्रौर ब्रपने कर्तव्य के पालन करने में हम कभी भी पीछे नहीं हमारे पास जितने शब्द होंगे श्रीर जितनी बुद्धि होगी, उसके श्रनुसार हम सरकार को समझाने की चेष्टा करेंगे, सरकार समझे न समझे, श्रागे श्राने वाले जमाने में मरकार को सद सबक मिलेगा। ५-६ वर्षों में जो काम इसने किया है, उस पर जो कुछ इसकी राय थी. उस से ही सरकार उन्टी जा रही है। क्योंकि जो कुछ भी ५-६ वर्ष का काम था, कमेटी ने उसका विश्लेषण किया ग्रौर विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने यह पुस्तकाकार के रूप मे एक रिपोर्ट दी है। इसके देखने के बाद मैं समझता हूं कि कमेटी के उन माननीय सदस्यों ने बहुत ही समझ बुझकर वह राय दी थी, लेकिन, सन् १६५४ में दो चार महीनों के भीतर सरकार ने प्रपनी राय बदली। मुझे नहीं मालूम कि मरकार की राय बदलने के क्या कारण थे। मं श्रब भी श्रपनी मजबरी जाहिर करता हं कि श्रगर वह मेहरबानी करके कारण माननीय स्वज्ञासन मन्त्री जी ने बतलाया होता, या माननीय व्रजिबहारी जी ने बतलाया होना, या किसी माननीय सदस्य ने बतलाया होता, तो म सोचने के लिए तैयार था, श्रौर म शायद सरकार के साथ होता । मुमकिन है कि सरकार या किसी माननीय सदस्य की सलाह से में भी कर्नावस हो जाता और मान जाता कि न्याय पंचायत को प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के ही द्वारा बनाना चाहिए, लेकिन बदिकस्मती हमारी कि माननीय सदस्यों में से किसी ने इस बात पर स्पष्ट नहीं किया ग्रौर न इसको माननीय स्वशासन मन्त्री ने इतनी मेहरबानी की कि वह मुझ को या श्रीर माननीय सदस्यों को बताये। तो फिर ज्यों का त्यों हमारा सन्देह बना हुन्ना है। किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा, विभव जी ने, ऐसे ग्रादमी ने, कहा कि कहीं हम ग्रपनी छाया से ही सन्देह न करने लग जाये। में जानता हूं आखिर यहां बैठा रहा हूं, कि ऐसे लोग भी मौजूद हे, जो हमको करेक्ट किया करेंगे, शुद्ध किया करेंगे। हम गलती कर सकते हैं, तो माननीय विभव जी जैसे श्रादमी भी तो यहां मौजूद है, जो अपनी छाया से सन्देह नहीं होने देगे। छाया तो दरिकनार मे तो माननीय विभव जो से भी सन्देह नहीं करूंगा। उधर के माननीय सदस्यों मे से ऐसे लोग भी ह, जिनको मे अपने से कम समझने वाला या कम ईमानदार नहीं मानता हं, कम प्रगतिशील भी नहीं मानता हूं। कुछ मजबूरियां हुं, एक मुल्क की स्थिति है, जिसकी वजह से भ्राज हम भीर वह दो जगह हे। आज हमारा यह विश्वास है कि हम सन्देह से डूबने वालों की दुनिया मे नहीं है सन्देह की दुनिया में डूबने वालों का साथ छोड़ दिया। हम रीम्रलिस्ट ह, वस्तुस्थिति को देखते हं, श्रौर उसके श्रनुसार चलने की कोशिश करते हं। सम्भव है, गलती हो जाय। जहां गलती हो, वहां माननीय रामकुमार श्रौर श्री सीताराम जी बैठे रहेगे. श्रौर माननीय चतुर्वेदी तो बैठे ही ह। वह दुरुस्त कर लेगे। सब लोग बैठे ह. भ्राखिर यह लोग करेगे क्या? इसीलिए तो डेमोक्रेसी को हम हिमायत करते ह कि जब दो विरोधी विचारों का द्वंद होता हं तो उस द्वंद के बाद कोई चीज सही निकल सकती है। एक श्रादमी सही नहीं मोच सकता, यह भी बात हो सकती है. लेकिन दूसरा मादमी मगर सही बात सोचता हो, तो मं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हं। मं फिर मालीर में इसी बात की दरस्वास्त करता हूं और ग्रव भी ग्राशा करता हूं कि देर ग्रायद दुरुस्त श्रायद, माननीय स्वशासन मन्त्री श्रपनी उस कमेटी की रिपोर्ट पर जिसके चेयरमैन थे, स्टिक करे श्रौर उघर जायं श्रौर उघर जाने के बाद में समझता हूं कि इस विधेयक की रूपरेखा दूसरी होगी और उस रूप में जब यह विधेयक पास होगा, तो माननीय स्वशासन मन्त्री जी की नेकनामी होगी, हम भी माननीय स्वशासन मन्त्री जी का गुणगान गायेगे और सरकार की जयजयकार होगी। अब इसके बाद अगर वह ऐसा नहीं करेगे, तो क्या होगा, यह मैं नहीं जानता। वह तो इतिहास भविष्य का बतलायेगा।

अश्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर कई बार कई क्रम में वाद विवाद हो चुका है और इस संशोधन पर जितने भी माननीय सदस्य बोले, उन्होंने जिल्नी बाने कहीं, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है, जो पहले नहीं कही गयी हो। मदन्यों ने ग्रापको कृपा से ग्रौर ग्रापको सलाह से बावजूद जो ग्रधिकार बढ़ा लिये हैं, वह गलत है । एक तो यह कि बहुत सी असंगत बाते कही गयीं। उनके उत्तर देकर में कम से कम अपने अधिकार नहीं बढ़ाना चाहता जिसको कि मं गलत समझता हूं। जो जितनी ग्रसंगत बातें है, उनको कहते के लिए एक ऐसा ग्रधिकार प्राप्त कर लिया है, माननीय सदस्यों ने कि ग्रगर वह न होता, तो यह सदन ज्यादा अच्छी तरह से काम करता। इसलिए मं उस अधिकार को कम से कम ग्रपने लिए तो नहीं बढ़ाना चाहता भ्रौर उन ग्रसंगत बातों का जवाब नहीं देना चाहता । किस-किस पर भ्राक्षेप. क्या-क्या बहस, क्या-क्या बातें कही गर्यी, वह सब इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखनी है। दूसरा ग्रिंथिकार यह माननीय सदस्यों ने बढ़ा लिया है कि जो बात एक दफे कही जाय. उसे बार-बार कहने का ग्रधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस ग्रधिकार को भी में गलत समझता हूं ग्रीर इस सदन का जो मूल्यवान समय है, उसमें बार-बार एक ही दलील को कह देने का ग्रंधिकार में ग्रपने लिए प्राप्त नहीं करना चाहता। इसके ग्रलावा एक भी प्वाइन्ट ऐसा नहीं हं जिसका कोई उत्तर देने की ग्रावश्यकता हो। इसलिए मुझे ग्रफसोस हं कि म इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष-प्रदन यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A निकाल दी जाय। (प्रदन उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर ग्रस्वीकृत हुआ।)

पक्ष मे (१७)

उमा शंकर, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गंगा घर, श्री
गेदा सिंह, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
बालेन्द्रशाह, महाराजकुमार,

मोहन सिंह शाक्य, श्री मदनमोहन उपाध्याय, श्री यमुना सिंह, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री राजवंशी, श्री रामसुभग वर्मा, श्री वीरेन्द्रशाह, राजा विष्णुदयाल वर्मा, श्री

प्रब्दुल मुई ज् लां, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री केवल सिंह, श्री किन्वर लाल, श्री कृपा शंकर, श्री गंगा प्रसाद, श्री गुरुप्रसाद सिंह, श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री चन्द्र सिंह रावत, श्री

चरण सिंह, श्री

चन्द्रहास, श्री

विपक्ष में (११०)

चुन्नी लाल सगर, श्री छंदालाल चौघरी, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री जयपाल सिंह, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगपति सिंह, श्री जवाहरलाल, श्री टोका राम, श्री वुलसी राम, श्री दीपनारायण वर्मा, श्री दीनदयालु शर्मा, श्री

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवदत्त मिश्र, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री घन्षघारी पाण्डेय, श्री घर्म सिंह, श्री नवलिकशोर, श्री नाजिम ग्रली, श्री नेत्रपाल सिंह, श्री नरदेव शास्त्री, श्री नागेश्वर द्विवेदी, श्री नारायणदास, श्री नौरंगलाल, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री पूत्त्लाल, श्री प्रतिपाल सिंह, श्री प्रभूदयाल, श्री पहलवान सिंह चौघरी, श्री प्रकाशवती सूद, श्रीम गी प्रभाकर शुक्ल, श्री फतेह सिह राणा, श्री फजलुल हक, श्री बलवन्त सिंह, श्री बसन्त लाल शर्मा, श्री बलदेव सिंह ग्रार्य, श्री बशोर ग्रहमद हकीम, श्री भूगुनाथ चतुर्वेदी, श्री भुवरजी, श्री मन्नीलाल गुरुदेव, श्री मान्धाता सिंह, श्री मुन्नूलाल, श्री मुहम्मद ग्रब्दुल लतीफ, श्री मोहनलाल गौतम, श्री मदनगोपाल वैद्य, श्री महीलाल, श्री मिजाजी लाल, श्री मुश्ताक ग्रली खां, श्री मुहम्मद मंजूरल नबी, श्री मोहन सिंह, श्री यशोदा देवी, श्रीमती रघनाथ प्रसाद, श्री राजकुमार शर्मा, श्री, राषाकृष्ण ग्रग्रवाल, श्री रामग्रधीन सिंह यादव, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री रामचन्द्र विकल, श्री

रामजी सहाय, श्री रामप्रसाद, श्री राम भजन श्री, रामवचन यादव, श्रो रामसनेही भारतीय, श्री रामेश्वरप्रसाद, श्री राजिकशोर राव,श्री राजाराम शर्मा, श्री राधामोहन सिंह, श्री राम किंकर, श्री रामगुलाम सिंह, श्री रामजीलाल सहायक, श्री रामदास ग्रार्य, श्री रामबल, मिश्र, श्री रामलखन मिश्र, श्री रामशंकर द्विवेदी, श्री रामसुन्दर राम, श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री लक्ष्मीशंकर यादव, श्री लक्ष्मीदेवी, श्रीमती विद्यावती राठौर, श्रीमती व्रजवासी लाल, श्री वजि हारी मेहरोत्रा, श्री वसी नकवी, श्री वीरसेन, श्री व्रजि हारी मिश्र, श्री शिवमंगल सिंह कपूर, श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री शुगन चन्द, श्री शिवनारायण, श्री शिवराम पांडेय, श्री शिवस्वरूप सिंह, श्री श्याम मनोहर मिश्र, श्री सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती सियाराम गंगवार, श्री सीताराम, डाक्टर सावित्री देवी, श्रीमती सियाराम चौघरी, श्री सुखीराम भारतीय, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री हरिक्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री हबोबुर्रहमान ग्रन्सारी, श्री हरदेव सिंह, श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री

श्री उपाध्यक्ष—यह जो श्री केशभान राय का संशोधन ४६-ग पर है, यह तो श्राफिस के द्वारा ही कर दिया जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम- निनीय ध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि इस संशोधन की कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बात इसमें श्रोमिट की जा रही है, वह यह है कि किसी भी गांव का रिप्रेजेन्टेशन न हुग्रा हो, वह इसमें श्रा गयी है। कोशिश यह होगी कि हर रेवेन्यू विलेज की गांव सभा हो श्रौर जब कांस्टिट्चूशन बन जायगा तो गांव उसमें श्रा जायगा, लिहाजा इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं रहती।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, श्रापकी श्राज्ञा से में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर श्री ग्रध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

श्रीमान्, इसके मानी है कि 12—B जो नयी चीज सरकार इस धारा द्वारा रखना चाहती है, वह यह है कि रक्षा दल के सदस्य पंचायतों की बैठक में भाग लिया करें श्रौर पंचायतों पर अपना प्रभाव डालने के लिए भाषण दिया करें श्रौर उनके कार्य में अपने को सिम्मिलित कर सकें। में समझता हूं कि ऐसा करने से पंचायतों का जो स्वतन्त्र रूप से निर्णय करने का ढंग है, उसमें बाधा पड़ेगी श्रौर वातावरण विगड़ेगा श्रौर पार्टीवन्दी बढ़ेगी। सरकार समझती है कि रक्षा दल उचित कार्य करेगा, लेकिन मेरी राय में उससे बड़ी गड़बड़ियां मर्चेगी। मं नहीं समझ पाया कि सरकार ने कैसे इसे उचित समझा, कैसे पंचायतों को श्रपने निर्णय करने में सुविधा होगी? में समझता हूं कि उनके श्राने से न्याय पंचायतों के निर्णय में बाधा पड़ेगी। देखा यह गया है, श्रीमन् कि किसी की गांव में पंचायत में अपने विचार रखने से मनाही नहीं है। पंचायत के लोग किसी को बुला सकते है श्रौर वह अपने विचार पंचायत के सामने रख सकता है। में समझ नहीं सका कि क्यों इस क्लाज को रखा गया है। मन्त्री जी के भाषण के बाद में यह तय करूंगा कि यह किस गरज से उपयोगी समझा गया है श्रौर तभी कुछ श्रौर कहूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, यह काफी दलील नहीं है विरोध करने की कि समझ में नहीं श्राया। इसके रखने का कारण यह है कि गांव में विकास के कार्य गांव सभायें करती हैं श्रौर गांवों में एक बड़ा भारी ट्रेन्ड फोर्स प्रान्तीय रक्षा दल का है। जो प्रान्तीय रक्षा दल वाले गांवों में ही रहते हैं, वे तो उसके सदस्य होकर भाग ले ही सकेंगे, लेकिन जो गांवों में नहीं रहते हैं, उनके लिए यह रखा गया है। हम चाहते हैं कि दो पहिये श्रलहदा- श्रलहदा न चलें। राजा साहब ने देखा होगा कि बाहर वालों को वोट का श्रधकार नहीं दिया गया है। सिर्फ दोनों मिलकर दोनों साथ-साथ कार्य कर सकें, यही इसका मंशा है। मेरा ख्याल है कि श्रव राजा साहब समझ गये होंगे श्रौर श्रपना संशोधन वापस ले लेंगे।

महाराजकुमार बॉलेन्दुशाह - अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह घारा है उसके कारण मुझे माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय ने जो सफाई दी उसमें में पूर्णरूप से सहमत हूं कि ऐसी योजनाओं के संबंध में और कंस्ट्रक्टिय वर्क के सम्बन्ध में प्रान्तीय रक्षा दल के लोग, जिसका वर्णन उन्होंने एक ट्रेन्ड फ़ोर्स कह कर किया है, अगर वे चाहें तो काफी सहायता दे सकते है । प्रान्तीय रक्षा दल किस प्रकार काम कर रहा है, इसके सम्बन्ध में में पहले कह चुका हूं और दोबारा इस बारे में कुछ कहने की गुस्ताखी नहीं करूंगा । इस धारा के अन्दर लिखा है कि गांव सभा की बैठक में उन्हें, प्रान्तीय रक्षा दल वालों को, बोलने का अधिकार होगा । प्रक्त यह पैदा होता है कि इसका क्या महत्व है । प्रान्तीय रक्षा दल वालों को गांव सभाओं में भाग लेने के लिये एनेबिल किया जा रहा है या उनको एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि जब वे चाहें तो उनकी बैठकों में भाग लें । यदि यह चाहा गया है कि यदि गांव अभा उनको आमंत्रित करे, क्योंकि यह ज़म्भीड़ की जाती है कि भविष्य में ये बहुत सुप्रर ज़ावेंग़े,

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

230

तो मेरा कहना है कि यह प्रान्तीय रक्षा वल के लोग ऐसा कर सकते है और मुझे कोई आपित न होगी । किन्तु जिस रूप में धारा ड्राफ्ट की गई है उसका मतलब में तो यह नहीं लगाता । में उसका यह मतलब लगाता हूं कि प्रान्तीय रक्षा वल के लोगों के पास एक विशेषाधिकार रहेगा कि जब वे चाहें, चाहे गांव सभा के लोग उनको चाहें या न चाहें, गांव सभा के काम मे दखल दे सके । में तो यह न समझूंगा कि मंत्री महोदय का यह विचार है कि हमेशा गांव सभा के काम मे दखल दें । मंत्री महोदय का ऐसा विचार न होगा । किन्तु यह समस्या ग्रा जाय कि ग्रनइंवाइटेड होने के बावजूद, जनता द्वारा ग्रस्वीकृत होने के बावजूद उनको यह ग्रधिकार दिया जाय कि वहां ग्राकर गांव सभा की बातों में, दखल दें तो उसका मतलब यह हो जाता है कि वे गांव सभा की पर्टी पालिटि स में वे भाग ले सकेंगे । इससे एक तो गांव सभा की बैठकों में ग्रड़चन होगी दूसरे यह कि प्रान्तीय रक्षा दल की जो सूरत है वह ग्रौर भी बिगड़ने का ग्रंदेशा हो सकता है । मेरे नाम में कोई संशोधन नहीं है किन्तु में ग्रापके द्वारा मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें यह स्पष्ट कर दें कि जब गांव सभा की ग्रोर से यह इच्छा प्रकट की जाय कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भाग लें तो वे उनकी सभाग्रों में भाग ले सकें। ग्राप प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों के लिये एक ऐसा इनेंविलिंग क्लाज ले ग्रायें कि ग्रामंत्रित होने पर वे गांव सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजक्फरनगर)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने रक्खा गया है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भी गांव सभाओं की बैठकों मे भाग ले सकेंगे, में समझता हूं कि यह एक बहुत ही भ्रच्छा सुझाव है। यह एक बहुत ही लाभकारी चीज है। ग्रभी माननीय मंत्री जी ने यह बात बतलायी कि वह गावों में एक बाडी है जिसने देहातों में संगठन पैदा करने में, प्रान्त में श्रमदान के काम में बहुत ही ज्यादा हिस्सा लिया है। मं इससे एक कदम ग्रागे चलकर माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने गांव के संगठन में ग्रौर गांव की रक्षा के कामों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने रक्षा समितियाँ बनायीं श्रौर उन्होंने गांवों में जो प्रबंध किया उसके कारण से वहां जो वारदातें होती थीं, उनमें बहुत सुधार हो गया। इसलिये अगर ऐसे लोगों की जो गावों के सुधार में अग्रसर है, उनको हम हिस्सा लेने देना चाहते हैं तो पंचायतों के लिये यह एक बहुत ही ग्रन्छी बात होगी। इसके ग्रतिरिक्त एक बात ग्रौर भी बहुत ग्रच्छी इसमें की गयी कि चुंकि वे लोग इलेक्टेड नहीं होंगे इसलिये उनको वोट करने का श्रिधिकार नहीं होगा । सिर्फ वे श्रपनी राय ही दे सकेंगे । मैं समझता हूं कि ग्रगर ग्राप इस प्रकार से देखें तो ग्रापको मालूम होगा कि ग्राज गांव बचा तों ग्रीर गांव के लोगों को एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके संगठन के लिये, उनकी रक्षा के लिये जो कदम उठाये गये है वे बहुत ही अच्छ कदम हैं। अभी माननीय बालेन्द्रशाह जी ने इस पर कुछ आपत्ति की, लेकिन वह कोई खास श्रापत्ति नहीं है कि जिसकी वजह से यह प्रावीजन इसमें न रक्खा जाय । मै माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा ग्रच्छा प्रावीजन इस बिल में रक्खा जिसके कारण गांव पंचायतों की हर प्रकार से भलाई होगी । इसलिये में इसका समर्थन करता हं ।

श्री शिवनारायण (जिला स्ती)—श्रध्यक्ष महोदय, जो श्रमेंड मेंट उधर से श्राया है, में उसका विरोध करता हूं। प्रान्तीय रक्षा वल के लोगों को इसमें इसिलये रक्खा गया है क्योंकि उन को कोई पे नहीं मिलती और इस प्रकार से वे कोई श्राफिस श्राफ प्राफिट होल्ड नहीं करते। इसिलये उनके लिये कोई ऐसी ककावट नहीं होनी चाहिये कि वे किसी पंचायत के मे म्बर न हो सकें। भारत के एक नागरिक होने के नाते उन्हें पूरा श्रधिकार है कि वे गांव सभाश्रों के मेम्बर हो सकें। में श्रापकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो इनेबिल शब्द श्राया है तो उनको इनेबिल नहीं किया गया है, बिलक उनको पूरा पूरा श्रधिकार विया गया है कि वे गांव पंचायतें के मेम्बर बन सकें।

राज्ञा बीरेन्द्रशाह—ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सर । श्रीमान जी, मेरा कहना यह है कि ग्रभी श्री शिव नारायण जी ने जो यह कहा कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग तनस्वाह नहीं पाते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष-यह तो प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

श्री शिवन र यप—जो राजा साहब ने बतलाया मालूम होता है कि प्रान्तीय **रक्षा**-दल के सिपाही, जो गांवों में घूमते हैं उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है । उनको कोई पे नहीं मिलत है, ज्यादा से ज्यादा एकाध वर्दी उनको मिल जाती है । तो हमारा सजेशन यह है कि जो बड़ा कोष्ट इस क्लाज में है वह हटा दिया जाय ग्रौर फिर नं० (२) जो यहां ग्राया है उसको हटा दिया जाय तो १२-वी हो जायगा । तो में सरकार से कहना चाहता हूं और विरोधी-दल के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर यह रखा है। प्रान्तीय रक्षा दल के लोग गांवों में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं श्रौर बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे गांवों का उत्थान हो । क यहां पर श्रीमन्, जर्मनी का एक कोटेशन देना चाहता हूं । जर्मनी में हिटलर ने भी गांच वालों को हवाई जहाज ग्रादि में ट्रेंड कर दिया था। उनको वह तनस्वाह तो नहीं देता था, लेकिन वे बड़े ही ट्रेड ग्रौर डिसिप्लिड थें। उसी तरह से हमारे प्रान्तीय रक्षा-दल के लोग भी ट्रेंड ग्राँग डिसिप्लिन्ड है। वे गांव के भूले भटके लोगों को हर तरह से मदद करते हैं। गांव के रहने वालें को शिक्षित करते है वह श्रमदान में भी सहयोग देते हैं। ग्रपने जिले में मैन देखा है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने बड़े ग्रच्छे ग्रच्छे काम किये हैं। इस-लिये गवर्नमेंट का जो यह बिल है वह बहुत ही सुन्दर है ग्रौर में राजा साहब के ग्रमेंडमेंट का विरोध करता हं । क्योंकि इस बिल द्वारा गांव वालों को गवर्नमेंट पूरा-पूरा श्रधिकार दे रही है हमारे सोञ्चलिस्ट भाई इससे घबड़ा रहे हैं.....

श्री ग्रध्यक्ष---यह ग्रसंगत सा है।

श्री शिवनार यण—डेमोक्रेसी के नाते जितने भी लोग गांवों के ग्रन्दर हैं, जितने भी ग्रसरकारी व्यक्ति है उनको पूरा श्रिवकार है कि वे पंचायत राज के मेम्बर हो सकते हैं। जो गांव में बसते हैं उनका यह नागरिक ग्रिवकार है श्रीर किसी के नागरिक श्रिवकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। ग्रगर ग्राप उनको तनस्वाह देते होते या वे ग्राफिस ग्राफ प्रोफिट होल्ड करते तब ग्राप कह उकते थे कि उनको मेम्बर न रखा जाय। लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्यनिसिपैलिटीज के इम्पलाइज इस ग्रसेम्बलों को मेम्बरी के लिये खड़े हो सकते हैं, उनके लिये हमारी सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है उसी तरह से हमारी सरकार ने पंचायत राज के लिये प्रान्तीय रक्षा दल को ग्रवसर दिया है कि वे वहां के मेम्बर बन सकते हैं। उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन शब्दों के साथ में राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूं ग्रौर इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामदास ग्रार्य (जिला मुजफ्तरनगर)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने की तो कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं थी, लेकिन में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल हमारे प्रदेश में हमारे गांव वालों की सुधार के लिये बना ग्रीर ग्राज वे कार्य उसने किये हैं जो गांव वालों को स्वयं ग्रपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं कि हम गांव की तरक्की के लिये किस प्रकार से प्लानिंग करें। उनके जो डेवलपमेंट के कार्य हं, जो रास्ते, गिलयां ग्रीर सड़कों है उनके लिये किस तरह से लोगों को प्रेरित करें कि वे काम उनके जरिये बहुत ग्रच्छे ढंग से हो सकें। हमारी सरकार ने श्रमदान का मसला समाप्त कर दिया है जो उनके द्वारा बहुत ग्रच्छा हो सकता है। वे लोगों को इकट्ठा करके, ग्रपनी राय देकर ठीक

[श्री रामदास ग्रार्य]

हैं इमिलये जो भी सुझाव वे देंगे उनसे गांव सभाश्रों को काफी मदद मिलेगी। तो इस नाते भी हम ग्राशा करते हैं कि उनसे गांव सभाग्रों को लाभ ही होगा। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं ग्रौर माननीय श्री बालेन्द्रशाह जी ने जो सुझाव दिया है मुझे ग्राशा है कि दे उसे वापस ले लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह-माननीय प्रध्यक्ष महोदय, मैने माननीय मंत्री जी के उत्तर की सना ग्रोर मझे दख हे कि मुझे जो भय पहले था वह ग्रब भी है। जहां तक मंत्री जी का कहना हैं कि डेवलपमेट के कामों को श्रौर रचनात्मक कामो को ठीक कराने के लिए वहां पंचायत राज के लोगों को चाहते है कि मदद दें, वह जाकर डेवलपमेंट की स्कीम को समझे इसमें तो मुझे कोई म्रापत्ति नहीं है लेकिन सरकार जो उनको मधिकार दे रही है उसके मनुसार वह हर एक काम को देखेंगे और चाहे उनकी दिलचस्पी हो या न हो वह सब बातो में दखलग्रन्दाजी करेंगे। में समझता हं कि जो डेवलपमेट के कार्य ऐसे है कि जिनमें राय लेगा जरूरी हो श्रीर जैसा कि श्री बालेन्द्रशाह ने कहा उससे में सहमत हूं लेकिन मै यह पसन्द नहीं करता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पंचायत राज का वर्कर अगर दूसरी जगह का हो तो वह गांव सभा में जाकर राय प्रकट करे। में समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर मंत्री जी को यह ग्रधिकार देना ही है तो वे इसमें सँशोधन कर दे कि विकास के कार्य में या किसी ग्रौर जरूरी कार्य में राय देने के लिए वह जा सकते है। इतने मे तो मुझे श्रापत्ति नहीं है वर्ना मे समझता हं कि बन्देलखंड में जो लोग पी० श्रार० डो० का कार्य करते हैं उनका काम संतोषजनक नही है। जैसा कि कुछ भाइयों ने बताया हमारे यहां पंचायत राज का काम जो है वह ऐसा है कि वहां कोई काम नहीं हुआ है और जो काम उन्होंने किया है उससे हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते ग्रीर वह लोग वहां पर वह रेस्पेक्ट नहीं रखते है और ग्रगर में यह कहं तो ताज्जुब न होगा कि हमारे यहा पी० ग्रारं डी॰ लोगों को लोग समझते है कि वह बीच के दलाल है, ऐसी भावना वहां लोगों में है। उनको समझा जाता है कि वह थाने वालों श्रौर लोगों के बीच के मामलों को तय कराते है। मे नहीं कह सकता कि श्रौर जिलों में क्या बात है। मै यह नहीं चाहुंगा कि वह हर लोग मामले में हर जगह जाकर ग्रपनी राय रखे इसमें यह नहीं रखा गया है कि वह डेवलपमेंट के काम ही में ग्रपनी इस तरह से तो वह हर बात में जाकर श्रपनी राय छांटने लगेंगे। में मंत्री जी से इसलिए प्रार्थना करूंगा कि वह या तो जैसा मैने कहा इसमें संशोधन कर लें, उसे मैं स्वीकार कर लुंगा वर्ना में श्रपने संशोधन को वापस लेने को तैयार नहीं हं।

*श्री मोहनलाल गौतम—श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रापके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हर मुहक्तमें के हर श्रादमी को बेइमान कहने का श्रिधकार सदन के मेम्बरों को है श्रौर इस सम्बन्ध में उनकी एक त्रिविलेज्ड पोजीशन है लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि वह लोग भी कहीं किसी मौके पर हम सबको बेइमान न कहने लगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस मामले में अपनी भाषा को संयत रखें। जैसे कि श्रभी पी० श्रार० डी० वालों को टाउट श्रौर बलाल कहा गया यह चीज ठीक नहीं है। मैंने श्रापके, श्रध्यक्ष महोदय, नोटिस में यह बता ला दी कि ऐसे शब्द किसी कर्मचारी या श्रफसर के लिए कहना माननीय सदस्यों के लिए श्रोभा नहीं देता।

महाराजकुमार बालेन्द्रशाह जी ने कहा कि यह होना चाहिए कि जब पंचायत उनको बुलाये तब तो वह ग्रायें वर्ना न श्रायें। यह भी एक सोचने की बात है। ग्रगर पंचायतों को यह ग्रायिकार दिया जाय कि वह जब बुलायें तभी ग्रायें तब दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि वह लोग भी चब चाहें उनके बुलाने पर श्रायें श्रौर जब चाहें न श्रावें। यह नहीं हो सकता कि हुक्म दें तो ग्रायें श्रौर जब श्राप श्रिवकार दें ऐसी संस्था को

^{*}वस्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वालन्टरी वर्क कर रहीं है श्रौर श्राप उनको बुलाकर काम लेना चाहते है उनसे काम करने के लिए कहते है कि किस नरह सड़कें बनावें, किस तरह नालियां बनवावें श्रौर इन कामों को करने के लिये बुलाने का श्रधिकार पंचायतों को नहीं होना चाहिये, बिल्क उन श्रादिमयों से कह दिया जाय कि वे श्राकर बैठकर वातें कर सकें। जब वे दोनों एक स्थान पर बैठकर सलाह करेंगे तो कार्य श्रच्छा होगा। यह बात साफ है कि उनको राय देने का श्रधिकार न होगा। मुझे श्राशा है कि माननीय राजा साहब इस बात को समझ श्रपने संशोधन को वापस कर लेंगे श्रौर मेरी बात को मान लेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष-क्या ग्राप इसमें कोई नया संशोधन दे रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, जो ड्राफ्ट बिल में है वही मान लेंगे ग्रौर ग्रपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री ग्रध्यश्र—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(प्रक्न उपस्थित किया गया श्रौर श्रस्वीकृत हुस्रा ।)

श्री रामनिरायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी ग्राज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं ि "खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-C की उपधारा (1) का भाग (b) (i) निकाल दिया जाय। ग्रध्यक्ष महोदय, यह १२ सी० जो इस विधेयक में है वह पहले विधेयक से कुछ भिन्न है ग्रौर एक नए विषय में लाई गई है जिसमें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में पेटीशंस का ग्रधिकार दिया जा रहा है ग्रौर नियत ग्रधिकारों के सामने पेटीशन प्रेजेन्ट करेंगे तो किन किन कारणों से इन चुनावों के खिलाफ पेटीशंस हो सकती है। माननीय स्वशासन मंत्री को यह बतलाना नहीं है कि जब पिछली मरतबा जिला बोडों के चुनाव हुये थे तो वहां सरकारी ग्रादेश यही भेजे गये थे कि रिटनिंग ग्रफसर स्वयं नामिनेशन फार्म भर दिया करें ग्रौर नामिनेशन पेपर के भरने में कोई गड़बड़ी के होने पर उस पेपर को रिजेक्ट न माना जाय ग्रौर पिछली मरतबा जो चुनाव हुये थे तमाम रिटनिंग ग्राफिसरों ने फार्म लेकर ग्रौर जितनी इत्तला थी उनको लेकर परचे भर दिये। माननीय स्वशासन मंत्री को यह मालूम है कि लोक सभा, विधान सभा ग्रौर म्युनिसिपल बोर्ड या जितने पिछले चुनाव हुये.........

श्री ग्रध्यक्ष—में समझता हूं कि ग्राप प्रपना दूसरा प्राविजो वाला प्रस्ताव भी साथ-साथ ले लीजिये तो ज्यादा ग्रच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—में ऐसा निराश नहीं हूं कि माननीय मंत्री मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। ग्रगर मान लेते हूं तो फिर वह ग्राटोमेटिकली खत्म हो जायगा। ग्रगर इसको मान लेगेंतो मेरा वह संशोधन नहीं ग्रायेगा। यह तो मेंने इसी ग्राशय से रखा है। तो में निवेदन कर रहा था कि लोक सभा, विधान सभा, म्युनिसिपल बोर्ड ग्रादि के चुनाव में भी सरकार की तरफ से यह हिदायतें एलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हिदायतें दी गई थीं कि टेकिनिकल मिस्टेक्स पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट न हो ग्रौर इस विषय पर तमाम चुनाव विशेवज्ञों का ध्यान ग्राक्षित हुग्रा है। में दूर नहीं जाता हूं। ग्रभी माननीय हुकुम सिंह जी के एलेक्शन की तरफ ध्यान दिलाता हूं। इलेक्शन हो गया ग्रौर दोनों तरफ से काफी रुपया खर्च हुग्रा ग्रौर काफी परेशानी उठाई गई, लेकिन एक पार्टी का गलत तरीके से नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था। इसिलये तमाम इलेक्शन ही वायड हो गया ग्रौर यह धारणा लोगों की होती चली जा रही है कि कम से कम एलेक्शन पेटीशन की एक ऐसी ग्राउन्ड होनी चाहिये। जहां तव कि नामजदगी के पर्चों........

श्री ग्रध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह आपको स्वीकार न हुआ तब आप दूसरा पेश करेगें ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी-जी हां, तब तो मूव करूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष-तो ग्राप एक साथ मूव कर दीजिये। क्योंकि उसका उससे सम्बन्ध है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो में श्रापकी श्राज्ञा से दूसरा संशोधन भी पेश किये देता हूं। में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई घारा 12-C की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जायः—

"Provided that if within three days, of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority, the election concerned, will be stayed. Illuster the decision of such application."

तो इस प्राविजन में मैंने रक्ला है कि ग्रगर किसी नामजदगी के परचे मे कोई गलती होने से वह परचा रद कर दिया जाय तो वैसी हालत में ग्रगर कोई एलेक्शन होने वाला हो तो फौरन रोक दिया जाय श्रौर पहले उस प्वाइंट को तय कर लिया जाय श्रौर उसके बाद एलेक्शन हो । श्रभी मैने हकम सिंह के एलेक्शन को ले करके निवेदन किया कि स्नामतौर पर कुछ लोग महमूस करते है कि नामि-नेशन पेपर के रेजेक्शन वाला मसला तो श्रवस्य ही एलेक्शन के पहले तये होना चाहिये श्रौर जहां तक मेरी जानकारी है एलेक्शन कमीशन भी इस पर विचार कर रहा है ग्रौर कई प्रदेशों से एलेक्शन कमीशन के सःमने इस किस्म के सुझाव श्राये हैं। इसलिए मै श्राशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस प्रस्ताव को मान लेगे। क्योंकि जहां तक टाउन एरिया का सवाल है, म्यू-निसिपल बोर्ड का सवाल है उनकी तो संख्या कम है, लेकिन पंचायतों की संख्या करीब ३५ हजारे के है। ग्रगर ग्रौसतन ३० हजार भी मान ले तो भी काफी इतनी बड़ी संख्या लोगों की हो जाती है। उनके नामजदगी के परचे मंजूर करने में श्रीर श्रनियमित होने पर रिजेक्ट करने में काफी श्रव्यवस्था श्रौर परेशानी पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का स्याल इस किस्म का नहीं है। ग्रगर सरकार इसको यहां से हटा दे श्रौर नियमों में व्यवस्था कर ले तो में समझता हूं कि इससे प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियतें हो जायंगी। ऐसी दिक्कतें माननीय स्वजासन मंत्री जी पहले पेश भी कर चुके है। उनकी घारणा ऐसी है कि जितनी कम अप्लोकेशंस हो सकें उतना ही अच्छा है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं एक नया रास्ता न खुल जाय। ग्रब तक जो प्रया रायज थी कि सरकार या डाइरेक्टर

श्री ग्रब्दुल मुईज खां—ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्राईर सर। ग्रध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी का जो संशोधन है उसकी वंडिंग ग्रगर देखेंगे तो "Provided that if within three day of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority the election concerned will be stayed, till after the decision of such application." यह "इज" जो है यह किस नाउन को गवनं करता है ? इससे तो ग्रापका संशोधन विलक्ष गलत हो जाता है।

श्री श्रध्यक्ष-स्थाप ठीक कह रहे हैं । इसमें जो "श्राफ" है वह बिलकुल गलत है । "श्राफ" को हटा देने से काम चल जायगा ।

श्रीर(मन(रायण त्रिपाठी--प्रध्यक्ष महोदय, मं सनसता हूं कि जब में ड्राक्टिंग कर रहा था तो 'एन अन्त्रोकेशन लिखना भूल गया था। प्रब' 'श्राफ' ''रिजेश्सन आफ ए नामिनेशन पेपर, कामा ऐन अन्त्रोकेशन इज्ञा....' यह हो जाय तो ज्यादा अञ्छा होगा : श्री ग्रध्यक्ष-मेरे स्थाल से 'of' ग्राप निकाल दे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है, श्रगर श्राप चाहें तो हटा मकते है।

श्री ग्रध्यक्ष--- 'of'' हटा दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हां, ग्रापकी ग्राज्ञा से हटा देता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय मंते संक्षेप में वे तमाम एप्रीहेशन जो विचार मेरे थे ग्रौर पृष्ठभूमि मे जो विचार काम कर रहे है वह मेने बता दिये हैं ग्रौर में समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री को कोई एतराज न होगा। क्योंकि जैसा मैने कहा इस सम्बन्ध में काफी दिक्कते हो जायेगी।

श्री ग्रध्यक्ष--ग्रब ग्राप श्रपना भाषण कल जारी रखें। माननीय वित्त मंत्री कुछ सुचना देना चाहते है कल के कार्य के सम्बन्ध में।

ग्रगले दिन के कार्यक्रम की सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) — कल तो यह बिल चलेगा। प्रिविलेज मोशन का डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर जिक चलेगा।

श्री अध्यक्ष--तहीं, ग्रापने मुझसे यह कहा था कि इलेक्ट्रीमिटी बिल चलेगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गौतम जी शायद कल बाहर तशरीफ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नही जा रहे हैं।

(इसके बाद मदन ५ बजकर १ मिनट पर भ्रगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थिगित हो गया।)

लखनऊ, ५ मई, १६५४ । कैलासचन्द्र भटनागर, सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४ पर)

Copy of letter No. XI-F 147-G 41-13421-13576, dated June 21, 1949. from the Director of Medical and Health Services, U. P., to Assistant Director of Medical and Health Services, of Ranges, all civil surgeons, all district medical officers of health and all Municipal Medical officers of health.

Subject:—Fees chargeable by medical officers-in-charge of branch dispensaries located in rural areas.

I have the honour to refer you to the Press Communique No. U. O. 1077A/V, dated November 10, 1948, a copy of which was sent to you with my circular endorsement No. M—443/G-147-G/41,—dated December 1, 1948, and to say that the rates or fees prescribed therein will apply also to Government medical officers in charge of branch dispensaries, whether male or female, located rural areas. These rates will operate within an area of 2 miles around the place where the dispensary is located.

If a medical officer has to go beyond the limit prescribed above, the rees will be settled by mutual agreement, but they should never exceed double of those laid down in the press communique referred to above. The fees thus settled, will of course be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.

It should please be noted that even for attending on emergent cases a doctor should not leave the dispensary during working hours. All the medical officers under you should please be apprised of the above orders and warned to observe this rule strictly.

निश्यवां २३७

नत्थी 'ख'

(देखिये ताराँकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पष्ठ १८४ पर)

GOVERNMENT OF THE UTTAR PRADESH MEDCIAL (A) DEPARTMENT.

7 5947 of 48-A/V-1353-47, dated Lucknow November 23, 1949 PRESS MEMORANDUM

It is hereby notified for the information of the general Public that Government have fixed the following rates of fees to be charged by different classes of Government medical officers for visits to patien at their residences with the municipal headquarters limits. The fees are exclusive of conveyance charges which have to be brone by patients:—

During Day

(1) Professors of the Sarojini Naidu Medical College, Agra. Who are allowed consultation practice Rs. 16 per visit.

(2) Civil Surgeons and Readers of the Sarojini Naidu Medical College Agra who are allowed private practice, Rs. 8 per visit.

(3) Women Doctors incharge of bigger state Hospital (Such as Agra, Kanpur, Lucknow, Banaras and Allahabad) Rs. 8 per visit.

(4) Medical Officers of P. M. S. (Grade I in the Men's and Women's Branch and Lecturers of the Sarojin Naidu Medical College, Agra), Rs. 4 per visit.

(5) Medical Officees of P. M. S. Grade II and of P. S., M. S. (Men's and Women's Branches), Rs. 2 per visit.

During Night.

The scale of fees during night shall be double of the above.

- 2. Fees not exceeding the above rates may be charge by the Government Medical Officers from private patients who visit them at their residence for consultation outside Hospital hours. The private patients of the medical officers shall not be entitled to free supply of medicinse dressings, etc., from Hospitals, unless they are admitted as indoor patients. In other cases where medicinse are supplied to such patients from hospitals, the charges according to the prescribed rates shall be paid unless there are special orders of Government applicable in particular case for free supply.
- 3. It a medical is required to go beyond the Municipal Headquarters limit, the fees will be settled by mutual agreement, but they shall never exceed double the rates laid down above. The fees thus settled will be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.
- 4. Government Medical Officers at Hospitals or dispensaries shall not leave the Hospitals and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances. This applies to Medical College Hospital also.
- 5. All Government meidcal officers are warned not to accept fees higher than the prescribed rates even if offered willingly by patients.

(Sd.) S. P. PANDE, Secretary.

OFFICER OF THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SER. VICES UTTAR PRADESH

No. XI. F-147-G 41/14638-836, dated Lucknow May 24, 1950 Forwarded to:

- (1) Assistant Director of Medical and Health Services, I to IV Ranges.
- (2) All District Medical Officers of Health
- (3) All Civil Surgeon.
- (4) All Municipal Medical Officers of Health.
- (5) Dy. Director (W) Maternity Section and Women Section.
- (6) Assistant Directors (Epidemiology), Health Publicity and Provincial Hygienic Institute.
- (7) Superintendent, Government Vaccine, Department Patwa Dangar.
 District Nainital.
- (8) Public Aralyst to Government.
- (9) All School Health Officers.
- (10) Anti-Malaria Officers Lalitpur (Jhansi and Gokul Nagar Distric Nainital.
- (11) Principal. Medical College and Superintendent, Sarojini Naidu Hos pital, Agra.
- (12) Superintendent, Mental Hospitals, Agra, Bareilly and Banaras,
- (13) Superintendent, K. E. Sanatorium, Bhowali.
- (14) Superintendent, Balrampur Hopital, Lucknow.
- (15) Superintendent, Lala Lajpat Rai Hospital, Kanpur
- (16) Chemical Examiner to Government, Agra.
- (17) Medical Superintendents. :-
 - 1 Dufferin Hospital, Lucknow.
 - 2. Lady Loyall Hospital, Agra.
 - 3. Alice Horsman Hospital, Kanpur.
 - 4. Ishwari Memorial Hospital, Banaras.
 - 5. Dufferin Hospital, Allahabad.
- (18) Director, U. P. Blood Bank, Luckhow.
- (19) Secretary, State Medical Faculty.

For information and communication to all medical officers working under them in continuation of this office Circular Letter No. XI-918-1170, dated January 9, 1950.

- 2. The Medical Officers should not leave the hospital and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances as noted below:—
 - (1) Attendance on Government Servants if any one's condition is acutely serious demanding immediate attention and he cannot be transport immediately to hospitals.
 - 2. When a medical officer has been treating a case at the letter's residence and the condition of the patient gets a sudden deterioration and he cannot be brought to the hospital and the Medical officer is called by his relatives during hospital working hours.

नित्ययां २३६

- 3. If any emergent call is made on the Medical Officer as a result of some serious accident (including Railways and Roadways) etc. when the patient or-patients cannot available in the vicinity.
- 3. The procedure that should be adopted by the medical officers when he leaves the hospital under any of the above circumstances during hospital working hours is that he should inform the other doctor in the hospital, available, or the senior compounder on duty as the case may be, subsequently all such absence should be recorded in register which may be initialled by the Civil Surgeon weekly in the case of District Headquarter Hospital and in case of branch dispensaries—the report be—submitted to the Civil Surgeon or District Medical—Officer of Health as the case—may—be, in writing.
- 4. A monthly report showing the particulars of emergent cases which the Medical officers attended during working hours in the last month should poease be obtained and submitted to this officer positively by the the next month. A strict watch should please be kept on the Medicall Officers and see that the number of emergent calls is not allowed to be large.

Yours faithfully,

(A. P. BAJPAYEE),

Capt. P. M. S.

Director of Medical and Health Services, U.P.

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू॰पी ऐक्ट ३, १६२१ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६२१ को संशोधित करना म्रावश्यक है म्रतएव निम्नलिखित म्रिधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम श्रीर प्रारंभ ।

- १—(१) यह म्रिधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) म्रिधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।
- (२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

एक्ट इ,१६२१ की प्रस्ता-वना का संशोधन । यू०पी०ऐक्ट ३,१६२१ की घारा २ का

संशोधन ।

१-क-इलाहाबाद यूनिर्वासटी ऐक्ट, १६२१ (जिसे यहां पर ग्रागे चल कर मूल ग्रिधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) के तीसरे पैराग्राफ से शब्द "unitary" श्रीर शब्द "and residential" निकाल दिये जायं।

२--मूल अधिनियम की घारा २ में :---

- (१) खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
- "(a) College means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statues."
- (२) खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा दिया जाय--
 - "(aa) Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."
 - (३) निम्नलिखित को खंड (d) ग्रौर (e) के रूप में रख दिया जाय-
 - "(d) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognised by the University."
 - "(e) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a College or a hostel."

- (४) खंड (f) में शब्द "college" के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जायं ।
- (x) खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (gg) के रूप में बढ़ा विया जाय—
 - "(gg) 'Student of the University means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."
 - (६) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
 - "(i) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."
- (७) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (m) के रूप में बढ़ा विया जाय--
 - "(m) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३---मूल ग्रिविनियम की घारा ५ में:----

यू॰पी॰ऐक्ट ३,१६२१

- (१) खंड (I) में शब्द "the University may think fit" की धारा ५ के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" का संशोधन। रख दिये जायं।
 - (२) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
 - "(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—
 - (a) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or carried on research in the University under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or
 - (d) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or
 - (c) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statues and ordinances, and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

- (३) निम्नलिखित खंड (४) के रूप में रख दिया जाय to recognise associated colleges.
- (४) उपधारा (6) में शब्द "hostels" के पश्चात् शब्द "and Associated Colleges", बढ़ा दिये जायं।

मू०पी०ऐक्ट ३,१६२१ की घारा। ६ का संशोधन ४—मूल ग्रिषिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक संड के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू॰पी॰ ऐक्ट ३१६२१ की घारा ७ का संजोधन

४—मूल ग्रिधिनियम की घारा ७ में उपघाराओं (१) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

- "(1) Teaching of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in the University or in an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations.
- The authorities responsible for organising such teaching shall be prescribed by the Statutes.
- (2) The courses of study and the curriculum shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.
- (3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels.
- Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University.
- (4) Where attendance at a course of instrution is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such conditions shall include provision for attendance at teachnig referred to in sub-section (1)."

यूव्पी ऐक्ट, ३, १६२१ की भारा = का संज्ञोचन ।

- ६—मूल ग्रिधिनियम की घारा द के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
 - (1) The State Government shall have the the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may directe of the University its buildings laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or

recognized by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

- (2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.
- (5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

७---मूल म्रिघिनियम की घारा १० में---

(१) उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपघारा (2) निकाल दी जाय --

द-मूल ग्रविनियम की घारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time office 'The-vice- of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.
 - (2) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office, of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

यू०पी० ऐक्ट ३,१६२१ की घारा १० का संजोघन ।

यू०पी० ऐक्ट ३,१६२१ की घारा ११ का संज्ञोधन।

- Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.
- (3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section(2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
- (4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no new name has been added under sub-section (3) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with subsections (2) or (3).
- (5) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 2,000 per month and be provided a furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowace of Rs. 200 per month.
- (6) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (7) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.
- (8) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.
- (9) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with subsection (6) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities.

ह--मूल ग्रिधिनियम की घारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया

यू०पी०ऐक्ट ३,१६२१ की घारा १२ का संशोधन।

- Powers and and academic officer of the University, and duties of the vice-Chancellor, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University He shall be an ex-officio member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meeting of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.
- (2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.
- (3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:
- Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.
- (4) (a) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.
- But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.
 - (b) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

- the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regadring the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.
- (b) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinance."

यू०पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा १३ का संजोधन।

१०—मूल ग्रिधिनियम की धारा १३ में उपधाराम्रों (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

- "The Treasure. 13. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of subsections (2) to (4) of section 11 shall apply as though for the words "Vice-Chancellor" the word "Treasurer" had been substituted therein.
 - (2) The term of office of the Treasurer shall be six years. but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.
 - (3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (6), (8), (9) and (10) of section 11 shall mutatis mutandis apply to the office of the Treasurer.
 - (4) The Treasurer shall be an ex-officio member of the Excutive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.
 - (5) The Treasurer shall have the duty-
 - (i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment),
 - (ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० एक्ट ३, १६२१ की धारा १४ संजोधन।

- ११—मूल अधिनियम की घारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
 - 14. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of "The Registrar. the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—
 - (i) the Vice-Chancellor;

- (ii) an educationist nominated by the Chancellor;
- (iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.
- (2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed the Ordinances.
- (3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be ex-officio Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.
- (4) He shall make all arrangements for an conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
- (5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statues and the Ordinances."

१२--मूल ग्रिघिनियम की धारा १६ में---

- (१) मद ^V के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "V. The Faculty Boards."
- (२) निम्नलिखित मद VI के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

 "VI. Selection Committees for the appointment of teachers."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की घारा १६ का संशोधन।

१३—मूल ग्रिधिनियम की वर्तमान घारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

17. (1) The Court shall consist of the following persons, "The Court namely:

Class I-Ex-officio members:

- (i) the Chancellor,
- (ii) the Vice-Chancellor,
- (iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,
 - (iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,
 - (v) the Treasurer,
 - (vi) the members of the Executive Council,

यू० पी० एक्ट ३, १६२१ की घारा १७ का संशोधन।

- (vii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,
- (viii) all Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments.
 - (12) such other ex-officio members as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members:

- (x) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four.
- (xi) All persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University.

Class III---Other members :

- (xii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.
- (xiii) Persons nominated by associations or individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes to or for the purposes of the University.
- (xiv) Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.
- (N) Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.
- (xvi) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.
- (xvii) Representatives of donors other than those included in items (xi) and (xiii).
- (Aviii) Representatives of the teachers of the University other than those in cluded in Class I, the Wardens, the non-Collegiate Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes.
- (xix) Persons appointed by the Chancellor.
- (2) The total number of members including the ex-officio but excluding the life members shall not exceed 125.
- (3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.
- (4) The number of members referred to in items (xii) to (xix) of sub-section (1), the manner of their appointment and their tenure shall, save where otherwise provided for in this section, be prescribed by the Statutes.

'5) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an ex-officio or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

१४-मूल ग्रविनियम की धारा १६ में--

- (१) उपधार, (1) में शब्द "the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances)" के स्थान पर शब्द "such acts of Executive and Academic Councils as are not in accordance with this Act, the Statutes, or the Ordinances." रक्खे जायं।
- (२) उपधारा (2) में निम्निलिखित खंड (e) के रूप में रख दिया जाय—
 "(e) of considering and passing resolutions on any
 matter connected with the University."

१४-मूल प्रिविनयम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-

- 21. (1) Subject to the provisions of this Act and the "Powers and duties Statutes, the Executive Council shall of the Frecutive have the following powers and duties, Council. namely—
 - (a) to hold, control and administer the property and funds of the University;
 - (h) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University;
 - (c) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
 - (d) to prepare the budget of the University;
 - (e) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances:
 - (f) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts;
 - (g) to appoint examiners and to arrange for the holding of examinations and publication of results;
 - (h) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition;
 - (i) to arrange for and direct the inspection of associated colleges, colleges, hostels and other places of residence of students;
 - (j) to direct the form and use of the Common Seal of the University;

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा १६ का संशोधन !

यू०पी०ऐक्ट ३, १६२१ की घारा २१ का संशोधन ।

- (k) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.
- (2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advice the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.
- (3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.
- (4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.
- (5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ३,१६२१ में एक नई घररा का बढ़ाया जाना। १६—मूल म्रिधिनियम की घारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित नई घारा 22-A के रूप में बढ़ा दी जाय—

"The Standing Committee of the Academic Council.

22-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The Constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३,१६२१ की घारा २३ का संशोधन। १७—मूल ग्रिंघिनियम की वर्तमान घारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

of Reference. 23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Treasurer;
- (iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
- (iv) two persons to be nominated by the State Government.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee,

- (3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resourcess of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.
- (4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

१८-मूल प्रिधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-

24. (1) The University shall include such Faculties as may "The Faculties. be prescribed by the Statutes.

- (2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.
- (3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.
- (4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.
- (5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.
- (6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head."

१६-- मुल ग्रिधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence Health and Discipline Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय।

१६-क-मूल म्रिघिनियम की घारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित घारा २८ के रूप में रख दिया जाय-

28. (1) Save where "Manner of to officers expressly provided the contrary, to officers and members of the authorities of appointment the University shall, as far as may be, be of officers and chosen by methods other than election. members of Authorities,

२७ य० ₹, ऐक्ट, में १६२१ नयो

य० ऐस्ट १६२१ की धारा 28 धारा का संशोधन।

एक्ट १६२१ धारा का संशोधन । एक बढामा जाता ।

- (2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
- (3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की घारा २६ का मंशोधन। २०—मूल म्रिधिनियम की घारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया

- "Teachers. 29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated College shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.
- (2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.
- (3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Manangement without the advice of the Selection Committee."

य० पी० ऐक्ट ३,१६२१ में एक नयी घारा का बढ़ाया जाना।

२१—मूल ग्रंघिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें 29-A श्रौर 29-B, के रूप में बढ़ा दी जायं—

'The Selection 29-A. (1) There shall be a Selection Committee. Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman:
- (ii) the Dean of the Faculty concerned;
- (iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases;
- (iv) the Head of the Department concerned;
- (v) a member of the Executive Council not being a teacher to be chosen by the Council;
- (vi) where the appointment is to be in an Associated College, the Principal of that college.
- (2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).
- (3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger

नित्थयां २५३

number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

- Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of study is prescribed for a post-gradutae degree shall be deemed to be a subject of study.
- (4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.
- (5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendations in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation.

"The Consultative 29-B. (1) There shall be established a Committee. Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

- (2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.
- (3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

२२--मूल श्रिधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की घारा ३० का संशोधन।

- 30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provided for the following—
 - (a) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;
 - (b) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards

- of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the institution and maintenance of colleges and hostels;
- (d) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University;
- (e) the classification and mode of appointment of teachers:
- (f) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (ff') the institution of degrees and diplomas;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions;
- (1) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition;
- (j) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;
- (L) the establishment of departments of teaching in the Faculties;
- (1) the maintenance of a Register of Registered Graduates:
- (m) the holding of Convocation;
- (n) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes; and
- (o) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३,१६२१ की घारा ३१ का संशोधन । २३—मूल ग्रिधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" ग्रीर "it" के बीच के शब्द "returned there to" निकाल दिये जांय-

यू० पी०. एक्ट ३ १६२१ की धारा ३२ का संशोधन। २४--मूल ग्रिधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

32. (1) Subject to the provisions of this Act and the "Ordinances. Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

- Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely
 - a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
 - (c) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomus of the University:
 - the conditions under which students shall be admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of doglees and diplomas;
 - the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University;
 - (e) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University;
 - (f) the number, qualifications, emoluments and terms and and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University:
 - (g) the lees which may be charged by the University for any purpose:
- (h) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in colleges and hostels:
- (i) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (j) the conduct of examinations;
- (k) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University;
- (1) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes;
- (m) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

२५—मूल ग्रिधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्न-लिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Faculty Board but may reject the draft received or return it to the Faculty Board for further consideration together with its own suggestions. यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ३४ का संशोधन। यू० पी० एक्ट ३, १६२१ की धारा ३६ का संजोधन।

२६--मूल ग्रिधिनियम की धारा ३६ में--

(१) उपधारा (3) में शब्द "any member of the Residence. Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (4) में शब्द "Management" के पहले आये हुए शब्द "Committee of" निकाल दिये जायं—

य० पी० ऐक्ट ३, १६२१ में बो नयी धाराख्रों का बढ़ाया

जाना ।

२७—मूल ग्रधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36-A ग्रौर 36-B के रूप में बढ़ा दी जायं—

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be "Associated named by the Statutes.
Colleges.

- (2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.
- (3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.
- (4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.
- (5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be be made to the Executive Council.
- (6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

36-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to Non-Colle-supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

२६—मूल ग्रिधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (2) ग्रौर (3) निकाल दी जायं ग्रौर निम्नलिखित नयी उपधारायें (4) ग्रौर (5) के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० एक्ट ३, १६२१ की घारा ३७ का संशोधन।

- "(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.
- (5) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise for the purpose of admission to a course of study for a degree any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२६--मूल ग्रिधिनियम की घारा ३८ में--

(१))उपधारा (I) के ग्रन्त में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" बढ़ा बिये जांय—

यू० पी० एक्ट ३, १६२१ की धारा ३८ कासंशोधना

- (२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
- "(3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

- "The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Adademic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."
- (४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय—
- "(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की घारा ४० का संशोधन। ३०--मुल प्रिधिनियम की धारा ४० में--

- (१) उपधारा (1) के भ्रन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय-
- "The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing. The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette" के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (c) of sub-section (1) of 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की घारा ४२ का संशोधन।

३१—मूल ग्रिधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ४४ का संशोधन।

- ३२—म्ल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—
 - "(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३३—मूल ग्रधिनियम की धारा ४५ मे शब्द "members" के पञ्चात् फल स्टाफ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

for by reason of some person having after part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

3४—मूल श्रिधिनियम की धारा ४७ में शब्द श्रीर श्रंक "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द श्रीर श्रंक "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जायं।

यू० पी० एक्ट, ३, १६२१ की धारा ४५ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट ३,१६२१ की घारा ४७ का संशोधन।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३५- मूल श्रिधिनयम, परिनियमों (Statutes) या श्रध्यादेशों (Ordinances) म किसी बात के होते हुए भी इलाहाबाद यूनिर्वासटी (मंशोधन) श्रिधिनयम, १६५४ (जिसे यहां पर श्रा रे चल कर "संशोधन श्रिधिनयम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन श्रथवा संगठित किसी निर्वाचिन श्रिधिकारी श्रथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस श्रिधिनयम द्वारा संशोधित मूल श्रिधिनयम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) श्रिधिकारी श्रथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित श्रथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा !

३६—मूल ग्रिधिनियम ग्रथवा संशोधन ग्रिधिनियम में किसी बात के होते हुए भी संशोधन ग्रिधिनियम के प्रचलित होने क पश्चात् चांसलर किसी भी लमय किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है ग्रौर ऐसी नियुक्ति के लिए घारा ११ में विणत प्रिक्रिया का श्रनुसरण करना श्रावश्यक नहीं होगा । इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन ग्रिधिनियम द्वारा संशोधित मृत्र-के प्रिनियम के ग्रधीन वाइस-चांसलर के सभी ग्रिधिकारों का प्रयोग तथा श्रीतियों ग्रौर कृत्यों का सम्पादन करेगा ग्रौर एक वर्ष तक श्रपने पद पर रहेगा । परन्तु ग्रीह ग्रावश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर ग्रविध को एक वर्ष तक हुए सकना है।

३७—संशोधन श्रिधिनियम के सरकारी गजट में अथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करें, जो संशोधित मूल श्रिधिनियम के श्रनुसार यूनिर्वामटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिए सामान्यतः श्रावश्यक हो जिसके श्रंतर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है श्रौर ऐसे परिनियमो के प्रचलित होने (coming into force) के दिनांक निश्चित करे।

इस घारा द्वारा प्राप्त ग्रिधिकारों के ग्राधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन ग्रिधिनियम द्वारा संशोधित मूल ग्रिधिनियम के ग्रिधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें ग्रिधिकांत (supersede) न कर दिया जाय।

३८--राज्य सरकार मूल श्रिष्ठिनियम के उपबन्धों से संशोधन श्रिष्ठिनियम हारा संशोधित उक्त श्रिष्ठिनियम के उपबन्धों के प्रति संश्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में श्राज्ञा प्रकाशित करके--

(क) ग्रावेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल ग्रिधिनियम उस कालाविध में जिसे श्राज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification), परिवर्धन ग्रथवा लोप

(omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह स्नावश्यक प्रथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा: या

- (ल) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मुल ग्रिधिनियम के ग्रधीन ग्रौर ग्रनुसार यूनिवसिटी प्राधिकारी संगठित ग्रथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवसिटी के ऐसे प्राधिकारों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ग्रविकार ग्रथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य ग्रौर कृत्य संशोधन ग्रधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों हार, प्रयक्त ग्रेथवा सम्पादित किये जायेंगे; या
- (ग) ग्रादेश दे सकती है कि संशोधित ग्रिधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statutes) ग्रध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित श्रौर श्रावश्यक समझे, उस समय तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई वात या कार्य करके उसे ऋषिकांत न कर दिया जाय ; या
- (घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे ग्रन्य ग्रस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह भ्रावश्यक भ्रथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन ग्रिधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई श्राज्ञा न दी जायगी।

उद्देश्य श्रौर कारण द्याराण इलाहाबाद यूनिवासटा ऐक्ट ग्राज से ३२ वर्ष पूर्व सन् १९२१ ई० में बना था। इस राज्य के विश्वविद्यालयों में सुवार का प्रश्न सन् १६३८ से हीं शासन के विचाराधीन रहा है। जबकि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी तब से इस समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रायोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली की त्रुटियों पर विशेषरूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "जांच सिमिति" ने, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री भ्रो० एच० मूथम थे, पूरी तौर पर जांच की है। प्रस्तुत विषेयक में विभिन्न समितियों एवं ग्रभिकरणों की सिफारिशों के ग्रोघार पर इलाहाबाद विक्वविद्यालय के विघान और कार्य-प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया गया है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हर गोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ मई, १६५४

वियान सभा की बँठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बर्ज दिन में स्रब्यक्ष, श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर, की श्रध्यक्षता में स्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

ग्रंसमान सिंह, श्री ग्रक्षयवर सिंह, श्री ग्रनन्तस्वरूप सिंह, श्रो ग्रब्दुल मुईज खां, श्री ग्रब्दुल रऊफ़ सां, श्री ग्रम्तनाथ मिश्र, श्री च्रलीजहीर, श्री सैयद ग्रवघशरण वर्मा, श्री ग्रवघेश प्रताप सिंह, श्री ग्रशरफ़ ग्रली खां, श्री म्राशालता व्यास, श्रीमती इरतजा हुसैन, श्री इस्तफा हुसैन, श्री उदयभान सिंह, श्री उमाञंकर तिवारी, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री उम्मेद सिंह, श्री उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री ऐंबाज रसूल, श्री ग्रोंकार सिंह, श्री कर्इयालाल, श्रो कमलासिंह, श्री कमाल ग्रहमद रिजवी, श्री करनसिंह, श्री कल्याणचन्द

मोहिले उपनाम खुझन गुरु, श्री कल्याण राय, श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री कालीचरण टंडन, श्री किन्दर लाल, श्री किशनस्वरूप भटनागर, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री कुपा शंकर, श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री कृष्णशरण आर्य, श्री केवलसिंह, श्री केशभान राय, श्री केशवगुप्त, श्री केशव पांडेय, श्री कैलाशप्रकाश, श्री खयाली राम, श्री खुशीराम, श्री गंगाघर, श्री गंगाघर जाटव, श्री गंगाघर शर्मा, श्री गंगा प्रसाद, श्री गंगा प्रसाद सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री गणेदा प्रसाद पांडेय, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्रो गुप्तार सिंह, श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री गुरु प्रसाद सिंह, श्री गुलजार, श्री गेंदासिंह, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री गौरीराम, श्री घनश्यामदास, श्रो चन्द्रवती, श्रीमती चन्द्रसिंह रावत, श्री चन्द्रहास, औ

चरणसिंह, श्री चिरंजी लाल पालीवाल, श्री चन्नीलाल सगर, श्री छेदालाल, श्री छंदालाल चौधरी, श्री जगतनारायण, श्री जगदीश प्रसाद, श्री जगदीशसरन रस्तोगी, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगन्नायबक्श दास, श्री जगन्नाय मल्ल, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री जगपति सिंह, श्रो जगमोहन सिंह नेगी, श्री जटाशंकर शुक्ल, श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री जवाहर लाल, श्री जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर जुगल किशोर, श्री जोरावर वर्मा, श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री झारखंडे राय. श्री टोक(राम, श्री डालचन्द, श्री तिरमल सिंह, श्री तुलसीराम, श्री तुलाराम, श्री तुलाराम रावत, श्री तंज प्रताप सिंह, श्री तेजबहादुर, श्री तेजासिह, श्री त्रिलोकी नाथ कौल, श्री दयाल दास भगत, श्री दर्शन राम, श्री दलबहादुर सिंह, श्री वाऊदयाल खन्ना, श्री दीनदयालु शर्मा, श्री दीपनारायण वर्मा, श्री देवकी नन्दन विभव, श्री देवदत्त मिश्र, श्री वेवमृति राम, श्री बेबराम, श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री

घनषघारी पाण्डेय, श्री धर्मेंसिह, श्री नत्युसिह, श्री नरदेव शास्त्री, श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री नरोत्तम सिंह, श्री नवलकिशोर, श्री नागेइवर द्विवेदी, श्री नाजिम ग्रली, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री नारायणदास, श्री नारायणदीन वाल्मीकि. श्री नेकराम शर्मा, श्री नौरंगलाल, श्रो पद्मनाथसिंह, श्री परमानन्द सिन्हा, श्रो परमेश्वरीराम, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री पहलवान सिंह चौघरी, श्री पातीराम, श्री पुत्तूलाल, श्री पृद्दनराम, श्री पुलिनविहारी बनर्जी, भी प्रकागवती सूद, भोमती प्रतिपालसिंह, श्री प्रभाकर शुक्ल, भी प्रभुदयाल, श्री प्रेमकिशन खन्ना, श्री फ़ज़लूल हक़, श्री फ़तेहसिंह राणा, श्री बलदेव सिंह, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री बलवन्त सिंह, श्री बशीर ग्रहमद हकीम, श्री बसन्त लाल, श्री बसन्त लाल शर्मा, श्री बाबुनन्दन, श्री बाबूलाल कुसुमेश, श्री बाबुलाल मोतल, श्री बालेन्द्रशाह, महाराजकुमार विशम्बर सिंह, श्री बंचनराम, श्री बेनीसिंह, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री भगवान सहाय, श्री भीमसेन, श्री भुवरजी, श्री भूपाल सिंह खाती, श्री भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री भोलासिंह यादव, श्री मकसूद ग्रालम खां, श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री मदन गोपाल वैद्य, श्री मदन मोहन उपाध्याय, श्री मन्नीलाल गुरुदेव, श्री महमूद ग्रली खां, श्री (रामपुर) महमूद ग्रली खां, श्री (सहारनपुर) महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री महावीर सिंह, श्री महीलाल, श्री मान्धाता सिंह, श्री मिजाजी लाल, श्री मिहरबान सिंह, श्री मुन्नूलाल, श्री मुरलीघर कुरील, श्री मुक्ताक़ ग्रली खां, श्री मुहम्मद म्रब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद ग्रब्दुस्समद, श्रो मुहम्मद तक़ी हादी, श्री मुहम्मद नसीर, श्री मुहम्मद मंजूरल नबी, श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री मोहन लाल, श्री मोहन लाल गौतम, श्री मोहनसिंह, श्री मोहन सिंह शाक्य, श्री यसुनासिह, श्रो यशोदादेवी, श्रीमती रघुनाय प्रसाद, श्री रघुराज सिंह, श्री रघुवीर सिंह, श्री रमेशचन्द्र शर्मा, श्री रमेश वर्मा, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा राजकिशोर राव, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राजवंशी, श्री राजारामु किसान, श्री

। राजाराम मिश्र, श्री राजराम शर्मा, श्री राजेन्द्र दत्त, श्री । राधाकृष्ण ग्रग्नवाल, श्रो । राधामोहन सिंह, श्री राम प्रधार तिवारी, थो रामग्रधीन सिंह यादव, श्री रामग्रनन्त पाण्डेय, श्री राम ग्रवध सिंह, श्रो रामिककरः श्रो राम कुमार शास्त्री, श्री रामकृष्ण जैसवार, श्री रामगुल म सिंह, श्री रा ₁ - नद्र विकल, श्री रामजी लाल सहायक, श्री रामजी सहाय, श्री रामदास ग्रार्य, श्री रामदास रविदास, श्री रामदुलारे मिश्र, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री राम प्रसाद, श्री राम प्रसाद नौटियाल, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री रामबली मिश्र, श्री रामभजन, श्री रामरतन प्रसाद, श्री रामराज शुक्ल, श्री रामलखन, श्री रामलखन मिश्र, श्री रामलाल, श्री रामवचन यादव, श्री रामशंकर द्विवेदी, श्री रामशंकर रविवासी, श्रो रामसनेही भारतीय, श्री रामसहाय शर्मा, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री रामसुन्दर राम, श्रो रामसुभग वर्मा, श्री रामसुमेर, श्री रामस्वरूप, श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री रामस्वरूप भारतीय, भी रामस्वरूप मिश्र विशारद, भी रामहरख यादव, श्री रामहेत सिंह, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री

लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री लक्ष्मण राव कदम, श्री लक्ष्मीदेवी, श्रीमती लक्ष्मीरमण ग्राचार्य, श्रो लक्ष्मीशंकर यादव, श्री लालबहादुर सिंह, श्री लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री लोलाधर ग्रष्ठाना, श्री लुत्पग्रली खां, श्री लेखराज सिंह, श्री वंशनारायण सिंह, श्री वंशीदाम धनगर, श्री वसी नक़वी, श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र , श्री विजयशंकर प्रसाद, श्री विद्यावती राठौर, श्रीमती विष्णुदयाल वर्मा, श्री विष्णुशरण दुब्लिश, श्री वीरसेन, श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री वीरेन्द्रपति यादव, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री वीरेन्द्रशाह, राजा व्रजभूषण मिश्र, श्री व्रजरानी मिश्र, श्रीमती व्रजवासी लाल, श्री व्रजविहारी मिश्र, श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री शंकरलाल, श्रो शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री शिवकुमार मिश्र, श्री शिवकुमार शर्मा, श्री शिवनारायण, श्रो शिवप्रसाद, श्री शिवमंगल सिंह कपूर, श्री शिवराज सिंह यादव, श्री शिवराम पांडेय, श्री शिवराम राय, श्री शिववचन राव, श्री

शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री शिवस्वरूप सिंह, श्री शुकदेव प्रसाद, श्री शुगनचन्द, श्री श्याममनोहर मिश्र, श्री श्यामलाल, श्री श्रीचन्द, श्री श्रीनाथराम, श्री सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती संग्राम सिंह, श्री सिच्चदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती सत्यसिंह राणा, श्री सम्पूर्णानन्द, डाक्टर । सावित्रीदेवी, श्रीमती िसियाराम गंगवार, श्री सियाराम चौधरी, श्री सीताराम, डाक्टर मुखीराम भारतीय, श्री सुन्दरलाल, श्री मुरुजु राम, श्री सूरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री सुरेशप्रकाश सिंह, श्री सूर्य्यबली पांडेय, श्री सवाराम, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री हबीबुर्रहनान ग्रंसारी, श्री हबोबुर्रहमान स्राजमी, श्री हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री हमीद खां, श्री हरखयाल सिंह, श्रो हरगोविन्द पन्त, श्री हरगोविन्द सिंह, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री हरदेव सिंह, श्री हरिप्रसाद, श्री हरिश्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री हरिसिंह, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

मध्नात्तर

श्रहप सूरेचर नारांकित प्रश्न

गन्ने के मन्य का नियरिंग

ं '१-- प्रेरिने हिं (जिला देवरिया) -- क्या सरकार ने गर्छः उत्पादकों प्रोर धीनी किलमालिकों के बीच गन्ना के मूल्य सम्बन्धी मामलों को तय करने के लिये विदलीय अम्मेलन वनाने की कोई तिथि निविचत की है? यदि हां. तो कब ?

इद्योग नंत्री (श्री हुकुम चिह) -- स्रभी नहीं।

२— भी रेड मिंह—क्या यह सच है कि प्रदेश के चीर्ना मिल मालियों से नगरा के नामने यह मांग रखी है कि उन्हें घाटा हो रहा है इसलिये मिलमालिकों को मेन सन से प्राप्त तथा इसरे प्रकार की मुद्धिया दी जाय है यदि हां, तो किन किन-मिली ने किस आधार पर प्राप्त की मांग की है?

र्भ हुन्मभिह--जी नही, यह मच नहीं है।

३--० े निर्मात को इसकी जानकारी है कि प्रदेश हैं चीनी मिल मालिक चीनी विकेतास्रों में मिल कर के चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं। यदि हा. तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

श्री हुवुमिंसह -- जो नहीं, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गेदासिह—क्या माननीय उद्योग मंत्री वताने की कृपा बनेगे कि इस लाकोस को न बुलाने का क्या कारण है ?

श्री हुन्मिं ह--ठीक वायुमंडल का उन्तजार है।

श्री रोदासिह—वह ठीक वायुमंडल कंसा होना चाहिये, दया इसको बतलाने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुर्मान्त्र — ताकि हर पार्टी प्रोपेन माइंड ले कर उस कान्क्रेन्स में स्राये।

श्री वीरेन्त वर्मा (जिला मुजपफ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेगे कि राष्ट्र की विभिन्न प्रदेशीय सरकारों से त्रिदलीय सम्मेलन के लिये कुछ आंकड़े सरकार ने इकट्ठा किये हे ?

श्री हुनुमिंगह-जी नहीं।

श्री गेदान्तिह —क्या माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो इधर दो तीन दिन में ग्रास बारों में खबर निकल रही है उसको देखा है ?

श्री श्रध्यक्ष—मे श्रखवारों में निकल हुई बात के सम्बन्ध में प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री गेदासिह—क्या इसकी भी जानकारी माननीय उद्योग मंत्री जी को नहीं है िं चीनी का भाव ऊंचा हो गया है? श्री हुकुमसिंह--जहां तक मेरी जानकारी है कुछ भाव गिर रहा है।

श्री नारायण दत्त निवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जून के महीने में त्रिदलीय सम्मेलन नैनीताल में बुलाया जा रहा है?

श्री हुकुर्मासह—मुझे इसकी जानकारी ग्रभी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेगे कि त्रिदलीय सम्मे-लन के समक्ष रखने के लिये सरकार ने उस फार्मूला को जो माननीय किदवई साहब ने बताया है कोई रूप रेखा तैयार की है?

श्री हुकुर्मामह—रूप रेखा वही है जो ग्रखबार मे निकली है।

श्री जगन्नथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या भाव गिरने का मतलब माननीय मंत्री जी का जो सरकार ने चीनी का भाव मुकर्रर किया था उससे भी कम है?

श्री हुकुर्मानह-नहीं, उससे कम नहीं है।

श्री नारायण दत्त निवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगे कि जो ग्रभी माननीय बीरेन्द्र वर्मा के जवाब में जिस श्रखबार का हवाला उन्होंने दिया है वह कौन सा श्रवबार है ग्रौर क्या उसे पढ़ने की कृपा करेगे ?

श्री ग्रध्यक्ष-ग्रखबार की बात के लिये में इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माननीय कि बबई साहब ने चीनी का भाव कम करने के सिलसिलें में जो बयान दिया है उसकी कार्यान्वित करने के लिये क्या क़दन उठाया है?

श्री हुकुमिसह—-ग्रभी कोई बात ऐसी नहीं की गई।

श्री नारायण दत्त निवारी—न्या माननीय मंत्री बतलायेगे कि त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने के लिये श्रभी तक उन्होंने क्या क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की है?

श्री हुकुर्मासह—उसमे ज्यादा प्रारम्भिक कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, एक खत जारी करना है।

श्री गेर्दासिह- च्या यह सही है कि उद्योग सिचव ने कुछ मिलमालिकों को ग्रौर कुछ ग्रौर लोगों को भी इस त्रिदलीय सम्मेलन के फार्मूले पर प्रारंम्भिक विचार करने के खिये बुलाया था?

श्री हुकुमसिह—जी नहीं।

मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण के लिए विदेशी सलाहकार

* '४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार ने मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री में बृटिश फर्म को मश[ि] रेया इन्तजामियां या किसी श्रौर शक्ल मे शामिल किया है? यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है?

श्री हुकुर्मासह—सरकार ने लन्दन के सर्वश्री हेनरी पूली नामक फर्म को फैक्ट्री के बनाने के काम में सलाह देने के लिये नियुक्त किया है?

**५—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार श्रापसी माहिदे की मुख्य शर्तों की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमिनह--मुख्य बतें इस प्रकार है:

- ?—-ग्रनुबन्ध की ग्रविध १ सितम्बर, १६४२ ई० से दो वर्ष के लिये निर्धारित की गयी है ग्रौर यह शर्त है कि फैक्ट्री १ सितम्बर, १६४४ ई० तक बन कर तैयार हो जायगी।
- ---श्री पूली ग्रौर उनके इंजीनियर काम की देख-रेख करेंगे ग्रौर श्री पूली की ग्रमुंपिस्थिति में फर्म की ग्रोर से उनके इंजीनियर काम करेंगे तथा समय समय पर श्री पूली स्वयं ग्राया करेंगे।
- ३---- इन इंजीनियरों के तथा श्री पूली के ग्राने जाने ग्रीर यहां रहने का खर्चा फर्म स्वयं बर्दास्त करेगा।
- ४—उपरोक्त सेवाश्चों के लिये फर्म को कुल २७,००० (श्ताइस हजार) यौंड स फीस के रूप में दिया जायगा।

श्री भगवान महाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७,००० गौंड्: में से इस फर्म को कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री हकुमसिह--इसके श्रांकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हैनरी पूली कम्पनी का कैपिटल कितना है श्रीर उसकी ठोसता के बारे में श्राप की विश्वास है या नहीं?

श्री श्रध्यक्ष—यह तो आप राय का सवाल पूंछ रहे हैं। स्राखिरी हिस्सा श्राप फिर से दुहरा दें श्रौर राय का सवाल न पूछें।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देते समय इसके इकोनामिक ठोसपने को पहले देख लिया गया था?

श्री हुकुम सिह—इस बात की जांच की गयी थी कि यह काम ठीक तरह से कर सकेंगे या नहीं। इनकी इकोनोमिक इस्टैबिलिटी के बारे में कोई जांच नहीं की गई।

श्री भगवान सहाय—यह ठेका विदेशी फर्म को देने से पहले क्या बृटिश हाई कमिश्नर को कंसल्ट कर लिया गया था कि इसकी इकोनामिक इस्टैबिलिटी कैसी है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी इकोनोमिक इस्टैं जिलटी की जांच करने की कोई श्रावश्य-कता नहीं थी क्योंकि उनके सुपुर्व में कोई रक़म नहीं कर रहा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी— क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देने से पहले कौन सा तरीका अपनाया गया है, क्या टेंडर्स काल किये गये है ?

श्री हुकुम सिंह——जहां तक खयाल है टेंडर्स काल नहीं किये गये है। लेकिन इस फर्म को कांट्रेक्ट किया गया ग्रौर यह काम करने के लिये तैयार हो गई। इससे पहले बम्बई एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से बातचीत की गई थी। लेकिन उनके टम्सं बहुत ग्रनफेयरेबिल थे लिहाजा उनकी शर्त मंजूर नहीं की गई ग्रौर विदेशी कम्पनी को ही ठेका दे दिया गया।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्षतों में से कोई ऐसी भी क्षते है जो मुकर्ररा वक्त पर ठीक तरह से फैक्टरी न बने तो उन पर कोई दंड लगता हो ?

श्री हुकुम सिंह-मुकररा वक्त से पहले ही बन जायगी।

श्री श्रब्दुल मूईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृषा करेंगे कि इस फर्म से मुझाहिदा करने से पहले कितने व्यक्ति या किन इंस्टीट्यूशन्म से इनकी योग्यता के बारे में मश्विरा किया गया?

श्री हुकुर्मीसह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है, वह रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को फैक्ट्री बनाने का ही केवल काम दिया गया है या चलाने की भी इसकी जिम्मेदारी है ?

श्री हुकुम सिह--बनाने का ही।

श्री भगवान महाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि ब्रागे इस कम्पने से किसी भी हालत में मश्विरा या इंतजाम के तौर पर संबंध रखने का इरादा है ?

श्री हुकुम मिह—यह प्रश्न कब्ल ग्रज वक्त है।

श्री बलवान सिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कम्पनी ने पहले भी कोई सीमेंट फैक्ट्री लगाने का तजुर्बा हासिल किया है?

श्री हुकुम सिह—सम्भवतः हासिल है।

श्री जोर, दन प्रमी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि किसी भारतीय फर्म ने भी इसमें शामिल होने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा कोई पत्र मेरे सामने तो श्राया नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला श्राजमगढ़)—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फेक्ट्री पर सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुकने के बाद बृटिश फर्म को ठेका दिया गया ?

श्री हुकुम सिह—कुछ लाखों की तादाद में खर्च हुग्रा था। वह हिसाब इस बक्त तो मेरे पास है नहीं।

गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार

**६--श्री झारखंडे राय (जिला ग्राजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव समाज के ग्रधीन जो प्रत्येक गांव सभा में जमीन है, उसे भूमिहीन मजदूरों को न देकर प्रत्येक प्राइमरी ग्रौर जूनियर स्कूल को देने की प्राथमिकता पर सरकार विचार कर रही है?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य) -- जी हां।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय इस योजना उर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह) —योजना तो यही है कि दफा १६८ में यदि गांव समाज के पास अगर जमीन ज्यादा तकसीम करने के लिये है तो नियमों के अनुसार सबसे पहला अधिकार उस हत्के के अन्दर जो भूमिहीन व्यक्ति है, उसको जमीन पाने का है। हम यह कर रहे है कि अगर वहां कोई स्कूल हो और वह कृषि सिखाना चाहे तो पहला अधिकार उसका अब हो जाय। इसमें योजना का क्या सवाल है यह मेरी समझ में नहीं आया।

हाई स्कूल व इण्टरमीडियंट की परीक्षाओं मे अनुचित तरीकों का प्रयोग

**७—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि इस वर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में पास होने के लिये बहुत से जिलों के विद्यार्थियों द्वारा अनिवित तरीक़ों का प्रयोग करने की शिकायतें सरकार के पास श्रायी है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम) — जी हां, कुछ शिकायते श्रायी है जिन पर रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

श्री सीताराम शुक्ल-क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या शिकायते आई है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—शिकायत यह है कि लड़कों ने नक़ल की ग्रीर कहीं कहीं जहां परीक्षा के सेंटर ये पाठशालाओं में वहां के सुपरिन्टेन्डेन्टों ने नकल कराने में उनकी इमदाद की।

श्री सीताराम शुक्ल-किससे रिपोर्ट मांगी जा रही है और कब तक ग्रा जायगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाई स्कूल ग्रीर इंटरमीडियेट बोर्ड जो होता है वही परीक्षा लेता है। उसी से यह रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इस परीक्षा से सरकार का कोई मतलब नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि लड़कों ने सभी परीक्षा क्षेत्रों में नकल की ग्रौर उसकी कोई रोक किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकी?

श्री हरगोविन्द सिह—यह तो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मालूम हुआ है वह यह है कि नक़ल काफी ज्यादा हुई है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला ग्रत्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि जिन कालिजों ग्रीर स्कूलों में सेन्टर्स बने हुए है, वहां से कापियां सीघी उन एक्जामिनर्स के पास चली जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह-जी हां, एक्जामिनर्स के पास जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इसी कारण से उन एक्जामिनर्स का जिनके पास कापियां जाती है, उन का पता लग जाता है, श्रौर विद्यार्थी श्रपने मार्क्स वगैरह कृवाने की बात किया करते है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन इस साल यह हुम्रा कि पार-सत से कापियां भेजी गयीं, लेकिन उन पर एक्जामिनर्स का नाम नहीं था। वह बिल्टियां सेल्फ के नाम भेजी गयीं मौर रिसोट को एक्जामिनर के नाम इन्डोर्स कर दिया गया भौर उसको एक्जामिनर ने खुड़ा लिया। तो इस साल तो बहुत कम पता लग सका कि कौन एक्जामिनर है, मौर नाम मालूम नहीं हो सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि यह पता ही न चल सके कि कापियां किसके पास ग्रागयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस साल यह प्रवन्ध हो गया है कि किसी विद्यार्थी या परीक्षार्थी को वह पता नहीं चल सकता कि कापी किसके पास गयी हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या यह सही है कि जो रेलवे रिसीट एक्जिमिनर के पास भेजी जाती है, उससे भी विद्यार्थी पता लगा लेते हैं ? श्री हरगोविन्द सिंह—रेलवे रिसीट पोस्टम्राफिस से जाती है, ग्रौर पासंस पर एक्जा-मिनर का नाम भ्रव नहीं रहता।

श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि परीक्षायियों ने छरे ग्रौर चाकू दिलाकर एक्जामिनेशन हाल में नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी कोई रिपोर्ट इस साल तो ग्रब तक मुझे नहीं मिली।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि इस वर्ष इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के ४० प्रतिशत विद्यार्थियों ने नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई गणना तो नहीं की गयी है। मई, १९५४ में श्रमदान श्रान्दोलन चलाने का विचार

** --श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मई, सन् ५४ में वह श्रमदान श्रान्दोलन चलाने का विचार कर रही है?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूर्लीसह) -- जी हां।

**६--श्री राम चन्द्र विकल--क्या सरकार इस श्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तथा इस पर होने वाले व्यय का श्रन्दाजा भी बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूर्लीसह—इस श्रमदान पखवारे में सिचाई के साधनों पर विशेष ध्यान दिया जायगा। श्रमदान द्वारा होने वाले कार्यों की सूची निम्नलिखित ह:——

- (१) पिछले श्रमदानों में किये गये कार्यों को पूरा करना।
- (२) सामान्य निर्माण विभाग व सिचाई विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाये।
- (३) तालाबों की सफाई करना।
- (४) तालाबों का गहरा करना।
- (५) गुलों की सफाई करना।
- (६) बन्धियों की सफाई।
- (७) पेड़ों के लिए गड्ढे बनाना।
- (८) पौधशालाये।

इस श्रमदान पखवारे में श्रोजार इत्यादि के साधारण व्यय के श्रलावा श्रौर कोई व्यय की सम्भावना नहीं है। श्रमदान में श्रच्छा कार्य करने वाले जिलों को ४०,००० ६० श्रौर हर एक जिले की श्रच्छा कार्य करने वाली ग्राम सभा को १,००० रु० पुरस्कार स्वरूप देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—ग्रान ए व्याइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सर, यह सवाल ही गलत छपा हुन्रा है।

श्री स्रध्यक्ष--वह १९५४ है, जहां पर कि ४ लिखा हुन्ना है। यह सही कर विया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक चलाया जा रहा है?

क्षी फूलसिंह--१० मई से २४ मई तक।

प्रश्नोत्तर २७१

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जो को यह पता है कि इस मौसम में ब्रिधिक गर्मी तथा प्रामों में काम की श्रिधिकता के कारण जनता इस सप्ताह में श्रमदान के कार्य में कम उत्साह लेगी?

श्री फूर्लिसह--यह सही है मगर ये ऐसे काम है कि इसी मौसम में होते है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार की तरफ से ऐसे झावेश नहर विभाग द्वारा जनता को भेजे गये हैं कि इस सप्ताह में तमाम नहरें बन्द रखी जायंगी और नहरों की सफाई होगी?

श्री फूलसिंह-जी नहीं नहरे बन्द हो जायेंगी, तो सिचाई का काम रुक जायगा।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि जो श्रमदान पिछले समय में हुन्ना है, उसमें बहुत जगह सीमेंट वगैरह न मिलने के कारण श्रमदान से लोगों को बहुत हतोत्साह सा हो गया है ?

श्री फूर्लीसह--उन कामों को पूरा करना है। इस योजना में उनका नम्बर १ स्थान है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—वया यह सही है कि डिट्रिक्ट प्लानिंग कमेटो सहारनपुर में श्रौर यहां इ: सदन के नाननीय सदस्यों ने माननाय मन्त्री जा से प्रार्थना की है कि १० मई के बजाय इसको किसी श्रौर तारीख के लिए श्रागे को बढ़ा दिया जाय?

श्री फूलिंसह—श्रब श्ररेंजमेंट्स इतने श्रागे बढ़ गये है कि इसको श्रागे पीछे करने मे दिक्कत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिन कमेटियों को सुविधा नहीं है, वह श्रागे पीछे कर नेंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

हरिजन ग्रमीनों के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को प्राथमिकता

**१०—श्री लक्ष्मी शंकर यादव(जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने कोई ऐसा श्रादेश जारी किया है कि जब भी किसी पिछड़ी जाति या परिगणित जाति के श्रस्थायी लेखपाल श्रमीन या क्लर्क को किसी कारण वश हटाया जाय, तो उसके स्थान पर पिछड़ी जाति श्रथवा परिगणित जाति के उम्मेदवारों को ही प्राथमिकता दी जाय, श्रौर उसके बाद श्रभाव में ही दूसरे को रक्खा जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-जहां तक श्रस्थायी लेखपालों का प्रश्न है, ऐसा कोई श्रादेश जारी नहीं किया गया, परन्तु मालगुजारी बसूली योजना के श्रन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले श्रमीन तथा श्रन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा श्रादेश जारी किया गया है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेगे कि लेखपालों के सिलिसिले में ऐसा ही ब्रादेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणिंसह-इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त आदेशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिलों में कोई लिस्ट पहले से होती है, या नयी दरस्वास्तें मंगा कर तब उन स्थानों की पूर्ति की जाती है ?

श्री चरणिंसह—यह तो म्रादेश जिलाधीशों को गया है। वह जैसा चाहें, करें। म्रगर कोई लिस्ट उपयुक्त कैन्डिडेट्स की मौजूद है, तो उसमें से ले लें, या प्रार्थना-पत्र मांग लें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई सरकारी झादेश जारो किया गया है कि इन स्थानों की नियुक्ति में १८ प्रतिशत जगहें उन्हें दो जायं?

श्री चरणसिंह--यह ग्रादेश तो कई महीने हुए जारी हो चुका था।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी शिकायतें स्रायी है कि हरिजनों को १८ प्रतिशत लेने के लिए कोई खास कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं श्रायी है। यहां माननीय सबस्यों ने कुछ सवाल किये हैं कि १८ फीसदी की तादाद पूरी नहीं हुई। इसके लिए मैं कई बार बतला चुका हूं कि हमको कोई नयी भरती नहीं करनी थी। जो लोग पहले से थे, उनमें १८ फीसदी की पूर्ति करने का सवाल था। क्योंकि कुछ लोग निकाले जा रहे थे। इसलिए बाहर से लेना मुनासिब नहीं समझा, यही मुनासिब समझ। कि उन्हीं में से ले लिये जायं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जानपुर) -- क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह श्रादेश क्या है श्रीर कब भेजा गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-वह ब्रादेश ४ जनवरी को भेजा गया था। उस ब्रादेश में यही हैं कि भरती में १८ फीसदी शैंडचूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन का खयाल रक्खा जाय।

तारांकित प्रक्न

बुलन्दशहर जिले के ग्रहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान हारा निर्माण

*१--श्री धर्मासह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के ब्रहार परगने में कच्ची सड़क पर कितनी लागत का कार्य श्रमदान द्वारा हुआ है, श्रौर वह सड़क कितनी लम्बी है?

श्री फूर्लिसह—बुलन्दशहर के ग्रहार परगने में कच्ची सड़क पर श्रमदान द्वारा ग्रनु-मानित ६०,८३२ ६० का कार्य हो चुका है। वह सड़क ११ मील लम्बी है उसमें से ५ मील पर उपरोक्त कार्य हुन्ना है।

*२--श्री धर्मीं प्रह-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क पक्की कब तक बन कर तैयार हो जायेगी?

श्री फूर्लीसह—उपर्युक्त सड़क जिला बोर्ड की है इसलिए जिला बोर्ड से इसको पक्का करने की प्रार्थना की गयी परन्तु धनाभाव के कारण पक्की नहीं हो सकी।

श्री धर्मीसह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा कितने समय तक कितने श्रादिमयों ने इस सड़क पर कार्य किया है ?

श्री फूर्लीसह—६०,८०० रुपये का काम इस सड़क पर हुआ है। कितने आदिमयों ने किया और कितने दिन तक किया इसका ब्योरा नोटिस आने पर दे सकता हूं।

श्री धर्मीसह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क के लिए सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

श्री फूर्लीसह—इस सड़क पर तो कोई विशेष सहायता नहीं दी है, लेकिन जिलेबार काफी सहायता दी जाती है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले का जो दौरा उपमन्त्री जो ने किया था, वहां के लोगों ने इस सड़क को पक्का कराने की प्रार्थना की थी?

श्री फूर्लीसह--जी हां।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या सरकार इस सड़क को जल्दी मे जल्दी पक्का कराने का विचार रखती है ?

श्री फूर्निसह--यह बड़ा काम है। नयी योजना ग्राने के समय इसका ध्यान रक्खा जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ११ मील के टुकड़े में जो ६०,८०० रुपया खर्च हुम्रा है, वह केवल पांच मील पर खर्च हुम्रा है?

श्री फूर्लासह-जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पांच मील के दुकड़ें में १२ हजार रुपये के करीब सिर्फ कच्चा ही कार्य हुन्ना है ?

श्री फूर्लीसह—जी हां।

श्री धर्मसिह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ६०,८३२ रुपया खर्च किया है, उसका एक तिहाई सरकार देने का विचार रखती है?

श्री फूर्लिसह—श्रमदान द्वारा जो काम होता है, उसका एक तिहाई तक देने की गुंजा-इश होती है, उस रुपये में जो श्रापने बजट में पास किया है, श्रौर जितना रुपया मिलता है, वह जिलेवार बांट दिया जाता है, श्रौर जिला, प्लानिंग कमेटी को, हक रहता है कि जो मुनासिब समझे वह दे दे।

श्री धर्मीसह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि जिला बोर्ड बुलन्द-शहर से जो प्रार्थना सड़क बनाने के लिए जिला प्लानिंग कमेटी ने की है, वह जिला बोर्ड ने स्वीकार की है या नहीं ?

श्री फूर्लीसह—जिला प्लानिंग कमेटी को प्र.र्थना करने की आवश्यकता नहीं है। रुपया उसके पास है, श्रीर वह खर्च कर सकती है।

पंचवर्षीय योजना के भ्रधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिये कार्य

*३—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के ब्रघीन लखनऊ जिला की उन्नति के लिए कौन कौन से कार्य किये जा रहेहैं ? क्या सरकार उन कार्यों की एक सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री फूर्लीसह—पंचवर्षीय योजना के ग्रधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिए सिचाई, कृषि, बागबानी, गन्ना विकास, सहकारिता, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, ग्रावागमन, शिक्षा, हरिजन सुधार तथा पंचायत के श्रन्तगंत कार्य हो रहा है, जिनकी सूची माननीय सवस्य की मेज पर रखी है।

*४—श्री हरिश्चन्द वाजपेयी—लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष कौन-कौन से कार्य लखनऊ जिले में किये श्रीर क्या जिला के निर्माण कार्य के लिए कोई स्थायी कार्य-कम बनाया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री फूर्लीसह—लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष जिले में जो निर्माण कार्य किसे हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज है। जिले में आगे के

निर्माण कार्य के लिए सन् १६५४-५५ की विकास योजना बनायी गयी है, वह योजना १ प्रप्रैल सन् १६५४ से कार्यान्वित होगी। इसका वर्णन विस्तार में सूची में ब्रा गया है।

(देखिये नत्थी 'क' म्रागे पृष्ठ ३३५-३३८ पर।)

*५—श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी—क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ग्रघीन लखनऊ जिला के देहाती हल्कः के लिए कोई कार्य किया जाता है? यदि हां, तो वह क्या है, ग्रौर यदि नहीं, तो क्या सरकार लखनऊ जिला में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य जारी किये जाने के प्रक्त पर विचार करेगी?

श्री फूर्लीसह—कम्युनिटी प्रोजेक्ट के श्रधीन लखनऊ जिला के देहाती हल्के के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु राष्ट्रीय विकास योजना के ग्रन्तगंत जिले में इस वर्ष गोसाईंगंज ग्रौर सरोजनी नगर के दो क्षेत्र मंजूर किये गये हैं, जहां विकास कार्य होगा।

श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना का कार्य हे खनऊ जिले में कब से आरम्भ हुआ ?

श्री फूर्लीसह—तमाम प्रान्त में एक ही दफा हुआ, श्रौर तभी से यहां भी हुआ।

श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंच-वर्षीय योजना के पूर्व कितने एकड़ जमीन में सिंचाई नहरों से होती थी श्रीर कितने एकड़ जमीन में सिंचाई पंचवर्षीय योजना के श्रयीन होने लगी ?

श्री फूलसिह—इसके लिए नोटिस की ग्रावश्यकता होगी।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि कोई भी ट्यूबवेल लखनऊ जिले के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अधीन नहीं बनाया गया ?

श्री फूलसिंह-माननीय मेम्बर ठीक ही कहते होंगे।

श्री हरिश्चन्द वाजपेयी—क्या यह सही है कि टिड्डी मारने या चूहे मारने या अन्य कार्य जिनका ब्योरा यहां पर दिया गया है, उनमें से कोई भी कार्य पंचवर्षीय योजना के ग्रधीन नहीं किया गया ?

श्री फूर्लिसह—यह तो शायद सही नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत इन सब कामों में कुल कितना रुपया लगेगा?

श्री फूर्लीसह—इसके लिए नोटिस की स्रावश्यकता है।

पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत बुलन्द शहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था

*६—ध्री धर्मसिह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के न्तर्गत जिला बुलन्दशहर में कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है ?

श्री फूर्लासह—जी हां। जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है।

*७--श्री धर्मींसह--यदि हां, तो क्या सरकार क्रुपया बतायेगी कि वे निर्माण-कार्व क्या-क्या हैं ? श्री फूर्लिस्ट्—पंचवर्षीय योजना के ग्रधीन कृषि, सिंचाई, बागबानी, पशुपालन, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, ग्रावागमन, यातायात, शिक्षा, घरेलू उद्योग-घन्धे, पंचायत राज, प्रान्तीय रक्षक दल तथा हरिजन उद्धार के ग्रन्तीत निर्माण कार्यों की योजना है। इन कार्यों की विस्तृत सूची माननीय सदस्य की मेज पर है।

*= श्री धर्मिसह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत श्राज तक क्या क्या कार्य पर्ण हो चुका है ?

श्री फूर्लिसह—बुलन्दराहर जिले में पंचवर्षीय योजना के श्रघीन सन् १६४३-४४ तक जो कार्य पूर्ण हो चुकें हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' ब्रागे पृष्ठ ३३६-३४६ पर ।)

श्री धर्मासह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत जो कार्य सूची में नत्थी हैं उनमें कितने कार्य वहां पर हो चुके हैं ?

श्री फूर्लासह—यह तो तत्काल नहीं बतलाया जा सकता। जांच करके बतलाया जा सकता है।

श्री धर्मसिह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत जो कार्य हुआ है या होने को है उसमें कितना धन सरकार ने खर्च किया है?

श्री फूर्लीसह-इसके लिए भी नोटिस की ग्रावश्यकता होगी।

श्री धर्मीसह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ायी जा रही है और धनाभाव के कारण उनको तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री फूलसिंह--श्रखबारों से ऐसा पता चलता है।

श्री राम चन्द्र विकल-क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बुलन्द । शहर जिले को एन० ई० एस० ब्लाक में देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री फूर्लीसह--प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट के ब्राने के बाद इस पर निर्णय किया जायगा।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से चंचवर्षीय योजना शुरू हुयी है तब से जो कुएं की सहायता दी जाती थी वह बुलन्द शहर जिले में बन्द कर दी गयी है?

श्री फूर्लिसह--मंशनरी वैल की सहायता बीच में बन्द हो गयी थी।

श्री रामचन्द्र विकल--नया एन० ई० एस० ब्लाक वहां किस क्षेत्र में देना चाहते हैं?

श्री फूर्लासह—जिला प्लानिंग कमेटी से मशविरा मांगा गया है।

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की स्नावश्यकता

*६—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार को पता है कि प्रान्तीय नियोजन कमिश्नर के ब्रादेश से, जिला नियोजन समिति गोंडा के Trans Rapti क्षेत्र के सब से पिछड़े हुए भाग को Community Project के लिये लगभग डेड़ साल हुये कुना था परन्तु ब्राज तक वहां पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री फूर्लिसह—सामूहिक विकास केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जिला नियोजन सिम-तियों के विचार मांगे गये थे उनमें से गोंडा भी एक जिला था। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने सिफं चंद ऐसे केन्द्र खोलने की ग्रनुमित दी थी इसलिये इस इलाके में केन्द्र न खोला जा सका। लेकिन यह सही नहीं है कि वहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। शासन की ग्रोर से मझगवां वधेलखंड बांध बनाये जा रहे हैं। ग्रौर प्रोजेक्ट्स पर भी विचार हो रहा है। इंतिया योक में एक एन० ई,० एस० ब्लाक खोला गया है।

*१०— श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल — क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त भाग में पिछले चार सालों में सूखा श्रीर श्रर्थ सूखा की दशा रही जिसमें गरीबों की जीवन रक्षा के लिये सरकार को लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ा है ?

श्री फूर्लासह--जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि मझगवां झौर बघेलखंड बाच ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं है जहां के लिये मांग की गई थी?

श्री फूर्लीसह-माननीय सदस्य की इत्तिला ठीक ही होगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि इंतिया थोक ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं हैं जहां के लिये स्कीम मांगी गयी थी ?

श्री फूर्लासह—वहां एन० ई० एस० ब्लाक खुल गया है तो दोबारा मांग नहीं होती, श्रौर श्रागे माननीय सदस्य जो कहते हैं वह ग़ालिबन ठीक ही होगा।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इंतिया थोक में कितना काम इस दिशा में हुग्रा है ?

श्री फूर्लीसह - नोटिस की ग्रावश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या इंतिया थोक ट्रांसराप्ती एरिया में ह?

श्री फूर्लिसह—माननीय मेम्बर को इस बात का ज्यादा ज्ञान है चूंकि वह वहां

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में पंचा-यतों द्वारा ढिढोंरा पिटवा दिया गया था कि वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम लागू की जायगी?

श्री फूर्लासह--मुझे इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ट्रांसराप्ती क्षेत्र में श्रमदान का विचार स्थगित कर दिया गया है या बिलकुल खत्म कर दिया गया है?

श्री फूर्लिसह—श्रमदान के ग्रलावा कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट इस साल नहीं खुल रहा है।

श्री शिव नारायण-- वया यह सही है कि ट्रांसराप्ती की स्कीम को कैंसिल कर विया गया है ?

श्री फूर्लिसह—मुझे तो ऐसी इतिला नहीं है।

जिला गोंडा की तहसील तरदगंज में विकास कार्य

"११--श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा) (ग्रनुपस्थित)-क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में कौन सा विकास कार्य किस स्थान पर हो रहा है?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) —सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत

. (देखिये नत्थी 'ग' ग्रागे पृष्ठ ३५० पर ।) पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत रुड़की तहसील मे कःर्य

*१२-श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)-क्या सरकार इस दंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में भी कोई कार्य करने जा रही है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-जी हां।

*१३--श्री दीनदयालु शास्त्री (ग्रनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, नो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में होने वाले कार्य नियोजन विभाग की श्रोर से दो नलकूप सहकारी आधार पर दौलतपुर व कोटा मुरादनगर में स्वीकृत हुये हैं। छः बीज भंडार निर्माण होंगे जिनसे केवल प्रथम श्रेणी का बीज वितरण के लिये उपलब्ध होगा।

सहकारी बैंक रुड़की द्वारा ६ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत की दर पर समितियों को कृषि उत्पादन के लिये ऋण दिया जाता है। भविष्य में इस दर को घटा कर ६ प्रतिशत कर दिया जायगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

पथरी नदी पर नियोजन विभाग द्वारा एक पूल निर्माण करने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा रुड़की तहसील में ४१ नलकूप बनाये गयें हैं। जो शीघ्र ही चालू किये जायंगे।

इसके स्रतिरिक्त श्रमदान द्वारा कई लम्बी सड़के तथा खरंजे व पंचायत घर इत्यादि बनाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार पंचवर्षीय योजना के ब्रन्तर्गत पथरी विद्युत् गृह तथा मुहम्मदपुर विद्युत गृह चालृ कर रही है। जिनकी ब्रनुमानित लागत क्रमशः २ करोड़ ३१ लाख रुपया तथा ३१ लाख रु० ब्रायेगी।

उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन पर व्यय

*१४—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—(जिला जौनपुर)—श्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन में १९५१ व १९५२ में कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री फूर्लीसह—-२,१४,८३४ रुपया।

*१५—ंश्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नगर तथा प्राम नियोजन में किसानों की खेती करने वाली जमीन भी ली जाती है?

श्री फूर्लीसह—यदि ग्रति ग्रावश्यक होता है तो उसको लेना पड़ता है।

*१६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—यदि हां, तो क्या उन्हें मुग्रावजा दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फूर्लीसह—जी हां।

श्री राम चन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की जमीन ली जाती है उन्हें किस हिसाब से मुश्रावजा दिया जाता है ?

श्री फूलिंसह—रेट तो मेरे सामने नहीं हैं लेकिन एक ही रेट है जो सब के लिये लागू है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बता ने की कृपा करेंगे कि ग्राम नियोजन के ब्रन्तर्गत ५१-५२ में विशेषकर क्या-क्या कार्य हुआ ?

श्री फूर्लासह -- इसके लिये नोटिस की ग्रावश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो खर्चा बतलाया गया है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का टी० ए० भी शामिल है ?

श्री फूर्लासह-- जीक नहीं कह सकता, गालिबन होगा।

'श्रमदान' सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रमदान

*१७—-श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृषा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में प्रत्येक सरकारी श्रादमी को कुछ न कुछ हाथ से मेहनत करने का स्रादेश था ?

श्री फूर्लिसह जो नहीं। परन्तु यह श्राशा की जाती थी कि सब सरकारी कर्म-चारी स्वेच्छापूर्वक श्रमदान सप्ताह में श्रमदान योजना को सफल बनाने के लिये कुछ न कुछ श्रम करेंगे।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाथ से मेहनत करने के स्रादेश देने में कोई कटिनाई है ?

श्री फूर्लिसह—श्रमदान की नीति स्वेच्छा पर ही निर्भर करती है, हुक्म से वह बात नहीं रहती।

जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन पर व्यय

*१८—श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन के द्वारा सन् १९५२-५३ में कुल कितना क्यय हुआ और कितना रुपया हरिजन वर्ग के मकानों और पानी के निमित्त दिया गया ?

श्री फूर्लिसह—विकास तथा नियोजन के द्वारा १०,१७,११६ रुपया व्यय हुम्रा श्रौर हरिजन वर्ग के मकानों तथा कुर्यों के लिये ४,००० रुपये की सहायता दी गई।

श्री रामजी लाल सहायक—क्या सरकार ऐसे लोगों की संख्या बतलायेगी जिनको मकानों के लिये सहायता दी गयी? प्रश्नोतर २७६

श्री फूर्लीसह--इमके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामजी लाल सहःयक—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४२-४३ में प्रदेश सरकार की जिला नियोजन सिमितियों ने हरिजन वर्ग को पीने के पानी के कुन्नों की सहायता के लिये कितनी सहायता दी ?

श्री फूर्लीसह—इसके लिये नोटिस की ग्रावश्यकता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी यह वतलायेगे कि इस रुपये में कितना रुपया हरिजनों को पीने के लिये कुग्रां के बनाने में दिया गया?

श्री फूर्जिमह —हिरजनों के लिये पानी पीने के कुन्नों के संबंध में जो रुपया जिलों में दिया गया है वह विशेष रूप से हरिजनों के लिये दिया जाता है और कुन्नों पर उसके खर्च की इजाजत नहीं दी जाती है। ग्रजवत्ता मकान बनाने के लिये जो रुपया दिया जा रहा है उससे नोगों को काफी फायदा हो रहा है।

श्री हिर्सिह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ोर से जो रूपा हिरजनों के मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में दिया गया था वह रूपया मकानों में लगा या नहीं?

श्री फुल्लिह—वह रुपया मंने श्रवं किया कि कम लगा मकानों में।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि जो रुपया बाक़ी है उसके लिये ब्रादेश जारी कर के फीरन हरिजनों के लिये बुएं बना देगी?

श्री पूर्लिसह—मकान बनाने में सहायता देने के लिये नदी योजना तंयार हो रही है जि..से हरिजनों के मकान बनाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

श्री खाजू तत्वन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि हरिजनों के पानी पीने के लिये कूल कितने कुरंबने हैं?

श्री फूर्लोसह-इसके निये नोटिस की ग्रावश्यकता है।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्शरनगर)—गया माननीय मंत्री जी बतलाने की कृता करेंगे कि कुरं के सम्बन्ध में जो हरिजनों से आधा रूपया लिया जाता है, वे अपनी आर्थिक समस्या की बिना पर उसे देने में असमर्थ रहते हैं?

श्री फूर्लोसह—हरिजनों से नकद रुपया ग्रामतौर से नहीं लिया जाता उनसे अमदान ही कराया जाता है।

गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिश्शा चलाने की मनाही

*१६—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वन विभाग द्वारा वन की सड़कों पर साइकिल और रिक्शा चलाना जर्म है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी) —िवना इजाजत जुर्भ है।

*२०—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में इस प्रकार वन विभाग की कितनी सड़कें हैं जो कई मील तक दोनों तरफ ग्राबादी के बीच से निकली हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--चार।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार जनिहत के लिये यह प्रतिबन्ध उठाने को तैयार है?

श्री जगमोहन सिंह नेनी—मोटर सड़क के बगल में ही बैलगाड़ी की सड़क भी है श्रीर उस पर हर एक को पूरी इजाजत है कि वे उस पर साइकिल रिक्ताः श्रादि चला सके । इस पर भी हम सुविधा देने को तैयार है लेकिन जंगलों में गैरकानूनी तरीक़े से कुछ लोग शिकार वगैरह खेलते है तो उसके लिये हम कुछ परिमट सिस्टम चालू करना चाहते है। क्योंकि बिलकुल खुला हुआ छोड़ देने से लोग गैरकानूनी तरीके से शिकार वगैरह खेलते है श्रीर जानवरों की हत्या की जाती है।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्योंकि उक्त चार सड़के गांवों से संबंधित है इसिन्ये क्या सरकार इन पर रिक्शा और मोटर चलाने की ग्राज्ञा प्रदान करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—में पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि हम इस पर विचार कर रहे है कि कुछ परिमट दे दें जिससे हर मौक़े पर वे चल सके और उन ग्रादिमयों को भी पता चल सके कि विना ग्राज्ञा के शिकार वगैरह किसने खेला है ? इसलिये डजाजत देने के प्रश्न पर विचार किया जा जकता है।

श्री केशव प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि मानीराम से टिकरिया जंगल को सड़क जाती है जिससे लोग दिन भर श्रमेक कामों के लिये गोरखपुर जाया करते है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी:—जी हां, जाते हैं जैसा मैने पहले बतलाया कि दूसरी सड़क भी बगल में जाती है। एक मोटर के लिये ग्रौर एक बैलगाड़ी, रिक्शा वग्रैरह सभी के लिये है।

मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिनों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा तुविधाप्रें

*२१—श्री स्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वन विभाग की स्रोर से कौन—कौन सी विशेष सुविधाये प्राप्त थीं स्रौर कौन—कौन से सामान लेने की सुविधाये उनको थीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी -- प्रत्न स्पष्ट नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य का श्राशय जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारी बनों से दिये जाने वाली सुविधाश्रों के बारे में सूचना प्राप्त करने का है तो यह सूचना एक सूची में दी हुयी है, जो मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' ग्रागे पृष्ठ ३५१ पर)

*२२—श्री श्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ग्रब सरकारी वन विभाग की ग्रोर से उक्त क्षेत्रों के निवासियों को कौन—कौन सी सुविधायें प्राप्त है ग्रौर कौन कौन से सामान किन शर्तो तथा किन मूल्यों पर मिलने का ग्रधिकार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' ग्रागे पृष्ठ ३५२-३५४ पर)

*२३—श्री स्रज भूषण मिश्र—क्या निकटस्थ जंगलों से लकड़ी निःशुल्क प्राप्त करने का सरकारी श्रादेश है ? यदि हां, तो उसके नियम क्या है ? प्रक्नोतर २८१

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लकड़ी की प्राप्ति के लिए जो मुविधाये हं उनका विवरण प्रकृत २२ के उत्तर में उल्लिखित सूची में दिया हुन्ना है। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह भी ग्रादेश दिया है कि प्रति वर्ष जाड़े की ऋतु में पहले बन विभाग के कर्मचारी उन विशेष क्षेत्रों को निर्धारित कर दे जिनमें में गांव वाले लकड़ी ले जा सके ग्रीर उन क्षेत्रों में जिन पेड़ों में लकड़ी प्रप्त की जा सके उनमें चिन्ह लगा दे। इनकी सूचना संबंधित गांव की लन्ड मनेजमेंट समिति के चेयरमैन को दे दा जायगी। यह व्यवस्था गांव वालों का सुविधा के लिए मरकार ने की है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की क्रुग करेगे कि जो सुविधायें दी गई है उनको ठौक से इस्तेम।ल करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके बारे में श्रादेश चले गए है श्रौर ऐसा समझा जाता है और श्राशा की जाती है कि सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से उनका पालन करते हैं।

बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग की लकड़ी में ग्राग लगना

*२४—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री जो को यह सूचना प्राप्त हुयी है कि तारीख १-४-५३ को बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग तथा वन विभाग के ठेकेदारों की लगभग १०० बैगन लकड़ी, स्टाक में स्नाग लग जाने के कारण जल गयी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

*२५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या ठेकेदारों ने इस सम्बन्ध मे फारेस्ट रेन्ज ग्राफिसर, मानिकपुर को, इस नुकसान के कारण श्रपने ग्रलाट की किस्त के बकाया रुपये को माफ करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—स्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि इस आग के लगने से कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, नुकसान हुझा है श्रीर वह एक केस में २१०० रुपर का हुझा, एक केस में १३,१२५ रुपए का, एक केस में ७८८ रुपए का, एक केस में २१०० रुपए का श्रीर एक केस में ६२५ रुपए का नुकसान हुझा है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या इन ठेकेदारों की शिकायतों पर विचार करके सरकार उस रकम को माफ करने को तैयार है जो उनको देना है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह ग्राग जंगल मे नहीं बल्कि डिपो मे लगी श्री ग्रौर वहां उन्होंने पूरी ग्रहतियात नहीं बर्ती जिससे ग्राग न लगे, इसलिए लीगली तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता लेकिन मारली सोचा जा रहा है ग्रौर यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र-क्या मंत्री जी बतायेगे कि ब्राग कैसे लगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह श्राग जैसा मैं ने कहा फारेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल में नहीं लगी थी, वह तो डिपो में रेलवे स्टेशन के पास लगी थी, इसलिये पता नहीं कि वह कैसे लगी।

*२६-२७--भी नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला ग्रलीगढ़)---[३ जून, १९५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

*२८-२६--श्री व्रज भूषण निश्र--[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]
*३०--श्री दाबू नन्दन--[हटा दिया गया ।]

"३१-३२--श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--[३ जून, १६५४ के लिये स्थितिन

*३३-३५--श्री राम लखन (जिला बनारस)--[३ जून, १६५४ के लिये स्थिति किये गरे।]

*३६-३=--भी लभ्मग राव कदम (जिला झांतो)--[२१ मई, १६५४ के निवे प्रक्त संख्या ४२-४४ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किने गये।]

भर्यहर कस्युनिटी प्रोजेंग्ट के विरुद्ध शिकाण्त

*३६--श्री झा खंडे त्य-व्या सरकार के पास भट्टहर कम्युनिटी प्रोटेक्ट के विन्द्ध कोई शिकायत प्राप्त हुयी है? प्रगर हां, तो उस पर दश कार्यवाही का गयी?

श्री फूरक्षित्—हाल में कोर्ट कियायन र एक नहीं हुयी है। जून, १६४३ में एक किनायत प्राप्त हुयी थी और कपावार कर्नचारियों को उचित दंड दिया गया।

श्री नारअंडे राष्ट्र—क्या मंत्री जी कृपया बतायेगे कि वह शिकायत क्या थी ?

श्री फूर्लातह—कुछ कर्मचारियों ने किसी बागवान को इस इलजाम मे फंसाना चाहा कि वह डालू है।

श्री झारखंडे राय — क्या मंत्री महोदय बताने की कृ्या करेगे कि किन-किन कर्मचारियों को कौन-सा दंड दिया गया ?

श्री फूर्लातह—िंडिटी डेवलपमेट ग्रफसर को हटा दिया गया, एक ग्रफसर को डिमोट कर दिया गया, एक का ट्रांसफर कर दिया गया ग्रीर एक को उसके महकमें को वापस कर दिया गया।

श्री नेंदासिह—इया यह सही है कि इस शिकायत की जांच नाननीय फूलसिंह जी ने भी की थी?

श्री फूर्लिसह -- जांच तो मैने नहीं की मगर थोड़ी बहुत देखभाल की थी।

श्री शुकदेव प्रतः व (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि कुछ समय पूर्व उनके पास कोई इस प्रकार की शिकायत श्रायी थी?

श्री फूर्लीसह—कोई ऐसी शिकायत नहीं श्रायी थी।

*४०-श्री नत्यू सिंह (जिला बरेली)-{१७ मई, १६५४ के लिये प्रश्न संख्या प्रव के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गन्ने का मल्य निश्चित करने के लिए सम्मेलन

*४१—श्री गेंद्रासिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गन्ना के मूल्य तथा लाभ संबंधी मामले पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन होने वाला था उसे बुलाने का कोई समय निश्चित किया गया ?

श्री हुकुर्मासह—ग्रभी नहीं ।

भी गेंदा सिह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृषा करक बतायेंगे कि इस सम्मलन को बहुन देर में बुलाने से सम्मेलन का उद्देश्य नप्ट हो जायेगा ?

श्री हुतुम सिंह—हम जल्द बुलाना चाहते हैं।

श्री गेंद्रानिह—क्या माननीय उद्योग मंत्री की को ज्ञात है कि इस सम्मेलन के न बुकाने के कारण मिल मालिकों को एक ग्रवसर जिल रहा है कि वह महंगे दामों नें चीनी डेंचें ?

श्री हुन्दुमसिह—ऐसा मेरा स्वाल नहीं है।

श्री गेंदातिह—क्या यह सही है कि चीनी की कीनन दरावर बढ़ती चीने जा रही है ?

भी नुपूर्मासह--मैने प्रभी इसका जवाब प्रापके ही सवाल पर दे दिया है।

४४२--श्री गेंदि।सिह--[२४ मई, १६५४ क निये प्रक्न तंस्या ७४ के ग्रन्नर्गत स्थानान्नरित किया गया ।]

*४३--श्री भोजामिह यादव(जिला गाजीपुर)--[३ जून, १९५४ के लिये स्यगित किया गया।]

*४४--श्री भगवान सहाय--[२०नई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*४५--श्री इस्तफा हुसैन--[१८ मई, १६५४ के लिये प्रक्त संख्या ४६ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६-४७--श्री जोरावर वर्मा--[३जून, १६५४ के लिये स्थगित किये गये।]

विलीनीकरण के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी
में लिया जाना

*४८—श्री वंश नारायण सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशी-राज्य के विलीनीकरण के समय स्थायी राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेशीय सरकार में स्थायी स्थान देने का निश्चय हुन्ना था?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कुछ शर्तों के म्रधीन राज्य के स्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने के बारे में तय हुम्रा था।

*४६—श्री वंश नारायण सिंह—पिंद हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के सभी स्थायी राज्य कर्मचारी स्थायी स्थानों पर नियुक्त कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उनमें से अधिकतर तो रख लिये गये, पर थोड़े से कर्मचारी जो हमारी आवश्यकता से अधिक थे या जिनके लिये उपयुक्त स्थान नहीं थे अथवा ऐसे जिन हे अनुभव और योग्यता का विचार करते हुये नौकरी में रखने के योग्य नहीं समझे गये उनकी नौकरी में नहीं रखा जा सका।

*४०--श्री वंश नारायण सिंह--क्र्या सरकार को मालूम है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने भ्रवकाश ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार उन सबको पेंशन दे दी गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-ऐसे श्रिषकतर कर्मचारियों को नियमानुसार पेंशनें दे दी गई हैं। बहुत थोड़े बचे हुये कर्मचारियों के मामलों में श्रावश्यक कार्यवाही हो रही है।

*५१-५२-श्री भगवान सहाय--[२० मई, १६५४ के लिये स्थगित किये गये।

मऊ (ग्राजमगढ़) में रंगाई व धुनाई का कारखाना

*५३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री १-४-५४ के प्रक्त संख्या ६ से ११ के उत्तर के संबंध में बतायेंगे कि मऊ (ब्राजनगढ़) में रंगाई धुनाई का कारखाना चालू नहीं है? यदि हां, तो कब से चालू हो जाने की ब्राशा है?

श्री हुकुर्मासह—इस कारखाने में हाथ से रंगाई का काम १६४६-५० से चालू है। ब्लीचिंग और फिनिशिंग का कारखाना शीध्र चालू हो जाने की ग्राशा है।

*४४—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारलाने में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन ६ मास से बाकी है ?

श्री हुकुर्मासह—क।रखाने के कर्मचारियों को मार्च सन् १९४४ तक का वेतन दिया जा चुका है।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

*४५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १६४२-५३ श्रौर ४३-४४ ई० में प्रदेश में कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गई हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--१९५२-५३ में ५३ ग्रीर ५३-५४ में ६६।

पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल

*४६—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरख उर जिले के पकड़ी रेंज के समीपस्थ मौजा पकड़ी न उनियां में कितने क्षेत्रफल का वन है ग्रीर वह वन किसका है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-पकड़ी नउनियां के वन का क्षेत्रफल २२६.६ एकड़ है ग्रौर यह वन सरकारी है।

*५७---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय---[३ जून, १६५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४६--श्री खुशीराम (जिला ग्रल्मोड़ा) - - [२७ मई, १९४४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--[१४ मई, १९५४ के लिये प्रक्त संख्या द४ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।] प्रश्नोत्तर २८५

जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की ग्रावश्यकता

"६१—श्री मुक्ताक ग्रली (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं की प्लानिंग कमेटी ने सरकार से यह सिफारिश की है कि सहसवान से गिन्नोर तक पुल्ता सड़क बनवा दी जाय ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-जी हां।

राम नगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना

*६२-श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (श्रनुपिस्यत) - क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामनगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना कब तक पूरी हो जायगी?

श्री हुकुर्मासह—योजना तैयार है। रामगढ़ की फैक्टरी जुलाई से जबिक सेव का मौसम ग्रारम्भ होता है, चलना शुरू कर देगी श्रौर यदि हो सका तो इससे पहले भी।

*६३—श्री धर्मदत्त वद्य (ग्रनुपस्यित)—ग्रब तक इस फैक्टरी ने क्या प्रगति की है ग्रौर इस पर श्रब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—बिल्डिंग १४-४-५४ को तैयार हो गयी। अब मशीने लग रही है।

मब तक कुल लगभग २ १/४ लाख रुपया व्यय हो चुका है।

*६४--श्री धर्मदत्त वैद्य (ध्रनुपिश्यत)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी में क्या-क्या कार्य किया जायेगा, ग्रौर इस फैक्टरी द्वारा निर्मित वस्तुग्रों के विक्रय का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हुकुर्मीसह—इस फंक्टरी में सेब तथा ग्रन्य फलों की लुगदी तैयार की जायगी। इस प्रकार ५०-६० फीसदी फल जो ग्रच्छें नहीं होते, जिन्हें चिड़ियां खा लेती है, या जो ग्रत्यिक पक जाते हैं, या जो ग्रोलों इत्यादि से बेकार हो जाते हैं, काम में ग्रा जायेंगे। कच्चे फलों को भी ठीक करके चारे के काम में लाया जायगा।

यह लुगदी लकड़ी के बैरल (डिब्बों) में भर कर मैदान मे ऐसे व्यवसायि श्रों के पास भेज दी जायगी, जो इसका मुरब्बा स्रौर चटनी बनावेगे।

विक्रय के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्केटिंग एडवाइजर से बातचीत हो रही है। इस प्रदेश के तथा भ्रन्य प्रदेशों के व्यवसायिश्रों से भी बातचीत की गयी है। वे लोग फैक्टरी में तैयार हुई लुगदी के लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सस्ती पड़ेगी।

*६५-६६--श्री हरिप्रसाद-[२० मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद का हेडक्वार्टर

*६७—श्रो इसरारुल हक्न (जिला ग्रागरा) (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सब-डिबीजनल मैजिस्ट्रेट फिरोजाबाद का मुस्तिकल हेडक्वार्टर उसकी बढ़ती हुई श्राबादी ग्रौर जरूरियात को देखते हुए फिरोजाबाद ही मे रखना उसके जेरेगौर है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-सरकार सब-डिबीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद को श्रागरे मे हटा कर फिरोजाबाद ले जाना चाहती है किन्तु सब-डिबीजनल ग्राफिसर की श्रदालत, उसके कार्यालय श्रौर निवासस्थान व श्रदालती हवालात (judicial lock up) के लिए इमारतें बनाये बिना वह ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को खेद है कि धन की कमें के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

क्दन-श्री बाबूस दन-[१८ मई, १९४४ के लिए प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नीरा से गुड़ बनाने की धोजना

*६६—श्री ल तू तन्दर—क्या सरकार ने नीरा से गुड़ बनाने की योजना कार्यान्विन कर दी है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में ?

श्री हुक्मसिह—(ग्र) जी हां।

(य) कानपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, बिजनौर ग्रौर नैनीताल जिलों मे।

*৩০—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[२४ मई, १६४४ के लिए प्रश्न संस्या १३ के म्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

द्वितीय पंचयर्थीय योजना

* ७१ — श्री शिवराता भिंह यादद — क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Second five year plan तैयार कर रही है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त--जी हां। सरकार सेकिंड फाइव इयर प्लान तैयार कर रही है।

*७२—श्री शिवराज सिंह याद्य —क्या सरकार इस प्लान की तैयारी के सम्बन्ध में जिला नियोजन सिमितियों से भी सुझाद मांगने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों से भी सुझाव मांगने का विचार रखती है। इन सुझावों के मांगने की विधि व प्रकार सरकार के विचाराधीन है।

*७३—श्री सारखंडे राय—[३ जून, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]
फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा

*७४—श्री इसरारुल हक़ (अनुपिश्यत)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि फिरोजाबाद में किन-किन लाइम फैक्टरियों को किस हिसाब से कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री हुकुर्मासह—इस समय फिरोजाबाद की किसी भी लाइम फैक्टरी को कोयले का कोटा नहीं दिया जाता है ?

*७५--श्री इसरारुल हक्क (ग्रनुपिश्यत)--क्या सरकार को इल्म है कि इन फैस्टरियों में से कई एक बन्द हो गयी हैं, परन्तु वह ग्रपना कोयले का कोटा बराबर उठाती है ?

श्री हुकुमसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति

*७६—श्री हरिइचन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृष्**। करे**गी कि इस वर्ष प्रदेश की शक्कर मिलों में गन्ना पहुंचना रोकने से कितने मिल कितने ति को के लिए बन्द उए ग्रीर शक्कर के उत्पादन में कितनी क्षति पहुंची? प्रश्नोत्तर २८७

श्री हुकुर्मा मह—प्राप्त सूचना के श्रनुसार प्रदेश में ६ मिले १ दिन, ३ मिल, ६ दिन, १ मिल ३ दिन, १ मिल ७ दिन तथा ३ मिनें द दिन पूर्णतः बन्द रहीं। इसके श्रितिरिक्त १६ मिलें कुछ ममय के लिए श्रांशिक रूप से बन्द रहीं। इन मिलों के बन्द रहने के कारण दन्त्वरी के प्रथम पक्ष में लगभग २.२४ लाख मन शक्कर का उत्पादन कम हुआ। लेकिन कुन शक्कर उत्पादन को कितना नुस्सान पहुंचा, यह श्रनुमान लगाना श्रभी सम्भव नहीं है।

"७७—-श्री हरि: बन्द्र बाजपेयी—क्या सरकार कृपना बतायेगी कि पिछले वर्षों मे गन्ने का क्या मूल्य निश्चित किया गया और वह मूल्य किन कारणों से घटाना गया ?

श्री हुर्नुर्निह—गन नीन वर्षों में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निन प्रकार निर्धारित किया गया --

		रु०−प्रा०–रा०	
१६५१-५२	••	११२० प्रति मन्।	
१९५२-५३	••	र ——३——० प्रति पन रेल १——५——० प्रति रच गेट	
१ ६ ५३—५४		१५० प्रति सन नेर	ल ।
(640-40	••	् १ प्रति सन गैर	= 1

प्रकृत का दूसरा भाग केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं।

*७=-- श्री हिर्श्य न्द्र या जिपेशी--क्या सरकार कृप्या बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में इस प्रदेश के भिलों द्वारा कितनी शक्कर बनायी गयी श्रीर इस वर्ष कितनी शक्कर बनने का स्रमुमान है ?

श्री हुनुम^{द्}रह्—पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के मिलों ने निम्नलिखित मात्रा में शक्कर उत्पादन किया—

> १६५१-५२ .. २२७.४४ लाख मन । १६५२-५३ .. १६०.६२ लाख मन ।

इस वर्ष ग्रनुमान किया जाता है कि लगभग १५० लाख मन शक्कर का उत्पादन होगा।

वित्त सिमित, हार्वजनिक भेखा हमिति, प्राक्कलन सिमिति तथा विभिन्न स्थायी सिमितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाल-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना

श्री श्रय्यक्ष--वित्त समिति मे १४ सदस्यों का निर्वाचन होने वाला था। इसमें २१ नाम श्रये हुये है नामजदगी मे। वह २१ नाम इस प्रकार है--

 १—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
 ५— श्री काली चरण टंडन

 २— , महाराज सिंह
 ६— ,, मोहम्मद सुलेमान ग्रथमी

 ३— ,, वलदेव सिंह
 १०— ,, भगवती प्रसाद शुक्ल

 ४— ,, विष्णु शरण दुब्लिश ११— ,, गंगा प्रसाद

 ५— ,, श्रीसिंह

 ६— ,, वीरेंद्र वर्मा १२— ,, नारायण दत्त तिवारी

 ७— ,, राधा कृष्ण ग्रग्नवाल
 १४— ,, जयेन्द्र सिंह विष्ट

[श्री ग्रध्यक्ष]

१५-- " जोरावर वर्मा

१६--श्री रामसुमेर

१६-- "तेज बहादुर

२०-- ,, जयपाल सिंह

१७-- ,, झारखंडेराय

२१-- " पुत्तू लाल

१८-- ,, तेज प्रताप सिंह

इसमे श्री वीरेंद्र वर्मा का नाम शायद वो मर्तबा श्रा गया है । इस तरह स २१ नामो की नामजदगी हुई है। श्रगर ७ सदस्यों के नाम वापस नहीं हुये तो फिर इसका चुनाव होगा। कल तक नाम वापस लेने की मियाद है।

सार्वजनिक लेखा समिति—इसमे २० सदस्यों का निर्वाचन होना है और २६ नाम आये हुये हे। वह इस प्रकार है —

१--श्री सुखीराम भारतीय

१४--श्री गोवर्द्धन तिवारी

२-- ,, राम स्वरूप गुप्त

१४-- ,, धनुषधारी पांडेय

३--- "रामजी ल.ज सहायक

१६--- ,, देवदत्त मिश्र

४--- ,, नन्दकुमार देव वाशिष्ठ

१७-- ,, देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह

५-- ,, बुजवासी लाल

१८-- ,, मदनमोहन उपाध्याय

६-- ,, केशव गुप्त

१६-- " महराजकुमार बालेन्दुशाह

७--- ,, सैयद मुहम्मद वसी नकवी

२०--- ,, जोरावर वर्मा

५--- ,, केशव प्रसाद पांडेय

२१--- "राम सुमेर

६— " मिही लाल

२२-- " हरदयाल सिंह

१०-- " पद्मनाथ सिंह

२३--- " तेजप्रताप सिंह

११-- ,, इतिजा हुसेन

२४— " तेजबहादुर २५— " झारखंडेराय

१२— " ग्रहारफ ग्रली खां १३— " रतनलाल जैन

२६--- ,, चिरंजीलाल जाटव

इनमें से स्रगर ६ नाम वापस नहीं हुये तो फिर चुनाव होगा। कल तक इसकी भी मियाद है।

प्राक्कलन समिति—इस समिति मे २५ सदस्य चुने जाने है श्रौर ३७ नामों की नामजदगी हुई है। वह इस प्रकार है —

१--श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट

६-श्री नारायण दीन

२---,, व्रज विहारी मेहरोत्रा

१०--,, कैलाश प्रकाश

३---,, भगवती प्रसाद शुक्ल

११---,, दीन दयालु शर्मा

४---,, लक्ष्मी शंकर यादव

१२--,, नवल किशोर

५—,, वंशीघर मिश्र

१३---,, जगदीश प्रसाद

६---,, कालिका सिंह

१४---,, बाबू लाल मित्तल

७--,, रामस्वरूप भारतीय

१५--,, स्राचार्य जुगल किशोर

५---,, शिव नारायण

१६--,, शांति प्रपन्न शर्मा

१७—–भी इस्तफा हुसैन	२८श्री जयपाल सिंह
१=—., शिव कुमार शर्मा	२६, रामेश्वर प्रमाद
१६—श्रीमती एस० एस० जहां बेगम	३०—, नेजप्रताप सिंह
२०—श्री रामनारायण त्रिपाठी	₹१—,,
२१—., राजा वीरेद्रशाह	३२,, झारखंडेराय
२२—,, शिवप्रसा व	३३,, जोरावर वर्मा
२३—,, शिवराज सिंह	३४—,, चिरंजीलाल जाटव
२४—,, गंगाधर मैठागी	३५—श्रीमती लक्ष्मी देवी
२५—,, महावीरप्रसाद शुक्ल	३६—श्रो उल्फत सिंह चौहान
२६—,, रामसुमेर	३७—,, रामहेत मिह
२७—–,, पुत्तूलाल	

इममें १२ सदस्य ग्रगर नाम वापस नहीं लेगे तो इसका भी चुनाव होगा।

स्थायो समितियां—ग्रब यह १८ स्थायो समितियां है। इनमे १२ स्थायी समितियों में जो १४ नाम होने चाहिये वह १४ हो नाम है, लेकिन बाकी ६ समितियों में १४ से ग्रधिक है। सेकिन नाम वापस लेने का ग्रधिकार सबको होने के कारण में ग्रभी "निर्वाचित हुये" घोषित नहीं करूंगा, केवल नाम पढ़कर सुना दूंगा, जिनकी नामजदगी हुई है।

सार्वजनिक निर्माण सिमिति—इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्रो मेहरबान सिंह	द—श्रो बद्रोनारायण मिश्र
२— "राजकुमार शर्मा	६— " दाताराम
३ ,, जटाशंकर	१० ,, केशव राम
४— " गुप्तारसिंह	११— " मथुराप्रसाद त्रिपाठी
५— "मुन्नूलालू	१२— "रामेश्वर लाल
६— "राजाराम शर्मा	१३—– "रामसनेही भारतीय
., रामवचन यादव	१४— "राजाराम घ्ररोरा

पुलिस स्थायी समिति --इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है

१——श्री संग्राम सिंह	६—श्रीवजभूबग मिश्र
२ "रानदुलारे मिश्र	१०—श्रीमती चन्द्रावती
३ ,, राम प्रसाद	११— ,, यशोदा देवी
४— " बसंतलाल शर्मा	१२— श्री हबीबुर्रहमान
५— ,, प्रभूदयाल	१३ "रामसुन्दर पांडेय
६— "रामनरेश शुक्ल	१४ "सुरेश प्रकाश सिंह
७—- " द्वारिका प्रसाद पांडेय	१५,, जयपाल सिंह
५ " कृष्ण स्वरूप भटनागर	

```
[श्री ग्रध्यक्ष]
       सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति--इसमे १४ सदस्य नामज्ञ
हुए है --
       १-- श्रो गुरुप्रसाद पाण्डेय
                                     ५--श्रो रमेश वर्मा
       २---,, राजनारायण सिंह
                                     ६---,, नत्थू सिंह
                                     १०-- ,, ग्रवधेश प्रताप सिंह
       ३--- ,, बलभद्र प्रसाद शुक्ल
       ४--- ,, सियाराम चौधरी
                                     ११---,, रघुनाथ प्रसाद
       ५--- ,, शिवराम राय
                                     १२--- ,, भोला सिंह
                                     १३--,, रामनरेश शुक्ल
      ६--, शिववचन राय
                                     १४--, शिवराजबली सिंह
      ७--,, मोहन सिंह
        सहकारी स्थायी समिति—इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई हे-
                                     ८--श्रीमती सज्जन देवी महनोत
       १--श्री उमाशंकर तिवारी
      २-- ,, भगवती प्रसाद दुबे
                                    ६-- श्री तेज बहादुर सिंह
      ३-- "हरी सिंह
                                    १०--,, रामशंकर लाल
      ४--- ,, बैजनाथ सिंह
                                    ११--- "रामसुभग वर्मा
                                    १२--- ,, तेजप्रताप सिंह
      ५---,, जवाहरलाल
                                    १३---,, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव
      ६--,, मिजाजी लाल
                                    १४--, फतेहसिंह राणा
          • ,, राजाराम ग्ररोरा
      सूचना स्थायी सिमिति--इसमे भी १४ सदस्यों की नामजदगी हुई हे -
      १---श्री तुलसी राम
                                    ५-- श्री रामदास
                                    ६--, नागेश्वर द्विवेदी
      ३---, फजलुल हक
      ३--- ,, बेचनराम
                                    १०-- ,, रामचन्द्र विकल
      ४--- "राजवंशी राय
                                    ११--श्रीमती चन्द्रवती देवी
      ५--- ,, रघुवीर सिंह
                                    १२-- श्रो कल्याण राय
      ६--- "वसंत लाल
                                    १३-- " नरोत्तम सिंह
      ७---श्रीमती सावित्री देवी
                                     १४-,, देवदत्त शर्मा
         श्रम स्थायी समिति-इसमे १५ सदस्यों की नामजदगी
      १-- श्री हरदेव सिंह
                                   ७--- ,, शिवराज बली सिंह
                                   ५--- ,, विजय शंकर सिंह
      २--- ,, तुलाराम रावत
      ३---,, मुरलीधर कुरील
                                    ६--- ,, जगन्नाथ मल्ल
      ४--- ,, रामलखन मिश्र
                                    १०--- ,, बासुदेव मिश्र
                                    ११--- ,, भीमसेन
      ५-- " हरख्याल सिंह
```

१२--श्रीमती यशोदा देवी

६—- "रामचरण लाल गंगवार

१३-शी वीरेन्द्रपति यादव

१५--श्री गंगा प्रसाद

१४--- ,, हरी सिंह

स्थानीय स्वज्ञासन स्थायी समिति--इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई हे :--

१--श्री ब्रह्मदत्त दोक्षित

५--श्री सुरजुराम ६-- ,, हरिश्चन्द्र ग्रष्ठाना

२--- ,, कुंवर कृष्ण वर्मा

१०-- ,, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव

३--- ,, महन्त जगन्नाथ बस्त्रा दास ४--- ,, व्रजिवहारी मिश्र

११-- ,, वीरसेन

५--- ,, बाबूराम गुप्त

१२-- ,, मलखान सिंह

६— ,, शिवशरण लाल श्रीवास्तव

१३-- ,, देवदत्त शर्मा

७-- ,, मकसूद श्रालम

१४-- ,, बैजनाथ सिंह

माल की स्थायी समिति--इसमे १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है ---

१-शो लाल बहादुर सिंह

६--श्री रामप्रसाद सिंह

२--- ,, मथुरा प्रसाद पांडेय

१०-- ,, विशम्भर सिंह

३--- ,, केवल सिंह

११--- ,, मकसूद ग्रालम खां

४-- ,, निरंजन सिंह

१२-- ,, द्वारिका प्रसाद

५-- ,, शिवस्वरूप सिंह

१३-- " नेकराम शर्मा

६-- ,, रामशंकर रविवासी

१४-- , ब्रजविहारी मिश्र

७-- ,, गेंदासिह

१५-- " जोरावर वर्मा

५-- " शम्भूनाथ चतुर्वेदी

सार्वजनिक निर्माण (विद्युत्) स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हई है ---

१--श्रो कल्याण राय

५- श्री राम प्रसाद देशमुख

२--- ,, ग्रब्दुल लतीफ खां

६-- श्रीमती प्रकाशवती सुद

३--- ,, घासी राम

१०-- श्री वासुदेव मिश्र

४— " भगवान सहाय

११--- ,, पुलिन बिहारी बैनर्जी

५-- ,, कल्याण चन्द मोहिले

१२-- ,, सुल्तान म्रालम खां

६--- "पुत्तूलाल

१३— " हरिस्चन्द्र ग्रष्ठाना

७- ,, नौरंग लाल

१४--- ,, भगत दयाल दास

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति--इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है।

१--- श्री परमानन्द सिन्हा

३--श्री गनेश चन्द काछी

२--- ,, गनेश प्रसाद पांडे

४-- " महमूद श्रली खां

[श्री ग्रध्य त]

५—श्री शिवमंगल सिंह १९—महाराजकुमार बालेन्दुशाह ६— ,, वंशनारायण सिंह १२— ,, बाब्राम गुप्ता ७— ,, भगवती दीन तिवारी १३— ,, ब्रह्मदत्त दीक्षित ६— ,, राजनारायण सिंह १४— ,, लक्ष्मी रमण श्राचार्य

६--- ,, महमूद म्रली खां १४--- ,, जयपाल सिंह१०--- ,, जयराम वर्मा १६--- ,, जोरावर वर्मा

शिक्षा स्थायी समिति--इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई।

१—श्री गंगाधर शर्मा ६--श्री विश्राम राय

२-- ,, मोहम्मद नसीर १०-- ,, परिपूर्णानन्द वर्मा

३--- ,, उमाशंकर मिश्र ११--- ,, देवराम

४-- ,, तेजा सिंह १२-- ,, सत्य सिंह राणा

५-- ,, नरदेव शास्त्री १३-- ,, गंगा सिंह

६--, , बोरेन्द्रपति यादव १४--, , रघुवीर सिंह

७--- ,, सहदेव सिंह १५--- ,, वीरसेन

८--- ,, राम स्वरुप

न्याय तथा विघान सम्बन्धी स्थायी सिमिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए-

१-श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ८-श्री वंशीदास धनगर

२-- ,, ग्रंशमान सिंह ६-- ,, केंदार नाथ

३--- ,, बलवीर सिंह १०--- ,, जयराम वर्मा

४— " द्वारका प्रसाद ११— " ग्रब्दुल लतीफ़ खां

५-- ,, लक्ष्मी रमण ब्राचार्य १२-- ,, भगवती दीन तिवारी

६--- " शिवनाथ काटज् १३--- " ज्वाला प्रसाद सिनहा

७- ,, शिव बल्श सिंह १४- ,, नरदेव शास्त्री

चिकित्सा ग्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए--

१—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि द—श्री श्रीनाथ भार्गव

२--- ,, पुलिन बिहारी बनर्जी ६--- ,, मदन गोपाल वैद्य

३--- ,, बाब् लाल कु दुमेश १०--- डा० जवाहर लाल रस्तोगी

४--- ,, नेत्रपाल सिंह ११--- ,, ग्रवधेश प्रताप सिंह

५--श्री उमा शंकर १२--श्री राम शंकर द्विवेदी

६--- ,, धर्म दत्त वैद्य १३--- ,, मुहम्मद नसीर

७--- ,, राजेन्द्र दत्त १४--- ,, गुरु प्रसाद

वित्त मिनि. सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समिनियों के निर्वाचन मे प्राप्त नाम निर्देशनों के सम्बन्ध मे सूचना

उद्योग न्थायी ममिति - इममे १४ सदम्य निर्वाचित हुये हे :--

१——श्री सत्य नारायण	८श्रीमनी प्रकाशवती सूद
---------------------	------------------------

--- ,, हरदयाल सिंह पिपल ६--श्रो ऐजाज रसूल

३--- ,, रामग्रवध सिंह १०--- ,, शिवराज बली सिंह

४--- ,, राजिकशोर ११--- ,, उम्मेद सिंह

५--- ,, उदयभान सिंह १२--- ,, महमूद स्रली खां

६—— ,, गजेन्द्र सिंह १३—— ,, भगवान सहाय

७— ,, ग्रब्द्ल ममद
१४— ,, शिवराम राय

कृषि तथा पशुपालन स्थायो सिमिति—इममे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१-भी रमेश चन्द्र शर्मा ५-- श्री शंकर लाल

२--- ,, पहलवान सिंह ६--- ,, भगवती प्रसाद दुबे

३-- ,, राघवन्द्र प्रताप सिंह १०-- ,, लाल बहादुर सिंह

४--- ,, लुत्फ़ ग्रली खां ११--- ,, श्रीचन्द ५--- ,, तिरमल सिंह १२--- ,, श्रीनिवास

६--- ,, महावीर सिंह १३--- ,, सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी

७-- ,, स्रवधशरण वर्मा १४-- ., झारलंडे राय

सदस्य ानवााचत हुय ह--

२--- ,, हरिप्रसाद ६--- ,, रामस्वरूप

३--- ,, महादेव प्रसाद १०--- ,, रघुनाथ प्रसाद

४--- ,, सत्यसिंह ११--- ,, कमाल ग्रहमद रिजवी

५--- ,, खुशीराम १२--- ;, बसन्तलाल शर्मा

६-- ,, बेनीसिंह १३-- ,, दीनदयालु शास्त्री

७--- ., चन्द्रहास १४--- ,, राजाराम शर्मा

विकास व नियोजन स्थायी सिमिति--इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है-

१--श्री चिरंजीलाल पालीवाल ५-- श्री वजभूषण मिश्र

२-- ,, रामहेतसिंह ६-- ,, भृगुनाय चतुर्वेदी

३--- ,, दीपनारायण वर्मा ७--- ,, किन्दरलाल

· ,, बलवन्तसिंह , लेखराज सिंह

[श्री ग्रध्यक्ष]

६श्री गुरुप्रसाद सिंह	१३श्री करनसिंह
१० ,, मदनमोहन उपाध्याय	१४ " तेज बहादुर
११ "फतेहसिंह राणा	१५ " नेकराम शर्मा
१२ " परमानन्द सिन्हा	१६— " वीर सेन

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति - इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है-

१—श्री भीमसेन	८श्री मुरलीधर कुरील
२— ,, कन्हैयालाल	६ ,, गुल्जार
३— ,, चुन्नीलाल	१० ,, पुत्तूलाल
४— " बेचनराम	११—– "रामलाल
४— " तुलाराम (इटावा)	१२—– " तुलाराम (लखनऊ)
६ ,, रामदास	१३— "गौरीराम
७ ,, सेवाराम	१४— ,, सुरजू राम

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरपतारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री स्रध्यक्ष-- प्रव में माननीय उपाध्यक्ष जी से कहूंगा कि वे श्रपनी रिपोर्ट पेश करें।

उपाध्यक्ष (श्री हरगोविन्द पन्त)—माननीथ ग्रध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी ग्राज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरक्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने जो प्रतिवेदन उपस्थित किया है, उस पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नंनीताल)—वाइंट धाफ ग्राडंर। श्रीमन्, में धापसे व्यवस्था जानना चाहता हूं ग्रीर ग्रापका ध्यान समिति की रिपोर्ट के पेच ४३ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें ग्रन्त में लिखा है, "ठीक है, तो इसी प्रकार रिपोर्ट तैयार की जायगी।" फिर नीचे बैकेट्स में लिखा है, "प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के पास हस्ताक्षरार्थ भेज दिया गया।" तो श्रीमन्, में ग्रापसे जानना चाहता हूं कि कोई कमेटी जब तक खुद कोई फैसला न करे ग्रीर उसकी रिपोर्ट मेम्बरों के कमरों में हस्ताक्षर के लिये भेज दी जाय तो वह कमेटी की रिपोर्ट कैसे मान ली जायगी, जैसे हाउस की ग्रपना फैसला यहां सदन में लेना चाहिये ग्रीर

दक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

म्रार हमारे पास दाहलशफा में कोई बिल दस्तखतों के लिये भेज दिया जाय तो मं ममझना हूं कि दस्तखत भले ही हम कर दें लेकिन उन दस्तखतों से कोई काम बनने वाला नहीं है। तो कमेटो की रिपोर्ट कमेटी की मीटिंग के सामने नहीं खायां। हाउम ग्राफ कामन्स में यह होता है कि कमेटी की रिपोर्ट सभापित तैयार करते हं ग्रीर उसके बाद वह रिपोर्ट समिति के सामने धाती है ग्रीर एक एक पैराग्राफशाइग्र ली जाती है। तो हाउस ग्राफ कामन्स की प्रणाली के धनुसार भी यह गनत है। तो में चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में चूंकि विशेषाधिकार समिति ने कोई प्रोमोर्डेट तो निश्चित नहीं किया इसलिये ग्राप व्यवस्था दें कि यह रिपोर्ट जिस पर मदस्यों के कमरों में भेज कर हस्ताक्षर कराये गये हैं क्या सिमिति की रिपोर्ट मानी जा सकती है।

दूसरे यह कि मेरी चिट्ठियां जो मंने इस कमेटी के सामने भेजी थीं मुझे ऐसा लगता है कि वे पढ़ कर मुनायो नहीं गयीं क्योंकि प्रोसीडिंग्स में भी वे नहीं है और न उनका कहीं जिक है। इसलिये में समझता हूं कि कमेटी के सामने जो हमारा केस है वह पूरा नहीं श्राया। तो इस सम्बन्ध में मं श्रापकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस इंक्वायरी के सम्बन्ध में तीन
मुख्य प्रश्न थे उन पर....

श्री ग्रध्यक्ष-मं इनके बारे में जानना चाहता हूं जो प्रश्न उठाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो हां, उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि तीन मुख्य प्रक्रन थे। उनके संबंध में कमेटी की राय ली गई थी श्रीर उनका विभाजन भी इस प्रतिबंदन में दिया गया है, उनका निक्चय होना चाहिये। कमेटी ने माना कि श्रव रिपोर्ट तयार होनी चाहिये श्रीर जो श्रस्वीकृति की राय देना चाहेंगे वह दे सकेंगे। इसिलये यह समिति के ही सदस्यों का निक्चय है श्रीर उसके श्रनुसार ही यह कार्यवाही की गई है।

दूसरे प्रश्न के विषय में यह कहना है कि हमारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रापके ही द्वारा इस सदन के लिये भेजा है और जितने भी कागजात हमारे सामने आये ये वह सब के सब हमने भेज दिये। कौन से पत्र छापे जायं और कौन से शामिल किये जायं, इसका निश्चय करना अध्यक्ष का काम है। उसके अनुसार जो पत्र मुनासिब समझे गये, छापे गये हैं, बाकी पत्र जिनके विषय में कोई माननीय सदस्य जानना चाहें, वह आपकी अनुमति से देख सकते हैं। रहा यह जैसा कि कहा जाता है कि उनके पत्र पर विचार नहीं किया गया, यह बात सही नहीं है। कमेटी के सामने जितने भी कागजात आये वह सब को दिखाये गये और उन पर विचार किया गया। में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने दो आक्षेप किये हैं ग्रौर वह मेरा इस सम्बन्ध में निर्णय चाहते हैं कि वैधानिक रूप से यह समिति की रिपोर्ट मानी जाय या न मानी जाय। पहला आक्षेप यह है कि समिति की जो रिपोर्ट तैयार हुई वह समिति के सामने, समिति की बैठक बुलाकर, नहीं रखी गई बल्कि दस्तखत बाद में कराये गये ग्रीर यह वैधानिक दृष्टि से ठीक है या नहीं क्योंकि उनका कहना है कि ममिनि का कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि बाद में दस्तखत करा निये जायं। जब इसके

[श्री ग्रध्यक्ष]

विपरीत भी कोई नियम नहीं है श्रीर उसका प्रोसीजर इस किस्म का नहीं है कि रिपोर्ट सिमित की बैठक में श्रानी ही चाहिये ऐसी श्रवस्था में केवल सिमित के सदस्यों का ही यह श्रिधकार था कि वह कोई निर्णय करते। जब सिमित के सदस्यों ने इस रिपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर दिये श्रीर उसके बाद कोई श्राक्षेप सिमित के सामने वह नहीं लाये श्रीर न सिमित के श्रध्यक्ष के सामने लाये ऐसी श्रवस्था में किसी दूसरे सदस्य को श्राक्षेप करने का श्रिधकार नहीं है। प्रोसीजर जो सिमिति के सदस्यों को सर्वमान्य था उसके ऊपर उपाध्यक्ष ने प्रकाश डाला है। जहां तक निर्णय का सम्बन्ध है वह रिपोर्ट में मौजूद है श्रीर बैठक में निर्णय हुश्रा है। ऐसी श्रवस्था में इस रिपोर्ट की श्रवंध नहीं कहा जा सकता है श्रीर यह सिमिति को रिपोर्ट मानी जायगी।

दूसरा जो आक्षेप उठाया गया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कौन से पत्र और कौन-कौन सी बातें जो सिमिति के सामने श्राई थीं, वह छापी जायं। मैंने इस सम्बन्ध में जो ग्रीर जगह प्रया थी उसकी देखकर, क्योंकि कोई उसके लिये निश्चित प्रोसीजर मौजूद नहीं था, यह निर्णय किया कि चूंकि सब के सब कागजात के छपवाने में व्यर्थ हो खर्चा होता है इसलिये जितनी सामग्री श्रावश्यक हो, सदस्यों की जानकारी के लिये और जो रिवाज और जगह मौजूद है उसके अनुसार कार्य होना चाहिये। इस रिपोर्ट में जो सदन में प्रक्त उपस्थित किया गया था वहां से लेकर किस तरह से वह प्रिविलेज कमेटी के सामने गया श्रीर इस संबंध में क्या-क्या चर्चा सदन में हुई वह इस रिपोर्ट में सब बातें श्रा चुकी हैं, श्रीर जो कागजात पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में यह भी नियम रखा गया कि जिन लोगों ने गवाहियां दीं जिस बंठक में, उनका जिक उसनें ग्रा जाना चाहिये ग्रीर जो प्रश्न उठ चुके है वह ग्रा जाने चाहिये। लेकिन ग्रगर ग्रीर कोई ग्रपने विचार पेश करता है, ऐसे खतों के सम्बन्ध में कहाँ भी, जो मंने दूसरी रिपोर्ट देखी, उनमें कहीं भी कोई तरीका नहीं देखा कि वे पत्र छापे गये हों । दूसरे , पहले भी एक आध बार रिपोर्ट छपी, उसमें यह पाया गया कि जो सदस्यों ने श्रापस में बातचीत की श्रीर विवाद किया वह भी छप गया, लेकिन यह विवाद गुप्त ही रहना उचित है। मैंने इंगलैण्ड की पालियामेंट की रिपोर्ट की देखा, उनमें केवल यह दर्ज है "प्रश्न पर समिति में चर्चा हुई या विचार हुन्ना, या इतने सदस्य उसमें मौजूद रहे ग्रीर उन्होंने विचार-विनिमय किया।" इस तरह की रिपोर्ट मैने देखी हैं। तो संक्षेप में यह बता देने को थी इससे भी बहुत कुछ काम छपाई का हल्का हो जाता है।

तो प्रोसीजर को तय करना मेरा काम होने के कारण ग्रीर छपाई के सम्बन्ध में मेरी जानकारी होने के कारण मेरी ग्राज्ञा के ग्रनुसार यह रिपोर्ट छपी है। इसलिए यह वैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता है कि यह रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं है। तिस पर भी माननीय सदस्यों के सूचनार्थ श्री नारायणदत्त तिवारी के भेजे हुए पत्र मेज पर रख दिये हैं, जो ग्रसम्बली के टेबिल पर हैं। जो माननीय सदस्य चाहें वह देख सकते हैं, लेकिन ग्रवैधानिक या श्रवूरी इस रिपोर्ट को नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ग्रापसे निवेदन करना चाहता था कि जो दो घंटे का समय इस कार्य के लिए रखा गया है वह कम मालूम होता है। वह बढ़ा दिया जाय।

श्री श्रध्यक्ष — में समझता हूं कि पहले इस पर थोड़ी चर्चा हो जाय। उसके बाद श्रगर श्रावश्यकता होगी तो बढ़ा दिया जायगा । श्री उपाध्यक्ष श्रपना भावण जारी रखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर २६७ विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालीन)—मं एक प्रस्ताव रखना चाहता था। श्री ग्रध्यक्ष—ग्रभी उक्का समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।
म नमझता हूं कि मुझे श्रिषक कहने की श्रावक्ष्यकता भी नहीं है, क्योंकि इस प्रतिवेदन की छ्यो हुई प्रतियां कई दिनों से माननीय सदस्यों के सामने मौजूद है श्रौर
इस नीमित ने पूरी द बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिये की श्रौर ऐडवोकेट
जनरल की श्रनुमित हमने इसमें हासिल की। जी कुछ शहादत श्रौर बयान हुए
उस पर विचार करके बहुमत से कोई फंसला उसमें किया गया है। इसलिये में
ममझता हूं कि इस पर मुझे श्रौर श्रिषक कहने की श्रावश्यकता नहीं है। में केवल
प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) — ग्रध्यक्ष महोदय, मं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय, ताकि ग्रधिक से ग्रधिक लोगों को भाग लेने का मीका मिले। उसके लिये मे प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट का टाइम कर दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष-तो इसमें सब की ग्रनुमित है?

तो ठीक है, इसी तरह से सब को टाइम दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज जो प्रथा इस सम्बन्ध में पालन की गयी हूं वह पहले जब रिपोर्ट पेश की गयीं उससे कुछ भिन्न मी हूं। पिछली मर्तबा जो रिपोर्ट पेश की गयीं तो फार्मल रेजोल्यूशन किसी सदस्य की तरफ से ग्राया ग्रीर उस पर वहस हुई। ग्रब माननीय उपाध्यक्ष ने यह रिपोर्ट पेश कर दी। तो पूरी रिपोर्ट एक रेजोल्यूशन की शक्त में हाउस के सामने हैं ग्रीर उसके खंडों या ग्रंशों या पैराग्राफों पर संशोधन देने का भी ग्रधिकार होगा, या किस तरह से उस पर विचार होगा, इस पर ग्रापकी राय जानना चाहता था।

श्री ग्रध्यक्ष--नियम ५३ में यह दिया हुन्रा हं--

"After the report of the Privileges Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members."

दूसरे नियम ५७ में यह दिया हुआ है--

"After any of the following motions is agreed to by the House—

- (1) Motion under rule 48 that the matter be taken into consideration; or
- (2) Motion under rule 53 that the report of the Privileges Committee be taken into consideration; or
- (3) Motion under rule 54 that the report of the Secretary be taken into consideration; or
- (4) Motion under rule 55 that the petition be taken into consideration; or

[श्री ग्रध्यक्ष]

(5) Motion under rule 6 that the question of the breach of privilege, as contained in the report of the Committee, be taken into consideration; any member may move a substantive motion indicating the commission of a breach of privilege and also suggesting the action to be taken by the House, and any other member may, move an amendment to the said motion. After a brief discussion of the motion and the amendments, if any, the Speaker shall put the question."

तो इन नियमों में स्पष्ट है कि रिपोर्ट पहले सदन के सामने विचारार्थ आती है। आगर सदन ने यह स्वीकार किया कि अभी इस पर विचार कर लिया जाय तो उसी क्षत विचार होगा और कोई प्रस्ताव जोिक नियम ५७ के अनुसार आना चाहिये वह आयेगा। लेकिन सदन ने अगर यह विचार किया कि आज नहीं विचार करना है तो यह सदन यह भी निर्णय कर सकता है कि आज न विचार करके किसी दूसरे रोज उसके अपर विचार कर लिया जाय। इसलिये आज यह प्रस्ताव सदन के सामने है कि विचार किया जाय या न किया जाय। पहले इसमें अगर सदन राजी हो जाता है कि विचार किया जाय या न किया जाय। पहले इसमें अगर सदन राजी हो जाता है कि विचार किया जाय तो कोई प्रस्ताव आ सकता है इसके बारे में। (थोड़ी देर रुक्कर) तो किसी का कोई प्रस्ताव नहीं है?

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके ग्रमी सूचना देने पर मंं, श्रीमन्, यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विशेषाधिकार की रिपोर्ट ग्राज न ली जाय क्योंकि हम लोग मोशन इस वक्त नहीं दे सकेंगे कल के लिये इसे इसी समय के लिए रख दिया जाय ताकि प्रस्ताव ग्रगर हम लाना चाहेंगे तो ला सकेंगे ग्रीर उसके साथ साथ अमेंडमेंट भी दे सकेंगे ग्रीर उसके ऊपर सदन विचार करेगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—श्रध्यक्ष महोदय, १३ मार्च की बंठक में स्रापने यह निश्चय किया था कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना न देने का जो कारण था, वह नियम के स्रनुसार प्रारम्भिक विश्लेषण के बाद सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना थी और उसी के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल की कोई सम्मति प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं श्रा सकी है। इसलिये मं प्रस्ताव करता हूं कि ऐडवोकेट जनरल की सम्मति श्राने तक के लिये इस विचार को पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मूल प्रस्ताव यह है कि विचार किया जाय। जसके जिपर दो संशोवन हैं। एक वोरेन्द्रशाह जी का ग्रीर दूसरा श्री कृष्णशरण ग्रार्य का। तो मैं पहले श्री कृष्णशरण ग्रार्य जी का संशोधन लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार तब किया जाय जब कि ऐडवोकेट जनरल की राय इस विषय पर लेली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ग्रध्यक्ष---प्रश्नयह है कि इस रिपोर्ट पर ग्राज विचार न किया जाय। बल्कि कल किया जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ंउत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोघन) विधेयक, १६५४ "खंड १४ (क्रमागत)

श्री श्रध्यक्ष—-उत्तर प्रदेश पंचायत राज (मशोधन) विधेयक, १९४४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुन्ना है, विचार जारी रहेगा।

विशेषाधिकार का प्रक्त उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना

े श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला ग्रत्मोड़ा)—ग्रध्यक्ष महोदय, मैने एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल उठाया था ग्रौर ग्राज के लिए ग्रापने उम पर ग्रपना निर्णय देने को कहा था। तो वह कब लिया जायगा जरा उमकी सूचना दे दें।

श्री श्रध्यक्ष—वह तो कल ही लिया जायगा। श्राज तो उसको इसलिए टाला गया कि माननीय बित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि वह श्राज के दिन उपस्थित नहीं होंगे श्रीर उनके पास नोटिस भेज भी दी गयी। गृह मंत्री उस वक्त मौजूद नहीं थे। श्राज श्रा गये हैं। मै समझता हूं कि प्रश्नों के बाद पहले ही इसको कल ले लिया जायगा। उसके बाद रिपोर्ट पर विचार होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रकृत पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गड़वाल)-शी नारायण दत तिवारी जी के प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ निश्चय हुग्रा वह कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे वातावरण में हुग्रां कि मालूम नहीं हो सका कि क्या निश्चय हुग्रा। इसलिए कृपया जो निश्चय हुग्रा है उसकी घोषणा कर दी जाय।

श्री ग्रध्यक्ष——तिश्वय यह हुग्रा है कि बजाय ग्राज के कल इसके ऊपर विचार किया जायगा।

में इसके ऊपर फिर पूरी राय ले लेता हूं क्योंकि मैने संशोधित प्रस्ताव के ऊपर राय नहीं ली थी। मुझ से थोड़ी सी गलती हो गयी।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर सदन कल विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुन्ना ।)

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) — आज करीब १४,२० मिनट इसके ऊपर सर्च हो चुके। इसके लिए जो २ घंटे का समय नियत था उसमें से कल १४,२० मिनट काट दिये जांग।

श्री श्रध्यक्ष — वह तो समय बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो बढ़ाने श्रौर घटाने दोनों को सेट श्रसाइड कर दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--रूल में लिखा है कि बहुत ब्रीफ डिस्कशन के बाद मामला सत्म हो जायगा । दो घंटे जरूरत से ज्यादा होते हैं।

श्री श्रध्यक्ष--दो घंटे से कम हो सकता है ग्रगर बहस बीच में खत्म कर दी जाय।

ासयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ म्रप्रैल, १६४४ की कार्यावाही में छपा है ।
*४ मई, १६५४ को कार्यवाही में छपा है ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संज्ञोधन) विधेयक, १९५४ खंड १४ (क्रमागत)

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) — ग्रध्यक्ष महोदय, कल मंने इस सम्बन्ध में ग्रपने दोनों प्रस्तावों को रखते हुए यह निवेदन किया था कि पहले प्रस्ताव से तो में यह चाहना हूं कि पंचायतों में कम से कम एक श्राधार पर पेटीशन न रखा जाय।

ग्रध्यक्ष महोदय, शान्ति नहीं है।

श्री स्रध्यक्ष—माननीय सदस्य जब यहां से जायं तो धीरे से जायं तो ज्यादा भ्रच्छा है स्रौर कृपा करके स्रापस में बात न करे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पहले संशोधन के द्वारा इस सदन से निवेदन किया था कि कम से कम प्रापर ऐक्सेप्टंस ग्रार रिजेक्शन ग्राफ ए नामिनेशन पेपर के ग्राधार पर कोई एलेक्शन पेटीशन न माना जाय ग्रौर दूसरे संशोधन में मेंने इस बात का सुझाव दिया था कि ग्रगर यह रखना ग्रावश्यक ही हो जाय तो ऐसी हालत में जिस दिन इस बुनियाद पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाय उसके तीन दिन के ग्रन्दर ग्रगर नियत ग्रिधिकारी के पाम कोई दरख्वास्त इस संबंध में ग्रा जाती है तो वह एलेक्शन रोक दिया जाय ग्रौर इस मामले पर निर्णय होने के बाद फिर ग्रागे एलेक्शन कराया जाय।

श्री श्रध्यक्ष—माननीय सदस्यों से कहूंगा कि श्रापस में बाते बहुत हो रही है। मं समझता हूं कि श्रापस में बातें नहीं करना चाहिये। श्रब मैं नाम ले दूंगा जो माननीय सदस्य बात करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पहले संशोधन के बारे में मैने यह कहा कि यह मामला अदेश की ३५ हजार ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है। ग्राप ३५ हजार ग्राम पंचायतों में २०-२० मेम्बर भी मान लिये जा ग्राँग एक-एक जगह के लिये १०,१५ या २० नामजदगी के पर्चे ग्रा ज "यं तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि दो-तीन लाख नामजदगी के पर्चों को देखना होगा। इसकी संभावना है कि गलत तरीके से पर्चे भरे जायेंगे, वे खारिज कर दिये जायेंगे जिससे कि बड़ी श्रव्यवस्था सी होगी। मेरा निवेदन यह था कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में रिटिंगिंग श्राफिसर स्वयं ही नामिनेशन पेपर भर देते थे ग्रौर टाउन एरिया, विधान सभा ग्रौर लोक सभा के चुनावों में इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि नामजदगी के पर्चे भरे जायं, लेकिन टेक्निकल ग्रांउड पर वापस कर दिये जायं उनको दुरुस्त करने के लिए उसी तरह से यहां भी यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोग चुनाव कराने जायेंगे उनके पर्चे रिटिंग श्राफिसर्स भर देगें ग्रौर वही सही माने जायेंगे। क्योंकि जितने उम्मीदवार टाउन एरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, विधान सभा ग्रौर लोक सभा में कुल मिला कर होंगे उनसे कई गुना ज्यादा नामजदगी के पर्चे गांव सभाग्रों के चुनावों में ग्रायेंगे।

दूसरा संशोधन यह है कि ग्रगर इन्प्रापर एक्सेपटेंस ग्रौर रिजेक्शन के ग्राधार पर तीन दिन के भीतर कोई शख्स पिटीशन दायर करता है तो जिस एलेक्शन से वह पिटीशन सम्बन्धित हो उसे रोक दिया जाय ग्रौर उस मामले के निर्णय के बाद ही एलेक्शन कराया जाय। पता नहीं कितनी कांस्टीट्यूएंसी होंगी या इसकी संभावना है कि पूरी गांव सभा को एक ही जगह इकट्ठा करके पूरा गांव पंचायत का एक ही जगह चुनाव करा लिया जाय। ग्रगर यह व्यवस्था की कि २५ पंच चुनने है ग्रौर उनमें एक भी नामजदगी का पर्चा रह कर दिया गया ग्रौर एलेक्शन दुबारा हुग्रा तो पूरी पंचायत का एलेक्शन रह समझा जायगा ग्रौर दुवारा एलेक्शन कराना पड़ेगा। ग्रगर छोटे-छेटे क्षेत्र बना कर गांव सभाग्रों का चुनाव कराया गया ग्रौर तीन उम्मीदवार हैं ग्रौर तीन सीट्स हैं ग्रौर ग्रगर एक का भी नामजदगी

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का पर्चा रह हो गया श्रोर इलेकान न रोका गया तो बाद में वह चुनाव फिर तीनों जगहों का कराना होगा। इसलिये मेरा दूसरा संशोधन भी उचित मानूम होता है श्रोर उसमें कोई विकान नहीं मानूम होती। मं समझता हूं कि मेरे कल श्रोर श्राज के भाषणों का श्रथं माननीय मंत्री जी ने श्रच्छी तरह से समझ लिया होगा श्रौर मुझे उम्मीद है कि वह मेरा पहला नहीं तो दूमरा संशोधन श्रवश्य मान लेंगे।

*स्वज्ञासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स में की गई थी कि रिटर्निंग ग्राफिससं स्वयं पर्चे को देख लें श्रौर मगर कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त कर ले, वही ठीक इसमें भी मालूम होती है इतना कहना मनासिब न होगा कि उस तरीके ने बहुत ग्रच्छा नतीजा दिखाया ग्रीर बहुत थोड़े पर्चे गल : तरोंके से खारिज हुये या गलत तरीके से मंजूर हुने। इसलिये, माननीय ऋध्यक्ष महोदय, श्राप देखेंगे कि इस प्रदेश में म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन्स में जिन प्रकार से ग्रसेम्बली स्रौर पालियामेंट के एने स्नान में गलत तरीके से पर्वे मंजूर होने या नामंजूर होने से जितने इलेक्शन पिटोझंम हुये और जितनो परेशानी हुई वह म्युनिसिपन बोर्ड स के इलेक्झंस में नहीं हुई। ऐसा मेरा ख्याल है। अगर इससे काम चल जाय तो मुझे कोई आपित नहीं है: मै यह कह सकता हूं कि इस तरह की हिदायत किर भी जानी चाहिये। मं इतना निवेदन और कर दं कि शायद यह भी नामुनासिब न हो कि अगर इस तरह से प्रपोजल प्रपोज करने वाले के नेफेन्ड करने वाले न हों तब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो खड़ा होना चाहे वह खड़ा हो जाय और बाकी वोटर उसको सेकेन्ड कर दें यह हो या न हो इसमें कोई गुजाइश प्रयोजन की सही होने की हो या न हो और उसका सेकेन्ड करने वाले भी सही है। या न हों। लेकिन यह प्र विजी इसका इसलिये किया जा रहा है कि इतना होते हुये भी ऐसा हो सकता है कि चाहे वह २-४ मामले ही हों कि किसी का सही पर्वा खारिज हो ग्रीर सही खारिज हुन्ना ग्रीर गलत मंजूर हो गया। में इस पर ग्रपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सामने यह समस्या है कि एक जगह पर शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पर एक मुसलमान एलेक्ट हो गया। भ्रव प्रश्न यह है कि वह भ्रा सकता है या नहीं मुमिकन है कि ऐसे २-४ ही केसेज हों, लेकिन किर भी हो सकता है कि उसके लिये ला में प्राविजन तो होना ही चाहिये। एक दफा इलेक्शन डिक्लेयर हो जाय तो उसके लिये दो ही तरीके है। या तो उसको एक्जिक्यूटिव प्रधिकार से रिमुव कर दें या उसका एलेक्शन पिटीशन के जरिये करायें। एलेक्शन मे जो कुछ भी गलती हों वह पीटीशन के जरिये ही दुरुस्त हों यह सही तरीका है। भ्रगर यह इसमें से निकाल दिया जायगा तो राम नारायण जी यह कहेगे कि रिटर्निंग श्रफसर जो चाहेगा करेगा श्रौर जिसकी चाहेगा उसकी खारिज कर देगा ग्रौर इसके बाद बड़ी मुसीबत हो जायगी ' तो से यह समझता हूं कि इसमें तो उनका भी फायदा है भ्रौर सबका फायदा है कि खामख्वाह रिटनिंग श्रफसर नामजदगी को गलत तरीके से खारिज कर दे तो तब यह एलेक्शन पिटीशन के जरिये फैसले का प्राविजन होना चाहिये।

ग्रगर ३ दिन की बात रखी जाय कि इस तीन दिन के ग्रन्दर हो जाय तो तीन दिन के ग्रन्दर मुमिकन है न हो पाये। एलेक्शन पीटिशन के बजाय बहुत संझट बढ़ जायगा। बड़े इलेश्शन का इन्तजाम होना ग्रासान होता है, लेकिन इसमें दिक्कत बढ़ जायगी ग्रौर ग्रगर यह प्रैक्टिकल न हुग्रा तो बाद में इस तरह की हिदायत दे सकते है ग्रौर इसके लिये क्ल्स में प्राविजन करने में मुझे ग्रापित नहीं है। इलेक्शन में जित हो भी सहूलियत हों, ईमा उदारी ग्रौर सही तरीके से फेयर एलेक्शन करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इन शब्दों के साथ में यह ग्राशा करता हूं कि राम नारायण जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही ग्रीर जो ग्राह्वासन दिया ग्रीर इसके संबंध में यह मसला उनके विचाराघीन है तो में

^{*}बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रो रामनारायण त्रिपाठी]

इस बात की संभावना देखते हुये कि शायद नियमों में व्यवस्था करते समय इस बात पर वह गौर करेंगे श्रीर इस प्रकार की व्यवस्था जैसी हम चाहते हैं वह कर देंगे, इसलिये में इस् संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री क्वंर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर) — मैं ग्रापकी ग्राज्ञा से यह संशोधन प्रस्तृत करता हं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12 c की उपधारा (2) A की पंकित १ में से ग्रंक (1) हटाकर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय श्रीर भाग (b) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" श्रपने स्थान पर से हट कर उसके नीचे क्लाज (२) के रूप में कायम किये जांय ग्रीर 12 c (1) (b) (ii) के बाद नया उप-खंड (iii) "by wrong counting or recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय। म्रगर मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो १२-सी की उपधारा (१) में जो दिया हुन्ना है कि किन-किन बातों पर इलेक्झन पैटीशन दायर होगा उसमें (१) (बी) में जो (ii) है उसके नीचे में यह बढ़ाना चाहता हूं कि "(iii) by wrong counting or recording of votes" पिछले एलेक्शन में यह देखा गया था कि हाथ उठाकर जो चुनाव होता है उसमें श्रकसर कर्मचारी या तो गलती करते हैं किसी भूल में या बहुत से कर्मचारी अगर मिला लिये जाते हैं तो वह गलती जानबूझकर कर देते हैं हालांकि एक तरफ बहुमत है, ज्यादा हाथ उठे हैं, लेकिन वे जानबूझ कर उसे कम दिखा देते हैं। तो या तो वैसे ही उससे गलती हुई या जानबुझ कर उन्होंने ज्यादा को कम लिख दिया। इसके लिये कोई बात इसमें नहीं रखी गई थी कि इसकी क्या दवा है। इसके ऊपर इलेक्शन पेटीशन श्रा सकता है या नहीं, या उसके लिये क्या इलाज है ? यह है कि इस बात पर बहुत ज्यादा ग्रसंतोष गांवों में है कि हाथ उठाकर वोट में बेईमानी होती हं जिसका कोई इलाज नहीं रखा गया है। इसी वजह से बहुत से माननीय सदस्य भी हाथ उठाने के खिलाफ रहे श्रौर वे च हते थे कि बाई बैलट इलेक्शन हो। श्रगर यदि बैलट से नहीं होता तो बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रावीजन इसमें हो ताकि यह बेईमानी दूर हो सके।

दूसरा ग्रंग मेरे संशोधन का क्लाज (२) की परिभाषा पर है।

*श्री श्रद्धुल मुईज खां (जिला बस्ती)—ग्रान ए प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर । श्रीमन्, इस संशोधन में २,३ बात इकट्ठा की गई हैं। खंड (ए) के बाद खंड (बी) में भी संशोधन रखा गया है। लेकिन उसके नीचे ग्राप देंखेंगे कि खंड (ए) के सिलसिले में जो संशोधन नीचे ग्राये हैं वे ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर हो जायेंगे, दोनों ग्रसंगत भी हैं। इस संशोधन की ग्राखिरी जो लाइन है यानी १२—सी (१) बी (ii) के बाद नया खंड (iii) जोड़ने के बारे में है वह एक बिलकुल नया संशोधन है। श्रीमान् जी नियम १७७ के सब-क्लाज (३) (४) के प्रमुसार जो बाद का संशोधन १४ ककक पर है वह ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर हो जाता है।

श्री ग्रध्यक्ष—यह उचित है। ग्राप ग्रपने संशोधन के उसी भाग को पेश करें जो पहले हिस्से से संबंध रखता है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—श्रीमान् मेरा धह ग्राबिरी संशोधन जो धारा १२-सी (१) (बी) (ii) से संबद्ध है उसी को में पेश करता हूं यानी इसके बाद नया उपखंड (iii) "by wrong counting and recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर कहीं रिकार्डिंग ग्राफ वोट्स बैसट पेपर के जरिये से हो तब तो कहीं उसकी लिखा पढ़ी होती है तथा उसकी वैरीफिकेशन भी हो सकती है लेकिन जहां हाथ उठाकर वोटिंग होती है उसकी वैरीफिकेशन नहीं हो सकती

^{*} वस्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां नहीं तरीके पर वोट्स का काउन्टिग हुआ है, यह साबित नहीं हो सकता। मान लीजिये किमी आदमी के ७०० के खिलाफ ३ वोट्स ही आये हैं वह भी यह कह सकता है कि गलत तौर पर काउँ टिंग हुआ है। इस प्रकार से पैसे वाले गरीब आदमियों को परेशान कर सकते हैं क्यों कि यह साबित ही नहीं हो सकता कि जो गिनती हुई थी वह सही हुई थी या गलत। अतः इसने मुकदमेवाजी बहुत बढ़ जायगी और उससे गरीब आदमियों को परेशानी होगी। मुझे अफसोस है कि में इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—बहरहाल जो खराबी थी उसके लिये मैने ध्यान ग्राक्षित कराया है ग्रीर में यह जरूर चाहूंगा कि रूत्स बनाते वक्त यह ध्यान में रखा जाय ग्रीर में इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृंवर कष्ण वर्मा—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूँ —

खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12—C की उपधारा (2) (A) की पंक्ति १ में से ग्रंक '(1)' हटा कर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय ग्रीर भाग (B) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" ग्रपने स्थान से हटाकर उसके नीचे क्लाज (2) के रूप में कायम किये जायं।

माननीय प्रध्यक्ष महोदय, यह सब-क्लाज (२) में एक भाग ए रखा गया है ग्रौर उसके नीचे एक भाग बी रखा गया है। यह भाग जो ए हैं उसमें हम यह देखते हैं कि उपभाग (१) तुरन्त ही कायम किया गया है लेकिन भाग ए का उपभाग (२) कहीं पर नजर नहीं श्राता। इसलिये भाग ए के बाद (१) जो श्रंक रखा गया है वह कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ग़लत रखा हुआ है। वहां पर भाग (१) के माने यह होते हैं कि उप-भाग (२) भी कोई है लेकिन चूंकि भाग ए का कोई उपभाग (२) नहीं है इसलिये यह उपभाग (१) वहां पर रखना अच्छा नहीं मालूम होता है ग्रौर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से नहीं होना चाहिये। हम भाग (स) को पढ़ते हैं—

"(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing-"

श्रव इनडचूरिंग के नीचे भाग (ए) श्रौर (बी) रखें गये हैं। तो श्रव इनडचूरिंग ही दूसरे भाग को गवर्न करता है। or as a reward to जो भाग (बी) में है वह किससे गवर्न होगा। यह श्रसल में बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। यह इनडचूरिंग से गवर्न नहीं हो सकता है। श्रसल में इसका मतलव यह था कि "ग्रेटिफिकेशन ऐज रिवार्डेड टु" यह वहां से कनेक्टेंट होता है इसिलये मेंने यह रखा है। श्रोर जो शब्द हैं "एज ए रिवार्ड टु" यह श्रलग नीचे रख दिए जायं। इस तरह से कांस्ट्रकान बदल दिया जाय तो ठीक होगा। इसस यह कनेक्ट हो जायगा श्रनकनेक्टेंड नहीं रहेगा।

श्री मोहनलाल गौतम—में ग्रध्यक्ष महोदय, श्री कुंदर कृष्ण वर्मा का ध्यान पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट की धारा १२३ की श्रोर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि:

"The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:—

(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent, or by any other person with the connivance of a candidate or his agent,

[श्री मोहन लाल गीतम]

of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly crindirectly, of inducing—

- (a) a person to stand or not to stand as, or to with-draw from beir a candidate at an election; or
- (b) an elector to vote or refrain from voting at an election or as a reward to—
 - (1) a person for having so stood or not steed, or for having withdrawn his candidature; or
 - (ii) an elector for having voted or refrained from voting."

इस तरह से हमने वहां स्क्रु वैसे ही इसे रखने की कोशिश की है और जैना वह चाहते हैं वह उससे भिन्न हो जायगा। इसिलिये इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है कि वह गलत है या सही। मे इतना ही निवेदन करूंगा कि पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट से इसको हूबहू रख दिया गया है ताकि स्नासानी रहे। इसिलिये स्नाशा है कि श्री कुंवर कृष्ण जी स्रपने संशोधन को वापस ले लेगे।

श्री कुंबर कृष्ण वर्मा -- मं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—ग्रध्यक्ष महोदय, मं ग्रापकी श्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई घारा 12-८ की उपघारा (2) के खंड (A) (1) के भाग (b) के उपभाग (1) की पंक्ति १ में शब्द "from" के स्थान पर शब्द for रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ में शब्द "Candidatures" के स्थान पर शब्द "Candidature" रखा जाय।

में समझता हूं कि "from" शब्द ठीक नहीं बैठता है आगर वहां "for" कर दिया ज:य तो ठीक होगा।

श्री ग्रध्यक्ष—वह तो जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में है उसी के ग्रनुसार होगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्ता—"फ्राम" के स्थान पर "फार" होना चाहिये श्रौर "कंडीडेचर्स" के स्थान पर "कंडीडेचर" होना चाहिये क्योंकि ये दोनों ग्रेमेटिकली भी रांग है।

श्री मोठनलाल गौतम—यह तो ग्राप स्वयं ही कर देंगे ग्रापको ही इसका ग्रिकार है।

श्री ग्रध्यक्ष-क्या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में कैडीडेचर है?

श्री मोहनलाल गौतम—उसमें तो "कंडीडेचर" है।

श्री ग्रध्यक्ष — वह ठीक कर दिया जायगा। कोई बात नहीं है। उसे पेश करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। ंश्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—-ग्रध्यक्ष महोदय, मं श्रापकी श्राज्ञा के निम्नलिखित मंशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड १४ में प्रस्तावित घारा 12-C की उपधारा (2) के भाग (b) के प्रोवाडजो के भाग (ii) को निकाल दिया जाय

यह भाग (ii) इस प्रकार है:

"(ii) induces or attempts to induce a condidate or an elector to believe that he or any purion in whom he is interested will become or be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interest with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause."

ग्रध्यक्ष महोदय, यह मेक्शन म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या ग्रसेम्बिलयों के जितने एलेक्शंस है उनमें कहीं भी इस प्रकार की कोई धारा नहीं है ग्रौर में समझता हूं कि इसकी ग्राव्यकता नहीं है। यह धारा हमको हमारे समाज को बाबा ग्रादम के जमाने की ग्रोर ले जाती है। इस धारा को हम रख कर यह साबित कर रहे हैं कि हमारा समाज ग्रब भी १०वीं शताब्दी में हैं। इस बीसवीं शताब्दी में ग्रगर कोई महन्त गंडा दे देंगे या पंडित जी पूजापाठ कर देंगे या मौलवी साहब फतवा पढ़ देंगे तो में समझता हूं कि इससे एलेक्टोरेट को कोई खास बात नहीं होने जा रही है ग्रौर इसे यदि रख भी दिया जाय तो उससे जो सफल केंडीडेट होंगे उनको ग्रलग करने के लिये एक ग्रच्छा बहाना होगा। वह भी कहेंगे कि पंडित जी उसे श्राप दे देंगे लिहाजा वह उनके खिलाफ कोई पेटीशन न करे तो में समझता हूं कि इस प्रकार की चीज रखना ग्रधिक ग्रच्छा नहीं लगता । इसलिये में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इसे स्वीकार कर लें तो ग्रधिक ग्रच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रौर जगह चाहे हो या न हो लेकिन यहां पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के दूसरे भाग का जो प्रोवाइजो है उसका दूसरा भाग इस प्रकार है:

"(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will be come or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure."

तो जो ग्राइडिया उसमें है वही इस्में रख दिया गया है। ऐसा विचार है ग्रौर श्रच्छा होगा कि एलेक्शन पेटीशन्स का जो प्रोसीजर है उसको सब को एक ही लाइन्स पर रख दिया जाय ग्रौर एक ही तरह की व्यवस्था हो जाय इसलिये रख दिया है। मुझे ग्राशा है कि जोरावर सिंह जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा- वापस लता हूं।

(सदन कं अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी श्राज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई घारा 12-G की उपघारा (5° की पंक्ति ३ में से शब्द "Summary" निकाल दिया जाय।

^{*} वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जोरावर वर्मा

ग्राध्यक्ष महोदय, मूल धारा इस प्रकार से है:

"Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and dispose of an application under sub-section (1)."

म्रध्यक्ष महोदय, जैसा मैने म्रभी कहा कि पेटिशन्स के सम्बन्ध में सबूत मिलना बहुत मुश्किल है ग्रौर ग्रगर समरी शब्द भी यहां पर रख दे तो क्या उससे न्याय होगा, यह सभी माननीय सदस्य समझ सकते है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले ग्रंग्रेजी जमाने में जब सत्याग्रह चल रहे थे तो जेलों में ही समरी हिर्यारंग हुग्रा करती थी, बिना किसी बात को जाने हुये ग्रौर बिना फंक्ट्स के। उसमे कभी तीन महीने की सजा हो जाती थी, कभी ५ महीने की सजा हो जाती थी, कभी ५ महीने की सजा हो जाती थी। इसलिये में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्रगर समरी शब्द इसमें से निकाल दिया जाय तो ग्रिधिक ग्रच्छा होगा ताकि पेटीशन्स में लोगों को, जो बाते हों, जो फंक्ट्स हों, उनको सामने रखने का मौका मिले ग्रौर उपसे सच्चा न्याय हो सके। मुझे ग्राशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

*स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर) — इसमे जानबूझ कर समरी रक्खा गया है ताकि इसमे बहुत बड़े कानूनी दांव पेच न हो सके बिल्क श्रासानी से समरी ट्रायल करके उसका फैसला कर दिया जाय। यह तो श्रासानी के लिहाज में ही रखा गया है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में जो होता है उसका बड़ा लम्बा प्रोसीजर चलता है इसलिये उसमें बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये समरी लफ्ज का होना बहुत ही जाकरी है इस वास्ते में समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी इसको वापस ले लेंगे।

*श्री जोरावर वर्मा—-ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सभा सिवव जी ने जो बताया कि इसमें समरी शब्द इन्टेंसली रक्खा गया है ग्रौर इसे निकाल देने से कुछ मामला बढ़ जायगा, मेरी समझ में ऐसा नहीं है क्योंकि समरी हिर्योरंग में न्याय नहीं होता है, यह सभी लोग जानते हैं फिर भी ग्रगर उनका ऐसा विचार है तो में जानता हूं कि ग्रगर इसे वापस न लूं तो यह पास होगा ही नहीं। इसलिये मेरे लिये यही श्रच्छा है कि में इसको वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थिगत हुन्ना श्रौर २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की श्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः श्रारम्भ हुई।)

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मं ग्रापकी ग्राज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G की ग्रन्तिम पंक्ति में शब्द 'State' के बाद 'fullstop' लगा दिया जाय ग्रौर उसके बाद के शब्द ''or in any specified area thereof'' निकाल दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी के साथ साथ मेरा यह दूसरा संशोधन है कि ग्रगर ग्रापकी ग्राज्ञा हो तो साथ—साथ पेश कर दूं—

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह 12-G इस प्रकार है —

"12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A,11-B, subsection (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Presidents of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including panches of Nyaya Panchyats in the whole state or in any specified area thereof".

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G के कृत्त में 'ू"stop' हटा कर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"ir extraordinary circumstances only."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इसमें स्टेट जो शब्द है उसके बाद फुलस्टाप नगा दिया जाय और "in any case specified area there of " निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोटय, में समझता हूं कि कोई भी जो ला हो वह पूरे प्रान्त, पूरे सुबे के निये एक सां हो। लेकिन इसे ऐक्ट से जो व्यवस्था रखी जा रही है कि किसी भी एरिया, किसी जगह पर जब सरकार की इच्छा हो तो उस एरिया की पंचायतों को डिज्ञाल्व कर दिया जाय। मालूम पड़ता है कि कुछ सरकार को इसमें पता नहीं क्या गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में जो यह क्लाज है वह बड़ा भ्रसंगत सा लगता है क्योंकि किसी एरिया का क्या मतलब है। कहीं कोई पार्टी हार गई या किमी विशेष व्यक्ति जो प्रभावशाली हो उसका ग्रेसर हो गया तब उस एरिया का इलेक्शन कैन्सिल कर दिया जाय तो उसका ग्रसर दूसरी जगह पर पड़ेगा। तो मेरा दूसरा संशोधन इसकी जगह पर यह है कि अगर माननीय मंत्री जी को संशोधन रखना ही हैं नो "or in any specified area there of" निकाल दिया जाय श्रीर उसके स्थान पर "ir extraorninary circumstances only."जोड़ दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, प्रान्त में ग्रगर कोई ऐसी परिस्थिति ग्रा जाये कि पंचायतों को डिजाल्व करने की ग्राव-क्यकता हो तो ऐसी परिस्थिति में तो यह कहा जा सकता है कि पंचायतें डिजाल्व कर देना किसी हद तक ठीक है, लेकिन बिना किसी स्पेशल परिस्थिति के जब जी चाहे सरकार का तब पंचायतों को डिजाल्व कर दिया जाय, यह में समझता हूं राज्य के लिये उचित नहीं जंचता। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे हो संशोधन हं ग्रगर वे उनको उचित समझें तो इनको मान लें, इससे यह क्लाज सार्थक हो जाता है।

ंश्री मोहनलाल गैतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने पेश किये है उनमें एक तो यह है कि or in any specified area there of निकाल दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि पूरे स्टेट में अगर ६५ हजार गांव सभायें है तो उसमें से एक भी कम न हों और अगर एक भी कम हो तो वह इस कानून के खिलाफ हो जायगा। यह इसमें इसलिये रखा गया है कि अगर किसी जिले में परिस्थित ऐनी हो, जैसे पहाड़ के जिलों की अवस्था अलग है, अगर वहां न रखना चाहें तो ऐसा कर सके। इसलिये इस दृष्टिकोण से कानून बनाने में इस तरह की कंटिजेन्सी को बग्रैर देखे हुये कानून अधूरा रह जायगा।

जनका जो दूसरा संशोधन है कि "in extraordinary circumstances only." जोड़ दिया जाय, मं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट ग्रगर जनरल इलेक्शन्स आर्डर करती है श्रौर कहती है कि जो मियाद थी ५ साल की उससे एहले दोबारा इलेक्शन हों तो एक्सट्रा-आर्डिनरी सर्क स्टांसेज तो होने ही चाहिये। अब एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्क स्टांसेज रख देने से इसकी कोई डेफिनीशन तो है नहीं इसलिये उसकी जज भी गवर्नमेट ही होगी कि एक्सट्राआर्डिनरी सर्क स्टांसेज हैं या नहीं। इसलिये इसके रखने का कोई जिस्टिफिकेशन तो हैं नहीं। लिहाजा यह दोनों संशोधन मुझे स्वीकार नहीं हैं लेकिन जहां तक उनकी स्पिरिट का ताल्लुक हं उससे मुझे कोई खास मतभेद नहीं है।

^{*}वस्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला श्राजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदक जो दोनों संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने उपस्थित किये हैं उनका में समयंन करने के लिये खड़ा हुशा हूं। श्रव तक की चुनाव की पद्धित जो हमारे प्रदेश ही में नहीं सारे भारतवर्ष में श्रीर दुनिया में है वह यही है कि किसी भी पंचायत का, किसी भी संगठन का चुनाव इतने दिनों पर हो। लेकिन श्रफसोस है कि पिछले पंचायत राज ऐक्ट में इस तरह की धारा रहते हुये भी कि चार साल के बाद, तीन साल के बाद पंचायतों का चुनाव होग वह धारा निकाल कर श्रीर निकाल कर ही नहीं बल्कि संशोधन करके ऐसी धारा रखी जा रही है, जिससे में समझता हूं कि जनता की भावना का समर्थन नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि सरकार के दिल में जब श्रस्थिरता श्रती है, उसके पैर के नीचे से जमीन निकलने लगती है तभी इस तरह की बाते सोचने के लिये वह उतारू हो जाया करती है श्रीर यह धारा ही यह साबित करती है कि सरकार का दिल इस तरह का है कि वह तैयार नहीं है एक साल, दो साल, पांच साल या जितना समय सरकार निर्धारित करे उसमें गांव पंचायत के पंच, सरपंच श्रीर सदस्य स्थिर होकर श्रपने गांव के बारे में कुछ निर्माण कार्य उंचा या नीचा, जो भी करना चाहते हों

श्री मोहन लाल गौतम—प्वाइन्ट श्राफ ग्रार्डर सर, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को यह ग्रंदाज नहीं है कि इस वक्त टाइप ग्राफ पंचायत का डिस्कशन या कितने दिनों तक पंचायतों को बढ़ाते चले जायं, यह सवाल पेश नहीं है। जो अमेंडमेंट है उसी पर यदि माननीय सदस्य बोलें तो ठीक है।

श्री राम सन्दर पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि जब चाहे तब सरकार चुनाव करा सकती हैं, इसके माने यह हो जाते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति जिस पंचायत या जिले के लिये यह होगी कि सारी पंचायतें या कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो ठीक काम नहीं करती हैं तो उनका चुनाव हो सकता है। में समझता हूं कि यही मतलब माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का था और यही हमारे कहने का मतलब है।

श्री मोहन लाल गौतम--उनका संशोधन यह नहीं है, जो आप कह रहे हैं।

श्री रास सुन्दर पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि जो में कह रहा या वह ठीक है श्रीर सरकार को इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिये कि जब चाहे तब चुनाव करायें। इस घारा के संशोधन के माने यह हो जायेंगे कि कोई भी पंचायत या सरपंच श्रपनी जनता की निगाह में ग्रगर ईमानदारी से काम करता होगा तब भी उसका कार्यकाल खतरे में ही रहेगा। में समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विपरीत बात है श्रीर सरकार के दिल में यह भावना भी लोकतंत्र के खिलाफ इसलिये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार चुनाव कराया करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रव तक इस सदन में इस पंचायत राज विघेयक के संबंध में जो भाषण हुये हैं श्रीर संशोधित विधेयक स्वीकार किया जा रहा है उसके देखने से पता चलता है कि सरकार ऐसे लोगों के इशारे पर काम करेगी जो पंचायत राज के सिद्धांत के विपरीत होंगे श्रीर में समझता हूं कि श्रागे चलकर ऐसे लोग जो पंचायतों में किसी तरह से श्राजायेंगे श्रीर ईमानदार होंगे इस प्रकार के बार-बार के चुनाव के कारण परेशान होंगे श्रीर पंचायतों के महत्व र्ण काम में शामिल नहीं हो सकोंगे। में समझता हूं कि इस धारा को जो माननीय मंत्री जी ने रखी है, निकाल दिया जाय श्रीर एक निश्चित समय निश्चित कर दिया जाय कि इतने दिनों के बाद चुनाव होगा। इन शब्दों के साथ में श्री जोरावर वर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह इसिलये रखा गया है कि हमारे प्रांत में जैसे पहाड़ी देश हैं या पंचायत जहां पहले बन गई हैं उनकी

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिज्ञाल्ब करने के लिये इस क्लाज का ग्लना आवश्यक है। इसलिये मेने दूसरे क्लाज को रखा था " a extracted run a roumstances" में समझता हूं कि प्रमृ प्राइते परिस्थित है. अगर जाड़ों में चुनाव हो रहा है तो में समझता हूं कि इस क्लाज की पूर्त हो मकती हे और अगर ऐमा नहीं है और जब सरकार चाहे और जब मंत्री जी की इच्छा हो नब गांव पंचायत डिज ल्व कर दी जाय। में समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट और डेमोकेसी का यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा और उसके कोई अर्थ नहीं रह जायेगे। आलिर इसकी रचना क्यों की जा रही है, पंचायते क्यों बनाई जा रही हे या फिर डेमोकेसी क्या है। में ममझता हूं कि जैसे नवाबी चाल-ढाल या राजा की इच्छा है, जब चाहा तब हुक्म जारी कर दिया इस प्रकार की प्रवृत्ति इस क्लाज में प्रगट होती हैं, जो डेमोकेसी और पंचायत राज के विरुद्ध पड़ गी है इमलिये में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर्लगा कि अगर वह इस क्लाज को स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा।

"श्री मोहनलाल गौनस—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं पुराने नवाब श्रौर राजाश्रों की तरह निरंकु होता ग्रगर यह माननीय सदन मेरे ऊपर ग्रंकु हा न रख पाता। लेकिन चूंकि मदन का बहुत कुछ श्रंकु हो हैं श्रौर उसी के मातहत मुझे काम करना होता है श्रौर इस सदन को ग्रिधकार है कि जब तक चाहे मुझे रहने दे श्रौर जब चाहे न रहने दे, इसिलये मेरे पास इतना श्रधकार नहीं है जितना कि जोवावर वर्मा जी ने मुझे देने की कोशिश की है। श्रौर जितने श्रधकार मुझे मिले है वह एक तरह में सदन के ग्रधकार हैं, क्योंकि मेरे कामों पर सदन को छानबीन करने का पूरा श्रधकार हैं। इसिलये उस निरंकु शता को न समझ कर श्रौर मेरे श्रधिकारों को सदन के समझ कर श्रौर यह र मझ कर कि इस सदन को कानून बदलने का भी ग्रधकार है, इस चोज पर गौर होना चाहिये। तो यह संशोधन इस प्रकार का है कि जब सारो स्टेट में चुनाव करने हैं, ग्रगर सब में न करना चाहे तो इसका ग्रधिकार वह नहीं देना चाहते। दूसरे माननीय सदस्य तो किसी ग्रौर हो चीज पर बोल गये। वह नहीं समझे कि माननीय जोरावर वर्मा क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि सरकार जब चाहे चुनाव कर दे, लेकिन ग्रगर उसके किसी हिस्से में कराना चाहे तो नहीं कर सकते। वह मुझे पूरा श्रधिकार देना चाहते हैं चुनाव करने का, लेकिन ग्रगर किसी एक दो जगह को छोड़ कर जुनाव कराना चाहूं तो यह ग्रधकार मुझे देने के लिये तैयार नहीं हे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—क्या ग्राप संशोधन को वापस लेना चाहते हैं। श्री जोरावर वर्मा—जी हां, वापस लेता हूं। (सदन की श्रनुमित से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रनाप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय. यह जो क्लाज

इसको कई बार पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि आ़ि यह संशोधन श्राया क्यों? इस क्लाज के द्वारा हमारी राज्य सरकार यह अधिकार चाहती है कि प्रधानों, उप-प्रधानों, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव जब चाहें करा सकें। चुनाव तो आ़ि होगा ही, ऐसी व्यवस्था है और उनका कार्य-काल भी निश्चित कर दिया गया है। लेकिन इस बात को समझने में जरा दिक्कत महसूस होती है कि जब भी चाहे फिर से चुनाव सरकार करा सकती है। ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के जो पेनल में होंगे उनका चुन.व गांव सभायें करेंगी, फिर कुछ ऐसे प्राविजंस हमारे इस विधेयक में रखें गये हैं कि जब भी चाहें, जब भी श्रविश्वास हो तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों को, न्याय पंचायतों के मेम्बरों को, प्रधानों और उपप्रधानों को निकाला जा सकता है। शायद में गलत कह गया। न्याय पंचायतों के बारे में तो प्राविजन नहीं है।

[ं] बक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेजप्रताप हिं]

मै चाहता तो यह था कि ा इसे स्वीकार कर सकता। गांव पंचायतों भ्रीर न्याय पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों ग्रौर उपप्रधानों को ग्राम सभायें ही रखती है, जिन्होंने गांव पंचायतो का निर्माण किया है, न्याय पंचायतों के लिये चुनाव किये हैं। उनके निकालने का श्रिधकार ग्राम सभाग्रो को ही होना चाहिये। यदि वे ग्रविश्वास के काबिल होती हे, उनका विश्वासपात्र नहीं रह जाता है तो गांव सभा को पुरा ग्रधिकार होना चाहिये कि वह ग्रपनी व्यवस्था स्वयं कर सके ग्रोर उनको हटा सके । ऐसे प्राविजंस रखे जाय उनके रिम्वल के, उनके पुनः चुनाव के, तब तो एक चीज समझ में त्राती है कि जो ग्राम पंचायते हैं श्रीर जिसे ग्राम राज्य की बात को लेकर यह विधेयक माननीय सदन ने पास किया है श्रीर जो शक्ति ग्राम भाइयों को टी है, उन्हीं में वह शक्ति भी रखते कि जब भी न्याय पंचायत उनका विश्वास खो देती तो वह उसको हटा सकते। राज्य सरकार भ्राखिर किस कारण से इस अधिकार को लेना चाहती है, यह हो सकता था कि जब चाहे ग्रामीण लोग या गांव सभाये उनको निकाल दे, ऐसी व्यवस्था उसमे रखी जाती या प्रेस्काइ दे एथारिटी को ही ऐसी शक्ति दी जाती कि वह किन्ही कारणोवश अगर चाहे तो उनको रिमृव कर सकनी तो वह भी चाज मानी जा सकती थी कि इनमें यह ऐब है, इसलिये उनको प्रेन्काइ है श्रथारिटी हटा देती है। लेकिन श्रमतौर से एक ऐसी जनरल शक्ति लेने का यह क्लाज कुछ समझ में नही श्राता कि इसकी उपयोगिता क्या है। मैं तो पूछना चाहुंगा माननीय मंत्री जी से कि भ्राखिर कौन सी कल्पना है इसके बारे में, इस पर वह प्रकाश डाले। इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले।

न्याय पंचायतों के पंचों के बारे में रिमुवल का जो मूल ग्रिधिनियम में क्लाज था वह हटाया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है। मेरी समेझ मे नहीं ब्राया कि ब्राखिर रिम्वल तो होना ही चाहिये, श्रगर कोई पंच ठीक काम नहीं करता है तो उसको हटाने का श्रिधिकार देना हो चाहिये, चाहे वह प्रेस्काइ इंड एथारिटी हो या गांव सभा हो जिन्होंने भी उनको चुना हो मूल रूप में तो उन्हों को उसका अधिकार होना चाहिये। मगर उनके अधिकार की बात हों श्राती नहीं। उनके ग्रधिकार की बात होती ग्रौर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी द्वारा भी उनके लिये प्राविजन होता तो मुझे कोई ऐसी भ्रापित न होती। वह प्राविजन तो मुझे दिखाई नहीं दया ग्रीर यह प्राविजन सामने ग्रा जाता है कि स्टेंट गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती है ग्राखिर वह कौन सी काल्पनिक एक्स्ट्राम्नाडिनरी सर्कम्स्टांसेज है या हो सकती है, यह कुछ मेरी समझ मे नहीं ब्राता और यदि ऐसी कोई सर्कम्स्टांसेज ब्राती भी है जिसकी कि ब्राज कल्पना नहीं की जा सकती तो ग्राखिर यह माननीय सदन है, इसके सामने वह चीज लायी जा सकती है। राज्य ऐसे मौके पर कोई न कोई विघेयक लाकर उनका सामना करता है। में समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस पर प्रकाश डालेगे कि श्राखिर इसकी उपयोगिता क्या है और ऐसे रिमुवल ग्रादि के लिये गांव सभाग्रों को सारी वाले क्लाज ब्राखिर इस विधेयक में क्यों नहीं रखे गये है जिसके द्वारा गांव सभाग्रों को पूरा ग्रधिकार प्राप्त होता कि जिसको उन्होंने चुना है, ग्रगर वह काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनको वह हटा वे अथवा प्रेस्काइब्ड एथारिटी ही कुछ कारणों को देखते हुये गम्भीर ब्रारोपों पर उनको निकाल सके। ऐसी चीजें इसमें नहीं है। गांव पंचायतों के लिये प्रधान श्रौर उप प्रधान के लिये श्रौर श्राखिर गांव सभा रं ही ग्राम पंचायत को भी बनायेंगी, उनके मेम्बरों को चुनेंगी और न्याय पंचायत के लोगों को भी चुनेंगी श्रांशिक रूप में लेकिन उनको इन्हें हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। यह बात कुछ समझ में नहीं आती। फिर ग्राम पंचायते ही तो गांव सभाओं का काम करेंगी, उनके प्रधान की हटाने का जब ग्रधिकार ग्रापने उनकी दे दिया है तो फिर इस व्यवस्था को भ्रपने हाथ में क्यों लेना चाहते है। मुझे इसकी उपयोगिता नहीं समझ में ग्राती है। इसलिये में माननीय स्वशासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर प्रकाश डालेगे।

श्री महन मोहन हम ख्या मानी संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया है में उसका ममर्थन करने के निये खड़ा हुन्ना हूं, हम उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं समझ पाये कि ज-चाहे प्रान्नीय मरकार पंचायनों का. किसी विधान में नहीं लिखा हुन्ना है कि स्रसेम्बलियों का भी चुनाव जब मरकार चाहे तो करवा दे। में ने भी विधान पढ़ रखा है। एक साल का एक्सटेंशन हो मकना है जब कि कोई लड़ाई हो और डिफेस के लिये ऐसा करना जहरी हो। स्रसेम्बली का चुनाव उन दिनों न हो मकना हो नो उस वक्त एक साल की मियाद बढ़ सकनी है। यह तो न मान मकता है। लेकिन जब चाहे, सभी चुनाव हुन्ना उनके स्नादमी नहीं छांटे गये स्नौर कह दिया कि फलां जगह फिर चुनाव होगा। यह ऐसा स्रधिकार क्यों लिया जा रहा है मेरी समझ में नहीं द्याया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली कोई भी पार्टी इस तरह का विचार ही नहीं कर मकती है। एक तरफ तो जब हमने कहा कि गीन मान के लिये स्नाप बुलाइये, स्नाग उनका टर्म नहीं वड़ाना चाहिये, उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन साल बहुत कम होते हैं। एक माल उमके जमने में लगता है, एक साल नये चुनाव की तेयारी में लगता है। एक ही माल बचता है काम करने के लिये। स्नाज प्रान्नीय सरकार स्रपने हाथ में यह स्रधिकार लेना चाहतें है कि स्नार उनकी मर्जी के मुनाविक चुनाव नहीं हुन्ना है तो दोबारा चुनाव करवा मकते है। इसमें साफ लिखा है:—

"Note ithstanding anything contained in sections 11-A 11-B, sub-section 13 of lotion 12 and section 45 the Side Government may at any time order a govern I election of Profile is of Gaon Sabbas and members of Gaon Panchagais including Purches of Nyaya Parchayats in the whole State or in any specified area thereof."

हम माननीय मंत्री जी ने जानना चाहते थे कि वह हमको वतलाते कि इसका कारण क्या है। वह दो चार मिसालें ही हन को दिखला देते नो हमे तसल्ली हो जाती। लेकिन यह हमारी बदिकस्मती है कि हम लोगों को पहले बोलना पड़ता है और माननीय मंत्री जी बाद को बोलते हैं। इसिलये में प्रार्थना करूंगा कि हमारे और भो साथी बोलने वाले हैं, इसके पहले कि वह बोले माननीय मंत्री जी कारण स्पष्ट कर दें। नहीं तो फिर यही पूछेंगे कि आखिर यह जो प्रावजन रखा जा रहा है यह क्यों रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी कारणों को नहीं बतलाते उस समय तक इतना बड़ा अधिकार कि पंचों का नये सिरे से चुनाव करवा दें, न्याय पंचायत का नये सिरे से चुनाव करवा दें, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अधिकार देना ठीफ नहीं है। इसिलये में इसका समर्थन करता हूं कि इसे निकाल दिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने विरोधी दल के माननीय सदस्यों की स्पीचेज सुनीं। उन्होंने यह पूछा कि सरकार ने इसको क्यों रखा है। मं उनको बतलाता हुं कि सरकार ने इसको क्यों रखा। सरकार ने इसलिये रखा है कि किसी गांव पंचायत में तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं ग्राता, में उनको समझ। रहा हूं जिन हिस्सों में करण्यान है, बदद्यानती है, नाना प्रकार की शिकायतें ग्राती है, इसके लिये सरकार ग्रपने हाथ में ग्रंकुश रखती है, प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के हाथ में पूरी शक्ति नहीं देती कि वह जो चाहे करे। गर्वनमेंट ने खुद अपने हाथ में ब्रेक रखा है। अगर किसी गांव में झगड़ा फिसाद हो, इस म्राइमी एक तरफ हो जाएं श्रौर पचास भ्राइमी दूसरी तरफ हो ज यं इसलिये हमने गांव ममाज को वह अधिकार नहीं दिया है बल्कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। प्रेस्काइब्ड ब्रायारिटी को भी इसीलिये नहीं रखा है। नाना प्रकार की शिकायतें ब्राती है। रिश्वत का खुला बाजार है। इस बिल के दौरान में माननीय सदस्यों ने कहा उधर से कि जब प्रेस्काइंब्ड श्रयारिटी नामिनेट करेगी तो बड़ी रिक्वर्ते होंगी। तो रिक्वत चलेगी। इन तमाम ऐबों को बचाने के लिये सरकार ने अपने हाथ में यह ताकत रक्खी है और पंचायतों के हाथ में उसको यह चीज बहुत सुन्दर है और में समझता हूं कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय मेरी बातों को समझ गये होंगे ग्रौर उम्मीद है कि श्रव श्री तेज प्रताप सिंह ग्रपना संशोधन वापस ले लॅगे।

"श्री ग्रवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं माननीय तेज प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुन्ना हूं। श्रीमान माननीय मंत्री बुद्धिमान व्यक्ति है और उनका सम्बन्ध लोकल बाडीज से बहुत दिनों से है। में समझना हूं कि इस वक्त केबिनेट में वही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस विषय में सबसे श्रिषक ज्ञान हो सकता है और मं यह दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन श्रीमन, मुझे श्राञ्चर्य तो तब होता जब माननीय शिवनारायण जी श्रागे श्रग्रसर हुए उनका फर्ज पूरा करने के लिये, इसी तरफ श्राञ्चर्य नहीं हुन्ना बिल्क उस तरफ भी श्राञ्चर्य होता है। श्रगर वह कोई उन्नतिशील पद पर जाना चाहते है तब तो दूसरी बात है परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा में ध्यानपूर्वक सुनता रहा श्रीर श्राशा करता था कि इससे कुछ निकलेगा, लेकिन सारांश कुछ भी नहीं निकला श्रीर एक निस्सार सी बात रही श्रीर श्रंघकार ही बढ़ा।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध हँ मैं यह ग्राशा करता हूं कि ऐसे ग्रधिकार सरकार क्यों ग्रपने हाथों में रखना चाहती है। जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा यह ग्रधिक उत्तम होता कि वह अपने ग्राप पर ही ग्रंकुश रखते ग्रौर सरकार के लिये प्रयत्न न करते। श्रीमान्, विधान सभा में ही नहीं, हर जगह, संविधान में भी प्रेसीडेंट ग्रौर गवर्नर को बहुत से ग्रधिकार दिये जाते हैं, लेकिन हर देश में ऐसी चीजों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई एमरजेंसी हो या कोई नेशनल डिजास्टर फोरसी किया जाता हो। श्रीमान्, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है में यह समझ रहा हूं कि संभवतः वह कभी इसका प्रयोग भी न करे ग्रौर प्रयोग करने की नौबत भी ग्राये तो वह भी कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में। श्रीमन्, मं ग्रापकी ग्राशा से यह पढ़ना चाहता हूं—

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A,11-B sub-section (3 of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of (President or Vice-President) Pradhan or Up-Fradhar, then that Office shall also be filled as far as may be in the manner laid cour in and under section 11-A or section 11-B as the case may be."

में यह समझता हूं कि "इन दो होल स्टेट" की नौबत नहीं आयेगी और अगर माननीय मंत्री जी ने इसको न रक्खा होता तो इस पक्ष से इतना विरोध न होता। जहां तक "एनी टाइम" का सम्बन्ध है इसमें भी आपित पैदा होती है। ऐट एनी टाइम के रखने से तो हर तीसरे महीने गांव पंचायतें बदलती रहेगी और वह हालत हो जायगी जैसे बहुत सी रियासतों में मैनेजर हर तीसरे महीने बदल दिये जाते थे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसमें कुछ संशोधन कर देंगे।

*श्री गेंदा मिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं बड़ी इन्तजार में था कि माननीय स्वशासन मंत्री माननीय तेज प्रताप सिंह जी के उत्तर में कुछ कहेंगे और फिर उनके उत्तर को में समझने की कोशिश करता, लेकिन माननीय तेज प्रताप सिंह जी और मदन मोहन जी उपाध्याय के निवेदन के बाद माननीय स्वशासन मंत्री ने कुछ कहने की मेहरबानी नहीं की श्रीर न उस तरफ के माननीय सदस्यों ने ही कुछ इस पर रोशनी डालने की कोशिश की। श्रगर माननीय शिवनारायण जी ने कुछ कहा तो वह ऐसा कहा कि जिसको बहुत ऊंचे लोग ही समझ सकते हैं। मेरी समझ में वह बात नहीं श्रायी। इसलिये में उनसे माफी चाहूंगा। मैं सरकार की इस तरह की

पार के र विरोधों ह अप म समझता ह कि इस विरेवक में सरकार ने प्रक्त जाह पर ऐसी रावर ने रवी ह कि उसके उनने से स्वर करता चित्र की सार अगर सरकार को सवर नहीं ह तो फिर इस बेस्बरी का स्वर्ण कर होगा वृत्तिया से जो बेसवर होते ह उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होता ह यो तो म इस वक्त हजार कह नेकिन सरकार सानने का कंपार नहीं मुले ऐसा लगता हि स्माननीय मर्जा की इस विधेयक से प्री तरह से उनकार नहीं का है। किर भी सरकार चारती ह कि यह विधेयक पान हो जार क्योंकि इस वियेयक के पान हो जार क्योंकि इस वियेयक के पान को जार क्योंकि इस वियेयक के पान को जार क्योंकि इस वियेयक के पान की जार क्योंकि इस वियेयक के पान को पान सरकार अपने की सजबूत होने की उम्मीव करती ह जो माननीय तेज प्रनाप निष्ट जी ने कहा कार माननीय सदन मोहन जी सक्त उसका कोई उत्तर न देकर केवल यह कह देना कि इस नरह की कानूनी अग्र यकता ह यह कुछ तर्कमणत वात नहीं मान्म होती ह।

मं माननीय स्वशासन मत्री जी श्रार दूसरे माननीय सदस्यों की सेवा में यह करना चाहना ह कि इस विधेयक में उर्ड जगह उन्होंने इस तरह के श्रियंकार लिये हें कि जिसकों पाने के बाद उनको सबर करना चाहिये। पहली नान तो यह ह कि जा न्याय पंचायन बनेगी उसके बारे में हम फनला कर चुके ह कि वह न्याय पंचायन चने हुई नहीं होगी। वहा पर गांव सभा के जिर्य में गांव पंचाय के चांच किया नामगा जिसमें में पांच श्रादमी न्याय पंचायन में जायेगे। इस उमूल को हम मान चके ह कि उसमें में पांच श्रादमी नियाय पंचायन में जायेगे। इस उमूल को हम मान चके ह कि उसमें में पांच श्रादमी की नामजदगी श्रेम्काइंड श्रथारिटी द्वारा होगी जो न्याय पंचायन बना दी जायगी। तो हम उनको चुना हुग्रा नहीं कह सकते। वह नामजद ह। तो गांव पंचायत का एक श्रग जो बडा महत्वपूर्ण श्रग ह वह श्रग चुना हुग्रा नहीं होगा। यह निश्चित हो चुका ह। इस विधेयक के जिर्य से हम इस बात को पास कर चुके ह। श्रव दसरी तरह हम गांव सभा की तरफ देखे। गांव सभा के निर्माण का श्रग हम दो दिन पहले इस विधेयक में पास कर चुके ह। खड १३ (८) को ग्रगर देखा जाय जिम पर काफी बहम हुयी उसको देखने के बाद यह मालूम होगा कि उसमें भी एक बडी पांवर सरकार ले रही ह। खड १३ (८) में यह लिखा हुश्रा है कि —

The water sub-section (2) is shall be called upon to close the full run perconnection (2) is shall be called upon to close the remaining number of members but it is again to be considered to the shall be law to the function of such authority as may be precibed to the relationshall be cated to the seats so remaining to the contrainer from an object to nembers of the Gao. Sabradically numbers of the contrainer shall be deemed on the been adly elected.

नामिनेट किये जायगे स्रारं वह डचूली एलेक्टेड ममझे जायां स्रोरं म तो इसकी कल्पना नहीं करता था कि कोई गांव नी पूरी सभा नहीं बनायेगा। लेकिन माननीय स्वशासन मत्री स्रोरं कुछ दूसरे सदस्यों ने यहा पर कुछ कहा जिससे स्पष्ट हो गया कि उनकी कल्पना यह भी हैं कि सूबे में कुछ ऐसे गांव भी हो सकते ह जहां कि पूरा का पूरा गांव पंचायत बनाने के लिये तैयार नहीं होगा तो प्रेस्काइटड स्थारिटी बना देगी। स्व माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के स्रनुसार स्रभी केवल ६-५ गांव सभाये ऐसी मिली है। परन्तु इस विधेयक के पास होने के बाद मैंकड़ों ऐसे गांव सकते हैं। फिर १४ के उपखंड १२ (अ) में रिक्त स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था है स्रोरं उसमें भी प्रेस्काइटड स्थारिटी को ही स्रधिकार है। प्रधान स्रोरं उप-प्रधान के सुनाव में तो ११-ए स्रोरं ११-बी के मुताबिक काम होगा।

अरि दिल्लाका को कर में का में भारतीय गेंदा हि जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्ने रिट्राफ्ट करने की कोशिश की है और आगे अमेंडमेंट आया है अगर कुछ कहना है तो अपना दशोधन दे दें।

श्री दिश प्रिट्—मुझे बड़ी खुशी है कि उस पर कुछ विचार होगा। फिर ग्राग कर १० खंड को देखें तो वहां भी कैजुगल वैकेंसी के लिये इसी प्रकार की गुंजाइश है कि उसे प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी ही करें। मेरे कहने की मंशा माननीय मंत्री जी की सेवा के यह है कि लगभग हर जगह नहीं तो बहुत श्रिधक जगह ऐसी पावर प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी के लिये उस विधेयक में सुरक्षित रखी गयी है।

फिर तो चुनावों ने गड़बड़ियां होंगी उनका भी फैसला करने का सारा प्रक्रिया प्रेस्काइव्ड ग्रथारिटी को हो है। इसमें यह डिवार कर दिया गया है कि कोई चुनाइ का भामला, खंड १४ के १२-आई के अनुसार दीवानी अदालत में जाय। कि इतने ब्रधिक ब्रधिकार लेने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी से मं सब करने के दरख्वास्त करता हूं श्रौर जैसा मैंने पहले ही कहा, यह में जानता हूं कि वह इस विधेय के बहुत से भागों से पूर्णतया सहमत नहीं हैं लेकिन चूंकि सरकार ऐसा चाहती है तो वह भी कर रहे हैं। तो मंतो यहां तक कहने के लिये मजबूर हूं कि चारें तरफ से जितने भी अधिकार सरकार लें अक्षनी है, उसके लेने में उसने 📸 कीताही नहीं की । भरकार ने इस विधेयक की बनाते समय इस बात की पूर क. मार्च रखे है कि कोई ग्राधकार प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी से बच न जावे। जहां देखता हं वहीं प्रेस्क्राइब्ड ग्रथारिटी सब कुछ कर सकती है, ग्रौर दीवानी ग्रदालत में भी उनका फैसला क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस विधेष में रखी गई है। में समझता हूं कि यह जनता के हित में बात नहीं है। में इन विधेयक के बनानेवालों के दिमाग की तारीफ़ जरूर करता हूं कि उन्होंने ब्राम जनता से अधिकारों को खुब छीना और कम से कम हमारे सामने ऐसा विधेयक भ्राज तक नहीं श्राया इस एसेम्बली की सदस्यता के जीवन में, इसके कहने में कोई संकोच नहीं जिसमें इतनी मजबूती के साथ सरकारी अधिकारियों को लादने की चेष्टा की गये हो। मं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरवानी करके यह जो खंड हैं उने माननीय मंत्री जी पास न करायें ग्रौर उनको जो ग्रस्तियारात ग्रौर जगहों पर मिले है उन्हीं को काफी समझें। इसमें तो यह भी है, जैसा कि श्रौर माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, सरकार जिस वक्त चाहे उस उक्त प्रदेश में जनरल एलेक्शन करा दे। सरकार किसी समय श्रगर ऐसा समझती है कि गांव पंचायत के जनरत इलेक्श होने चाहिये भ्रौर ऐसी परिस्थिति किसी समय भ्रगर सामने भ्राती है तो सरकार मौजूद है यह विधान सभा मौजूद है, ये दोनों रहेंगे श्रौर उनको रहना है, में समझता हूं ग्रौर माननीय स्वशासन मंत्री जी की जिन्दगी में विश्वास करता हूं कि वे भी जिन्दा रहेंगे श्रौर में भी यहां मौजूद हूंगा, हम सब भी वहां होंगे, प्रगर उस समय श्राप इस दफा को लेकर श्रायेंगे तो उस स्थित का ज्ञान हमको भी होगा। श्राज उस समय कहेंगे कि सारे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव करा[ं]दिया जाय तो मं समझता हं कि उस समय ज्यादा बहस की जरूरत न होगी। ग्रोर जिस तरह माननीय मंत्री जी हम से यह पास करा लेते हैं कि ३ बरस के चुनाव के बाद ६ वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव होगा उसी तरह से यह विधान सभा फिर भी कर सकती है। जैसा कि मानुनीय मंत्री जी इस समय कह रहे हैं उस वक्त ऐसा ही कह कर चुनाव करा सकते हैं। माननीय स्वशासन मंत्री की नाराजगी की बात रहेती तो समझ में म्रा सकता था, वैसे उनकी नाराजगी से भी कुछ बन बिगड़ सकता है लेकिन में इतना ही समझता हूं कि वे पूरी तरह से प्रपने मतको चलाने में ग्रसमर्थ

है क्योंकि उनका झपना मन नो १३ झाइसियों की कमेटी से व्यक्त है गा आ लेकिन वा गो को बान नय की गर्या थी उनका उनटा उनके ऊपर लादा ज रहा है और वे उस बोझे को दोने के नियो सजबूर है । न दोयों तो जाये वहां। सानर्त य स्वाहासन संजी जी चाहने ही रहेगे उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, यह बड़ी बेइंसाफी की बात हो रही है।

माननीय स्टब्सामन संबी जीके ऊपर ह बोझा लादा जायगर होंग रायग्रही की प्रोप में जादा जायगा। कुछ गुम प्रहों की छोग से तदा जाता तो हमें हवें होना ग्रीप उसके लक्षण भी गुम होने लेकिन परप्रह उत्पर तह बोडा लादर नहीं ग्रीर वे उसके लिये मुजबूर हो जायेगे। में इससे बिन्जुल नहीं प्रशा है कि वंद्रीयनों में पार्टीबन्दी होगी ग्रीर उसमें कांग्रेस का बहुबन हो । न है से देखा के इस्ता न मनाता हूं कि मच्ची कांग्रेस का बहुमन हूं जाय तो उससे देश का कल्यान हो लगाना नेकिन वह कांग्रेस है कहां? कांग्रेस की सरकार है और वह उन पाण्यहों की है जो क्लेंद्र के नाम में मशहूर हूं। जो जनरल इलेंद्र न हैंपा वह इन पापप्रहों के इंगान पर होगा स्रोर वह इकारा श्रव्छा नहीं है। म बहुने ही शाग्रह पूर्वक श्रीरे जितनी भी हमारे अन्दर ताकन श्रीर वृद्धि है उन सब की खर्च करके कह देना चाहता हू कि कम में कम इम खंड का पास कराने की नक्षत्रीक माननीय स्वशासन नंत्री जी न उठाये। कंबिनेट को भी मनाये कहीं-कही तो ग्रपनी राय के मं प्रिवेल करे उनके ऊपर भी। सब की राय उनके ऊपर प्रिवेच हो जानी हे और यह देख कर उनके जयर हमें बड़ी दया श्राती है। पुरानी याद ग्राती है कि हमारे श्रागे चलने वाली की यह दुर्गति हो रही है कि अपनी राय मना ही नहीं पाने। एक भी राय उनकी नहीं मानी जाती ह। में कहता हूं कि एक राय भी तो हमारे द्वागे चलने वाले की मान ली जाय। यह बड़ा भारी अप्रजातांत्रिक है। श्रौर राज्यों के भी पंचत्यत कानून 🗔 मेने पढ़ाहै लेकिन जहां तक मेने इस किताब को पढ़ा है उसमें कहीं भी ऐपा नहीं है कि मेरे सूबे के मुकाबिले में इस तरह का केई सेक्सर मध्य भारत, विहार, उई।सा या बम्बई में नहीं बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हसको कहीं भी नहीं मिला कि किसी राज्य में इस तरह का कोई कानून दनाया गया है।

न्याय पंचायतों के बारे में भी मं क्या कहूं, उसको चर्चा छोड़ देता हूं क्योंकि उमको चर्चा यहां बहुत हो चुकी है। तो जब और दाही इस तरह का कानून नहीं बनाया गया है तो फिर सिर्फ यूँ० पी० मेही इस तरह का कातून क्यों बनावे ? उत्तर प्रदेश अपने को प्रगतिशील कहता है तो अगर उत्तर प्रदेश में इनी प्रकार का प्रतिरामी कानून बना ग्रोर वह भी माननाय स्वशासन मंत्री जी के मंत्रित्व मे बना तो मुझे कर्ट होगा ग्रौर जो हमारे साथ बैठे हुये है उन सभी को कप्ट होगा ग्रपने दिल की बात कहता हूं कि ग्रगर माननीय स्वजासन मंत्री जी ग्रपने मित्री की नहीं मना पाये तब यह पास तो हो ही जायगा, लेकिन में सोचता हूं कि माननीर मंत्रः जी को अपने मित्रों को मनाना चाहिये। अगर सारे सुबे भर मे जनरल एलेश्झन है: तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी यही देगे उपाध्यक्षे महोदय, कि भाई शायद इमकी जरूरत भी न पड़े, क्यों घदड़ाने हो ? अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो में कहता हुं कि काहे को वक्त खराब किया जाय, फिर जिस बदत जरूरत पड़ेगी उस बदत विचार कर लिया जायगा श्रौर मेरा विश्वास है कि उस समय भी साननीय स्दशासर मंत्री जी श्रौर हम लोग विचार करने की हैसियत मे होंगे कि इस सूदे का भार बुरा सोच सके । मं इतना ही कह कर दरस्वास्त करता हूं कि माननीय सदन ग्रीर माननीय मंत्री जी से कि वे कम से कम इस खंड को न पास कराये।

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मँ माननीय तेज प्रताप त्र है जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुन्ना हूं। मैंने जैसा पहले कहा था कि

^{*}बक्ता ने भाषण का पुनर्नीक्षण नहीं किया।

[जी जोरावर वर्मा]

यह घारा बड़ी कम्पलीकेटेड है ऋौर यदि मैं यह कहूं कि माननीय मंत्री जी यह धारा जोड़ कर इस पंचायत राज रूपी नवजात शिशु के गले में फांसी लटक रहे हैं तो कोई गलत न होगा। अगर पंचायत राज के गले में यह फांसी लड़क दी गयी तो आज जो एलेक्शन हो गया उसको कल ही माननीय मंत्री जी एक ही आईर हे खतम कर देंगे। तो में समझता हूं कि इस तरह का बन्धन, श्रौर इस तरह की फांमी पंचायत राज के गले में लटका दी जा रही है। ग्रगर इस फांसी को निकाल दिया जाय तो में समझता हूं कि पंचायत राज के साथ में न्याय होगा, डमोकेसी के साथ न्याय होगा। इसमें यह भी नहीं बतलाया गया है कि कब माननीय मंत्री जी की कृपा दिए सारे प्रान्त ा उसके किसी एक भाग के ऊपर होगी जब वे ग्राम पंचायतों को डिजान्व कर देंगे। पतानहीं कि उनको क्या शक हो गया है। कुछ मेरी समझ में नहीं स्राता कि कुछ सिहासन थोड़ा बहुत डोलने लगा है या कुछ ऐसे ग्रासार नजर ग्राने लगे ह जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उनके पहले के माननीय मंत्र खेर जी द्वारा इस ऐक्ट में बहुत कुछ सुधार की कोशिश की गयी है फिर क्यों यह फांसी लटकायी जा रही है जिससे उस ऐक्ट के ग्रस्तित्व को ग्रौर जो उसकी स्थित है उसको खतरे में डाल रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, श्रगर इस एक्ट में _{कम} में कम इतना लिखा होता कि ऐसा हो सकता है "रीजंस टुबी स्पेसिफाइड" कम से कम कुछ रोजन दिया गया होता, कुछ कारण बतलाया गया होता कि इस परिस्थित में इतने समय में हम ऐसा कर सकते है तो सम्भवतः यह धारा जस्टीफाइड होती। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे माननीय मंत्री बी इसपर जिदकर रहे हैं सिर्फ इसलिये कि उनके साथ मेजारिटी है, बहुमत है और उसने वह इसको पास करा सकते हैं इसके अलावा मं समझता हूं कि इसमें कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे तो बहुर म्राच्छा होगा। मने इसीलिये जो संशोधन थे वह वाया मीडिया था। माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः उनको समझा नहीं। मैने कहा था कि ग्रन्त में फुलस्टाप लगाया जाय और उसके बाद इन एक्स्ट्राम्प्राडिनरी सरकमस्टासंज तो म्रधिक म्रद्धा होगा। पता नहीं कि उन्होंने किस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया श्रौर उसका श्रथं उलटा लगाया। में समझता हूं कि इस घारा को इस ऐक्ट में से निकाल ने तो ग्रधिक ग्रच्छा होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला ग्राजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब तक के भाषणों को सुनने के बाद में यह नहीं समझ सका कि इस खंड के इस पंचायत राज्य श्रमेंडिंग बिल में रखे जाने की क्या जरूरत थी। कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति ब्राज हमारे देश में या हमारे प्रदेश में है जिससे इस कानून में इस चीज को रखने की जरूरत पड़ी कि किसी समय भी पांच वर्ष के ग्रन्दर सरकार ग्रगर चाहे तो पूरे प्रदेश में या उसके किसी भाग में चुनाव करा सकती है। सोचने से यह मालूम होता है कि इस सरकार की सारी चेष्टा एक तरफ को जा रही है कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था श्रौर उसकी समर्थक मौजूदा सरकार इन दोनों को स्थायी बनाया जाय। किसी ग्रांधी तूफान से बचने की तमाम रक्षापंक्तियां यह सरकार ग्रपने चारों ग्रोर खड़ा कर रही है अप्रौर उसी दशा में यह भी एक प्रयत्न है। इस विघेयक में ने कम्पलसरी लेबर को निकाल कर जो थोड़ा ग्रच्छा काम किया गया था उसको न्याय पंचायतों के सदस्यों की नामजदगी का प्रस्ताव रख कर तथा उसी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में या प्रदेश के किसी जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में ग्रगर सरकार समझती है कि एक स्थान की पंचायतें उनके विरोधियों के हाथों में है या वह सरकार के गलत कदमों का या गलत आदेशों का जो दिये जा रहे हैं, पालन नहीं करती है, तो उनका नया चुनाव कराने की व्यवस्था करके उसको खत्म किया जा रहा है।

जेन का का का कि के आ जान मुर्ज के उन्हें के नाम का ना उन्हों ना विक्षाम किया जाता है जो जिला न्याकान के नेकों के किया क्लेक्ट्रकों ही होती है ग्रेश जिला क्लेक्टर ती में क्यांचा इ. कि छुड़े कि इसके चारहे हा प्रधावन किसे से एक हिटलर ने द्निया में जा किया इंगाए विकास साधी है सेनिया छह गरकार ४१ लिटिल हिटलसी सम्मोता है में कारणाई प्रोपाइण एका ने उन्छोटी हिटलरों को जितने अधिकार दिने हैं ना परे भी जिनमें प्रधिरात देना चाहती है प्राप्त दिये जा रही है. म समझता ह न उसन प्रदेशन हम सामार के सियोर्स दानक होगा उन्हों की रिपोर्टी पर मुन कि के उन्हें में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह सरकार प्रदेश के जिसी भी भा से सुनाद प्रकार पा किसार त्यारी है। मैं समझता है कि इस धारा के म्बोरार के कारे के बार रमाम वह प्रास्थिति तस्य जो इस ऐक्ट में पहले से छ इन्हें हुइ नक खन्स है जायंगे क्रीर इस विल के बनाने वाले महाशयों ने बहुत सोच एक्क् ों के प्रकृत प्रच्छी ताह से विद्यार काके तमाम उन चीजो को जो रिष्ठमें ऐक्ट में पर्यार्थ। रिजर्मे कि जनता की प्रपत्त मनीभावताओं को प्रकट करने - एक किन्त र होते-हेटे घटके ने सना को प्राप्त करने का ग्रवमर मिलताथा उनको जन्म करने पर नहान, को मेट्नाइन करने ग्राप करतीय एक करने की कोशिश की गई । एक हाय में बीज नेकर दूसरे हाथ में लेने की प्रेटा दिखलाई पड़ती है। सम्पूर्ण विधेयक में . खेरों की का खंडों की केमी नहीं हे लेकिन उस तरह की बलामें ज जोड़ कर जो बीजे एक जगह दी जानी हे बन दूसरी जगह छीने ही जानी ह यही प्रक्रिया पूरे विधेयक मे दिखाई पड़ती है । मं ग्राप के द्वारों मेरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रगर मरकार ने यह तय कर लिया है कि इन बिन को उसी रूप में पाम करना है जिस रूप में यह सरकार हारा बनाया गया है तब नो मारी बहम बेकार है लेकिन ब्रागर जिरोधी लोग कोई ब्रच्छा मुझाब देते है उसकी मानने की उदारना अग्ने मरकार में हो तो उन की बातों की श्रोर भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये त्रोर गोर करना चाहिये और खानजा मंत्री महोदय को जो किसी जमाने मे नमाजयादी विचार के रहे हु, उन के मंत्रिका न में ऐना विधेणक देश हो ग्राँग उस में ऐसी प्रति-म्याबादी या रीएक्सनरी धाराये जोड़ी जायं ग्रीर ऐसा प्रदम्प दिया जाय, यह देखकर मुझे प्रकमीन होना है। अन्त में म एक चेनावनी देना चाहना हं कि गर ऐसे कानून बनते रहेगे और इम नरर की धाराये ग्रौर कानून ग्रगर जनना के ऊपर लादे जायेगे तो जनतो को मौजूदा शासन में जो थोड़े बहुर अधिकार मिले ह या कुछ ब्राजादी मिली ह उमका भी ब्रपहरण हो जायगा ग्रगर इस तरह में बेकडोर से ग्राधिकार छीने जायेगे इन इच्दों के माथ में मंत्री महोदय से ग्रापिल करूंगा कि वह ठंडे दिल से गौर करे ग्रौर इम धारा को निकालने की कोशिश करे

श्री रामना स्मिन (जिला बस्ती)—म प्रस्ताव करता हूं कि प्रकृत उपस्थित किया जाय।

भी प्रशास अभी श्री बालेन्द्रशाह को समय देने के बाद, में प्रश्न उपस्थित करने की बात को देखुंगा।

अन्य के स्वापित के स्

^अ वरता ने भाषण का पूनर्वोक्षण नहीं किया ।

[महाराज कमार बालेन्द्रशाह]

ग्रापके द्वारा माननीय मंत्री जी को ग्रौर बहुमत दल के सदस्यों को बताना चाहता ह कि इस थारा के द्वारा जो मंत्री जी प्रपने हाथ में ग्रिधिकार रखना चाहते हैं कि जब कभी वह चाहे बिना किसी कारण दिये हुये दोबारा चुनाव करा सकते है। यह एक बहुत ही कन्ट्रोडिक्टरे थारा है। यह किसी विशेष सिद्धांत के हिसाब से ही नहीं बल्कि यह तो जनतंत्र राज्य के सिद्धान के ही खिलाफ जाती है और पब्लिट गवर्नमेट के खिलाफ पड़ती है, इस में ग्राटोक्रेसी की बुग्राने में ज्यादा न कहकर श्राप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस श्रोर श्राकांवत कराना चाहता हूं कि इस तरह से वह बड़ी एनामलस चीज पैदा करने जा रहेहै । कोई इल्लीगल तो नहीं किन्त ग्राञ्चर्य की बात है कि जब प्रधान की ग्रवधि का प्रश्न इस सदन में ग्राता है ग्रीर जब कि विरोधी दल के सदस्य यह कहते हैं कि संभवतः चुनाव अनुचित हों, सम्भवतः गलत व्यक्ति मुने जायं ग्रौर संभवतः केवल सरकार के हित के लिये यह उचित हो कि उनकी ग्रविष ४ मान के बजाय ३ साल रख दी जाय, उस समय मंत्री महोदय ताव में ग्राते हैं ग्रौर बड़े जोश से कहने है कि बारम्बार चुनाव करने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्री महोदय यह भी कहते है कि जिन व्यक्तियों को एक बार चुन लिया जाय उनको कांस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिये समय दिया उन्होंने ग्रौर उनके साथियों ने यह भी कहा कि यदि तीन वर्ष रख दिये जाते है तो पहला वर्ष चुनाव के हलचल मे ही बीत जायग श्रौर तीसरा वर्ष भी उसी प्रकार बीतेगा। परिणाम यह होगा कि केवल बीच का ही एक वर्ष काम करने के लिये रहेगा। तर्क में जोर है यह समय इस पर विचार करने के लिये नहीं है। इसका निर्णय हो चका है किन इसका उल्लेख यहां में इसलिये कर रहा हूं कि यह एक ग्रजीब सी बात है कि जब उसी कारण को सामने रखते हुये और उन्ही संभावनात्रों को ध्यान में रखते हुये यहां से सुझाव हुन्ना कि प्रविष पांच साल के बजाय तीन साल कर दी जाय तो उसका मंत्री महोदय विरोध करते है ग्रौर ग्राज जबिक प्रश्न यह है कि जब एक बार चुनाव हो गया हो मै श्रापका ध्यान इस तरफ भी श्राक धन करूंगा कि किन-किन हुंडी कैप्स में यह चुनाव होगा और कितना इंडेपेंडेट चु ,ाव हम इसको मान सकते है। यह एक प्रश्न है तो जैसा कि मै पहले कह रहा था कि यह एक बड़ी कंट्राडिक्टरी पोजीशन है कि मंत्री महोदय उनकी श्रवधि लम्बी भी चाहते है किन्तु साथ ही उनकी विधि एक से स्रोवरनाइट समाप्त करने का स्रधिकार भी श्रपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहां तक उचित और कहां तक आवश्यक अधिकार वह अपने हाथ में ले रहे हैं जैसे कि हमारे पहले एक वक्ता ने बतलाया ।

दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय के कुछ न बोलने के कारण हमको इस संबंध में भी जैमें कि ग्रौर धाराग्रों के संबंध में करना पड़ा, केवल मात्र ग्रनुदान पर बहस करनी पड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कारण से मेंने ग्रापसे बोलने की ग्राज्ञा मांगी ग्रौर में ग्राज्ञा करता हूं कि विशेषकर माननीय गेदा सिंह जी की तरफ से जो तर्क मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये उनको न दोहरा कर केवल उनकी ग्रोर मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकांषत करके ग्रौर यह प्रश्न जो मेंने उठाया कि यह कंट्रोडिक्ट्री पोजीशन जो मंत्री महोदय कियेट कर रहे हैं, में मानता हूं कि इसमें कोई इल्लीगिलटी नहीं होगी किन्तु इससे यह ग्रवश्य प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय को जहां तक जनता में ग्रविश्वास है वह तो स्पष्ट ही है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेम्काइच्ड एथारिटी का नाम बारम्बार रक्खा है उसका यहां कि के न करके—किन्तु यह भी स्पष्ट हो जायगा कि मंत्री महोदय को ग्रधिक—जैसा कि मेरे साथी ग्रवधेश प्रताप मिह जो ने कहा, में भी उनसे सहमत हूं कि पंचायत राज के संबंध में ग्रनुभव है किन्तु फिर भी ग्रनुभव कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वह पंचायतराज विभाग के मंत्री होने के बावजूद, गुस्ताखी माफ हो यहां, ग्रौर ग्रौर जगह बारम्बार घोषणा करने के बावजूद कि वह यह देखना चाहते हैं कि पंचायत राज ग्रौर डिस्ट्रिक्ट बोडं ग्रौर ग्रौर जगहों में डिसेट्रलाइजेशन फूले ग्रौर फले, में नहीं समझ पाता ग्रौर में न मान्ंगा कि इस प्रकार मंत्री महोदय कोई सही कदम उठा रहे हैं।

यदि मंत्री महोदय यह चाहते है और यदि उनकी यह हार्विक इच्छा है कि इस स्रोवर सेंट्रलाइजेशन के युग में जब पूरा देश इस सेंट्रलाइजेशन की पीड़ा से रो रहा है, इस संबंध में एक

बार नहीं, कई बार यहां इस सदन में चर्चा हो चुकी भ्रोर बारम्बार यही मांग हुई कि राज शासन डीमेंटुलाइ - इ किया जाय। इस मांग के जवाब में माननीय स्वकासन मंत्री ग्रार माननीय मुख्य मंत्री ने इन्हीं शब्दों में उत्तर दिया कि डीसेंट्रलाइजेशन तो बहुत हद तक इस सूबे में प्रचित्त है। में पूछता हूं कि क्या यही एक मिसाल है जिसे रखा है? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जीमेट्रलाइजेशन पहले ही से स्थापित है। यदि यही डीसेंट्रलाइजेशन है तो में ममझना हुं कि यह उमका एक परवर्टड इन्टरप्रेटेशन होगा। यदि यह डीसेंट्रलाइजेशन है तो में ममझती हूं ि इसमें बेहतर तो वही पहले का मेट्नाइजेशन था। क्योंकि इस डीसेंट्रनाइजेशन का नतीजी यह होगा कि वह सेन्ट्रलाइजेंशन तो स्रभी लखनऊ में सेंट्रलाइज है बहु सेन्ट्रलाइजेशन और उसकी जो बुराइयां है वह श्रव उसी प्रकार से जिले-जिले में पहुंचाई जा रहीं है। यह डीसेंट्रलाइजेंशन किसी भी सूरत से नहीं होगा और में मंत्री महोदय का ध्यान इसी भ्रोर स्राक्टेंट करता रहूंगा भ्रीर कर रहा हूं कि डीसेंट्रलाइजेशन को वे उमी रूप से कार्यान्वित करें। उपाध्यक्ष महोदयं, इस संबंध में ग्रापकी ग्राज्ञा से उत्तर प्रदेश की जो बहुत सी पम्फलेट छपी है उनमें से एक पैम्फलेट जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है "सरवे आफ दी विकर्ग ग्राफ दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट" की चन्द लाइनें पढ़ना चाहता हूं। उसमे लिखा है पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में "A sec a' experiment pregnant with great ressibilities was under taken for the formation or Pancheyals with Twey to the decentralisation of functions of day to day administration." बहुत सही कहा।

मं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक से इसकी पूर्ति हो रही है ? क्या यह पंचायत राज संशोधन विधेयक में किसी प्रकार से भी जो मंत्री महोदय ने इन्टरप्रिटेशन किया डीसेन्ट्रलाइजेशन ग्राफ डे टु डे एडिमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ? में पूछना चाहूंगा कि क्या यही डीसेंट्रलाइजेशन का तरीका है, चुनाव करके उसको रद्द कर दिया जाय ? चुने हुये व्यक्तियों से कहा जाय कि तुम ४ साल के लिये चुने जाते हो ग्रौर किसी कारण किसी व्यक्ति की शक्ल से

.,,,,,,,,,, €t ... भहोदय, इस संबंध में मै ग्रापका ध्यान इस ग्रोर ग्राक्षित करूंगा कि जब क्वालिफिकेशंस को बदल दिया गया है यानी पहले ३० वर्ष की श्रायु श्रौर शिक्षित होना श्रावश्यक क्वालिफिकेशन रखी गयी थी। ग्रब मै उस निर्णय को उस समय चैलेंज करना श्रावश्यक नहीं समझता, यह मेरा फर्ज नहीं है। जब उचित समय था उसको चैलेंज कर चुका हूं श्रौर श्रब जनता उवित समय पर चैलेंज करेगी स्रौर हमें विदवास है कि मंत्री महोदय ने हालांकि हमारी स्रावाज ठुकराई परन्तु हमें यह भी विश्वास है कि जनता की भ्रावाज नहीं ठुकरायेंगे। किन्तु इस संबंध में म जो कह रहा था वह यह कि इस विघेयक की और जितनी घाराओं को हम पहले देख चुके है उनका एक सारांश निकलता है और वह यह कि शुरू से आखिर तक एक बात यह कि इलेक्शन के सिद्धांत को बारम्बार ठुकराया जा रहा है। हां, में जानता हूं कि इसका उत्तर यह दिया जायगा कि गांव सभा इलेक्शन द्वारा गांव पंचायत को छाट रही है और यही कहेंगे संभवतः मंत्री महोदय कि इलेक्शन्स की प्रणाली यहां स्थापित की गई है, किन्तु मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के एक कम्पेरेटिवली ग्रनइम्पार्टें ट इलेक्शन के ग्रधिकार जनता को देकर ग्रौर जहां कि ग्रधिक महत्व है-हालांकि हमें ग्रभी तक कोई ऐसा कारण नहीं दिखा कि क्यों वहां भी इलेक्शन न हो पाया किन्तु उसका निर्णय हो चुका, तो वहां इलेक्शन्स को न स्वीकार करके श्रौर केवल इलेक्शन्स को ही ग्रस्वीकार नहीं किया गया बल्कि साथ ही साथ वैसी ग्रवस्था में ग्रौर वैसे स्थान में पूर्ण रूप से नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रख कर और उस नियुक्ति को ग्रपने हाथ में रखने के बावजूद भी ग्रागे ग्राकर एक ऐसा क्लाज रखना कि उस नियुक्ति को भी वे रह कर दें, इससे यह स्पष्ट है कि हरएक कदम पर एक किस्म का सेफगार्ड रखा गया है ताकि यदि किसी कारण पहली फोर्टरेस से कुछ गलती हो जाय भार एनिमी आगे बढ़ जायं तो सेकेंड लाइन ब्राफ डिफेंस उसके पीछे ढकेले। में ग्रागे बताऊंगा, ग्रभी तो हम कुल १२ वीं

महाराजकुमार बालेन्डुशाह]

धारा तक पहुंचे हैं। बारम्बार यह कोशिश प्रत्यक्ष है और यदि मंत्री महोदा यह को कि इस पंचायत राज मंशोधन विशेषक से ब्रव उत्तर प्रदेश से वंगापन राज का दिसीय है। ता के ब्रव उत्तर प्रदेश की पंचायत मुचाङ रूप से चलेगी, ब्रव जनता इस पंचायती को सहयोग देती हो के ब्रव्ह हैं कि मंत्री महोदय भूल करेंगे।

इम संबंध में इतना और में कहना टाइंगा हातांकि हमारे संकी महोदय के पंचायत राज के बारे में बहुत अनुभव हैं, ने मानता हूं कि संकी महोदय ने अनुभव हात करने के लिये बहुत लम्बा चौड़ा दौरा किया है जिन्नु यथावांकित ही वे दौरा कर सके के नाम महम्मता है कि मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर हहेंग को पूरे ५२ जिलों का है. कि न का पूरे इमिलिये यह भी संभव है कि जिस अनुभव से संकी सहोदय ने इस विधेयक को हमारे सामने का वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं हो सम्मता या संशव है कि जिन जिन्हों की पिन्होंने को मंत्री महोदय और उनके विभाग ने ध्यान से एख कर इस पियेयक को लाग्ट कराया है जा उन परिस्थितियों के लिये यह विधेयक, में नहीं जा तो कि सही है या नहीं, हो सकता है कि प्रकृत हो ।

तालाब की गंद करेगी ही इसलिये पहले से ही उसकी गंदा कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोद्य में मान सकता हूं कि बहुत जगह पंचायत राज ग्रभी भी ग्रच्छी तरह से जाम नहीं कर रहा है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं, हालांकि में मानना नहीं चाटता कि जो यहां पर मंत्री महोदय ने एक बार हमको कहा था कि न्यान पंचायन बहुत श्रच्छी तरह में काम करती हे श्रीर उनके लगभग ६०, ६५ प्रतिशत फैसले अपहेल्ड रहें, मेने उस बार उनके लिये ताली बजाई थी, श्रौर में चाहता हूं कि यह सही निकले किन्तु में साथ ही साथ यह भी कहंगा कि संभवतः ये ग्रांकड़े पूर्ण रूप से सही न हों। किन्तु में इसने यह बहस निकालना चाहता हूं कि यदि ये ख्रांकड़े गलत भी हों फिर भी जो कुछ मंत्री महोदय ने पिछले दिनों किया श्रीर जो श्रभी तक इन् विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले तक पंचायत राज्य के निर्माण के लिये किया उसके लिये वे अवस्यमेव धन्यवाद और बदाई के पात्र है। मैं उनमे यही कहंगा कि इस एनोमलस ग्रोर कंट्राडिक्टरी विधेयक को जिसका परिणाम यह होगा हि पंचायत राज मे जनता का अविश्वास फैलेगा, वह एक बार फिर जहां-जहां आवश्यक हो उसको संशो वित करके जनता के बीच इस रूप में भेजे। मंत्री महोदय की ग्रधिकार है, बहमत उनके साथ है, इस सदन में अवश्य है और भविष्य में कहां तक बहुमत उनके साथ रहेगा में इस संबंध में कोई भविष्यव णी नहीं कर सकता हूं। मंत्री महौदय स्वयं ही ग्रौर उन कारनामे इसमे भविष्यवाणी करेगे। हमारा कर्तव्य यह है कि च्रयने विचारानुसार हो सकता है कि हमारे विचार गलत हों लेकिन में चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमें बतलाये और यह न कहें क्योंकि इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई या कोई तर्क नहीं दिया राया, इ लिये में उत्तर देना ग्रनावश्यक समझता हूं, यह कोई उत्तर नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण दिपय पर पंचायत राज्य की स्थापना पर, यह उत्तर ग्रापने बारम्बार ग्रीर में समझता हूं कि भविष्य में ग्रीर धाराओं के ऊपर, संभव है क्योंकि दुर्भाग्यवश तर्फ बहुत सीमित है। विरोधी दल को जब ऐमे विधेयक का सामना करना पड़ता है तो उसके सामने ग्रीर क्या विचार हों। जो चीज बुरी है उसको बुरी बतलाये हमारा कांच्य है कि उसको हम भाषा में बदलकर भले ही बतला दे लेकिन बुरेपन की बात तो हम कहेगे ही। इसका परिणाम भ्रवश्य यह होगा कि यहां पर जो बहस होती है वह काफी होती है और एक प्रकार से दुहराना होगा। मगर उसा प्रश्रं यह नहीं है कि दुहराने के कारण मंत्री महोदय उसे महत्वपूर्ण न समझें। इसका यह प्रर्थ है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम गुस्ताखी करते हैं कि मंत्री महोदय का और सदन का समय नेते श्रापकी श्राज्ञा लेकर बारम्बार दुहराने की प्रार्थना करते है श्रीर श्राज्ञा मांगते हे।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैने कहा-विधेयक पारित हो सकता है और हो जायगा किन्तु मैं चाहता था क्योंकि मुझे भी हालांकि मंत्री महोदय के बराबर कभी भी मैं इतना अनुभव प्राप्त नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे भी इस डिलेंट्रलाइजेशन के विषय पर बहुत ज्यासा दिलचल्पी है। हमारे प्रदेश में सुचाल रूप से राज्य का शासन करने के दो ही। तरीके हैं। एक तो यह कि डिलेंट्रलाइजेशन किया जाय और दूसरा वह होगा कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाय। यह मंत्री सहोदय के हाथ में है। मुख्य मंत्री से अधिक उनके हाथ यें यह प्रिकार है कि इस प्रदेश में डिलेंट्रलाइजेशन की तींच मही रूप में पड़े। यह नहीं कि बाहर से दिखाने के तिये गांव पंचायत, टाउन एि याज म्युनि निपल तथा डिल्ट्रिक्ट बोर्ड्स की स्थापना कर दी जाय किन्तु उन्हें कंगाल बना दें और दूसरी तरफ लायविलिशीज बढ़ा दें और प्रिकार देने के प्रश्न में साफ रखें।

ग्रध्यक्ष महोदय मैंने बहुत समय लिया। श्रद इतना ही कहकर श्रपना भाषण समाप्त करता हूं। मुले आजा है कि मंत्री महोदय हमारे विकारों पर ध्यान देंगे बाहे हसारे विधार तर्त हात ही क्यों न हों लेकिन वह इस बात को श्रदश्य ध्यान में रखेंगे कि हमारा एक मत से दिचार है कि यह दिधेयक और चाहे जो हुछ हो लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उससे दिलकुल नहीं हो रहा है।

श्री राम तत्वन तिश्र—उपाध्यक्ष पहोदय, मेरा विवादान्त का प्रस्ताव रखा आय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह कि प्रस्तुत संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

्त्रप्रन उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर विमनलिखित सतानुसार स्वीकृत हमा—

यक्ष में-६२ विपक्ष में-१३ ो

श्री तेज प्रताप सिंह--नाननीय उपाध्यक्ष महोन्य मैंनै प्रार्थना की थी माननीय स्वज्ञासन मंत्री जी से कि कुछ इसका उत्तर देते, मुमक्तित है कि मेरी समझ में ब्रा जाय,लेकिन मेरा दुर्भीत्य, उन्होंने यह ज इरत नहीं समझी। मैं इसकी चेव्हाओं या कुचेव्हाओं की श्रीर संकेश नहीं करना चाहता, यह ठीक भी नहीं है श्रीर न इससे लाभ हो सकता है। लेकिन इतना जरूरे कहुंगा कि इस क्लाज के द्वारा अविश्वास की भावना जो प्रामों और गांव सभाओं के प्रति झलकती है वह निश्चित है और इससे भला नहीं हो सकता। भविष्य की ब्राशंकाओं की कल्पना करना मुमेकिन है दुरदेशी हो, लिकन में तो इसे खतरनाक समझता है जब कि हमारे में वह शक्ति है कि हम कभी भी उसका मुकाविला कर संते हैं। इस माननीय हदन को वह शक्ति प्राप्त है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो हम उसका मुकाबजा कर सकते है और उसकी संभालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हालत में पहले से ही किन्हीं आइंकाओं के ब्राधार पर, कुछ सोच करके, हम ऐसी धारायें यहां रखें, यह मेरी समझ से ठीक नहीं है । बाक्तिवान होना तो ठोक हो है, होना ही चाहिये। लेकिन दूसरों को अशक्त करके, निर्जीय करके शक्ति का ग्रर्जन करें इसमें कोई लाभ मुझे प्रतीत नहीं होता। ग्रागे जिन्हें हमें साथ लेना है, पंच वर्षीय योजना द्वारा देश का उत्थान करने के लिये जिनके सहयोग की हमें आदश्यकता है उनक: हम ग्रपने साथ न लेना चाहें ग्रौर उन पर विश्वास न करें तो यह कोई उच्छी चीज नहीं है । देश के उत्थान के लिये बहुत आवश्यक है कि हम जनता का सहयोग प्राप्त करें, उनमें वह जीवन डालें, उनमें वह इ से टिव दें कि वह हमारे साथ चल करके उन योजनात्रों को सफल बनावें। यदि हम उन्हें निर्जीव करते हैं तो उनका सहयोग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्राखिर शिवतवान ही तो हमें सहयोग दे सकते हैं, भावना के साथ हमारे साथ चल सकते हैं ग्रीर तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन में समझता हूं कि इस प्रकार उनको यह श्रंतिस शक्ति न देना कि वह अपने पंचों को या उन लोगों को हटा सकें, यह ठीक नहीं है।

दूसरे आगे क्या परिस्थितियां होंगी उनका भी समय से बहुत पहले इलाज सोच रखना में समझता हूं कि यह खुद मर्ज को पैदा कर देने वाला है। इससे बहुत दड़ी संभावना

श्री नेज प्रताय सिंह]

है कि हम में वह कमजोरियां पैदा हों कि हम उन परिस्थितियों को सम्हाल न सके, उघर हमारा मंकेन करना ही ठीए नहीं है। आखिर पेसिमिस्ट होना, निराशावादी होना हमारे देश के लिये लाभदायक नहीं है श्रीर में तो समझता हूं कि इस घारा द्वारा जो निराशावादिता की झलक दिखलाई पड़ती है उसे हमें हटाना चाहिये। हमारे देश ने पहले ऐसे कार्य किये हैं जिन पर हमें गर्व हो सकता है, होना भी चाहिये। ग्राज नैतिक स्तर हमारा चाहे जितना गिरा हो, हमारी स्थिति चित्र के विषय में च हे जितनी खराब हो लेकिन ग्राशावादी होना कि हम ागे भी बड़े कार्य कर सकते है, यह तो एक ग्रावश्यक चीज है। हमें ग्राशावादी होना कि चाहिये ग्रीर में मानीय मंत्री जी से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि वह कुछ इसके बारे में निवेदन करे, कुछ बतलाने की कुणा करे। हमारे माननीय साथियों ने जो इसमें हिस्सा लिया ग्रीर जो ग्रपनी भावनाये प्रगट की उसके लिये में उन्हें घन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी ने जो कुछ कहा उसके लिये जे उन्हें वन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टीबन्दी ग्रीर करण्यान को दूर करना हमारा मबका ही फर्ज है लेकिन हम तो कोई ऐसा कदम उठाये जिससे वह चीजे दूर हों तब तो ठीक है लेकिन किसी चोज का गलत ग्रर्थ समझ लेना यह ता ठीक रहीं है। इतं ग्रीवार कर ले।

*श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोवय, माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो मेरी तारीफ की उसके लिये में उनकी बधाई देता हूं। लेकिन ग्रगर मेंने किसी समय यह कहा हो कि कोई नयी बात नहीं जिसका मुझे उत्तर देने की ग्रावश्यकता हो तो में जानना चाहता हं कि कौन सा ऐसा प्वाइन्ट रह गया है जिसका मेने उत्तर नहीं दिया, उसका उत्तर देने का में प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरी दिक्कत यह हो रही है कि गेंदा सिंह जी के दिमाग में सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट नहीं है। उनके दिमाग में बहुत सा बोझ है। वह सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट पर नहीं बोलते बल्क ग्रयने इमोशंस का एक्सप्रेशन उसमे करने लगते है। उन्हें ग्रपने किसी मित्र की याद ग्राती है या क्या वह उसका इक्स रेशा कर रहे है, ग्रगर उन सब का में उत्तर देने लगूं तो इस सदन की शान के खिलाफ कार्य करूंगा। इसलिये में उन तमाम बातो का उत्तर नहीं देना चाहता।

झारखंडे राय जी को यह डर है कि कहीं ५१ छोटे हिटलर न पैदा कर दें। उस वक्त किसी ने कहा छोटे हिटलर नहीं तो छोट स्टैलिन ही पैदा फर दे। परन्तु कोई श्रावाज मेरे कान में पड़ी कि ऐसा न करना नहीं तो श्रनथं हो जायगा। जिस डिमोक्रेसी को यहां जगह दी गयी है ग्रे.र जिस प्रकार यहां डिमोक्रेसी चल रही है संसार साक्षी है कि यहां की डिमोक्रेसी एक सुन्दर डिमोक्रेसी है। हिटलर श्रोर स्टैलिन को जगह देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है श्रोर न में बाहता हूं कि यहां हिटलर श्रोर स्टैलिन श्रायें। लेकिन में यह विश्वास दिलाना चाहतम् हैं कि झारखंडेराय जी के कहने के मुताबिक यहां ट्रांजीटरी पीरियड में डिक्टेटरशिप होनी चाहिये थी।

करने की कम से कम मेरी हिम्मत नहीं है

जो यह रखा जा रहा है इसमें बड़े २ दिह जाहिर किये गरं, सारा विषेयक ही गंदा हो गया। बहुत से अधिकार गवर्नमेंट को मिल गये। एक बहुत बड़ी दलील यह दी गयी कि जब कई एक अधिकार है तो यहां अधिकार की क्या जरूरत है। मुझे डर है कि कहीं इस दलील को बढ़ा कर कभी यह न कह दिया जाय कि इतने मुहकमें है तो पुलिस के मुहकमें की क्या जरूरत है। जहां-जहां इंतजाम की जरूरत है यह अधिकार है। आपको अधिकार है कि हिसाब की जांच करवायें, आपको अधिकार है कि गलत

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मादमी को निकाल दें तो फिर इन्ति क्या जरूरत है। मं नियेदन करूंगा कि इसकी उसकी मेरिट के साथ भीर भिष्ठकारों से ग्रलग देखा जाय। यह देखा जाय कि इसकी जरूरत है या नहीं। यह तो सभी को मालूम है कि कोई भी लेजिस्लेवर ऐसा नहीं है जिसके लिए ऐसा इंतजाम न हो कि ग्रगर ग्रावश्यकता पड़े तो ग्रपने ग्रायू—काल से पहले वह खत्म हो सके। जहां तक मेरा ग्रन्दाजा है मोटा-मोटा पालियामेंट ग्रपने ग्रापको ग्रपने टर्म से पहले डिजाल्व कर सकती है। ग्रभी ट्रावनकोर कोचीन में सोशालिस्ट पार्टी को भी मिनिस्ट्री मिल गयी। ग्रगर यह प्राविजन न होता ग्रीर पूरे काल तक वह लेजिस्लेवर चलता तो कम से कम पी० एस० पी० को मिनिस्ट्री मिलने का ग्रवकाश उतने दिनों तक न होता, यह तो हुं दलीलें। हर चुनी हुई बाडी को ग्रगर ग्रावश्यकता पड़े तो उसके टर्म से पहले ही चुनाव करवाने का ग्रावकार है। लेकिन यह तो कुछ जनरल दलीलें है, उससे ज्यादा बहस नहीं है।

एक खास बात श्रभी इस वक्त कही गयी, उपाध्याय महोदय, उसको में श्रापके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो पंचायतें इस समय प्रदेश में हं उनका चुनाव भिन्न भिन्न समय पर हुश्रा था। पहले इस प्रदेश में सब पंचायतों के लिये चुनाव हुश्रा लेकिन दो हिस्से मिर्जापुर श्रीर जौननार अवर को छोड़ दिया गया। उनकः किनाय श्रलग हुश्रा, एक चुनाव पहले हुश्रा था श्रीर दूसरा यह हुश्रा। तीसरा चुनाव गढ़वाल का श्रलग हुश्रा, बनारस में श्रलग, रामपुर में श्रलग श्रीर झांसी के श्रास—पास के जो गांव हं उनमे श्रलग चुनाव हुश्रा। इस प्रकार इस प्रदेश में समय समय पर श्रलग श्रलग कई चुनाव हुए। इस कानून के पास होने के बाद हर पंचायत की श्रवि पांच साल की हो जायगी। श्रगर एक साथ खत्म नहीं करते तो एक साथ सबका चुनाव नहीं करा सकते। जनरल प्रिसिपल के श्राधार पर यह नहीं है, न श्रविकार लेने की नियत से है बिल्क वास्तविक दिक्कत यह है कि इसके बिना सारे सूबे में जो पहले श्रलग—श्रलग चुनाव श्रलग श्रलग जगहों पर हुए थे उनका चुनाव, माननीय श्रध्यक्ष, एक साथ नहीं हो सकता।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री श्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस कानून के बाद हर एक की अवधि पांच वर्ष की हो जायगी और अगर एक साथ सत्म नहीं किया जाता तो ५,६ बार चुनाव कराना होगा। अगर सबको एक साथ तोड़ कर एक दफा उनका एक साथ चुनाव हो जाय तो सबकी अविध एक दिन से ही शुरू है। सकती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कतें आयें और पांच साल के पहले आवश्यकता पढ़ें, जैसे इस प्रदेश में जनरल चुनाव में दिक्कतें भ्रायों। जब चुनाव ड्यू हो तो किसान खाली न हो, फसल बोता हो या काटता हो, ब्याह होते हों । म्युनिसिपल बोर्डस के चुनाव में ये दिक्कतें भ्रायों भ्रौर कई तारीखें बदलनी पड़ीं। बहुत सम्भव है कि पांच वर्ष से दो महीने पहले ही चुनाव करने की ग्रावश्यकता पड़ जाय । लेकिन ग्रगर कोई माननीय सदस्य इस भ्रम में है कि जब जी में भ्रायेगा पंचायतों का चुनाव रद्द कर दिया जायगा भ्रार फिर जनरल इलेकान कराया जायगा और फिर ग्रिविकार जमाया जायगा तो माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस भ्रम में में नहीं हूं कि इस प्रकार से शक्ति आती है। में यह समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट ग्रपने किसी कार्य को जस्टीफाई न कर सके, इतने बड़े प्रदेश की ६०,६५ हजार ग्राम पंचायतों को तोड़ कर उनका जनरल इलेक्शन क्यों कराया ग्या, गवर्नमेंट इसका माकूल जवाब न दे सके तो इससे बजाय ताकत ग्राने के उल्टी घटेगी हों। चुनाव तो क्या ग्रगर नामिनेट करने की भी बात होती तो बार-बार ऐसा करने से ताकत नहीं मिलती। लोग नाराज होंगे कि हमारा काल क्यों खत्म कर दिया गया। इससे रिसेंटमेंट बढ़ेगा श्रौर जो इस तरह का काम करने वाला होगा उसको कमजोरी मिलेगी।

में निवेदन करता हूं कि मै इस भ्रम में नहीं हूं कि इस तरह के गलत काम करने से ताकत मिलेगी। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनको सोच कर यह रक्खा गया है। इस तरह का प्राविजन ृथी के ्च लास्याः]

हम राज्य राज्या है। प्रतिकारिकेट होना हमित्या ना की चुनाय नार अनिविद्या ने गाम्ने हो उत्तर हा इन तहतो है था। पाद्यान गरता है की होती नवाई है। प्रती हाणी पाने नहीं हुई है। होता निक्तित को ने प्रशासीय हैदा जिंदा कि की परेशानी था। इस वाही के प्रस्तात्म करा हालमा हूं की अन्तरीय मूबर इस संहोधन हो दापस ने ने है।

र्थी जारा अ--अक्स धह है कि बंद १४ में प्रस्थावित गरी, तथा 12-८ निकाल की जार ।

्णारण उपस्थिण िया गार प्रदेश त्या मठ धार शिक्ष स्त्रीने पण शिक्षिण स्मारकुणार प्रारीकृत हमान्य

यक्ष ले—१४ विजय चे—११)

क्षी को कार पर में क्यान में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के अधीन प्रस्तावित धान। 12-H से स्थान पर निग्नलिखित रहा दिया जाय—

"IP.IT It all colony in the Office of the Prodlam. Up-Prodher or of an intion Cast Product a list by reason of his death, time regrated of avoid real of the ecotion it slads he filed to a entrace this term in her a term as far as may be, provided, colon 11-4, 11-B or 12, as the case may be."

माननीय गच्यक क्योद्य. इसको निष्ठायट करने में जो पहले हम धारा का कंन्द्रका वा उसको नुष्ठ मिन्पली पाई किया गया है। दूसरी बार यह है कि एलेटबान पिटीशन से जो उसह वाली ह यो भी उनकी की पी इस तम्ह की जायेगी क्षीर जो भी वैकेशी होती उसमें दें। बाले हैं। एक ने यह हैं कि बाकी मानज वे लिये वह होतो और उत्तम दुनाय उसी तरह से होगा जेमा कि उसका एनेदबान रहले हुआ था। उसी तनह से यह एलेदबान भी होगा। यह केवल इसका मानव है। इसमें मुझे कोई विकास नहीं सामूम होती है। इसलिए से माजा करता है कि यह मानव इस संशोधन को जिसा कादिवाद को मंजूर करेगा।

र्भ अध्यक्ष्य—प्रदत्त यह है कि खंड १४ के ग्रधीन प्रस्तावित धारा 2-H के स्थान पर निम्नलिखित धारा कि दो जाय ।

2-H. If a vacar cy in the Office of the Predhan, Up-Prechanger and reer of a Gaca Pancheyet arises by reason of his death, removed, resignation or avoidance of his election it shall be five for the verainder of his term in the manner, as far as may be, provided in setion 11-A. 11-B, or 12, as the case may be."

(प्रश्न उपस्थित किया गया भ्रौर स्वीकृत हुम्रा ।)

श्री अतन मोदन एपःश्रमण—मानदीय श्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी स्राज्ञा ने मै यह रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ मे प्रस्तावित धारा 1े-ा की पंक्ति १ के शब्द रा०० के स्थान पर "०० रख दिये जायं।

श्रध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल मीधामाधा प्रस्ताव है श्रौर जिस स्थान पर 'नो रवला गया है वहाँ 'श्रोनली ए' रख दिया जाय । फिर यह धारा इस प्रकार से हो जायगी —

"12-1. Only a civil court sould have jurisdiction to question the legality of any action taken in any decision given by an Officer or authority appointed and other this Act. in connection with the conduct of election thereunder."

श्राध्यक्ष महोदय. यह केवल एक पादिक संशोधन है. माननीय मंत्री जी को इसमें न्याद्य दिक्कन भी नहीं होनी चाहिये इसको स्वीकार करने में । क्योंकि हम यह समझते हैं जैसा कि माननीय वालेन्द्रवाह जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि जो प्राविजन इसमें रक्खें जा गहे है उन सब से हमारा बराबर सम्यिद्धान बढ़ना ही जा रहा है। पंचों के इलेक्शन को गढ़ करने से यह ससपीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। पंचायत राज के आफिनर या अधिकारी जो भी कर्य करेंगे वह गलत करें , जनना के खिलाफ करेंगे. उसके लिये कोई रेमेडी हमारे पान नहीं है। लेकिन नाननीय मंत्री जी चारने हैं कि हम कोई रेमेडी भी सीक न करें, किसी मिविल कोर्ट के पास भी न जाये। वही एक ऐसी जगह है जहां इंसाफ हमें दिखायी पड़ता है, वैमे नो जुडिशियरी भी उन्हों की हैं। इसलिए में समझता है कि अगर यह लगा दिया गया मिविल कोर्ट का कोई जुरिसडिकार र होगा तो हमारा नस्रियान और भी ज्यादा बढ़ गयगा। कोई भी पंचायन अधिकारी, प्रधार, उप प्रधान या पंचायत राज का आफिसर ऐसा कोई काम करता है जो ठीक नहीं है तो उनके लिये निक्षित कोर्ट का ज्यूरिसडिकान तो अवस्य ही होना चाहिये और सिविल कोर्ट का केर्र का करना ही उनको कुछ, मनवा सकता है । में और ज्यादा कहना नहीं चाहना क्योंकि यह शाब्दिक संशोधन है तथा ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को कोई एतराज होगा नो उनके वारे में बाद को बतलाउंगा।

*श्री मोहनल।ल गौतम—मानर्गाय ऋष्यक्ष यहोदय, माननीय उपाध्याय जी को मं एक क्षांतिकारी कार्यकर्ता की हैसियत से तो जानता हो था लेकिन वे एक अच्छे वकील और वकीलों के पोयक है, यह आज ही मालूम हुआ। इस संशोधन को रख कर वे चाहते हैं कि वकीलों की चांदी हो और गरीब आदमी दिट जायं। गांव सभा में वही लोग जा सकें जो मुकदमा लड़ा सकते हों। मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि गरीबों के हमर्दद और गरीबों की भलाई चाहने वाले लोग यह कहें कि जब तक सबको सिविल कोर्ट में न ले जाया जायेगा, जब तक सब पैसे वाले उनको परेशान करके न निकाल दें तब तक गांव सभायें ठीक ही न हो मकेंगा। में नहीं समझ सका कि किसी परिणाम की वजह से या इस विधेयक को हंसी मजाक का विधेयक बनाने के लिये यह संशोधन उन्होंने दिया है या यह भी हो सकता है कि कहीं मंत्री मुलावे में आ जानं तो जनता के सामने उनको बेवकूफ बनाया जाय। यह संशोधन जिसे शाब्दिक कहा जाता है बहुत खतरनाक है। इसके लिये में उनको चन्यवाद देता हूं कि वह इस सदन को भुलावे में डालने में माहिर हो गये हैं। मुझे अफसोस है कि में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मंत्री जी ने मेरा यह छोटा सा शाब्दिक संशोधन मंजूर नहीं किया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह जो कहा कि वे वकीलों के हिमायती है तो उन्हें मालून है कि मं वकील हूं। मेरा विश्वास जुडिशरी पर है श्रीर मं मंत्री जी के मुंह से मुनना चाहता था कि उनका विश्वास जुडिशरी पर श्रव नहीं रहा है। मुकद्दमेवाजी रुक तो सकती नहीं है। पंचायतों के केस में श्रवश्य मुकद्दमें लड़ेगे लेकिन इसका नतीं जा कुछ न हो तो कोई लाभ नहीं है। लड़ें श्रीर इंसाफ मिल जाय, उसके लिये सिविल कोर्ट्स है। मेरी यह कभी मंशा नहीं थी कि में उसे केवल शाब्दिक कह कर स्वीकार करा लूं। यहां तो बहुत विद्वान् लोग बैठे है। इस संशोधन में केवल ४ शब्द हैं लेकिन इस तरफ के लोग भी मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं मालूम होते क्योंकि कोई बोलने को उठा ही नहीं, तो मं श्रपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्षा—श्रध्यक्ष महोदय, मं श्रापकी श्राज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—I की पंक्ति ३-४ में शब्द "an officer or authority

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्गा]

appointed under this Act" के स्थान पर शब्द "the prescribed authority" रह

इस विधेयक में प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी के सिवाय कोई दूसरा श्राफिसर दिखायी नहीं देता, इसिलए यदि इस स्थान पर भी वही रख दिया जाय तो कंस्ट्रक्शन श्रधिक श्रच्छा रहेगा श्रौर इसमें शब्द भी कम है। मुझे श्राशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—ग्रध्यक्ष महोदय, प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी से काम चलता नहीं है क्योंकि वह कोई ग्रलग दूसरा ग्रफसर भी हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां ग्रब तक प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को गालियां दी जा रही थीं श्राखिर में मेरे साथ सहानुमूर्त हो गयी है कि प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी ग्रावश्यक है। लेकिन फिर भी जो शब्द इस समय हैं उन्हीं से काम ग्रच्छा चलेगा और में इस संशोधन को स्वीकार करने में ग्रसमर्थ हैं।

श्री जोरावर वर्मा--- ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रेस्काइब्ड ग्रथारिटी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन मंत्री जी संशोधन को मंजूर नहीं करते तो में वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमित से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह—ग्रावरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी घारा १२—जे के ग्रंतिम शब्द "prescribed" के स्थान पर शब्द "delegated by the Pradhan" रख दिये जायं। में समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेगे क्योंकि ग्राखिर प्रधान ग्रौर उप प्रधान में ऐसी ग्रंडरस्टेंडिंग तो होनी ही चाहिये कि वह जो कार्य न कर सके या कुछ कार्य भार ज्यादा हो तो प्रधान, उप प्रधान को ग्रपना पावर डेलीगेट कर सके। में समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं मालूम पड़ती है इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री कृपाशंकर—श्रध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि कुछ समझने मे माननीय सदस्य को गलती हुई है। श्राप चाहते हैं कि "prescribed" के स्थान पर "delegated by the Pradhan" कर दिया जाय। तो जब रूल्स बनेंगे उस वक्त देखा जायगा कि कौन-कौन से पावर प्रधान, उपप्रधान को डेलिगेंट कर सकता है श्रीर कौन-कौन से कार्य है जिनके लिये प वर डेलिगेंट करना ठीक होगा। इसलिये श्रभी इस लफ्ज का यहां रहना ही ठीक है।

श्री तेज प्रताप सिंह—में तो समझता हूं कि "prescribed" के स्थान पर "deregated by the Pladhan" हो जाता तो अच्छा होता लेकिन जब माननीय मंत्री जी की ऐसी ही इच्छा है तो में अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का ग्रंग माना जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना ।)

खंड १५

मुल ग्रधिनिम की घारा १३ में शब्द "biennial" के स्थान पर शब्द "half yearly"

के ग्रीर घारा के ग्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड बढ़ा दिया जावे :---

"Provided that where for any reason an annual estimate of income and expenditure is not passed by a Gaon Sabha in its *Kharif* meeting, it may be passed by it at any subsequent meeting, before such date as may be prescribed under Sub-section (4) of section 41."

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मं श्रापकी ग्राज्ञा से यह संशोधन पेश करता हं कि खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"मुल म्रिघिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

- "13. (i) The Pradhan shall present the half yearly report of business including accounts duly passed by the Gaon Panchayat before the Gaon Sabha at its *Kharif* and *Rabi* meeting summoned under section 11(1) for its acceptance.
- (ii) If the Gaon Sabha, by a majority of three-fourths members present and voting, refuses to accept the report such refusal will amount a vote of no-confidence in the Gram Panchayat and the Gram Panchayat including the Pradhan and Up-Pradhan shall within a week tender its resignation to the prescribed authority.
- (iii) A fresh election of the Gram Panchayat including Pradhan shall be held for the unexpired part of the term of the Gram Panchayat in the manner as may be prescribed
- (vi) The Up-Pradhan shall be elected as provided in section 11 (B) 2."

ग्रध्यक्ष महोदय, प्रधान के लिए यह श्रावश्यक है कि वह गांव पंचायत में जो बजट तैयार करें वह गांव सभा के सामने खरीफ श्रोर रबी की फसल में हर ६ महोने बाद पेश करें। यह उस प्रधान के लिए बन्धन श्रवश्य होगा श्रोर वह वही टैक्स लगायेगा जो गांव-सभा मन्जूर करेगी। हमारा पिछला श्रनुभव है कि गांव सभाश्रों ने जो टैक्स लगाये उन में से २५ प्रतिशत भी वसूल नहीं हुए क्योंकि प्रधानों श्रोर गांव-पंचायतों ने जो टैक्स लगाये उन में गांव-सभाश्रों की विशेष सलाह नहीं रही है श्रोर गैर उनकी इच्छा के ही वह टैक्स लगाये गये है श्रोर इसी कारण से इन टैक्सेज को कोई गांव सभा वसूल नहीं कर सकी है। इसलिए में चाहता हूं कि प्रधान श्रोर गांव पंचायत के लिए यह श्रावश्यक बन्धन हो कि वह इस प्रकार से एस्टीमेट पेश करे श्रोर उस पर गांव सभा की भी कंसेन्ट हो श्रोर श्रगर वह नामंजूर करदे तो उसका मतलब यह है कि वह बजट गांव-सभा की इच्छा के विरुद्ध है श्रोर जो लोग वहां मौजूद है उनमें से श्रगर तीन चौथाई बजट को पास नहीं करते है तो इसका मतलब यह होगा कि गांव-सभा उनमें विश्वास नहीं करती हैं। इसलिए में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री मोहन लाल गौतम—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, श्रगर प्रेसीडेंट को हटाने की बात है तब उस का प्राविजन है जो श्रागे खंड १६ में श्रायेगा श्रौर उसमें १५ दिन की नोटिस के बाद स्पेशल मीटिंग बुलायी जावेगी श्रौर दो तिहाई मेजारिटी से उसको हटाया जा सकता है। श्री जोरावर वर्मा की मुख्य श्रापित्त तो यह खत्म हुई श्रौर इस तरह से संशोधन की जान जो थी वह तो निकल गयी। जिस तरह से उन्होंने श्रागे रखा है उसमें है कि "report of business including accounts duly passed by the gram-panchayat before the gaon sabha जब रिपोर्ट तैयार हुई श्रौर वह पंचायत के पास गयी श्रौर एकाउन्ट पेश हुआ श्रौर उसको श्रगर गांव सभा ने, उसको तीन चौथाई मेजारिटी ने श्रस्वीकार कर दिया तब वह प्रधान भी श्रलग हो जायगा श्रौर पंच भी इस्तीफा दें देंगे श्रौर नया चुनाव होगा। इस तरह के बोट श्राफ नो कानफिडेंस में ईशू क्लीयर होना चाहिये। रिपोर्ट में तो तमाम चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें जो श्रस्वीकार हो सकती है। वह हिसाब भी जो पेश होगा वह भी तो वही होगा खो बजट में पास हो चुका है, उसी खर्च का वह हिसाब होगा श्रौर श्रगर बजट के बाहर

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहनल ल गौतम]

की चीज पास की है तो श्रलग हो सवाल उठ सकता है श्रोर सरचार्ज का मामला श्रा जान है। श्रगर इन सब चीजों को निकाल कर प्राविजन कर दें तो नो कानिफडेंस का प्रस्ताव नने में दिक्कत होगी श्रोर एक्जीक्यूटिव पावर उसके लिए देनी पड़ेगी श्रोर इस तरह में बहुत काफी दिक्कत पैदा होगी श्रोर इश्रूज साफ न होंगी। अगर श्राप वोट श्राफ नो कन्फीडेंस लात चाहते हैं श्रोर गांव सभा से निकालना चाहते हैं तो उसके लिये प्राविजन इसमें श्रनग है इन शब्दों के साथ में श्राशा करता हूं कि माननीय जोरावर सिंह जी जब उनके प्रस्ताव की भावना का प्राविजन हो गया है श्रोर जब इसके लाने से बहुत सी कठिनाइयां दिखायी पड़नी है तो अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर दर्म!—मं चाहता था कि जंसे गवनंमेंट ने अपने यह अधिकार इसमें सुरिक्षत कर लिये हैं १२ (जी) में कि वह चाहें तो गांव सभा को डिजाल्व कर दें तो मं समझता हूं कि ६ महीने के लिये गांव सभा को अधिकार दे दें तो ज्यादा अच्छा था और ऐमा करने के लिये कोई स्पेशल मीटिंग नोकान्फीडेंस वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मं समझता हूं कि जब गवनंमेट को १२ (जी) के अन्दर अधिकार है तो गांव को दे दिया जाय तो अधिक अच्छा हो। लेकिन माननीय मंत्री जी इससे सहमत नहीं हूं इसलिए मं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की श्रनुमित से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री ग्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १५ इस विधेयक का ग्रंग माना जाय। (प्रदन उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुग्रा।)

खण्ड १६

यू० पो ऐक्ट १६—मूल ग्रिधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रव २६, १६४७ दिया जाय—— की धारा १४ का संशोधन ।

Remval of Pradhan and up-Pradhan.

and-up pradhan by a majority of two-thirds of the meeting specially convened which at least 15 days previous notice shall be given remove the pradhan and-up-pradhan by a majority of two-thirds of the meeting shall be such as may be prescribed."

*श्री जोरावर वर्म:—-ग्रध्यक्ष महोदय, मं ग्रापकी ग्राज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:—

खंड १६ में प्रस्तावित धारा १४ की पंक्ति ४ में शब्द "Vice-President" तथा शब्द "ur-pradhan" निकाल दिये जायं।

श्रध्यक्ष महोदय, यह जो थारा हं इयमे गांव सभा के प्रधान को निकालने का प्राविजन है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उप-प्रधान को भी उसमें रखा है। मेरा ऐसा स्थाल है जैसा इस ऐक्ट में है श्रौर सब जगह होता है कि जो श्रादमी जिसको चुनता है उसी को हटाने का श्रधिकार होता है लेकिन उप-प्रधान को तो गांव सभा चुनती नहीं है इसलिये उसको हटाने का भी श्रधिकार नहीं होना चाहिये। उसके हटाने के लिए इसमे मैने श्रागे एक

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

मंडोबन रखा है उसे म्रागे बनाऊंगा लेकिन उसके हटाने का प्राविजन यहां रखना म्रच्छा नहीं है। इर्मालये में म्राञा करता है कि मंत्री महोदय इस मंजीधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री दोहन नाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जैता कि हम ऊपर धाराश्रों को म्वीकार कर चुंके हं कि एक प्रधान है ग्राँर एक उपप्रधान है। प्रधान का चुनाव तो गांव मभा से होगा लेकिन उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायनें करेगी ऐसा हम स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन जब वह चुन गया तो फिर ग्रगर गांव सभा उसको उसके किसी ऐसे कार्य के लिये निकालना चाहनी है जो ग्रहितकर है तो उसको ग्रलग करने का ग्रधिकार उसे होना चाहिये। ग्रव मवाल यह है कि जिसको जो चुने उसको ही निकालने का ग्रधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिन लोगों को जिनने चुना हो वही ग्रलग करें ग्राँर दूसरा कोई न करे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होता भी है ग्राँर नहीं भी होता है। इसमें कोई ग्रसंगत बात नहीं है। मुझे ग्राशा है कि मेरी इस बात को वे स्वीकार करेंगे ग्राँर फिर ग्रगर उनके संशोधन को स्वीकार करते है तो फिर उपप्रधान चाहे जितनी धांधली करें जो एकजीक्यूटिय गांव सभा की होगी वह ग्रपने को हेल्पलेस पायेगी ग्राँर उसको ग्रलग नहीं कर सकेगी चाहे कितना हो वह उसके कार्य को नापसन्द करें। जो बात उनको ग्रसंगत मालूम होती है उसका जवाब मंने वे दिया। इसलिए ग्रव मुझे ग्राशा है कि वे ग्रपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—श्रध्यक्ष महोवय, गांव सभा को तो पूरा श्रधिकार गांव पंचायतों को हटाने का हं, उससे श्रगर वह लोग चाहें तो पूरी पंचायतों को हटा दें, उससे प्रधान भी श्रलग हो सकते हं श्रौर उपप्रधान भी । लेकिन श्रगर माननीय मंत्री जी को दिक्कत मालूम होती है तो मं इसको वापस लेता हं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री ग्रध्यक्ष--प्रक्त यह है कि खंड १६ इस विधेयक का ग्रंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थिन किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

१७--मूल अधिनियम की घारा १५ में--

- [(१) खंड (h) में जन्द "hats" श्रीर जन्द "within" के बीच जन्द "held on land vested in the Gaon Samaj established under section 113 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 1950" [be] रब दिय जाँय]
- (१) खंड (h) में शब्द "State Government" तथा शब्द "and" के बीच में शब्द "or the District Board" रख दिये जायं ;
 - (२) खंड (t) के स्थान पर निम्नालिखित रख दिया जाय--
 - "(1) the maintenance and control of class (1) and Kaiser-Hind forests, waste lands (benap), water channels and drinking places (panghat) in the hill patties of the Kumaon Division".
- श्री कृपाशंकर—ग्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड रखा जाय—
- संड (g) में शब्द "the disposal of" के बाद म्राने वाले शब्द "the dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and carcasses" रख दिया जाय।

ग्रय्यक्ष महोदय, यह संशोधन भाषा की शुद्धि के लिये रक्खा गया है।

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री ग्रध्यक्ष-यह नया खंड कौन सा है, ठीक समझ मे बात ग्रायी नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—श्रोरीजिनल ऐक्ट की धारा १५ के उपलंड (g) regulating places for the disposal of the dead bodies of human beings and animals and of other offensive matter जो है उसमें शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर श्री कृपा शंकर जो "dead bodies and carcasses" रखना चाहते हैं। उनको "the dead bodies of human beings and animals" शब्द श्रच्छे नहीं मालूम हुए इसलिये वह चाहते हैं कि उनके बजाय "dead bodies and carcasses" शब्द रख दिये जायं।

श्री ग्रध्यक्ष--इसमें जो १७ वां क्लाज है उसमें सेक्शन १५ को ग्रापने अमेंड किया है?

श्री मोहन लाल गौतम—मूल ग्रधिनियम की धारा १५ की उपधारा (g) में शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर शब्द "dead bodies and carcasses" रख दिये जायं। यानी प्रिसिपल ऐक्ट की धारा १५ से इनका मतलब है।

मूल क्रिधिनियम की धारा १५ के खंड (g) में यह चेंजेज हो जाय, यह मतलब है।

श्री ग्रध्यक्ष-- फिर उसके बाद मैं लूंगा क्योंकि यह बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है।

श्री कृपाशंकर—-ग्रध्यक्ष महोदय, मं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के ग्रधीन प्रम्तावित धारा १५ के कोञ्ठांकित उपखंड (१) के बाद ग्राने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-इसको ब्राप पूरा रेखांकित करना चाहते है।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह—प्रध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि इससे पहले जो संशोधन माननीय स्वशासन मंत्रों ने पेश किया था उसकी कम संख्या १ बनेगी क्योंकि वह "जी" है जो पहले से है यह "एच" है तो यह दो बनेगी ख्रौर "ख्राई" ब्राता है वह नम्बर तीन बनेगा क्योंकि वह संशोधन जो मंत्री महोदय ने पेश किया था वह अमेंडिंग बिल मे १७ ख्रन्डर सेक्शन १५ ख्राफ प्रिंसिपल ऐक्ट में बन कर ख्राया है। "Corpses" रेखांकित दोनों के सामने ख्राया है।

श्री ग्रध्यक्ष—हां, तो "H" को मैं ले रहा हूं। उसको ग्रभी छोड़ देता हूं क्योंकि पू०पी० ऐक्ट करना चाहते हैं। तो श्रागे बढ़ रहा हूं, जरा इसको साफ कर दें। २६, १६४७

ही बारा १५ री कृपाशंकर—मूल ग्रधिनियम की धारा १५ के उपखंड "एच" में ऐसा जोड़ दिया हासंशोधन। क होगा। खंड १७ के उपखंड "ए" में शब्द "impose" के बाद "or under the Act—रखा जाय तो ठीक होगा।

श्री श्रध्यक्ष—खंड १७ के श्रधीन प्रस्तावित धारा १५ के कोव्टांकित उपखंड (१) के बाद ग्राने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गत्रा ग्रीर स्वीकृत हुग्रा ।)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या इससे काम नहीं चलेगा? खंड "H" में शब्द जो है तो उसी तरह खंड "G" में शब्द डिसपोजल के बाद श्राने वाला यह कर दिया जाय तो मूल श्रधिनियम की घारा १४ ऐसी हो जायगी। तो मेरे ख्याल में कोई क्लाज श्रागे जोड़ा जाय यह मेरी समझ में श्रा नहीं रहा है। और वह शाब्दिक होगा तो श्राप देख लीजियेगा।

श्री ग्रध्यक्ष—-ग्रगर ऐसी चीज है तो श्रापको ग्रधिकार हे। मुझे शिकायत नहीं मालूम होता ।

महाराजकुमान बन्लेन्युशाह--उममे नम्बर का फर्क पड़ेगा। अगर पहले ग्राना दे तो नम्बर चेंज करना पड़ेगा।

श्री श्रध्यक्ष--हां, वह तो हं, वह दुरस्त किया हा नकेगा। प्रश्न यह हे कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड गइ, जाय --

"खंड (g) में शब्द "ine disposa, of" के बाद आने वाले शब्द "the dead podies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and careasse." रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह—ग्रथ्यक्ष महोदय, ग्रापकी न्नाज्ञा से में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (ग्र) रख दिया जाय—

"१ (अ) — मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the paner of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made thereus cer" निकाल दिये जायं।

ग्रध्यक्ष महोदय, जब हम इस घारा को पढ़ते हे श्रौर उसके बाद मे यह सोचते हे कि जो ये न्याय पंचायतें बनायी जा रही है वे एक नये तरीके ने बनायी जा रही है श्रौर जो १२ –ए हैं उसमें जो प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी रखी गयी है श्रौर जो ग्रवालतों पंचायतों का पंनेल होगा उसका कोई संबंध नहीं रहा श्रौर जो धारा ४३ है उसकी श्रगर हम देखते है तो उसमें जो प्रेस्काइब्ड श्रथारिटी है उससे श्रगर इस चीज की रखने हे तो हमारा जो मतलब है वह पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब हम उस घारा को पढ़ते हे जिसमे पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शन एंड ऐडिमिनिस्ट्रेशन श्राफ ए गांव पंचायत हे श्रौर फिर एडिमिनिस्ट्रेशन श्राफ सिविल ऐंड किमिनल जिस्टस इन दि इलेक्शन वगैरह है, तो यह वैसे एक टेक्निकल बात है श्रौर में समझता हूं कि श्रगर हम इसको रखते है तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी में प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले।

श्री मोहन लाल गौतम् —यह बहुत सुन्दर संशोधन हं श्रौर मुझे स्वीकार है श्रौर जो मुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसके लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (ग्र) रख दिया जाय।

"१(श्र) - मूल ग्रधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the panel of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made there under" निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुन्रा।)

श्री धर्म सिंह—श्रध्यक्ष महोदय, जो मैंने यहां पर संशोधन रखा है श्रौर मैंने उसकी कापी श्रापको दे दी थी श्रापको श्राज्ञा से मैं उसको पेश करता हूं:—

"संड १७ में मूल म्रिधिनियम की घारा १५ में संड (r) में "manure" के बाद तथा सेमीकोलन से पूर्व निम्निलित राब्द जोड़ दिये जायं —

"and for tanning and curing of hides"

[श्रीधर्म सिह]

इसके रखने का मतलब यह है कि अगर हम पावर्स, ड्यूटीज फंक्शन्स ऐंड ऐडिमिनिस्ट्रेशन श्राफ गांव पंचायत के डिस्कीशनरी फंक्शन्स की देखते हु जो कि १६ वां प्राविजन है तो उसमें जो क्लाज है उसमे एलाटमेट श्राफ प्लेस फार रेस्टोरिंग मैन्योर है श्रौर इसके साथ साथ ग्रगर हम ग्रोर ग्रागे पढ़ते ती उसी खंड मे १६ वी मे (एम) धारा है उसमे यह है कि २२० गज आबादी के बाहर चमड़े का टैनिंग और डाइंग वगैरह ही सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, जब हमने यह प्राविजन कर रखा है कि कोई भी भ्रादमी जो चमड़े का काम करता है उसको उस काम के करने के लिये २२० गज ग्रावादी के बाहर करना पड़ेगा। ऐसी हालत में जब दिन प्रति दिन उनकी हालत को देखते है जो गरीब श्रादमी चमड़े का काम करते हे, वह कहां करे तो एक समस्या उपस्थित हो जाती हं क्योंकि ग्राम मे श्रादमी उनको जगह नही देते हैं। जब समस्या को देखते ह कि उनको जगह नहीं मिलती है और उनका काम बहुत बड़ा हं ग्रीर कोई भी गांव का ग्रादमी जगह देने को तैयार नहीं हो । ग्रीर किसी भी क़ीमत पर उनको जमीन नहीं मिलती। ऐसी हालत में क्यों न पंचायने इस तरह का प्रावीजन करे या इस तरह का रेजोल्यशन पास करे या कोई भी चीज करे कि जो भी श्रादमी चमड़े का काम करे उसके लिये जमीन का प्रवन्ध हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग चमड़े पा काम करते है वहीं उनका घर होता है, वहीं उनका खाना पौना होता है श्रौर वहीं उनके लिये रहन-सहन की व्यवस्था होती है श्रौर उनकी जिन्दगी बहुत खराब हो जाती है। इधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी॰ द्वारा जब गंदगी रहती है तो उनका चालान होता है और नतीजा यह होता है कि वह इस काम को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाता है।

ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध हे लाखों की तादाद में लोग इस काम को करते हैं ग्रांर यदि हम इनको सहायता नहीं देते हे तो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी तिजारत को धक्का लगेगा। में समझता हूं कि यह ग्रत्यन्त उपयोगी है इसलिये इसको रक्खा जाय। में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर ले।

*श्री रामदास अर्थ-माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री जी के उन भावो को सराहना करता हूं कि जिन भावों से माननीय मंत्री जी ने हमे आश्रवासन दिया है, इसको मानने के लिये। श्राज हमारे प्रदेश में चमड़े की बड़ी भारी श्रावश्यकता है, उसकी देखते हुये चमड़े के उद्योग को उन्नत करना चाहिये। ग्राज यह हो रहा है कि ग्रपने गांव में चमड़े के लिये स्थान बहुत ही न्यून है और बहुत से कारखाने गांवों के अन्दर आ गये है। इसकी वर्जह से दूसरे गांव वालों के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा ग्रसर पड़ता है क्योंकि जहां चमड़े के टैनिंग के कारखाने होते है, जहां चमड़े रंगने का काम होता है, वहां बड़ी बदबू रहती है, श्रौर जहां चमड़े को छीला जाता हैं, पानी में डाला जाता है वहां तो बहुत श्रधिक बदब् हो जाती है। इसलिये सफ़ाई के लिहाज से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि चमड़े के कारखाने गांव से बाहर रक्खे जायं। जो चमड़े का वाम करते है उसके स्वास्थ्य पर ही इसर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। गांव के पास जहां तालाब होते है वहां यह चमड़ा साफ करते है। उसकी वजह से पानी में बदबू हो जाती है इसलिये ऐसे पानी का प्रबंध ग्रलग होना चाहिये ताकि जानवरों को किसी किस्स की तकलीफ न हो। इन सब भ्रावश्यकताओं को देखते हुये भीर भ्राबादी बढ़ती जाती है उसकी वजह से जो कारखाने पहले गांव के बाहर थे वे भ्रब भ्रन्दर भ्राते जा रहे हे। इसलिये इस बात की गुंजाइश होनो चाहिये कि चमड़ेके कारखाने गांव से २२० गजके फासले पर हों ताकि गांव वालों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जो लोग इस काम को करते है उनके खाने पीने और रहने सहने का स्थान ग्रलग होना चाहिये। गांव समाज को भ्रधिकार दिया जाय कि वह चमड़े के काम करने वालों को जगह दें और ऐसा मेरा ख्याल है कि अपने देश की उन्नति के लिये उनको जमीन की मिलनी

^{*} वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।

चाहिये और यदि ऐसा न हो सके तो मामूली कीमन ली जाय और वह जगह गांव से बाहर होनी चाहिये। में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करे और इस महोधन को स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—इन तमाम बलीलों के बाद जो हो माननीय मदस्यों ने ही है. में उनका समर्थन करते हुये इस मंशोधन को म्बीकार करना है।

श्री ग्रध्यक्ष—प्रक्त यह है कि खंड १७ में मूल ग्रधिनियम की धारा १५ में खंड () में : ______________________________ के बाद, तथा सेमीकोलन में पूर्व निम्निनिषित शब्द जोड़ विये जायं —

"and for tanning and curing of nides."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुमा।)

श्री कृपाशंकर—में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्न- जिल्लित नया उपखंड (१-क) रखा जाय —

"(१-क) खंड (x) में शब्द "raposed by" के बाद शब्द "or under this Act or " रखा जाय।"

श्री ग्रध्यक्ष—प्रक्रन य है कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (१–क) रखा जाय —

"(१-क) खड (s) में शब्द "imposed by" के बाद शब्द "or under this Ac or" रखे जायं!

(प्रक्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऋध्यक्ष-प्रत्न यह हे कि नंशोधित खंड १७ इस विधेयक का ग्रंग नाना जाथ।

प्रदन उपस्थित किया गया क्रोर स्वीकृत हुक्रा)

खंड १८

१८--मुल श्रिधिनियम की धारा १६ में---

- (१) खंड (b) में शब्द "them" श्रीर उसके बाद पड़ने वाले सेमी-कोलन के बीच में शब्द "including the maintenance of pedigree bulls."
 - (२) खंड (1) में शब्द "sweepings" श्रौर उसके बाद पड़ने वाले मेमीकोलन के बीच में शब्द "and making arrangements for the disposal of carcasses of animals": रख दिये जायं; श्रौर
 - (३) खंड (r) के बाद निम्नलिखित नया खंड (s) जोड़ दिया जाय—
- "(s) making arrangements for the seizure and disposal of stray cattle, stray dogs, wild animals and menkeys."

श्री कृपाशंकर—में प्रस्ताव करता हू कि खंड १८ के उपखंड (१) की ग्रन्तिम पंक्ति में शब्द "padigree bull" के उपरांत नेमीकोलन रन्ता जाय श्रोर उप खंड के श्रन्त में श्राने बाने कोष्टक श्रीर उसके श्रन्तर स्थित कोलन को हटा दिया जाय श्री ग्रध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की ग्रंतिम पंक्ति में शब्द "pedigree bull" के उपरान्त सेमीकोलन रखा जाय ग्रीर उप यंड के ग्रन्त में ग्राने वाले कोष्ट्रक ग्रीर उसके ग्रन्दर स्थिति कोलन को हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ग्रौर स्वीकृत हुग्रा।)

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ; ६ मई, १६५४। कैलास चन्द्र भटनागर, सचिव, विद्यान सभा, उत्तर प्रदेश।

पू० पी० ऐक्ट २६, १६४७ हो घारा १६ हा संशोधन ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रक्षन ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर।) लखनऊ जिले में पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत होने वाले विकास कार्य की सूची

१---सिचाई

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले में नहरों के विस्तार में तेजी से कार्य हुआ जिसके परिणाम स्वस्प जिले में १६५२ ई० में नहरों द्वारा १,२७,०४२ एकड़ क्षेत्रफल की सिचाई होने लगी। इस कार्य में पुनः विस्तार हो रहा है और सन् ५६ ई० तक नहरों द्वारा प्रति वर्ष १,४४, २८१ एकड़ क्षेत्रफल की सिचाई की जा सकेगी।

ट्यूबवेल की संख्या १६४६ में १७ से बढ़ कर १६५२ ई० में ३२ हो गई। शीघ्र ही २० नलकूपों का ग्रौर निर्माण हो सकेगा। जिले में सहकारी समितियों द्वारा ७ नलकूप तथा ह्यक्तिगन नलकूप इस वर्ष निर्मित होंगे। शासकीय नलकूप शासकीय फार्मों ग्रौर जंगलों में लगाये जा रहे हैं।

सन् १६४२ ई० में जिले में कुल १०२ पॉम्पग प्लान्ट थे। ५३, ५४ में सहकारी समितियों ग्रौर पंचायतों द्वारा ६ पम्पिंग प्लान्ट चलाये गए। शासन ने १३ पम्पिंग प्लान्ट्स के लिये तकाबी की सहायता जिले को प्रदान किया है।

सिचाई के कुत्रों से सिचाई हो रही है। प्रतिवर्ष १४५ कुत्रों के हिसाब से सिचाई के कुत्रों का निर्माण हो रहा है ग्रीर लगभग १२० कुत्रों में प्रतिवर्ष के हिसाब से बोरिंग होती है। ५२, ५६ में १७५ रहट प्रतिवर्ष के हिसाब से लगाई जायंगी।

२--कृषि

इस समय जिले में १८ स्थायी श्रौर एक घूमने वाले सीड स्टोर हैं जिनमें प्रति सीड स्टोर में १,५०० प्रति मन से ८,००० प्रतिमन तक बीज रखा जाता है। दो श्रौर सीड स्टोर बनाने का प्रयत्न जारी है। जिला नियोजन समिति ने जिले में बहुत से सीड बंक खोलने की योजना को स्वीकृत कर लिया है जिसके श्रनुसार श्रच्छे बीजों के रिजस्टर्ड एकत्रीकरण की योजना है। इस प्रकार ग्राञा की जाती है कि १९५६ ई० तक सिचित भूमि का श्रिषक भाग उन्नतिशील बीजों से परिपूरित हो जायगा।

प्रान्तीय शासन ने भूमि ग्रौर ऊसर जमीन को कृषि योग्य बनाने का कार्य बड़े स्तर पर प्रारम्भ किया है। रहीमाबाद ऊसर फार्म ग्रौर रहमान खेरा भूमि संरक्षण फार्म शासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके सिवाय ७,००० एकड़ ऊसर भूमि व्यक्तिगत साधनों से किसानों द्वारा उपजाऊ बना कर कृषि योग्य की जा रही है। कानपुर सड़क पर एक ऐसे क्षेत्र में जो मुख्यतः ऊसर क्षेत्र कहा जा सकता है एक राष्ट्रीय विकास क्षेत्र खोला गया है।

कृषि के उत्पादन को ऊपर उठाने के लिये ५२,५३ में ८३६ कृषि यंत्र प्रयोग में लाये गये। सन् १६५६ तक १,५०० उन्नतिशील कृषि यन्त्रों को प्रयोग में लाने की योजना है। कृत्रिम खाद कम्पोस्ट तथा हरी खाद के प्रयोग का ग्रविकाधिक प्रचार किया जा रहा है। उन्नत विधियों द्वारा प्रति वर्ष १६१० कृषि प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया जाता है।

जिले में फसल प्रतियोगिता का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है। कृषि रक्षा सेवा की एक इकाई जिले में कार्य कर रही है और टिड्डियों के विनाश, गन्धी चूहे तथा मेंगों हापर के विनाश का कार्य कर रही है। मैन्गों हापर से बचाव के लिये औषिघयों के छिड़काव का कार्य गहन स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाव के लिये कृषि नाशक औषिघयों को सस्ते वामों पर सहकारी केंद्रों द्वारा विकय कराया जा रहा है तथा उनका प्रचार किया जा रहा है।

३--वागबानी भ्रौर वक्षारोपण

सिंचाई के छोटे माधनों के ग्रधिक उपलब्ध होने के कारण साग सिंब्जियों का उत्पादन का प्रचार बहुत बढ़ रहा है। साग मिंब्जियों सम्बन्धी श्रनुसंधान फार्म जिले में चल रहे है। शहर में ग्रालू के बीजों को सड़ने से सुरक्षित रखने के लिये एक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है ग्रॉंग देहानों में इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये कार्य किया जा रहा है। शिक्षण केन्द्रों में किचेन गार्डन, बागवानी ग्रौर साग सब्जी को छोटे—छोटे खेतों में पैदा करने का प्रचार किया गया है।

निम्निलिखित तालिका वृक्षारोपण के विषय में है जिसमें इम छोटे से जिले में विगत तीन माल के वक्षारोपण की स्थिति ज्ञात हो सकेंगी।

		पेड़ जो लगाये गये		पेड़ जो बचे	
व ष	منعد سعد شرب التعربي شناء ا	फचढार 	गैर फलदार	फलदार	र्गरफलदार
१६५१ १६५२ १६५३	••	₹४,१६ <i>=</i> ₹६,११६ ६४,३४०	। ३,७१८ ६,६१४ १,१३,३ <i>६७</i>	१४,५७७ २३,३४२ ग्रोब्म ऋतु	१,४४० ३,४०० के उपरान्त गिना जायगा
योग		१,२७,६२७	, १,२४,०२६		

४--गन्ना विकास

गन्ने की ग्रांसत पंदावार सन् १९४६ ई० मे ३०० मन प्रति एकड़ से बढ़ कर सन् १९५२ ई० मे ३४० मन प्रति एकड़ हो गई। गन्ना विभाग का एक ग्रपना बीज भंडार, एक ट्रैक्टर तथा एक पंस्पिंग सेट हैं।

५--सहकारिता

इस छोटे में जिले के ग्रन्तर्गत ५७१ सहकारी सिमितियां कार्य कर रही है। ३०० नई सिमितियां ग्रौर मंगठिन की जा रही है ताकि जिले के समस्त ग्राम सहकारी ग्रान्दोलन के ग्रन्तर्गत ग्रा जावे।

- १८ विकास संघ तथा १ दुग्ध संघ जिले में कार्य कर रहे है। जिले में एक सहकारी बंक तथा एक जिला सहकारी विकास संघ (डी० सी० डी० एफ०) भी है जो रुपये के लेन देन का भी कार्य करते है। सन् १६५२, ५३ में समितियों द्वारा भ्रपने सदस्यों को लगभग ५ लाख रुपया दिया गया। सन् १६५६ तक इसे बढ़ा कर १२ लाख प्रतिवर्ष कर देने की योजना है।
- १३ बीज भंडार चालू है ग्रौर यूनियन्स ग्रपने बीज गोदामों के भवन भी निर्माण करा रही है। सन् १६४६ तक जिले मे १७ बीज गोदामों के पक्के भवन बन जावेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों मे १० सहकारी भट्टे भी चल रहे हैं।

६-चिबिकित्सा एवं जनस्व≀स्थ्य

संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिये जिला स्वास्थ्य ग्रधिकारी तथा संक्रामक स्वास्थ्य ग्रधिकारी द्वारा गहन उपाय काम में लाये जा रहे हैं। जिनके फलस्वरूप गत दो वर्षों से संक्रा-मक रोग पूर्णतया नियन्त्रित है। सन् १६५२-५३ ई० में जिले भर में हुंचे के ४,७०,२७५ चचक के ३,,१०० स्रोर ताउन के ७,३६२ टीको लगाये गये इस वर्ष जिले में मलेशिया निर्वेधक कार्य भी गए गए हैं सार डी० टी० टी० के खिड़काव का प्रवन्ध भी किया गया है। चहा मार ने बा सार जे के बिड़े नियोजन तथा स्वास्थ्य स्रिकारियो द्वारा निर्माण निर्माण कर गर्ध है। चान मुण्या राजे के बिड़े नियोजन तथा स्वास्थ्य स्रिकारियो द्वारा नालिया बनायों का गर्ध है। नान टेन निर्माण के कार के किया का पही है नाफ पानी के कुझे का विर्माण है. रहा है जार कुछों को नियमित क्य में कीटा मुक्त किया जाता है। राज्य में पावान साक बणने के तरीकों में भी पुष्य करने की चेटा की जा रही है। साथिक चिकिता के जिला का भी स्रायोजन किया गया है।

3——पहा दलन

म्र) पशु चिकित्सा--

जिलें को रेन्डरपेस्ट रोग से पूर्ण रूपेण सुवन करने का आन्दालन सफलतापर्वक चलाया लाव टीके लगाये गये जिसके फलस्वरूप इप वर्ष कंदल २ या २ १ तोत को पूर्णतया नियन्त्रण से रखने के लिये प्रति वर्ष ४०,००० टीके लगाने का लक्ष्म निर्धारित किया पर है। जानवरों के इलाज तथा टीके लगाने के लिये सिएस तथा बेस्सीन बनाने के हेतु जखनऊ से एक बाइयोला त्रिवल उत्पादन सेक्शन खोला गया है।

(१) नम्ल सुध र--

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नस्ल मुधारने हेतु ४६ मांड़ १६ भेरू २ भेड़े ११ बकरा. १६ गुग्रर ग्रौर १ घोड़ा विनिरित्न किये गये। १६५६ तक इम संख्या में घमठाः ३०.२४.२४.३०.२० ग्रार १ को वृद्धि का जावेगी। प्रतिवर्ष ६,००० निकम्मे साँड़' तथा दछडों को विधया किया जाना है।

वैज्ञानिक तरीकों के ग्राघार पर ३०० जानवरों के बाड़े निर्मित किये जा चुके है। सन् १९५६ ई० तक यह संख्या १,२०० हो जावगी। जिले में हरे चारे उने बरसीम के पढ़ा करने की ग्रोर कदम उठाये गये हैं ग्रीर चारागाहों को भी मुधारा जा रहा है। सन् १९५६ तक ७ एकड़ भिम में चारे की उन्नतिशील खेती होने लगेगी।

चक गजरिया में एक विञाल मिकेनाइज्ड राजकीय फार्म चलाया जा रहा ह जिम्मे ए ह बड़े कृषि फार्म के ब्रलावा उन्नतिशील नस्लों की गायों भसों तथा मुग्नियो के ठ ः रखने के प्रदर्शन किये जाते हैं।

=—ग्रावागमन

लखनऊ में पक्की (मेटिल्ड) सङ्के पर्याप्त मात्रा में है। स्टार तथा ग्रिड फ मूंला के ग्रनुमार लखनऊ में ६६ मील पक्की सड़के होना चाहिये ग्रौर ४३० मील कच्ची (अनमेटल्ड) सड़के। उर इस समय लखनऊ में ११८ मील पक्की सड़के ह ग्रौर सन् १९५६ ई० तक १७ मील ग्रौर वन जायंगी।

लखनऊ में कच्ची सड़कों की कुल लम्बाई उपरोश्य फार्मूले द्वारा निर्धारित प्रावध्यकता से ३०२ मोल कम थी। पिछले वर्ष श्रमदात द्वारा १०६ मील लम्बी कच्ची सड़के बनाई गई। इस वर्ष १६५ मील १ फर्लाग १०८ गज लम्बी कच्ची सड़क बनाई गई। इस प्रकार २६० मील १ फर्लाग १०८ गज कच्ची सड़क बन चुकी है। शेष चतुर्थ श्रमदान श्रान्दोलन के श्रन्तगंत बनायी जायगी।

अमदान--

उपरोक्त सभी कार्य जिले में विगत वर्षों में नियोजन विभाग के प्रयास से हुये है। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास गांव वालों के पास पहुंचने का ढंग है। ग्रौर गांवों के निवा-सियों को ग्रपनी स्थिति सुधारने का उत्साह दिन्ताना है। गांव वाले ग्रधिक टियाऊ सार्वजनिक कार्यों पर श्रमदान देते हें ग्रौर ग्रपनी परिस्थितियों को सुधारने का दृढ़ निश्चय प्रकट करते हैं।

६---शिक्षा

४६ जूनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल श्रौर ३२ हायर सेकेण्डरी स्कूल जिले मे चल रह ह १७ पुस्तकालय तथा ४५ वाचनालय जिले में पिछले वर्ष खोले गये थे। सैनिक शिक्षा युवकों को एन० सी० सी० तथा पी० ई० सी० द्वारा दी जाती है।

नियोजन विभाग के कर्मचारियों के लिये विभिन्न विभागों के शिक्षण के लिये जिले में २ शिक्षण शिविर चलते ह जिनमें एक बख्शी का तालाब तथा दूसरा प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्य कार्यालय के पास है।

१०--हिंग्जन बेलफेयर

हरिजनों को गृह उद्योग के धन्धे चलाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है। १४,४० द ६० ५२, ५३ में चमड़े बढ़ईगिरी तथा अन्य कारोबार करने के लिये हरिजनों को दिया गया। इस वर्ष हरिजनों को २४,३०० ६० दिया गया है। हरिजनों की १८ सहकारी सिर्मातया उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु काम कर रही है। बख्शी तालाब पर हरिजनों को वैज्ञानिक ढंग से चमड़ा साफ करना सिखाने का एक व्यापारिक केंद्र खोला गया है। इसमें प्रतिवर्ष शासन द्वारा ५५,००० ६० क्षात्रों को १ होस्टल, पुस्तकालय, रात्रि पाठशाला फीस तथा पुस्तकों को ऋय करने में व्यय होता है। यह आशा को जाती है कि ५६ तक शासन द्वारा जिले में ३ लाख रुपया इस कार्य पर व्यय होगा। शासन हरिजनों को कुओं के निर्माण के लिये कार्फ सहायता वेती हैं। जिले में १०३ पानी पीने के कुओं के हेतु हरिजनों को सहायता प्रदान की गई है। भवन निर्माण के लिये भी हरिजनों को सहायता दी गई।

पंचायत

जिले में नियोजन के कार्य का सारा भार गांव सभाश्रों पर है। यह कहना अनुचित न होगा कि इस जिले में पंचायतों ने निर्माण कार्य में अत्याधिक रुचि दिखलायी है। पंचायतों ने प्रारम्भ से सन् १६५३ तक १८ पक्के और २१ कच्चे पंचायत घरों का निर्माण किया है। १६५३-५४ ई० में लगभग ४० पक्के पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में निर्मित इसमाइलगंज गरम्भा, बिजनौर सालेनगर तथा वरगवां के पंचायत घर उल्लेखनीय है। सन् १६५६ तक का लक्ष्य १८६ है।

पंचायतों ने भ्रब तक जिले में कुल १४४ लालटेने लगवाई है। इस वर्ष मे १०० लाल-टेने ऋय की गई हैं। तथा ५०० लालटेने के लगवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सन् १६५६ तक का लक्ष्य १४८० है।

प्रारम्भ से सन् ५३ तक पचायतों ने ५४ पुस्तकालयों का स्थापना की। वर्तमान वर्ष में २० ग्रीर पुस्तकालयों के खोलने की व्यवस्था की गई है। जिसमे १० पुस्तकालयों के हेतु पुस्तक क्रय कर ली गई है श्रीर ग्रन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सन् ५६ तक का लक्ष्य १० है। पचायतों द्वारा क्रय किये गये रेडियो की संख्या १० है। इसी प्रकार सामुदायिक अवण योजना द्वारा प्रवत्त रेडियो की संख्या भी लगभग २५ है। सन् ५६ तक का लक्ष्य ५० है। कच्ची सड़के, तालाबों, रास्तों, गूलों ग्रादि के निर्माण, मरम्मत तथा सफ़ाई के साथ साथ पंचायतों में पक्की सड़कों के बनवाने का भी उत्साह पैदा हो रहा है।

संक्षप मे पचायतों ने श्रपने सीमित श्रार्थिक साधनों के होते हुये भी विभिन्न निर्माण कार्यों में श्रत्याधिक रुचि दिखलाई है।

नत्थी 'ख'

(देन्त्रिये तारांकित प्रक्त ७ व ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

जिला बुलन्दग्रहर में पंचवर्षीय योजना के ग्रधीन होने वाले कार्य की सूचना

कृषि मम्बन्धी विकास कार्य—इस जिले की विकास योजना में कृषि उन्नति की योजना जो प्रथम स्थान दिया है।

उन्नितिशील बीज का वितरण—इस योजना के ग्रन्तर्गत सन् १६५१-५२ में १४,१२६ मन रबी का ग्राँर २,४६७ मन खरीफ का, १६५२-५३ में ११,६५७ मन रबी का ग्राँर २,२२६ मन खरीफ का नथा १६५३-५४ में १४,६३१ मन रबी का ग्राँर १,३४५ मन खरीफ का बीज बांटा गया। जिले में वर्ष १६५५, ५६ में ३४,५०० मन रबी बीज का वितरण करने का हमारा लक्ष्य है।

कृषि प्रदर्शन—कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि मम्बन्धी प्रदर्शन किये जाते गरे हे। जिनका यहां के किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्नतिशील बीज तथा खाद सम्बन्धी, खेन सम्बन्धी यांत्रिक फसलों के हेर फेर ग्रादि के प्रदर्शन कृष मिलाकर सन् १६५१-५२ मे ३६०३ तथा १६५२-५३ में २३८५ ग्रीर दिसम्बर १६५३ तक १७०६ प्रदर्शन कराये गये हैं। हमारा लक्ष्य १६५३-५४ व १६५४-५५ तथा १६५५-५६ मे प्रतिवर्ष २१०० प्रदर्शन करने का निश्चय किया है।

उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण—सन् १६४१-४२ में उन्नतिशील यंत्र ६४, सन् १६४२-४३ में ३१७ ग्रीर दिसम्बर १६४३ तक १४४ बांटे गये है। सन् १६४३-४४ ब १६४४-४४ तथा १६४४-४६ में बांटने का लक्ष्य ४६० व ४४० ग्रीर ४४० है।

खाद का उत्पादन श्रौर वितरण—हमारा यह लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जानवर के पीछे एक टन कम्पोस्ट तैयार करें। सन् १९५१-५२ व ५२-५३ श्रौर ५३-५४ में दिसम्बर ५३ नक कमा: ७६० टन. २४२.५ टन, ३०३ टन श्रोमोनियम सल्फेट १९५२-५३ व ५३ ५४ में ४-४ टन सुपर फास्फेट बांटा गया श्रौर ५१-५२ तथा ५३-५४ में ७.५ टन तथा १.५ हड्डी की खाद बांटी गयी। इन तीन सालों में खली कमा: २,०१० मन २,३०४ मन तथा २६८ मन बांटी गयी। इन खादों के साथ-साथ हरी खाद जैसे मूंग टी १, ढेचा सनई श्रादि का वितरण भी निम्न प्रकार से किया गया।

	१९५१-५२	そよとーさま	ととスタースス
मूंग टी १	३५ मन	१७४ मन	१५८ मन
मनई डेंच ।	२.२ टन	४.५ टन	४.७ टन

फमल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को कुछ विशेष सुविधायें देकर प्रांतीय सरकार ने इम योजना पर ग्रौर भी प्रगति लावी है। इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्न पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया है जिससे श्रन्य कृषक भी इस योजना में भाग लेने के लिये प्रेरित हो सकें।

१६४१-४२ १६४२-५३ १६४३-५४ पुरस्कार जो बांटे गये १,४०० ६० ५,१०० ६० ६,३५० ६०

जिला बुल दशहर के एक कृष क जयपाल चन्द्र को स्नाल् में ७३५ मन से स्रधिक पैदाबार करने में प्रदेशीय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार स्रौर कृषि पंडित की उपाधि प्राप्त हुयी। वर्ष १९५२-५३ की प्रदेशीय रबी फसल प्रतियोगिता में गेहूं की सबसे स्रधिक उपज करने में प्रथम पुस्कार इस जिले के कृषक श्री राम किशन सिंह, ग्राम बरकतपुर को प्राप्त हुन्ना। उन्होंने एक एकड़ में ५४ मन से स्रधिक गेहूं पैदा किया।

कपास की उन्नति—यह बहुत श्रावश्यक है कि जिले में सन् १६५५-५६ में कपास के क्षेत्रफल को ५०,००० एकड़ तक बढ़ाया जाय । यह पूरा क्षेत्रफल उन्नतिशील जातियो का है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य हो चुका है।

कपास का क्षेत्रफल १६५१-५२ १६५२-५३ १६५३-४५ ३०,०७१ एकड़ ३०,८४१ एकड़ २४,६७७ एकड़ कपास का बीज जो बांटा गया २,००४ मन देशी १,६८२ मन देशी ६७१ मन सुवरा

उद्यान तथा वृक्षारोपण में सन् १६५२ से भ्रब तक निम्नलिखित प्रगति हुई है

१—नवीन उद्यानों का लगाना—नवीन उद्यानों का क्षेत्रफल जो कि इस जिले में लगाना चाहिए था उसके लक्ष्य का १६५६ तक का योग १५४६ एकड़ निश्चित हुग्रा था जिसमें से श्रष्ट तक ६०३.२५ एकड़ नवीन उद्यान रोपित हो चुके हैं।

२—पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार—जीर्णोद्धर का लक्ष्य १९५६ तक का ३,१६६ एकड़ निश्चित हुआ था जिसमें से स्रब तक १,७३८.५ एकड़ पुराने वागों का जीर्णोद्धार हो चुका है।

३—-फलदार वृक्षों का रोपण संख्या—वृक्षारोपण केवल फलदार वृक्ष १६५६ तक के लक्ष्य का योग १,४६,१२४ वृक्ष निश्चित हुआ था जिसमें अभी ६१,२१४ वृक्ष लग चुके हैं। अन्य वृक्षारोपण का लक्ष्य २३,१६६ था। अनुमानतः गत ३ वर्षों में १०,००० से अधिक इस प्रकार के वृक्ष लगे हैं।

४—-पौदागृहों की स्थापना—इसमे १९५६ तक केन्द्रीय पौदागृहों की स्थापना का लक्ष्य २ था और ग्रन्य ग्राथिक सहायता प्राप्त पौदागृहों का लक्ष्य १० था जिसमे से ३ तो केन्द्रीय पौदागृह कर दिये गये है और १० ग्रन्य की व्यवस्था बीज इत्यादि बिना मूल्य के देकर स्कूलों तथा बीज गोदामों पर की गयी है।

५—शाक भाजी के बीजों का वितरण—इसका लक्ष्य १६५ पौंड बीज वितरण था जिसमें स्रभी तक १७१ पौंड वितरित किया जा चुका है।

वन लगाने की योजना

वर्ष १६५२, ५३ तथा १६५३,५४ में ११ मन बबूल के बीज का वितरण किया गया जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बड़े बड़े चकों का ७,४४० एकड़ रकबा मुहकमा जंगलात को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सिंचाई के साधनों का विकास

छोटे-छोटे सिचाई के साघनों में पक्के कुंग्रों का निर्माण व मरम्मत कुग्रों मे बोरिंग करना, रहट लगाना, पंपिंग सेट, लगाना तथा ट्यूबवेल इत्यादि है। इन कार्यों के लिये समय-समय पर छूट तकावी सामान की सुविधा दी गयी है जो कि इस प्रकार है; पक्के कुग्रों का निर्माण व मरम्मत इस योजना के श्रन्तर्गत वर्ष १६५० तक कुग्रों को ५०० ६० तक की छूट दी जाती थी। जनवरी, १६५१ तक कुग्रों के लिए २५० ६० तक की छट दी गयी।

मार्च सन् १९५० के उपरान्त गत चार वर्षों में १७४९ नये क्य निर्माण हुए। सन् १९५६ तक ३,२०० कुए बनाने के लिये योजना है। पुराने कुग्रों की मरम्मत के लिये ईंट् सीमेंट का प्रबंध कया जाता है। तथा तकाबी भी प्राप्त हो सकती है। इसी योजना र ग्रन्तर्गत ३००० कुग्रों की मरम्मत हो जाने की श्राक्षा है। वोरिंग---पक्के कुम्रों के बोरिंग करने की योजना के म्रन्तर्गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार प्रगति हुयो--

सन्	लक्य	प्रगति	
१९५१-५२	१७५ प्रति वर्ष	Yo	
१ ६५२-५३	१७५ ,,	58	
१९४३-४४	શ્ બ્ર ,,	२३ (सितम्बर, १९५३) तः	F

हमार। लक्ष्य यह है कि मार्च सन् १९५६ तक ८७५ कुग्रों में बोरिंग करा दिया जावेगा। इस कार्य के लिये श्रव तकावी की मात्रा ४०० रु० प्रति कुएं तक बढ़ा दी गयी है।

गत तीन वर्षों में १९३३ रहट लगाये गये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ३३२० रहटों के लग जाने की संभावना है। रहट के लिए २५० रु० तक तकावी दी जाती है।

सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १६४२-५३ में इस जिले के लिये १५ कुएं स्वीकृत हुए थे। जिनमें से १४ कुओं पर कार्य आरम्भ किया गया। इस वर्ष जिले के लिये म कुएं स्वीकृत किये गये है। आगामी दो वर्षों में ५२ और कुएं बन जाने की आज्ञा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कुएं के लिये १०,००० ६० तकावी के रूप में दिया जाता है जिसमें से ५००० ६० तक छट प्राप्त हो सकती है।

गत तीन वर्षों में उक्त कार्य के लिये निम्नलिखित तकावी वितरित की गयी:

		१६५१-५२	१६५२-५३	१९५३-५४	योग
नलकूप निर्माण	• • •	20,000		२१,४५०	३१,४५०
नलकूप निर्माण प रक कु ग्नों का निर्माण	• • •	द६,३ ५०	१,०००	8,400	६१,८५०
रहटों का लगाना	• •	१,२००	₹,६७५	१,५००	६,३७५
कुओं की बोरिय	• _	٧oo	• • •	३,०००	३,५००
सहकारी नलकूप	• •	• •	१,५०,०००	50,000	२,३०,०००
पंपिम सेटों का लगाना	•••	• •	• •	१६,०००	१६,०००

के अन्तर्गत व्यय कर दी जायगी।

पशु पालन सम्बन्धी विकास योजनायें इस प्रकार हैं

म—पशु धन की उन्नति?—हरियाना व मुर्ग सांड पंच वर्षीय योजना में कुल १०० देने ये जिनमें से म्रब तक ४४ दिये जा चुके हैं। सन् १६५१ व ५२ में १३ गायें ग्राम मौगलौर में तकावी पर दी गयी।

२ - सूत्र्यर सांड १५ देने थे जिनमें से ११ दिये जा चुके है।

३ - बकरा सांड १५ देने थे जिन में से इंग्रभी एक भी नहीं दिया गया है।

४—मेढ़ा सांड १५ देने थे जिनमें से ग्रभी एक भी नहीं दिया गया । कोई मांग् प्राप्त नहीं हुयी ।

४---१,५०० मुर्गियाँ देनी है जिनमें से ८५६ दी जा चुकी हैं।

६--- ३,४०० ग्रंड देने ये जिनमें से ६६६ दिए जा चुके हैं।

व—पशुर्ओं का इलाज—पांच वर्षों में १,१४,००० पशुर्ओं का इलाज कराने के लिए लक्ष्य था । जिनमें से ४८,४६६ पशुर्ओं का इलाज हो चुका है।

स—पशुर्ओं का बिया करना—१२,५०० जानवरों को बिया करने की योजना थी। जिनमें से सब तक ४,३१५ पशु बिया किए जा चुके हैं।

द—छूतवार बीमारियों के टीके—धुर्का व वेदन के ४,००,००० टीके लगाने की योजना में से सब तक ६,२६,८४६ टीके लग चुके हैं। इस वर्ष सारे जिले में वेदन (म्रार०पी०के०) हे टीके लगाने की योजना चालू की गयी हैं जिसके अन्तर्गत ३,३४,४१२ टीके लगाये गए।

इ—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना—सन् १६४४ व ४६ तक एक केन्द्र बुलन्दशहर में खोलने की व्यवस्था विचाराधीन है।

एफ—नया ग्रस्पताल खोलना—एक ग्रस्पताल खोलने की व्यवस्था थी जो प्रभी बहादुरनगर में खोला जा चुका है इसके ग्रलावा वर्तमान वर्ष मे २ पशु निरीक्षक केन्द्र बरौला व ऊंचा गांव मे खोले गए हे।

जी——बूट बाथ बनाना——५० बूट बाथ बनाने की योजना है। अवतक ४ बूट बाथ बन सके है।

एच—पशु प्रदर्शनी व मेले—पशुग्रों की उन्नति व गांव वालों को पशुग्रों के पालने के उत्साह दिलाने के लिए हमारा लक्ष्य कम से कम ४ पशु प्रदर्शनी प्रति वर्ष करने का है। ग्रव तक २७ मेले गत तीन वर्ष मे किये जा चुके है।

स्राई—दवाइयों के बक्स—जो स्थान पशु चिकित्सालयों से दूर है उनमे दवाइयो के बक्से विये जाते है। ४ बक्से वर्ष १९४२-४३ में विये जा चुके है। पांच वर्षों में ४८ बक्सों का प्रबन्ध करने की योजना है। इस वर्ष २४ बक्सों के लिये शासकीय स्मनुदान प्राप्त हुन्ना है।

सहकारी कार्यो की योजना

पंचवर्षीय योजना के म्रन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में सहकारी म्रान्दोलन की प्रगति के लिए सहकारी नलकूपों का निर्माण, सहकारी भट्ठों का खोलना, सहकारी कृषि फार्मों का चालू करना, सहकारी बीज भंडारों का खोलना तथा उनके भवनों का निर्माण करना सहकारी चकबन्दी समितियों का संगठन करना, तथा सहकारी भवन निर्माण समितियों का चलाना व सहकारी ग्राम समितियों का बनाना, ग्राम समितियों में सदस्यता बढ़ाना तथा उनके हिस्सों की पूंजी में वृद्धि करना है।

१—सहकारी नलकूप—जिले के लिए सन् १९५२ व ५३ मे १५ नलकूप स्वीकृत हुए थे जिनमें से निम्नलिखित नलकूपों के प्रस्ताव प्राप्त हुए ग्रौर उनको निम्न प्रकार से चालू करने की व्यवस्था की गयी:

कम सं०	नाम समिति	धन जो समिति ने जमा किया	तकावी जो दी गयी	विवरण
8	मडौना जाफराबाद	३,५४०	१०,०००५०	कार्य हो रहा है
२	केशवपुर राठला	7,000	१०,००० र०	2)
츳	परवाना महमूदपुर	१,०००	१०,००० ह०	"
x	सटाना ें " ु	7,000	१०,०००₹०	"
×	रूनसी	٧,000	१०,००० र०	,,
ĘĘ	दशहरा	313	१०,००० र०	>>
e),	दशहरा करौरा	7,000	१०,०००६०	77
Ę	भौं बहादरनगर	• १,२००	05000,08	"
3	उसमानपुर े	₹,000	₹0,000₹0	23
१०	डेरी मच्छा	3,800	१०,०००६०	H

श्म मं	ः नाम समिति	भन जो समिति तकावी जो ने जमा किया दो गयी विवरण
4 5	मकोंडा	२,५०० १०,००० कार्य हो रहा है।
92	रुक नपुर	२,००० १०,०००६० "
१३	वचयोली	२,००० १०,०००च० "
१४	नगर	२,००० १०,०००₹० ,,

इन नलकूपों का निर्माण कृषि इंजीनियरिंग विभाग की देख रेख में हो रहा है। स्नाज्ञा हूं कि स्रिधकांज्ञ र्यूबवेल इस वर्ष जून तक बन कर तैयार हो जायेंगे। वर्ष १९५३ व ५४ में जिले के लिए इस योजना के अन्तर्गत १० कुए स्वीकृत हुए थे। परन्तु प्रार्थना पत्रों की कमी के कारण केवल प्र नलकूपों को बनाने की योजना रखी गयी। शेष २ शासन को वापस कर दिये गए।

२—सहकारी भट्टों का निर्माण-निम्नलिखित सहकारी संस्थाग्रों ने ग्रपने भट्टे १६५२ व ५३ तथा १६५३,५४ में चलाने की व्यवस्था की है।

ऋम सं०	नाम संस्या	स्थान जहां खोले गये	वर्ष	विवरण
8	सहकारी संघ, श्रौरंगाबाद	श्रौरंगाबाद	१९५३-५४	चालू है। कोयले की
१	सहकारी संघ, कुचेसर	कुचेसर	१९५३-४४	कमी के कारण चालू नहीं हुग्रा। कोयले का इंतजाम किया जा रहा है।
ş	सहकारी समिति, दानपुर	दानपुर	१९५२-५३	चालू है। चालू है। चालू है।
8	सहकारी संघ, खुर्जा	खुर्जा शहरा	१९५२.५३	चालू है।
ሂ	कन्ज्यूमर्स सोसाइटी, खुर्जा	खुर्जा	१९५३-५४	चालूं है।
Ę	जिला विकास संघ, बुलॅन्दशहर	लानपुर	१९४३-४४	कोयले की कमी के कारणकार्य रुका हुन्ना है। कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है।
૭	कंज्यूमर्स स्टोर, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	१ ६ ५२–५३	चालू है। चालू है।
5	ग्राम समिति नासिरपुर, भेसरौली	नासिरपुर	そとメラーメメ	चालू है।
	दम योजना के ग्रन्तर्गत वर्ष १६	प्रदासक २०३	न्दरे खोलने की	योजना है ।

इस याजना क ग्रन्तगत वष १६५६ तक २० भट्ट खालन का याजना ह।

३-- सहकारी कृषि फार्मिंग सिमिति-योजना के अन्तर्गत साल १६५२,५३ में एक समिति खोली गयी जिसका विवरण इस प्रकार है --

ऋ० सं०	नाम समिति	तावदाद मेम्बर	सरकार कर्ज जो मेम्बर	दारा कोलिला	निर्ज पूजी	। भूमि फार्म	जो में है
१−−िन	ाष्ट्रान्त व्यक्तियों (की सहकारी सरि		२४,४६४ ६०	७,३१६	হ ০	२३२	एकड्

४--सहकारी बीज भंडार-इस योजना के पूर्व इस जिले में कृषि विभाग के १३ बीज भंडार सहकारी विभाग को १६४८ में प्राप्त हुए थे।

इनके ग्रतिरिक्त सन् १६४०,५१ में ३ बीज गोदाम कानपुर, करौरा तथा कुचेसर में खोले गए, जिनमें कार्य ग्रारम्भ किया गया परन्तु गोदाम, मौबहादुरनगर से ग्रति समीप होने के कारण सन् १६५२,५३-में बन्द कर देना पड़ा। उपरोक्त १५ बीज भंडारों मं ग्रपने निजी भवन निर्माण ग्रथवा क्य कर लिए है।

इसके म्रतिरिक्त समस्त बीज भंडारों र्पर पूर्ण रूप से 'ए' क्लास बीज बनाया जा रहा है, जिनमें ४० प्रतिशत 'ए' क्लास हो चुका है ग्रौर शेष ३ वर्ष में पूरा हो जायगा ।

- ५—सहकारी चकबन्दी सिमितियां—इस योजना से पूर्व जिले में ६ सिमितियां बन चुकी थी जिनमें चकबंदी का कार्य समाप्त हो चुका था। इस योजना के ग्रन्तर्गत ग्राम परथला, खंजरपुर, सुरजावली व चरौरा में कार्य चल रहा है।
- ६-सहकारी भवन निर्माण समितियां—इस योजना के पूर्व इस जिले मे ७ समितियां खोली जा चुकी थीं जिनमें से निम्न २ समितियों में भवन निर्माण का कार्य भी चल रहा है।
 - (१) गवर्नमेंट एजूकेशनल श्राफीशियल हार्जीसंग कीश्रापरेटिव सोसाइटी, बुलल्दशहर
- (२) शिवपुरी श्राफीशियल कोश्रापरेटिव हार्डींसगृ सोसाइटी, बुलन्दशहर । इसके श्रतिरिक्त पुर्षार्थी व्यक्तियों की १ भवन निर्माण समिति श्रौर बनायी जा रही है।
- ७---ग्राम समितियां---४८५ ग्राम समितियों का निर्माण ३० जून, १६५३ तक हो चुका है। १-७-५३ से २८-२-५४ तक १७ समितियां श्रौर बनायो गयीं। यह समितियां श्रूपन सदस्या को सस्ते सूद पर कर्जा, बीज-यंत्र तथा खाद श्रादि वितरण करने का प्रबन्ध करती है।
- द—सदस्यता में वृद्धि—साल १६५२, ५३ तक सहकारी संस्थास्रों के सदस्यों की संख्या १८,६०१ थी, जिनमें १-७-५३ से २८-१-५४ तक ३६८ सदस्यों की वृद्धि की गयी है।

हिस्से की पूंजी में वृद्धि—साल १९४२, ४३ के अन्त में ३,१३,०४० रु० इस मद में था १-७-४३ से २८-२-४४ तक १३,६४१ रु० हिस्से की पूंजी में भ्रौर बढ़ाया जा चुका है।

जन-स्वास्थ्य कार्यों की योजना तथा प्रगति इस प्रकार है

ग्रस्पतालों की व्यवस्था गत तीन वर्षों में राजघाट, दादरी, भौंबहादुरनगर, जेवर, ककोड़, बरोसा सेंदपुर श्रौर थोरा में ऐलोपैथिक श्रस्पताल खोले गए। शिकारपुर में एक नया प्राइवेट वार्ड खोला गया। एक नया जनाना श्रस्पताल १९५३ में श्रनूपशहर में खोला गया। श्रायुर्वेदिक श्रौषघालय जहांगीरपुर, बिसरल, ऊंचागांव तथा खानपुर में स्थापित किए गए। जिले के सदर श्रस्पताल में भी श्रावश्यक सामान बढ़ाया गया। शासन का विचार एक श्रस्पताल दनकौर में भी खोलने का है। वर्तमान वर्ष में रामघाट में एक श्रायुर्वेदिक श्रौवधालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

चक्षु सहायता शिविर लगाने की योजना के अन्तर्गन १९५१,५२ मे १९५२,५३ मे १९५२,५३ मे १९५२,५३ मे १९५२,५३ में प्रतिवर्ष दो-दो कैम्प जिला चक्षु निवारण समिति द्वारा गांधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ की सहायता से चलाये गये। आगामी २ वर्षों में ४ कैम्प और लगाने की योजना है।

बी०सी०जी० के टीके—१६५२,५३ में २०,४०६ व्यक्तियों के तपेदिक से बचाव के लिये टीके लगाये गए तथा ६२,२५१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया।

मलेरिया निरोधक कार्य—इस योजना के ब्रन्तर्गत सन् १६४२,४३ में ४०० मलेरिया प्रसित प्रामों को दवा छिड़कने के लिये चुना गया और अधिकांश ग्रामों में दवा छिड़कवाई गयी। सन् १६४३,४४ में पुनः उन्हीं ग्रामों में दवा छिड़काई गयी।

नित्थयां ३४५

भयानक रोगों की रोकथाम—सन् १६५२ मे ३२,००४ तथा १६५३ मे १,०२,८८६ टॉके स्वास्थ्य विभाग द्वारा हंजे की रोकथाम के लिये लगाए गये। सन् १६५१-५२ में ६२.६१५ तथा १६५२-५३ मे १,०१,२४६ टीके चेचक के लगाये गये।

ज्ञा-बच्चा केन्द्र--इस समय जिले मे ४ सरकारी तथा ३ ग्रन्य केन्द्र खुले हुए हैं। यंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत जिले मे ४ ग्रन्य केन्द्र खुलने की ग्राजा है।

सड़कें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य

सार्वजिनक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा स्थानागढ़, बुलन्दशहर, श्रन्पशहर, श्रन्पशहर, श्रन्पशहर, श्रन्पशहर दुराहा, डिवाई स्टेशन रोड, खुर्जा जेबर दनकोर, से दनकोर रेलवे स्टेशन तथा बुलन्दशहर से झाझर जाने वाली जिला बोर्ड द्वारा सौंपी गई १०६ मील ४ फर्लाग सड़कों की मरम्मत तथा सुधार का कार्य १९५२ तक किया गया। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत स्थाना बुगरासी सड़क को जो कि ४ मील ६ फर्लाग लम्बी है मिट्टी डालकर चौड़ा तथा ऊंचा किया जा रहा है श्रौर उस पर पुलियां बनवाई जा रही है। इम सड़क के तीन मीलों पर मिट्टी का कार्य गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में अमदान द्वारा कराया गया है, जिमका श्रनुमानित मूल्य १२,००० ६० से श्रधिक है।

डिवाई स्टेशन सड़क (राम घाट)—इस सड़क पर जिला बोर्ड तथा नियोजन विभागद्वारा श्रमदान में मिट्टी का कार्य वर्तमान वर्ष में कराया जा रहा है। जिला बोर्ड ने भी इस सड़क के लिए कुछ धन स्वीकृत किया है।

जिला बोर्ड तथा जिला नियोजन सिमित के संयुक्त प्रयास से स्थाना से सठला भौंबहादुरनगर होती हुई कुचेसर तक ११ मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य १६५१ में आरम्भ हुआ था। जिला बोर्ड ने अभी तक इसके ३ मील पक्के कराये हैं और ६ मील में आवश्यक पुलों का निर्माण कर्युया है। इस समय जिला बोर्ड इसके १ मील को और पक्का करा रहा है। इस सड़क के लगभग ३ मील जिला नियोजन सिमिति हारा पक्के कराये जा चुके हैं और एक बड़े पुल का निर्माण कराया गया। गत वर्ष तथा इस वर्ष इस मड़क के ४ मीलों पर अमदान हारा लगभग ५,००० र० की लागत का मिट्टी का कार्य हुआ। इसमें से २ मील और पक्का कराने की योजना है। इस सड़क के लिये कुल २०,००० र० १०५२-५३ में तथा २५,००० र० १६५३-५४ में शासन हारा दिया गया है। जिले के विकास कार्यों में इस सड़क का निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गत वर्ष में कुल ६७८ मील सड़कों का पुनःनिर्माण हुआ तथा २६४ मील रास्तों को समतल व साफ करके सुधार किया गया।

यातायात सम्बन्धी योजनायं तथा प्रगति

सन् १६५१-५२ ५३ में कोई नयी सर्विस पूर्णतः रोडवेज द्वारा नहीं ली गई। सन् १६५३-५४ में दिल्ली बुलन्दशहर स्विस को लेने की योजना अवस्य थी। वर्ष १६५४-५५ में खुर्जा जुवर तथा अलीगढ़ अनूपशहर भ्रौर मेरठ बुलन्दशहर की सर्विस लेने की योजना है। वर्ष १६५४-५६ में बुलन्दशहर, अनूपशहर तथा बुलन्दशहर स्यानागढ़ मुक्तेश्वर स्विस को लेने की योजना है। यातायात का राष्ट्रीकरण घीरे घीरे किया जावेगा। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक ऐसी सुगमतायें अस्तुत की जा रही हैं जो पहलें कभी प्राप्त नहीं थीं।

शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सन् १६४१-५२ में जिले में २५ विद्यालय थे। लक्ष्य यह है कि १६५५-५६ तक ३३ विद्यालय बालकों के लिये हो जायेंगे। १६५१-५२ में बालिकाओं के २ विद्यालय थेजो कि १६५५-५६ में ४ हो जावेगे। जूनियर हाई स्कूल १६५१-५२ में बालकों के लिये ३६ थे। १६५५-५६ में यह संख्या बढ़कर ६८ हो जावेगी।

प्राइमरी विद्यालयों की संख्या १६५१-५२ में ४३७ थी यह संख्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४६४ हो जावेगी।

बालिकान्रों के लिये १६५१-५२ में केवल जूनियर हाई स्कूल थे। १६५५-५६ तक यह संख्या ६ हो जावेगी। बालिकान्रों के १६५१-५२ में १४ प्राइमरी विद्यालय थे जो १६५५-५६ में बढ़कर ४० हो जावेंगे।

विद्यालयों के लिये खेती की शिक्षा देने के लिये शासन द्वारा प्रध्यापकों का प्रबन्ध किया जा रहा है ग्रौर श्रावश्यक जमीन इत्यादि को भी उपलब्ध करने को योजना है।

बुलन्दशहर कृषि विद्यालय में ग्राम सेवकों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताम्रों के लिये बहुधन्धी शिक्षा देने हेतु क्रमशः ६ मास तथा ४ मास की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता शिक्षा पाते हैं। इस समय इसमें कार्य कर्ताम्रों का तीसरा दल शिक्षा पा रहा है। कार्यकर्ताम्रों को वैभागिक कार्य की जानकारी के म्रतिरिक्त देहातों में जाकर भ्रौर रहकर कार्य करने की शिक्षा दी जाती है भ्रौर सब कार्यों को हाथ से करने का म्रम्यास कराया जाता है:

घरेल उद्योग

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जिला नियोजन समित की एक उपसमिति का निर्माण शासकीय ब्रादेशानुसार किया गया है। जिला नियोजन समिति ने ३,००० ६० उद्योगों के सहायता का प्रविधान वर्ष १९५३-५४ के बजट में कर दिया है।

बुलन्दशहर की पंचायत राज पंचवर्षीय विकास योजना के लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण

हमारा पंच-वर्षीय लक्ष्य १८७ पंचायत घरों का था। जिनमें से ३२ पंचायत घरों की व्यवस्था हो चुकी है।

गांधी चबूतरों का निर्माण—पंच वर्षीय योजना में १८७ पक्के तथा ६८५ कच्चे गांधी चबूतरे का लक्ष्य रक्षा गया था जिनमें से स्र्बूतक ६२ पक्के तथा ३१२ कच्चे गांधी चबूतरों का निर्माण हो चुका है।

पुस्तकालय व वाचनालय—पंच-वर्षीय योजना में १८७ पुस्तकालय तथा ६८४ वाच-नालयों की व्यवस्था रक्खी गई थी। ग्राम सभाग्रों द्वारा पूर्णतः संचालित १६ पुस्तकालयों में २४० पुस्तकें हैं श्रौर ग्राम सभाग्रों से श्रनुदान प्राप्त १७ पुस्तकालयों में ४७६ पुस्तकें हैं। इस प्रकार कुल पुस्तकालयों की संख्या ३३ है। प्रत्येक ग्राम सभा में प्रदेशीय पंचायत राज पत्रिका नियमित रूप से पहुंचती है पंचवर्षीय योजना की श्रविध में हमारा लक्ष्य यह था कि प्रत्येक गांव सभा में इस पत्र के ग्रतिरिक्त एक दैनिक पत्र भी पहुंचने लगे। परन्तु श्रायिक कठिनाइयों व धनाभाव के कारण इसकी प्रगति में बाधायें उपस्थित हुई हैं। जैसे ही गांव सभाग्रों की ग्रायिक स्थिति ठीक हो जावेगी, श्रिषक पुस्तकालय व वाचनालय चलाये जायेंगे।

रेडियो मनोरंजन तथा खेलकूद के साधन—योजना के ग्रन्तर्गत १८७ पंचायती श्रदालत केन्द्रों में रेडियो का प्रबन्ध करने, ६८५ ग्राम सभाओं में ग्रखाड़े चलान तथा १८७ पंचायतो ग्रदालती केन्द्रों में व्यायाम शालायें चलाने का लक्ष्य रक्षा गया है। ग्राम सभाओं द्वारा ग्रब तक ६२ रेडियो सेटों की व्यवस्था की जा

बुकी है। जन स्वास्थ्य के हेनु ६४२ अलाड़े तथा ११६ व्यायामशालाओं की स्थापना कर गई है। इन में में ३२ ग्राम सनाओं ते शासकीय अनुदान से खेल कुद का सामान वार्णावाल तथा मुगदर आदि देने का प्रबन्ध किया गया है। इस विशा में सब से महत्व पूर्ण प्रयास पिछले वर्ष किया गया जब कि ग्राम सभा पंचायती अदालत तथा निरीक्षक क्षेत्र पर प्रतियोगितायें कराई गई और जिला स्तर पर एक बृहत खेलकृद तथा संगीत समारोह आयोजित किया गया।

फसल प्रतियोगिता व उन्नितिशील बीज की योजना एवं कृषि सुधार—उन्निति-शील बीज योजना के ब्रन्तर्गत १८७ ग्राम सभाग्रों में उन्नितिशील गेहूं व डिब्लिंग रीति के प्रदर्शन किए गए। गत वर्ष पंचायतों द्वारा मूंग टाइप १ के प्रदर्शन किए गए। क्पाम २१६ एक के बीज का वितरण व प्रचार भी पंचायतों द्वारा किया गया।

पशु नस्त-सुधार के लिये सांडों का प्रबन्ध, पशु ग्रौषधि पेटिकाग्रों की व्यवस्था—पशु नस्त सुधार के लिये १०० सांडों को देने का लक्ष्य रक्खा गया था। ग्रब तक कुल ५४ सांडों की व्यवस्था हो चुकी है। पशु-चिकित्सा के लिए ४ गांव सभाग्रों के लिये पशु ग्रौषधि पेटिकाग्रो का प्रबन्ध किया गया।

सड़कों का निर्माण व मरम्मत—पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत १,२५५ मील कच्ची सड़कों का निर्माण एवं ७५० मील सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। इस सम्बन्ध में प्रगति के ग्रांकड़ों से स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लगभग पूरा हो सकता है। पंचायतों द्वारा विद्यालयों, प्रान्तीय रक्षक दल तथा ग्रन्य विभागीय कार्यकर्तात्रों की सहायता से ६७८ मील कच्ची सड़कों का पुनः निर्माण हुग्रा है। इस ग्रवि मे ३६४ मील से ग्रिधिक सड़कों को विस्तृत समतल व साफ किया गया।

पक्की नाली तथा खरंजों का निर्माण—पंचायती श्रदालत क्षेत्र को इकाई मानकर पंचवर्षीय योजना में १८७ मील पक्की नाली व खरंजों के निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया है। ३ मील २ फर्लाग खरंजों का निर्माण कार्य श्रभी सम्पन्न हुआ है। वर्तमान वर्ष में नियोजन समिति द्वारा आर्थिक श्रनुदान प्राप्त होने के कारण इस दिशा में श्रच्छी प्रगति होने की सम्भावना है।

पुलों तथा पुलियाओं का निर्माण—इस योजना मे २०० पुलियों का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा मे स्नाश्चर्यजनक प्रगति हुई है। १५५ पुलियाओं का निर्माण हो चुका है।

रोशनी का प्रबन्ध —ग्रामों मे रोशनी के प्रबन्ध के लिये पंचायतों ने सार्वजनिक लालटेनों की व्यवस्था की है। योजना मे ५ लालटेन प्रति ग्राम सभा के हिसांब से जिले में ६८५ ग्राम सभाग्रों में ३,४२५ लालटेनों का लक्ष्य रक्ला गया था। श्रव तक कुल १,६४५ लालटेनों का प्रबन्ध हो चुका है। जिस का ग्रर्थ यह है कि ग्रौसतन २ लालटेन प्रत्येक गांव सभा में लग चुकी है।

मेटरिनिटी चैस्ट तथा श्रौषिध पेटिकाश्रों की व्यवस्था—जन स्वास्थ्य के हेतु पंचायत राज योजना में ६८५ श्रौषिधि पेटिकाश्रों का लक्ष्य था। श्रव तक कुल २०२ श्रौषिध पेटिकाश्रों का प्रवन्ध हो चुका है।

पानी पीने के कुओं की मरम्मत—ग्रामों मे शुद्ध जल की व्यवस्था के लिये इस योजना में १,३७० कूपों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। जिनमे से ग्रव तक ४०० से श्रविक कूपों की मरम्मत की जा चुकी है। इसके ग्रतिरिक्त नए कुओं के निर्माण के जिये इँट, सीमेंट का प्रवन्य कंन्ट्रोल दरों पर किया जाता है।

खाद के गड्ढे तथा सोखते—सफाई के हेतु २,००० सोखते तथा १४,००० घूरों की खाद के गड्डों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रक्षा गया था। स्रव नक ६०० सोखते व ७,७४१ खाद के गड्डे बनाये जा चुके हैं।

सफाई सम्बन्धी उपनियम—ग्रामों में सफाई का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व गांव सभाग्रों पर है। श्रतएव ग्राम सभा द्वारा सफाई सम्बन्धी उपनियम बनाये गये हैं। इन उपनियमों को जिले की समस्त ग्राम सभाग्रों द्वारा पास करा कर लाग् किया जायेगा। इस समय केवल २६ गांव सभाग्रों मे यह उपनियम लाग् किए जा चुके हैं।

बुलन्दशहर की पंचायतों द्वारा गत २ वर्षों में पंचायत कर वसूली मे संतोषजनक प्रगति दर्शाई गई है। इस समय ५६ प्रतिशत कर वसूल किया जा चुका है।

प्रान्तीय रक्षक दल तथा जन शक्ति संगठन योजना

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र पर स्थित जोन वर्करों की देखरेख में प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र पर एक हल्का सरदार की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में १ ग्रूप्न नीडर ग्रौर ११-११ रक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रभी तक हल्का सरदारों की नियुक्ति तो सम्पूर्ण हो पाई है। परन्तु ग्रूपलीडर व सेक्शन लीडर ग्रौर रक्षक कमशः २१,५१० व ६२१ व ७,७६७ हो पाये है। प्रान्तीय रक्षक दल के अवैतिक तथा वैतिक , कर्मचारियों की मदद से ५ वर्षों में ६० विकास तथा शिक्षण शिविर योजना करने की योजना है। गत तीन वर्षों में ३२ शिविरों का ग्रायोजन सफलता पूर्वक किया जा चुका है। इन शिविरों की देख रेख में सड़कों का बनाना, रास्तों का चौड़ा करना, तथा समतल करना, नाली निर्माण, खाद के गड़ढे बनाना प्रामों की सफाई, सुरक्षा समितियों का संगठन, खेलक्द प्रतियोगिताग्रों का ग्रायोजन इत्यादि कार्ये कराये जाते हैं। गणतन्त्र दिवस १६५३ के ग्रवसर पर जो ग्रान्दोलन हुग्रा उसके फलस्वरूप जिले को अमदान कार्यों में २०,००० ६० प्रदेशीय पुरस्कार प्राप्त हुग्रा। वर्तमान वर्ष में लगभग गणतन्त्र दिवस अमदान ग्रान्दोलन में ३०२ मील ४ फ० सड़कों का पुनः निर्माण हुग्रा। ग्रान्दोलन है कि इन सड़कों पर १,६०,४६,६३१ घनफीट मिट्टी का कार्य हुग्रा। गत तीन वर्षों में ६,७ लाख रुपयों से ग्रिक्त के अमदान का कार्य हो चुका है। यह सब कार्य जनता तथा विभागीय कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग में संपन्न हुए।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा जन स्वास्थ्य सम्वर्धन हेतु खेलकूद प्रतियोगिताश्रों का स्रायोजन कराया जाता ह। गत ३ वर्षों में २५ स्थानों पर दंगल तथा २८ स्थानों पर प्रतियोगिताश्रों का स्रायोजन किया गया। जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन ग्रामों की रक्षा के हेतु २४ की संख्या में ३ वर्ष में संगठन कराया गया।

हरिजन उद्धार सम्बन्धी कार्य

जिले में हरिजन सहायक सिमिति की देखरेख में हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कियों की व्यवस्था करना, हरिजनों के मकानों के लिए प्राप्त शासकीय भ्रनुदान का वितरण करना, गृह उद्योग घंघों को प्रोत्साहन देकर भ्रार्थिक उन्नति इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

सन् १९४१-५२ में नियोजन विभागद्वारा कुयें बनाने के लिये उचित दर पर इंट तथा सीमेंट की व्यवस्था की गई झौर २७ नयें तथा ११ पुराने कुग्नों के लिये सामान दिया। १९५२-५३ में ५१ नये कुग्नों का निर्माण हुग्ना तथा १६ कुग्नों की मुरम्मत हुई। १९५३-५४ में ग्रनुदान स्वरूप तथा स्वयं निर्मित कुग्नों की संख्या ३१ प्र'र मरम्मन किये जाने वाले कुन्नों की संख्या ३६ ह। हमारा लक्ष्य है ५ वर्ष में २०० नये कुन्नों का निर्माण तथा २०० कुन्नों की मरम्मत करना। गत लेच बर्चों में शामन में जिले को प्रतिवर्ष सात हजार रुपये इस कार्य के लिये श्रमुदान प्रचार हुए है। श्रमुदान के श्रतिरिक्त २५१ व्यक्तियों को उचित मुल्य पर ईट, सैमेट का प्रवन्ध किया गया।

हरिजनो को मकानों सम्बन्धी मुविधा देने के लिये १.००० ह० का ग्रनुदान वर्षे १६४३-४४ में दिया गया।

ृह-उद्योग के लिये १.४४० रु० १६४२-४३ में तथा १६४३-४४ में १,०४० रु० के महायता हरिजनों को दी गई। विश्वास है कि पंचवर्षीय योजना के स्रन्त में ७.२४० रु० का स्रनुदान इस मद में वितरित हो जावेगा।

हरिजन सहायक समिति द्वारा श्रायोजित सम्मेलनों, प्रचार कार्यो इत्यादि विभिन्न व्यय के लिये शासन से २,००० ६० की सहायता प्राप्त हो चुकी है। पिछले ३ वर्षों मे १८ सम्मेलन कराये गये ह। श्रौर भविष्य मे भी कराने की योजना है।

हरिजनो की शिक्षा की ग्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। १२वे क्लास तक के विद्यार्थियो को छात्रवित्तयां देने तथा ग्रन्य सहायता दी जाती है। जिला बोर्ड तथा नगर पालिकान्नों को भी छात्रविनयां देने के लिये शासन से ग्रनुदान प्राप्त होता है। इसी प्रकार ग्रन्य विद्यालयों में हरिजनो विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के हेतु ग्रनुदान दिया जाता है।

नत्थी 'ग'

(देखिये ताराकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर।) जिला होंडा ने नरबगंज तहसील में होने वाले विकास कार्यों की सूची

- १—नवाबगंज के निकटवर्ती क्षेत्र मे १० बड़े सहकारी ट्यूबवेल ग्रौर सरज् रेलवे स्टेशन के पास एक वड़ा सहकारी ट्यूबवेल लग रहा है।
- २—- बुजेनपुर तथा नगदही गांव में टेढ़ी नदी पर १६,००० रुपये की लागत के पुल का काय श्रारम्भ किया जा चुका हें, मिट्टी डाली जा चुकी हें। यह कार्य गांव पचायत द्वार श्रमदान मोर दान के वल पर हो रहा है। इसमें सरकार से श्राधिक सहायता भी दी जायती।
- ३—पसका. दुर्जनपुर, निहालपुर, रामगढ़, बुढ़ौलिया ग्राम सभाम्रो मे पचायत घर तथा बेलसर गाव सभा में पचायत घर एवं बीज गोदाम का निर्माण हो रहा है। कार्य एक चाथाई शेष है।
 - ४---नवाबगंज मे एक पाठशाला भवन का निर्माण हो रहा है।
- ४—प्राम सभा मसौलिया , मलांव, ज्ञानपुर, बेलसर, परसपूर दुर्जनपुर, निहालपुर, सिघोटी में एक-एक छोटे-छोटे ट्यूबवल लग रहे ह। दो कुवो में इंजन भी लग गये ह। गाव पंचायत बड़नापुर, झादमपुर, उमरी वेग मांज, कादीपुर मरच।र में भी छोटे ट्यूब वेल लगाने का विचार है।
- २—गोडा जिले की तहसील तरबगंज में दो पंचायत निरीक्षक क्षेत्र तथा ६० पंचायती स्रदालत क्षेत्र ह । प्रत्येक पंचायती स्रदालत क्षेत्र विकास कार्यों के लिये इकाई मानी गई है। गाव में विकास कार्य प्रत्येक क्षेत्र के विकास सिमित्त के बनाये हुये योजनाश्रो के श्रनुसार हो रहे ह । इन योजनाश्रो के श्रनुसार निम्नलिखित विकास कार्य इस तहसील में हुश्रा ह :

सड्को का निर्माण ११ मील २ फर्लाग ७० गज। सड़कों की मरम्मत १६ मील ४ फर्लाग १८० गज। पंचायत भवन का निर्माण चार (४) पुलिया का निर्माण •• पांच (४) गांधी चवुतरों का निर्माण . . • • ग्रड़तीस (३८) नालों की खुदाई • • ६६३३ गज बंधियों का निर्माण • • चार (४) सोख्तों का निर्माण · - तिहत्तर (७३) कच्चे घर को पक्का करना • • एक सौ ग्रठाईस (१२८) सुरक्षित पानी पीने के कुश्रों का निर्माण .. पैतीस (३५) पुस्तकालय की स्थापना ... •• चार (४) क्रीड़ास्थल की स्थापना ... एक (१) कम्पोस्ट गड्डे का निर्माण ... • • छ सौ छियासठ (६६६)

लगभग २५,००० मन प्रेस्ड कम्पोस्ट प्रतिवर्ष तैयार होती है।

हड पम्प लगाये गये तीन (३) वृक्षारोपण (फलदार) ग्राठ सौ तिरसठ (८६३) (ग्रन्थ) .. उन्नीस सौ बहत्तर (१९७२)

इस वर्ग ४३,७६१ मन उन्नतिशील गन्ने के वीजों का वितरण किया गया। ७ छोटे पंपिंग सेट वितरित किये गये।

१६७ विभिन्न प्रकार के श्रीजारों का वितरण किया गया। २,१०७ मन खाद वितरित की गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये नारांकिन प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पट २=० पर)
प्रजीपुर नथा इलाहाबाद जिले के पहण्ड़ी इलाके के जिलामियों को जमींदारी
उन्मलन के पूर्व जो विद्येग मुविधाये प्राप्त थी स्रोर को समान
लेने की मुविधाये थीं उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पूला, घाम, कांटे डेन्यादि
	₹	3	४
	धनी जमींदार गायों	एक निर बोझ लकड़ी	ज्यादातर उमींदार लोग
	की चराई का कुछ नहीं लेते थे। दूमरे जानवरों की चराई का निर्ला । में १) तक फी जानवर था।	का दाम () में इ) नक निया जाता था। इन मह- मुल का दर ठेकेदार जो जमीदारों में एक मुस्त जंगल खरीदते थे तय करते थे।	बांस इसरती लकड़ी तथा फम इत्यादि जो घर बनाने के कार्य में आता ह उसका के इं शुल्क नहीं लेते थे। इसके अलावा ओर कामों के लिये अगर वन उपज ली जाती थी तो उन लोगों से जमींदार निम्नलिखिन दः में दाम लेते थे। १०० बांस-॥ में २) तक। एक हल के लिये पूरी लक्ष्णी॥ कांटों इत्यादि के लिये कुछ नहीं लेते थे।
<u>श्ना इलाहाबाव</u>	करछना तहसील में जमींदार जंगलों को नीलाम कर दिया करते थे ग्रौर ठेके- दार निम्नलिखित दर से चराई लेते थे।	मफ्त मिलती थी	करछना में हल तथा झोपड़ी वग्रं रा बनाने के लिये लकड़ी मुफ्त मिलती थी। मेजा तहसील में इमारती लकड़ी मुफ्त मिलती थी। बांस कड़ी इत्यादि ३) प्रति वर्ष की दर में ली जा सकती थी। इसकी मात्रा कोई निञ्चित नहीं थी।
	सितम्बर-ग्रक्तूबर तक के लिये गाय व बैलों का—।॥ भैसों का—१॥		पूला व घान वगरा फी गाव के लिये नीलाम कर दिया जाता था। दाम नाम मात्र के लिये बहुत कम होते थे।
	इसके उपरान्त में जनवरी तक के लिये, बैल—१) भैस—२) श्रन्य स्थानों में कोई चराई नहीं ली जाती थी।	गाय व	

नत्थी 'ङ' (देखिये तारांकित प्रश्न का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी वन त्रिभाग की स्रोर से मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निव सियों को जो सुविधाये प्राप्त हे स्रौर जो सामान जिन शर्तो या मूल्य पर मिलते है उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लक्ड पूला, घास कांटे इत्यादि	श्रन्य रियायते
१	२	₹	Å	પ્ર દ
जिला मिर्जापुर १—सोन फारें स्ट डिवीजन	१- गाय मुफ्त २-बैल मुफ्त कृषि कार्य के लिये २ ग्रा॰ ग्र-य बैलों के लिए ३-भैस ४ ग्रा॰ प्रति वर्ष ४-भेंड़, बकरी १२ ग्रा॰ प्रति वर्ष ५-ऊंट ३ ६० प्रति वर्ष ३० ६० प्रति वर्ष ३० ६० प्रति वर्ष १ ६० प्रति वर्ष भ-घोड़ा ४ ग्रा॰ प्रति वर्ष	वालों को मुफ्त ार्ष	लकड़ी (पूरा सामान) ४ ग्रा० प्रति हल बॉस १ से १०० तक द्र ग्रा० प्रति संकड़ा। बांस १०१ से ५०० तक १ ६० संकड़ा।	२-चमड़ा १ ६० ४ म्रा० सिझाने की प्रति म्रदमी पत्ती। ३-डेकुलावन १ ६० ४ म्रा० तेलियों के प्रति म्रादमी लिये। ४-डेकी चावल १६० ४ म्रा० कूटने के लिये प्रति म्रादमी

नम इन	म् चराई	जनाने की लकड़ी	इमारनो लकड़ी. पूला, घाम, कांटे इत्यादि
?	P	3	8
	चारे की घाम नि इस्तेमाल के लिय मुफ्त ।	ये माल के लिये मुफ्त फी घर फी साल तेंदू, ककोढ़, बेर, धवल घंटा, करि तथा मनार इत्यादि के १०० पेड़	कांटे. फुल, फल तथा घर के लिये लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिए मुफ्त ।
		मुफ्त ।	मरम्मत व मकान बनाने मरम्मत व मकान बनाने की लकड़ी फी घर हर नीन साल साल, श्रासा तेंडु या सीघा का एक पेड़ जो मोटाई २४३' होमुफ्त। दूसरे प्रकार के १२ पेड़ जो १४ + ११२' के होंमुफ्त। हल वर्गरा बनाने के लिये लकड़ी। २ पेड़ कोकट के जो ११/२४२ के होंमुफ्त। २ पेड़ कोकट के जो ११/२४२ के होंमुफ्त। बांस छत छाने तथा घरा घरने के लिये।

		المبيد المراجع والمنتسوس		والمراجع المراجع المرا	
नाम इलाका	चराई	जलाने व	ने ल कड़ी	इमारती लकड़ी, पत्ता घास, कांटे इत्यादि	ग्रन्य रियायते
				बांस, छत घेरने तथा घेरा घेरने के लिये १०० बांस फी घर एक साल में मुफ्त	
जिला इलाहाबाद	फी साल प	ती जानवर	पुरानी रिया- यतें बदस्तूर रहेगी	पुरानी रिया- यतें बदस्तूर रहेंगी	पुरानी रिया- यतें बदस्तूर रहेंगी
	गाय	१ म्रान	•		•
	वैल	۰۰ ۶ "			
	भैस	¥ "			
	भेंड	? "			
	बकरी	ربي لا بم			
	घोड़ा या	-			
	अंट	•• ३ रु०			
	हायी ३००	रु० साल या	१ रु०		
	प्रति दिन		^ >		
		जानवर्गे के	लिये		
	महसूल वृ	गुना होगा।			

उत्तर भदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

विवात सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रध्यक्ष, श्री ग्रात्माराम गीविन्द खेर की ग्रध्यक्षता में ग्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

ब्रांसमान सिंह, श्री म्रक्षयवर सिंह, श्री प्रजीज इमाम, श्री ब्रनन्त स्वरूप सिंह, श्री म्रब्दुल मुईज खां, श्री ग्रब्दुल रऊफ खां, श्रो ग्रमरेश चन्द्र पांडेय, श्री ग्रमृत नाथ मिश्र, श्री श्रली जहीर, श्री सैयद भवषशरण वर्मा, श्री भ्रवषेशचन्द्र सिंह, श्री भवषेशप्रताप सिंह, श्री ग्रशरफ़ ग्रली खां, श्री म्राशालता व्यास, श्रीमती इरतजा हुसैन, श्री इस्तफ़ा हुसैन, श्री उदयभान सिंह, श्री उमाशंकर, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री उम्मेद सिंह, श्री उल्फर्तासह चौहान निर्भय, श्री ऐंबाब रस्ल, श्री श्रोंकारसिंह, श्री कन्हेयालाल, श्री कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री कमला सिंह, श्री कमाल ग्रहमद रिज्ञदी, श्री करन सिंह, औ ऋस्याणकृत्व मोहिले उपनाम खन्नत गुर, श्री

कल्याणराय, श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री कालीचरण टंडन, श्री काशीप्रसाद पांडेय, श्री किन्दरलाल, श्री किशनस्वरूप भटनागर, श्री कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री कृपाशंकर, श्री कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री कृष्णशरण ग्रार्य, श्री केवलसिंह, श्री केशभान राय, श्री केशवगुप्त, श्री केशव पांडेय, श्री कॅलाशप्रकाश, श्री खयालीराम, श्री खुशीराम, श्री खुबसिंह, श्री गंगाधर, श्री गंगाघर जाटव, श्रो गंगाधर शर्मा, श्री गंगात्रसाद, श्री गंगाप्रसाद सिंह, श्री गज्जूराम, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री गर्जेशप्रसाद जायसवाल, श्री गजेशप्रसाद पांडेय, श्री गिरजारमण शुक्ल, श्री गुप्तार्रासह, श्री गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री गलजार, श्री गेंदासिंह, श्री गोवर्घन तिवारी, श्रो गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री गौरीराम, श्री घनश्यामदास, श्री चन्द्रभान् गुप्त, श्री चन्द्रवती, श्रोमती चन्द्रसिंह रावतः श्री चन्द्रहास, श्री चरणींसह, श्री चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री चिरंजीलाल पालीवाल, श्री चुन्नीलाल सगर, श्री छेद।लाल, श्री छेदालाल चौघरी, श्री जगतनारायण, श्री जगदीशप्रसाद, श्री जगदीशसरन रस्तोगी, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री जगन्नाथ बख्श दास, श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री जगपति सिंह, श्री जगमोहन सिंह नेगी, श्री जटाशंकर शुक्ल, श्रो जयराम वर्मा, श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री जवाहर लाल, श्री जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर जगल किशोर, श्री जोरावर वर्मा, श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री झारखंडेराय, श्री टीकाराम, श्री डालचन्द, श्री तिरमलसिंह, श्री तुलसीराम, श्रो तुलाराम, श्री तुलाराम रावत, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री तंजबहादुर, श्री वजासिह, श्री त्रिलोकीनाथ कौल, श्री इयालदास भगत, श्री

। दर्शनराम, श्री दलबहादुर सिह, श्रो दाऊदयाल खन्ना, श्री दोनदायलु शर्मा, श्री दीपनारायण वर्मा. श्री देवकीनन्दन विभव. श्री देवदत्त मिश्र, श्री देवनन्दन शुक्ल, श्री देवमूर्ति राम, श्री देवराम, श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री धनुषधारी पांडेय, श्री धर्मसिंह, श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री नबदेवशास्त्री, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री नरोत्तमसिंह, श्री नवलिकशोर, श्री नागेश्वर द्विवेदी, श्री नाजिमग्रली, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री नारायणदास, श्रो नारायणदोन वाल्मीकि, श्री नेकराम शर्मा, श्री नौरंगलाल, श्री पद्मनाथसिंह, श्री परमानन्द सिन्हा, श्री परमेश्वरीराम, श्रो परिपर्णानन्द वर्मा, श्री पहलवार्नासह चौधरी, श्री पातीराम, श्री पुत्त्लाल, श्रो पुद्दनराम, श्री पुलिन विहारी बनर्जी, श्री प्रकाशवती सूद, श्रीमती प्रतिपाल सिंह, श्री प्रभाकर शुक्ल, श्री प्रभू दयाल, श्रो प्रेम किशन खन्ना, श्री फजलूल हक, श्री फतेह सिंह राणा, श्री बद्रीनारायण मिश्र, श्री बलदेव सिंह, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बझीर ग्रहमद हकीम, श्री वसन्त्रत्तं. श्री वस्तननाल इमा. श्री बाबुनन्दस. श्री बाबूनान जुमुमेदा. श्री बद्धलन मीनन श्री बालेन्द्रशह. महाराजकुमार विश्मवर मिह. श्री बेचनराम, श्री बेनीसिंह. श्री बजनायप्रमाद मिह. श्री ब्रह्मदन दीक्षिन, श्री भावतीदीन निवारी श्री भगवनीप्रमाद जुक्ल. श्री (वारावकी) भगवानदीन वान्मीकि. श्री भगवान महाय. श्री भोममेन, श्री भुवरजी. श्री भूपानसिंह खाती. श्री भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री भोलासिंह यादव, श्री मकमूदग्रालम खां. श्री मंगलाप्रसाद सिंह. श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी. श्री मयुराप्रसाद पांडेय. श्री मदनगोपाल वद्य, श्री मदनमोहन उपाध्यायः श्री मन्नीलाल गुरुदेव, श्री मलखात सिंह, श्री महतूद भ्रली खां, श्री (रामपुर) महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) महाराज सिंह, श्री महावीरप्रसाद शुक्ल. श्री महावीरसिंह, श्री महोलाल, श्रो मान्घाता सिंह, श्री मिजाजीलाल, श्री मिहरबान सिंह, श्री मुन्नूनाल, श्रो मुरलोघर कुरोल, श्री मुस्ताक़ ग्रली खां, श्री मुहम्मद ग्रब्दुल लतीफ, श्री मुहम्मद इब्राहोम, श्रो हाफिज मुहम्मद तक़ी हादी, श्री मुहम्मद नसीर, श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री मोहनलाल, श्री मोहनलाल गौतमः श्री मोहनसिंह. श्री मोहर्नामह शाक्य, श्री यमुनानिहः श्री यशोदादेवी, श्रीमनी रघुनाथप्रमाद, श्री रघुराजीसहः श्री रघुवीर सिंह श्री रमेशचन्द्र शर्मा, श्रो रमेश वर्मा श्री राघवेन्द्रप्रनाप सिहः राजा राजिकझोर राव, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राजवंशी, श्री राजाराम किसान, श्री राजाराम मिश्र. श्री राजाराम शर्मा श्री राजेन्द्रदत्त, श्री राघाकृष्ण श्रग्रवाल, श्री राघामोहन सिंह, श्री रामग्रघार तिवारी, श्री रामग्रधीन सिंह यादव, श्री रामग्रन्नत पांडेय, श्री रामग्रवध सिंह. श्री रामकिकर, श्री रामकुमार जास्त्री, श्री रामकृष्ण जैसवार, श्री रामगुलाम सिंह, श्री । रामचन्द्र विकल, श्री रामजीलाल सहायक, श्री रामजी सहाय, श्री 🤈 रामदान ग्रार्य, श्री । रामदास रविदास,श्री रामदुलारे मिश्र, श्री रामनरेश शुक्ल, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री रामप्रसाद, श्री रामत्रसाद नौटियाल, श्री रामप्रसाद सिंह, श्री । रामबली मिश्र, श्री 🕛 रामभजन, श्री रामरतन प्रसाद, थो रामराज शुक्ल, श्री । रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री रामलाल, श्री रानव बन यादव, श्री रामशंकर द्विवेदी, श्री रामशंकर रविवासी, श्री रामतनेही भारतीय, श्री रामसहाय शर्मा, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री रामसुन्दर राम, श्री रामसुभग वर्मा, श्री रामसुमेर, श्री रामस्वरूप,श्री रामस्वरूप गुप्त, श्रो रामस्वरूप भारतीय, श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री रामहरख य दव, श्री रामहेत सिंह, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्तीरमण ग्राचार्य, श्री लत्मीशंकर यादव, श्रो लालबहादुर सिंह, श्री तालबहादुर सिंह कश्यप, श्री लोलाघर श्रष्ठाना, श्रो लुत्कग्रली लां, श्री लेखराज सिंह, श्री वंशनारायण सिंह, श्री बंजीदास घनगर, श्री वंशीघर मिश्र, श्री बसीनकवी, श्री बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री विजयशंकर प्रसाद, श्री विद्यावती राठौर, श्रीमती विश्राम राय, श्री विष्णदयाल वर्मी, श्री विष्णुशर्ण दुब्लिश, श्री बोरसेन, श्रो वोरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री बीरेंद्रपति यादव, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री वरिन्द्रशाह, राजा व्रजभूषण मिश्र, श्री रजरानी मिथ्र, श्रीमती ब्रह्महासी लाल, श्री

व्रजविहारी मिश्र, श्री वजविहारी मेहरोत्रा, श्री शंकरलाल, श्री शिवकुमार मिश्र, श्री शिवकुमार शर्मा, श्री शिवनारायण, श्री शिवप्रसाद, श्री शिवमंगलसिंह, श्री शिवमंगलसिंह कपूर, श्री शिवराज सिंह यादव, श्री शिवराम पांडेय, श्री शिवराम राय, श्री शिववक्ष सिंह राठौर, श्री शिववचन राव, श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री शिवस्वरूप सिंह, श्री शुकदेव प्रसाद, श्री श्गनचन्द, श्री श्याममनोहर मिश्र, श्री श्यामलाल, श्री श्रीचन्द, श्री श्रीनाथ भागंव, श्री श्रीनाथराम, श्री सईद जहां मलफी शेरवानी, श्रीमती संग्रामसिंह, श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती सत्यसिंह राणां, श्री सम्पूर्णानन्द, डाक्टर सावित्रीदेवी, श्रीमती सियाराम गंगवार, श्री सियाराम चौधरी, श्री सीताराम, डाक्टर सीताराम शुक्ल, श्री मुखीराम भारतीय, श्री मुन्दरलाल, श्री सुरुजूराम, श्री सूरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री सुरेशप्रकाश सिंह, श्री सूय्यंप्रसाद ग्रवस्थी, श्री सुर्य्यवली पांडेय, श्री सेवाराम, श्री हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री हबोबुर्रहमान ग्रंसारी, श्री हबीबुर्रहमान ग्राजमी, श्री हबीबुर्रहमान खाँ हकीम, श्री

प्रक्नोत्तर

हमीद खां, श्री हरसयाल सिंह, श्री हरगोजिन्द पन्त, श्री हरगोविन्द सिंह, श्री हरदयाल सिंह पिपल, श्री हरदेवसिंह, श्री हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नात्तर

७ मई, १६५४

ग्रल्पसूचित तारांकित प्रइन

पंचायत राज इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान ग्रौर उन पर नियुक्तियां

**१--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद) - क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेगे कि प्रदेश में इस समय कितने पंचायत राज इन्सपेक्टरों की जगहें खाली हैं?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—इस समय ६८ पंचायत निरीक्षकों के पद खाली हं, जिनमें से ५० पदों पर स्थानापन्न (officiating) रूप में नियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई चुनाव इस सम्बन्ध में कराया था? यदि हां, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितने प्रकार की लिस्ट सबमिट की श्रौर कितने श्रादिमयों की?

श्री मोहन लाल गौतम---२८ पदों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्शन कराया गया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने विभागीय सेक्रेटरियों या श्राफिस के लोगों में से भी कुछ लोगों का इस पद के लिये चुनाव कराया है ? यदि हां, तो कितने लोगों का ?

श्री मोहनलाल गौतम—३३ प्रतिशत लोगों का चुनाव विभाग के कार्यकर्ताश्रों में से होगा ग्रौर वह ग्रभी पूरा नहीं हुमा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलायेगे कि पबलिक सर्विस कमीशन की लिस्ट उनको किस तारील को प्राप्त हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और विभाग द्वारा नये इन्सपेक्टरों का चुनाव हो चुका तथा लिस्ट बन चुकी है तो उनकी नियुक्ति में सरकार इतनी देर क्यों कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रोसीजर में जो समय लगता है उसी के ब्रनुसार हो रहा है। ब्राज्ञा है कि वह नियुक्तियां जल्द हो जायेंगी।

मधुबन (भ्राजमगढ़) में ऐलोपंथिक ग्रस्पताल का निर्माण

**२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला ग्राजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृप। करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ में मधुबन जिला ग्राजमगढ़ में एलोपैयिक ग्रस्पताल का जो निर्माण होने वाला है उसमें ग्रब तक कौन-कौन सी कार्यवाहियां की जा चुकी है ? ग्रन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को राय इस क्षेत्र मे एक उचित स्थान पर विकित्सालय स्नोनने के लिये लें। ज्योंही जगह नियत हो जायगी, ग्रागे की कार्यवाही की जायगी।

बजट में फिलहाल २४,००० रुपये की त्यवस्था भी कर दी गई हं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय स्वास्थ्य जंत्री जी की पता है कि १० ग्रप्रेक को प्रश्नकर्ता ग्रीर ज्ञिवराम राय एम० एल० ए० श्रीर जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के सम्मुख जूनियर हाई स्कूल, मधुबन के सामने जमीन तय कर ली गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-इसकी हमारे पास तो सूचना नहीं ब्रायी हं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेगे कि कब तक श्रस्पताल बनने का काम प्रारम्भ हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-ज्योंही जमीन के बारे में निर्णय हो जायगा श्रीर ज्योंही हमारे पस इस बात की सूचना श्रा जायगी, उसके बाद उचित श्रादेश इमारत बनाने के जारी कर दिये जायेगे।

[३० अबेल, १९५४ के स्थागित प्रकत]

तारांकित प्रक्त

जौनपुर जिले के ग्राम पाण्डेपुर तथा समस्त जिले में डकैतियों की संख्या

*१——श्री बाबू निन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर सदर थाने के ग्रन्तर्गत ग्राम पांडेपुर में कुछ समय पूर्व एक डाका तथा एक चोरी हुई? यदि हां, तो उस पर श्रव तक क्या कार्यवाही हुई?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) -- जी नहीं। प्रक्न का दूसरा भाग नहीं उठता:

"२--श्री बाबू नन्दन-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन थानों पर कितने डाके माह जुलाई सन् १६५३ से श्रव तक पड़े, उसमें कितने डाक् पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे मे देखी जा सकती है।

(देखिये नत्यी 'क' ग्रागे पुष्ठ ४३७ पर)

श्री बाबू नन्दन् स्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि जिन थानों पर श्रिधिक डाके पड़े हं उनकी उचित व्यवस्था के लिये सरकार की तरफ से कोई श्रादेश भेजा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। देखभाल खासतौर से उनको र उनी चाहिये ग्रौर कोई विशेष ग्रादेश तो भेजा नहीं गया।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई ब्रावेश भेजा गया है कि डकैतों के पकड़ने के लिये जनता के बीच मे प्रदर्शन कराया जाय? यदि हां, तो किसके द्वारा श्रीर किस भांति ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा तो कोई खास ग्रावेश नहीं है। ग्राम रक्षक समितियों को जरूर बतलाया जाता है कि किस तरह से डकेंतों को गिरफ्तार करना चाहिये। बही प्रदर्शन हो सकता है। दूसरा कोई प्रदर्शन तो नहीं होता। प्रव्नोत्तर ३६१

श्री बाब नन्दन-स्या माननीय मजी जी बनलाने की कृपा करेगे कि यह जो उकेत हैं बह बहरी ह कि जिले हो भी शामिल ही

डाक्टर सम्यूर्णनन्द—इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जितनी डकंतियां ह उन सबके मुक्त्रमें श्रदालन में हे। श्रभी साबित भी नहीं हो सकता कि कौन डकंत है, कोन नहीं। इनमें में एक पर भी श्रभी फैनला नहीं हुआ है?

ब्राजमगढ़ जिले में कन्यनिन्टों की गिरणतारी

"३—श्री झारखंडे राय(जिला ग्राजमगढ़)—वया मरकार बतायेगी कि ज्न माह में कुल किनने कम्युनिस्ट श्राजमगढ़ जिले में गिरयतार किये गये ग्रीर क्यों?

"४--क्या मरकार बतायेगी कि वे कम्युनिस्ट किन-किन धाराख्रों की मातहत गिरफ्तार किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोग कान्न तोड़ने के ग्रपराध में गिरफ्तार किये जाते हैं न कि राजनैतिक सम्पर्क के ग्राधार पर । ग्रतः इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृहमंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पाम ऐसा कोई रेकर्ड जेल या जेल के बाहर पुलिन में नहीं रहता कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से मम्बन्ध रखता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्रब कुछ खास-खास व्यक्तियों के बाबत तो जानकारी होती ही है लेकिन जितने शस्स हे उन सबके राजनेतिक विचारों के बाबन तो कोई खाम जानकारी रखने की कोशिश भी नहीं की जाती।

श्री झारखंडे राय—माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि ग्राजमगढ़ मे गत जून मेएसे ग्रादमी कितने गिरफ्तार हुये जिनका मम्बन्घ कम्युनिस्ट पार्टी से था ?

श्री ग्रध्यक्ष—इसका उत्तर तो माननीय गंत्री जी दे चुके है कि राजनैतिक सम्पर्क मे गिरफ्तारी नहीं होती है।

1/2

×

ग्राम ग्रसलाई (श्राजमगढ) में प्रजा मोश्तालिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा का भंग किया जाना

*

*६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेगे कि ग्राम ग्रसला थाना ग्रहिरौला, जिला ग्राजमगढ़ में जिला प्रजा सोशिनस्ट पार्टी द्वारा गत ६ जनवरी ग्री द फरवरी को सार्वजिनक सभा करने का ग्रायोजन किया गया था, जिसकी सूचना जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को दे दी गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न में कथित तिथियों में ६ जनवरी के लिये झायोजित सार्वजनिक सभा की कोई पूर्व सूचना जिला श्रिधकारियों को नहीं मिली थी। गत द फरवरी के लिये प्रायोजित सभा की सूचना केवल जिलाधीश को ही मिली थी।

*७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों तिथियों को सार्वजनिक सभायें श्रसलाई ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों हारा बलपूर्वक भंग कर की गर्यों ?

डाक्टर म्सम्पूर्णानन्द—उक्त सभाये ग्रसलाई ग्राम के भृतपूर्व जमींदारों की राय के विरुद्ध उनके बागीचे में ग्रायोजित की गई थीं। ग्रतएव उन्होंने वहां पर सभा नहीं करने दी। ६ जनवरी को उन्होंने कुछ बल का भी प्रयोग किया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही नहीं है कि ६ जनवरी, १६५४ की सभा की नोटिस १५ दिन पहले छपवा कर सारे देहात में श्रौर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट श्रौर जिला श्रिकारों के यहां भेज दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश श्रौर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास किसी प्रकार की सूचना, उस मीटिंग की नहीं श्रायी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि द फरवरी को जो सभा की गयी उसकी इतिला जिलाघीश को २ फरवरी को श्रौर एस० पी० को ४ फरवरी को दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश तो कहते हैं कि उनको इत्तिला दी गयी थी। लेकिन एस० पी० कहते हैं कि उनको इत्तिला नहीं मिली ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि २ फरवरी की सूचना पर जिलाघीश ने एस० पी० को वहां ग्रावश्यक प्रबन्ध करने का ग्रादेश दे दिया था, फिर भी वहां ग्रावश्यक कार्यवाही नहीं की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। एस० पी० को जिला मैजिस्ट्रेट ने ग्रव्यक कार्यवाही के लिये ग्रादेश दिया था श्रीर जो ग्रावश्यक कार्यवाही हो सकती थी वह की गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि ६ फरवरी की सभा में वहां के स्थानीय जमींदारों के साथ ही वहां के सब-इन्सपेक्टर भी थे श्रीर सभा बलपूर्वक विघटित कर दी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) — क्या जिन्हें चोट श्रायी उनमें किसी को गंड़ासा श्रौर भालों की भी चोट लगी है ?

श्री श्रध्यक्ष-किस तारीख की मीटिंग के संबंध में।

श्री गेंदा सिंह—द फरवरी की मीटिंग में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय गेंदासिंह जी को कुछ श्रम हो रहा है। द फरवरी की मीटिंग में किसी को चोट नहीं श्रायी। माननीय रामसुन्दर पाण्डेय ने ६ फरवरी का जिक किया था इसलिये मैंने कहा था कि ६ फरवरी को कोई मीटिंग नहीं हुई। ६ फरवरी को जो सभा हुई थी, ऐसी खबर मिली कि उसमें कुछ जमींदारों के ऊपर बलप्रयोग हुआ था लेकिन अगर किसी को चोट आयी भी हो तो न किसी ने डाक्टरी जांच करवायी और न रिपोर्ट करवाई। इ सलिये यह कहना मुक्किल है कि किस को क्या चोट आयी।

श्री उमाशंकर (जिला ग्राजमगढ़)—श्जनवरी की सभा के लिये कोई नोटिस ख्र्यी थी यह माननीय गृह मंत्री को मालुम है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय-- क्या यह सही है कि ६ फरवरी की सभा विघटित हुई ?

प्रश्नोत्तर ३६३

श्री श्रध्यक्ष- ६ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई यह उनसे कहा गया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—६ जनवरी की सभा विघटित हो जाने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में प्रार्थनापत्र दिया था कि उचित कार्यवाही की जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो प्रार्थना-पत्र ग्राया होगा वह जिला ग्रिषकारी के पास भेज दिया गया होगा।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६ जनवरी की जो सभा हुई उसमें सभासद जो थे वह शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-चूंकि ग्रधिकारियों को कोई खास सूचना नहीं थी इसलिए हम कह नहीं सकते कि किस प्रकार वह लोग सुसज्जित थे।

श्री व्रजिवहारी मिश्र (जिला ग्राजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां दोनों पार्टीज में झगड़ा हो गया ग्रौर जो लोग बाद में सभा करने गये उनको रोका गया तो उस पर झगड़ा हुन्ना?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-यह बात तो ८ फरवरी को भी हुई थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जिलाधिकारियों से पूछने की कृपा करेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सभा भंग होने पर जो झगड़ा हुन्ना उसमें किसके द्वारा जांच कराई गई श्रीर जांच का क्या नतीजा हुन्ना?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सभा होने ही नहीं पाई। जमींदार लोगों ने ग्रपने बाग में सभा होने ही नहीं दी। फिर जांच क्या होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि ६ जनवरी को सभा हुई यो ध्रौर बल प्रयोग किया जमींदारों ने तो उस पर क्या कार्यवाही हुई श्रौर उसका क्या नतीजा रहा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मं समझा था कि ८ फरवरी को बाबत ग्राप यह कह रहे है। ६ जनवरी की बाबत दरियाफ्त करके बतला सकूंगा।

भी उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ६ जनवरी को जो बुर्घटना हुई थी उसकी जांच में तहसीलदार फूलपुर ने क्या किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्रगर इसकी जानकारी मुझे होती तो मैने इस प्रश्न का उत्तर श्री रामसुन्दर पांडेय को ही दे दिया होता।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सोश्नलिस्ट पार्टी की तरफ से ग्राजमगढ़ जिले में ग्रौर भी किसी स्थान पर भूमि के मालिक की इच्छा के विरुद्ध सभा की गई?

श्री अध्यक्ष—इसमें और जगहों का प्रक्त आप कर रहे है। यह प्रक्त केवल दो हो जगहों से सम्बन्ध रखता है। श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि प होते। जनवरी को सभा की गई थी जिसमे स्रापने स्वीकर किया है कि भूतपूर्व जमींदानों के बाग में की गई था तो क्या भूतपूर्व जमींदारों ने प्रजासोशिलस्ट पार्टी के कार्यकर्नाक्रे के पास नोटिस भेजी थी कि यहां पर सभा न करो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई नोटिस दो ई या नहीं दी थी।

श्री लक्ष्मीरमण श्राचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय गृह मंत्री बनक्षे की कृपा करेंगे कि सभा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पुलिस में हुई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला-धीश श्रौर सुपरिटेंडेंट पुलिस को खबर देने के बाद उस दिन पुलिस भी उस मीटिन में गई थी श्रौर श्रगर हां, तो उसके रहते हुए बलप्रयोग कैसे हुन्ना?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—द तारीख को पुलिस गई थी। पुलिस के जाने में नतीजा यह हुन्ना कि कोई बलवा नहीं हो पाया लेकिन पुलिस किसी की जमीन में जबरदस्ती सभा नहीं करा सकती, हां, मारपीट नहीं होने पाई।

बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक थाने के ग्रन्तर्गत डाके ग्रौर कत्ल

*द—श्री धर्मासह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृप करेगी कि बुलन्दशहर जिले के प्रत्येक थाने के श्रन्तर्गत पिछले दो वर्ष में किनने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--डकैतियों की संख्या जिले में १९५२ में २२ थी ग्रौर १९५३ में २६ थी। थानेवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्यी 'ख' श्रागे पृष्ठ ४३५-४३६ पर)

*६--श्री धर्मीसह-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डाकों में कितने मर्द, ग्रौरत तथा बच्चों की हत्या हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५२ में ७ पुरुषों ग्रौर १९५३ में ९ पुरुषों की हत्या हुई। स्त्रियों या बच्चों की कोई हत्या नहीं हुई। थानावार ग्रौर डकंतीवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' स्रागे पृष्ठ ४३८-४३६ पर)

*१०—श्री धर्मीसह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन डाकों से सम्बन्धित डकैत पकड़े गये तथा मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसका विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' म्रागे पुष्ठ ४३८-४३६ पर)

श्री धर्मिसिह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पिछले दो साल में जो डकैतियां हुईं उनमें कितना धन लूटा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसके लिये नोटिस की स्रावश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय गुह मंत्री यह बतलायंगे कि इन डकैतियों में कितने हथियार पकड़े गये ग्रौर उनमें कितने विलायती थे?

प्रज्ञोत्तर ३६४

इ इन्द्रन सम्पूर्णनन्द--किनने स्रादमी पकड़े गये उनकी संख्या मेरे पान हैं के किन्ने किन्ने क्षियार पकड़े गये इसकी संख्या तो मेरे पान है नहीं।

भी रामचन्द्र दिकल (जिला बुनन्दशहर)—क्या मरकार यह बतलाने की छपा करेरी कि बुनन्दशहर जिले के थाना दनकौर में दिसम्बर, १९५३ ई० में एक डकेती हुई जिससे डाकू पकड़े राये और कुछ ग्रादमी भी मारे गये लेकिन वह इसमें दर्ज नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी सूची मे उसका नाम नहीं है। अगर ऐसा वाकया हुन्ना हुनो उसकी खबर दे, उसका पता लगाया जायगा।

श्री धर्म सिंह—क्या माननीय मंत्री जी वतलायेगे कि जिन थानों में डकैतियां अधिक पड़ रही है उन थानों के खिलाफ मरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थानों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है। जहां पर ज्यादा डकैतियां हो जायं वहां के भ्राफिसर से जवाब तलब किया जाता है कि वहां पर ऐमा क्यों हुन्ना।

*

लेबर म्राफिसर्स तथा कांसिलियेशन म्राफिसर्स की नियुक्तियां भ्रौर उनमें हरिजनों का श्रनुपात

*१२--श्री पुत्तू लाल (जिला ग्रागरा) -- स्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने लेबर ग्राफिसर्स तथा कांसिलियेशन ग्राफिसर्स लिये जा रहे हैं ग्रीर उनमें से कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रक्खे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १६५४ में स्रभी तक लेबर स्राफिससं की दो स्रौर कान्सिलियेशन स्राफिससं की तीन जगहें पब्लिक सिवस कमीशन के द्वारा भरी गई हैं। चंकि रिक्त स्थानों की संख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिये हरिजनों के लिये स्थान सुर-क्षित करना सम्भव नहीं था।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इससे पहले लेबर श्राफिसर श्रौर काँसिलियेशन श्राफिसर के २, २ श्रौर ३-३ स्थानों का चुनाव हो चुका है किन्तु उसमें कोई हरिजन नहीं लिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो हां, यह सही है। दिक्कत यह है कि लेबर डिपार्टमेंट में जगह बहुत थोड़ी है। केवल २, ३ जगहें होती हैं उसमें परसन्टेज बैठाना बड़ा कठिन होता है फिर भी में इतना बतलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कि ग्रब हमने यह निश्चय किया है कि ग्रागे से जो जगह लेबर ग्राफिसर की खाली होंगी चाहे वह २ हों या ३ हों जो कुछ भी हों कम से कम उसमें से एक जगह हम हरिजन उम्मीदवार के लिये रिजर्व कर देंगे।

मथुरा जिले में अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्थ समाजियों की गिरफ्तारी

*१६—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो वर्षों में ग्रमेरिकन मिशन के लोगों ने मथुरा जिला में धन देकर ग्राठ हजार ग्राविमयों को ईसाई बनाया? डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय मेथोडिस्ट तथा रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने गत हो वर्षों में लगभग २५० ग्रामीण व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया है। परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस धर्म परिवर्तन में धन का भी उपयोग किया गया है।

*१७--श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या सरकार की यह नीति है कि विदेशियों के यहां की अनपढ़ तथा गरीब जनता की मनोवृत्ति बदलने का इस तरह का मौका दिया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला ग्रलीगढ़) — क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये ग्रमरीकन मथुरा जिले में कब से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसके लिये सूचना की ग्रावश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिन २५० श्रादिमयों का धर्म परिवर्तन किया गया वे कौन लोग हं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-वे पहले हिन्दू थे, जात बिरादरी का पता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण श्राचार्य—क्या इन धर्म परिवर्तन करने वालों के सम्बन्ध मे कुछ काग्रजात बरामद हुये है तथा इकरारनामें निकले हैं कि एक निश्चित धनराशि उनको दी गई ग्रौर यदि वे पुनः धर्मपरिवर्तन करे तो वह धनराशि वापस लेने को व्यवस्था की गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि यह ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने यह कहा था कि कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले है कि धर्म परिवर्तन के लिये रुपया पैसा भी खर्च किया गया।

श्री नेकराम शर्मा—मथुरा जिले में कितने ग्रमरीकन ग्रौर दूसरे लोग ग्रोर देशों के हैं जो इस कार्य में लगे हुये हे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामदास श्रार्य (जिला सुजफ्फरनगर)—क्या सरकार जो लोग ईमाई हो गये हैं उसका कारण जानने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसकी कोई खास जरुरत नहीं मालूम होती।

श्री रामचन्द्र विकल क्या यह सत्य हं कि मथुरा जिले मे ग्रार्थसमाज के कृद्ध कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन के काम को रोकने के लिये गिरफ्तार किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रचार रोकने के कई ढंग होते हे। कुछ व्याख्यान वहा हुये थे जिसके फलस्वरूप कुछ लोग एक गिर्जाघर मे घुस गये, वहां की इमारत श्रार शीशे तोड़ दिये गये श्रीर श्रगर प्रचार का यही तरीका हो तो जरूर कुछ गिरफ्तारियां इम सम्बन्ध में हुई।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला ग्रागरा)—क्या माननीय मंत्री जी को इन मिशनरियों की कुछ राजनैतिक हलचले भी मालूम हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैने ८-७ दिन पहले यहां कहा था कि कुछ ऐसा कार्य मालूम होता है जो विदेशियों को नहीं करना चाहिये, इसकी श्रोर मैने काफी संकेत किया था श्रोर मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। श्री लक्ष्मीरमण श्राचार्य—१०० का मुक्कद्वमा जो गिर्जाघर के सम्बन्ध में चल रहा है उसमे एम० श्रो० बलदेव तथा श्रन्य साक्षियों ने क्या यह स्वीकार किया है कि बर्ज्यान्यों द्वारा घन देकर प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है?

श्री ग्रध्यक्ष-ये बाते मुकदमे के मिलसिले में ह जो सबजुडिस है। में इसकी इजाइन नहीं देना।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या मरकार श्रमरीकन मिशनरियों जी रिविधियों के सम्बन्ध में तहकीकात कराने के विषय में जांच कराने की सोच रही हैं ?

ड इटर सम्पूर्णानन्द—इसके सम्बन्ध में में यह निवेदन कर चुका हूं कि यह प्रकृत केन्द्रीय ग्राँर प्रादेशिक सरकारों के सामने हैं।

प्रनापगढ़ जिले में विद्यार्थी भ्रान्दोलन के मम्बन्ध में विद्यायियों पर श्रीभयोग

"१=—श्री रामश्रथार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थी ग्रान्दोलन से सम्बन्धित प्रतापगढ़ जिले के कितने विद्यार्थियों पर ग्रीन किन-किन धाराग्रों के ग्रन्तर्गन ग्राभयोग चलाया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रतापगढ़ जिले मे गत विद्यार्थी ग्रान्दोलन के सम्बन्ध मे १०१ विद्यार्थियों के ऊपर इंडियन पेनल कोड की विभिन्न धाराग्रों के ग्रन्तगंत ग्रिभयोग चल रहा है। दो मामलों में विद्यार्थियों पर टेलीग्राफ ऐक्ट की धारा २५ के ग्रन्तगंत भी ग्रिभियोग चल रहा है। इंडियन पेनल कोड की धाराएं इस प्रकार है:

१४७।३०७।३३२।३३६।३६६।३८३।३७६।३६४।४२६।४२७।४३६४४७ तथा

श्री रामग्रधार तिवारी—क्या माननीय गृहमंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि इन धाराश्रों के श्रलावा दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के श्रन्तर्गत भी इन विद्यार्थियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है।

श्री रामग्रधार तिवारी—क्या सरकार उनको फर्स्ट ग्राफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट के मातहत उनको मुक्त करने पर विचार करेगी?

श्री श्रध्यक्ष—मं इसको इजाजत नहीं देता। इसका श्रभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह मालूम है कि जिन विद्यार्थियों पर मुकदमा चल रहा है वे १०-१८ के बीच में है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई सूचना नहीं है। केवल एक केस का जिक्र हुआ था। सीतापुर, लखीमपुर जिलों में किसी लड़के के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है जो १५ वर्ष से कम हो। प्रतापगढ़ की बाबत इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी है। श्री वीरेन्द्र वर्मा--जिन १०१ विद्यार्थियों पर श्रिभयोग चल रहा है उनमें हे कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित रहे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक भी नहीं।

पुलिस विभाग में ग्राबकारी विभाग से ग्रागत ग्राई० पी० एस० ग्रफसरों के प्रोबेशन की ग्रवधि

*२८—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेगे कि पुलिस विभाग में श्राबकारी विभाग से जितने श्राई० पी० एस० श्रफसर प्रोवेशन क श्राये हं? क्या उनके प्रोबेशन की श्रवधि श्रभी तक समाप्त नहीं हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राई० पी० एस० में केवल एक ग्रफसर ऐसे है जो पहले केन्द्रीय ग्राबकारी विभाग में नौकर थे। उनका दो साल का निर्धारित परीक्षणकान मार्च ३१, १६५२ तक था ग्रौर यूनियन पिंडलक सर्विस कमीशन की सलाह पर उसे बाद को ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया। किन्तु वह ग्राई० पी० एस० में ग्रभी तक स्थायी नहीं किये जा सके है क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के ग्रधीन ग्रपने पूर्व पर के ग्रहणाधिकार (lien) की समाप्ति की श्रनुमति श्रभी तक नहीं दो है।

*२६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या उन्होंने सरकार के पास श्रपनी मांगों का कोई स्मृति पत्र भेजा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन्होंने ग्रपने वेतन के बारे में केन्द्रीय सरकार के लिये एक प्रार्थना पत्र भेजा था जो उस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसी विषय में उन्होंने फिर एक दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया जो केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया था, जिसका उत्तर केन्द्रीय सरकार के श्रभी दो चार दिन हुये प्राप्त हुस्रा है। श्रीर उस पर श्रावश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेगे कि उन श्राफीन का नाम क्या है श्रौर वे किस जगह काम कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनका नाम रघुबीर प्रसाद है, वह फंजाबाद में है?

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रृंगार दुबे पर श्राक्रमण की जांच

*३०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेगे कि प्रज्ञ सोशलिस्ट पारटी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल शंगार दुबे के ऊपर हुये श्राक्रमण के संबंध में पुलिस द्वारा जो जांच हो रही थी इस समय तक उसकी रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द — जांच समाप्त हो गई है। सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (final report) लगा वी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रत्मोड़ा)—क्या सरकार इस मामले में किनी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या किसी बड़े सी० श्राई० डी० श्राकीसर द्वारा उसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डी० ग्राई० जी० ग्रौर सी० ग्राई० डी० ने इस मामले को वेख लिया है। जो लोग ऐसी ग्रवस्था में हैं कि वे उनको सहायता वे सकें जब तक वे कोई सहायता देने को तैयार न हों तब तक किसी भी जांच का कोई फल नहीं निकल सकता। जैसा कि पहले ही प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुका हूं।

प्रश्नोत्तर ३६६

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या मरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस मंबंध में किमी को गिरफ्नारी हुई या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जब कोई पहचाना ही नहीं गया नो किमी का गिरफ्तार होना ग्रनम्भव था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नंनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की हृपा करेंगे कि क्या इसकी जांच के परिणामस्वरूप ग्रव तक किसी ग्रपराधी का कोई पता चना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द- जी नहीं। पता चला होता तो जरूर गिरफ्तारी की गयी होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह मही है कि जांच के समय श्री बलशंगार दुबे से इस संबंघ में कुछ पूछतांछ नहीं की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक चोट की बात है, जब डाक्टर ने प्रत्यक्ष ग्रपनी ग्रांखों से देखा कि चोट लगी है तब सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ बयान दिया था ग्रीर कुछ लोगों के नाम बतलाये थे। इसके ग्रवाला ग्रीर क्या पूछताछ होती।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—वया माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दलश्रुंगार दूबे को जो चोट लगी थी उसकी कोई रिपोर्ट सरकार को मिली कि यह चोट कहां से लगी या प्राकृतिक तरीके से कहीं से ऊपर से ग्रा गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्राकृतिक चोट तो थी नहीं क्योंकि सर से लेकर पैर तक चोट के निशान थे। वह किसी मनुष्य की पहुंचाई हुई चोट जरूर थी।

श्री गेंदा सिह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने इस मामले में इनक्वायरी की थी क्या कुछ लोगों के ऊपर शुबहा भी उनका था और उनसे उन्होंने पूछताछ की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो ग्रासपास के जमींदार है उनके ऊपर उस किस्म का शुवहा था, संभव है कि उन लोगों ने ऐसी कोई हरकत की हो क्योंकि ऐसा उनका खयाल था कि कुछ दिन पहले श्री दलश्रृंगार दुवे ने कोई स्पीच वगैरह ऐसी दी थी जिसमें उन जमींदारों को बुरा भला कहा था लेकिन महज इस सबूत पर किसी को गिरफ्तार करने के लिये कोई काफी सामग्री नहीं होती।

श्री गेंदासिह—क्या श्री दलशृंगार दुबे ने कोई ज्ञिक.यत वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध भी की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी हां, उनके खिलाफ भी उनको शिकायत थी।

श्री गेंदासिह—क्या सरकार की तरफ से श्री दलश्रुंगार दुवे की शिकायत पर कोई इनक्वायरी करायी गयी कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध उनको क्या शिकायत थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो हां, ऐसी गोल शिकायत पर जैसी जांच हो सकती थी वैसी जांच करायी गयी और उस शिकायत का कोई खास भ्राधार नहीं पाया गया ?

> वित्रान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी पर स्रभियोग और उनकी पेशी;

*३२—श्री गेंदासिह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध क्या ग्रिभियोग है श्रीर इन ग्र.भयोगों का ग्राधार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तारीख ६ फरवरी, १६५४ की शाम को श्री नारायणदत्त तिवारी ने श्रपने कुछ साथियों के साथ काशीपुर, जिला नैनीताल में स्थानीय चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई रोकने के इरादे से मिल के पास घरना दिया था। श्रपने इस कार्य से उन्होंने काशीपुर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा किमिनल प्रोसीजर कोड की घारा १४४ के ग्रन्तगंत लागू की गई श्राज्ञा का उल्लंघन किया।

*३३—-श्री गेंदासिह—-श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो श्ररजी हाई कोर्ट इलाहाबाद को दी है उसकी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उन्होने दरख्वास्त में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी और उनको छोड़ा जाय। खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनकी ग्ररजी सारिज कर दी है।

*३४--श्री गेदासिह-शो नारायण दत्त तिवारी गिरफ्तारी के बाद किस भैजि-स्ट्रेट के सामने, किस समय श्रीर कहां पर पेश किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गिरफ्तारी के बाद श्री तिवारी काशीपुर में ही वहां के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने करीब ५ बजे शाम को पेश किये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दया माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सहस्य सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट क सामने शाम को किस स्थान पर पेश किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेश तो वैसे उनके मकान पर ही किये गये लेकिन इस संबंध मे में इतना ही कह सकता हूं कि यह सवाल प्रिविलेज कमेटी के सामने श्रा चुका है श्रीर कोई नया प्रकाश में इस प्रश्न के उत्तर में डाल सकूंगा इसकी संभावना बहुत कम मालूम होती है।

े श्री गेदासिह—क्या मार्ननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस गिर-फ्तारी पर ब्रीच श्राफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया है वह ४ तारीख की है श्रौर यह ६ तारीख की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द संभव है दोनो मिल गये हों।

श्री गेंदासिंह--चया श्री नारायण दत्त जी ६ तारीख से पहले भी दफा १४४ तोड़ने के संबंध में गिरफ्तार हुये थें]?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- प्रश्न ६ तारीख के बारे में था, उससे पहले के लिये सूचना चाहिये।

श्री गेंदासिह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाईकोर्ट में सरकार की श्रोर से पैरवी करने वाले कीन साहब थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-इसके लिये सूचना की ग्रावश्यकता है।

श्री नारायणदत्त्रं तिवारी—वया सरकार ने मैजिस्ट्रेटों को कोई ऐसी स्राज्ञा दो है कि जब वह दफा १४४ का समियोग किसी पर लगायें तो वह उस का रिमूवल भी कर सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णीनन्द--जो कुछ कानून में लिखा है उसके ऊपर ब्रादेश देने का सरकार को ब्राविकार नहीं है।

श्री गेंदासिह क्या सरकार बतायेगी कि ६ तारील की गिरफ्तारी पर उसी दिन मामता झदालत में येज हुआं और उसी दिन फैसला हो गया ? डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि फैसला हो गया लेकिन, मै निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फैसला किस तारील को हुन्ना और क्या यह सही है कि फैसले की पेशी एक दिन ही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैसला हुग्रा ऐसा मेने नहीं कहा था लेकिन उन से मालूम हुग्रा कि फैसला हो गया, मेने भी सुन रखा था कि ऐसी बात है लेकिन ग्रदालत में ग्रक्सर ऐसा होता है कि एक ही दिन में फैसला और पेशी हो जाती है।

> गाजीपुर शहर में मन्दिर श्रौर मस्जिद का झगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*४१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कोई मंदिर ग्रीर मस्जिद का झगड़ा है? ग्रगर हां, तो वह क्या है ग्रीर सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। गाजीपुर शहर के कोट मुहल्ले मे जब एक पुरानी मिल्जिद की दीवार की नींव खोदी जा रही थी तो मजदूरों को कुछ मूर्तियां मिलीं। इस खबर को मुन कर वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई श्रौर उसने एक लाल झंडा मूर्तियों के पास गाड़ दिया। श्रिषकारियों ने जब देखा कि संबंधित पार्टियों में कोई समझौते की श्राशा नहीं हैं तो मूर्तियां हटाकर पुलिस लाइन के मंदिर में रखवा दो गर्यों। इसके बाद एक भीड़ फिर इकट्ठी हो गई श्रौर उसने उस मिल्जिद की दीवारों को गिरा दिया श्रौर उस स्थान पर एक चबूतरा बनाया। इस मामले के संबंध में एक पार्टी ने श्रदालत दीवानी में मुकदमा दायर किया है। श्रतएव वर्तमान स्थित में उक्त मामले पर कोई श्रालोचना करना उचित न होगा।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त झंडा गाड़ा गया, मस्जिद की दीवार गिरायी गई श्रौर चबूतरा बनाया गया उस वक्त वहां पुलिस थी? डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस के कुछ श्रादमी थे।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस ने क्या किया? डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिवा इस के कि देखते रहे ग्रीर कुछ नहीं किया।

श्री गेंदा सिह—जिस लाल झंडे का जिन्न किया गया वह किसी पार्टी का झंडा था या कोई घार्मिक झंडा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-मेरे खयाल से वार्मिक झंडा था।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री जी से गाबीपुर का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था कि पुलिस नागरिकों के साथ वहां ज्यादती कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस तरह के प्रतिनिधि मंडल मिलते ही रहते है, शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां के प्रतिनिधि न मिलते हों।

> क जिला रायबरेली के याना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां

*४३—श्री गुप्तार सिंह (बिला रायबरेली)—स्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी की स्थानीय पुलिस तथा साम बनपुरवा मुखरे रंजीत-पुर के किसानों के दरमियान गत जनवरी २४ व २५ के मध्य में समय पांच बजे सुबह कोई अगड़ा हो गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्व-जी हां।

*४४—श्री गुप्तार सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि इस झगड़े में कितने किसानों को चोट ग्राई है ग्रौर कितने पुलिस वालों के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो पुलिस कांस्टेबिलों के श्रौर ५ ग्रन्य व्यक्तियों के चोटें श्रायीं।

*४५—न्श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस झगडे का क्या कारण था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारतीय दंड विधान की धारा ४२७/४४७ के म्रन्तर्गत एक मामले में कुछ लोगों को पकड़ने के लिये पुलिस पाटः प्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुरवा गयी। उन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिये पुलिस से मारपीट की।

श्री गुप्तार्रासह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगे कि ग्राम बनपुरवा मंजरे रंजीतपुर के किसानों ने श्रीम न् गृह मंत्री के पास मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये कोई दरस्वास्त दी थी ग्रीर यदि हां, तो उस पर जांच हुई ग्रीर उसका क्या परिणाम हुन्ना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच तो हुई लेकिन जब मामला श्रदालत में है तो जांच की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ब्रादिमयों की गिरफ्तारी किन दफाओं के ग्रन्तगंत की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१४ ब्राविमयों की गिरफ्तारी होने को थी पांच तो उसी वक्त गिरफ्तार हो गये जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिये गई थी, २ ब्राविमी गिरफ्तार नहीं हुये, स्वयं जाकर ब्रवालत में हाजिर हुये और वह लोग जो गिरफ्तार हुये जहां तक मुझे मालूम है दका १४१/१४२ तथा ३२४/३२५ में उन पर मुकदमे चल रहे है।

श्री गुप्तार सिह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों में एक गिभणी श्रौरत भी थी जिसके छ टने के बाद १५ दिन बाद बच्चा पैदा हुग्रा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है। बहरहाल जमानत पर सब लोग छूटे हैं। श्रव उनमे कोई श्रौरत थी जिसके पेट में बच्चा था श्रौर उसके छूटने के बाद बच्चा पैदा हुश्रा इसकी मुझे सूचना नहीं है।

गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गवे मुकदमें श्रीर उनमें सजाएं

*४७—श्री भोला सिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर की जमानिया तहसील से सन् १९५३ में पूरे साल में पुलिस द्वारा कितने मुकद्दमें चलाये गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-१२४।

श्री भोला सिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि किन-किन धाराश्रों में ये सजाये हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रच्छा होता यदि माननीय सदस्य ने पहले से ब्यौरा पूछ लिया होता उन्होंने केवल संख्या पूछी थी इसलिये इतना ब्योरा तो नहीं है लेकिन जो मालूम है वह यह है कि- १२४ में से ११ तो बलवे में चालान हुये, द-३२४/३२४ में, १४ सेंघ लगाने मे, १६ चोरी में, '३४-१०६/११० में, २३-१०७/११७ तथा १२ फुटकर घाराग्रों में चालान हुये।

थाना मेहदावल जिला वस्ती मे चोरियां, डकंतियां ग्रीर हायांए

ं ४= श्री राजाराम शर्मा (जिला बम्ती) — क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना में हदावल बम्ती के क्षेत्र में सन् ५१ – ५२ ग्रीर ५२ – ५३ में ग्रलग ग्रलग कितनी चोरियां. कितनी डकॅतियां ग्रीर कितनी हत्याये हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई ह।

वर्ष		7 7 4 H H H H H H H H H H	चोरी	डकॅती	हत्या
१६५१			ሄ ሂ		~~~~~~ २
१६४२	• •		२६		3
६४३१	• •	• •	२०	8	ጸ

श्री राजाराम द्यामा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगे कि सन् १६५१ तथा १६५२ से ५३ में अधिक हत्याये हुई इसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-यह में ठीक कहीं बतला सकता कि क्यों अधिक हुईं।

श्री राजाराम शर्मा—जो चार हत्यायें हुई उसमें से कितनी खेतों के झगड़े से सम्बन्धित हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतना में ग्रभी कह सकता हूं कि इन चारों मामलों मे जिन लोगों ने हत्यायें की थीं वे गिरफ्तार हुये थे ग्रीर उनपर मुकदमे चल रहे हैं ग्रीर ज्यादा व्योरा मेरे पास इस समय नहीं है।

मेंहदावल (बस्ती) के कछार मे जनहित एवं कृषि रक्षा के लिए प्लिस चौकी

*४६—श्री राजाराम शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगे कि फसल की रझः के लिये थाना मेहदावल (बस्ती) के कछार साल की तरह इस साल भी पुलिस की चौकी बनाई गई है? यदि नहीं कायम की गई. तो उसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत वर्ष इस क्षेत्र में फसल की रक्षा के लिये कोई पुलिस चौकी नहीं बनाई गई थी वरन् कुछ सिपाही इस कार्य के लिये तैनात कर दिये गये थे। इम वर्ष भी वहीं व्यवस्था कायम रही।

श्री राजार।म शर्मा—जनहित ग्रौर कृषि रक्षा के हितार्थ क्या सरकार वहां पुलिस चौकी कायम करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रगर उस व्यवस्था के विना ही काम चल जाय तो फिर खर्चा बढाने की क्या जरूरत है। पारसाल भी वहां बिना चौकी के काम चल गया श्रौर इस साल भी चल रहा है।

थाना ईसा नगर जिला खीरी का भवन और थाना कर्मचारियों के लिए वदार्टर

*४०-श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खोरी)-न्या सरकार को जात है कि थाना ईसानगर जिला खीरी का भवन बहुत बुरी दशा में हें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५१--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार थाने का निरीक्षण करवाने के पश्चात् थाना कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने का विचार कर रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्व--जी हां।

*४२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ियोर्ट जिला ऋधिकारियों से प्राप्त हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस थाने मे कर्नचारियों के क्वार्टर्स कब तक बन जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मै ब्राशा करता हूं कि जो कुछ थोड़ी सी चीजें जिनकी स्थानीय ग्रधिकारियों को बहुत ही भ्रावश्यकता पड़ती है, वह ग्रगर १८–२० हजार रुपये में तैयार हो जाय तो वह इस साल के भीतर बन जायेगे।

गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की योजना

*५४--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सम्यूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि बिरनो थाने की इमारत खपरैल की बनी हुई है श्रौर ब दरों के द्वारा उसे उजाड़ देने से कर्मचारियों को वर्षा ऋतु में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, बात बिल्कुल सही है। इस साल बजट में १,१०४ रुपया रख दिया गया है जिससे उसकी मरम्मत हो जायगी। उम्मीद है कि इतने में काम चल जायगा।

श्री कमलासिंह क्या सरकार को यह मालूम है कि उस थाने का ३/४ हिस्सा तक ध्वस्त हो चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक इसी रूप में तो नहीं मालूम है लेकिन जब ग्राप कहते हैं तो बात बिल्कुल सही होगी।

नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में भ्राने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या

*५५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान पाकिस्तान से परमानेंटली सेटिल होने के लिए ग्राये हैं ग्रौर कितने ग्राने वाले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में २४,०६८ मुसलमान मई, १६४० से ग्रमी तक स्थायी रूप से बसने के लिये ग्राये हैं। प्रदेश की सरकार के पास ग्रभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भविष्य में ग्रौर मुसलमान स्थायी रूप से बसने के लिये पाकिस्तान से इस प्रान्त में ग्राने वाले हैं।

*५६—श्री गंगाघर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद कितने मुसलमान उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में सेटिल होने के लिये गये हैं और कितने जाने वाले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-सरकार के पास उन मुसलमानों कि सही संख्या जो इम पंक्ट के बाद स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसने चले गये है उपलब्ध नहीं है। हमारी मूचना के ब्रनुसार लगभग ३१,००० मुसलमानों ने इस बीच में ब्रपने पुराने निवास स्थानों को छोड़ा। इनमें से कितने पाकिस्तान गये ग्रौर कितने अपने शहरों को छोड़ कर और शहरों या प्रान्तों में बस गये इसका ठीक से पता चलाना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

सरकार के पाम कोई ऐसी सुचना नहीं है कि श्रव कोई मुसलमान इस प्रान्त से गाकिस्तान बसने के लिये जाने वाले है।

श्री गंगाबर मैठाणी-क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ४० के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में बसने के लिये ग्राये है उनको बसाने का सरकार ने क्या प्रबन्य किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-नेहरू-लियाकत जो पैक्ट था उसमें कहा गया था कि वह लोग जो लौटकर वापस श्रा जायेंगे उनके मकान श्रीर उनकी जायदाद उनको वापस मिल जायगी। उसी के लिहाज से उनको श्रपने घर श्रौर मकान वापस गये होंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पार्टीशन में जिन लोगों ने कोग्राप्ट किया था पाकिस्तान के लिये उनमें से कितने लोग वापस ग्राये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नेहरू-लियाकत पैक्ट में इतनी बात ग्रौर थी कि पहली फरवरी और ३१ मई, १९५० ई० के बीच में जो लोग चले गये थे वह अगर परमानेंटली बसने के लिये वापस श्राना चाहें तो श्रा सकते है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन मुसलमानों की सम्पत्ति इवैकुई प्रापर्टी घोषित कर देने के बाद भी उन्हें वापस दे दी जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो दे दी गई होगी क्योंकि वह तो सन् ४० की बात है ग्राँर श्राज सन् ५४ है। जो लोग श्राय होंगे उनमें से श्रिधकांश लोगों को वापसं हो गई होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग बसने के लिये ग्राय हं वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे या बाहर के थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-शर्त यह थी कि जो लोग उत्तर प्रदेश से गये थे वही लोग बसने पायेगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी-स्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग यहां सेटिल होने के लिये आये हं उनको सरकार ने क्या सहूलियतें दी हं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-बस यही सहूलियतें थीं कि उनकी जो प्रापर्टी है वह वापस लौटा दी जारेगी।

डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना

*६द—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी) (श्रनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में झांसी जिले में रामपुरा गांव के समीप झांसी की पुलिस ने डाकुओं के दल को, जिसका नेतृत्व स्वयं मानसिंह कर रहा था, बेतवा की घाटियों में घेर लिया था?

ड कटर सम्पूर्णानन्द—द मार्च, सन् १६५४ को झांसी की पुलिस ने डाकुग्रो के एक सशस्त्र गिरोह को, जिसको मार्नासह का गिरोह कहा जाता है, रामपुरा ग्राम के समीप एक पहाड़ी पर से बेतवा नदी के खंडहरों मे जाते हुये देखा। डाकुग्रों के दल को पूरी तौर से नहीं घेरा जा सका।

*६६—श्री कृष्णचन्द्र स्रार्य (स्रनुपस्थित) - क्या यह सही है कि पुलिस डाकुस्रों के दल को पकड़नें में स्रसमर्थ रही ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। बेतवा नदी कई स्थानों पर उथली ग्रौर उतराऊ थी। जिस भाग में गिरोह धूम रहा था वह भाग नदी के बड़े-बड़े खंडहरों ग्रौर धन जगलों से धिरा है। गिरोह तुरन्त ही उन घने जगलों में घुस गया ग्रौर रात्रि होने के कारण उसका पीछा नहीं किया जा सका।

*७०—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (ग्रनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री डाकुग्रों के दल की संख्या तथा उनके शस्त्रों ग्रादि के सम्बन्ध में तथा पुलिस की संख्या के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह पता नहीं कि डाकुग्रों के गिरोह में कितने भ्रादमी थे परन्तु ग्रनुमान है कि १४ ग्रौर १८ के बीच थे? उनके शस्त्रों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पुलिस की कुल संख्या ७ प्राविशियल ग्राम्ड कान्स्टेबुलरी सेकान ग्रौर ६ सशस्त्र गार्ड थी।

देवरिया लाक-ग्रप में कैदियों की जगह

*७३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (ग्रनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया लाक-ग्रप (Lock-up) में कितने कैदियों की रहने की जगह है ग्रौर कितने कैदी इस समय है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—देवरिया लाक-ग्रप मे ७६ कैदियों के लिये जगह है। तारीख २३-४-१९४४ को वहां १४२ कैदी थे।

मौजा डीह, जिला राय बरेली में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु

*७४—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (ग्रनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जो डाका १४ ग्रीर १५ दिसम्बर, सन् १९५३ की बीच की रात में मौजा डीह, जिला रायबरेली में पड़ा उसमें एक ग्रादमी जान से मार डाला गया?

*७५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले में ग्रब तक स्थानीय पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाका तो कोई नहीं पड़ा किन्तु दफा ४६०/३०२ ग्राई० पी० सी० का एक मामला ग्रवश्य हुग्रा जिसमे एक व्यक्ति जान से मार डाला गया। मामले की जांच ग्रभी जारी है।

श्रतारांकित प्रक्त

जिला बरेली में बन्दूक, राइफल ग्रौर रिवाल्वर के लाइसेंस

१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृषा करेगी कि जिला बरेली में बन्द्क, राइफल और रिवाल्वर की दरख्वास्तें सन् १६५३ में कितनी ब्राई और कितने लाइसेंस दिये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्रावश्यक सूचना संलग्न विवरण मे देखिये। (देखिये नन्धी 'गं ग्रागे एटठ ४४० पर)

प्रनापगढ़ जिने के प्रन्येक थाने में पुलिस कर्मचारियों की संख्या

२—श्री रामग्रधार तिवारी—क्या मरकार यह बताने की कृपा करेगी के प्रतापगढ़ जिले में प्रत्येक थाने की sanct.cred strength कितने पुलिस के कर्मचारियों की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-व्योरा साथ की तालिका में दिया हुन्ना है।

(देखिये नत्थी 'घं स्रागे पृष्ठ ४४१ पर)

३—श्री रामग्रधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १६५३ से जनवरी सन् १६५४ तक प्रतिमास प्रत्येक थाने पर कितने पुलिम कर्मचारी रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णीनन्द—इस प्रकार का व्योरा देना जनहित मे ठीक न होगा। [७ मई, १९५४ के प्रक्न]

तारांकित प्रक्न

जौनपुर जेल में सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए केंदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या

*१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार वताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सजायापता और Under trial कुल कितने कैदी जौनपुर जेल में है और उनमे कितनी संख्या पिछड़ी तथा हरिजन जाति की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस जेल में ३१ मार्च, १९४४ को १२७ सजायाफ्ता ग्रीर १०२ विचाराघीन बन्दी थे। पिछड़ी तथा हरिजन जाति के बन्दियों की संख्या ४५ थी।

*२--श्री बाबूनन्दन-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् ५३ ई० से नवम्बर सन् ५३ तक कितने कैदी जौनपुर जेल से भाग गये श्रौर उसमें से कितने पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मार्च से नवम्बर, १९५३ तक जिला जेल जौनपुर से दो कैदी भागे थे। इनमें से एक कैदी पकड़ा गया और फिर जेल में लाया गया।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जौनपुर जेल से यह जो २ कैदी भागे थे, किसकी लापरवाही से भागे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सी० ग्राई० डी० इसकी जांच कर रही है श्रौर उसकी रिपोर्ट श्रभी श्रायी नहीं है।

शिक्षा पुनः संगठन योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोडने का विचार

*३—श्री झारखंडे राय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा पुनःसंगठन योजना के मातहत कितने प्राइमरी स्कूल तोड़े जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—इस विषय में सरकार ने कोई स्पष्ट मादेश नहीं निकाले हैं। जिला परिषद् स्वयं विचार करेगी। *४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार जो प्रध्यापक बेकार होंगे उन्हें काम पर लगाने की कौन सी योजना पर सरकार विचार कर रही हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रक्त नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार का ऐसा विचार है कि प्राडमरी स्कूल्स तोड़े जायं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

नैपाल भेजी गई पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि पी० ए० सी० की जो बटेलियने ग्रभी हाल में नैपाल भेजी गई थीं उन पर कुल कितना व्यय हुन्ना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत जुलाई में नैपाल में भेजी गयी पी० ए० सी० की यूनिटों पर कुल २६,२०४-११-० व्यय हुग्रा।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्चा केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को मिलेगा या नेपाल से दिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मै यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार का प्रक्ष ग्राज से काफी पहले हो चुका है ग्रीर में बतला चुका हूं कि रुपया मिल जायगा केन्द्रीय सरकार से। श्रब केन्द्रीय सरकार ग्रपने पास से देगी या नैपाल सरकार से लेगी, इसका हमको पता नहीं है।

*६-७-श्री रामसुन्दर पाण्डेय-[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-६-श्री धर्मसिह-[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-श्री श्रमींसह-[२१ मई, १६५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्रागरा जिले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्टे

*११—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५२ से थ्रब तक ग्रागरा जिले में डकैतियों व कल्लों की कितनी रिपोर्ट दर्ज की गईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्व—तारीख १-१-१९५२ से तारीख २८-४-१९५४ तक डकैतियों की ४२ तथा कत्लों की ६५ रिपोर्ट दर्ज की गई।

*१२--श्री पुत्तू लाल-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी डकैतियों व कत्लों में पुलिस ने चालान किया श्रौर कितने मामलों में तफतीश करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती के ४२ मामलों में से २६ में चालान किया गया, ५ में बाद तकतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा द्र में जांच जारी है।

कत्ल के ६४ मामलों में से ४४ में चालान किया गया, १४ में बाद तफतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा ४ में भ्रभी जांच जारी है। प्रमान के प्रमान क्या सरकार को जात है कि डकॅनियों व कन्लों की मुक्ज देने बाने लोगों के विनद्ध अधि तर मामलों में १०७ ११७ जा० फौ० के मुकदमें बना दिये जाने है ? यदि हां, तो क्यों ?

ठारदर समर्गिनन्द—की नहीं। अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। परन्तु कभी कभी दलों में आपसी झगड़ों के कारण या झूठी रिपोर्ट करने वालों के विरुद्ध जन्मी कार्यवाही करनी पड़नी है।

श्री पृत् त'ल-क्या सरकार यह बतलाने का कट करेगी कि इन ग्रपराधों के बढ़ने का क्या कारण है ग्रीर सरकार उनको रोकने के लिये क्या कर रही है?

ड क्टर सम्पूर्णानन्द—श्रपराथ बढ़ने का ठीक कारण बता सकना तो बड़ा मुद्दिकल है। रोकथाम की जा रही हैं। में समझता हूं कि इस वक्त रिपोर्टिंग बड़ी श्रच्छी होनी है। जो सरकार की तरफ से श्रादेश दिया गया है कि रिपोर्ट पूरी— पूरी लिखी जाय, उसकी वजह से भी संख्या कुछ बढ़ी हुई मालूम होती हैं।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ १०७, ११७ जाब्ता फोजदारी की जगह पर १८२ के मुकदमें क्यों नहीं चलाये जाते?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८२ के मुकदमें भी चलाये जाते हैं श्रौर १०७/११७ मे यह होता है कि लोग श्रपने घरों में बैठे रहते हैं श्रौर फसाद रुक जाता है।

*१४—श्री बाबू नन्दन—[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।] फैजाबाद के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता; देने का आ्रादेश

*१५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् १९४२-४३ के बजट में फेंजाबाद के किन-किन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सरकार ने प्रति स्कूल ५०० रुपये की सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सिचव (डाक्टर सीताराम)--

- (१) जूनियर हाई स्कूल, देवीपुर।
- (२) ग्रार० डी० जू० हा० स्कूल, सुचितगंज, सोहावल।
- (३) जुनियर हाई स्कूल, बसखेरी।

*१६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध का स्रादेश कब हुआ ?

ड.क्टर सीताराम—उपर्युक्त दो पाठशालाग्रों को १६४८-४६ से तथा तीसरी पाठशाला को १६५१-५२ से यह स्रावर्तक स्रनुदान दिया जा रहा है।

> पिहानी (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता

*१७—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिहानी. जिला हरदोई में सन् १६५० से म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो स्कूल चल रहे है उसके निमित्त सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को कितना ग्रान्ट देती है?

डाक्टर सीताराम—कुछ भी नहीं।

*१८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्यक्त स्कूलों में ग्रब तक म्युनिसिपल बोर्ड पिहानी का लगभग ४० हजार रुपया व्यय हो चुका है ग्रौर वहां के स्टाफ को चार चार माह तक वेतन नहीं मिल पाता है?

डाक्टर सीताराम-सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

*१६—श्री कन्हैया लाल व। तमीकि—क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड, पिहानी को इस घाटे की पूर्ति के निमित्त शीघ्र ही किसी प्रकार की ग्रायिक सहायता देने का विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम—पूरी सूचना मंगाई जा रही है, उसके भ्राने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसियल बोर्ड, पिहानी ने इस विषय में शिक्षा विभाग से कुछ लिखा-पढ़ी की है।

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, म्यूनिसिपल बोर्ड के ग्रध्यक्ष ने एक रेप्रेजेंटेशन गर्वनमेंट के पास भेजा है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच करने में कितना समय लगेगा?

श्री हरगोविन्द सिह—जांच का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि स्राया पिहानी म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिये कोई स्रनुदान दिया जाय या नहीं।

प्रदेशीय मालबानों में प्रोहिबिटेड गोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा

*२०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (ग्रनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन बोर के हथियार प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में श्राते हैं? क्या केन्द्रीय सरकार के श्रादेश से ही प्रतिबन्ध लगाये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—निम्नलिखित बोर के शस्त्र प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में श्राते हैं:--

- (क) ३०३ बोर के रायफल ४१० बोर से मस्केट तथा इस किस्म के शस्त्रों के हिस्से तथा इनमें लगने वाले पुर्जे,
- . (ख) ऐसी रायफर्ले, जिनमे ३०३ बोर के रायफल के कुछ खास हिस्से लग[ं] कर इस्तेमाल होती है,
 - (ग) ४४१ से ४५५ तक किसी भी बीच के बोर के पिस्तौल या रिवाल्वर या ३८ बोर या ६ मि० मी० ''कैलिबर'' के पिस्तौल। रिवाल्वर तथा इन शस्त्रों के हिस्से व पुजं।

यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार के ब्रादेश से लगाये गये हैं।

*२१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (ब्रनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय मालकानों में प्रोहिबिटेड बोर के कितने हिषयार ब्रब तक जमा हो चुके है?

ढाक्टर सम्पूर्णानन्द--- ८०५।

हाथरस नगर में पैविलियन के लिए नगरपालिका को ग्रांट

*२२—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला ग्रलोगढ़)—क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि नगरपालिका, हाथरस को एक पैवीलियन बनाने के लिये १६४६-५० में कितनी ग्रान्ट दी गई थी और वह पैविलियन नगर हाथरस में कहां बनाया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, इसके लिए रुपया नहीं दिया गया था। प्रक्त नहीं उठता।

देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी

*२३—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला ग्रलीगढ़)—क्या सरकार बताने की हुपा करेगी कि दिसम्बर के ग्राखरी हफ्ते में देहली दरवाजे, ग्रलीगढ़ में गोली चली थी, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दफा ३०७ ताजीरात हिन्द में हुई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक रिपोर्ट घारा ३०७ के अन्तर्गत २६ दिसम्बर मन् १९५३ को रग्घा उर्फ रघुवीर सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई, जिसमें कह; गया या कि डालचन्द उर्फ डल्ला ने उसके ऊपर दो बार गोली चलाई।

*२४—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में उन लोगों को नहीं पकड़ा जिनके नाम रिपोर्ट में थे, परन्तु रिपोर्ट करने वालों को पकड़ कर जेल भेजा गया था? यदि हां, तो ग्रागे क्या कार्यवाही इस मामले में हुई?

डाक्टर सम्यूर्णानन्द— सूचना रिपोर्ट (F. I. R.) के नामों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग फरार है। फरार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा द७—दद के ग्रन्तर्गत कार्यवाही की गई है। मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। दोनों पार्टियों के विरुद्ध किमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के ग्रन्तर्गत कार्यवाही की गई हं, क्योंकि उनके ग्रायसी सम्बन्ध खराब हो रहे थे ग्रोर शान्ति भंग होने की ग्राशंका थी।

गोरखपुर विव्वविद्यालय सम्बन्धी बिल

*२५—श्री द्वारिकः प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—वया सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल विधान सभा के सम्मुख कब रखने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—ग्राञा की जाती है कि बिल विघान सभा के श्रागामी श्रिविदेशन में प्रस्तुत किया जा सकेंगा।

लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के ग्रध्ययन के लिए यात्रा ग्रौर उस पर व्यय

*२६—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरलपुर)— क्या यह सच है कि लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों का अध्ययन करने जा रहे हैं? यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है तथा इसमें कितना खर्च होगा? डाक्टर सम्पूर्णायन्द--ग्रभी हाल में जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों की कार्य प्रणाली का प्रध्ययन करने गए थे।

इस यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना तथा उनके कैंदियों के सुधार सम्बन्धी संस्थाओं की कार्य प्रणाली समझने में सहायता देना है,

इस यात्रा पर कुल ३४२३ रु० श्रौर ६ पाई खर्च हुन्ना था जिसमे ने इस्सरकार ने केवल १,११४ रु० ६ ग्राने ३ पाई खर्च किया था श्रौर शेष २३०८ रु० श्राने ३ पाई श्रन्य प्रदेशों की सरकारों ने जिनके विद्यार्थी स्कूल में शिक्षण प्राप्त करने ग्राये थे ।

*२७-२८--श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)--[३ जून, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४७-४८ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रतायगढ जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

*२६—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि १६५२ तथा १६५३ में कितने व्यक्तियों को प्रतापगढ़ जिले में रिवाल्वर दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— सन् १६५२ में ३ तथा सन् १६५३ में ५ व्यक्तियों को रिवाल्वर लायसेंस दिये गये।

*३०-३१--भ्री देवकीनन्दन विभव--[१६ मई, १६५४ के लिये प्रक्त संख्या ६२-६३ के ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्थित तथा विषैले पानी से उत्पन्न दुष्परिणामों की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था

*३२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १६४६ में एक जांच समिति गन्ना फैक्ट्रियों के दुर्गन्धित तथा विषेते पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के सम्बन्ध में बनाई गई थी? यदि हां, तो इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- जी हां। कमेटी ने ग्रपनी रिपोर्ट ग्रब भेजी है जो सरकार के विचाराधीन है।

*३३—श्री श्रीचन्द—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वुर्गिन्धित तथा विषैले पानी को साफ करने के लिये एक्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट किन-किन गन्ना फैक्टरियों में लगाये जा चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— शासन ने स्रभी इस सम्बन्ध में कोई स्रादेश नहीं दिया है स्रोर उसके पास इस विषय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

नगरपालिका मेरठ में सहायक हाजिरी श्रफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी श्रादेश

*३४—श्री सुल्तान स्रालम खां (जिला फर्वखाबाद)—क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका, मेरठ में सहायक हाजिरी श्रफसर की जगह ११ श्रगस्त, १९५३ से श्रव तक खाली पड़ी हुई है? श्री हर गोविन्द सिंह—३ ग्रगस्त. १६५३ में नहीं बन्कि ३ दिसम्बर १६५३

"३५—श्री सुल्नान श्रालम खां—क्या मरकार को यह जात है कि महायक हाजिनी ब्राप्टमर, नगरपालिका, मेरठ के रिक्त स्थान को भरने के लिये मरकारी ब्रादेश स० =६२६ १५—७४४६-५३, १५ ब्रक्टूबर, ५३ जारी हुआ था?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह राजाज्ञा सहायक हाजिरी श्राफिसर के पद को भन्ने के निये नहीं जारी हुई थी बिल्क यह इसके द्वारा श्री नजीरउद्दीन फेजी को ट्रेनिंग की योग्यना के बंधन से मुक्त किया गया था।

"३६—श्री मुल्तान स्रालम खां—क्या यह सत्य है कि स्रव तक इस सरकारी स्रादेश का पालन नहीं हुसा?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

"३७-३८-अो गंगाघर मैठाणो-[४ जून, १६५४ के निये स्थगित किये गये।]
गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों श्रौर सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतनक्रम में श्रन्तर

"३६--श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस) -- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुप्तचर पुलिस इंस्पेटरों श्रीर मिविल पुलिस सब-इन्पेक्टरों (थानेदारों) के देनन-क्रम में क्या ग्रन्तर है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुग्तचर पुलिस इंस्पेक्टरो का वेतन क्रम ६० २००-१०-२५०-प्र० ग्र०-१५-४०० हं और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों (थानेदारों) का वेतन-क्रम ६० १२०-६-१८०-प्र० ग्र०-१०--२०० हे।

"४०—श्री बल देव सिह—क्या थाने के इंचार्ज मव-इन्सपेक्टरों को घोड़ा रखना ग्रावक्यक हे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी नहीं।

हमीनपुर मे गत वर्ष दिवाली के ग्रवसर पर पकड़े गटे जुन्नाड़ी

*४१—श्री मन्नी लाल गुहदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष दिवाली के श्रवसर पर जिला हमीरपुर में क्तिने जुए किन-किन ग्रामों म पक्ड़े गये ग्रीर उनमें कितने ग्रादिमयों ने सजा पाई ग्रीर कितने छट गये?

डाक्टर सम्यूर्णानन्द—मांगी गई मूचना संलग्न विवरण पत्र मे देखी जा सकती है। (देखिये नत्थी 'इ' स्रागे पृष्ठ ४४२ पर।)

फर्रखाबः व के थाना का रमणं ज तथा किम्पल मे जन वर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां

"४२—श्री रें ्सिह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि थाना कायमगंज श्रीर किम्पल, जिला फर्रुखाबाद में पिछले एक वर्ष में कितने कत्ल, कितनी डकेंती, कितनी राहजनी तथा कितनी चोरियां हुई श्रीर उनमें से कितने में मुकदमें चले श्रीर कितने मुकदमों में सजा हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्य--सूचना संलग्न विवरण पत्र मे देखी जा सकती हे।

(देखिये नत्थी 'च' म्रागे पृष्ठ ४४३ पर)

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अन्दान में कटौती

*४३—-श्री गोवर्धन तिवारी (जिला ग्रल्मोड़ा)—क्या राज्य के उच्चनर माध्यमिक विद्यालयों के ग्रनुदान में इस वर्ष कुछ कटौती की गई हैं? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत कटौती की गई ग्रीर क्यों की गई?

श्री हरगोविन्द सिह—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

सांसी ज्ञहर (म्युनिसियल क्षेत्र) में चोरियां और उनकी रिपोर्ट

*४४—श्री लक्ष्मण राव कयम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में फरवरी ग्रीर मार्च में चोरियों की किन्नी रिपोर्ट दर्ज हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्य-चोरियों को कुल १६ रिपोर्टे दर्ध हुयीं।

४४५—११ लक्ष्मण राव काउम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समय मे जो चोरियां हुई है उनमे कितनी पकड़ी गई ह?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६ चोरियां पकड़ी गयीं।

*४६--श्री श्रमरेशचन्द्र पाण्डेय(जिला मिर्जापुर)—[१४ मई, १९५४ के लिये प्रज्न संख्या ८४ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

*४७-४६--श्री सूर्य्य प्रसाद ग्रवस्थी (जिला कानपुर)--[२१ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

*५०-५२--श्री ग्रमरेशचन्द्र पाण्डेय--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित गिये गर्द ।]

सुभाषनगर ने साबद्र कोंव (जःलोन) पुलिम स्टेशन से हिस्ट्रीशीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना

*५३—-श्री चित्तर्राप्तह निरंजन (जिला जालौन) —क्या सरकार को विदित है कि मुहल्ला सुभाषनगर (ग्रिष्टितयाबाट) से संबंधित कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन का रिजस्टर नं० ८ जिसमें हिस्ट्रीशोटर्स नामांकित रहते हैं, गायब हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ।

सरकार का ग्रामों के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार

*५४--श्री मञ्जीलाल गुरुदेव--ध्या सरकार ग्रामों में मुखियों के पद को तोड़े जाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है।

*५५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१२ मई, १६५४ के लिये स्थगित किया गया ।] प्रत्नोत्तर ३८५

जिला मुरादाबाद में चार वर्षों में ग्रिधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर

"४६—श्री स्याली राम (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद पुलिस में कान मब-इन्मपेक्टर व इन्सपेक्टर ऐसे हे जिन्हें जिले में चार बर्ज में ऋधिक समय हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुरादाबाद जिले में ऐसा कोई इन्सपेक्टर नहीं है। परन्तु १४ मव-इन्सपेक्टरों को मुरादाबाद जिले में ४ वर्ष में ग्रिधिक समय हो गया है। इनके नाम मंत्रान मुची में दिये हुदे है।

(देखिये नत्थी 'छ' म्रागे पृष्ठं ४४४ पर।)

ं 3—श्री स्थानी राम—क्या गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे नियम बना रक्खे हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी जिले में ३ वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता?

डाक्टर सम्पूर्णात्रन्द--जी नहीं।

े ४=-४६--श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)--[२१ मई, १६४४ के लिये स्थिगत किये गये।

"६०-६१-श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवस्या)-[२१ मई, १६४४ के लिये स्थिगत किये गये।]

एटा जिले में ग्राम सिमितियां ग्रीर उनका डाल्जों से मुकाबिला

*६२—श्री बाब्राम गुप्त (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में थानेवार कितने गाँव हे और उनमें से कितनों में ग्राम रक्षा समितियां इन चुकी हे? क्या किसी ग्राम रक्षा कमेटों ने कहीं डाकुओं का मुकाबला भी किया ग्रथवा और कोई उल्लेखनीय कार्य किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एटा जिले के समस्त ग्रामों मे ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी ह। मांगी हुई मूचना संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ज' श्रागे पष्ठ ४४५ पर।)

चन्दौसी (मुरादाबाद) भे थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्याएं

*६३--श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद) --क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि फरवरी मास मे चन्दौसी जिला मुरादाबाद में दिन के दो बजे के लगभग थाने के निकट ही तीन हत्याये की गई हैं। यदि हां, तो ग्रब तक पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने में क्या-क्या कार्यवाहियां की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हो। इस संबन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो श्रभी फरार है। उनको भी पकड़ने का पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है।

*६४-श्री महीलाल-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना से पूर्व दिन में ही एक स्त्री की हत्या चन्दौसी नगर में हुई थी? उसके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हो रही है। डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। हत्यारों का पता लग गया है ग्रौर उनको गिरफ्नार करन की कोशिश की जा रही हैं।

राजकीय इंटर कालेज, रामपुर में कक्षा ११वी मे कामर्स की शिक्षा

*६५—श्री फ़जलुलहर्क (जिला रामपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालिज, रामपुर में कक्षा ११ में कामर्स की शिक्षा कब से हो रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह--२७ ग्रगस्त, १६५१ से।

जौनपुर जिले मे ग्राम रक्षा समितियों का संगठन ग्रौर ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस

*६६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी हां।

*६७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो किन-किन थानों पर ग्रौर किन-किन ग्रामों में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जौनपुर जिले के समस्त थानों के सब ग्रामों मे ग्राम रक्षा सिम-तियां बन गई है। कुछ छोटे ग्रामों को निकटवर्ती बड़े ग्रामों मे मिला दिया गया है।

*६८-श्री रमेशचन्द्र शर्मा-क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या ग्राम-रक्षकों को बन्द्क का लाइसेस दिया जाने वाला है? यदि हां, तो किस शर्त पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम रक्षा समिति के सिक्रय सदस्यों को बन्दूक के लाइसेस दिये जाते हैं यदि वे उसके लिये योग्य हों।

*६६--श्री राम चन्द्र विकल--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित क्या गया।]

*७०-७१--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--[२१ मई, १६५४ के लिये स्थिगत किये गये।]

१६४६ के मध्य में ग्रस्थायी हप से नियुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स ग्राफ स्कूल्स की संख्या ग्रीर उनका स्थायीकरण

*७२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि जुलाई ग्रौर ग्रगस्त, १६४६ ई० में शिक्षा विभाग में जो सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स श्राफ स्कूल्म ग्रस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे उनकी संख्या कितनी है ग्रौर सरकार उनको स्थ या बनाने का निर्णय कब करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—जुलाई, १६४६ में कुल ८५ विद्यालय प्रति उप निरीक्षक ग्रस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, जिनमें से कुछ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, कुछ लोक सेवा परिषद द्वारा सहायक श्रध्यापक तथा विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक के लिये चुन लिये गये हे श्रौर श्रव इनमें से केवल श्राठ शेष बचे हैं जिनके स्थायीकरण के प्रदन पर उस समय विचार किया जायेगा जब विभाग में स्थायी पद रिवत होंगे।

१६ अ में हाथरम में मामूहिक जुर्माने की धनराशि ग्रीर उमका ब्यय किया जाना

" ७३ — श्री नन्दज्मार देव वाझिष्ट (जिला ग्रेलीगढ़) — क्या मरकार यह बताने की हुया करेगी कि १६४७ में हाथरस में जो मामूहिक जुरमाना वमूल किया गया था उसकी बनराधि किननी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मन् १९४७ के साम्प्रदायिक उपद्रवों के सिलसिले में हाथरम मिटी में ४२,७६३ रु० वसूल किया गया था।

"७४—%ी नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह धनराशि किस कार्य पर व्यय की गई है? यदि ग्रभी व्यय नहीं हुई है, तो सरकार उसे किम कार्य पर व्यय करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार द्वारा लगाये गये ग्रन्य जुरमानों की भांति यह जुरमाना भी मरकारो कोष में जमा कर दिया गया। यह बताना कि सरकारी कोष से यह घनराशि किम कार्य में खर्च की गई या की जावेगी, संभव नहीं है।

कारीय कर (सीतापुर) में डकैती और उस पर कार्यवाही

"७५—श्री गंगाधर गर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १६-१७ जुलाई, १६५३ की रात को जो डकैती गांव कारीपाकर, थाना महोली, जिला सीतापुर में पड़ी थी, उसकी सर्वप्रथम जांच थाना महोली के किस पुलिस श्राफिसर ने की थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस डकंती की सर्वप्रथम जांच श्री रामिककोर सब-इन्सपेक्टर ने की थी।

*७६—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कारीपाकर डकैनी के सिलसिले में श्रव तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्यूर्णानन्द—दो व्यक्तियों के विरुद्ध ग्राई० पी० सी० की धारा ४१२ के अन्तर्गत मुकदमा ग्रदालत में भेज दिया गया है।

वसन्त कन्या इंटर कालेज, कमक्षा, शहर बनारस का स्थानान्तरण

"७७—श्री शिवमंगल सिंह कप्र(जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बमन्त कन्या इन्टर कालेज (थ्योसिफिकल कन्या इन्टर कालेज), कमक्षा, शहर बनारम की प्रवन्थक समिति ने कालेज को कमक्षा से राजघाट स्थानान्तरित करने के विषय में सरकार में ब्राज्ञा मांगी है ?

श्री हरगोविन्द सिह—जी नहीं।

जिला बिलया में हरिजनों के लिए मकान तथा पीने के पानी के लिए सहायता एवं कुग्रों का निर्माण

*७८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बिलया)—क्या सरकार कृपन, बतायेगी कि गत दो वर्षों मे पृथक-पृथक हरिजनों के लिये मकान तथा पानी पीने के कुये बनवाने के निये कितना रुपया जिला बिलया को दिया गया था ग्रौर जिला ग्रिवकारियों द्वारा वह रुपया किस प्रकार क्यय किया गया?

श्री हर गोविन्द विह—गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलिया में मकान तथा पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये हरिजनों के लिये स्वीकृत श्रनुदानों के व्यय का विवरण उत्तर के माथ नत्थी है।

*७६—-श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिल्यः में गत दो वर्षों में कितने हरिजनों ने कुयें बनाने के लिये जिला नियोजन अधिकारी के पान्र प्रार्थना-पत्र दिये और कितने कुयें बने ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बिलया के नियोजन प्रधिकारी के पास कुन्नां बनवाने के लिये २६८ हरिजनों ने त्रावेदन-पत्र भेजे। ६२ नये कुये बने श्रीर ५३ कुटों की मरम्मत हुई।

उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिए १६५३-५४ ोमें लोशल वर्कने की नियुक्ति एवं उन पर व्यय

*८०—श्री पुत् लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १६५३-५४ में उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये कुल कितने सोशल वर्कर्स निधुक्त किये गये होंर उनकी ग्रानरेरियम देने में कितना धन व्यय किया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह--१६५३-५४ के वित्तीय वर्ष में ४७ सोशल वर्कसं नियुक्त किये गये उनको स्नानरेरियम देने में फरवरी, १६५४ तक लगभग ७,०३० रु० व्यय किया गया।

मऊ थाना (ऋाजमगढ़) में चोरियां ऋौर डकैतियां

* द १ — श्री रामसुन्दर पाण्डेय — क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मळ थाना जिला ग्राजमगढ़ में जनवरी ग्रौर फरवरी मास सन् १६५४ में कितनी चोरियां ग्रौर डकैंतियां हुई हं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल २६ चोरियां हुयीं। डकैती की एक भी घटना नहीं हुई। उन्नाव जिले में थानेवार कत्ल श्रीर डाके तथा गुंडों, बदमाशों श्रादि की सूची

*८२—श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १ जनवरी, १६५३ से १५ फरवरी, १६५४ तक उन्नाव जिले में थानेवार कितने डाके पड़े, कितने कत्ल हुये तथा उक्त अपराधों में कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्तो में देखी जा सकती है। (देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४४६ पर।)

*८३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस समय उक्त जिले के गुन्डों, बदमाशों श्रौर समाज विरोधी तत्वों जैसे निषिद्ध मादक द्रव्यों का रोजगार करने वालों एवं जुम्रा खेलाने वाले लोगों की कोई सूची बना रही है या बनाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी सूचियां समय-समय पर म्रावश्यकतानुसार बनती ही रहती हैं।

^{*}विवरण छात्रा नहीं गया।

क्ष्री राष्ट्रमाराघण की पुनः गिरफ्नारी के संबंध में विशेषाधिकार की सबहेलना का प्रकृत उठाने की प्रार्थना पर श्री स्रध्यक्ष की व्यवस्था

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्नारी के सम्बन्ध से जिलेगिकिए की श्रवहेनता का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की व्यवस्था

भी राध्यक्ष--मेरे यम श्री महन मोहन उपध्याय ने एक विशेषधिकार का प्रदूष उठाने के लिये एक पत्र भेदा है। यहाँ पर उन्होंने मूचना दे दी थी कि वे उस प्रदूष को उठाये। इस पर्य में श्री राजनारायण जी की जी दूसरी गिरक्तारी हुई उसके प्रदूष में द्वार कुट रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में भी जो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने सूच प्रदूष दे उठके प्रदूष में प्रदूष उठाया गया है। इसके पहले कि उसके क्रिका में रिपोर्ट दें से यह जानना चाहना हूं गृह मंत्री जी से कि क्या यह मामना प्रदूषण के प्रसूष में प्रदूष है।

गृह मंत्रों । डाण्या मास्या भाषा । — प्रध्यक्ष पहोदयः जो पहले ३३२ के मुकदमें दे उनके लिये ६ तारी ल है और जो १९७ के मुकदमें ह उनके लिये व तारी ल है।

श्री सदन सोहर उराध्या तिला हान्योहा,—बाध्यक्ष महोत्म, सेने जो यापमे इजाजर मांगी हे यह दिशोदाधिनारी की अवहेलना हुई हे उनको पेश करने को इजाहन संती है। उनका जहना यह है कि लीधन मानेस्टेशन वर्गरह हुआ है शोर उस पर सामगीय गृह संबी की ने कहा कि बहु अवासन के सामने है।

श्री श्रध्यक्ष — मेरे मामने जो पत्र हे वह मौजूद है इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं हे कि मोलेम्डेशन बर्गरा हुआ है। इसमें कई श्रीर बाते ह जिनका फंमला में दूंगा। पहले आप जो नानकारी रक्षते हे कि यह मामना श्रदालत के सामने हे या नहीं उसके पारे में श्राप कुछ कहना चाहते ह जसा कि श्रमी गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह सामला अदालत के सामने हे. उसके जपर श्राप कुछ कहना चाहते हं?

श्रो सदन मोहन उपाध्याय—जी नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष-तो किर ग्राप कृपा करके बैठ जाइये।

जो मेरे सामने श्रो मदन मोहन उपाध्याय जी का पत्र मौजूद है उसमें उन्होंने निर्फ गोल शब्दों में 'विशेषाधिकार की श्रवहेलना' हुई यह कहा है श्रोर जो सूचना मने मदन को दी थी जिला नेजिस्ट्रेट की सूचना के श्राधार पर कि किस तरह वह गिरफ्तार हुये, उस सूचना में उपाध्याय जी कहते हैं कि मंजिस्ट्रेट ने सदन को थोखा दिया. गलतबयानी की इत्यादि इत्यादि बाते उनके पत्र में दर्ज है। मंने इस सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह जो के प्रश्न उठाने पर यह फैसला दिया था कि रोजमर्रा का शासन का जो कार्य है श्रोर विशेषकर फौजदारों का, उनके मम्बन्ध में कोई प्रश्न प्रिविलेज का या काम रोको प्रस्ताव का नहीं उठ सकता है।

इसके बाद भी उन्होंने यह उचित समझा कि यह प्रिन्तिज या विशेषाधिकार की ग्रवहेलना का प्रश्न उठायें। एक ग्रौर भी ग्रव की बार यह वाकया
मालूम हुग्रा कि यह मामला ग्रदालत के सुपुर्द भी है। इसलिये ग्रौर भी विशेष कर
यह प्रश्न सदन में उठ नहीं सकता है। में इस बात की ग्रनुमित श्री उपाध्याय जी को
नहीं देता हूं कि वह इसको उपस्थित करें, इस कारण कि वह ग्रदालत के सामने है
ग्रौर इस कारण भी कि रोजमर्रा के इन्तजाम का प्रश्न है। जहां तक राव ग्रौर झूठ सूचना
देने का मामला है उसके बारे में गेंदा सिंह जी ने जब मामला उठाया था तब मैने ग्रपना
निर्णय दिया था वही इसके लिये भी लागू रहेगा।

श्रो गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ग्राध्यक्ष महोदय, मै एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्रो ग्रध्यक्ष--यह प्रक्त पूछने का समय नहीं है।

श्री गेंदासिह—मै विशेषाधिकार के प्रवन के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी वे प्रवन पूंछना चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष—गृह मंत्री जी ने जो सूचना श्रभी दी है उसके सम्बन्ध ने श्राप पूंछना चाहते हैं?

श्री गेंदा सिंह—जी हां। क्या माननीय गृह मंत्री जी को जानकारी है कि वह मामला चार्जशीट के साथ मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मेरी इत्तिला तो यह है कि तारीख भी तय हो चुई; है। पहले मुकद्दमों की तारीख ६ है ग्रीर दूसरे मुकदमें की तारीख़ द है।

श्री ग्रध्यक्ष--दूसरे मुकदमे जो ११७ है उनमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—श्रध्यक्ष महोदय, तारीख तो हर मुकदमें में पड़ जाती है लेकिन यह किस काम के लिये पड़ी है?

श्री ग्रध्यक्ष—यह विवाद का समय नहीं है। ग्राप विवाद शुरू कर रहे हे। लखनऊ यूनीर्वासटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह) — ग्रध्यक्ष महोदय, मं लखनऊ यूनीर्वासटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङा' स्रागे पृष्ठ ४४७--४६८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के श्रतिवेदन पर विचार

श्री ग्रध्यक्ष—ग्रब श्रो नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा को विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

श्री राघा मोहन सिंह (जिला बिलया) — माननोय ग्रध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि विज्ञेश विकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--में प्रथम यह बताये देता हूं कि १० मिनट का समय प्रत्येक स्वस्य को मिलेगा, जैता कि कल निञ्चय हुम्रा था।

श्री राघा मोहन सिंह—जहां तक इस प्रश्न पर विचार करने का सम्बन्ध है, में माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है ख्रौर यह तो हमारा सरकार का भी स्पष्ट मत है जिसे गृह मंत्री ने पहले वक्तव्य में साफ कर दिया था कि सदन के या माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न पर वह दृढ़प्रतिज्ञ है कि उसकी रक्षा को जाय। वे भी इसकी उतनी ही कदर चाहते हैं जितनी कि इस सदन का कोई सदस्य चाह सफता है। में यह कहना चाहता हूं कि इस केस के ऊगर जब हमको विचार करना है तो एक बात और अपने सामने रखनी पड़ेगी, वह यह है कि हमको किसी भावावेश में नहीं, अपने अधिकारों को बढ़ाने के विचार से नहीं, और कम करने के विचार से भी नहीं, बिल्क हमको तो एक न्यायालय के सदृश्य इस बात पर विचार करना है कि जो आज का कानून है उसके अनुसार हमारे तथा सदन के क्या विशेषाधिकार हैं। तब हम इस पर क्या निर्णय करें। में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाथ बंधे हुये हैं। जो कुछ भी हमारे संविधान

ने प्रस्मार हमको प्रशासित मिने हुये वृधन वही ह जो राउँ प्रशासम के गरिय मेट ने प्रियार ह जह पाइरी, प्रिविने के जार इस्प्रास्त है वह पाइरी, प्रिविने के जार इस्प्रास्त है। इस प्राप्त है। वह प्रशिक्षण प्राप्त है। वह प्रित्र प्राप्त हो। इस प्राप्त प्राप्त है। का जो प्रित्र प्राप्त है के का जो प्रित्र प्राप्त है वह कि लाज कह माने नहीं है। इस प्राप्त प्राप्त है के प्राप्त है। का प्रेर में, स्प्राप्त है कि लाज कहें प्रश्चित है। इस प्राप्त को माने प्रस्ता के प्राप्त है। का प्राप्त है। स्प्राप्त है। स्प्राप्त के माने प्रस्ता को प्राप्त है। प्राप्त इस भवन के माने प्रस्ता को प्राप्त है। विवाद को प्रस्त्त है। को प्राप्त है। विवाद को प्रस्त्त को प्राप्त है। को प्राप्त है। को प्राप्त को माने को माने को माने के माने को माने को प्राप्त है। हम जने को प्राप्त है। हम उन्हें प्रस्त्व करें हमको काम करना है।

भव इस प्रश्न पर प्रबह्म अपने ह नो जहां नक इसके बाकपान का रास्बन्ध है, यटनाम्रो का सम्बन्ध हं सब नामनीय सबस्यों की काम हे, म उनको दोहराना नहीं चाहना । उनाध्यक्ष महोदय ने ऋपनी छोटो में म्यं च में ग्रीर इस कमेटो के प्रतिवेदन में भी यह बाने साफ कर दी हे ब्रोर जो कुछ भी मंबंधिन बाकबात होंगे वह थोड़े में जब्दों में में आपके सामने रख दूंगा। प्रदन यह है कि माननीय ना प्रश्ण दत्त निवारी को ४ तारोख को काशोपुर में ग्रपने। पार्टी के ग्रादेश के ग्रतुसार गन्ना ले जाने वालों की गाड़ियों को रोक रहे थे। वहां के एम० डो० स्रो० वहा पहुंचते हे स्रौर उनको बनुलाने है कि ऐना नहीं करना चाहिये। इसके बाद में वह कार्य जारी रहता है तब एम० डी० म्रो० उनकी नार में हल्द्वानी ले जाकर छोड़ने का म्रादेश देने हु। कमेटी के सामने एस० डो० स्रो० को बुलाया गया। मं मानतीय सदस्यों मे अनुरोघ करूंगा कि कृपा कर उनके बयान को पहुँने का कट करे। उसने दो बाते भाफ मालूम होती है। एक यह कि उनकी प्ररेस्ट करने की मंत्रा कर्नी नहीं थी दूसरे यह कि वहां ग्रांकर उन्होंने यह देवा कि गन्ना ले जाने वाले लोग बहुत इम्पेशेट हो रहेथे. उनका गन्ना रुका हुन्रा था। वह लोग चाहनेथे कि हम गन्ना जरूर ले जायं ग्रौर यह श्रंदेशा थाकि बीच श्राफ पोप्त होगा। एस० डो० ग्रो० का कहना हैं कि वे लोग कह रहे थे (ग्राप लोग हट जाइये, हम गन्ना लेकर जायंगे)। ग्रार हम देखेंगे कि क्या होगा। ऐसी सूरत में ग्रगर एस० डी० ग्रो० वहां से हट जाते हं और लोगों को मौका देते हैं कि कोई गन्ना रोके ग्रौर कोई गन्ना ले जाये तो वह एक ब्रीच श्राफ पीस श्रवश्य हो जाता, श्रतएव माननीय नारायण दत्त जी की सुरक्षा का भी प्रश्न था क्योंकि यह तो गवन मेट का परम कर्तव्य है कि वह प्रत्ये ह मान नीय सदस्य की रजा का भी प्रवन्ध करे। ऐसी सूरत में जो कुछ कार्यवाही की गर्या उसका मतलब केवल यही नहीं था कि गन्ना शांतिपूर्वक मिले के अन्दर जाय बलिक यह भी मतलब था कि नारायण दत्त जी के जीवन की रक्षा की जाय। उनकी रक्षा का भी प्रश्न था। इसलिए एत० डी० एम० ने एक तरह का प्रिवेटिव मेजर (Preventive Measure) म्रस्तियार किया। सुरक्षा का रास्ता अपनाये। जो स्नाज्ञा माननीय सदस्य को दी गयी उसमें कहीं भी शब्द "स्ररेस्ट" नहीं लिखा है । उन्होंने यह समझा कि जिस तरह से कार्यवाही चल रही है उसते बीच ग्राफ पीस (शांति भंग) की पूर्ण श्राशंका है श्रौर इसके लिए यानी सुरक्षा के विचार से यह जरूरी समझा कि नारायण दन जी तिवारी वहां से तत्काल हटा दिये जायं । ग्रतएव जो ग्राज्ञा मैजिस्ट्रेट ने दो वह केवल मात्र मुरक्षा के खयाल से दी ब्ररेस्ट या कनकाइनमेट नहीं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा ग्रसंगत से हो रहे है क्योंकि वह प्रतिवेदन को स्वीकार करने को प्रस्ताव में कह रहे हैं ग्रीर उसने ग्ररेस्ट को मान लिया गया है। लेकिन वह बार-बार भाषण में कह रहे हैं कि ग्ररेस्ट करने का मंशा नहीं था। श्री राधामोहन सिह—जहां तक कमेटी का सवाल है अरेस्ट तो हमने मान ही लिय है कि अरेस्ट हुआ लेकिन सवाल तो अरेस्ट के किस्न का है। उस समय उक्त परिस्थित में जे अरेस्ट हुआ वह किस किस्म का था? किस मंगा से था? कनकाइनमेट को मंशा थी या नहीं? एक आदमी, जो कुर्ं में गिरने जा रहा हो उसको हम रोक ले, पकड़ लें तो उसको केवर रोकना ही अरेस्ट हो जाता है? लेकिन परिस्थिति और पकड़ने की मंशा सामने रखने पर बड़ा श्रंतर पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—प्दाइंट आफ आइंग् प्रध्यक्ष महोदय, में यह प्वाइंट आफ आईर रेज करना चाहता हूं कि जहां तक अरेस्ट का सम्बंब है यह तो रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कमेटी को यह राय थी कि अरेस्ट हुआ। अब उसमें माननीय वक्ता की राय यह न रही हो, यह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष — मेने तो उसके ऊपर उनको रोक दिया। इसलिए इसभे श्रव कोई प्वाइंट श्राफ श्राडर का सवाल बाकी नहीं रहा।

श्री राधामोहन सिंह—जहां तक प्रश्न कमेटी का है हमने तो मान लिया ्रिं श्ररेस्ट हुआ। लेकिन अरेस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज है उनको कैसे भूला जाय ? कोई आदमी कुए में कूद रहा है, उसको हमने पकड़ लिया तो वह अरेस्ट हो गया ? इसी तरह से नारायण दत्त जी कानून तोड़ने पर तुले हुए थे, शांति रक्षा का एक ही रास्ता था। अतएव उनको वहां से हटा दिया गया था। तो जैसा मैने पहले निवेदन किया, दोनों में बड़ा श्रंतर है। अतएव हमें तो यह देखना है कि उनका क्या मंशा था। मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस में पन्ना ५०-५१ पर इस सम्बन्ध में एक रूलिंग दी हुयो है। उन रूलिंग में यह साफ है। के जहां तक अरेस्ट की बात है, उसकी मंशा अपर यह हो कि वह कनकाइन कर दिया जाय तब तो श्रीमान अध्यक्ष मह दय को इसिला देना लाजिमो होता है लेकिन जैसा इस केस में जब उन्होंने उनको अरेस्ट किया तो उनकी यह मंशा कभी नहीं थी कि कनकाइन किया जाय बिल्क यह मंशा थी कि उनको हल्द्वानी ले जाकर छोड़ हैंगे। उनका श्रांका में भी दर्ज है।

एक ऐता हो केस बोच श्राफ त्रिविलेज का ब्रिटिश पालियामेट के सामने श्राया था। उसरें यह था कि कनविक्शन हुम्रा लेकिन जमानत बेल की दरख्वास्त पड़ गयो ग्रौर यह हुन्रा कि मंजूर कर लो जाय लेकिन बेल की कार्यवाही करने में ५ घंडे ला गये थ्रीर उस ५ घंडे तक वह कंकाइनमेंट में रहे, बाहर नहीं जा सके जब तक कि बेल नहीं मंजूर हुयो। हाउस आफ कामन्स की प्रिविलेज कमेटी में इस केस के सम्बन्ध में जब प्रक्त वहां पर श्राया तो इस पर यह रूलिंग हुई कि इस केस में इत्तिला देना लाजिमी नहीं था। इसको वजह यह बतायी गयी कि जब कनविक्शन हुआ तो यह मंशा नहीं था कि कनफाइनमेंट में रखें, तुरन्त बेल स्वीकार कर लिया गया। श्रब बेल के मंजूर होने में चाहे ४ घंटे लग गये या चाहे जिल्ला समय लग जाता । जब निर्णय छोड़ने का हो जाय तो इसकी इतिना देने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही इस केस में भी है कि जब मैजिस्ट्रेट ने नारायण दत्त जी को गिरफ्तार किया तो उसके साथ हो छोड़ने का विचार था। उसमे उतना ही दक्त लगा जितने में कि वह काशीपुर से हल्द्वानी पहुँ वे ठीक उसी तरह जिस तरह कि बेल के मंजूर करने मे ५ घंटे लग गये वैसे ही उनको काशीपुर से हल्द्वानी लाने में ५ घंटे लग गए जो कि लाजिमी या । उसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उनकी अरेस्ट करके कनफाइनमेंट में रखा जाय । तो यह जो हाउस ग्राफ कामंस का केस है वह बिलकुल इसी तरह का है। कुछ माननीय सदस्यों ने असहमति की टिप्पणियां दो हैं।

जहां तक प्रश्न नारायण दत जी के ग्ररेस्ट का है वह तो हम मान लेते हैं। केवल प्रश्न इतना ही है कि सदन को इसको इत्तिला मिलना चाहिये थी या नहीं। ग्रब सदन के समने जब यह प्रदन श्राता है ते यह हाउस ग्राफ कामंस का जो केस है वह हमारे इस केस में विलकुल मेल लाता है। हमको इस बात का स्थाल रखना चाहिये कि हम कोई ेमी Precedent (परिपाटी) न कायम करे जिससे हमे आगे चल कर दिक्कत हो। म एक बान ग्रीर निवेदन करना चाहता हूं कि बहुन से माननीय सदस्य समझते हे कि इस प्रश्न में हमारा ऋधिकार कुछ कम हो रहा है। लेकिन यहां पर हम लोगों के सामने यह प्रश्न दिलकुल नहीं है। जब हम ब्रिटिश पॉलियामेट का इतिहास देखते हैं तो मालूम होता है कि जब तक पालियामेट के मेम्बरों और गवनंमेंट में लड़ाई थी तब तक पालियामेंट के मेम्बरों के प्रिविनेज बहुत ग्रविक थे। लेकिन जिस तरह से पालियामेट का गवर्नमेंट पर कब्जा होता गया. एक्टीक्यूटिव पूरी तरह पार्ति यामेंट के समक्ष जिम्मेदार हो गयी तो पार्तियामेंट के सामने मवाल ब्राया कि हमारे ब्रविकार मीमित होने चाहिये। यदि ब्राप १६५० तक देखेंगे नो वह अधिकार इतने कम हो गये हैं कि ऋिमिनल केसेज में जहां तक अरेस्ट और डिटेंशन का मवान है उसमे कोई भी विशेषाधिकार का प्रक्ष्त नहीं रह गया । यहां पर केवल विशेषाधिकार यह रह गया कि स्पंकर महोदय को इत्तला मिलनी चाहिये। अगर इत्तिला मिल गयी होती तो प्रदेन नहीं उठता । इसलिए हम लोगों को बहुत शांतिपूर्वक ग्रयने सदन की मर्यादा को देखने हुए और नदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए देखना है कि हमारो डेमोकेमी का काम कैसे चलेगा । पूर्ण जिम्मेदारी तथा गम्भीरता से निर्णय करना है । जो फेंक्ट्स हमारे सामने हैं उनको देखने हुए क्मेटी की रियोर्ट बिलकुल सही है।

एक बात में श्रौर कह देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने श्रतहमित टिप्पणी में लिखा है कि यदि हम इस तरह से निर्णय कर देंगे, तो पुलित को छूट हो जायगी कि किसी माननीय सदस्य को पांच दिन तम उटेन किये रहें श्रौर फिर छोड़ दें। लेकिन हमें हर केत की मेरिट्प देखकर हीं फैसला करना है। श्रगर ऐसा केत होगा तो हम विचार करेंगे श्रौर सजा देंगे। हमको तो श्रीवकार है हीं। हमको तो एक न्यायालय की तरह जो वाकयात हमारे सामने ह उन पर फैसला करना है। इसलिए से निवेदन करूंगा कि इन बातों का न विचार करते हुए हमें जो मौजूदा प्रश्न है उस पर विचार करना है श्रौर कमेटी के प्रतिवेदन को मंजूर करना चाहिए।

श्री स्रध्यक्ष--प्रहां पर दो प्रस्ताव ग्रीर हं जो ग्रीर प्रस्ताव ग्राये हे उनको में मंद्रोधन के रूप में लुंगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला ग्रत्मोड़ा) — माननीय श्रध्यक्ष महोदय, ग्रापर्कः श्रानः ने जेता कि श्रापने कहा ग्रपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश करता हूं कि विशेषाधिकार मिनित का प्रतिवेदन निम्नलिखित ग्रपनादों के साथ स्वीकार किया जाय ।

"सदन विशेषाधिकार सिमिति के प्रतिवेदन से श्रसहमिति प्रकट करते हुए माननीय नारायण दत्त तिवारों की ४ फरवरी, १६५४ की गि री की सूचना न देने के सम्बन्ध में कार्शापुर (नैनीताल) के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है श्रीर निश्चय करता है कि उन्हें विधान सभा की नियमावली के नियम ६३ (१) के अनुसार चेतावनी दी जाय।"

श्रव्यक्ष महोवय, इस संशोधन को पेश करते समय मं सबसे पहुले इस सबन के माननीय सबस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं श्रापके जिरये कि हमें थोड़ी देर के लिए यह भूल जाना चाहिये कि सदन में हम लोग जितने भी इधर या उधर बैठे हुए हैं, वह किसी पोलिटिकल पार्टी के हैं। श्राज हमारे सामने इस सबन की मर्यादा का प्रश्न है। इस सबन की प्रिविलेखेज का प्रश्न है श्रीर वह अधिकार जो श्रिधकार हाउस श्राफ कामंस ने बहुत वर्षों

[श्री महन मोहन उपध्याय]

का लड़ाई के बाद हासिल किया, जिते कायम रखा, श्रार ग्राज उसी त्रिविजेज को हम इम महन् के माननीय सदस्य कायम न रख सकेंगे तो इतिहासकार इस उत्तर प्रदेश की विधान नम् को जिसका भारत को राजनीति मे, भारत मे, एक प्रतिष्ठा का स्थान है उसे हम बन्द कर देगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतके पहले कि मैं कुछ कहूं.....

श्री भगवती प्रताद शुक्ल (जिला बाराबंकी) -मै प्वाइंट ग्राफ ग्राडंर रेज चाहता था। यह जो नियम ६३ का हवाला माननीय उपाध्याय जी दे रहे हे इसमे शब्द 'चेतावने' कहाँ नहीं हैं। इसमे 'भर्त्त्ना' है, 'कारावास' है लेकिन 'चेतावनी' कहीं नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष--इसमें जो शब्द हैं 'ऐडमानिशन' उतका ग्रर्थ 'चेतावनी' से ही है। इनमें जो शब्द 'ऐडमानिशन' ग्राया है उससे 'चेतावनी' शब्द थोड़ा कमजोर ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मं तो इस सदन के अधिकारों पर लड़ रहा हूं। हमें आज भूल जाना चाहिये कि कीन किस पार्टी का है और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आज इसको पार्टी इस्यून बनाया जाय और थोड़ो देर के लिये भूल जायं कि माननीय नारायण दत्त जी का प्रश्न है। किसी और मेम्बर का भी प्रश्न यह कल को हो सकता है।

श्री ग्रध्यक्ष--इस सिद्धान्त को सब लोग स्वीकार करते है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--ऐसे ऐटमास्फियर में सब लोगों को लाना चाहता हूं तः कि सब लोग यह समझ लें कि यह नारायण दत्त जी के अपमान का ही सवाल नहीं है बल्कि हर एके सदस्य के अपमान का सवाल है। हो सकता है कि वह अप्राफिसर एक नया अप्रिसर हो वह यहां के नियमों को न जानता हो। मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इस बात को दलीज देने के प्रिविलेजेज कमेटो के सामने कि गिरफ्तारी हो नहीं हुई बल्कि प्रिविलेजेज कमेटो के सामने क्षमा याचना कर लेते तो अध्यक्ष महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिविलेजेज कमेटी उनकी क्षमा कर बड़ी लड़ाइयों के बाद तो हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है और वह यह है कि अगर इस सदन का कोई माननीय सदस्य यहां न आ सका हो तो किन किन कारणों से वह बंचित रह गया है यह ऋधिकार उन प्रिविलेजेज के ऋन्दर है। प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की हुई लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर प्रिवेटिव अरेस्ट हो तो उसको सूचना माननीय अध्यक्ष को नहीं देनो चाहिये। अरेस्ट हुई है, पुलिस कस्टडी में वह ले लिये गये और अगर पुलिस कस्टडी से बाहर आ गये होते तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जो के ऊपर चार्ज लगाया जाता कि वह पुलिस कस्टडी से तो ग्रध्यक्ष महोदय, जो छोटा सा ग्रधिकार हमें मिला है ग्रीर श्री टंडन जो वहां के मैजिस्ट्रेट है वह यह कहते है कि साहब हमने उनको अरेस्ट ही नहीं किया तो यह उन विशेषाधिकार की अवहेलना होती है और इससे और भी कंटेम्प्ट आफ़ दि हाउस होता है।

श्री अध्यक्ष---यहां यह प्रकृत नहीं है कि उन्होंने क्या गवाही दी!

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मं यह कह रहा था कि उन्होंने दलील दी कि कोई अरेस्ट ही नहीं हुई और प्रिविलेजेज कमेटो ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरण्तारी तो माननीय नारायण दत्त जी की हुई है लेकिन यह जो फैसला दिया कि गिरण्तारो तो बरूर हुई लेकिन कोई सूचना देने की जरूरत न थी क्योंकि वह त्रिवेटिव अरेस्ट है, में इससे सहमत नहीं हूं। में माननीय बालेन्द्रशाह और अब्दुल मुईज खां जो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस कमेटी की बैठक में इस बात पर विवार नहीं किया कि वह किस पार्टी के मेम्बर है। मान-

नीय रामनारायण ग्रार गेदा सिंह जी ने भी मेज पालिय नेटरी प्रेक्टिस से काफी एग्जास्पिल्स इस बदन के मामने रक्की है। अगर हमें इस हाउत की मूबरनेनी की रवता है और जो माननीय महम्य इस मदन के हे उनकी प्रनिष्ठा की रखना है उनकी एक्जिक्टिट ब्राफिसर के चंगुल से बचाना चाहते हु, क्योंकि नहीं तो रात दिन ऐमे मामले आयेंगे तो अगर इस प्रकार की अरेस्ट को जिबेटिव अरेन्ट घह कर वे लोग प्लो लेने लगे कि हमारे लिये ऐसा करने की जरूरत नहीं है नो म मनझना हं कि हमारे सदन के जो राइट हं. उन पर कुठारायात किया जा रहा है। हम चाहते ह कि एक छोटा सा अधिकार हमको मिला हुआ है उस अधिकार की कम से कम रक्षा की जाय क्रींर उस क्रियकार को दबाया न जाय। यह चीज उथर के बैठे हुये सदस्यों पर भी लागू होती है ग्रें र सदन के हर एक माननीय सदस्य पर यह लागू हो सकती है। मै तो यह चाहता हैं कि इस प्रक्ष्म पर हमें जरा गर्म्भारतापूर्वक विचार करने की जरूरत है और एक नमूना हमारी इम विदान सभा का हो नहीं बल्कि जो ग्रीर स्टेट ग्रमेम्बलीज है उनके सामने रखना है । हमारी जो पालियामेट है उसने भी क़रोब क़रीब इतने ही मेम्बर है और पूर्व के लोग भी हमारी तरफ देवने हं कि हमारे यहां किस तरह की कन्वेशन और कार्यवाही होनी है और किस तरह का हम फैनला करने हे उसको बाहर भी देखा जायगा । इस कारण यदि एक ग्रादमी को ग्ररेस्ट किया जाय ग्राँर फिर यह कहा जाय कि नहीं साहब यह तो प्रिवेन्टिव ग्ररेस्ट थी, कोई क्रिमिनल ग्राफेन्स नहीं था इसलिये माननीय स्वीकर को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं समझी गयो यदि इस प्रकार से कहने हे तो यह एक भूज है और में समझना हूं कि इसने हमारो प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होगी। म यह भी नहीं चाहना हूं कि उन मंजिस्ट्रेट साहब को कोई बहुत ज्यादा सजा दी जाय। यह माना जा सकता है कि उनसे ग़लती हुई होगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जैसा माननीय बालेन्दु बाह ने कहा है कि "यदि समिति के सामने बग्रैर कोई दोष स्वीकार करके दुख प्रकट करता तो स्वाभाविक और शोभनीय होता । मेरा यह शुबहा है कि वह मंजिस्ट्रेट ऐसा करता यदि उसे राज्य कर्म आरी होने पर श्रिधिक श्रीर अनुचित भरोसा न होता श्रीर न दिलाया जाता "यह शक हो रहा है। अगर ऐसा शक हमारे सामने है तो वह शक नहीं करना चाहिये। मं स्वयं शक नहीं करता हूं वह बालेन्दु शाह जी को होगा। में यह कहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात की रुकावट नहीं डाली गयी। हमारे इस प्रान्त के जितने एक्जि-क्यूटिव आफिसर हं उनको यह मालूम होना चाहिये कि हमारे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य क्या ग्रयना ग्रयिकार रखते हैं। उनको इस बात को चेतावनी होनी चाहिये श्रौर वह तभी हो सकतो है कि जब उन मैजिस्ट्रेट साहब को जिन्होंने माननीय नारायण दत्त तिवारी को गिरफ्तार करके इस माननीय सदन के माननीय स्पीकर को कोई मूचना न देकर जो सदन के अधिकारों की अवहेलना की है उनको इस सदन के सामने बुलाया जाय और वह इस सदन के सामने आकर क्षमा याचना करें ग्रीर माफी मार्गे। तब इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं ग्रीर इस प्रान्त के ब्राफिसर समझ सकते हैं कि यह सही हुआ। तब हम लोगों को इस बात की खुशी होगी कि हमारे इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन को इस सदन के सामने रखता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं श्राप की ग्राजा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को इस रूप में स्वीकार किया जाय—

''सदन विशेषांविकार समिति के प्रतिवेदन से ग्रसहमिति प्रकट करते हुये माननीय नारायण बत्त तिवारी की ४ फरवरी, १६५४ की गिरफ्तारी की सूचना न देने के संबंध में काशीपुर (नैनीताल) के सव-डिविजनल नंजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है। परन्तु चूंकि उन्होंने ग्रज्ञानतावश ऐसा किया इसलिये उन्हें कोई दंड नहीं देना चाहता। परन्तु

श्री राम नारायण त्रिपाठी है

338

भविष्य में ऐसी भूल न हो इस कारण सदन स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करता है कि प्रशासनीय श्रिविकारियों, नंजिस्ट्रेटों तथा जजों का सदन के माननीय सदस्यों की फीजदारी के मामले मे गिरफ्तारी निरोधात्मक गिरफ्तारी (Preventive detention or arrest) देने या जेल से मुक्ति के संबंध में माननीय श्रध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना देना कर्तव्य है"।

इस संशोधन पर मं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जहां तक इस विषय का संबंध हे मेरी यह राय है कि इसकी पार्टी का विषय न बनाया जाय। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि यह पार्टी का मामला न बनाया जाय। मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इन दोनों विचारों से सहमित प्रकट करते हुये इस पर अपने विचार प्रकट करेगे। ब्राध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत जिंदल है। ऐसी सूरत में हम लोगों के लिये भी कठिनाइयां हैं और नयी उम्र के मैजिस्ट्रेट को भी कठिनाइयां में इस मसले पर माननीय एडवोकेट जनरल की राय की विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि यह त्रिवेंटिव प्ररेस्ट है। डिटेंशन तो नहीं कहा क्योंकि वह कानूनी होता है। लेकिन अगर कोई प्रकार हो सकता है उसके किमिनल चार्ज के अलावा तो वह प्रिवंटिव अरेस्ट है। में भाननीय राधामोहन सिंह जो को याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लंड में भी यह व्यवस्था है कि प्रिवेटिव डिटेंशन में भी सदन को सूचना देने का नियम है। तो एडवोकेट जनरेल के मुताबिक श्रगर प्रिवेंटिव श्ररेस्ट भी है तो भी तो सदन को सूचना देना श्रावश्यक था।

धारा १४४ के बीच में १८८ आई० पी० सी० के मुताबिक़ ही सजा दी जा सकती थी। काशीपुर के मैजिस्ट्रेट का आर्डर भी डिफैक्टिव है लेकिन गैर-कानूनी होते हुये भी इस प्रकार का श्ररेस्ट का एक ट्रेडिशन सा बनता चला जा रहा है। सदन की जान कर खुशी होगी कि मैने विशेषाधिकार समिति में भी यह कहा था कि यह प्रिवैटिव ग्ररेस्ट के खिलाफ़ सा है ग्रीर मैने मान-नीय गेंदा सिंह जी से असहमति प्रकट की थी क्योंकि हम इसे पार्टी का सवाल बनाना नहीं चाहते। विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि स दे पांच घंटे की गिरफ्तारी के बाद भी सूचना देना श्रावश्यक नहीं है। इसी सदन में, माननीय श्रध्यक्ष, श्राप ने लोक सभा के माननीय श्रध्यक्ष का उद्धरण पेश किया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चाहे डिटेंशन १५ मिनट का ही हो, सदन को सूचना पाने का अधिकार है। यदि आज हम यह फै ला कर देते हैं कि साढ़े पांच या छः घंटे की गिरफ्तारी के लिये सूचना देने की जरूरत नहीं है तो हम अनजाने प्रशासकीय अधिकारियों के हाथ में ऐसा हथियार दे देंगे कि वह माननीय मुख्य मंत्री को या किसी भी माननीय सदस्य को साढ़े पांच घंटे तक बन्द रख सकेंगे श्रीर इस नजीर का फ़ायदा उठा कर सूचना भी नहीं देंगे।

विद्योषाधिकार समिति ने कहा है कि वह प्रिजन में नहीं भेजे गये। मने अपनी असहमित टिप्पणं: में इस बात का जिक्र किया है कि प्रिजन के माने कोई दीवाल वाले जेलखाने के ही नहीं हैं। कोई प्रशासकीय अधिकारी अगर किसी पब्लिक स्ट्रीट पर किसी को रोक ले तो वह प्रिजन हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने सर्वमान्य डिक्शनरियों का हवाला ग्रपनी ग्रसहमति की टिप्पणी में दिया है। एक बात माननीय सदस्यों के दिमाग़ में श्रा सकती है कि सदन ने इस समिति को नियुक्त किया और उन्होंने छानबीन के बाद जो फ़ैसला दिया उसे मान लेना चाहिये। लेकिन में कहुंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उस समिति के प्रति ग्रादर प्रकट करते हुये, क्योंकि ग्रगर में ऐसा नहीं करूंगा तो में अपने प्रति भी निरादर करूंगा क्योंकि में भी उसका मेम्बर हूं, म यह कहूंगा कि यदि यह आदरणीय सदन किसी मामले में विशेषाधिकार समिति से सहमत नहीं है तो इस सदन को पूरा अधिकार है कि अभी अपनी असहमति प्रकट करे। में इस बात की आशा नहीं करता कि मैजिस्ट्रेट को जानकारी होगी, श्रौर उन्हें सजा न दी जाय। इसिवये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें सजा न दी जाय लेकिन उनको दोषी मान लिया जाय और भविष्य में

ऐसी बाने दुहराई न जायं इसलिये सदन यह घोषणा करता है कि ऐसी परिस्थितियों में सदन को इित्तना देना इन सरकारी अधिकारियों, जजों और मैजिस्ट्रेटों का कर्नव्य है। में समझता हूं कि मेरा यह संशोधन सदन के हर माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप होगा क्योंकि इसमें किसी मैजिस्ट्रेट को न तो सजा देने की भावना है और न किसी राग्द्रेष की ही कोई भावना है। मैं म.नर्नाय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से अपोल कहंगा कि इसको एक मत से स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि सभी इस माननीय सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं और किसी पार्टी या दें। की भावना से सजा नहीं देना चाहते हैं, केवल सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि इस सदन के सब माननीय सदस्य इस मंगोधन को अक्षराक्षर मंजूर कर लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालाँन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मं आपकी आज्ञा मे एक मंशोधन पेश करना चाहता हूं श्री नारायण दत्त निवारी की गिरफ्तारी के संबंध में....

श्री अध्यक्ष--मं श्राप से पूछना चाहता हूं कि "भत्संना देता हूं" इसका क्या श्रर्थ है ?

राजा वीरेन्द्रशाह—"देता हुं" के बजाय "करता हूं" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मेरा मतलब है कि "भर्त्सना" गब्द से ब्रापका क्या तात्पर्य है?

राजा वीरेन्द्रशाह--वारा ६३ के ब्रनुतार मेंने उसको रक्ला है।

श्री अध्यक्ष-उसका अर्थ ग्रापके विचार में स्पष्ट नहीं है इसलिये ग्राप श्रपने प्रस्ताव को थोड़ी देर बाद सुधार कर रक्खें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो संशोधन ग्राय हैं। एक श्री राधामोहन सिंह का....

श्री अध्यक्ष--- श्रापका एक अमेंडमेंट मेरे पास आया है। क्या आप उसको पेश करना चाहते हैं?

श्री नौरंगलाल-एक मेम्बर ने

ं श्री अध्यक्ष--- ग्रापने मेरे पास जो संशोधन भेजा है क्या उसकी कापी श्राप के पास नहीं है ?

श्री नौरंगलाल-वह चार लफ्ज का है इसिलये मैंने उसकी कापी नहीं रक्खी।

श्री ग्रध्यक्ष--कृपा करके उसकी नकल मेरे पास से ले लीजिये।

श्री नौरंगलाल-मं उसको पेश करना नहीं चाहता।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) — श्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि इस संबंध में ज्यादा विवाद ग्रीर बहस की जरूरत नहीं है। मामला यहां पेश हुग्रा, विशेषाधिकार समिति में गया ग्रीर वहां से उसकी रिपोर्ट श्रायी। इस सदन के दव सदस्यों का यह मत है

^{*}वन्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गी.वन्द चल्लभ पंत]

कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर किसी दलबंदी के श्राधार पर यहां बहस मुवाहिसा नहीं होता चाहिये। जहां तक इस खास वाक़े के हालात का ताल्लुक़ है उनमें कोई मतभेद नहीं है। क्या बात हुई, इसको सब जानते हैं। श्री नारायण दत्त जी, काशीपुर में जी कि गन्ना किसान ला रहे थे, वहां कारखाने में देने से लोगों को रोक रहे थे। वह १४४ के खिलाफ था। देसे भा फोनन के खिलाफ बात थी। पर उनके ऊपर कोई मुक्तदमा नहीं किया गया, किती जुर्म में वे पक्रे नहीं गये। गो कि जुर्म में नहीं पकड़े गये पर वे एक जोप में बिठलाये गये और उनको सद-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपने बंगले पर ले गये और काफो से उनको दावत की और उसके बाद उनको मौका दिया कि वे हलद्वानी, जो उनके घर के करीब है वहां पहुंच जाय बनुकाबले इसके कि वे काशीपुर में अपना वक्त खराब करें। में समझता हूं कि इसनें कोई मतभेद नहीं है कि श्री नारायण दत्त जी के साथ उनका तमाम जितना भी व्यवहार रहा वह शिष्टता का रहा, सम्मान का रहा, आदर का रहा और प्रेम का भी रहा। इसलिये कोई ब्रोच आफ प्रिविलेज का प्रक्त उठता नहीं। इसमें भी कोई मतभेद नहीं है कि उनको पकड़ कर जहां हवालात या जेलखाने भेज सकते थे वैसा न करके उनको मकान पर ले गये ग्रीर उन्होंने उनके साथ रियायत की ग्रीर उनके साथ काफी मुरीयत की बात की। वसे वे कहते हैं कि कालेज में उनके साथी रहे लिहाजा इस तरह से वे उनके साथ पेश आये। श्री नारायण दत्त जी ने कोई बीच इस हाउस का किया है या नहीं किया है, यह मैं जानता नहीं हूं कि कोई मेम्बर इस हाउस के कानून की ग्रवहेलना करें तो वह बोच श्राफ प्रिविलेज होता है या नहीं। लेकिन इस बात को सभी मानते है कि श्ररेस्ट हुआ और प्रीवेंटिव अरेस्ट हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि ग्राया इत्तिला देने की जरूरत थी या नहीं श्रौर इत्तिला न देना कोई ब्रोच श्राफ़ प्रिविलेज है या नहीं। जैसा श्रौर मामलों में होता है वैसे इसमें भी है कि जिस शख्स को बीच श्राफ त्रिविलेज के लिये सजा देनी हो उसके खिलाफ जुर्म सावित होना चाहिये। बर्डेव ग्राफ प्रूफ उनके ऊपर है जो यह कहते हैं कि बीच ग्राफ प्रिवि-लेज हुआ जैसा कि और बातों में होता है। लिहाजा इस किस्म को जब बीच श्राफ प्रिवितेज हो तो उस मामले की इत्तिला देना जरूरी है, पूरी तरह से सही है, या नहीं या यह बीच ग्राफ प्रिवि-लेज इस्टेब्लिश्ड है, यह बात ग्राती है। बीच ग्राफ प्रिविलेज के बारे में जो कुछ भी हाउस ग्राफ कामंस या हमारे पालियामेंट में रवेया रहा है उसी के ब्राधार पर हम काम कर रहे है। ब्रभी वैसा कोई कानून हमने बनाया नहीं है लेकिन चूंकि वहां यह कानून है कि ग्रगर किसी ग्रादमी को पकड़ कर जेल में भेजा जाय या प्रिवेटिव डिडेंशन हो तो फौरन् उसकी इत्तिला हाउस ग्राफ कामंस को देनी चाहिये और उसी के ब्राघार पर हम यहां भी यह मानते हैं कि ब्रगर इस तरीके पर कोई बात हो तो उसको इत्तिला देनी चाहिये। श्री रामनारायण जी ने 'प्रिजनर' का माने यह कहा कि कहीं भी कोई म्रादमी पकड़ कर रखा जाय तो वह त्रिजनर हो जाता है। की बात यह है कि स्राया जब श्री नारायण दत्त जी जीप में जा रहे थे तो स्रगर वह कोई ऐसी चीज करते जो त्रिजन ऐक्ट के मुताबिक जुर्न होता है तो वे मुजरिम हो जाते हैं या नहीं। में समझता हूं कि नहीं होते क्योंकि वे प्रिजनर नहीं थे। यह जरूर है कि वे गिरफ्तार हुये ग्रौर उनकी मर्जी से उनको ले जाया गया। हो सकता है कि नीम रजा उनकी रही हो। अब सवाल यह होता ह कि ऐसा बीच आफ प्रिविलेज कोई इस्टेब्लिश्ड हो तो कोई केस किसी ने कीट नहीं किया कि इस फिल्म के मामले बीच श्राफ प्रिविलेज के समझे गये। श्रव जब तक कि कोई बीच श्राफ प्रिविलेज इस्टंब्लिइड न ही तब तक उसके लिये यह कहना कि किसी भ्रादमी ने जुर्म किया है, यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है जो इस जुर्म की ग्रायद करते हैं। इस किस्म का कोई केस नहीं बतलाया गया है । इस समय मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस ग्रीर दूसरी जितनी किताबें हैं, उनमें यही है कि कोई 'फार कमिटल दु प्रिजन' अरेस्ट हो तो उसकी इत्तिला देनी चाहिये। इसलिये इस मौके पर जो कुछ हुआ वह इन अलफ़ाज के अन्दर नहीं आता लिहाजा उसका मतलब कीच आफ़ प्रिविलेज नहीं था, मगर यह कहा जाय कि उसका मतलब न हो मगर तब भी ऐसा होना चाहिए वह बात इसरी है।

अहाँ नक झद नष्ट ब्रिविनेजेज का नाम्लुक हैं. हाउस आफ़ कामन्स के ब्रिविनेजेज का नाम्लुक हैं वहाँ इस नप्ट के माम्लों में ब्रेच् नहीं माना राजा हे अरेर यह की के मानने का कोई मामला नहीं है और इस तरह के फ़ैसले भी हुए हे. जिनमें कहा गया है जिल्ला देर भे के ई छोड़ा जाय तो इतला की जरूर नहीं है। इस तरह की बाने है लेकिन चुंकि प्रिविलेजेज के बारे में कई नरह के उनाल है और में थे। इं मा हाउन आफ़ ले मन्म की रिपोर्ट से पढ़कर मुनाये देता है जि मे त्रिविनेज्ञ के बारे में कुछ सक्त ई मिलती है। यह एक मामला था जिसने १६१८ में मिस्टर एडमंड डिवेनरा का जाउन्ट जार्ज एन० लन्छेट हो। मिस्टर डब्लू टी० कासयेव का व मिस्टर जीज्ञ मेग्ने का। उनके नामों से भी जायद कई सदस्य वाकिफ होंगे, यह ब्रायरलैंड के एक मुबसेट के नीडर थे. यह पनडे गरे ग्रोर रिस्प पर किए गरे थे ग्रीर कानून के मुनाबिक जैल भेजे गरे थे । यह लाग १० मई को पकड़े गरे और उनकी इतला हाउस आफ कामन्स की पर्ने जुन तक नहीं रिनो। वहां सदान उठा ि फ़ौरन हो इत्तला देना जरूरी है। १८ मई की बान थीं. ब्राज पहेली जुन हो गई. इनने दिन तक नहीं लिखा गया, यह बात गलत है । इस भिनमिले में वहां जो कुछ स्पेंकर ने कहा वह में हाउस के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस में इसी मामले में नहीं बल्की प्रिविलेजेज के मोमलों में श्राम तौर पर क्या हालत है उसका एक ग्रन्छा नकता सही मानों में सामने ग्रा जाता है । उस समय जो स्पीकर ने कहा था वह भी मे पढ़ बूं-"This is a question addressed to me. I believe that is only the preliminary stage." नो मेम्बर ने कहा था कि:

"Sir, to satisfy both you and my hon'ble friend, the question I have to put is clear, and it is this:—whether it is not the duty in such cases to intimate atonce, and without delay, that such arrests have been made. May I point out to you, Sir, that the letter states that these arrests were made on the 17th and 18th May, some on one day and some on the other, and it was not until the 1st June, a fortnight later, that the Chief Secretary wrote to you an intimation on the fact of the arrest."

भव रूल यह है कि इम्मीजिएटली इन्टीमेट फरना चाहिये लेकिन १२-१३ जून तक इन्टोमेशन नहीं हुआ और जिनके बारे में यह बात थी वह जो पफड़े गये थे वह एक रिनाउन्ड मेम्बर थे और जिनके बारे में दो राय नहीं हो सकती। स्पीकर ने जो कहा उसकी भी में मदन के सामने रखें देना हूं। मिस्टर स्पीकर ने कहा—

"The Hon, ble Member is aware that there is no statutory injunction upon magistrates, or persons committing Members of the House to inform the House of that act. It is entirely a matter of custom and of courtesy, and I think that, as a rule, it is better that the letter should be written atonce. Letters postponed are sometimes forgotten, and it is better to take action atonce. I have no doubt that if it had been present to the mind of the Chief Secretary, he would have communicated atonce. Better late than never."

इस तरह में यह मामला खत्म हुन्ना ।

एक सदस्य-- प्रापने यह कहां से पढ़ा है ?

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-यह हाउस ग्राफ़ कामन्स की चीज है, १६१८ का है, वाल्यूम १०६, १३ मई से १३ जून तक का वाल्यूम यह है।

^{े *}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गी-न्द बल्लभ पंत]

इससे स्राप देखेगे कि प्रिव्लिजेज के बारे में जो बात है वह जितने जोर से हम समझने हैं कि इत्तिला न देना एक बड़ा भारों जुर्ग ह वह ऐमी बात नहीं है स्रोर फिर यदि ही भी गई ने १५ दिन के बाद दो गई स्रोर उसमें कोई शुबहा नहीं था कि एरेस्ट हुस्रा, डिटेशन हुस्रा, जेल भी भेजे गये थे । टाइम की बात थो मगर उन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं है कि जिससे मैजिन्ट्रेट बाउन्ड है कि ऐसा करे, कस्टम है, कंबेशन है उसके मुताबिक ऐसा होता है लिहाजा स्रगर देर हैं गई तो ऐसी कोई उस्त्र को बात नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्रगर हम यह भें समझ ले कि कितो मामले में उचित हीता यदि ऐसा करता मगर यह कहना कि यह एक जर्म ऐसा किया गया तो हमें इसे समझना है कि स्राया ऐसी कोई बात है या नहीं। इसिन्दें में स्रजं करता हूं कि त्रिबेटिव डिटेशन इस मामले में जरूर हुस्रा, वह वहां से उनकों ले गये क्रोर छोड़ दिया। स्रगर पकड़ कर जेल में छोड़ दियों जाने तब जितने हाउस स्राफ़ कामन्म के रवेंथे हैं उनके मुताबिक कोई बात नहीं होती।

इसके बाद चार-पांच दिन के बाद फिर नारायण दत्त जी पकड़े गये श्रौर मुकदमा भी उन पर चलाया गया। उसकी इत्तिला तो यहां श्रा गयी। हो इसमें रामनारायण जी ने यह भी कहा कि इसमें कोई बदनीयती नहीं है। ग्रगर कोई बात थी तो बेइल्मी थो । में जरा श्राज बढ़ना चाहता हूं लाइल्मी भी नहीं थी बिल्क ऐसा कोई हन. ऐसा कोई प्रिविलेज डिफाइन्ड नहीं था ग्रीर जो कुछ था भी उसमें में कुछ ऐसा नहीं हुग्रा जिसके लिय यह कहा जाय कि कोई बीच श्राफ त्रिविलेज हुआ। इसलिये में समझता हूं जो कि रिपोर्ट है श्रौर जिसमें उन्होंने यह माना है कि ब्रोच ग्राफ त्रिविलेज नहीं हुग्रा यही सही बात है ग्रीर इसमें इन मैजिस्ट्रेंट ने जो इत्तला नहीं दो कम से कम उसने इसी इत्मोनान से नहीं दिया कि इनमें देने का जरूरत नहीं। दूसरे में तो फौरन दो जैसे पकड़ा श्रीर जेल भेजा श्रीर श्रगर इसमें भी पकड़ने श्रौर उसके बाद जेल भेजने की बात होती तो इसमें भी देता। तो में समझता हूं कि यह कहना कि बीच आफ प्रिविलेज हुआ है इन सब बातों को देखते हुये में समझता हूं इस मामले में बहुत गुंजा-यश नहीं है श्रौर काफी कारण इसमें नहीं है। इसके साथ ही बर्डेन श्राफ प्रूफ जैसा मने कहा हम पर होता है कि ब्रीच भ्राफ त्रिविलेज हुआ लेकिन वह बर्डेन श्राफ प्रुफ डिस्वार्ज नहीं हुआ। इसलिये यह बात नहीं है कि बीच श्राफ त्रिविलेज है। लेकिन श्राइंदा के लिये में समझता है कि हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम अपने हाउस के प्रिविलेजेज को बढ़ावें। हम उन्हें कम करना नहीं चाहते श्रौर में समझता हूं कि हम एक्जीक्यूटिव को यह हिदायत यहां से भेजे तो अच्छा हो और में समझता हूं कि हमें भेजना चाहिये और इस तरह के एरेस्ट में भी जो कि प्रिवेटिव डिटेंशन का ऐरेस्ट हो और जब बेल न हो इसमें भी स्पीकर को इत्तिला मिलनी चाहिये थ्रोर इसको भी उसी कैटिगरी में ट्रोट करना चाहिये जैसे कि श्रौरों में की जाती है। ताकि इसकी सफाई आइन्दा के लिये हो जाना चाहिये। लेकिन जहां तक सभी लोगों के लिये कानून रखने की बात है। पुलिस वाले और मैजिस्ट्रेट जिसकी च हें उसके ऊपर उनको कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है, उनके कानुनी अधिकार में किसी को कोई दस्तन्दाजी नहीं करना चाहिये। मगर कोई इस तरह से गिरफ्तार हो और कोई जमानत में रिहा न हो और वह प्रिवेंटिव डिटेशन चाहे वह एक जगह से पकड़ कर दूसरी जगह भेजें तो भी उसकी इत्तिला स्पीकर को दे दें यह हिदायत हम भेज देंगे भ्रौर इससे में समझता है कि कोई बात भ्राइंदा के लिये दिक्कत की नहीं रहतो।

जहां तक इस मामले का ताल्लुक़ है मैं समझता हूं विशेषाधिकार समिति की जो राय है वह बिलकुल सहो है। गिरफ्तारी हुई, प्रिबेटिव डिटेंशन भी हुआ, मगर बीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ। न तो कोई बोच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हुआ और न ऐसे प्रिविलेज के लिये कोई ला या प्रैक्टिस ऐसी है जिससे बीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हो सके और जहां तक आइंदा की बात है हम इस क़िस्म की हिदायत दे दें जिससे यह प्रिविलेज भी हो जाय चाहे यह प्रिविलेज अब तक न रहा हो और चाहे यह प्रिविलेज और जगहों पर भी न रहा हो। मैं समझता

द्रांत इचन बाउम मी नामवादी समाठीक होती हु आंर विमेमधिकार सिनित को रिपोर्ट से उनना ही मिरिने का सबाद माता है अगर आप आनानी से मिरिने का समेटी को रिपोर्ट को उनना दें कमेटि कि मिरिने का सबाद माता है अगर आप आनानी से मिरिने के अगर अमकी कार अमनी निर्मेट दें इचार में मिरिने मिरिने कि बिन्हुर न माने तो भी ठोक नहीं है। किर उन्होंने कोई महा हेने थी अन मी नहीं कहीं है। राम नारायण जी ने भी यही हहा है। स लेकिन आइन्हा ने कि मिरिने के कर देना चाहना हूं ताकि दि सकते न हो। इनकी जो हापन है और जिम मिरिने के कार मिरिने के सामने हैं और जाती है कि उम हिसाब में यह दीच आफ दिवने के तहीं है निर्मा हाउम को इसी नगह पर इस मामने को तम कर देना चाहिये।

महार जकुमार दालेन्दुशाह--प्रध्यक्ष महोदयः श्रापकी श्राज्ञा हो तो म श्री राम न राज्य में के मंद्रोधन पर एम पंजीयन पेट करना चार्न है कि राम नारायम जी के नंशोयन के स्थान पर निर्माणिक रच दिया जाय :--

द्वी नगरायगदत्त निवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विद्योगियकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिबंदन पर विचार करके इस सबन का यह निश्चित कर ह कि संबंधित ग्राधिकारों ने साननीय श्री ग्रध्यक्ष की गिरफ्तारी की सूचना सर्वाधित निवारों के स्पष्ट न होने के कारण नहीं दी। श्रत्य सबन श्री बी० एन० टंडन, सब-डिवीइनय निजारें है का काशोपुर, नैतीताल को दोधी न ठहराते हुये भिष्ठिय के लिये यह स्पष्ट शाओं से खे जिन करणा है। कि प्रशासकीय ग्रीवकारियों निजारें तथा जजों का सबन के माननीय सबस्यों के लेजदारी के स मलों में गिरफ्तारी निरोधात्मक गिरफ्तारी के पश्चात् प्रत्येक रिमांड पर नथा रण्ड देने या जेन ने मुक्ति के संबंध में माननीय श्रध्यक्ष द्वारा सबन को सूचना देना ग्रानिवार्य कर्त्तव्य है। "

श्री अध्यक्ष—ग्राप विशेषाधिकार हे, यह नहीं कहना चाहने। जब ग्राप उसकी र नहीं मानने हं महन का ते ऐमी हानन में ग्राप हिदायन कोई नहीं दे मकते हैं। माननीय पुष्य मंत्री जी नो एग्जीक्यूटिव की तरफ से दिवायन देगे, उनकी इनका ग्रिधकार है लेकिन इस सहन को विशेषाधिकार न मानने हुये हिदायन देने का क्या ग्रिधकार है ?

महाराजकुमार बालेन्डुशाह--ग्रध्यक्ष महोदयः इस संबंध में म ग्राटका घ्यान इस ध्रोर जार्काषत करना चाहना हूं कि विशेषाधिकार समिति के मामने केन्द्रीय सरकार का एक सर्कुलर पेश क्या गया जिममे स्पष्ट लिखा हुन्ना था कि फनः-फना समय सूचना देना जावश्यक है।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक हे लेकिन जब तक ग्राप इने विशेयाधिकार नहीं मानते हे तब तक न इन हिदायत देने वाले प्रस्ताव को ग्रवैध करा: दूंगा।

महाराजकुमार वालेन्दुशाह—म उमे विशेषाधिकार मानता हूं लेकिन यह कहता हूं कि स्पष्ट नहीं ह।

श्री अध्यक्ष—नो म्राप 'म्रस्पप्टता' के लिये सदन की राय लेना चाहते हा म इसकी इजावन नहीं दूंगा।

श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय प्रध्यक्ष महोदय, म माननीय राम नारायण जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से यह मुनने को मिना कि माननीय नारायण दत्त जी को गिरफ्तारी का जो प्रश्न है वह विशेषाधिकार की अबहेलना नहीं हैं। म माननीय मुख्य मंत्री जी को केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड की पाल्यामेट में सूचना देना कोई साजारण बात नहीं है। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक ऐतिहामिक पृष्ठभूमि है। सूचना देना एक सुलह है। शुरु शुरू में इंगलेड की

[श्री गेदः सिंह]

पालियामेंट का विशेषाधिकार इस हद तक था कि कोई माननीय सदस्य किसी फ़ौजवारी के जुर्म में, करल के जुर्म में, डकैती के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे भीरे इसमें ढिलाई हुई ग्रीर वह ढिलाई इस हद तक पहुंची कि दोनों में, पार्लियामेंट ग्रीर ग्रहानमें ने यह समझौता किया कि इस प्रकार विशेषाधिकार के नाम पर कहीं उसका दुरुपयोग हो सन्ताह इसलिये जहां तक इस तरह के जुर्मी का संबंध है किसी माननीय सबस्य की गिरफ्तार करना ने श्रदालतों को या पुलिस को कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद उसकी न सिर्फ सूचना देना माननीय श्रध्यक्ष को, बल्कि उस है साथ साय मानवाय सदस्य को िस जुर्म में भी पतार किया उसक क्या कारण है यह बतलाना भी ग्रावश्यक है। यह बात निश्चय है ग्रीर इस निश्चय के साथ सुचना देने को प्रया इंगलैंड को पालियासेंट में हैं। मैं बहुत विनम्नतापूर्वक माननीय मह्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल नारायण दत्त जी का नहीं था और नहें, यह प्रश्न तो सनुचे भवन, सनुचे जो सदस्य हैं, उनका है। मै उनसे विचार करने को कहता है और माननीय सदन से भी इस प्रक्त पर विचार करने को कहता हूं कि जो उदाहरण मोतनीय मुख्य मंत्री जी ने सन् १९१८ का पेश किया कि माननीय स्वीकर ने यह घोषणा की कि कोई ब्रिधिकार हमारा मैजिस्ट्रेट पर सूचना पाने का नहीं ह । उस संबंध में मे उनसे यह कहना चाहंगा कि जिस प्रकार की हिदायत की चर्चा उन्होंने की हैं कि ऐसी हिदायत वे दे देंगे। इस प्रकार की श्रगर हिदायत पहले दी जा चुकी है जिसकी कि पूरी तरह से हम लोगों ने कमेटी में छानबीन की श्रीर इस हिदायत के ऊपर इस बात को माना गया कि वह हिदायत ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम पाबन्दी करें। वह हिदायत हमारे चीफ़ सेकेटरी साहब की थी यू० पी० के। श्रीर वह हिदायत श्रायी हुयो थी पालियामेंट से । उन्हीं की हिदायत श्रायी थी श्रीर उसके श्रनुसार वह हिदायत सारे डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट्स, एस० डी० एम० सभी ग्रविकारियों को भेजी जा चुको है मौर भेज करके उसमें यह प्रार्थना को गयो है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेवर का, पार्लियामेंट का गिरफ्तार हो तो उसकी सूचना दो जाय माननीय ग्रध्यक्ष को ग्रौर उसका पूरा पूरा कारण बताया जाय। लेकिन हम लोग मजबूर हो गये इसलिये कि उस हिदायत को यह ने माने कि केवल हिदायत देने के बाद हम उससे विशेषाधिकार का दावा कर सकते है। वहीं बात में उनसे फिर देरख्वास्त करना चाहता है कि वह एक बहुत अजीब हालत हो जायगी कहीं किसी भी पालियामेंट में।

में अब तक तो यह नहीं समझ पाया था कि सूचता नहीं देनी चाहिये, रीजन नहीं बताना चाहिये। में तो रीजन न बताने की बात कहता हूं कि न सिर्फ सूचना देनी चाहिये बिक रोजन भी बताना चाहिये कि किस कारण गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमारा विशेषाधिकार है। यदि हमारा कोई विशेषाधिकार है तो न केवल सूचना देना बिल्क कारण बताना कि किस कारण से सबस्य गिरफ्तार किया गया है यह आवश्यक है। मैं दो एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सबन के सामने और माननीय मुख्य मंत्री के सामने खास तौर से कि जिस प्रकार से श्री टंडन न गुस्ताखाना तरीक़े पर जवाब दिया वह भी मैं समझता हूं कि कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश किया। वे जवाब देते हैं कि उनको गिरफ्तारी का ज्ञान नहीं कि गिरफ्तारी किसको कहते हं और किस तरह से गिरफ्तार करते है।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न नहीं है। इस समय प्रिविलेज का प्रश्न हमारे सामने हैं। गिरफ्तारी की सूचना देना कर्तव्य है या नहीं, सिर्फ इसी प्रश्न पर श्राप श्रयने को सीमित रखें।

श्री गेंदासिंह—तो माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा श्री शिब्बन लाल सक्सेना का मामला कि वे गिरफ्तार किये गये श्रीर गिरफ्तार किये जाने के बाद जिस तरह से ५-६ घंटे माननीय नारायण दत्त जी को घुमाया गया उसी प्रकार घुमाने का सवाल भी नहीं था माननीय शिब्बन लाल जी को। शिब्बन लाल जी के बारे में तो सरदार जी ने यह कहा था पालियामेंट में कि उन्हें तो हम ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे कि जहां पर जाकर वे स्वस्थ रह स हें श्रीर श्रिधक श्राराम पा सकें। गिरफ्तारी की भी बात नहीं,

संक्रिय हमना हो प्रवर्त ये बाद सामनीय जवाहर लाज् हो से वालियामेट से उसकी भूल स्वीकार को, सुचना देने की बान भी उन्होंने स्वीकार की।

श्री गोविन्द बल्याम धेल--श्या शिखन लाल जी के मामले में सूचना देने की बात इस्

श्री गेदा मिह—दिख्यन लाल जी के मामले में शिकायन तो यह थी कि उनको वह में हुट या क्ये गया लेकिन ऐसा तो कोई मोचना भी नहीं है कि सूचना देना या न देना भी किसे ग्राचिकारी की मानों पर ह : हम नो नमझने ह कि सूचना देना श्रीर उसके साथ-साथ कारण बनवान, श्रावच्यक है श्रीर जमा मेने कहा. इसके पछि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके में से कोई कोटेशन देकर माननीय मुख्य मंत्री को समझाने का दावा नहीं करता, उनको इनमी पालिया मेटरी जिन्दरी है जिससे उनका ज्ञान इस सम्बन्ध में होगा ही। लेकिन में उनसे इनमी में श्रापील करना चाहना है जि केवल नाग्यण दत्त जी के मामले में यह फेमला कर लेना कि किशी मैजिस्ट्रेट की मुजी पर है कि जिसके वाहे गिरण्यार करें श्रीर जी में श्राये तो स्चना दे या न दे उचिन नहीं है। में नो यह कहना चाहना हूं कि श्रार मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय नो न मालूम कितने उदाहरण ऐसे मिनेंगे कि सूचना देने के बाद माननीय सध्यक्ष की नरफ में बारेंट जारी हुसा श्रीर उसके बाद जेललाने में माननीय सदस्यों को छुड़ाया गया।

"श्री गोविन्द वल्लभ पंत—रेदा सिंह जो मेरी वात को शायद कुछ ठीक नहीं समझे या मेठीक नहीं कह पाया। मेने तो यह बात दिखलाने की कोशिश की थी कि प्रिविलंज का बीच क्या चीज है। जहां तक इन बात का ताल्लुक है कि अगर कोई पकड़ा जाय तो उसकी इत्तला मिले. उसके सबब बतलाये जायं और उसके लिये हिदायत हो. जो न करे उसको बीच समझा जाय, उममे मेरा कोई मतभेद नहीं है। इम खास मामले में में यह कहना हूं कि जो हालात थे उनमें वह ब्रांच नहीं है। आयन्दा के लिये हम इसको नाफ कर देगे और उसके बाद कोई ऐसा मामला आयन्दा हो तो फिर हम उसके ऊपर कार्यवाही करेगे। लिहाजा कोई सवाल यह नहीं है कि किमो को पकड़ा जाय तो इनचा दे या न दे उसकी अधिकार हे, बिल्क जिन हालात में यह वाकया हुआ वह ब्रांच आफ प्रिविलंज नहीं हो सकता, यह मेरा कहना है।

श्री गेंदा मिह—माननीय मुख्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण मुनने के बाद हमें संतोष होता है क्योंकि में मान लेता हूं कि नारायण दत्त जी के नामले में कीई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से श्री टंडन जी की छना मुनामिव नहीं समझने ह, लेकिन कम से कम इस सदन के अधिकार का स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री ने कर दिया इससे मुझे संतोष हैं। लेकिन जो उन्होंने बताया कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, ग्रध्यक्ष महोदय. ग्रापने मुझे रोक दिया शुरू शुरू में कि में इस पर कुछ कहूं लेकिन जब अरेम्ट हे यह माननीय प्रिविनेज कमेटी ने इसकी माना कि गिरफ्तारी हैं ग्रीर फिर प्रिविनेज कमेटी यह कहनी हैं कि चूंकि ४—५ घंटे की गिरफ्तारी हैं, प्रिवेटिव हैं, किमिनन चार्ज नहीं हैं, में मेज पालियामेटरी प्रेक्टिस से कहना हूं कि ग्रापर किमिनल चार्ज नहीं हैं तो गिरफ्तारी करने के पहले सूचना देने की बात तो ग्रलग हैं उस मामले में तो इजाबत लेनी चाहिये थी। ग्रगर किमिनन चार्ज हीता तो ऐसी हालत में उनकी पूरी तरह से गिरफ्तार कर लेने का हक था। लेकिन ग्रगर किमिनल चार्ज नहीं है ग्रीर प्रिवेटिव डिटेशन मी नहीं है तो फिर है क्या? ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रजीब हालन है। ऐडवोकेट जनरल साहब यह फरमाते हैं कि १४४ का त्रीच तो यह है.....

श्री अध्यक्ष--ग्रापका समय समाप्त हो गया।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने रखा है में उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्,

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

विशेषाधिकार समिति ने जो इश्यूज इस मामले में पहले सर्वसम्मिति से तय किये थे उनको में ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको ग्राज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

- (१) क्या श्री नारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हलद्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी?
- (२) क्या यह गिरफ्तारी (प्रीवेंटिव) निरोधात्मक भी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी श्रपराध के सम्बन्ध में थी ?
- (३) यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे यह जिस प्रकार की हो तो क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री ग्रध्यक्ष की देना ग्रावश्यक था ग्रीर क्या सूचना न देने से सदन के किमी विशेषाधिकार की ग्रवहेलना हुयी ?

श्रीमन्, में यहां आपके द्वारा सदन को बतलाता हूं कि समिति की रिपोर्ट में सभी सदस्य अपर की दो बातों से सहमत है, जो मतभेद हैं वह सिर्फ तीसरी बात पर है कि यह सूचना देना आवश्यक नहीं था श्रध्यक्ष को श्रीर विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुयी।

भीमन्, मै श्रापके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जब दो चीजें स्पष्ट हो गयीं श्रीर जब यह मौजूद है हमारे सरीर्ट में, विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता है। इसके सरीट में पालियामेंट की घारा का जी उल्लेख किया गया है श्रीमन्, में उससे सहमत हूं जैसा कि श्री रामनाराण जी ने कहा कि चाहे वह जेल में ही या एक घंटे की भी रोका जीय या कहीं भी रीका जाय तब भी वह श्रिजन के माने में थ्रा जाता है। इसलिए जो धारा का कोटेशन विया गय। है वह हमारे पक्ष में भ्रा जाता है। यह विशेषाधिकार का सवाल है भ्रीर भ्रध्यक्ष को सूचना न देने का जो सवाल है वह उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए में यह समझता है श्रौर जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना, में यह मानता हूं, जहां तक यह बातें बतलायों गयीं कि नारायण दत्त जी तिवारी कैसे गये, क्या हुन्ना, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। में समझता हूं कि जो माननीय सदन के हर मेम्बर का राइट हैं ग्रीर प्रिविलेज है ग्रीर जो माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि पहले हमारे क्या राइट थे। ग्रगर हम उनको निगाह में नहीं रखेंगे तो एक त्रिसीडेंट हो जायगा। यदि सूचना नहीं दी गयी तो यह हो जायगा कि एक केस में ऐसा हुआ। में यह मानता हूं कि श्राइन्दा के लिए ग्राप सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन में यह कहता हूं कि इसने हर्न ही क्या है जेब कि यह स्पष्ट है ब्रौर एक एम० एल० ए० श्रो अब्दुल मुईज खां ने अपना नोट आफ डिसेंट दिया है कि विशेशांधकार के सिवाय और दूसरा सवान उठता नहीं है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है।

हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनको भत्सेना दी जाय ग्रौर उनको हिदायत कर दी जाय। सरकार उनसे नाराज नहीं है ग्रौर उनकी बैंड एंटरी नहीं होगी। लेकिन हमेशा के लिए एक नमूना बन जाय उसके लिए में सहमत नहीं हूं। में समझता हूं कि विशेषाधिकार की श्रवहेलना हुयो है ग्रौर उनको भत्तेना दो जाना जरूरो है।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्यगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः स्रारम्भ हुयी।)

स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना

श्री ग्रध्यक्ष — मुझे एक सूचना देनी है कि स्थायी सिमितियों के संबंध में ग्राज तीन बजे तक नाम क्षपस लेने की तिथि थी। १ सिमितियां ऐसी हैं जिनके विषय में यह कहा गया है कि उनमें नाम कुछ लोगों के बापस नहीं हुए और यह सम्भावना है कि चुनाव न करना पड़े यदि कुछ सम्रय बढ़ा दिया जाय। इसिलिये में नाम वापस लेने का समय बढ़ा देना चाहता हूं। वित्त मिर्मितः लेखा मिर्मितः प्राक्कलन मिर्मितः, सामान्य शामन स्थायो समिति श्रीर पुल्तम म्यायो मिर्मितः, इनके जो माननीय मदस्य नामज्ञद हुए हं उनके नाम वापस लेने का सम्बद्ध ११ तारीत्व, ३ वजे तक म बढ़ा देता हू ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना

श्री श्रध्यक्ष—दूसरी एक श्रोर मूचना है। मेरे पानने एक प्रस्ताव श्री काली चरण जी ने भेजा ह कि "म प्रस्ताव करना हूं कि प्रक्षिया नियमावनी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम संख्या ११ को निर्माम्बन कर के जब तक पंचायन राज विधेयक विचाराधीन हूं. सदन प्रति दिन ६ बजे शाम नक तथा १२ मई को उस समय नक बंडे जब तक कि उक्त विधेयक पारित न हो जाय, तथा विधेयक १२ मई तक पारित करने के हेनु उक्त विधेयक पर मशोधन के प्रस्तावक तथा मंत्री जी को भाषण के निये १० मिनट तक श्रन्य मदस्यों के निये ५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय"।

यह प्रस्ताव म सोमवार को लूंगा. चूंकि इसमे नोटिस की ग्रावश्यकता है, इसलिये उम दिन इम प्रस्ताव पर विचार किया जारेगा। मने सूचना दे दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की ग्रवहेलना के विषय में विशेशिधकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री ग्रध्यक्ष--ग्रव जो विषय सामने हं उस पर विवाद जारी रहेगा।

*श्री केशव गुप्त—(जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् ग्रध्यक्ष महोदय, मेने श्राज ग्रपने नेता माननीय पंत जो का भाषण सुना। उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया कि भविष्य में वह मैजिस्ट्रेटों को इस बात की हिदायत भेज देगे कि वह शी घ्र से शी घ्र किसी प्रकार गिरफ्तारियां हमारे प्रतिनिधियों की हों तो वह उसकी सूचना श्राप को देगे लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आदेश जारी करने से कोई विशेषाधिकार इस हाउस का या हाउस के प्रतिनिधियों का बढ़ने वाला नहीं हं, क्योंकि हमारे संविधान ने तो यह निक्चय कर दिया कि हमारे प्रिविने जेज वही रहेगे जो कि हाउस आफ कामंस के हैं या पालियामेंट के हे उस समय तक जब तक कि कोई लाज हम इनऐक्ट करके कोई नये विशेषाधिकार अपने निए म्रस्तियार न कर लें। इसलिए एक्जिक्युटिव म्रार्डर के जरिये से हाउस के कोई विशेषाधिकार बढ़ जायं, ऐसी कोई मुझे संभावना नहीं मालूम होती श्रीर जिस समय तक हमारा यह संविधान है उस समय तक ऐसा होना संभव नहीं है। मब देखना यह है कि जो प्रश्न हमारे सामने हैं उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न ग्राता है या नहीं ग्राता है, मैने भी इसका विचार करने की थोड़ो सो कोशिश की ग्रौर मंने उसमें जो निर्णय है, उसको देखा। यह तो मानी हुयी बात है कि झरेस्ट हवी और इसको तो विशेषाधिकार समिति भी सर्वसम्मति से स्वीकार करती हैं कि अरेस्ट हुँगी। लेकिन अब देखना यह हैं कि वह अरेस्ट किस प्रकार की है आया वह किसी क्रिमिनल ग्राफेंस में थो या क्या थो। इस चीज को हमें देखना है। ग्रगर वह क्रिमिनल म्राफेंस में थी या ऐसे किमिनन आफेंस में थी जिसके चाजेंज फ्रेम हो सकते है तब तो एक होटो सी बात हो सकनी है कि मैजिस्ट्रेट ने इत्तिला दो या नहीं। इसको हाउस ग्राफ कामंस भो मान चुका है ग्रीर बहुइय बात पर जोर देता है कि किमिनल ग्राफेंस में सूचना दे दो जाय। लेकिन सुबना का कोई वक्त मुकरंर नहीं है और जैसा श्रभी पढ़कर सुनाया गया दस या १२ दिन तक सुवना न देने पर भो उसे विजेशियकार का प्रक्न नहीं माना । सूचना मिलनी चाहिए चाहे देर में हो क्यों न मिले । लेकिन यहां पर एक बिलकुल दूसरा प्रक्न है। यहां तो गिरक्तारी

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

होती है लेकिन किसी कानून के अन्दर नहीं होती है। अगर १४४ की अवहेलना मे भी गिरफ्तारं, होती है तो उसमें भी १८६ को कार्यवाही होती है। यहां पर कोई गिरफ्तारी १४४ या १२६ को मातहत, जैसा कि किमिनल प्रोसोजर कोड के मातहत प्रोवाइडेड है, नहीं हुयो है। इसमें नकोई वारंट जारो हुआ है और न कोई और कार्यवाही हुयो है। वारंट का भी एक फार्न दिया हुआ है कि वह इस तरह से जारो होगा। लेकिन उसमें वह कुछ भी नहीं हुआ है। यह गिरफ्तारी किसी कल के अन्दर नहीं आती है। इसलिए में समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति को इस प्रक्रन पर अवश्य विचार करना चाहिये था कि अगर इस प्रकार की गिरफ्तारो हो कि जो किसी भी कानून के अन्दर न आतो हो तो वह उस के अपर क्या हमारे विशेपाधिकार होंगे उसको उन्हें सोचना चाहिये था और उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये यह भी उन्हें परामर्श देना चाहिये था। मेज पालियामेंटरी प्रैक्ट्स के पेज १२० पर यह लिखा हुआ है:—

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a Member of the House of Commons during a session of Parliament, or during the forty days preceding or the forty days following a session."

तो यहां पर गिरफ्तारो होतो है ५ फरवरी की, हाउस मोट कर रहा है ११ फरवरी को। मैंने अर्ज किया कि १८८ में गिरफ्तारी नहीं हुयी, १४४ के केस में भी नहीं हयी, क्योंकि १४४ के केस में भी १८८ को तरह हो गिरफ्तारी होतो है। उसका भी एक प्रोमीजर दियाहुग्राहै, वारंट का फार्म भी दिया हुग्राहै, इसलिए उसमें भी यह गिरफ्तारी नहीं होती। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गिरपतारो जब किसी में नहीं श्राती तो इसमे तो एक कंटेम्प्ट का प्रश्न हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूं कि इसपर विशेषाधिकार समिति को श्रपनी सम्मत्ति देनो चाहिये थी ग्रीर जो ऐडवोकेट जनरल ने ग्रपनी सम्मति दी है ग्रीर उन्होंने यह कहा है उसके अन्दर कि आगे जाकर इसके अपर फिर सोचकर अपनी रिपोर्ट देगे कि म्राया इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, उनकी इस सम्मति को भी विशेषाधिकार समिति को अवश्यमेव मंगाना चाहिये था, क्योंकि उससे बहुत कुछ रोशनो इस प्रश्न के ऊपर पड़ सकती थो। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रश्न को फिर दोबारा विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय ग्रौर वह फिर इस पर विचार कर ग्रौर इस दब्टि से विचार करे कि यह कंटेम्पट श्राफ दि हाउस तो नहीं हो गया, कहीं इल्लोगल अरेस्ट तो नहीं हो गया कि न १४४ के अनुसार अरेस्ट है न १८८ के अनुसार है, वारंट नहीं डिटेन्शन नहीं, १०७ नहीं, तो यह कहीं कंटेम्प्ट का प्रश्न तो नहीं है और कंटेम्प्ट ज्यादा होनियस हो जाता है ब नस्बत प्रिविलेज ग्राफ हाउस के, क्योंकि जैसा मैने पहले ग्रर्ज किया कि इन्फार्यशन देने का तो बहुत थोड़ा सा सवाल है। वह इन्कार्मेशन दे, न दे, १५ दिन में दे, १८ दिन में दे क्योंकि ग्रभी एक रूलिंग माननीय मुख्य मंत्री जो ने कोट की कि १५ दिन की देर होने पर भी उसे उन्होंने कोच श्राफ प्रिविलेज नहीं माना तो िर्फ साधारण सूचना देने को मं इतना श्रावश्यक नहीं समझता जितना कि इस प्रश्न को कि क्या यह श्ररेस्ट लोगल थी या इल्लीगल थी। श्रगर इल्लोगल थो तो उसके बारे में क्या विशेषाधिकार है, ग्रौर उस पर क्या होना चाहिए, यह विचार होना म्रावश्यक है । यह दृष्टिकोण मैने म्रापके सामने रखा ।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला ग्राजमगढ़)—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मं माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के परचात् इस सम्बन्ध में राय प्रगट करना जरा बड़ा कठिन सा हो गया है। हम उनकी दलोलों से चाहे प्रभावित हुए हों या न हुए हों लेकिन उनकी हिमालियन परसोनेलिटो का बोझ तो हम पर ग्राही गया है। फिर भी जी मानता नहीं ग्रीर में चाहता हूं कि में भी ग्रपनी राय इस सम्बन्ध में व्यक्त करने की कोशिश करूं। में स्पष्ट रूप से समझता हूं कि बीच ग्राफ दि प्रिविलेजेज ग्राफ दि हाउस इस सम्बन्ध में हुग्रा है ग्रीर मिस्टर टंडन इस सम्बन्ध में रिस्पांसिबिल हैं जैसे किसी ग्रपराध के सम्बन्ध में कोई रिस्पांसिबिल हो सकता है।

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो विशेषाधिकार सिमिति की रिपोर्ट हे उसके पृष्ठ द पर से की पालियामेटरी प्राकृत के पृष्ठ = ०-=१ में उद्धरण विया गया है। उस उद्धरण का उन्होंने महारा दिया है जोन उससे कन्त्रिकान अपलाई करके यह कहा है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। उस उद्धरण में कहा गया है -- Where a Member is convicted but released on bail nonung un appeal "the auty of the Magistrate" to communicate with the Speaker coes not arise."

म नम्बनापूर्वेक इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहना हूं कि यह जो उद्धरण है इस केन मिन्नम्बन लानात्मुक साहँ, इज नाट एप्लाई एट आल। एक तो किन्वकान का प्रभन ही सही उठना। इसलिए क्निंग विलक् वेकार मी है। लेकिन अगर मान भी लिया जाय थोड़ी देर के लिए, वह अप्लाई हीनी हे नो हम ऐसे केस की कल्पना करें जिसमें मैजिस्ट्रट के कोर्ट में केस गया आर उस मंजिस्ट्रट ने उसकी सजा दो। ला प्रैक्टिशनमें की मालूम होगा कि जिस समय मंजिस्ट्रेट ने मजा दो वहां पर उस समय वकील बेल अप्लीकेशन लिये तैयार रहता हैं। उसने बेल अप्लीकेशन दो और वह मंजूर हो गयी। उसमें एक मिनट के डिटेशन की भी परिस्थित नहीं पँदा होनी। लेकिन म एक ऐसे केस की कल्पना करता हूं जब एक आदमी को मजा हो जाय, दो घटे या चार घंटे कस्टडी में भेज दिया जाय, वहां पुलिस की हवालात रहनी हं उसमें बन्द कर दिया जाय। तो उस हालत में क्या होगा? उसके लिये यह हिना अप्लायी करेगी या नहीं ? में समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करेगे। इस क्लिंग में स्ता को कल्पना भी नहीं की गयी है जबिक दो चार घंटे किमी को कस्टडी में रखा गया हो। में आपकी आज्ञा से पूरे उद्धरण को पढ़ना चाहता हूं—

"The Committal of a Member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the Member is committed to prison, ball not being allowed; and subsequently, if the Member be not released from custody, or acquitted, the judge informs the Speaker of the offence for which the Member was condemned, and the sentence that has been passed upon him. Where a Member is convicted but released on bail pending an appeal, the duty of the magistrate to communicate with the Speaker case not affect.

तो कस्टडो का बो शब्द आया हुन्ना हं वह मेरे कथन का समर्थन करता है। स्रगर एक प्रादमी का कनिवकान हुन्ना और एक घंटे से एक वर्ष और हजार वर्ष तक कस्टडो में गहा, तो जो उद्धरण दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी इनफार्म करने की स्पीकर को उस वक्त नहीं हं तो जो किंजग दी गयी हं पहले तो कनिवक्तान के बारे में है। कोर्ट में केस गया और मजा हुयी। तो यह किंजग वहां अप्लाई नहीं करती। इसरा सवाल हं और इसी उद्धरण में हे कि कस्टडो के सम्बन्ध में सूचना देना जरूरी हैं। कोर्ट में सजा होती हैं, कोर्ट आईर देनी हैं कि 'टिल दि राइजिंग आफ दि कोर्ट कनफाइन रहेगा—उस हालत में क्या होगा, इसकी कल्पना इसमें नहीं की गयी हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थित पैदा हो तो भी मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि स्पाकर को इत्तला मिले या न मिले। मेरा निवेदन यह हैं कि जो उद्धरण दिया गया है और उन्हीं दलीलों से पूरे इस ऐक्शन को डिफेड किया गया है उनका केस एक्सपोज हो जाता है। माननीय नारायण दत्त तिवारा एक किनट से पांच वर्ष तक भी कस्टडो में थे तो यह रेम्पॉमिबिलिटी थी उनकी कि वह स्पीकर को इत्तला देते, और इत्तला न दें तो बीच आफ दी प्रिवलेज हुन्ना, जो नकीर दी गयी, उसके मुतादिक।

एक दूसरा प्रक्न उपस्थित होता है कोई ग्रावमी गिरफ्तार हो श्रौर बड़े ग्रच्छे बंगले मे ले जाकर रक्खा जाय जैसे काश्मीर में क्यामाप्रसाद मुकर्जी रक्खे गये थे तो उसमें कर्टनी [ओ केशव गुप्त]

का क्वेश्चन नहीं होता। ५ घंटे जोप मे रक्बा गया, श्राइस कीम खिलाते हुए ले गये और कन्कन्न तक या लंका तक पहुंचा जाते तो कर्टसो का क्वेश्चन नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस क्टंन् से हमारे सब श्रिकार छोन लिये गये। हमारे प्रिविलेज हैं श्रीर पालियामेंट की प्रोमींक ने इसे तय किया है। हमारे कांस्टोट्यूशन श्राफ इंडिया में भी लिखा गया है—

"In other respects the powers, privileges and immunities of a House the Legislature of a State and of the members and the committees c. House of such Legislature shall be such as may from time to time be define by the Legislature by law and until so defined shall be those of the Hc. of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its member and committees at the commencement of this Constitution."

तो इस लेजिस्ले बर को पूरा श्रधिकार है कि जो श्रब तक क वेशंस है उनको फालो करें क कन्बेंशंस एस्टेब्लिश करें श्रीर यह डिफाइन करें कि यह प्रिविलेजेज क्या है। श्रव श्रवस्त श्रा गया है जबिक यह डिफाइन कर दिया जाय कि हमारे प्रिविलेज क्या है। श्रा हाउन के किसो सदस्य का श्रामान होता है तो उससे पूरी सरकार की शक्ति कीण होनी हैं में समझता हूं कि हमारे मंजिस्ट्रेट टंडन साहब ने मेज को पालियामेंटरा प्रेक्टि पढ़ी हो या न पढ़ी हो लेकिन इतना वह श्रवश्य जानते थे कि जब कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेचर का गिरफ्तार हो तो स्पीकर को सूचना देनी चाहिये। इस डिटेल्स चाहे मालूम हों या न मालूम हों, उनको चाहे यह न मालूम हो कि किस वजन ए सूचना देनी चाहिये या न देनी चाहिये श्रीर श्रा श्रा उनको डाउट था तब तो उनको ग्रीर में सूचना देनी चाहिये थी। लेकिन जब उन्होंने सूचना नहीं दो तो इस बात के मानने में केंद्र दिक्कत नहीं मालूम होतो कि उन्होंने जानबूझ कर सूचना न देने का निश्चय किया नेकि उन्होंने डेलीबेटली इस बात को एवायड किया ग्रीर प्रिविलेजेज को बोच किया जैसा कि खिंह में लिखा गया है कुछ घंटों के लिए रक्खा गया, इससे कोई श्रन्तर नहीं पड़ता। श्ररेस्ट उनके किया गया श्रीर बोच श्राफ प्रिविलेज हुश्रा श्रीर टंडन ने जानबूझ कर इसे किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—म्ब्रध्यक्ष महोदय, मं प्रस्ताव करता हूं कि इस किः पर वादविवाद के लिये दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री इस पर कुछ राय देगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—में तो समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी यदि सदन् चाहता हो तो में कोई रोफना नहीं चाहता। दर श्रस्त उम्मीद यह थो कि दो धंट में बहस समाप्त हो जायगी। जो रूल हूं वह भी ऐसा ही है कि जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जाय तो उस पर बीफ डिस्कशन होना चाहिये, श्रब जैसा श्रध्यक्ष महोद्य, उचित समझें करें।

श्री अध्यक्ष—मं सदन पर छोड़ता हूं ग्रौर सदन की राय लिये लेता हूं। नियम नं यही है कि कम से कम डिस्फरान होना चाहिये, यह ख्याल रखते हुए सदन अपनी राय दे:

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यदि में कह सकूं तो यह तो स्पेसिफिक ईब्यू है। प्रथम ने कमेटी को कमिट किया श्रीर कमेटी ने उस पर राय दी। श्रव यह कहना कि श्रीर बीं होनी चाहिये थीं या नहीं, श्रध्यक्ष ने रूल श्राउट किया कि यह नहीं हो सकता बातो उनके बार में कोई सवाल नहीं उठता। दरश्रसल उसकी रिलेबंसी भी नहीं होती। जन् तक इन्धामें की बान है उस के लिए बहुत च्यादा इम्पोर्टेन्स श्रटेच नहीं करना है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, ग्रापके निर्णय के के पहले में यह निवेदन करना चाहताहूं कि इस बात परध्यान दिया जाय कि यह जो

विजेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयी है वह एक राय के अन्तर में अपी है यानी असेर ४ के मन में आयी है। वह इस प्रकार के निणय में अपी है अगर यह बान भी ध्यान में राजी जाय तो इसके लिये अधिक समय देना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि इस वादिवाद का समय ५ वजे तक बढ़ा विया जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (ज्ञिला मनपुरी) — ग्रध्यक्ष महोदय, इस भवन को केवल इस प्रश्न पर निर्णय लेना है कि चाहे किनी भी प्रकार की सदस्य को गिरपनारी या डिटेन्शन हुआ हो, तो दोनों में से कोई हालत हुयी हो. मॅजिस्ट्रेट को या अन्य अधिकारी को स्पीकर को मुचना देना मावश्यकीय था या नहीं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोग इस ननीजे पर ब्राये कि ममिति ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये कि जिसके दगरण बहुमत ने यह समझा कि स्प. कर को मुचना देना प्रावश्यकीय नहीं था। सबसे मजबूत स्रोर जबरदस्त प्वाइंट जिसके बारे में यह कहा गया है कि गिरफ्तारों के बारे में सूचना नहीं देनी चाहिये थी वह यह था कि उनको जेल में ने हीं भेजा गया। अगर वास्तव में हम इस प्रश्न पर निश्चय कर ले तो हमको यह देखना पडेगा कि बन्दोगह या प्रिजन की परिभाषा क्या है? अगर वास्तव में प्रिजन की परिभाषा केवल उसी स्थान से मानी जाय, जिसकी श्राम तौर पर बन्दीगृह कहते हे ती बास्तव में हाउस के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हे लेकिन यदि यह इसके विपरीत है तो अधिकारों को ठेस पहुंची है। श्रीर उसमें यह नहीं श्राता है। में तो यह कहना चाहता हैं कि प्रिजन की परिभाषों देखने के लिये जो हमारा प्रिजन्स ऐक्ट है अगर उसी को हम देखें तो मालुम होगा कि उसमे क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा से उसका ग्राशय केवल उस दन्दीगृह से नहीं है बल्कि जहां कहीं भी एक मेम्बर को डिटेन किया जाता हो तो वहां वह किमिनल प्रिजनर कहा जायगा । इस सम्बन्ध में प्रिजन्स ऐक्ट में त्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा इस प्रकार से है कि:

"Criminal prisoner means any prisoner duly committed to custody under writ, warrant or order of any court or authority exercising criminal jurisdiction."

इसके बाद अगर हम बन्दीगृह की परिभाषा देखते हैं तो हमको अपने यहां की परिभाषा को न देखकर हमको इंग्लंन्ड के प्रिजन्स ऐक्ट की परिभाषा को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकार हमारे संविधान द्वारा डिफाइन नहीं किये गये हैं। उसमें यह माना गया है कि इंग्लंन्ड के पालियामेंट के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होने हैं वही विशेषाधिकार हम लोगों के हैं। तो इस तरह से हम लोगों को वहां पर जो प्रिजन्स की परिभाषा है इस सम्बन्ध में अपनानी पड़ेगी। यह जो समिति की रिपोर्ट प्रस्तुन की गयी हे उसके पेज ६ पर प्रिजन्स की परिभाषा इस तरह से दो गयी है:

"The prison of the King's bench is not any local prison confined only to one place and every place where any prison is restrained of his liberty is a prson....."

इसके बाद हम देखते हे कि उसी पुष्ठ पर फिर हमको कन्फाइनमेन्ट की परिभाषा मिलती है--

"Every confinement of the person is an imprisonment whether it be in a common prison, or in the stocks, or even by forcibly detaining one in the public street."

इन परिभाषाओं में मालूम होता है कि केवल बंदीगृह ही प्रिजन नहीं है। बल्कि जहां भी सबस्य को रोका या गिरक्तार किया जाय,वहीं वह प्रिजन कहलायेगा चाहे वह टैम्पोरेरी हो या परमानेंट प्रिजन हो। हुमारे तर्क की पुष्टि लोक सभा के श्रादेश से भी होती है जी हमारे चीफ़ सेकेटरी

[श्री बीरेन्द्रपति यादव]

द्वारा जारो किया गया है। उसमे त्रिजन शब्द का जिक नहीं है। उसमे यह है कि अगर किसे सबस्य को गिरफ्तारो हो, रोका जाय, डिटेंशन हो या उसकी दण्ड दिय। जाय या किसी के मुकद में के सिलिसले में मुक्त किया गया हो तो स्पीकर को सूचना देनी होगी। म सिमित के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि सबस्य को जेल नहीं भेजा गया तो विशेषाधिकार को अवहेलन नहीं हुई। आमतौर से ऐसा होता है कि मुलिजमान को गिरफ्तार होने के बाद वहीं जमानन पर छोड़ दिया जाता है और जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसा कि पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि एक शब्स पर मुक्तदमा चल रहा है और आम तौर से काबिल ज़मानत जुमों में में जिस्ट्रेट वहीं छोड़ देते हैं, और यदि मैं जिस्ट्रेट ने नहीं छोड़ा तो उसी दिन सेशन जज से दोनों प्रकार के जमें में जमानत हो कर छूट जाते हैं, तो यदि सिमिति के तर्क को माने तो सदस्यों का हमें हैं हैं सेमेंट हुआ करेगा और जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा।

इस देश के कर्मचारियों श्रौर विशेष तौर से पुलिस कर्मचारियों श्रौर इनालंग्ड हे कर्मचारियों में बहुत श्रन्तर है। यदि ऐसा न होता, तो यह श्रापत्तियां उठाने की श्रावश्यक्ता ही प्रतीत नहीं होती।

बहुत से तर्क इस तरह के भी अ।ये हैं कि तिवारी जी अपनी इच्छा से हल्द्वानी जाना चाहने थे और मैंजिस्ट्रेट का विवार कभी भी नहीं था कि उनको जेल मे रखे परन्तु तिवारी जी की मुक्त करने का विवार उनका शुरू हो से था। मैं समझता हूं कि इस तर्क में भी ज्यादा तत्व नहीं है। उनकी जोप में कोई आकर्षण नहीं था या मनीरंजन विषय ऐसा नहीं था जिसकी बिना पर उनकी जोप में तिवारी जो स्वयं जाकर बैठ जाते।

इसके बाद समिति की श्रोर से यह भी कहा गया है कि डिटेंशन १ या साढ़े पांच घंटे का था श्रोर श्रगर दो एक महोने का होता तो डिटेंशन कहा जा सकता था। मेरो समझ में श्रगर डिटेंशन १ मिनट का ही रहा हो तो वह डिटेंशन होता है। सदस्यों को विशेष तौर से ऐसी परिस्थितियों में हाने से श्रोर भो ज्यादा है रैसमेंट श्रागे चल कर हो सकता है। इंग्लंड में पुलिस की स्थानि अंचे पैमाने पर है, बदिक स्मती से हम श्रपने देश में उसके विपरीत पाते हे। वहां के विशेषाधिकार बहुत लड़ाई के बाद बने हें श्रोर बहुत वर्षों के तजुर्बे की बिना पर है। हाउस श्राफ कामन्स के सिद्धांतों को हमें मानना होगा लेकिन बहुत रिजिडलो नहीं। जहां तक प्रिजन का सवाल है। इस देश की परिस्थिति को देखते हुए, वहां के सिद्धान्तों में कुछ फिलेक्सिवितिटी लानी पड़ेगी। माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रिधक नहीं कहना चाहता केवल इतने ही शब्द कहना चाहता हूं कि तिवारो जो को पकड़े जाने से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुश्रा है। में माननीय मुख्य मंत्री जो से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिये कुछ न कुछ इलाज निकाले वरना भवन की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जायगी श्रीर पड़ रही है श्रीर इन्डिविज्यल मेम्बर्स की प्रतिष्ठा तो खतरे में पहले से ही पड़ चुकी है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—प्रध्यक्ष महोदय, पहले में प्रपनी कमजोरी कब्ल करता हूं ग्रपनी कमो बतलाना चाहता हूं वह मेरी कमजोरी यह है कि में लाइयर नहीं हूं, कानूनदां नहीं हूं ग्रीर इस वक्त प्रश्न कानून का है। इसिलये ग्रपनी कमजोरी को कबूल करने के बाद अपने विचार पेश करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री के तर्कपूर्ण उदार व्याख्यान के बाद भी मुखाालफत हो रही है। उसका कारण मेरी समझ में नहीं खाता अपीजीशन की बेंचेज की ख्रीर से यदि मुखालिफत होती तो हमें कोई शिकायत नहीं होती लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई भी(शोर)

श्री अध्यक्ष—इसके मिलसिले में इस तरह की पार्टियों के बारे में बातें नहीं होनी चाहियें । श्री मीनाराम द्युक्त-अगर ग्राप जरा मुनने की मेहरवानी करेगे तो जात होगा कि इस उर विजेबाधिकार का प्रस्त उठाना कहां तक उचित है गा इस मंजीयन को पान करने के नवीजे पर बहुं विजेशा श्रीर जरा उंचे दिमार में मुन लेने के बाद चाहे तो बड़ी खुजी में सक्तियक कॉडिंग ।

अध्यक्ष महोहय. एक कानून बनता है लेकिन उसका जहां ऐप्तिकेशन होता है उसकी क्रिक्यि नित्रों जो दे वे कर जमील-प्राप्तमान का ग्रन्तर पड़ जाता है । एक कानून बनता है उसैती के किये। डकॅनी करना जुर्म हे लेकिन एक डकेनी करने वाला अपने लिये उकेती करता है ग्राप्त दूररा दूररों के लिये उकेंत अपना है. इन दोनों उकेतियों में जर्म र-ग्रासमान का श्रन्तर है। इक भी उकेनी उालने हु और जेलडाने के जाने हु लेकिन भगत सिंह और राम प्रसाद विस्मित भी उकेनों के कारण जैन गरे थे। एक की हम बुरा कहने हे और दूसरे की इज्जत की नज्ञर में देवने है। इसनिये मेरी एजारिया ह कि जरा विचार की जिये कि आया उस मैजिस्ट्रेट न बर्र नियन में यह गरनी को था का जानवृक्त कर की थी कि स्पेकर साहब की नाराणणदत्त जी के बारे में मुचना नहीं दी। जब उन्होंने उनको गिरफ्तार किया तो स्पीकर साहब को सूचना दे दी गया। फिर म्यं कर माहब को मूचना देने का मनलब यह होना है ताकि स्पीकर साहब यह हेन्त नकें और उस र ऐकान ने मके और उसमे जान-पड़तान कर सके। यदि ज्यादती हुई है तो ऐकान ने मके। लेकिन वहां तो गिरफ्नारी का भवाल ही नहीं है। बाल की खाल तो में नहीं निकालना चाहना लेकिन यह माफ जाहिर है कि उनको इसलिये पकड़ा गया कि एक जगह पकड़ कर दूसरी जगह छोड़ दिया जायगा। उनको पकड़ा गया यह ठीक है लेकिन यह भी वाक्या है कि उनको लेजाकर छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो ऐसी हालत में सूचना देना क्यों जरूरी था? मेरी गुजारिक है कि इस पर गौर फरमाया जाय। हमारे माननीय तिवारी जो की शादो १० तारी के होने वाली है इसिलये में यह चाहता हूं कि दबी जबान मे जवाब दं ताकि उनको शादी में वाघा भी न पड़े। श्रीर उत्तर भी दे दु हुजूरवाला, श्राप देखिये कि काश्तकार वहां पर जमा थे, वे अपना गन्ना वेचना चाहते थे, वे ग्ररोब ग्रौर भूखे थे, उनको जा कर रोकना कहां तक ठे.क था ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—प्वाइंट श्राफ श्रार्टर सर, श्रध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्न यह है कि विशेवाधिकार की श्रवहेलना हुई है या नहीं। माननीय शुक्ल जी डिटेल्स में जा रहे है। जब माननीय गेदानिह जी बोल रहे थे तो श्रापने श्राज्ञा दी थी कि वे फैक्ट्स पर न जाकर विशेषाधिकार के प्रश्न पर ही बोले।

श्री अध्यक्ष-वे कानून नहीं जानते, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया है।

श्री सीताराम शुक्ल अध्यक्ष महोदय, मं श्रजं कर रहा था कि मं उघर नहीं जाऊंगा लेकिन इशारा किया जा सकता हूँ श्रोर प्वाइंट के जरा बाहर जा कर भी उससे फायदा उठाया जा सकता है। मंने पहले हो अर्ज किया था कि कायदे कानून वही रहा करते हैं लेकिन नियत से बहुन बड़ा फर्क हो जाया करता है। एक श्रादमी है जो किसी को एक चपत मारता है श्रीर वह मर जाता है तो उसको ६ महीने की मजा होती हैं, एक श्रादमी किसी को गोली मारता है तो उसको फांसी की सजा होती है श्रीर एक श्रादमी किसी डाकू को मारता है तो उसे इनाम मिलता है। तो कानून जो बनता है वह नियत पर बहुत डिपंड करता है। श्रायक्ष महोदय, इस श्रादरणीय सदन की हिस्टरी में नई बात हुई कि जहां किसी ने माननीय श्रायक्ष के हुक्म की श्रवहेलना की हो लेकिन हमारे माननीय मेम्बर श्री तिवारी जो ने श्राप के हुक्म को यहां तोड़ा श्रीर बार-वार तोड़ा। तब फिर श्राप ने पुलिस को श्रार्डर दिया और उसने उनको बाहर कर दिया। तो क्या श्रापने उनको गिरफ्तार किया था? मजबूरी थी जिमने श्राप को यह तरोक़ा श्रव्यार करना पड़ा। उसी प्रकार पब्लिक का नुक्सान हो रहा था तो मैजिस्ट्रेट ने उनकी जीप में बैठा कर दूसरी जगह भेज दिया तो में समझता है कि इसमें कोई गिसती उसकी नहीं थी।

४१२

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यहां सूचना देने का है।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरी प्रार्थना कि सूचना देने की श्रावश्यकता नहीं दें माननीय 'मुख्य मंत्री जी के यह कहने के बावजूद कि मे श्रायन्दा के लिये श्राहंग् देंगा कि ऐसी हरकन होने पर खबर दें दी जाय, इस श्राद्यासन के बावजूद भी आर बह्मक के कोई रिमार्क नात होता है कि मैजिस्ट्रेट ने ग़लती की तो मुफ्त मे यह एक उसकी शिक को जाती है श्रीर हुजूरवाला, श्रगर हमारे दोस्त जानबूझ कर कानून को तोड़ने ह तो उसे रोकना ही पड़ेगा..........

श्री अध्यक्ष-यह ग्रसंगत सा है।

श्री सीताराम शुक्ल—मै कहता हूं कि जानबूझ कर कानून तोड़ने वालों के मण कितनी रियायत की जायगी। इसलिए में निवेदन करता हूं कि जो रियोर्ट ग्रायं । उसकी पास किया जाय।

श्री नवलिकशोर (जिला बरेली)—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, विशेषाधिका सिमिति का जो प्रतिवेदन सदन के सामने हैं उस पर काफी देर से विवाद हो रहा है। जो होट सा प्रश्न है वह यह है कि माननीय तिवारी जी को ४ तारी ख़ को गिरफ्तार कर हल्द्वानों में ने जाकर छोड़ दिया गया। तो जो यह गिरफ्तारी हुई उसकी सूचना इस भवन के विशेषाधिकारियों को होनी चाहिये थी श्रीर यदि नहीं हुई, तो उससे इस भवन की श्रव-हेलना होती है या नहीं होती है। में श्राप की श्राज्ञा से दो तीन बाते रखना चाहता हूं। में पार्लियामेटरी प्रैक्टिस के पेज १२१ पर जो इस संबंध में लिखा हुग्रा है उसे में श्राप की श्रज्ञा में पढ़ता हूं—

"Although the privilege of freedom from arrest does not extend to comminal charges, it is the right of each House to receive immediate information for the imprisonment or detention of any Member, with the reason for which he is detained."

पेज ७६ पर श्रीमन् इस तरह से है--

"In all cases in which Members are arrested on criminal charges the House must be informed of the cause for which they are detained from their service in Parliament."

पेज १२० की दो लाइनें भी मैं पढ़ देना चाहता हूं ---

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a member of the House of Commons during a session of Parliamer: or during the forty days preceding, or the forty days following a session."

इसके ग्रलावा पेज ६९ पर यह भी दिया हुन्ना है--

"Privilege protects Members of Parliament with the same sanction as well from illegal molestation as from the legal process of arrest. Either is equally a breach of privilege."

श्रीमन्, इस कमेटी ने इस संबंध में तीन ईश्यूज अपने सामने बनाये। पहला ईश्यू तो यह कि उनकी गिरफ्तारी हुई वह टेक्निकल सेंस में श्ररेस्ट हुआ या नहीं। इस पर सर्व- सम्मित से यह तय हुआ कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई वह अरेस्ट है। तो सवाल यह है कि वह अरेस्ट है तो वह अरेस्ट किसो किमिनल आफेंस या किमिनल चार्जेज के सिलसिले में है या यूं ही है। जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं उनकी डेफिनिट व्यू है कि यह जो अरेस्ट है शमें न तो किसी किमिनल आफेंस की बात है न किमिनल चार्जेज की बात है। इस सम्बन्ध में प्रति- वेदन के पेज तीन पर लिखा है कि "उनको गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी और किसी और-

हानो ब्राप्टीय का जिसी फोबदारी प्रदर्शय के सम्बन्ध में त थें। इ.सिबेदन में यह भी कहा। सवा है कि मुचना देने की खाडद्यक्ता नभी होती है। जब कि कोई महत्य कोजदारी। खारीक पर दा क्रोन्द्रकी प्रदेश के मध्यत्य में कारावाम में भेजे जांच 🖰 मात्र साहित है कि करेटी भी मानती ह ि वह प्रकेट किमिनल चार्रा रूप नहीं थी और प्रकर किमिनत चारी पर नहीं था तब सूचना हैन इस्ते नहीं था: अहर यह माने ने कि कि कि जिस्से वार्ज पर यातव है। से समझेता है िक इस नदम के नुचना देनी जनगाथी। मगर जेना कि माना गया कि नहीं थी तो ब्राखिर सवाल उह ह कि यह क्या चे. ब थी और किए आवार पर थी। म समझना हूं कि अगर हम उस ब्यू को मामें जमी कि एडवोकेट जनरल माहव की है कि यह केन कि यनने वार्ज के मिलमिले में नहीं या नद नो श्रीमन्, यह मामना मदन की कण्डेम्पट की क्लाज के अन्तर्गत माफ नार में आ जाता इ झोर यह झोर भी ज्यादा बड़ी सपती है झोर जैसा कि राधामोहन विष्ठ जी ने कहा कि अरेस्ट इस मेन्स में नहीं बल्कि इस मेन्स में हुई नव नी म नमझता है कि जैना मने पहले भा कहा कि यह ग्रनेस्ट इन्जे एन मानेस्टेशन में ग्रा जानी है। तब भी बीच होता है। श्री टंडन ने ग्राप के ग्राडर में निवाह कि क्रोंकि भी नामयणदन निवासी ने दका १८८ का तोड़ा ह इननिये आदेश दिये गर्ने कि थानेदार कार्ड पुर उनको वहां में हटा दे स्रोर हन्द्वानी ने जा कर छोड़ दे । वह कम से कम ५ घंटे नी इन नरह निरम्नार रहे ही। इसलिये वह चाज तो लागू नहीं होती कि इन हालात में इनाना देने की जहरन नहीं है। क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्द ह कि उनकी हल्द्वानी ने जा कर छोड़ा ज्ञ य याती उनके ऊरर पाबन्दा लगा दी गयी। टंडन जी ने कुछ भी कहा ही ग्रोर मंगा भी कुछ रही हो लेक्नि जंसिक एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम को देखना यह है कि उनका ऐक्शन क्या था। उनका ऐक्शन कानूनी नहीं था, एक हेफेजार्ड तरीक़े का था। किसी मैजिस्ट्रेट के लिये इस तरह की कानूनी चाज के जो रिजल्ट्स ह उनका सोचना एक कठिन सवान होता है। दफा १८४ के मिलितिने में जो ऐक्सन हुत्रा वह दका १८८ के अन्दर होना चाहिये था सो नहीं हुआ वन्कि एक गुजन इंग से उनको अरेस्ट किया पया जेसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है। ब्ररेस्ट फिल किस्म की थी इस बारे में कंफ्यजन जरूर हे मगर जो भी हो न भी इसको ब्ररेस्ट उरूर मानता हूं। ग्रनः सूचना देना भी ग्रावश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष-- ग्राप ग्रमंगत हो रहे हं।

श्री नवलिक शोर—म यह कह रहा था कि दो ची बे ह कि श्ररेस्ट हुई श्रांर या जैसा कि टंटन जी का व्यू है कि अरेस्ट नहीं हुई। मेरा निवेदन यह है कि यदि अरेस्ट हुई श्रांर बिना किसी फीजदारी प्रारोप या अपराध के हुई तब बीच आफ प्रिविलेज तो हुआ ही मगर उससे कहीं भयंकर भवन की मानहानि की बात हो जाती है। यदि अरेस्ट नहीं था तब मालेस्टेशन था वह भी बीच है। इन शब्दों के साथ में यह कहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि इनटेन्शन था या नहीं। में भी समझता हूं कि इनटेन्शन नहीं था श्रीर जानवूसकर ऐसा नहीं किया गया लेकिन बीच आफ प्रिविनेज इस नेन्स में हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद उनका कर्तव्य था कि आप को सूचना दी जाती। लेकिन वह नहीं दी गयी इमलिये बीच हुआ और जरूर हुआ। बस मुझे इतना ही कहना था।

*श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय प्रध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों के प्रकट हो जाने के बाद, तिवारी जी के प्रस्ताव के मूव हो जाने के बाद ग्रीर यह जानते हुये कि तिवारी जी १४४ दफा तोड़ने जा रहे हैं, यह जानते हुये कि उन्होंने श्री टंडन से यह बताना मुनासिव नहीं समझा कि वह फ़ाइनेंस कमेटी को ग्रटेन्ड करने जा रहे हैं, इन जमाम बातों को जानते हुये ग्रीर सब से बड़ी बात यह कि मे इस सदन में सब मे कम बोलन बालों में से हूं फिर नी मुझे प्रेरगा हुई कि इस हाउस मे ग्राज दोलूं। ग्रीर इस कमेटी की रिगोर्ट जो सदन के सामने हैं उसके मुताल्लिक कहूं कि यह रिगोर्ट मंजूर न फरमाई जाय ग्रीर इमको दोबारा कमेटी के सुपुर्व पुनःविचार के लिये कर दिया जाय तो इसके कुछ कारण हैं ग्रीर सब

[श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल]

से पहला कारण यह है कि अगर यह रिपोर्ट मंजूर हो जाती हे तो इसके माने यह होगे कि मक या तो इस बात पर विचार नहीं करना चाहता कि यह गिरफ्तारी जो तिवारो जो को हुई वह वक्ट किसी किमिनल चार्ज के मातहत हुई या नहीं श्रीर श्रगर नहीं है तो इसका क्या श्रहर है या तो हाउस इस सवाल को नजरदाज करना चाहता है और या इस हो नजरन्दाज नहीं करन चाहता। जब यह सवाल हाउस के सामने पेश है तो इस सवाल को इस बिना पर कि इन्फामहत्त नहीं दी गयी और इक्फार्मेशन न देना इसलिय कि किमिनल चार्ज के मातहत गिरफ्तारी नहें हुई है इसलिये सदन के विशेषाधिकार को अवहेलना नहीं हुई है यह मुझे गलत सी बात मालूम होते है। मेने तिवारी जी के कम्प्लेन्ट को पढ़ा। उसमे यह है कि की रामरूप मिह, जिलाघोश, नेने ताल श्रौर श्री बी० एन० टंडन, एस० डी० एम०, काशीपुर ने उन्हें कोड श्राफ किमिनल प्रोमीज की धारा १४४ तोड़ने के अभियोग भे ४ फरवरी, १९५४ की सांयकाल ४ बजे के लगभग गिरण्ता किया और थाना इन्चार्ज, काशीपुर के हिरासत में दे दिया। तत्पश्चात् काशीपुर का एक पृत्निय दस्ता, जिसमें एक पुलिस सब-इन्संपेक्टर व छः हथियार बन्द कांस्टेबिल थे, उन्हे एक जीव मे काशीपुर से लगभग ५० माल दूर हल्द्वानी ले जाया गया जहां उन्हें साढ़े नौ बजे रात्रि को छोड विया गया। पुलिस भ्रौर श्रधिकारियों द्वारा इस प्रकार साढ़ें पांचे घंटे हिरासत में रखे जाने हे कारण वे फायनेंस कमेटी की बैठक में लखनऊ आने से वंचित रह गये और उन्हें एक दिन की हेर हो गयो। पुनः उनके गिरफ्तार किये जाने की सूचना भी श्रध्यक्ष को नहीं दो गयो जो विशेषा-धिकार की म्रवहेलना है। इसने उन्होंने किसी खास बात को नहीं लिखा कि म्रवहेलना इस कारण से हुई कि इसकी इतिला माननीय स्पीकर की नहीं हुई। उन्होंने इस बात की नही लिखा कि में इस बात को मानता हूं कि इसकी इत्तिला स्पीकर साहब को नहीं हुई इसिनये श्रवहेलना हुई बल्कि कुल का कुल कम्प्लेन्ट माननीय अध्यक्ष ने कमेटो के सुपुर्द कियाँ श्रीर कमेटी ने इसपर एक तरीके से विचार भी किया। एडवोकेंट जनरल का स्टेटमेंट भी है। एडवोकेंट जनरल से भी इस बात को पूछा लेकिन जब उनका जवाब न आया तो कमेटी ने इस सवात को श्रपने सम्मुख रखा। में एउँवोकेट जेनरल साहब की बात को श्रापके सम्मुख रखता हूं-

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, be cause this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i. e. not a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want some time."

तो मं यह जानता हूं कि यह सवाल कमेटी के सामने दरपेश हैं। एडवोकेट जेनरल ने इसका जवाब देन के लिये समय लिया। उसके बाद कमेटी ने २ अप्रैल, १६५४ की बैठक में श्री करहेंया लाल मिश्र, एडवोकेट जेनरल के उत्तर के बिना हो। इसका विचार किया। उनसे यह पूछा गया था कि प्रिवेटिव डिटेंशन के सम्बन्ध में सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं और उसके लिये सूचना देना आवश्यक है या नहीं। दोनों प्वाइंट्स को उनको रिफर किया गया। एडवोकेट जेनरल का उत्तर इस विषय में समिति की अन्तिम बैठक तक प्राप्त नहीं हुआ। और इस पर उन्होंने तीन सवाल सिर्फ अपने रूबरू बनाये। यानी जो कमेटी है विशेषाधिकार की उसने तीन सवाल बनाये। पहला सवाल यह था कि क्या श्री नारायणदत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशोपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी। इसका जवाब कमेटी ने दिया कि हां यह अरेस्ट थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधालक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी। इसके बारे में कहा गया कि गिरफ्तारी निरोधालमक थी। तीसरा प्रश्न यह था कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह जिस प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देन से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। इसके बारे में उन्होंने क्या सूचना न देन से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। इसके बारे में उन्होंने

भी जाराबार, दर्जानवारी की गिरपनारी से संबद्ध में विशेषाधिकार की स्रवहंलना ४१६ के विषय में विशेषाधिकार से मेन के प्रतिबंदन पर विचार

कहा कि सुचना देना तकरी नहीं था श्रोण सूचना न देने का जरूरत न होते का कारण यह बन्लिया कि वह क्रिमिनल चार्न के श्रन्दर श्रदेस्ट नहीं थी।

हम् नियं अध्यक्ष महोदय, में आपके मामने आर्ज करना चाहना हूं कि जिस कमेटी के अपने हम मामने हो रेकर किया उमने अपने मामने कोई चाँथा सवाल नहीं रक्खा । मेरी नमक में नहीं आता कि कमेटी कि रिपोर्ट में कोई चाँथा सवाल क्यों नहीं रक्खा गया। ए उबोकेट जनरल का फर्ज था कि वह कमेटी को उम सवाल का जवाब देता । इसलिये म अपके हारा यह कहना चाहना हूं कि इस सवाल को कमेटी को दोबारा रेफर किया जाना चाहिये और उनकी राय मालूम होनी चाहिये और तब उनके बाद इस रिपोर्ट को इस हाउस के मामने वेदा होना चाहिये । में इनना और भी अर्ज करना चाहता हूं और उसके बाद कम करगा कि नवाल यह नहीं है कि टंडन माहब को क्या मजा मिलनी चाहिये उनके बारे में हम बहुन मुलायम एटीट्यूड रखने हैं। लेकिन मवाल तो यह है कि अगर हाउस ने इस तरीके से इस रंजोल्यूडान को मंजूर किया तो तब जब यह कमेटी प्यूपुल के सामने जायगी उस वक्त क्या यह सवाल पदा नहीं होगा कि यह सवाल मदन में या कमेटो के सामने नहीं आया। या तो इस सवाल को नजरअन्दाज किया गया या तदन को समझ में बात नहीं आयो। गिरफ्तारी चाहे इल्लीगल हो, चाहे नाजायज हो जिसको किमिनल चार्ज के मात्त न कहा जा सकता हो, उसकी इन्फामें शन देने या न देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो गारा रा

श्री अध्यक्ष---ग्रव ग्रापका समय समाप्त हो गया ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बारावंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, में निश्चय ही माननीय मदस्यों के भाषण सुनने के पहले से ही इस विचार का हूं कि इसमें इस मदन के विशेषा—धिकार की अवहेलना हुई हैं। में इसपर अधिक न कहकर केवल श्री टंडन के उस आर्डर को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके एक एक शब्द की व्याख्या आपके सामने करना चाहना हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि जो यह किमिनल चार्ज का शब्द कहा गया है वह कहां तक सही अथवा गलत हैं। श्री टंडन ने जो आर्डर दिया है उसके शब्द में आपकी आजा में पड़ना चाहता हूं: "Sri Naram Dutt Tewari is committing a breach of section 144 Cr. P. C. by obstructing the sugarcane carts, trucks and wagons from entering into L. H. Sugar Factory, Kashipur" इससे एक आफ्स के तीन भाग होते है। एक तो यह कि एक आदमी आया "about to commit or is committing an offence" और "has committed an offence." तीन भाग होते हे इसके—

"Committed an offence. Has committed an offence and is about to commit an offence."

श्री नारायणदत्त तिवारी एल० एच० शुगर फंक्टरी के भीतर केन ट्रक्स श्रीर कार्ट ग्रार वंगन जाने से रोकते थे। दिस इज दी चार्ज। ग्रब इसका पिनशमेंट क्या हो? क्योंकि १४४ के बीच पर पिनशमेट श्राफ ग्रार्डर का १८८ है यह बिल्कुल निश्चित है। इसलिये उन शब्दों के किसी ग्रार्डर में यह नहीं लाया जा सकता था। ग्रब १४४ के ब्रीच के लिये १८८ में ग्रार्डर दिया जाय तो वे लिखते हं।

"I hereby order this punishment provided for breach of section 144. I hereby order the S. O. Kashipur to remove him under escort to Haldwani and release him there."

श्री नारायणदत्त तिवारी किसी प्लेजर द्रिप या साइट सोन के लिये नहीं ले जाये गये थे। उनकी मर्जी से उन्हें नहीं ले जाया जा रहा था। ग्रगर यह है तो दफा ३४२ ब्राई० पी०-सी० जिसमें क्रिमिनल रेस्ट्रेण्ट डिफाइन किया गया है साफ जाहिर होता है कि टंडन साहब ३४२ के मुजरिम है। यानी यह एक डेफनिट चार्ज है जिसका यह पनिशमेट हो जाता है कि उन्हें [श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

हल्द्वानों ले जाकर छोड़ा जाये। अब एक डेफिनिट चार्ज हो जाता है तो सदन को सूबना न देना श्रीर किमिनल चार्ज हो जाता है। हमारी समझ में विशेषाधिकार की अवहेलना है। विशेषा-धिकार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ३ पर यह लिखा हुआ है कि——

"The failure of a Judge or magistrate to inform the House of the committal to prison of a Member on a criminal charge or a criminal offence would, therefore, constitute a breach of privilege",

म्रव इससे यह स्पष्ट है कि किमिनल म्राफेंस था कि वे ऐस्ट १४४ का बीच कर रहे थे। म्रव दूनरी बात जो इसमें निखी हुयी है——

"though it is otherwise where a member is convicted but released on bail pending an appeal...."

नारायणदत्त तिवारी १४४ के बीच करने में किन्वक्ट हो गये। लेकिन इसनें ब्रांर ग्रागे लिखा हुग्रा है कि ग्रगर वे किन्वक्ट हो जाने के बाद बेल पर रिलीज हो जाते है तो बीच ग्राफ प्रिवितेज वह नहीं होता। लेकिन वह किन्वक्ट हो गये, उन्होंने सजा भी पूरी काट ली ग्रौर उसके बाद रिलीज हुए। इसलिये यह बीच ग्राफ प्रिविलेज हुग्रा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--- प्रध्यक्ष महोदय, मं बहुत देर से यह सीच रहा था कि हमारी स्रोर के बहुत से सदस्य इस प्रस्ताव की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। में जो प्रस्ताव ग्रापके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि विशेषाधिकार समिति की रियोर्ट जो सदन के सामने विचाराधीन है उससे यह प्रकट होता है कि श्री नाराप्रवत तिवारो किसी किमिनल चार्ज पर गिरफ्तार नहीं हुए । कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया और न अपनी रिपोर्ट ही दो कि तिवारी जी की इस प्रकार की गिरफ्तारी से विशेषाविकार की अबहेलना या सदन का अपमान है या नहीं। यह प्रश्न अत्यन्त स्रावन्यक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह रिपोर्ट पुनः विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन वापस भेजी जाय भ्रीर वह अन्ती रिपोर्ट सरन के सम्मुख १५ दिन के अन्दर-अन्दर उपस्थित करे। श्राच्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने ग्रापने विचार इस सदन के सन्मुख रखे कुछ बातें तो ऐसी है कि जिनसे यह बात मानी जाती है, and we must take it for granted, इसको तो यह मान लेना चाहिये कि गिरफ्तारी हुयी यह बात तो ठीक है कि इसके ऊपर बहस करना बेकार है। एक बात तो मान कर चले कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी हुयी। ग्रब यह हो सकता है कि उस गिरफ्तारी का नतीजा क्या हुग्रा, उनको छोड़ दिया या उनको चार्य पिलाई या उनको श्राराम सं कहीं रखा, मगर गिरफ्तारी जरूर हुयी। श्रब वह गिरफ्तारी किस नियत से की गयी श्राने चल कर इनपर कोई हमला न करें या वह गिरफ्तार इस ब जह से हुये कि आगे चल कर कुछ कास्तकार उनके ऊपर कोई हिययार न चला दें या उनको किसी प्रकार से बचाने का सवाल था, इस बात को इस समय हमें नहीं देखना है। हमें यह विचार करना है कि जिस शख्स ने यह गिरफ्तारी की या जिसकी हम सजा देने जा रहे हैं अगर यह साबित भी हो जाता है तो हमारी सजा क्या होगी। क्रिमिनल ला में इंटेंशन देखा जाता है किसी ऋाइम के करने के लिये। अगर यह बात साबित हुई होती कि हां, काइम किया तो फिर इंटेंजन देखा जायगा इस बात के लिये कि हमें उसकी सजा क्या देनी हैं। तो ब्राज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ब्राया यह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी यानी जो गिरफ्तार करने वाले सज्जन ये उन्होंने इस हाउस का कंटेम्प्ट किया या नहीं किया। श्रव जैसा कि हमारी समिति का मत श्राया श्रीर में जमझता हूं कि हमें यह मान हो लेना चाहिये क्योंकि हमे दोनों बातें अपने ध्यान में रखनी हैं, यानी एक तरफ तो हमें इस सदन के सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखना है और दूसरी तरक जो समिति हमने विशेषाधिकार के लिये बनायी उसके भी ग्रधिकारों का ध्यान हमें रखना है। तो विशेषा-धिकार समिति ने दो बातों को माना है, एक बात तो यह कि अरेस्ट हुआ और दूसरी बात उसने

बर् मार्न हं कि यह ऐसा अनेस्ट था तो प्रिवेटिन वहा जा मकता है और इस वजह से उसने यह माना है। इसने माननीय प्रध्यक्ष महोदय को इसना देना कोई नहीं या। म इन होतो याों का ऐसा राजना हं जिन पर तमे बहुन करने को आवश्यकता नहीं है। मगर का इसका नाम्ये यह हुआ कि जिन्होंने मारावज्य का को विरुप्तार किया वे अपने हमें में बना में, बावजूद इसके कि उन्होंने इसका नहीं दो कोई जुर्म बनता है या नहीं और आजा इसको इस हाउस को से एउर करना चाहिये या नहीं। म समझना हूं और जेसा कि साननीय द्वारा प्रसाद को से आपके सामने दिस्तारपूर्वक बनलाया, इसके बावजूद कि उन्होंने इसन नहीं दी तब भी वे इस हाउस के अदेश्यक के मुजरिस हो जाने है। इसका, देना और न देना नो अध्यक्ष के दिने है गेरिन जो गोटेस्स की बाव ह सहार ने हमारों के लिये लागू होतो है।

श्री अध्यक्ष—ग्राप कृषा करके इसकी मेरिट के अपर कि ऐसा चार्ज लगाया गया मानहीं लगाया गया इसका जिन्न नहीं कर साने हैं। ग्राप यह छह मकते ह कि कमेटी के सामने दुन: विचार के लिये मेज जाय। इसके बारे में आपको जो कुछ कहना हो वह कहें।

श्री बलवन्त मिह्—ग्रथ्यक्ष महोदय. पं इपी सम्बन्ध मे अपने प्वाइंट को लिलार-पूर्वक कहने के लिये ही यह बात कह रही था। खर मेरा मतलब यह है कि जो प्वाइंट इममें है वह यह है कि ग्रार हम यह भी मान लेने है कि उन्होंने हमारे विशेषाधिकार की अबहेलना इस प्रकार ने नहीं की नी भी भी समझना है कि उन्होंने हाउस का कंटेस्ट अवस्य किया और हाउन के कन्टेस्ट का प्वाइंट, जेसा कि ग्रमी माननीय द्वारकाप्रमाद जी ने सदन के सम्बु र खा, विशेषाधिकार समिति के सामने आया अवस्य, मगर उसके पास पूर्ण डाट न होने की वजह से और जो हमारे ऐडवोकेट जनरल श्री कन्हैया लाल साहब की राय न होने की वजह से वह उसके उत्तर पूर्णनया अपनी राय कावम नहीं कर सकी। इसलिए में समझता हूं कि उनके सामने इसको फिर से मेजा जाय जिलते वह ग्रमी पूरी राय दे सके और यह प्वाइंट सक्ष्म के सामने और हमारे सामने आ जाना चाहिये कि आया इस दिवेटिंटव अरेस्ट से इस सदन का कंटेस्ट हुआ या नहीं। इसिलये मेरा प्रस्ताव है कि कमेटी के सामने यह दुवारा जाना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—प्रध्यक्ष महोदन, इस घटना से दो मध्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते है। एक तो यह कि गिरफ्तारी स्वतः हमारे सदन के किनी विदोधाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा यह कि गिरफ्तारी की सूचना सदन को न देना सदन के विदोधाधिकार की अवहेलना है या नहीं। सिमित ने केवल एक प्रश्न पर बिचार किया है और वह यह कि इस गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को न देना सदन के विदोधाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा प्रश्न जो स्वतः गिरफ्तारी का है वह इससे अधिक महत्व का है और सदन के सामने और सिमित के सामने इस प्रश्न को आना चाहिये था। लेकिन उनका मौन रहने का मतलब यह है कि इत गम्भोर प्रश्न की उपेक्षा कर दो गयी है।

जो माननीय बलवन्त सिंह जो ने प्रस्ताव सदन के सपक्ष रखा है में उसका समर्थन करता हूं। जान बूझकर या ग्रनजान में जेसा कि माननीय नुख्य मंत्री जो ने कहा कि समिति के सामने केवल एक ही प्रदन गया था ग्रीर वह यह कि विशेषाधिकार की श्रवहेलना, सूचना श्रध्यक्ष को न देने से हुयी या नहीं। इसिलिए सिमिति को माननीय मुख्य मंत्री जी की राय में ग्रधिकार प्राप्त नहीं था कि वह विचार करे या नहीं। मेरी समझ में.....

श्री अध्यक्ष-मं ग्रव इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समिति को पूर्ण ग्रविकार है कि वह प्रिविलेज के ग्रौर भी प्रश्न निकाल सकती है। इसके सम्बन्ध में केवल प्राइमाफेमो

[श्री ग्रध्यक्ष] ऐवीडेंस से जो मुझे विदित हुग्रा उस पर निर्णय देकर मैने समिति के पास विचारार्थ भेज दिया था।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी श्रवस्था में समिति ने श्रपने कर्त्वय का पालन नहीं किया है। इसिलये इसको समिति को दुबारा भेजा जाय, में श्रीर जोर से समर्थन करना चाहना हूं श्रीर यह श्रीर भो श्रावश्यक हो जाता है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों की, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है, यह राय है कि यह लघु प्रश्न हो जाता है कि इस सदन को सूचना दी या नहीं दी। लेकिन गिरफ्तारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रवस्था में यह प्रश्न श्रीर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कभी भी दो राय नहीं हो सकती है जबिक सदन ने इसको मान लिया है कि गिरफ्तारी किसी ऋिमनल चार्ज पर नहीं हुयी है श्रीर जब किसी ऋिमनल चार्ज पर गिरफ्तारी नहीं हुयी तो निस्संदेह यह इल्लीगल है.....

श्री अध्यक्ष---श्राप इसके ऊपर राय न दें क्योंकि समिति ने कोई निर्णय नहीं दिया श्रीर यह तो समिति का प्रतिवेदन है जो विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी स्थित में श्रगर यह किमिनल चार्ज पर गिरस्तारी नहीं हुयी है तो यह ऐसी गिरफ्तारी हैं जिससे माननीय सदन के विशेषाधिकार की श्रवहेलना हुयी है। इसलिये में थोड़े से शब्दों में ही क्योंकि बहुत से मेरे साथियों ने उद्धरण किये हैं. कहना चाहता हूं श्रीर मुझे श्रधिक कुछ कहने की इस सम्बन्ध में श्रावश्यकता नहीं है। में समझता हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है। इसलिए यि इस पर समिति विचार न करे श्रीर माननीय सदन भी विचार न करे तो ऐसी नजीर बन जायगा जिससे कहा जा सकता है कि सदन ऐमे प्रश्न पर भी मौन रहा जो श्रधिक महत्व का प्रश्न था। इसलिये यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिये सदन का कर्तव्य हो जाता है कि व्यक्तिगत भावनाश्रों से ऊंचा उठकर सदन के सम्मान की रक्षा के लिये विचार करें श्रीर इस प्रस्ताव को स्वीकार करे श्रीर इसको पुनः समिति को भेजा जाय।

माल मंत्री (श्री चरणिंसह)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अभी कुछ तकरीरें माननीय सदस्यों की सुनी हैं, उससे मुझे आर्शाका यह है कि कुछ गलतफहमी हो रही है और इस गलतफहमी की वजह से यह प्रस्ताव माननीय बलवन्त सिंह जी ने पेश किया है कि जो असल मामला था उस पर कमेटी ने विचार नहीं किया और इसी वजह से उनके प्रस्ताव का समर्थन कई दोस्तों ने किया। देखना हमको यह है कि बीच आफ प्रिविले जे हुआ या नहीं। फिर बीच आफ प्रिविलेज तय करने से पहले यह तय करना है कि प्रिविलेज हमारे क्या-क्या हैं। क्या इस हाउस का यह प्रिविलेज है कि कोई मेम्बर गिरफ्तार हो, पुलिस गिरफ्तार करे, या मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करें तो गिरफ्तारी लीगल है या इल्लीगल है इसकी मेरिट्स में जाना क्या यह हाउस का प्रिविलेज है? में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस का यह प्रिविलेज हरिगज नहीं कि वह इसकी मैरिट्स में जाय कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। और जे भी डिसेंटिंग मिनिट में केसेज कोट किये गये हैं वह सिक्सर्टोन्थ और सेवेन्टीन्थ सेंचुएरी के कोट किये गये हैं। उसके बाद बराबर वहां के ला और प्रैक्ट्स में बताया गया है कि वह प्रिविलेज अब मंसूख हो चुके हैं और केवल एक ही प्रिविलेज रह जाता है कि वह मैजिस्ट्रेट से किसी सबस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सुचना प्राप्त करे।

कुछ सदस्य—नहीं नहीं। श्री अध्यक्ष—शांति से सुनिये।

श्री चरणिंसह—ग्रध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि में इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य से किसी बात में ग्रपने को कम नहीं मानता कि ग्रगर कोई

महन का विविद्ये हु नो उसकी घटाया जाय खोर जो वोस्न यह कहने हु कि नहीं, यह विविद्ये भी इस हाउस की हास्ति हु कि यह उस दान की सेन्ट्रिंस में जाय कि सेजिस्ट्रेट ने ठीक सजा ही या नहीं दी. कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ने ठीक सजा दी या नहीं दी. कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ने ठीक रिज्या के कि सेज पास्थि। में जिस्से विविद्ये से कोर्ड विविद्ये के कि पास है कि सेज पास्थि। में यह दावा किया है कि डिसेटिंग मिनिट में मानके पेज पर जो के नेज विवे गये है कि. "निरम्तारियों में इस बान की भी में में मानकीय सदस्य की राम हालूनी ढंग में गिरम्तार कर ने या दीवानी के मामने में फोजदारी का रंग देकर गिरम्तार करे. अनिविद्ये के विवेदान में रक्षे या परेवान करे। ऐसी दशा में यदि मानकीय अध्यक्ष हारा मदन की सूचना मिनतीं है तो मदन गिरण्यारी या विवेदित अरेग्ट सम्बन्धी खादेश की वैचना पर विचार कर समाराई बीर यह सदन इस नतीं पर पहुंचना है कि मानकीय मदस्य की गिरम्तारी अनिविद्ये हैं की मानकीय मदस्य की गिरम्तारी अनिविद्यान है तो वह नानकीय सदस्य की घुड़ा कर उनसे सदन की सेवा से सकता है।"

ग्रांर ग्रागे चनकर. "इस मन्दन्ध में हम यहां केदन ब्रिटेन के हाउस ग्राफ कामंस के श्री फरेर के मामने की चर्चा करेगे। में की पुम्तक के ७१ पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में लिखा हुग्रा है कि श्री फरेर को हाउम ग्राफ कामन्त ने ग्राने मुक्ति के श्रादेश में छुड़ाया तथा शेरिफ्स द्वारा इस कार्य में बाधा डाले जाने के कारण होरिफ्स को महन की मानहानि के लिये सजा दी। में की पुम्तक के पृष्ठ ७१ ग्रांर ७२ पर सर्वश्री डिग्म. ऐसिंगल मिल्स, वर्टन तथा शर्ने के मामलों में पता चलेगा कि मूचना पाने पर मदन ने माननीय सदम्यों को बन्दीगृह से खुड़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की।"

श्रापकी इजाजत से मं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह डिसेंटिंग नोट पढ़ा, जिन्होंने यहां तकरीर की है, वह सब इस डिमेंटिंग मिनिट में जो ये बातें लिखी हुयी हूं उससे प्रेरित है श्रीर मृतास्मिर हे। लेकिन मे की पालियामेंटरी प्रैक्टिस पर जो वह केमेज दिये गये हूं फेरमें श्रीर डिग्स के यह हिम्टारिकन रेट्यू किया गया है, इसलिए कि हाउस आफ कामंस श्रीर हाउस आफ लाई स में झगड़ा रहा, पालियामेंट श्रीर किंग में बहुत दिनों तक झगड़ा रहा। गुरू में यह ठीक है कि मेम्बर अगर गिरफ्तार होता था तो स्पीकर की तरफ में रिट जाता था शेरिफ के नाम श्रीर शेरिफ को हाउन में बुलाया जाता था श्रीर हाउस यह तय करता था कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। यह बिलकुल स्पष्ट है श्रीर में मानता हूं। लेकिन इसके बाद वह सब चीज खत्म हो गयी श्रीर में अपने माननीय दोस्तों का ध्यान पेज ७६, ७६ श्रीर ६० की नरक दिल ऊंगा ग्रीर में श्रापकी इजाजत से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह हाउस इस र.इट को ऐश्रोगेट कर लेता है कि वह यह तय करें कि किसी भी मामले में जो मेम्बर गिरफ्तार हो वह श्ररेस्ट जायज है या नाजायज है, तो वह कोर्ट स के राइट्स को ऐश्रोगेट करता है। हमारे प्रिविनेजेज उतने ही है जो हाउस आफ कामंस के है श्रीर उसके लिए एक मुस्तिद किताब है "में की पालियामेंटरी प्रैक्ट्स" उसमें हिस्टारिकल रेट्यू करके दिखलाया गया है कि बेगक पहले ऐमा था, लेकिन श्रव नहीं है।

एक सदस्य-हरिगज नहीं।

श्री चरण सिंह-ग्रागे चलकर उन्होंने लिखा है पेज ७६ पर-

"Soon afterwards it was enacted; by 2 and 3 Anne, c. 12, that no action suit, process, proceeding, Judgement, or execution against privileged persons, employed in the revenue, or any office of public trust, for any forfeiture, penalty, etc., should be stayed or delayed by or under colour or pretence of privilege of Parliament."

[श्री चरण सिंह]

पहले तो उन्होंने कहा कि केस इसकी वजह से नहीं रुकेगा ब्रागे चलकर वह कहते ह-

"Still more important limitations of the privilege were effected by the Parliamentary Privilege Act, 1770, whereby any person may at any time commence and prosecute an action or suit in any court of law against peers or members of Parliament and their servants; and no such action or process shall be interfered with under any privilege of Parliament."

पहले हर सूट स्रीर हर ला को त्रोसोडिंग को हाउस स्राफ कामंस रोक दिया करताथा। इसके बाद नये ऐक्ट बने कि ऐसा हो नहीं संकता। में पेज ७८ को तरफ माननीय दोस्तों का ध्यान दिलाऊंगा:---

"The privilege of freedom from arrest is limited to civil causes. and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation."

यानी जो दीवानी के मामले हों उनमें जब संशन शुरू हो उससे ४० दिन पहले ग्रीर जब बत्म हो तो उसके ४० दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर रुफते। लेकिन किमिनल केसेज में नहीं। उसके ग्रागे हैं:--

"In early times the distinction between "civil" and "criminal" was not clearly expressed. It was only to cases of "treason, felony and breach (or surety) of the peace" that privilege was explicitly held not to apply (see page 68). Originally the classification may have been regarded as sufficiently comprehensive. But in the case of misdemeanours in the growing list of statutory offences, and particularly, in the case of preventive detention under emergency legislation in times of crisis, there was a debatable region about which neither House had until recently expressed a definite view."

में बाद में इसका तज्मा करके सुना दूंगा।

"A review of the development of the privilege reveals a tendency to corfine it more narrowly to cases of a civil character and to exclude not only every kind of criminal case, but also cases which, while not strictly criminal partake more of a criminal than of a civil character. This development is in conformity......"

श्री मदनमोहन उपाध्याय—प्वाइंट श्राफ ग्राइंर । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय च ण सिंह जी कह रहे हैं क्या यह चोज उन केसेज पर भो लागू हो राकती है जो कि कोर्ट में हैं ही नहीं । यह तो उनकी बातें कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--यह तो प्वाइंट ग्राफ ग्राइंर नहीं है। ग्राप तो इन्फामेंशन पूछ रहे है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जी हां । यह इन्फार्मेशन चाहता था ।

श्री अध्यक्ष-तो यह इस तरह से श्रापको नहीं करना चाहिये। प्वाइंट श्राफ ब्राइंर कहकर इन्फार्मेशन मांगना उचित नहीं है।

शो चरणसिंह—"This development is in conformity with the principle laid down by the Commons in a conference with the Lords in 1641: Privilege of Parliament is granted in regard of the service of the Commonwealth and is not to be used to the danger of the Commonwealth."

अं नाग्यण दन निवारी की गिरफ्तारी के संबद्घ विशेषाधिकार की स्रवहेलना के विश्य में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

इसका मनलब यह है कि झरेम्ट में जो फोडम है, गिरफ्नारी में जो मुम्तमना होने का राइट है. झबिकार है. वह केवन दोवानों के मामनों तक मीमित है, किसिनन कमेज में नहीं है। में बड़ो खुओं ने इन्तजार कहंगा कि कोई नाहब मुझे कोई ऐसी नजोर दिखना दे इबर की झौर में यह भो वनना दूं कि जो आपने नजोरें पेश की. वह पहले की हं. उसके बाद ये ऐक्ट्म बने हं।

श्री हरिक्चन्द्र बाजपेयी (जिना लखनऊ)--यह तो ग्रापके खिलाफ जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-माननीय मदस्य इस तरह से ग्रापम में बहस न करें।

श्री चरण सिह—तो उन्होंने छहा है कि सिविल ग्रीर किमिनल में जो ग्रन्तर है पहले वहीं नहीं साफ था। किमिनल केवल उनको माना जाता था—दीजन केलानी ग्रीर ग्रीच ग्राफ दियीम। बाद में टेंडेसी यह हो गरी कि सिविल कैरेक्टर के जो मामले हैं केवल उन्हीं तक यह ग्रिकार सोमित रहेगा। उसने गिरफ्तारी नहीं होगी ग्रीर किमिनल या दवासी किमिनत केसेज को गिरफ्तारी से प्रिविलेज का कोई ताल्लुक नहीं है। पर ग्रागे चल कर पृष्ठ १२० पर कहते हैं—

"The privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges"

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से में कहूंगा ि मेने बलवन्तिसह जी को इस बारे में रोक दिया था कि इसको विशेषता पर विचार न हो। मेने उनको इसलिये इजाजत दो कि चूंकि समिति ने एक बात पर विचार नहीं किया और इस कारण वे प्रश्न को समिति के पास विचारार्थ वापस भेज सकते हे।

श्री चरण सिंह—मं बहुत श्रदब से श्रर्ज करना चाहता था कि इस पर विचार हो ही नहीं सकता। इस पर विचार फरने की जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष-तो श्राप यह कहते क्यों नहीं ?

श्री चरण सिंह—मं यही दिखला रहा हूं कि गिरफ्तारी सही हुयी है या नहीं हुयी है, गिरफ्तारी जायज हुयी है या नाजायज हुयी है यह तो हाउस देख ही नहीं सकता। इस पर वह विचार कर ही नहीं सकता। पृष्ठ १२० पर यह लिखा है।

श्री अध्यक्ष-इतको मैरिट्स पर नहीं जाना है। श्राप सीघे यह कह दें कि इसके ऊपर करेटो नहीं विचार कर सकती थी इसलिये समिति ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

श्री चरण सिंह—चंकि त्रिविलेज के बारे में कहा गया गिरफ्तारी नाजायज हुयी तो उसके तय करने के लिये कि गिरफ्तारी जायज हुयी या नाजायज हुयी श्रीर नाजायज हुयी तो बोच हुयो, में श्रर्ज करना चाहता हू:

"The privilege of freedomfrom arrest does not extend to criminal charges and upon the same principle the mer nment of a Member under regulations made to prevent a breach of the pe ce has been held not to constitute a breach of privilege.

Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information of the imprisonment or detention of any Member with the reason for which he is detained."

में आपको इजाजत से यह खर्ज करना चाहता था केवल एक ही प्रिविलेख है हाउस की, किमिनल केस या धरेस्ट के सिलिसले में । वह यह कि उसकी यह इलला दी जाप कि गिरफ्तारो हुनी और असका क्या कारण हैं। श्री अध्यक्ष—श्राप उसकी मेरिट्स में फिर जा रहे हैं। सिमिति की रिपोर्ट में बिया है कि ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया डेफिनिटलों कि प्रिवेटिव श्ररेस्ट में ब्रोच श्राफ प्रिविलेख हुआ या नहीं। उन्होंने तुरन्त राय देने में श्रसमर्थता प्रकट की। इसी पर मेम्बर्स ने श्रपना यह मत रखा है कि पुनिवचार के लिये प्रश्न वापस भेजा जाय। में प्रश्न की मेरिट्स के अपर विवाद की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इससे बहस बढ़ जायगी। श्रभो सिर्फ सवाल यह है कि क्या सूचना न देने ने बीच श्राफ प्रिविलेज हुश्रा या नहीं। इसके अपर श्राप बहस कर सफते हैं। लेकिन श्रगर सदन यह समझता है कि कमेटी ने पूरा विचार नहीं किया तो उसके लिए उनका प्रश्न को वापस भेजने का संशोधन है। श्रगर श्राप यह कहते हैं कि विवाद श्रस्त उठाये हुए प्रश्न पर सिमित ने विचार कर लिया था और वह इस फैसले पर श्रा गयी थो कि वह प्रश्न विचार में नहीं लिया जाशकता तो श्राप इतना ही कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न की मेरिट्स के अपर डिस्कशन करना—इससे तो वह बहुत लम्बा हो जायगा। में उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चरणिसह—सं मंिरट्स पर खुद हो बिलकुल जाना नहीं चाहता। मैं ग्रर्ज करता हूं कि जो माननीय बलवन्त सिंह का संशोधन है कि इस मसले पर फिर विचार करने के लिए वापस जाय मेरो गुजारिश यह है कि इस पर कमेटो निवार कर हो नहीं सकती। जो ग्रापने मेरा ध्यान ग्राक्षित किया है वह मेरे नीट्स में मौजूद है। जो ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया ग्रौर उन्होंने जो जवाब दिया उसो से भ्रम पैदा होता है इस सिलसिले में कि यह प्रिबेटिव ग्ररेस्ट है या किमिनल चार्ज पर है। यह बिलकुल गैर मुताल्लिक है। प्रिवेटिव ग्ररेस्ट है ग्रौर इत्तिला नहीं दो जाती फिर भी बीच ग्राफ प्रिविलेज है यह में मानता हूं। यह जो इस रिपोर्ट के पुष्ठ ४० पर जिक किया गया—

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, because this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i.e., not on a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want sometime."

में इसके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल नहीं था कि प्रिवेटिव अरेस्ट की इत्तला देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिए। फमेटी इस बात की मानती है कि प्रिवेंटिव श्ररेस्ट करके जेल में रक्खा जाय या किसी श्रादमी को प्रिजन में भेजा जाय तो बीच श्राफ प्रिविलेजेज है लेकिन श्रगर प्रिवेंटिव श्ररेस्ट करके एरोप्लेन में ले जाकर कहीं दूर छोड़ दे तो इत्तिला देने को कोई भ्रावश्यकता नहीं है। प्रिवेटिव अरेस्ट बोच है या नहीं यह क्वेश्चनही नहीं है। तीन क्वेश्चंस कमेटी ने रक्षे थे उन्हीं से मालुम हो जाता है। पहला था-क्या श्रीनारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्ह्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थो ? दूसरा था-क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी श्रपराध के सम्बन्ध में थी ? यह दूसरा सवाल था लेकिन यह रिलेवेंट नहीं था। तीसरा सवाल यह है कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह किसी प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री ग्रध्यक्ष को देना ग्रावश्यक या ग्रीर क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयो तो यह तीसरा सवाल रिलेवेंट या । चाहे प्रिवेटिव अरेस्ट हो या चाहे चार्ज के ऊपर अरेस्ट हो हमने ते किया है चूंकि प्रिजन में नहीं भेजा गया लिहाजा बीच आफ प्रिविलेजेज नहीं हुआ। में माननीय संदस्यों से जानना चाहूंगा कि क्या वे कोई नजीर दे सकते हैं हाउस ग्राफ कामन्स की या ग्रीर कहीं की एक श्रादमी गिरफ्तार किया गया हो ग्रीर गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया हो ग्रीर बगैर प्रिजन में भेजे इस्तिला देना जरूरी समझा गया हो । पेज ७८ में भ्राप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ---

"The commital of a member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the

communiting Judge or mugistrate. On these occasions, the first communities on to the Speaker is made when the Member is committed to prison, and being allowed."

निरुक्तर होने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय श्रीर इसमें चाहे कितना ही समय कर जाय नेष्ठिन मैजिस्ट्रेट उसे बेल पर छोड़ दे तो त्रीच श्राफ प्रिविलेजेज नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—मं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री मे कि प्रिवेटिव प्ररेस्ट बंच ग्राफ प्रिविलेज है या नहीं।

श्री चरण सिंह—श्रीच श्राफ प्रिविलेजेज नहीं है। जब वह प्रिजन को कमिट किया जाय ने। वहीं बीच श्राफ प्रिविलेजेज है। श्रदालत में जाय श्रीर छोड़ दिया जाय, उसमें कई घंटे नग जायं, नो वह बीच श्राफ प्रिविलेज नहीं होता।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गड़वाल) — माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समिति की रियोर्ट सदन मे प्रम्तुन है उस विषय पर माननीय सदस्यों के लम्बे चौड़े भाषण हुए। मं भी इस रिपोर्ट को क्रिटिकनी देखता हूं और मुझे दुख है कि मेरे दिमाग में स्पष्ट यह बात मानी है कि जो रिकर्मेंडेशन है वह मुझे कतई गलत नजर माती है। वह इसलिये नहीं कि में हर बात की अपोज करता हूं या मेरे दिमाग का ट्रेंड अपोजीशन करने का है बल्कि इसलिए को रिपोर्ट में जिस तरह से फैक्ट्स दिखाये गये है उनसे इनफ्रेन्स निकलता है कि हाउस का बीच ग्राफ प्रिविलेजेज इस मामले में हुग्रा। में बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। ६ करोड़ जनता की रक्षा का भार इस सदन के ऊपर है और अगर यह सदन अपने राइट्स की ही डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझे इसमें शक है कि यह सदन ६ करोड़ जनता की रक्षा का उत्तरदायित्व निभा सके। मान लोजिये की नारायणदत्त जी ने आफेन्स किया हो। यह ठीक है, हम मानते हैं कि नारायणदत्त जी ने श्राफेन्स कमिट किया श्रीर हम यह भी मानते हैं कि उनकी ग्ररेस्ट हुयो जिसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं है। हम यह कहना चाहते है कि ग्रगर ग्रफेंन कमिट हुमा श्रीर उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया तो क्या उस हालत में यह मैजिस्ट्रेट को डिय्टो नहीं थी कि वह इस माननीय सदन को सूचना दे कि यह प्रिवेटिव घरेस्ट थी। में घ्रापको यह बताना चाहता हूं कि हमको इसके लिये बेसिक प्रिसिपल की देखना होगा । प्रगर बेसिक प्रिंसिपल को सही तरीके से देखा गया होता तो जितनी कंट्रोवर्सी इस सदन में दिखायी दे रही है वह कंट्रोवर्सी भ्राज यहां पर उपस्थित नहीं हुयी होती । यह सदन ६ करोड़ की जनता के जिस्टस की गारन्टी करता है और जनता की जिस्ट्स देने वाला है भीर माथ हो जो कानून जनता के लिये बनाये जाते है उनको जिन्दगी देनैवाला भी यह हमारा सदन है। इसलिए में यह बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के मेम्बरों के जो प्रिविलेज है वह वही माने जाते हैं जो कि ब्रार्डिनरी ला से ऊपर होते हैं। उस प्रिविलेज की इस सदन को रक्षा करनी है और इस सदन का काम है कि प्रिविलेज की रक्षा की जाय क्योंकि उससे लार्जर इन्टरेस्ट सर्व करना होता है और सबके फायदे के लिये वह चीज होती है। वह लार्जर

म काइ बड़ा महत्व का अरा उपारमा हु यह किया जाय और उसकी उपस्थिति यहां सदन में बहुत जरूरी क्योंकि मुमिकन है कि सदन में बड़े बड़े डिसोजन होते हों और उसकी वजह से ६ करोड़ की जनता के जीवन पर असर पड़ता हो और मान लाजिये कि वह डिसोजन जनता के खिलाफ जाता हो तो उन माननीय सदस्य को जो अरेस्ट किया गया है वह अरेस्ट जनता के इन्टरेस्ट के खिलाफ हुवी या नहीं हुयी ? में यह बताना चाहता हूं कि वह सारे राइट जनता के है जो कि इस सदन के राइट हैं। इमलिये में यह बताना च हना हूं कि यह सदन मुप्रीम हो जाता है और एक सुत्रोम बाडी चाहता है। हमको उनको अरेस्ट को कामन ला के बजाय उनकी अरेस्ट को कुछ बूसरे नुक्ते नजर से देखना होगा। इसलिए जो यह प्रिविलेश

[श्रो चन्द्र सिंह रावत]

का सवाल है उसको हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि वह किस नेचर का है। जहां कर मैजिस्ट्रेट के ब्रार्डर का सवाल है जिससे यह प्रिविलेज का सवाल उत्पन्न होता है उसमें वह देखना ह, वह प्रिवेटिव है या प्युनिटिव है वह तो अपने बस को बात नहीं है और चेन्न्र मिनिस्टर के बा को भा बात नहीं है कि वह ऐसा होना चाहिये या है। वह तो मेजिस्ट्रेट का ब्रार्डर हो बतायेगा और यह जो मेजिस्ट्रेट का ब्रार्डर है वह चिल्ला चिल्ला कर वतला रह है कि वह क्या आर्डर है और धिस प्रकार का है। हमको देखना यह है कि मेजिस्ट्रेट का के ब्रार्डर है उसको स्थिट क्या है और किस ब्राइन क्यार्डर है उसको स्थिट क्या है ब्रोर किस ब्राइन को हमारे सामने रखता है। में सदन के सामने उस मैजिस्ट्रेट के आर्डर को पढ़ना चाहन है ताकि हम सही फैसले पर पहुंच सकें।

"Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144, criminal Procedure Code by obstructing sugarcane carts, trucks and wagons from entering into Lalitpur Sugar Factory, Kashipur. I, hereby, order the S. O. Kashipur, to remove him under escort to Haldwani and release him there." इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय नारायणवत्त तिवारो आफेन्स कमिट कर रहेथे। यह आर्डर स्पष्ट है कि गह नहीं कि वह कमिट करने जा रहेथे बिक्क कमिट कर रहेथे। यह आर्डर स्पष्ट है कि गारायण दत्त जी ने १४४ सेक्शन को डिफाई किया इसके कारण वह अरस्ट किये गये। वह इसलिए किया गया कि प्यनिटिव आर्डर था जसको जन्में किये

जहां तक भविष्य में ला को ब्रोच करने का स्वाल है तो भविष्य में ब्रोच न करने के लिए उनको वहां से हटा दिया जिसको हम इसके साथ साथ प्रिवेटिव श्ररेस्ट भी कह करने हैं। ता उनका श्ररेस्ट प्रिवेटिव श्रीर प्यूनिटिव दोनों था।

त्या प्राचित्र प्राचित्र का जिल्ला है। जात ह अगर माजस्ट्रट किसा को लिबटों को खत्म करने के लिये आईर करता है कि वह टेम्पिल के बाहर नहीं जा सकता। अगर बाजार के चौराहे पर किसी को टेरोराइज कर दिया जाय कि अगर वह वहां से हटेगा तो गोलों से उड़ा दिया जायगा चाहे पुलिसमेन भो दूर भाग जाय, तो वह भो त्रिजन हीगा। इसिलये माननीय नारायण दत्त जो को जेल की कस्टडों में रखकर मैजिस्ट्रेट के ऊपर इनकम्बेंट था कि हाउस को इतिला देता। मैजिस्ट्रेट का कांडक्ट कनेटों के सामने अब बोर्ड नहीं रहा है। उन्होंने कमेटों के सामने आनेस्टलों और स्ट्रेटफारबर्ड बयान नहीं दिया है। वह जानते थे कि वह पोलिटिक्स के स्ट्रेंट रहेथे तो उनके ऊपर और भो अधिक जिम्मेदारों हो जातों है। इसिलये में चाहता हूं कि उन्हें यहां बुलवाकर रिप्रिमेंड किया जाय।

*श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी की तकरीर के बाद उनके इतिमान दिलान के बाद कि इस वक्त जी कुछ भी हुआ, प्राइन्ता के लिये वह बहै सियत हमारे मुख्य मंत्री के ऐसी हिदायत जारो कर देंगे कि आयन्दा ऐसी गलती न हो, में समझता हूं कि ज्यादा डिसकदान का मौका न था। लेकिन एक चीज उनकी तकरीर से भी मालूम हुई कि उनके ख्याल में भी ऐसी हिदायत जारो करना जरूरी है। उनका यह इतमोनान बहै सियत मुख्य मंत्री के है। यह स्वाल अभी बाकी है कि अगर फिर भी कोई अफसरान गलती करें तो क्या वह उनके खिलाफ ऐक्दान बहै सियत मुख्य मंत्री के लेंगे या बीच आफ प्रिविलेज के लेंगे। मुख्य मंत्री जो का यह खयाल कि वह हिदायत जारो करेंगे, इस बात की दलील हो सकती है कि यह प्रिविलेज हा इस का जरूर था। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य मंत्री जो हाउस को इज्जत रखने के लिये सही मानों में तर्जुमानी कर रहे है।

^{*}बन्ता ने भावण का पुनर्शक्षण नहीं किया।

इसारे एउवाकेट जनरल ने जहां कि जिस किस्स का अरेस्ट यहां हुआ ह वह बीच आफ बिविकेट ह या नहीं. इसाम जवाब देने के लिये वह कुछ वक्त चाहेगे, तो सेटा राय है कि इस वक्त इस सवाल की मुन्तवी कर दिया जाय और एउवोकेट जनरल से उनकी श्रोप नियन कर लो जाय ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--ग्रध्यक्ष महोदय. जो निपोर्ट हमारे सामने श्रामी ह जान जिनके बारे में यहा पहले मुक्त्य हुआ वह इसा एक बान से सम्बन्ध रखनी है कि स्वना नहीं दा गया। इसने विजेवाधिकार की श्रवहेलना था या नहीं। इसके अनिरिक्त कियो श्रीर बात पर विजेवाधिकार कियित वे विचार नहीं किया। जहां तक स्वता पान क्वां हो मा अपने विचार प्रकट कर चुका और इस बारे में कुछ कहना अन्वक्ष है। जहां तक गिरफ्तार का निल्तु है, वह भी प्रवेदिव हे या नहीं इसमें भी विजेवाधिकार का पान के बारे में इस सदन में मा देखता हूं काफा कहा ना कियोवाधिकार का मिति हो की विचार करना चाहिये। आया यह कीई विजेवाधिकार का प्रका जा स्थान है या नहीं, इस पर भी वहीं विचार हो सकता है। हमे यह देखना है कि यह विजेवाधिकार का प्रका हो स्थान है या नहीं, इस पर भी वहीं विचार हो सकता हो। इसके बारे में यहां भिन्न मत मालूम होते है। यह तो अदालन का काम है कि वह यह देखे कि कोई मुकदमा झूठा हुआ है या सच्चा। यहां पर हाउस का खान ऐसा मालूम पड़ना है कि जिस तरी के पर हम इस मामले में गिरफ्तार। हुई ह चह ऐसे है जो विजेवाधिकार की परिध के भीतर आती है। लेकिन इसके बारे में दूमरा तरफ में ऐसा पहा जाता है कि यह अदालत की बात है और यह विशेषाधिकार की परिध के मालूस हो स्वा कर की परिध के स्वा कर की स्वा कर की परिध के स्वा कर की स्वा किया की परिध के स्व की स्वा की स्व की स्व

हम यहां बहत । गलन बात है। नजीरों का पेश करना. पिछले इतिहास का बताना इसमें है ता है. इस प्रकार ने यह एक क़ानूनी सवाल हु। यह जजवात का नवाल नहीं है। इसमें नी सवाल यह है कि क़ानून इस बारे मे क्या कहता है। हमे यह देखना है कि भ्राखिर इस बारे में इंगलन्ड में जी प्रिविलेजेज हं वे क्या है। हमको कोई चीज अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन सवाल तो यह है कि हम बंधे हुए है इंगलन्ड के कानून में। जो क़ानून वहां पर लागू होता है यहां पर भी हम वैसा ही करने की कोशिश करते है। इस वाकये को हाउस ग्राफ कामन्स ग्रौर हाउस ग्राफ लार्ड्स किस प्रकार मे इनको देखते हैं उसी प्रकार से हमें इसको देखना है ग्रौर उसको देखकर हमें यह तय करना हं कि कानून के अन्दर यह चोज आती है या नहीं और अगर आती है तो विशेषाधिकार की भ्रवहेलना हुई है या नहीं। हमे भ्रच्छा लगे या बुरा लेकिन यह विशुद्ध कानुनी सवाल हे, किमी भी प्रकार की स्ट्रांग फीलिंग्स की बात नहीं है। में समझता हू कि इस बारे में शंकायें है. इसलिये उसका निर्णय विशेषाधिकार समिनि हो कर सकती है। इसलिये मै समझता हूं कि सारे मदन को इस बारे में एक मत होकर यह निर्णय करना चाहिये कि विशेषाधिकार क्षमिति इस बात को देखें कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति की परिधि के ग्रन्दर है या नहीं ग्रीर ग्रगर ऐसा है तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है या नहीं। इन दोनों बातों के लिये केवल १५ दिन का समय देना गलत बात होगी क्योंकि यह एक वहुत हो उलझा हुन्ना सवाल है श्रीर इसमे ज्यादा समय लग सकता है। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि १५ दिन तक श्रमेम्बली बैठी रहेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष-श्री गेंदा सिंह का मामला जुलाई में झायेगा तभी इस पर भी विचार हो जाय ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—चूंकि इत तरीके पर विशेषाधिकार समिति के सामने हर श्रादमी श्रपनी राय दे सकता है, जो कोई वकील हों उनसे पूछा जा सकता है, श्रगर यहां पर कोई चीज ऐसी है जिससे कि विशेषाधिकार की श्रवहेलना होती है तो यह सारे

[गोविन्दवल्लभ पंत]

सदन से सम्बन्ध रखता है, किसी एक गिरोह या व्यक्ति से इसका सम्बन्य नहीं है। पान्न वह उत्तको परित्रि के अन्दर आता है या नहीं आता है यह कानूनी बात है। लिहाजा में सम्बन्ध हूं कि इस पर ज्यादा बहुस मुबाहिसा की जरूरत नहीं है और इस प्रश्न पर यहां बहुस करके किन्न नतीजे पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसिलए में आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस तर्गके का आप उसको बना कर विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें और फिर इस समय इस पर वहन् स्थिगत कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष-मं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में एक जानकारी चाहना हूं श्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और एक नया ईश्यू खड़ा हो गया कि श्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जा रहा है। तो एक ईश्यू हमारे सामने था कि श्राया नोटि उन्हें देना चाहिये था या नहीं देना चाहिये था स्पीकर की श्ररेस्ट के बारे में श्रीर उस मामने में श्रिविलेज कमेटी ने फैसला दे दिया कि नहीं देना चाहिये था। तो श्रव जब श्रिविलेज कमेटी में दूसरे ईश्यू पर बहुस होगी तो उसमें हम किर इस ईश्यू को उठा सकते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब मं दे देता हूं। जब कमेटी के सामने कोई मामला वाक जाता है तो वह उस विषय पर गौर करके पुनविचार भी कर सकती है। जैसा कि मानतंत्र मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न एक कानूनी बात है और अगर कोई नव मुझाब आता है और उससे मालूम होता है कि कोई गलती हुई है तो उसको दुख्स करने के लिये समिति सब तरह से विचार कर सकती है और प्रिविलेज कमेटी को पूर्ण अधिकार है कि क उस पर नजरसानी करे।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का सुझाव मुझे मंजूर है ग्रीर मं समझता हूं कि यह बहुत ही पेचीदा कानूनी महन्त है इस्तिलये इस वक्त इसको वापस कर दिया जाय ग्रीर बहुत से माननीय सदस्य जो कानूनी तब रखते हैं उनकी तथा ऐडवोकेट जनरल की राय लेकर इस पर निर्णय किया जाय। मं अपन प्रस्ताव वापस लेता हं।

(र्ह्यन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--मं समझता हूं कि इस सदन की सर्वतम्मित से यह राय है कि इसकी वापत भेजा जाय ।

(प्रदन उपस्थित किया ग्रौर स्वीकृत हुन्ना।)

***उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४**

श्री ग्रध्यक्ष--ग्रब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४ पर विचार जारी रहेगा।

खंड १८—(ऋमागत)

िश्वी जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्राप की आज्ञा ने निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

खंड १८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (s) के बाद निम्नितिति नये खंड (t), (u) श्रौर (v) रख दिये जायं:—

(t) for securing and making arrangements of house sites and new lands for house sites and all such lands appurtenant

^{*} २२ श्रद्रैल, १९४४ की कार्यवाही में छपा है। देवक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

the Lifetium exicing poses free Tall phonge on the sureduled cases people as may ne required by then summation the Lindshee Landshee Grown of the Guard Sabra

nesk už su nev u ne il rēge. O voz vim kriu-solutur (tise i Oz piružilyek iciling eure aur

to take all such steps as be necessary to blevent additer-

ब्रध्यक्ष महोदय, ब्राज गाव की जो परिन्थित है उससे प्रत्येक माननीय मदस्य परिचित है। इमारे पुज्य बापू जी कहा करने थे कि भारनवर्ष गावी में रहता है। स्वराज्य हो जाने के बाद मभी जानेते ह कि बापू के हृदयोद्गार पूर्ण हो गए परन्तु स्वराज्य हुए लगभग ६-७ वर्ष हुए लेक्नि गावो में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। गावों में जो ग्राबादों की परिस्थिति, मकानों म्रादि की है वह शहरों के मुकाबले में बहुत खराब है म्रोर आबादी जो बढ गयी ह म्रोर खेती भी गावों को ब्रावादी से नजदीक तक होनी प्रारम्भ हो गयी ह जिसके कारण वहा की बस्ती का एक्स-टेशन ग्रमभव हो गया है। जहां तक वहां की गरीब पब्लिक का प्रश्न ह उन के लिये बहुत मुश्किल है कि वह ब्रपने मकानों को दोमंजिले या निमजिले बना मके या ब्रोर जमीन हासिल कर सके। गांबों में ऐसी परिस्थित ह कि वहा मकान एक ही है ? उसी में पशु बधते ह, उसी में भूमा लकड़ी तमाम मामान रखा जाता है. उसो में रोटी पकाते ह श्रोर जगह का बहुत श्रभाव रहता है। मुझे तो यहां नक देखने की मिला ह कि एक ब्रादमी के पास एक ही कमरा है, उसी में वह दोनों पति पत्नी. उनके लडके, बहु और लड़की भ्रोर दामाद रहते हु अ।र जगह की इतनी कमी है कि उन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिये किसी तरह से पर डाल कर कपड़े की आड़ में जीवन बिताना पड़ रहा है। जो नगर निर्माण श्रौर ग्राम निर्माण समिति ह उनका मुख्य प्रयोजन नगरों का हो निर्माण ह ग्रौर ग्रगर हम उस मिमित की रिपोर्ट को पढ़े तो मालूम होगा कि निर्माण कार्य जितना हे वह ग्रधिकतर नगरों में ही हो रहा ह बन्कि वहा पर क्या-क्या सुविधाये दी जायं यह विचार होता है। नगरों के मजदूरों के लिये ही सेन्ट्रल गवर्नमेट की श्रोर में लोकल बाडीज-म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज मे रहने के लिये व्यवस्था की जा रही हे. लेकिन जो देहात के गरीब किमान या मजदूर ह, ग्ररीब पब्लिक है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। यदि वह अपने मकानों को एक्सटेड करना चाहते हतो उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगो के पास जमीन हे वह इतनी श्रधिक क़ीमन मांगते ह कि वे बेचारे उसको खरीद भी नहीं सकते ह । बहुत में मकान ऐसे ह कि जिनमें लोग रहते हैं ग्रीर वही ग्रपना चमड़ा भी पकाते हु, ग्रार गन्दा काम करते हु, जिससे तरह-तरह की बीमारिया वहां ग्रपना गढ बनाये रहती ह।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठा-मीन हुए।)

श्रीर जो बीमारिया पहले शहरों में रहनी थी वह श्रब देहातों में घर किये हुए ह। इसका एक-मात्र कारण लोगों के पास रहने के लिये जमीन की कमी है जिसके कारण वह बेचारे वहाँ पशुपिक्षयों की तरह जीवन बिताते ह। श्रध्यक्ष महोदय, "बापू श्रीर हरिजनों पुस्तक के पेज ३३ पर लिखा हुश्रा है कि "वसे बहुत से लोग हमदर्दी दिखाने के लिये तो हरिजनों को सभापित बना देगे श्रीर कुस्तियों पर बिठा लेते ह लेकिन श्रगर उनमें देखा जाय तो वह उसके ऊपर इयू कंसी-डेशन नहीं करते हें । त्रापू ने कहा था कि सबर्ण हिन्दुश्रों को चाहिये कि वे उन मुविधाश्रों को प्रहण न करें जो कि हरिजनों को प्राप्त नहीं ह। उपाध्यक्ष महोदय, क्या म इस सदन के माननीय मदस्यों से पूछ सकता हूं कि क्या कोई ऐसा है जो उन मुविधाश्रों को जो हरिजनों के पास नहीं है उनको ग्रहण नहीं कर रहा है ? ऐसा नहीं ह। बापू को श्राशा थी कि जब स्वराज्य हो जायगा तो वे हरिजनों के लिये क्या करेंगे यह उन्होंने उसी पुस्तक के ७६ वे पृष्ठ पर लिखा है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य होने ही हरिजनों को श्राबाद, सुखी तथा संतुष्ट करना ही सरकार का प्रथम [श्रो जोरावर वर्मा]

कत्तंत्र्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सात-म्राठ वर्ष स्वराज्य को हुये हो गयं लेकित हिरिजनों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है श्रौर में कह सकता हूं कि राजनीतिक वृष्टि में तो स्वराज्य हो गया है लेकिन श्राथिक दृष्टि से श्रभी एसमें क़दम उटाया नहीं गया है। में समझता हूं कि प्रजातंत्र की तीन हो सीढ़ियां है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत श्रावश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उन्हें सुविधा मिलनी चाहिये। जीवन की मूलभूत श्रावश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा श्रौर घर। तो में यह चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह जो पुराना ऐक्ट हैं उसकी धारा जो १५ हैं उसकी श्रावादी के लिये जो एक्सटेंशन हैं; उसका प्राविजन हैं, लेकिन वह एक्सटेंशन किस प्रकार होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। तो में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कहंगा कि इस ऐक्ट में जो मेने यह संशोधन रखा है स्वीकार कर लेंगे जिससे माननीय बापू का जो श्राग्रह है कि उनको श्रपने मकानों के बनाने के लिये कुछ सहलियतें प्राप्त हो सकें श्रौर जिम तरह से दूसरी स्थानीय संस्थाये, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्रादि काम करती हैं, उमी तरह का काम गांव सभाएं भी करें।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गोतम) — माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक द्वस संशोधन का संबंध है उसमें तीन बाते कही गयी हैं। एक हैं लंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबरर ग्रीर खास कर हरिजनों के लिये मकानों ग्रीर मकानों के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीजों के लिये जितनी जमीन हो सके मुफ्त दी जाय। दूसरा है ऐसी कमेटियां बनायी जायं जो डिफेस ग्रीर चेंकिंग ग्राफ काइम्स का काम करें ग्रीर तीसरी बात, फूड ऐंडल्टरेशन के सिलसिले में कुछ काम करें। में एक-एक कर के तीनों चीजों को लेता हूं।

जहां तक फूड स्टप्स के ऐडल्टरेशन का संबंध है गांव सभा के पास ऐसी मशीनरी नहीं हैं जो इसके बारे में काम कर सकें। यह एक बहुत पेंचीदा चीज है और यह श्रधिकार सिर्फं म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है। लेकिन वह क्या करती है? वह नमूना ले कर भेज देती है श्रौर रिपोर्ट उनके पास श्रा जाती है श्रौर तब वे मुकदमा चलाती हे। तो गांव सभा के जिम्मे श्रगर इस काम को डालें तो बहुत बड़ा बोझ होगा। यह काम किसी दूसरे मुहकमें के सुपुर्द किया जाय। गांव सभा में जितनी ताक़त हैं उससे वह इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती। जहां तक डिफोंस श्रौर काइम्स चेंकिंग की बात है इस संबंध में कुछ कार्यवाही हो रही है। विलेज में डिफोंस कमेटियां बन रही हैं श्रौर वे श्रागे किस तरह से गांव सभाश्रों के साथ मिल कर काम करेंगी या उनका क्या श्रागेंनाइजेशनल संबंध होगा यह देखा जायगा लेकिन वह कार्य हो रहा हैं श्रौर जंसा हो रहा है उसको वैसा ही फिलहाल होने दिया जाय।

श्रव सवाल है तीसरा, मकानों के लिये, लंडलेस श्रौर ऐग्रीकल्चरल लेबरसं श्रौर खास कर हिरजनों के लिये जमीन हो। जहां तक इस बात का संबंध है कि गांवों की श्रावादियां ठीक-ठीक बसी हुई नहीं हैं, यह सही हैं कि माडेल विलेजेज हों यह श्रच्छी चीज है श्रौर वहां हरिजनों की बस्ती श्रच्छी तरह से बसाई जाय यह ठीक है। यह ऐसी बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि इसको किस तरह से किया जाय। इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। में उन सब किनाइयों का जिक्र न करते हुये यही कहूंगा कि इस श्रोर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन बड़ी मुश्किलें नजर श्राती है। श्राथिक कठिनाइयां सब से बड़ी हैं। इसलिये इस वक्त भी श्राफ एनी चार्ज, जितनी-जितनी जमीन, एज में बी रिक्वा-यर्ड बाई देम, (जितनी जमीन की उन्हें श्रावश्यकता हो) इसका फंक्ला तो वे खुद करेगे कि कितनी जमीन की उनको जरूरत है, उनको दे दी जाय, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। श्रगर इसका बोझ गांव सभाश्रों पर न पड़ कर के किसी श्रौर पर पड़ता तब तो किसी हद तक बात समझ में श्रा सकती थी। लेकिन गांव सभाश्रों के लिये यह कहना कि फ्री श्राफ चार्ज दें, श्रौर फिर श्राज कल जो सविधान है जिसमें यह हं कि कम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उस

^{*}वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोनेतात को गाय समाये दे भी सकेग; या नहीं, म लमझता है कि एक सोचने की बान है। इसलिये यह कोई ग्रामान सवाल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी गांव सभाओं पर उान दी लाय कि यह की ग्राफ चार्ज जिननी जमीन को जकरन एपीक चरल लेक्स को हो। उनसे मकानों के लिये ग्राफ उनके मकान से मंत्रीवित चीजों के लिये ग्राम एकने के लिये. उपला राज्ये के लिये चमड़ा साफ करने के लिये. जिननी चीजों के लिये जकरत हो क्योंकि एज िक्सार्य वाई देम. इसका फ़ंमला तो यह खुड करेगे, उननी जमीन गांव सभा दें मके। दूसरी दिक्सतों के ग्राल्या इसमें फाइनेन्सल स्वाल भी ग्राप्ता है। गांव सभाग्रों के प्राप्त केवल हजार पांच मों क्या होना है जिसे भी वह बड़ी मुद्दिल से बसूल कर पानी है. उसकी वर इस काम से लगाये. यह कहां तक ठीक होगा। यह सवाल देखने का है। इसलिये यह गांव सभाग्रों के लिये प्रेक्टिकेविल नहीं हो नकता। किसी ग्राप्त मंस्था के लिये होता तो उस वर विचार हो सकता था लेकिन पंचायत राज ग्रीर गांव सभाग्रों के ऊपर इसकी जिस्मेदारी जातना गलन होगा।

माननीय जोरावर वर्मा जो श्रावेश में श्रा कर ऐसी वान कह गये जो कि सत्य से बिल्कुल परे हैं। उनका यह कहना कि स्वराज्य प्राप्त करने के बाद हरिजनों की हालत गिरती जा रही है, म कहना हूं कि श्रांखे बन्द करना हूं श्रीर श्रंथा होना हूं। श्रगर यह कहा जाय कि स्वराज्य हामिल करने के बाद हरिजनों की हालत गिरी है तो उमका जवाव नहीं दिया जा सकता। श्रगर श्राप श्रव भी कहने हे कि श्रव हालत गिरी हुई ह श्रीर पहले श्रव्छी थी। तो क्या श्राप तयार हे उस हालत में श्राने के लिये जिसमें श्राप के बाप दादा थे? में कहता हूं कि हरिगंज नहीं श्राप तैयार होंगे। इसलिये तो यह कहा जा सकता है कि तरक्ज़ी कम हुई लेकिन यह कहना कि गिरते जा रहे हे बिल्कुल गलत है।

श्राज बनारस जैमे कंजर्वेटिव शहर मे विश्वनाथ के नंदिर मे हरिजनों के दाखिल होने के लिये सारा बनारम का नागरिक समुदाय तैयार है कि हरिजन उसमे जाये। में श्रापसे पूछतः हूं कि क्या यह छोशी चीद्ध हैं ? ४ साल पहले या ७ माल पहले क्या श्राप कभी यह विश्वास कर मकते थे कि बनारस में वहां के नागरिक विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों को जाने देने के लिये तैयार होंगे ? इमिलये श्रांखे बंद कर के किमी के लिये कुछ कहना में समझता हूं कि मुनासिब नहीं है।

एक वान और कही श्री जोरावर वर्मा जी ने कि जो मुविधाये हरिजनों को प्राप्त नहीं हं वह स्वयं प्राप्त न करे। में दावें के स थ कह सकता हूं कि जितनी गंदगी में भंगी रहता है झाड़ धौर टोकरी के साथ में समझता हूं कि उस अवस्था में माननीय जोरावर वर्मा जी नहीं रह सकते, और न खाना खा सकते हं। इसिलये हरिजनों के नाम पर इतनी बाते कि हिये कि जितनी मुना-सिव हों। क्या कोई माननीय सदस्य भंगी के घर में जहां पर उसकी टोकरी और झाड़ू रक्खा हो वहां पर बैठ कर खाना खा सकता है? तो चमारों की भिगयों से कहीं अच्छी हालत है और उसमें अच्छी हालत और लोगों की है। हम खुद चाहते हे सुघारों की रफ्तार तेज हो लेकिन यह कहना कि हालत गिरती जा रही है यह बात समझ में नहीं आती।

मुझे श्राज ३० साल हो गये हरिजनों का काम करते। मंने सन् १६२४ ई० में काम करना शुरू किया था। मंने पहले वाल्मीकियों का काम किया। उनके यहां सब से पहले मंने खःना खाना शुरू किया था जब कि कोई सोच भी नहीं सकता था। में कहता हूं अपने ३० वर्ष के तजुब से उपाध्यक्ष महोदय, जो मंने सन् १६२४ से हरिजनों के उद्धार के लिये काम शुरू किया था कि श्राज कल कुछ तो पहले से श्रच्छे ही हं। यह कहना कि हरिजनों के लिये कुछ किया ही नहीं गया ऐसा श्री जोरावर वर्मा के मंह से सुन कर मुझे श्रफसोस होता है। जो लोग काम कर रहे है कम से कम उनके उत्माह को कम तो न कीजिये। इस तरह के शब्दों से हरिजनों का नुक्तान होता है।

अश्री रामदास श्रार्य (जिला मुजफ्जरनगर) -- उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री जी से इस संशोधन के संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने यह फ़रमाया कि हरिजनों के कार्य बहुत कुछ हो रहे हैं इस बात से तो इंकार नहीं करते कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ हुन्ना लेकिन माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे कि ग़रीब लोग जो हमारे देश में रहते हैं, हरिजन और दूसरे लोग, उन्हें हमारे देश वाले दबाये हुये थे। श्राज महर्षि दयानन्द, प्रातः स्मरणीय महामा गांधी जी की कृपा से उन ग़रीबों का उद्धार हुआ, इसको हम मानते हैं। लेकिन में भ्रापसे यह भी कहता हूं कि अब भी इनकी इतनी शिकायत है कि जितनी मदद उनकी की जाय थोड़ी है। ब्राज ब्राप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनको मकानों की श्रावक्यकता है श्रीर पंचायतें उसका प्रबंध नहीं कर सकतीं। मै श्रापसे यह श्रर्ज करता है कि म्रापने जो यह फर्माया कि गांवों में गांव सभायें ठीक तरह से म्रपनी माली बुनियाद पर इसकी प्रबन्ध कर सकेंगी या नहीं जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं। चाहे वे बाल्मोिक हो, चमार हो या कोई भी हो ग्रौर जिन्होंने उनके बीच में काम किया है वे जानते है कि छोटे-छोटे मकानों में १०, १५ ब्रादमी रहते हैं। हमारे यहां मुजप्फरनगर के सिकन्दरपुर गांव में मैने लाल बहाद्र शास्त्री को चमार का मकान दिखाया था कि किस तरह से वे गुजर कर रहे है। उनके डंगर, ढोर सभी उसी में रहते थे। इसलिये ग्राज सभी की शिकायत है कि उनके लिये मकानों की व्यवस्था की जाय। वहां ग्रापने देखा होगा तो इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि मकानों की ग्रत्यंत श्रावश्यकता है। में यह नहीं कहता कि मकान उनको बिल्कुल मुफ्त दिये जायं लेकिन थोड़ी क़ीमत पर तो दिये जायं भ्रौर यह भ्राझ्वासन दिया जाय कि तुम्हारी सरकार तुम्हारा ख्याल कर रही है । तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे ग्रौर उनका उत्साह बना रहेगा । मैं तो यह ग्राशा करता है कि माननीय मंत्री जी इस तरह के इस संशोधन को मंजूर नहीं करना चाहते । भ्रगर ऐसा नहीं होगा तो मकानों के प्रगड़े में उन लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के देखते हुए में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि चाहे पंचायत राज विधेयक में या रूल्स के अन्दर कहीं भी ऐसी गुंजाइश कर दें जिससे उन ग़रीबों की, चाहे वे हरिजन हों या ग्रौर कोई हों, रहने के लिये मकानों की ग्रावश्यकता पूरी हो सके।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बहुत सुन्दर श्राया है श्रीर में इसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। श्राज गांवों की जो दशा है में माननीय मंत्री जी को निमंत्रित करता हूं कि चल कर उसे देखें। श्राज हरिजनों के दरवाजों पर लोग कांटें रूंध रहे हैं। में मानता हूं कि जमींदारी का खात्मा हुआ लेकिन श्राज लठेत वैसे के वैसे हैं, श्राज राजा श्रीर रानियों के डंडे वसे के वैसे हैं, उसमें कोई श्रन्तर नहीं है। जमींदारी श्रवालिशन के बाद भी श्राज हमारी वही दशा है जो पहले थी। श्राज गांव पंचायतों में स्था हो रहा है? जो पंच बन गया है वह श्रपने रिश्तेदारों को जमीन बांट रहा है। इसमें केवल शिडयूल्ड कास्ट्स का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उन ८० फीसदी लोगों का प्रश्न है जो गांवों में रहते हैं, उन भूखे नंगों का प्रश्न है जिनके वोट से यह श्राज गवर्नमेंट बनी है।

इसमें जो दूसरा संशोधन है वह मैं भ्रापकी भ्राज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:---

"To form a sub-committee for purposes of defence and checking crimes in the village."

स्राज गांवों में जितना काइम बढ़ रहा है उसकी कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस वाले भी स्राज उन गुंडों से मिल कर बड़ी स्राफ़त ढ़ा रहे हैं। स्राज किसी एम० एल० ए० की कीमत नहीं समझी जा रही है। विशेषाधिकार का जो प्रश्न स्राज यहां स्रोजूद था वह बड़े महत्व का था। उसमें तो खर फैसला हो गया कि फिर से कमेटी के सामने जाय लेकिन सही मानों में स्राज सरकार की जो पुलिस है वह कोई परवाह नहीं कर रही है। सुंडें लोग नंगे, भूखे, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह गरीबों का प्रश्न है स्रमीरों का

^{*} वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। ब्राज जो लोग भीत्र मांग रहे हैं दरवाजे दरवाजे पर उनमें ब्राह्मण भी है, कोई चमार हो नहीं है। इसलिये सही मानों में ब्रगर राम राज्य ब्रापको कायम करना है तो इन बातो को ठीक करना होगा।

नीमरी बात मिलावट के बारे में कही गयी है। यह बहुत मही है। गांवो की हालत यह है कि स्रहीर लोग डालडा शहरों में ले जा कर जमा देते हैं और फिर उनको मथ देते हैं स्रोर स्नाप पता भी नहीं लगा मकते कि डालडा है या घी। म दो मेर घी स्नाप्त के महीने में बम्ती में लाया था और लखनऊ में जब खाया तो उममें में काला काला न जाने क्या निकला। में कहना हूं कि मरकार इस समेडमेंट की जरूर माने। स्नाप्त हमने गांवों को ठीक नहीं किया तो में ममझता हूं कि यह पंचायत राज बेकार हो जायगा। स्नाज गांवों में त्राहि त्राहि मची हुई है। स्नार स्नाप इसको नहीं मानते हैं तो इस पंचायत राज को बन्द कर दीजिये। में ममझता हूं कि यह तीनों स्नमेंडमेट दुरुस्त है स्नीर सरकार को इन्हें स्वीकार करना चाहिये।

अश्री नेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म माननीय जोरावर वर्मा द्वारा प्रस्तृत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुन्ना हूं। मंत्री जी ने कहा कि कुछ कारणवश मंशोधन मंजूर नहीं किये जा सकते। उन्होंने कहा कि गांव सभाग्रों की माली हालत ऐसी नहीं है कि जमीन मुग्नाविजा दे कर ली जाय ग्रौर बिना पैसे के हरिजनों को या खेतिहर मजदूरों को दो जा सके। फायनेशियल कंडीशन वाला सवाल ऐसा है कि हरिजनों की हालत बहुत ही दयनीय है ग्रौर उनके बारे में ग्रगर हमने कुछ नहीं किया, उनके नियें कोई व्यवस्था नहीं की, तो उनकी दशा कैसे बदलेगी ? में समझता था कि माननीय स्वशासन मंत्री कई दिनों से जो हरिजन विषयक अमेडमेंट्स आये थे उनको मानते आये थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इसको अवश्य मानेगे। फिर यह तो हरिजनों के रहने का घर का सवाल था, इमे तो मानना ही चाहिये था। कल ही माननीय स्वशासन मंत्री जी ने चमड़े के साफ करने वालों के लिये जमीन की जो जरूरत पड़े उसका प्रबन्ध करने के लिये संशोधन स्वीकार किया है कि उसको गांव सभाये करें। कोई उद्योग कैमे कर सकता है जब तक कि उसके घर की व्यवस्था ठीक न हो जाय । हम सब जानते है कि हरिजनों की बस्ती कितनी गंदी और मंकुचित दायरे मे होती है ग्रीर उनका रहना मुक्किल हो जाता है। इसमे कोई संदेह नहीं है ग्रीर सभी इसको महसूस करते हैं। फिर हम उनके लिये कोई प्रबंध करे यह ठीक ही है, ग्रगर हम नहीं करेगे तो कौन करेगा ? ग्रगर वे ठीक तरह से नहीं रह सकते है तो तरक्की कैसे कर सकते है ?

हमारे प्रदेश में खास कर देहातों में सब से बड़ा समाज हमारे हरिजन भाइयों का ही है। उनकी दशा को सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा हम कोई तरक्की नहीं कर सकते है और न उनकी भावनाओं को बल दे सकते है जिससे वे ठीक तरह से हमारे साथ किसी भी काम में आगे बढ़ें। म माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जहां तक साइट्स लेने का सवाल है, इमें वह जरूर करंं, जैसे कि वह मंजूर करते आये हैं, तभी हम उनकी दशा सुधार सकते हैं और उनकी भावना को बढ़ा सकते हैं। जहां तक फायनेशियल कंडीशन का सवाल है वह तो कहीं न कहीं से ठीक करनी ही चाहिये। आखिर उनकी दशा और कौन सुधार सकता हं? गांव सभायें मुघारें या हमारी सरकार सुधारें। जहां तक हो सके किया जाय। इस शविजन को रखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुखफ्करनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय हमारे सदन के सामने है मे समझता हूं कि उसका अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों को हरिजनों के मकान देखने का अवसर मिला है वे इस बात को जानते है कि आज खाने पीने के बाद अगर गरीब आदिमियों की कोई बुरी व्यवस्था है तो मकानों के मामले में है। हमने देखा है कि एक मकान के अन्दर ४-५ गज की सोपड़ी है और उसे यदि सोपड़ी कहा जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया !

[श्री बलवंत सिंह]

श्रसंगत सी बात होगी क्योंकि छान भी नहीं है, दोवार के उसकी ठीक नहीं है, उसी के अन्दर एक बाप रहता हे उनकी वाबी रहती ह जबक लड़का ग्रौर जवान लड़की रहती है ग्रौर उसकी बीबी बच्चे रहते है। ग्रौर को उसका खाना पीना होता है और गाय भैस भी बंधती है। ऐसी दशा में श्राप देनेहें 🗣 श्राज कल जो गरीब ग्रादिमयों के पास मकान गांवों में हे वह ऐसी बुरी ग्रवस्था में हैं जिनके हम नहीं कह सकते है कि वह एक इन्सान के रहने की जगह है। में इस श्रोर श्रापका ध्यान दिन-ऊंगा कि जब चकबन्दी का कानून पेश हुआ तो सदन ने इस बात की व्यवस्था की थी कि गरीव ब्रादिमयों के लिये एक ऐसी बात रक्खी जाय कि जो जमीन ली जा सके खेती से हटा कर वह गराव स्रादिमयों को टी जाय जिसमें वह स्रपने मकान बना सके। इस वात की हमारे देश में चाहे पुर के हों या पश्चिम के, जरूरत हो गयी है कि गरीब आदिमियों के मकानों के लिये जमीन मिनर के सवाल पर विचार हो। चाहे वह किसी प्रकार से आ। लाये। मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हो सकता कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि हम बिला पंसा दिये किसी गरीब ब्रादमी के जमीन दे सके। अञ्छा तो यह हो कि बिना पैसा दिये ही गरीब आदिमियों के लिये जमीनों हा बन्दोबस्त कर दिया जाय लेकिन अपने अपने स्थान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। म यह भी जानता हूं कि अगर हमने कोई ऐसा प्रबन्ध किया कि जो मुफ्त में ही जमीने दिलवाना शुरू कर दीं तो में समझता हं कि बहुत ग्रादमी ऐसे इकट्ठे हो जायंगे जो जमीन के लिये गरीब बनना शुरू कर देगे और यह एक बहुत बड़ी मुक्किल पड़ जायगी कि जमीन लेने से किसको रोका जाय। बहरहाल हम यह जानते है कि जमीन हमारे पास महदूद है, थोड़ी संख्या में है ग्रीर जो देहातों में ग्रास पास में मकान बना सके वह जमीन कम संख्या में है श्रौर श्राज कल जो जमींदारी का खाला हुआ उसमें अधिक तर वह जमीन खेती में ले आयी गयी और उसकी वजह से ऐसी जमीन जिसमें मकान बन सके वह हमारे पास कम है। तो ऐसी दशा में यह कुछ ज्यादा मुनासिव नहीं होगा कि मपत जमीन दी जाय, लेकिन उसकी कीमत इतनी थोड़ी रखी जाय जिससे उन लोगो हो इस बात का उत्साह तो न हो कि वह मुक्त में जमीन लेने के लिये भाग पड़ें। इसके अनिरिक्त जरूरत इस बात की है कि गांवों की जो ब्राबादी है उसको एक नया रूप देना चाहिये ब्रौर इस कानन में हमें ऐसी व्यवस्था मंजूर करनी चाहिये जिससे कि हमारी ग्राबादी का पुनःसंगठन हो मंदे भ्रौर उसमें कुछ ऐसा ढंग लाया जा सके जिसको कि हम अच्छी भ्राबादी कह सकें। खास तौर से में समझता हूं कि हरिजनों के जहां क्वार्टर्स है, उनके मुहल्ले है, उनकी दशा अत्यन्त शोवनीय कल भी कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया था कि ग्रव्वल तो हमारी सोसायटी की परानी ऐसी व्यवस्था थीं कि जो गरीब श्रादमी होते थे वह गांव से दूर रखे जाते थे ग्रीर ऐसे स्थान पर रखे जाते थे जहां पर अक्सर तालाब हुआ करता था और जो रही से रही भूमि हुआ करती थी वह हरिजनों, चमारों और भंगियों और जो ढ़ेड़ थे उनको दी जाती थी। अब सोसाइटी बदलती हर एक ग्रादमी इस बात की इच्छा रखता है कि मै भी एक ग्रच्छा सुन्दर जीवन व्यतीत करूं। उसके लिये यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उनके लिये मकानों की श्रद्धी व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी का विश्वास है ग्रौर में ग्रपने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ग्रोर ग्राकॉयत करूंगा, कि ग्रब जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हो गये है, जिन्होंने एक सोशन पोजीशन श्रस्तियार कर ली है, अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुंच गये है और इस भवन के सदस्य भी हो गये हैं, क्या स्राप उनसे यह स्राशा करते है कि वह ऐसी बुरी जगहों पर रहें जहां पर कि पहले उनके बात-दादा रहा करते थे। तो अब यह निश्चित बात है और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि अब उनकी माँग और भ्र ज्यादा बड़ गई है और बढ़ी हुयी मांग और भूख को हमें ध्यान में रखना चाहिये, किसी प्रकार से उसको सप्रेस नहीं करना चाहिये, दबाना नहीं चाहिये बल्कि उनकी जायज और मुनासिब जो मांग है उसके लिये हमें साधन पैदा करने चाहिये जिससे कि हम उस मांग को पूरा कर सकें। हम मानते है कि ऐसे लोग जो पहले जमीन के मालिक है, चाहे जमींदार की हैसियत से, भूमिधर की हैसियत से या किसान की हैसियन से, उनको यह बुरा अवश्य लगेगा कि जबकि उनकी जमीनें उनसे ली जायंगी और वह गरीव स्रादिमयों को दी जायंगी मकान बनाने के लिये, लेकिन यह भी तो हमें समझना चाहिये कि भगर सोसाइटी को तरककी देना है, समाज को उन्नत करना है तो हमारे जो गरीद प्राद्मों ह उत्का उत्तर हाता अत्यान आवश्यक ह। म ते हम बात का मानना ह कि जमे जब नक समार के प्रत्यर ग्रार कत्यार रहता है ग्रार पह व्यवस्था रहती है कि गोर काला का सेव-भाव है ता का ही नव तक वटा के ग्रायर काति नहीं हो स्पानी जक तक कि उप्राप्त रा भेव-भाव ना मिट बाद ना से यह भी मानता है हि यही हगाड़ा उत्याद होना रहेगा जब तक कि हसारे प्रहा के गारीब होन्यन ग्रार नो पिछड़े हुद का ह उत्तरा भेव-भाव न किटा दिया जाय अर बह तब सम्भव हो सकता र जब कि हम उत्तर श्रीकार वे सोमाद्दी के ग्रायत कि वह उद्योत कर सके तथा हम प्रहा भी ग्रीकार देना होगा कि उत्तर सकानात प्रत्ये वेते ग्राय उत्तर निये हम प्रकार की व्यवस्था की बाद जिससे कि वह सकानात बना सका। तो उसके निये सब से मुख्य चील ह भूमि। ग्रार किसी के बाम चार प्रसा भी ह ग्रार उसकी ग्रवस्था एसी ह कि वह सन्तान बना भी सकता हा लेकिन ग्रार उसके पास भी नहीं ह तो वह सकान बनायेगा कसे हमन्ति से यह समसता हू कि भूमि की त्यवस्था करना किसी न किसी नप म हमें ग्रायत्म ग्रावश्यक ह ग्रार वह हम कानन के जिरये स कर सकते ह क्योंकि से यह जानना ह कि ग्रार ग्राज ग्राप इस बान का प्रयन्त करें ग्रार कहे कि माई राजेब ग्रावसी ह उसके जिये साई त्यस न दे दा, ना स कहना ह कि यह नामुमिनन ह कि उसे समार सिल जाय ग्रार उसका सकान वह सके

हमने यह दारा कि विनो वा भाव जी का जो दान म भिम दी गयी ह उसम में बहुत मी भीम का नो पना नहीं ह कि वह भीम ह कहा। लोगों न दान का तो बहाना किया श्रार नाम के लिय भूमि दे दी। हमें माल्म ह कि बहुत जिलों में ऐसी व्यवस्था ह कि भूमि के नाम में नो कहा कही १००-१०० बीघे जमीन उन्होंने दी ह लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि उस भूमि में विनो हो नहीं मकनी है श्रार फिर वह भूमि ह भी या नहीं, यह भी मन्देह ह। वास्तव में उन्होंने एसी भीम नहीं दी जो कि किमी के काम में श्रा सके। तो इसके लिये व्यवस्था यहा रखी जा रही ह कि कानून के जिये में मूमि ले ली जाय श्रार म ममझता हू कि यह बहुत श्रावश्यक ह कि गरीब श्रादमियों के लिये भीम का श्रवन्य इस नरह में किया जाय। श्राप यह देखने ह कि कार्यों निर्मा या म्युनिस्थितिहीं ह में अभीन दी जानी ह मकानात बनाने के लिये श्रार उसमें गवर्नमेंट को तरम में महायना होनी ह। तो म इसकी श्रीर माननीय मंत्री जो रा व्यान श्राकीयन करना कि जो यह प्रस्ताद माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया ह म इसका पूर्णनया ममर्थन करना ह श्रार यह व्यवस्था इस पचायत राज कानून में होनी चाहिये। गरीब श्रादमी के लिये मकान बनाने के लिये या उसके कारोबार के लिये जसे चमडे बगरह का कारोबार ह, उसके लिये भूमि की व्यवस्था अकर कर देनी चाहिये। इसलिये म माननीय जोरावर वर्मा के प्रस्ताव का पूर्णतया ममथन करना ह।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढवाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना में माननीय श्री जोरावर वर्मा ने इस सशोधन को पेश क्यि, उस भावना को समझते हुउं म इस सशोधन का मनर्थन करता हू किन्तु माथ ही माथ मुझे ऐसा लगता हूँ कि यदि यह मशोधन जिस रूप में पेश किया गया ह उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें कुछ वचानिक कठिनाद्या मामने आयेगी। इमलिये म आपकी आज्ञा में इस सशोधन में कुछ मशोधन पेश करना चाहना हू। पहली पिक्त में शब्द "अरेजमेट्स" और 'आफ' के बीच में यह रूव दिये जाय—

We expression so the prescribed authority and on payment f Coi pelse on as fixed of the prescribed authority

श्री उपाध्यक्ष-प्रद्रग्राप लिच कर मर पास भिजवा दीजियेगा।

मनाराजकुमार वालेन्दुशाह—जी हा, म लिखित भेज दूगा धाप के पास। ध्रोर चाथा पक्ति में जो Free o. ary Charge" ह वह हटा दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौनम-यह श्रव पटा कने जायगा. जरा पढ कर बना दीजिये।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह—ग्रब यह इस तरह पढ़ा जार्यगा-

"for securing and making arrangements, with the previous sanction the prescribed authority and on payments of compensation as fixed by prescribed authority, of house sites and new lands etc." और आगे चल हर "free of any charge" हटा दिया जायगा।

इसमें जिस रूप से जोरावर वर्मा जी ने इसे पेश किया है उसमे मुझे यह आपित दिखलाई पड़ती है कि जो कार्यवाही जमीन के श्रक्वायर करने में करनी पड़ेगी वह किसी न किसी रूप मे ऐक्वीबीहन प्रोसीडिंग या उस तरह की कोई प्रोसीडिंग होगी। तो वहां पर "free of any charge रखना मेरे ख्याल से अनकांस्टीच्यूशनल बात होगी क्योंकि जहां पर टाइटिल का प्रल स्राता है वहां यदि किसी की टाइटिल का राइट डिप्राइव किया जा रहा है तो साथ ही साब दर ग्रनिवार्य हो जाता है कि उसको किसी प्रकार का कम्पेसेशन मिलना ग्रावश्यक है। यह हमारे संविधान के म्रनुसार है । इसलिये यह रखना भावश्यक है। साथ ही साथ जो मने पहला प्रतिबन्ध लगाया है, उससे माननीय मंत्री जी यह न समझे कि मुझे प्रेस्काइब्ड अथारिटी से कुछ प्रेम बढ़ गया है। चूंकि इस संबंध में काफी कंटेस्ट हो सकता है। गांव सभा किसी जमीन को भक्वायर करना चाहे **थ्रौर उसके लिये बहुत से श्रादमी कंटेस्ट** करने के लिये हो जायं तो गांव सभा को एक प्रकार का इनीशियेटिव दिया जाय इन कार्यों को करने के लिये। वे लेडनेन लेंबर श्रौर शेड्युल्ड कास्ट के लिये जमीन श्रक्वायर करने के लिये कार्यवाही कर सकती है लेक्नि शुरू करने से पहले प्रेस्काइब्ड प्रथारिटी की राय ले ले। ग्रगर उनको कोई वैधानिक ग्रार्णत नहीं है तो उनको कार्यवाही चलाने की इजाजत दे सकते है। साथ ही साथ कम्पेंसेशन के लिये ऐट ए रीजनेबिल रेट, यह गवर्नमेंट पर है। जो भ्रापत्ति होगी भ्रक्योजीशन प्रोसी-डिंग्ज के पहले वह कम्पेसेशन के संबंध में होगी। उससे बच जायेंगे क्योंकि यह लिखा नहीं है कि कम्पेसेशन ऐडीक्वेट होना चाहिए। किसी प्रकार का कम्पेसेशन देना स्रावश्यक होगा।

में स्नाशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने दिया है यह जोरावर वर्मा जी को भी स्रौर माननीय मंत्री जी को भी स्वीकार होगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय जोरावर क्यां जो ने जो संशोधन पेश किया है उस में इस प्रकार ग्रपना संशोधन पेश करता हूं — "free of charge" निकाल दिया जाय तथा "landless agricultural labourers and especially for the Scheduled castes" के स्थान पर "houseless person or Familes" रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मृहिकल यह है कि यह संशोधन मेरे सामने नहीं है श्रौर यह कैसे फिट इन करता है या नहीं करता है यह जब तक संशोधन सामने न हो कैसे देखा जा सकता है। जहां तक उन भाषणों का सम्बन्ध है जो भावनाओं का समर्थन करते हैं में उनसे सहमत हूं लेकिन जो कानून की बात है, जब तक संशोधन सामने न हो, उस वक्त तक मैं किस पर विचार करूं।

श्री धर्मसिह--यह इस प्रकार होगा

"for securing and making arrangements house sites and new lands for all such lands appurtenant to that for domestic purposes for the houseless persons or familes peoples as may be required by them within the jurisdiction of the Gaon Sabha."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है यह तो सभी माननीय सदस्य मानने है कि गांवों में उन लोगों को जो कि गरीब है श्रौर बहुत बड़ी तादाद में है उनकी हालत हमेशा से खराब चली थ्रा रही है। मान्य मन्त्री जी ने एक बात कही कि हमारे सामने एक ग्राधिक प्रश

्यह मानी बात ह कि । जब ग्राम पंचायत ग्राबादी के लिये जमीन देने की व्यवस्था करेगों को उन्के सामने प्राधिक प्रश्ने होगा। लेकिन सं माननीय मंत्री की का ध्यान जो १६ क्याज ह इसकी तरक ब्राक्टिंग करना चाहना हूं ब्रोर उपमें सांक मात्र लिखा है कि ग्राम दच यमें प्रावादी के एक्सटेशन के लिये जमीन की व्यवस्था करेगी या प्रावादी से लिये एक्सटेशन करेंगी । तो फिर प्रक्त यह स्नाता है कि को एक्टिक बाते हैं उनमें प्राम सभासी के स्नितियासित क्ति र इह वह कमे करेगी है मेरा निवेदन यह है कि यह तो किसी न किसी कर पे चाहे माननीय मदी हैं। हेल्से में प्राविजन करे या इस नरह की कोई चीज देश करे कि जो गांच का रहते वाला ग्राउमी है उसके लिये जमीन की व्यवस्था हो। इसमें दी राये नहीं हो सकती। जब हम उनके बनों को देखते हु तो वह एक ही घर में खाते हु, एक ही घर मे पीते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही पर में बच्चे पैदा करते हु तो आ़ख़िरकार उन भावनाओं को जो घर करती है समाज के व्यक्तियों में उनको दबाया नहीं जा सकता । ग्रीर यह मानी हुई बात है कि ग्रापको उसका क्रियों न किसी तरीके से प्रदन्ध करना पड़ेगा । साननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि जहां तक मरकार की बात हु हम मानते हु और इस बात की देश मानता है कि जहां तक हरिजनी की हलन को सुधारने की बात है उनके लिये गांधी जी ने बहुत कामे किया है और सरकार भी कर रही हं ग्रीर ग्रागे भी करेगी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि उनकी यह नहीं भूतना चाहिये कि उनके बाप दादा क्या थे ...

श्री मोहनलाल गौतम—मने जिस प्रसंग में वह बात कही उस प्रसंग से उसकी ग्रलग न की जिये। उसी कंटेंस्ट में उसको कहिये कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हरिजनों की हालत बराबर सुधरती जा रही है। ग्रगर ग्राप भी इस बात को मान रे हं कि सुधार हुन्ना है तो मेरी बात को ही कहने हे। श्री जोरावर जी ने जो बात कही थी वह बहुन सख्त थी कि उनकी हालत गिरती जा रही है।

श्री धर्मी मह—म भी इस बात को मानता हूं कि ग्राजादी के प्राप्त होने के बाद जहां तक देश में हरिजनों की हालत थी वह मुधरती जा रही हैं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन परम्परा की ग्रोर जाना या उस बातावरण की तरफ जाना कि वह क्या थे और क्या नहीं थे में समझता हूं कि किसी प्रकार से ग्रच्छा नहीं है। तो जैसा कि मैने बताया यदि हम उनके रहने के लिये प्रबन्ध नहीं करते हे तो इस प्रकार से समाज के जो व्यक्ति नी क कहे जाते हे हो सकता है कि ग्राज उनके पास पंसा न हो तो उनके लिये मेरा निवेदन यह है कि किसी तरीके से रूल्स में प्राविजन किया जाय। जब पिछला ऐक्ट बना था तो उसमें नहीं रखा गया। एक्सटेन्शन ग्राफ ग्राबादी तभी हो सकता है कि जब गांव सभा या जो वहां की गांव पंचायत हो वह इस बात की कोदिश करे कि उन लोगों को जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है उनके लिये मकानों का प्रबन्ध करे ग्रीर ग्राबादी बढ़ाने की कोशिश करे।

अहां तक मुधार की बात है हम लोग यह मानते ह कि मुधार हुमा ह म्रीर माज हमको पश्चाताप करना पड़ता है कि हमारे यहां की परम्परा में भ्रीर हमारे देश में यह कलंक रहा है कि यहां पर खुमाछूत कायम रही। एक तरफ गरीबी रही है भ्रीर दूसरी तरफ भ्रमीरी चली म्रा रही है। भ्रगर अब इस प्रकार का वातावरण रहता है तो उसमें समाज के नाम पर एक दूसरे को एक- प्रतायट कर सकता है। हम जानते हैं कि यहां पर एक बिल आया था म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में तो उसमें प्रश्न यह था कि भंगियों को कूड़े की भी आवश्यकता है या नहीं श्रीर उनको वह दिया जाय या नहीं। जिस कूड़े को हमारे समाज में भंगो को छोड़ कर दूसरा उसके पास को निकालना भी पसन्द नहीं करता और देखना भी पसन्द नहीं करता और नाक भींह सिकोड़ते हैं उस कूड़े की बाबत तय नहीं हो सकता था कि यह कूड़ा उसको दिया जाय या नहीं। इमने समाज बनाय था कि सोसाइटी चले और उस सोसाइटी में यह गन्दगी आयी और उस गन्दगी के साथ यह बातावरण चला। इसका एक बहुत तम्बा इतिहास है। लेकिन अब समय का

[श्री धर्मांसह]

तक़ाजा है कि हम अपने देश में रहने वाले ग़रीबों के लिये उनके रहने के लिये किसी प्रकार कर प्रबन्ध करें। मं माननीय मंत्री जी से केवल इत नी प्रार्थना करूंगा कि जहां इस तरह के संगोध्या का संबंध है तो उसकी आपको मान गा चाहिये और उनकी आदादी बढ़ाने के लिये कोई आदिजन होना च हिये क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। इसिलये मेरा निवेदन है कि कल्स में इस तरह की चीज आप प्रोवाइड करें और अगर कल्स में नहीं रखते हे तो जमीन प्राप्त करने के लिये क्यावट आ सकती है। मं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसकी सूरत को समझने हुंये इस प्रकार का प्राविजन करे और इसको माननें की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो म इन तमाम संशोधनों के बजाय जो (16) का (i) है वहां एक्सटेशन आफ़ आबादी में चूंकि गांव में कोई हाउसलेस नहीं होता है, उसमे यह रखना चाहता हूं।

"and provision for house sites for weaker sections of the public"

इससे सबका प्वाइंट मीट हो जायगा। बाक़ी बातों के बारे में में परसों बताऊंगा। म यह भी नहीं चाहता कि हर जगह "हरिजन" शब्द श्राये।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका श्रीर माननीय बालेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने कहा कि वर्मा जी ने जोश मे श्राकर भाषण दिया। उससे हमको यह मालूम हुआ कि मंत्री जी को गांव का श्रनुभव नहीं है। उन्होंने तो यह कहा कि शहर में रह कर उन्होंने हरिजनों के लिये बहुत कार्य किया है। लेकिन मुझे एक कहावत याद श्रा गई कि "जा के पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।" गांवों मे हरिजनों की हालत से मंत्री जी वाकिफ नहीं है। पूज्य बापू ने जो कुछ कहा उसे कोई भुला नहीं सकता।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० मई, १९४४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थागित हो गया।)

> केलासचन्द्र भटनागर, सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : ७ मई, १६५४।

नत्थी 'क' देखिये ३० यप्रेन १६५४ के नारांकिन प्रका २ का उत्तर मीछे पृष्ठ ३६० पर)

म्म- पु ^{ल्लिम} स्टेशन स्या			डकैनियों की मंख्या	पकड़े गये उकैतों की संख्या	
5	मराय खड़ा		? ?	Ę	१६५३
\$	केराकट		?	ሂ	27
3	मछली शहर		ę	ی	27
E	मरीयाहं े		8	€,	2*
Ł	मीरगंज [े]		ę	१३	12
€,	बदलापुर	• •	१	Ę	22
3	कोनवार्ला	• •	१	૭	22
5	केराकट		8	હ	8578

नत्थी 'ख'

(देखिये ३० म्रप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न द-१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर।)
बुलन्दशहर जिले मे १९५२ व १९५३ मे हुई डकैतियों का विवरण

ζ,	C	X.	٦	
	_	_	_	-

ऋम	****	*****	डकैतियों	मृत	त	हुये	गिरफ्तार डकैतों	मृत डकैतों क
संख्या	थाना	ग्राम	की संख्या	पुरुष	स्त्री	बच्चे	की संख्या	संख्या
8	२	₹	Å	¥	Ę	૭	ξ	Ę
8	कोतवाली	गिनौरा	ę		• •	• •	. 8	
२	स्पाना	कमालपुर बरौली		5	• •	.u.	१४ १६	• •
ą	गुलाथी	मीठपुर	8			• •	१२	• •
ጸ	श्रौरंगाबाद	गिनौरा	१	্ধ	• •	• •	२६	
X	शिकारपुर	खखुन्द	१	• •	• •		११	• •
Ę	सिकन्दराब	ाद पीलंखान	वाली१	• •	• •		१२	• •
e	डंकौर	खेरली	१	• •		٠.	१८	₹
ಽ	काकोरी	ग्रलियाबा	इ १	Ş	• •	• •	હ	• •
3	खुरजा	केवली खु	रे १	• •	• •	• •	5	8
	_	गौस पुरतन	ग १	3	• •	• •	१५	• •
		मोजपुर	१	१	• •	• •	१ ३	• •
		शक्लों	8	• •	• •	• •	₹	• •
		दिनोल	8	• •	• •	• •	હ	• •
0	पहसू	लदपुरा	१	१	• •	• •	२४	१
		बरकतपुर	8	• •	• •	• •	• •	• •
		नगली लील		१	• •	• •	२०	• •
		नागर	Ş	• •	• •	• •	२६	• •
		सिंघगढ़ी	१	• •	• •	• •	१३	• •
8	ग्रनूपशहर	पतरामपु		• •	• •	• •	१ ६	• •
२	डेबाई ।	शकरगंज	१	• •	• •	• •	१५	१
		डबाई कस्ब	र १	• •	• •	• •	3	• •
\$	जहांगीरावा	द	• •	• •	••	• •	• •	• •
	कुल	• •	२२	G	• •	• •	२ ह४	¥

नित्ययां

१६५३

		डकैतियों	मृ	त हुये		गिरफ्तार 	मृत डकैतों की संख्या
कम. संख्य		की संख्या	पुरुव	स्त्री	बच्चे	एएँतों की संख्या	
8	२	ą	Å	ሂ	Ę	હ	5
8	कोलसना	ę	१		• •	Ę	
	मम्मन कर्ल	१ १	१	• •	• •	5	१
२	चितसोना	१	• •	• •	• •	4	• •
₹	•••		• •	• •	• •	• •	• •
8	इसमाइला	8	• •	• •	• •	• •	• •
X	कृतवपुर	१	• •	• •	• •	20	• •
	चितसौन	8	• •	• •	• •	G	• •
	रसुवीर	8	• •		• •	१४	• •
Ę	मुरादांबाद	१	• •	• •	• •	१०	• •
9	छुँहारपुर	१	Ş	• •	• •	• •	• •
5	• •	• •	• •		• •	• •	• •
3	गीसपुरतेना ग्रदैजाकला	१	• •	• •	• •	२	• •
	ग्रदैजाकला	8	• •	• •	• •	११	. •
	जावल	१	• •	• •	• •	Ę	• •
	कैरोला	8	• •	• •	• •	5	• •
	फैराना	8	• •	• •	• •	¥	• •
१०	श्रलीगढ़ श्रन्	7 8	• •	• •	• •	88	• •
	शहर सड़	ñ	• •	• •	• •	• •	• •
	वेदरामर	१	8	• •	• •	ሂ	• •
	नगला-सर			• •	• •	₹ =	• •
	जलालपुर	~ 8	१	• •	• •	१२	• •
	पीतमपुर	8	• •		• •	5	• •
११	सोहरखा	8	२	• •	• •	१०	• •
१२	कसेरकलां	१	8	• •	• •	. ¥	• •
• •	वुलसी गढ़ी	į	• •		• •	१४	• •
	नंगला मर	Ş		• •	• •	१४	• •
	हीरपुर	Ŕ	• •	• •		१=	• •
१३	होरपुर पियाना कलां	Ą	8		• •	4	8
• •	टोली	१ १	• •	• •	• •	*	• •
	कुल	२६	3		• •	. २२२	२

नत्थी 'ग'
(देखिये ३० ग्रप्रैल, १६५४ के ग्रतारांकित प्रक्ष्म १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)
श्री नत्थूसिंह के ग्रतारांकित प्रक्ष्म संख्या १ के सम्बन्ध में विवरण

किस्म हथियार	कित	नी दरस्वास्तें श्राईं	कितने लाइ	सेंस	दिये	गये
बन्दूक	• •	१,००६		१६४		-
राइफेल	• •	५२		३०		
रिवाल्वर	• •	१३६		३२	•	
कुल	• •	१,१६७		३२६		

नत्थी 'घ'
(देखिये ग्रतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)
प्रतापगढ़ जिले मे प्रत्येक थाने पर पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

ऋम तंख्या		थाना		कर्म	चारियों की संख्य
१	कोतवाली श्रौर	उसके मातहत दो पृ	लिस चौिकयाँ	• •	38
7	कुंदा	• •	• •	• •	२०
3	रानीगंज	• •	• •	• •	१७
8	रानीगंज कंघई	• •		• •	१७
ሂ	पट्टी	• •	• •	• •	१७
Ę	पट्टी जेठवारा	• •	• •	• •	१ ७
ં	बंघराय	• •	• •	• •	१८
5	संगीपुर	• •	• •	• •	१७
3	श्रंतू	• •	• •	• •	१५
१०	लालगंज	• •	• •	• •	38
११	संग्रामगढ	• •	• •	• •	१७

नत्थी 'ङ'
(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर)
सन् १९५३ में दिवाली के अवसर पर जिला हमीरपुर के ग्रामों मे पकड़े हुये
जुवों का विवरण

कम-सं	स्या ग्राम का ना	म	पकड़े गये जुवों की संख्या	पकड़े गये स्रभियुक्तों की संख्या	कितने म्रभि- युक्तों ने सजा पाई	कितने ग्रभि- युक्त छ्ट गये
₹	मिश्रीपुर बसौरा		8	5	• •	ς
२	बसौरा		₹	२२	• •	२२
३ ४	सिजहरी		ર	२६	१३	१३
ሄ	सुमेरपुर		*	३ १	₹ १	
ሂ	सिजहरी सुमेरपुर महोबा	• •	Ę	३ 乂	३ %	••
Ę	सूपा		१	१७	१७	••
૭	सूपा खरेला		2	₹ १	२३	5
5	विहूनी तेइया	• •	8	४१	• •	& \$
3	तेइया	• •	8	3	••	3
	योग		38	२२०	११६	१०१

नन्थी 'च'
(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पोछे पृष्ठ ३८४ पर ।)
थाना कायमगंज तथा कम्पिल. जिला फर्रुखाबाद में पिछले वर्ष (१६४३) में हुये
कत्ल, डकैती, रहजनी तथा चोरियों का विवरण

थाना		ग्रपराध		रिपोर्ट हुयी	चालान हुये	सजा हुई
कायमगंज	• •	कल्ल		Ę	ሂ	२
		कत्ल डकैती रहजनी चोरी	• •	• •	• •	• •
		रहजनी	• •	• •		• •
		चोरी		४१	१४	Ę
कम्पिल		क़त्ल		ર	• •	
		क़त्ल डकैती		8	ą	• •
		रहजनी चोरी		• •		• •
		चोरी		१२	8	• •

नत्थी 'छ' (देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

ऋम-संख्या	नाम सब-इन्सपेक्टर	ऋम-संख्या	नःम सब-इन्सपेवटर
8	चौ० तेजपाल सिंह	5	श्री परमेश्वरी दत्त
₹	ठा० त्रिलोकसिंह राना	3	श्री इताग्रत उल्ला खां
3	श्री सच्चिदानन्व नोटियाल	१०	श्री गिरिराज सिंह पोर्सवाल
૪	श्री इयामविहारी लाल	११	श्री श्रब्दुल हुबीब खां
ሂ	श्री प्रहलाद सिंह	१२	श्री स्नानन्द सिंह तोमर
Ę	श्री मेघामल शेरपाल	१३	श्री जरीफ हुसैन
Ġ	श्री मुस्ताक स्रली खां	१४	श्री हरीनाथ सिंह

नत्थी 'ज' (देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर ।)

_	•	-		_	•	. 9.	^	•		_
रम जि	ल इ	र प्रत्यक	थात	あ	ग्रस्तगत	गांग्रो	क्रो	म ख्याः	निम्नलिखित	₹ .
\$11 101	• •		• • •	4.	-1 -(1 -1 /1	-11-41	4.1	11 641		G.

थाना			ग्रामों की संख्या		थाना	ग्रामो की	मंख्या
?	एटा	- •	१५६	 -	सकीट		१६३
3	निधौली		६३	ጸ	मारहरा		१११
ሂ	क:सगंज		११५	Ę	सिदपुरा		१३
9	ग्रभापुर		ER	5	सहावर		११५
3	सोरों		33	१०	ग्रलीगं ज		१४७
११	जैवरा		ह १	१२	गंजडुन्डवारा जलेमर		इ३
१३	पटियाली		६२	१४	जलेमर		११५
१५	ग्रवागढ़		४ ४				

प्रत्येक ग्राम मे ग्राम रक्षा समिति की स्थापना हो चुकी है।

डकंतों का मुकाबला करने में निम्नलिखित ग्राम रक्षा समितियों ने श्रच्छा काम किया है:---

- १—थाना सकीट के अन्तर्गत ज्यूरी ग्राम मे ग्रामीणों को पता चला कि एक ग्राम के बात में कुछ दुश्चरित्र एकत्रित हैं। ग्रामीणों ने उनको घेर कर लाठियों से ग्राहत किया ग्रीर तीन को जीवित पकड़ लिया जिनके पास ग्राग्नेय ग्रस्त्र भी थे। इसके फलस्वरूप पुलिस ने पूरे गिरोह का पता लगा लिया। यह गिरोह इस जिले व ग्रन्य जिलों की कई डकैतियों के लिये उत्तरदायी था।
- २—प्राम रक्षा समिति निकटवर्ती ग्राम के बन्दूक के लाइसेन्सदारों की सहायता से थाना पिटयानी के अन्तर्गत नगला पोपही ग्राम में डकैतों का पीछा किया तथा उनमें से २ को पकड़ लिया जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण गिरोह का जिसमें अधिकांश जिला फतेहगढ़ के थे पता लगा भौर अभियुक्तों का चालान किया गया।
- ३—-प्राम सहाय सुखदेव, थाना जलेसर की ग्राम रक्षा समिति ने उस मार्ग को जिसमें डकंत जाने वाले थे रोक दिया ग्रौर जब डकंत लूट का माल ले कर जाने लगे तो उन पर बल्लमों से ग्राक्रमण कर दिया। २ डकंत मौक्ने पर पकड़े गए ग्रौर एक पूरे गिरोह का जिसमें ग्रधिकतर ग्रहेडिया जाति (पहले जरायम पेशा) के थे पता लगा वह नष्ट कर दिया गया।
- ४—थाना कासगंज के भूपालगढ़ी ग्राम में तीन लुटेरों ने २ जुलाहों का कपड़ा व रुपया गांव के सपीप ही दिन के समय छीन लिया। ग्रामीणों ने लुटेरों का पीछा कर के तीनों को मय माल के पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा किया गया यह एक प्रशंसनीय कार्य था।
- ५—थाना ग्रावागढ़ के ग्रन्तर्गत टिकाघर ग्राम में जब कुछ चोर एक मकान का दरवाजा उतार रहे थे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने उन पर ग्राक्रमण कर दिया। फलस्वरूप चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया ग्रौर उनके चोटे भी ग्राईं। इस हाथापाई में एक गांव काले के भी चोट ग्राई जो बाद में ग्रस्पताल में मर गया।
- ६—इस म्रन्तिम कार्य में ग्राम समदपुरा, थाना एटा के निकट से कुछ दुश्वरित्र व्यक्तियों को जाते हुये गश्त करने वाली पार्टी ने टोका भ्रौर दोनों भ्रोर से बन्दूकों का प्रयोग भी हुन्ना। एक डकंत श्राहत हुन्ना ग्रौर गांव के निकट बाद में पड़ा मिला। इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप एक गिरोह का पता चल सका जो कई डकंती की घटनाम्रों के लिए उत्तरदायी था।

नत्थी 'झ'
(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)
उन्नाव जिले मे पहली जनवरी, सन् १९४४ से १४ फरवरी, १९४४ तक
डकैतियां तथा हत्यायों का विवरण

			डकैतियां		कत्ल			
ऋम- संख्या	थाने का नाम	संख्या	पकड़ें गये लोगो की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	पकड़े गये लोगो की संख्या	दंडिन व्यक्तियो की संस्या	
8	कोतवाली		-	-	و	१४	3	
	सफीपुर फतेहपुर	१	£	****	Ę	१५	9	
र ३	फतेहपुर	२	१७	-	¥	8	२	
ሄ	बांगरमऊ	२	२०	_	Ę	१ ६	8	
ሂ	श्रोराह	₹	२१	-	२	₹	_	
Ę	हसनगं ज	8	१३	₹	ሂ	१०	२	
৩	गंगाघाट	_	_	5	Ę	४	२	
5	श्रचलगंज	१	११	१०	₹	ሂ	8	
£	श्रज्ञगैन	ş	₹0	_	9	5	_	
१०	धारानगर	१	१२	-	२	_	_	
११	बीहर	¥	३२	१२	ሂ	Ę	¥	
१२	पुरवा	_	_	-	_	-	_	
? ₹	मोरावां	२	দ		ሂ	3	5	
१४	श्रसोहा	8	२४	-	२	१	_	

नत्थी 'ङा'

(देग्विये पीछे पृष्ठ ३६० पर)

लखनऊ यूनिवर्मिटी (संशोधन) विधेयक, १६५४

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६२० को संशोधित करना आवश्यक है; अत्रएव निम्निलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

य्० पो० ऐक्ट ४, १६२०।

१--(१) यह ऋधिनियम खलनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) स्रधिनियम, १९४४ कहलायेगा।

मंक्षिप्त शीर्षनाम श्रोर प्रारम्भ ।

(२) यह ऐसे दिनाक पर प्रचलित होगा जिने राज्य सरकार सरकारी गज्जट मे इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

२--लखनऊ यूनिर्वासटी ऐक्ट, १६२० (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) से शब्द "unitary", और शब्द "and residential" निकाल दिये जाये।

यू॰ पी॰ ऐक्ट संख्या ४, १६२० की प्रस्तावना का संशोधन। यू॰ पी॰ ऐक्ट ४, १६२० की घारा २ का संशोधन।

३--मूल श्रिधिनियम की घारा २ में--

- (१) खंड (a) के स्थान पर निम्निलिखित खंड (a) श्रौर (aa) के रूप में रख दिया जाय--
- "(a) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."
- "(aa) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorised to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."
 - (२) खंड (b) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (bb) ग्रीर (bbb) के रूप में बढ़ा दिया जाय—
- "(bb) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution recognised by the University."
- "(bbb) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a Hall."

- (३) खंड (e) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ee) के रूप में बढ़ा दिया जाय---
- "(ee) 'State Government' means the Government of the State of Uttar Pradesh."
 - (४) खंड (f) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ff) के रूप में बढ़ा दिया जाय--
- "(ff) 'Student of the University' means a person enrolled in the University or a Constituent College for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."
 - (१) खंड (४) में शब्द "any of its Colleges or Halls", के स्थान पर शब्द "any Associated College, Constitutent College or Hall", रख दिये जायं—
 - (६) खंड (h) से शब्द "wholly or partly", निकाल दिये जायं ग्रीर शब्द "instruction" के पश्चात् "for degrees or to guide or conduct research" बढ़ा दिये जायं।

४---मूल श्रिधिनियम की धारा ४ में----

- (१) उपधारा (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।
- (२) उपघारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
- "(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—
 - (a) shall have pursued a course of study in the University, an Associated College or a Constituent College or carried on research in the University, under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or
 - (b) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or
 - (c) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ४, १९२० को घारा ४ का संशोधन।

388 तन्थियां

- (३) उपवारा (4) में शब्द 'members' के स्थान पर शब्द 'students' रख दिया जीव ।
- (४) उपचारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया ज्ञान --

"to maintain Constituent Colleges and Halls and to recognise Associated Colleges and Halls not maintained by the University."

(५) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (8-a) के रूप में वढा दिया जाय--

"(8-a) to inspect Associated Colleges and recognised Halls." यु॰ पी॰ ऐक्ट ५, ५--मल अधिनियम की धारा ५ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय--

१६२० की घारा ५ का संशोधन ।

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

६--मूल श्रिधिनियम की घारा ६ में--

यु० षी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा ६ का संशोधन।

- (१) उपघारा (1) में शब्द "conducted by the University" श्रीर पुन: शब्द 'conducted in the University" के पश्चात् शब्द "or an Associated College or a Constituent College" बढा दिये जायं :
- (२) उपघारा (३) में शब्द "Ordinances and" के पश्चात् शब्द "subject thereto by" बढ़ा दिये जायं।
- (३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"In addition to the recognised teaching, tutorial and other supplementary instruction shall be given in the University or an Associated College or a Constituent College or under the control of the University or such College, in a Hall."

७--मूल ग्रिधिनियम की घारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित एख विया जाय-

यु० पी० ऐक्ट ४, १६२० की बारा ७ का संशोधन ।

7. (1) The State Government shall "Visitation the right to cause an inspection be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

- (2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.
- (5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

यू॰ पी॰ ऐक्ट ४, १६२० की घारा ६ का संशोधन। द—मूल भ्रिषिनियम की घारा ६ में उपघारा(1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्निलिखित रख दिया जायः—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की घारा १० का संशोधन । ६---म्ल म्रिधिनियम की भारा १० के स्थान पर निम्निलिस रल दिया जाय---

- "The Vice- 10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.
 - (2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the

नन्थियां ४५१

Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor:

- Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.
- (3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
- (4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no name has been added under the proviso to sub-section (2) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with subsections (2) and (3).
- (5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (6) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible to re-appointment.
- (7) Subject as aforesaid, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.
- (8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause [other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term] the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive

Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall, in so far as may be, apply for the filling of the vacance. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under subsection (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा ११ का संशोधन। १०--मूल श्रिधिनियम की घारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Powers and duties of 11. (1) The Vice-Chancellor shall be the Vice-Chancellor. the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an ex-officio member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of

University but shall not by virtue of this subsection be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

the meeting of any authority or other body of the

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (a) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

नित्थयां ४५३

But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

- (b) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.
- (5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

११---मूल श्रिघिनियम की घारा १२ में उपघाराश्रों (!) से (5) तक के स्थान पर निम्निसिखित रख दिया जाय---

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा १२ का मंजोबन।

- "The Treasurer. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 10 shall apply as though for the words 'Vice-Chancellor the word 'Treasurer' had been substituted therein.
 - (2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.
 - (3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (5), (7), (8) and (9) of section 10 shall mutatis mutandis apply to the office of Treasurer.
 - (4) The Treasurer shall be an ex-officio member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual

estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

- (5) The Treasurer shall have the duty--
 - (i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment).
 - (ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ४, १९२० की बारा १३ का संशोधन।

१२-मूल म्रिधितियम की धारा १३ के स्थान पर निम्निलिखित रख विया जाय-

"The Registrar.

13. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of the University and shall
be appointed by the Executive Council on the
recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) an educationist nominated by the Chancellor;
- (iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.
- (2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.
- (3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be ex-officio Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these Authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.
- (4) He shall make all arrangements for and conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
- (5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the

नित्थयां ४५५

University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

१३-मूल स्रिधितयम की घारा १५ में मद (5) के स्थान पर निम्नलिखिन रस दिया जाय:--

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा १४ का संशोधन ।

- "(5) The Faculty Boards,
- "(5-a) Selection Committees for the appointment of teachers, and"
- . १४-म् त्रिविनयम की बारा १६ के स्थान पर निम्नितिखत रज्ञ दिया जाय-

यू० पी० ऐक्ट रः १९२० की घारा १६ का संझोधन।

"16 (1) The Court shall consist of the following persons, namely:

Class I-Ex-officio members:

- (i) the Chancellor,
- (ii) the Vice-Chancellor,
- (iii) the Treasurer,
- (iv) all Principals of Constituent Colleges and Associated Colleges,
 - (v) All Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments,
- (vi) the Minister of Education, Uttar Pradesh,
- (vii) the Minister of Health, Uttar Pradesh,
- (viii) the Director of Medical Services, Uttar Pradesh,
- (ix) the members of the Executive Council,
 - (x) such other ex-officio members as may be prescribed by the Statutes.

Class II-Life members:

- (xi) such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four.
- (xii) All persons who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University.

Class III—Other members:

(xiii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies

- (4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications, and emoluments of teachers and the appointment of and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.
- (5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की घारा २१ का संशोधन। १७--मूल अधिनियम की घारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित नई घारा 21-A के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"21-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की घारा २२ का संशोधन।

१८—मूल ग्रिधिनियम की घारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Committee 22. (1) The Committee of Reference shall consist of—

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Treasurer;
- (iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be appointed in the manner prescribed by the Statutes;
- (iv) two persons to be nominated by the State Government.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.
- (3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be provided by or under this Act.
- (4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under subsection (3)."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०**ृँ**की बारा २३ का संशोधन।

१६--मूल म्रिविनियम की घारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Faculties. 23. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed

by the Statutes.

14 There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department in the Faculty and shall be chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Depart-

ments comprised in the Faculty.

(6, There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The seniormost Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the seniormost Reader thereof shall be the Head."

२०--मुल अविनियम की घारा २५ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and such other", के स्थान पर शब्द 'such' रख दिया जाय।

२१---मल ग्राधिनियम की वारा २६ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and of all other" निकाल दिये जायं।

२२--मुल ग्रविनियम को वारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित वारा 26-A के रूप में रख दिया जाय--

"Manner of appointment 26-A. (1) Save where expressly provided of officers and members to the contrary, officers and members of of Authorities. the authorities of the University shall, as far as may be, be chosen by methods other than election.

य० पी० ऐक्ट ५, १६२० की घारा २६ का संशोधन । य० पी० ऐक्ट ५, १९२० में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

य० पो० ऐक्ट ५,

१६२० की घारा

२५ का संशोधन ।

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any appointment according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

२३---मुल अधिनियम की घारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following-

(a) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(b) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities

यु० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा २७ का संशोधन ।

and Boards of the University and the filling c-vacancies and all other matters relative: those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide;

- (c) the institution and maintenance of College, and Halls;
- (d) the designation, manner of appointment, power, and duties of the officers of the University;
- (e) the classification and mode of appointment of teachers;
- (f) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (ff) the institution of degrees and diplomas;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions;
- (i) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition;
- (j) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;
- (k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;
- (1) the maintenance of a Register of Registered Graduates;

(m) the holding of Convocation;

- (n) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes; and
- (o) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा २६ का संशोधन। २४—-मूल ग्रिघिनियम की घारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया

"Ordinances.

जाय---

- 29. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.
- (2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—
 - (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University;

- " the conditions under which students shall admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas;
- (d) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Halls maintained by the University;

(e) the recognition of Halls not maintained by the

University;

f) the number, qualifications, emoluments and terms and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University;

(g) the fees which may be charged by the Univer-

sity for any purpose;

- (h) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in Halls:
- i) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators:

(1) the conduct of examinations;

- (k) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University;
- (1) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and
- (m) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided tor by the Ordinances".

२५--मुल अधिनियम की घारा ३० में--

(१) उपधारा (1) के खंड (d) में शब्द "the Residence, Health and Discipline Board", के स्थान पर शब्द 'the relative Board established under Section 25' रख दिये जायं।

य० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा ३० का संशोधन ।

- (२) उनचारा (३) में शब्द "made by the Executive Council" श्रीर शब्द "shall" के बीच में, शब्द "shall have effect from such as date it may direct and" रख दिने जायं।
- २२--- मृत ग्रविनियम की घारा ३१ रें प्रधारा (3) के पश्चात् तिस्नलि । उपरारा (4) के का में ब्हा दिया आए--

यु० री० ऐवट ५. १६२० की घारा ३१ का संशोधन ।

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of Faculty concerned but may reject the draft received or return it to the Board of Faculty concerned for further consideration together with its own suggestions.

यू०पी० ऐक्ट ४, १६२० में ३ नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७——मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक "Teachers" के अन्तर्गत धाराएं 31-A, 31-B और 31-C के रूप में बड़ा दिया जाय—

- "Teachers. 31-A. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3, the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.
 - (2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.
 - (3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Management without the advice of the Selection Committee."

"The Selection Committee.

- 31-B. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—
- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;
- (ii) the Dean of the Faculty concerned;
- (iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases.
- (iv) the Head of the Department concerned;
- (v) One member of the Executive Council, not being a teacher, to be chosen, by the Council.
- (vi) where the appointment is to be in an Associated College the Principal of that College.
- (2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).
- (3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of

नित्ययां 853

study is prescribed for a post-graduate degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendation in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation."

"The Consulmittee.

- 31-C. (1) There shall be established a Comtative Com- mittee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.
 - (2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.
 - (3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

२८—मूल श्रिधिनियम की घारा ३२ से शब्द "in a College or Hall, CI" निकाल दिये जायं।

२६--मुल ग्रधिनियम की धारा ३३ में---

- (१) उपघारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
- "(1) Halls maintained by the University shall be such as may be named by the Statutes."
- उपघारा (2) से शब्द 'Colleges and' निकाल (२) दिए जायं।
- (३) उपघारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---
- "(3) The conditions of residence in Halls and other places of residence for students of the University shall be prescribed by the Ordinances and every Hall and such other place shall be subject to inspection by an officer of the University or other person, authorised in this behalf by the Executive Council."

य० पो० ऐक्ट ५, १६२० की घारा ३२ का संशोधन। य० पी० ऐक्ट ५, १६२० की घारा ३३ का संशोधन । (४) उपवारा (4) श्रीर उसके प्रतिबन्धात्मक बाक्य में शब्द 'College or Hall' के स्थान पर शब्द 'Hall or otheplace of residence for students of the University' रख दिए जार्य ।

यू० पी० ऐक्ट ४, १९२० में तीन मयो घाराश्रोंका बढ़ाया जाना। ३०—मूल ग्रधिनियम की धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिक्षित तई उपधाराएं 33-A, 33-B ग्रीर 33-C: के रूप में बढ़ा दिया जाय-

"Associated 33-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart

instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the College and be responsibe for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council.

Non-Collegiate Delegacy. 33-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any College or Hall. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

"Constituent Colleges.

- 33-C. Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes.
- (2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the College and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the College. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes."

३१-नूल प्रश्वितियम को घारा ३८ में--

(१) उपधारा । में शब्द "including at Principal and one Provost" निकाल दिये अयं।

यू० मी० हेक्ट ४१ १६२० की झारा ३४ का मंडीधन १

(२) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 5 के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(5) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances."

३२--मूल अविनियम की घारा ३५ में--

(1) उपवारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

यू॰ दी॰ ऐक्ट ४, १६२० की श्वारा ३५ का मंत्रोधन।

- "(3) At least one person who is not an employee of the University or an Associated College or Hall shall be appointed examiner for each subject of study for a degree."
- (२) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--
- "(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."
 - (३) उपचारा (4) के पश्चात् निम्नलिक्षित नई उपचारा (5) के -- रूप में बड़ा दिया जाय--
 - "(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

३३---मूल श्रिधिनियम की बारा ३६ के श्रन्त में निम्नलिखित बड़ा दिया जाय---

"The Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and when no action is taken of the reasons therefor."

३४-मूल स्विनियम की घारा ३७ में--

(१) उपधारा (1) के श्रंत में निम्निसिखित एक मये पैराग्राक के रूप में यदा दिया जाय---

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing.

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा ३६ का संज्ञोधन।

यू॰ पी॰ ऐक्ट ४, १६२० की बारा ३७ का संसोधनी The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances."

(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette", के स्थाप्त शब्द "printed" रख िया जाय और उपधारा के म्रंत में निम्नलिखित बढ़ा विया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget

on in violation of any provision of the Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6)के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय-

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (c) of sub-section (1) of Section 20, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget."

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की घारा ३६ का संशोधन। ३५--पूल ग्रिधिनियम की धारा ३६ में शब्द "body of the University" ग्रौर शब्द "the matter", के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"or whether any decision of the University or any authonity thereof is in conformity with this Act. the Statutes or the Ordinances."

यू० पी॰ ऐक्ट ५, १६२० की घारा ४१ का संशोधन। ३६—मूल प्रधितियम की धारा ४१ में निम्नलिखित उपघारा (2) के रूप में बढ़। दिया जाय ग्रौर वर्तमान घारा को उपघारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ४, १९२० की बारा ४२ का संज्ञोषन।

३७—मूल ग्रविनियम की घारा ४२ के ग्रन्त में शब्द 'members' के पश्चात् ग्राये हुए फुलस्टाप के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ४, १६२० की बारा ४४ का संशोधन। ३६--- मूल स्रविनियम की बारा ४४ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940)" रख दिये जांब।

संक्रमणकालीत उपश्रन्ध

३६—-मूल प्रधिनियम, परिनियमों (Statutes)या प्रध्यादेशों (Ordinances) में किया बात के होते हुए भी लखनऊ यूनिर्वासटी (संशोधन) ग्रिधिनियम, १६५४ । जिसे यहा प्राप्त वल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संपठित किसी निर्वाचित ग्रिधिनारी ग्रथवा प्राधिनारी का कार्यकाल संशोधन ग्रिधिनयम होता संशोधन ग्राधिनयम के उपबन्धों के अनुसार तदनुष्क्ष (corresponding) प्रविकारी प्रथवा प्राधिनारी के नियुक्त, निर्वाचित ग्रथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा ।

४०—मंशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पञ्चान किसी भी समार राज्य सरकार के लिए वैच होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो मशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यनः ब्रावश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है ब्रौर ऐसे परिनियमों के प्रचित्त होने के दिनांक निश्चित करे।

इस घारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के स्राधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधिन मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिकांत (supersacio) न कर विया जाय ।

४१--राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपवन्थों से संशोधन अधिनियम द्वारा मंशोधिन उक्त अधिनियम के उपवन्थों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन में सरकारी गंबर में आज्ञा प्रकाशित करके ---

- (क) मादेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल प्रिविनयम उस कालाविध में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के मधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या
- (अ) ग्रादेश वे सकती है कि संशोधन ग्रिधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल ग्रिधिनियम के ग्रिधीन ग्रीर श्रनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित श्रयवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ग्रिधिकार ग्रयवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य ग्रीर कृत्य संशोधन ग्रिधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुष्ट्य प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त ग्रयवा सम्पादित किये जायेगे; या
- (ग) ग्रादेश दे सकती है कि संशोधित ग्रिधितियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) ग्रध्यादेश या विनियम (Regulation)ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों ग्रांर लोगों (omissions) के ग्रधीन, जैसा कि वह उचित ग्रीर श्रावश्यक समझे, उस समय तक भ्रागे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन ग्रधिनियम द्वारा संशोधित मूल ग्रिधिनियम के ग्रधीन कोई बात यार्य क कारके उसे ग्रिधिकांत न कर दिया जाय, या
- (घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे ग्रन्य ग्रस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह ग्रावश्यक ग्रयवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संबोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात ऐसी कोई ग्राज्ञा न दी जायगी।

उद्देश्य ग्रौर कारण

लखनक यूनिर्वासटी ऐक्ट ग्राज से ३३ वर्ष पूर्व १६२० में बना था। उस समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है यद्यपि इस राज्य के विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन का प्रश्न १६३६ से ही शासन के विवाराधीन रहा हे जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। तब से विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन की समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों (इंडियन यूनिवसिटी एजुकेंग्नन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया है। उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों के ग्राधार पर विश्वविद्यालय के संविधान एवं श्रिधकारियों तथा समितियों के कार्य की उन्नति करने का प्रस्ताव है।

म्रतः यह विधेयक सदन के विचारार्थं उपस्थित किया जा रहा है।

हरगोविन्द सिंह,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

_{की} कार्यवाही

की

ऋनुक्रमिशाका

खंड १३६

双

ग्रंप्रेजी--

प्र० वि०—साहित्य की प्रतियों के में प्रकाशन पर ग्रापत्ति । खं १३६ पृ० ११३–११४ ।

ग्रधिकृत भूमि--

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिले में नहर की खुद ई के लिये——। खं० १३६, प्० १०४–१०५।

ग्रध्यक्ष, श्री---

द्मनुपूरक प्रक्तों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रक्त नहीं उठता' कहने पर——का निर्णय । खं० १३६, पृ० १२१–१२२।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विषे-यक, १६५४। क्षं १३६, पु० ३३, ३४, ३४, ३६, ३७, ३८, ३६ ४०, ४४, १२७, १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३४, १३६, १४०, १४१, १६३, १६६, १६७, १६८, १६६, १७०, १७१, १६२, १६३, १६६, १६७, १६६, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २३१, २३३, २३४, २३४, ३२६, ३२८, ३२६, ३३०, ३३१, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४ को १२ मई, १६५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना। सं० १३६, पृ० ४०५।

कलिपय स्थामी समितिमों के निर्वाचन का कार्यक्रम । सं १३६,पू० १७२।

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति। खं० १३६, पू० ३१।

लाउड स्पीकर श्रौर पंस्में की खराबी। खं० १३६, पृ० १२४।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७-२१४।

विशेषाधिकार का प्रक्त उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना। सं० १३६, प्० २६६।

श्री नारायणदत्त तिवासी की नारफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। सं० १३६, पृ० २६६।

प्रमुक्तमांणका

[प्रध्यक्ष, श्री---]

- श्री नारायणवत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिक।र की ख़बहेलना के विषय मे विशेषाधिकार समिति के प्रतिबंदन पर विचार। खं० १३६, पू० ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६७, ४०१, ४०२, ४०६, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१७-४१६, ४२०, ४२१, ४२२, ४२४, ४२६।
- श्री नारायणवत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २६४, २६४–२६६, २६७–२६८।
- भी नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रदन से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारायं समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पू० ३२।
- श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषा-धिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना। खं० १३६, पृ० १६१।
- श्री राजनारायण की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थागन प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, षु० १२४–१२७।
- श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी

 के सम्बन्ध में विज्ञेषाधिकार की

 सबहेलना का प्रक्त उठाने की

 प्रार्थना पर—की व्यवस्था।

 सं० १३६, पृ० ३८६-३६०।
- श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना। खं०, १३६, पु० ३१।
- स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम बार्यस लेने के समय में वृद्धि की स्चना। सं०१३६, पृ०४०४–४०५।

ग्रनुदान---

प्र० वि०—राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के—में कटौती। खं० १३६, पृ० ३८४।

मनुपूरक प्रक्नो---

के उत्तर में माननीय मंत्रियो द्वारा 'प्रक्ष्म नहीं उठता' कहने पर श्री ब्राध्यक्ष का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१-१२२।

श्रन--

प्र० वि० की पँदावार में वृद्धि। खं० १३६, प्०१७।

ग्रपीले--

प्र० वि०—मार० टी० ग्रो० द्वारा रह किये जाने वाले मोटर लाइसँसों की ग्राज्ञाग्रों के विरुद्ध---। खं० १३६, पृ० १६।

मन्दुल मुईज लां, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषयक, १९४४। खं० १३६, पृ० ३४, ३४, ३६, १३४, १६७, १६६-१७०, १९२, १९३, २२४, २३४, ३०२।

ग्रभाव--

प्र० वि०—जिला टेहरी गढ़वाल की निदयों की घाटियों में सिंचाई के साधनों का——। खं० १३६, पु० १०६–१०७।

ग्रभियोग---

- प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में विद्यार्थी ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियो प —— । खं० १३६, पृ० ३६७— ३६८।
- प्र० वि०—विधान सभा के सदस्य भी नारायण दत्त तिवारी पर ——गौर उनकी पेशी। खं० १३६, पू० ३६६-३७१।

प्रतक्रमणिका

ग्रमेरिकनो---

प्र० वि० — मथुरा जिले मे — -हारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना ग्रोर कुछ ग्रायं समाजियों की गिरफ्तारी। सं० १३६, पृ० ३६४ —३६७।

ग्रली बहीर, श्री संयद--

उत्तर प्रदेश श्रौद्योगिक गृह-व्यवस्था विषेयक, १९४४। सं० १३६, पृ० ३३।

ग्रवघेश प्रताप सिंह, श्री----

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १६४४। खं० १३६, पृ० ३१२।

ग्रस्पताल--

प्र० वि०—— के कार्यकाल में मेडिकल श्रफसरों को बाहर न जाने का ग्रादेश। सं० १३६, पृ० १८४—१८४।

ग्रहार परगने ---

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२– २७३।

आ

ब्राई० पी० एस० ब्रफसरों----

प्र० वि० पुलिस विभाग में ग्राबकारी विभाग से ग्रागत के प्रोबेशन की ग्रविध सं० १३६, पृ० ३६८।

ग्राज्ञाओं---

प्र० वि०—मार० टी० म्रो० द्वारा रह् किये जाने वाले मोटर लाइसेंसों की— के विरुद्ध म्रपीलें। खं० १३६, पृ० १६।

प्राडिट व्यवस्था---

प्र० वि०--राज्य की पंचायतों के लेखों की----। सं० १३६, पृ० १७६-१८०।

ग्रावेश-

प्र० वि० — जरीप्रयाके सम्बन्ध में भारत सरकार का — । म्वं० १३६, पृ० १०२।

प्र० वि०—फंजाबाद के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का——— खं० १३६, पृ० ३७६।

ब्रायति---

प्र० वि०—साहित्य की प्रतियो के ग्रंग्रेजी में प्रकाशन पर——। खं० १३६, पृ० ११३–११४।

ग्राबकारी---

प्र० वि०—से ग्राय। खं० १३६ पु० १०६-११०।

श्राबकारी विभाग---

पितस विभाग में सागत ग्राई० पी० एस० श्रफसरों के प्रोडेशन की ग्रविष । खं० १३६, पु० ३६८।

म्राय-

प्र० वि०—ग्नाबकारी से—। खं० १३६, पृ० १०६-११०।

मार० टी० मो०--

प्र० वि० — द्वारा रह किये जाने वाले मोटर लाइसेंसों की माजामों के विरुद्ध श्रपीलें। खं० १३६, पृ० १६।

श्रार्य-समाजियों---

प्र० वि० - मथुरा जिले में समेरिकनों द्वारा घर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाना और कुझ ----- की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६५ - ३६७।

ग्रावश्यकता--

प्रव विव चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की — । खंब १३६, पृष्ठ १२०-१२१।

कम्युनिस्टो---

प्र० वि०-साजमगढ़ जिले मे---की गिरफ्तारी । खं० १३६, पृ० ३६१।

कम्हरिया सागर बांध---

प्र० वि० — जिला हमीरपुर मे — की मरम्मत । खं० १३६, पृ० १२३।

कर्मचारियों--

प्र० वि०—खाद्य विभाग मे——की छटनी । खं०१३६, प्०१६५–१६६ ।

प्र० वि०—विलीनीकरण के पश्चात काशी राज्य के——का सरकारी नौकरी में लिया जाना । खं० १३६, प्० २८३—२८४।

कर्मचारी---

प्र० वि०--जौनपुर जिले में कलेकान विभाग के---। सं० १३६, पृ० १३-१४।

कलेक्टरी--

प्र० वि०---गाजीपुर---में विचाराधीन मुकहमें। लं० १३६,पृ० १४-१४।

कलेक्शन विभाग---

प्र० वि०--जौनपुर जिले मे-----के कर्मचारी।सं०१३६,पृ०१३-१४।

कांसिलिएशन माफिसर्स--

प्र० वि०—लेबर माफिसर्स तथा——— की नियुक्तियां भीर उनमें हरिजनों का मनुपात । खं० १३६, पृ०३६४ ।

कागजात में सेहत--

प्र० वि०—महोवा एवं चरलारी के तहसीलवारों द्वारा—— । लं० १३६, पृ० २६-३०।

कामर्स--

राजकीय इंटर कालेज, रामपुर में कक्षा ११ वीं में———की शिक्षा । खं० १३६ पृ० ३८६ ।

कारखाना--

प्र० वि०—मङ (म्राजमगढ़) में रंगाई व धुनाई का——— । खं० १३६, पु० २८४।

कार्य---

प्र० वि०—तहसील नकुड जिना सहारनपुर में नलकूपों का -----। खं० १३६, पृ० ११८।

प्र० वि०—- त्ववर्षीय योजना के श्रधीन लखनऊ जिले की उन्नत के। खं० १३६, पृ० २७३—२७४।

प्र० वि०--पंचवर्षीय योजना के झन्तर्गत रहकी तहसील मे----। खं० १३६, प्० २७७।

कार्यक्रम---

सदन के झागामी---के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० ३२।

कार्यवाही----

प्र० वि०—कारीपाकर (सीतापुर) में डकेंती श्रीर उस पर ———। सं० १३६, पृ० ३८७।

कार्यस्थगन प्रस्ताव---

श्री राजनारायण की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बंध में——की सूचना।

खं० १३६, पु० १२५-१२७।

काशीप्रसाद पंडिय, श्री---

ब्रेखिये, "प्रश्नोत्तर"।

काशी राज्य--

प्र० वि०—विलोनीकरण के पश्चात्
—क कर्मचारियों का सरकारी
नौकरी में लिया जाना। खं० १३६,
प्० २८३–२८४।

काइतकारों---

प्र० वि०-- बनारस जिले के शिकमी -----की बेदखली। खं० १३६, प्० ५-६।

किसान-

प्र० वि०—बारावंकी जिले के भूमिधर ——। खं० १३६, पृ० २६।

किसानों--

प्र० वि०—खाम स्टेट कोटद्वार तराई व । भावर से —— को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, प्०१६।

प्र० वि०—जिला रायवरेली के थाना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम वनपुरवा मजरे रंजीतपुर के——में झगड़ा ग्रीर उसमें गिरफ्तारियां। सं० १३६, पृ० ३७१-३७२।

कुंग्रों का निर्माण-

प्र० वि०—जिला बलिया में हरिजनों के लिए मकान तथा पीने के पानी के लिए सहायता एवं—— । खं० १३६, प्० ३८७–३८८।

कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विघेयक, १६५४। खं० १३६, पृ०४७, ५०—५१,१३२—१३३, ३०२,३०३,३०४।

कृपाशंकर, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
विशेयक, १६४४। खं० १३६, पृ०
३७-३६, ४७, ४८-४६, १३४,
१३६-१४०, ३०६, ३२६, ३२६,
३३०, ३३३।

कृषकों---

प्र० वि०—जिला मुक्सरनगर में—— को ट्रैक्टरों के लिए तकाबी। खं० १३६, पृ० १७।

कृषि-टैक्स---

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा———। खं० १३६, पृ० २९।

कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री--

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

कृष्णशरण ग्रायं, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पू० २६८।

केशभान राय, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विभेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ६१–६२।

केशवगुप्त, श्री---

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पु० ४०५-४०६।

कैदियों---

प्र० वि०—जौनपुर जेल में सजायाक्ता विचाराघीन तथा जेल से भागे हुए-तथा उनमें हरिजनों की संख्या । खं० १३६, पृ० ३७७।

प्र ० वि० — देवरिया लाक-घर में —— की जगह। खं० १३६, पृ० ३७६।

कोट(---

प्र० वि०—फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का—— । खं० १३६, प्० २८६।

कोयले--

प्र० वि० — फिरोजाबाद की लाइ म फैक्ट्री को — का कोटा। खं० १३६, पृ० २८६।

क्षति ---

प्र० वि०—-जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से----खं० १३६ पृ० ६-- ।

प्र० वि०—वनारस जिले के कसवार राजा परगने में झे:ले से———। खं० १३६, पू० १५।

प्र० वि०—बस्ती जिले में ग्रनेक गांवों की वर्षा से—— । खं० १३६, प्०२६।

प्र० वि०—मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में———। खं० १३६, पृ० २८६—२८७।

क्षेत्रफल---

प्र० वि०—पकड़ी मउनियां, जिला गोरलपुर के वन का ———। लं० १३६, प्०२८४।

ख

खराबी--

लाउडस्पीकर ग्रौर पंखों की—। स्तृं० १३६, पू० १२५।

खंदी--

प्र० वि०—शारवा नहर, पुरवा जांच जिला रायबरेली में——के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पू० ११२।

खाद्य विभाग--

प्र० वि०-----में कर्मचारियों की छटनी। खं० १३६, पृ० १८५-१८६।

खाम स्टेट---

प्र० वि०——कोटद्वारा (गढ़वाल) ——-में जमीन का वितरण। खं० १३६, पृ० १८–१६।

लामस्टेट कोटद्वार---

प्र० वि०— ———तराई व भावर से किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार । खं० १३६, पृ० १६।

खुशीराम, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

खेती को हानि--

प्र० वि०—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से। खं० १३६, पृ० १०।

स्यालीराम, श्री—— देखिये, "प्रक्तोत्तर"।

ग

गंगाधर मैठाणी, श्री—— . देखिये "प्रश्नोत्तर " ।

गंगा प्रसाद सिंह, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गजेन्द्र सिंह, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २१७–२२०।

गज्जूराम—भी देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गन्ना--

प्र० वि०—िमलों में——न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति। खं॰ १३६, पृ० २८६-२८७।

गन्ना फैक्टरियों--

प्र० वि०——— के दुर्गन्धित तथा विषैते पानी से उत्पन्न दुष्परिणाम की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिये एफ्लुएंट ट्रोटमेंट प्लंट की स्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८२।

गन्ने--

प्र० वि०— ——का मूल्य निश्चित करने के निये सम्झेलन । एंट १३६, प्र २६२-२६३।

प्र० वि०———के मूल्य का निर्धारण। । लं० १३६, पृ० २६५–२६६।

तबन--

प्र० वि०—वनारत जिले में जमीवारी उन्मूलन कीय में——— १ छं० १३६. प्०२६।

गर्को का नाला--

प्र० वि०-जिला मधुरा की नहमीन छाना में -----निकालने का कार्य । खं० १३६. पु० ११७-११८ ।

गांव सभा---

प्र० वि०-----की जनीनों को प्राइमरी व ज्ञितपर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६६।

गांवों--

प्र० वि०--बस्ती जिले में अनेक--को वर्षा से क्षति। खं० १३६, पृ० २६।

विरफ्तारी--

प्र० वि०--ग्राजमगढ़ जिले में का धुनिस्टों की----। खं० १३६, पृ० ३६१।

कानपुर में श्री राजनारायण की ——— के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की श्रवहे-लना का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

प्र० वि० — देहली दरवाजे, स्रातीगढ़ में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की ———। खं० १३६, पृ० ३८१।

श्री नारायणदत्त्रं तिवारी की----से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रक्त पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २६६। श्री राष्ट्रप्त इस निवासी जी———से सर्वेष्ट्र विदेश कियान के उर्देश पर जिल्लाक्षित्रण कक्षिति के प्रतिदेश पर विचार गाउँ १३६, दृष्ट स्ट्रेर्स उर्देश

श्री नागाप्रकल जिल्ही की———हे माहकु हिनेदाधियात ही, सहहेलमा के हिराय के हिनेदाधियार नमिति के प्रतिहेदर पर हिन्नार १ एं ७ १३६. मुठ ३७६ – ४०१ ४०५ – ४२६

श्री नारायम क्या निवारी हारा एठाये गारे विनोप धिकार को प्रदाय से सरकत्र विकास, धिकार स्टिनि को प्रतिकेदन पर जिल्लारार्थ नसद निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः———। खं० १३६. पु० ३२।

श्री राजनारायण की पूर:——के सम्बन्ध में लूचना । खं० १३६. पृ० ३१।

र्नुटों, वरमानी--

प्र० त्रि०-- उप्रत्य जिले से धानेदार करल ग्रीर डाके, तथा--- ग्रादि की मूची। एवं० १३६, पृ० उदय।

गुड़---

प्र० वि०—नीरा मे-—-दनारे की योजना। खं० १३६, पृ० २८६।

गुप्तचरगुलिस--

प्र० वि०———— इन्सपेक्टरों और निवित्र पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन-क्रम में अन्तर। खं० १३६, पृ० ३६२।

.गुप्तार सिंह, थी— देखिये "प्रश्नोत्तर"। गुरु प्रसाद, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गृह निर्माण--

प्र० वि० -- जौनपुर जिले में बाढ़-पीड़ित ग्रामों को -- -- के लिये सहायता। खं० १३६, प्०२३६।

गृह व्यवस्था--

उत्तर प्रदेश श्रौद्योगिक---विधेयक, १९५४। खं० १३६, ए० ३३।

गेंदा सिंह, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
विधेयक, १९४४। खं० १३६, पृ०
३४, ४३-४४, ६३-६४, ६७-६८,
६६, ७३, १२७-१२६, १६७-१६६,
१६६-२०४, २२०-२२६, ३१२३१४।

विद्यान सभा के सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी पर श्रमियोग श्रौर उनकी पेशी। खं० १३६, पू० ३६६–३७१।

श्री नारायणदत्त की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० २९६, ४०१-४०३ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रति-वेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की ग्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री ग्रध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, प्० ३८६-३६०। गोमती---

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——की बाढ़ से क्षति । खं० १३६, पृ० ६-- ।

गोली--

प्र० वि०—देहली दरवाजे ग्रलीगढ़ में ——चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी खं० १३६, पृ० ३८१।

गोवर्धन तिवारी, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर"

गोविन्व वलल्भ पन्त, श्री---

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रक्त पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन । खं० १३६, पृ० २६६ ।

श्री नारायणवत्त तिवारी की गिरण्तारी
से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय मे विशेषाधिकार
समिति के प्रतिवेदन पर विचार।
र्लं० १३६, पृ० ३६७-४०१, ४०३,
४०८, ४२५-४२६।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी खं० १३६, पू० ३२ ।

सदन के ग्रागामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना । खं० १३६, पृ० ३२।

ग्राम नियोजन---

प्र० वि०---उत्तर प्रवेश नगर तथा -----पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७७--२७८ ।

ग्राम रक्षा समितियों---

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——— का संगठन श्रौर ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस । खं० १३६, पु० ३८६ । न्नाम समितियां---

प्र० वि०—एटा जिले में ——ग्रौर उनका डाकुग्रों से मुकाबिला । स्रं० १३६, पृ० ३८४ ।

ग्रामीण क्षेत्रों---

प्र ० वि० में पीने के पानी की व्यवस्था। खं० १३६, पू० १८८।

ग्रामों---

प्र० वि० सरकार का के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार । खं० १३६, पृ० ३८४।

घ

घनश्याम दास, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

घोड़ा रोशन घास-

प्र० वि०—जौनपुर जिले में "— को नष्ट करने का प्रबंध । खं० १३६, पृ० १८ ।

च

चन्द्र सिंह रावत, श्री— बेखिये "प्रश्नोत्तर" ।

> उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १५१–१५२ ।

> श्री नारायण दत्त तिवारी की गिफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की ग्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पू० ४२३-४२४ ।

चरण सिंह, श्री---

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६,पृ० ४१८–४२३।

चाल-

प्र० वि०—मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा—की गई बर्से। खं० १३६, प्० ३०-३१। चिकित्सालय भवन--

प्र० वि०—नानपारा तहमील थाना खेरी घाट के पास——का निर्माण। खं० १३६, पृ० १६०।

चित्तर सिंह निरंजन, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> प्र० वि०—सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालीन) पुलिस स्टेशन से हिस्ट्री-शीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं०१३६,पृ०३८४।

चिरंजी लाल जाटव, श्री देखिये "प्रक्रोत्तर"।

चोरियां---

प्र० वि०—झांसी शहर (म्यूनिसिपल क्षेत्र) में——ग्रीर उनकी रिपोर्ट। खं०१३६,पृ०३८४।

प्र० वि०—याना मेंहदावल जिला बस्ती में ———डर्क तियां भ्रौर हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३७३।

प्र० वि०—मऊ थाना (ग्राजमगढ़) मॅ—अप्रौर डकैतियां। खं० १३६, पृ० ३८८।

छ

छटनी--

प्र० वि०—खाद्य विभाग में कर्मचारियों की———। खं० १३६, पृ० १८५— १८६।

स्रूट--

प्र० वि० --- लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में ----। खं० १३६, पृ० २८।

ज

जंगली गायों व बैलों---

प्रविश्—सांसी जिले में-फसल को हानि । खं० १३६, पृ० १६।

जगन्नाच प्रसाद, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर"

जगन्नाथ मल्ल, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विघेयक, १९४४। खं० १३६, पृ० १४२।

जनाने ग्रस्पताल---

प्र० वि०—सैंबपुर में——— - की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पू० १०२।

जमींदारी उन्मूलन कोष--

प्र० वि०--बनारस जिले में----में गबन। खं० १३६, प्०२८।

जमीन--

प्र० वि०—कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में——का वितरण । खं०१३६, प्०१६–१६।

जमीर्नो--

प्रव विव्यागित सभा की ----को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को दें का विचार। खंब १३६, पृष्ठ २६८।

जयपाल सिंह, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) ृविधेयक, १९४४। खं० १३६, पृ० ५३-५४, ५६, ५७।

जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विघेयक, १९५४। खं० १३६, प्०४६,६२।

जल-व्यवस्था---

प्र० वि०—कनखल की कृष्णनगर कालोनी मॅं———। खं० १३६, पृ०१७८— १७६।

ज्याङी---

प्र० वि०—हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये———। खं० १३६, पृ० ३८३।

जूनियर स्कूलों--

प्र० वि० --- गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व---को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

जूनियर हाई स्कूलों--

प्र० वि०--फैजाबाद के प्राइवेट----को सहायता देने का ग्रादेश। खं० १३६, पृ० ३७९।

जूरी प्रथा--

प्र० वि०----के संबंध में भारत सरकार का श्रादेश। खं० १३६, पृ० १०२।

जेल--

प्र० वि० — जौनपुर — में सजायापता विचाराधीन तथा जेल से भागे हुये केंदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पु० ३७७।

जेल ट्रेनिंग स्कूल--

प्र० वि०—ज्ञालनक ——के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के ग्रध्ययन के लिये यात्रा और उस पर व्यय । खं० १३६, पृ० ३८१-३८२।

जोरावर वर्मा, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंधायत राज (संशोधन) विषयक, १९४४। खं० १३६, पृ० ३४, ४१-४२, ६१,१४८, ३०४-३०७, ३०८-३०६, ३१४-३१६, ३२४-३२६, ३२७, ३२८-३२६, ४२६-४२८।

श्री नारायण बत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिबेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७।

सदत के स्रागामी कार्यक्रम के संबंध में सुचना। खं० १३६, पू० ३२। झारखंडे राय, श्री-देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विद्येक, १९५४ । खं० १३६, पृ० ३१६—३१७ ।

झोल---

प्र० वि०—विखरा (वस्ती) ----से नहर निकालने का कार्य। खं० १३६, प्० १०७-१०८।

ਣ

टी० बी० के टीके--

प्र० वि०--जौनपुर जिले में----। खं० १३६, प्० १८१-१८२।

टेंडर---

प्र० वि०—कानपुर शहर में ईधन सप्लाई के—— । खं० १३६, पु० १६०-१६१।

टेस्ट वर्क-

प्र० वि०—देवरिया जिले मे तरया सुजान के——का बन्द होना। खं० १३६, पृ० २४–२५।

प्र० वि——पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें। खं० १३६, प्०२२-२४।

ट्रांस राप्ती क्षेत्र-

प्र० वि०---जिला गोंडा में ------में विकास कार्य की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० २७४--२७६।

ट्रैक्टरों---

प्र० वि०—जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को ——के लिये तकाबी। खं० १३६, पृ० १७। डकें(न्य; ---

प्र० वि०—-प्रहंखाबाद के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गत वर्ष ———, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां। खं० १३६, प्०३८३–३८४।

प्र० वि०—मऊ याना (ग्राजमगढ़) में चोरियां ग्रोर ———। खं०१३६, पृ० ३८८।

डकैतियां और हत्यायें--

प्र० वि०—याना मेंहदावल जिला बस्ती में चोरियां, ——। खं० १३६, पृ० ३७३।

डकंतियों--

प्र० वि०—-जाँनपुर जिले के ग्राम पांडेपुर तथा समस्त जिले में — —की संख्या। खं० १३६, पृ० ३६०-३६१।

डक तियों व कत्लों---

प्र० वि०—न्नागरा जिले में ——की दर्ज रिपोर्ट । खं० १३६, पृ० ३७८– ३७६ ।

डकैती--

प्र० वि०—कारीपाकर (सीतापुर) में ——ग्रीर उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पू० ३८७।

डाकुग्रों—

प्र० वि०—एटा जिला मे ग्राम समितिय ग्रोर उनका — से मुकाविला। खं० १३६, पृ० ३८५।

डाके--

प्र० वि०—मौजा डीह, जिला रायबरेली में——से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, प्० ३७६।

डाके ग्रीर कत्ल-

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक थाने के झन्तर्गत ——। खं० १३६, पु० ३६४-३६४। डेक---

प्र० वि०—बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राष्ती नदी पर——बनाने का बिचार। ख० १३६, पृ० १०५— १०६।

त

तकावी--

प्र० वि०—जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को द्रैक्टरों के लिये——। खं० १३६, पृ० १७।

तराई व भावर---

प्र० वि०—-खाम स्टेट कोटद्वारा ——से किसानों को हिस्सेवार बनाने का विचार । खं० १३६, पृ० १६ ।

तराई स्टेट फार्म---

प्र० वि०——के संबंध में पूछताछ। खं० १३६, पृ० द-६।

तहसील---

प्र० वि०--पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत रुड़की ---में कार्य। खं० १३६, पु० २७७।

तहसीलदारों---

प्र० वि०—महोवा एवं चरलारी के ——द्वारा कागजात में सेहत। खं०१३६,पृ०२६-३०।

ताड़ी श्रौर नीरा---

प्र० वि०--निर्मद्य क्षेत्रों में ---- बेचने की सुविधा। खं० १३६,पृ० ११५।

तेज प्रताप सिंह, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रवेश पंचायत राज (संशोधन) विघेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १९६-१९८, १९६, ३०६-३१०, ३२१-३२२, ३२६, ४३१।

तेजा सिंह, श्रीं—-देखिये "प्रश्नोत्तर"। थाना कर्मचारियों--

प्र० वि०—थाना ईसानगर जिला सीरी का भवन ग्रौर-----के लिये क्वार्टर। खं० १३६, पृ० ३७३-३७४।

थाने--

प्र० वि०—गाजीपुर के बिरनों — की इमारत नई बनवाने की योजना। खं० १३६, पृ० ३७४।

प्र० वि०—चन्दौसी (मुरादाबाद) में — के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३८४–३८६।

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक ——में पुलिस कर्मचारियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

₹

दरॅ—-

प्र० वि०—टेस्ट वर्ग्स पर दी जाने वाली मजदूरी की———। खं० १३६, प्० २२–२४।

दल बहादुर सिंह, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दाताराम, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दिवाली---

प्र० वि०—हमीरपुर में गत वर्ष ——के भ्रवसर पर पकड़े गये जुग्राड़ी। खं० १३६, पृ० ३८३।

दीनदयालु शास्त्री, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दुकार्ने---

प्र० वि०—जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की——। खं० १३६, पृ० १२५। देवकी नन्दन विभव, श्री-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९४४। खं० १३६, पु०२१३-२१४।

देवदत्त मिश्र, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोघन) विषयक, १६५४। सं०१३६, पृ० २१४-२१७।

देवमूर्तिराम, श्री

देखिये "प्रक्नोत्तर"।

देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री---टेखिये "प्रश्नोत्तर"।

देशी व विलायती शराब—

प्र० वि० — जिला मुरादाबाद में —— की दुकानें। खं० १३६, पृ० १२४।

द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विघेयक, १९५४। खं० १३६, पु० ६०–६१।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरयतारी से संबद्ध विशेषाचिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१३-४१५।

देखिये "प्रक्नोत्तर" ध

षमंदत्त वैद्य, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर।

धर्म सिंह, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> उत्तर प्रदेश पचायत राज (संशोधन) विषयक, १६४४। खं० १३६, पू० ३३१-३३२,४३४ ४३४-४३६।

धुनाई---

प्र० वि०—मऊ (म्राजमगढ़) में रंगाई व — का कारसाना । सं० १३६, प्० २८४। न

नगर---

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश——नया ग्राम नियोजन पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७७–२७८ ।

नगरपालिका---

प्र० वि० में तहायक हाजिरी श्रफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये सरकारी श्रादेश। खं० १३६, प्र० ३८२ — ३८३।

प्र० वि०—हायरस नगर में पैविलियन के लिये—को ग्रांट । खं० १३६, प्० ३८१।

नित्ययां---

सं० १३६, पृ० ७४-६४, १७३, २३६-२६०, ४३७-४३८।

नत्य सिंह, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नरेनी-कालिजर सड़क-

प्र० वि०—बांदा जिले में — पर पुल निर्माण योजना। सं० १३६, पु० ११०।

नलकूप--

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले——। खं० १३६, प्०१२३।

प्र० वि०—हायरस तहसील में काले वाले कोव——। खं० १३६, पृ० १२२।

नलकूपों--

प्र० वि०—ग्राजमबद् तथा गाओपुर जिलों के सिये——का वितरण। सं० १३६, पृ० १२४—१२५।

प्र० वि०—तहसील न्हुड़ विला सहारनपुर में का कार्य। सं० १३६, पृ० ११८।

प्र० वि० पंचवर्षीय यहेनना के मन्तर्पत बुलन्दसहर जिले में का निर्माण । सं १३६, पृ० १०३-१०४।

[नलक् शें--]

प्र० वि०——मुजपफरनगर जिले मे———— का निर्माण। खं०१३६,पृ०१११— ११२।

नवलिक्शोर, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विभेयक, १९४४। खं० १३६, पु० २१०-२१३।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, प्० ४१२-४१३।

नष्ट---

प्र० वि०--जौनपुर जिले में "घोड़ा रोशन घास" को ---- करने का प्रबन्ब--। खं० १३६, पृ० १८।

नहर--

प्र० वि०—तहसील सलोन, जिला रायबरेली में——के विस्तार की ग्रावश्यकता। खं०१३६, प्०१०७।

प्र० वि॰——बिखरा (बस्ती) झील से निकालने का कार्य। खं० १३६, प० १०७—१०८।

प्र० वि०---सुल्तानपुर जिले में---की खुदाई के लिये द्यिष्ठत भूमि। खं १३६, पृ० १०४-१०५।

नागेक्वर द्विवेदी, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

माम-मिर्वेशनों----

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त ——के संबंध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७–२६४।

मारायण बत्त तिवारी, श्री---वेजिये "प्रक्लोत्तर"।

की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषा-षिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिबंदन। खं० १३६, पूर्व २६६। ——की गिरफ्तारी से संबद्घ विशेषा-धिकार की स्नवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३६०-४०४, ४०५-४२६।

की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषा-धिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २६४–२६८।

च्यारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रक्त से संबंद्घ विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विवासर्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनासम्ब की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

नाव-दुर्घटना---

प्र० वि०—गंगा नदी में जबहीं घाट पर ———। खं० १३६, पृ० १८७— १८८।

नियमों तथा ग्रादेशों---

प्र० वि०—भूमि संबंधी समस्त ——के सहित प्रकाशन की ग्रावश्यकता। खं० १३६, प्०६।

नियोजन---

निर्धारण---

प्र० वि०---गन्ने के मूल्य का---। लं० १३६, पृ० २६४--२६६।

निर्मद्य क्षेत्रों---

प्र० वि०——में ताड़ी ग्रौर नीरा बेचने की सुविधा। खं० १३६ प्० ११४।

निर्माण---

प्र० वि०—ग्राजमगढ़ जिले में मऊ कासिमाबाद सङ्क का —— । व्यं० १३६, पू० १२४। प्रः वि०--- बुलन्देशहर जिले के स्रहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान

द्वारा —-। खं० १३६, पृ० २७२-२७३।

प्र० वि०--मधुबन (म्राजमगढ़) में एलोपैथिक ग्रस्पताल का ----। खं० १३६, पृ० ३४६-३६०।

प्र० वि०—मिर्जापुर सीमेट फैक्ट्री के ——के लिय विदेशी सलाहकार। खं० १३६, प्० २६६ – २६८।

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में नल-कूपों का——। खं० १३६, पृ० १११–११२।

प्र० वि०—रितणी लाल-बनजिया देवी सड़क पर लट्ठों के पुल का——। खं० १३६, पृ० १२२-१२३।

निर्माण कार्य-

निर्वाचन---

वित्त सिमिति सार्वजिनिक लेखा सिमिति, । प्राक्कलन सिमिति तथा विभिन्न स्थायो । सिमितियों के——में प्राप्त नाम— । निर्देशनों के संबंध में सूचना । खं० १३६, पू० २८७–२६४ ।

स्थायी समितियों के ——— से नाम वःपस लेने के समय में वृद्धि की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०४-४०५।

निर्वाचन का कार्यक्रम— कतिपयस्थायीसमितियों के—— । खं० १३६, पृ० १७२।

नीरा--

प्र० वि०--ते गुड़ नाने की योजनाः। सं० १३६, प्० २८६ ।

नीलाम---

प्र० वि०—जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का — । खं० १३६, पु० १५-१६। नेकराम शर्मा, श्री--

श्चनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा "प्रश्न नहीं उठता" कहने परश्री श्रद्यक्ष का निर्णय । सं० १३६, पु० १२६ ।

नेत्रपाल सिंह, श्री— देखिये 'प्रश्नोत्तर"

नेहरू लियाकत पंक्ट--

प्र० वि०——के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में ग्राने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७४–३७५।

नौरंगलाल, श्री---

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पु० ३६७।

4

पंचवर्षीय योजना--

प्र० वि०——के ग्रवीन लखनऊ जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पृ० २७३–२७४।

प्र० वि०—के ग्रन्तगंत बुलन्दन्नहर जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १३६,प० १०३–१०४।

प्र० वि०—के ग्रन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० २७४-२७४।

प्र० वि० के ग्रन्तगंत रुड़की तहसील मे कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

प्र० वि०—द्वितीय — । खं० १३६, प्र० २८६।

पंचायत के सरपंच--

प्र० वि०—देवरिया जिले में दुदेही श्रदालत ——की मुझलली। सं० १३६, पृ० १८०–१८१।

पंचायत घरों--

प्र० वि०—को लिये "श्रावाज" रेडियो । खं० १३६, पृ० १८७ ।

पंचायत मंत्रियों---

प्र० वि०—बिलया में——को वेतन मिलने में विलम्ब। खं० १३६, प्०१८०।

पंचायत राज--

प्र० वि० इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान ग्रौर उन पर नियुक्तियां। खं० १३६, पृ० ३४९।

उत्तर प्रदेश ——— (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३-७३, १२७-१७१, १६२-२३५, -२६६, ३००-३३४, ४२६-

४३६।

उत्तर प्रदेश —— (संशोधन) विधेयक, १६५४ को १२ मई, १६५४ तक पारित करने के संबंध में प्रस्ताव को सूचना। खं० १३६, पृ० ४०५।

पंचायतों के लेखों-

प्र० वि०—राज्य की-——की ग्राडिट व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १७६–१८०।

पंडित के ताल---

प्र० वि०—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार ——में पानी भर जाने से खेती को हानि। खं० १३६, प्०१०।

पक्की---

प्र० वि०—चौराहा कासगंज सड़क को —करने की झावश्यकता। खं० १३६, १ प्० १२०-१२१।

पक्की सड़क---

प्र० वि०—जिला बदायूं में सहसवान से गिझोर तक—की भ्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० १८४।

पक्की सड़कें---

प्र० वि०—जिला हमीरपुर में निर्माण की गई———। खं० १३६, पृ० १२२। पद—

> प्र० वि०—सरकार का ग्रामों के मुिंबयों के——को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३८४।

पद्मनाथ सिंह, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९४४। खं०१३६, पृ० १४५-१४६।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४०६-४०८।

परमिट--

प्र० वि०—कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के——। खं० १३६, पृ० ३०।

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री— देखिये प्रश्नोत्तर"।

परीक्षाश्रों---

प्र० वि०—हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की——में भ्रनुचित तरीकों का प्रयोग। खं० १३६, पृ० २६६-२७०।

पशु-चिकित्सालय---

प्र० वि०—मिडियाह्ं तहसील में—— की श्रावश्यकता । खं० १३६, पु० १० ।

पश्चिमी क्षेत्र---

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के——में बनने वाले नलकूप। खं०१३६,पृ० १२३।

पहाड़ी क्षेत्रों---

प्र० वि०—मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के——के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०-२८१।

वाकिस्तान--

प्र० वि०—नेहरू नियाकत पंक्ट के बाद
— से उत्तर प्रदेश में ग्राने वाले
तथा यहां में जाने वाले मुसलमानों
की मंख्या। खं० १३६. पृ० ३७४-

पानीराम, श्री-⊶

देखिये "प्रक्तनोत्तर" ।

पानी--

प्र० वि०—देवरिया जिलेके ग्राम बेलपार पंडित के ताल मे——भर जाने । से खेती को हानि। खं० १३६. प० १०।

पो० ए० सी०--

प्र० वि॰—नैपाल भेजी गयी ——की यूनिटों पर व्यय। खं०१३६,पृ०३७८।

पो० डब्ल्यू० डी०---

प्र० वि०—जिला बोर्ड बस्ती को—— द्वारा वापस की हुई सड़कें। खं० १३६, प्० ११०-१११।

पोने के पानी-

प्र० वि०—ग्रामीण क्षेत्रों में—की व्यवस्था। खं०१३६,पृ०१८८।

पुत्तूलाल, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पुरवा ब्रांच--

प्र० वि०—शारदा नहर, ——, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

पुल—

प्र० वि०—जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर——की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० ११४।

प्र० वि० — बांदा जिले में नरैनी कालिजर सड़क पर —— निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

पृत्तिम---

प्र० वि०—गाजीपुर की जनानया नहमील में ——हारा चलावे गावे मुक्तदमें श्रोर उनमें सहावे ख १३६. पृष्ट ३७२

प्र० वि०—गाजीपुर शहर से सन्दर ग्रीर सम्बद्ध का झगड़ा तथा—के विरद्ध शिकायन। खं०१३६ प्र०३७१

प्र० वि०—जिला रायवरेली के थाला मरेनी की——त्या ग्राम वनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किमानों में झगड़ा ग्रीर उसमे गिरफ्तारियां। खं० १३६. प्० ३७१–३७२।

प्र० वि०—डाक् मान मिह के गिरोह का झांमी की ———— के घेरे में निकलना। खं० १३६, पृ० ३७५— ३७६।

पुलिस कर्मचारियों--

प्र० वि०—प्रनापगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में — की संख्या। खं०१३६, पृ० २७७।

पुलिस चौकी--

प्र० वि०—मेंहदावल (बस्ती) के कछार में जनहित एवं कृषि रक्षा के लिये ——। खं० १३६, पृ० ३७३।

पुलिस विभाग---

प्र० वि० में भ्रावकारी विभाग से भ्रागत भ्राई० पी० एस० भ्रफसरों के प्रोबेशन की भ्रविध। खं० १३६, पृ० ३६८।

पुलिस सब-इन्सपेक्टर---

प्र॰ वि०—जिला मुरादाबाद में चार वर्षी से श्रधिक समय वाले ——— व इन्सरेक्टर। खं० १३६, पृ० ३६४।

पुलिस स्टेशन--

प्र० वि०—मुभाषनगर मे सम्बद्ध कोंच (जालौन) ——से हिस्ट्रोशोटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

पुस्तकालय समिति---

----के रिक्त स्थानों की पूर्ति। खं०१३६,पृ०३१। पूछ्रनाछ--

प्र० बि०--तराई स्टेट फार्म के संबध मे---। खं० १३६, पृ० प्र-६।

पूर्ति--

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की ——— ' खं० १३६, पृ० ३१।

पशन--

प्र० वि०--राजनैतिक पीड़ितों को---। खं० १३६, प्० २८४।

पंदावार--

प्र० वि०—— स्रन्न की ——— मे वृद्धि । खं० १३६, पृ० १७ ।

पैविश्लियन--

प्र० वि०—हायरस नगर में ———के लिये नागरपालिका की ग्रांट। खं० १३६, पृ० ३८१।

प्रजा सोशलिस्ट पाटा---

प्र० वि०—-प्राम श्रसलाई (श्राजमगढ़)

मे----द्वारा स्रायोजित सभा का
भंग किया जाना। खं० १३६, पृ०
३६१-३६४।

प्र० वि०———, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रृंगार दुबे पर ग्राक्रमण की जांच। खं० १३६, पृ० ३६८—३६६।

प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क---

प्र० वि०—— पर व्यय। खं० १३६, प्०१२३।

प्रतिवेदन---

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का---। खं० १३६, पृ० २६६।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्घ विशेशिधकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के ——पर विचार। खं०१३६, पृ०२६४-२६८।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के ——पर विचार। खं० १३६, पृ० ३७९-४०४, ४०५-४२६। श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से संबद्ध विशेषाधिकार समिति के — पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ०३२।

प्रबन्ध--

प्र० वि०— जौनपुर जिले में ''घोड़ा रोजन घास'' को नष्ट करने का ——। खं० १३६, पृ० १८।

प्र० वि०—तहसील जसराना, जिला मैन-पुरी में सिचाई का— । खं० १३६, प्० ११६।

प्रयोग--

प्र० वि०—हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं में ग्रनुचित तरीकों का———। खं०१३६, पृ० २६६– २७०।

प्रश्न--

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के—— से संबद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिर- फ़तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

'प्रक्न नहीं उठता'—

स्रनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा — कहने पर श्री स्रध्यक्ष का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१-१२२।

प्रश्नोत्तर

इसराहल हक, श्री--

फिरोजाबाद की लाइम फेक्ट्री को कोय ने का कोटा। खं० १३६, पृ० २८६। सब-डिविजनल में जिस्ट्रेट फिरोजाबाद का हेड क्वार्टर। खं० १३६, पृ० २८४—२८६।

उमाशंकर, श्री---

म्राजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूयों का वितरण। खं० १३६, प्० १२४–१२५। कन्हैया लाल वाल्मोकि, श्री--

लखनऊ कलेक्टरी में हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की भर्नी । खं० १३६, पृ० २१--२२

कमला सिंह, श्री-

मैदपुर में जनाने स्रम्पताल की स्रावत्य-कता। खं० १३६, पृ० १०२।

काशीप्रसाद पांडेय, श्री--

मुलतानपुर जिले में सहकारी नलकूप। खं० १३६, पृ० १०४।

कृष्ण चन्द्र शर्माश्री---

डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना। खं० १३६, प्० ३७५-३७६।

कृष्णशरण ग्रार्य, श्री---

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में ग्रोले से हानि। खं० १३६, पृ० २७।

खुशोराम, श्री---

जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का नीलाम। खं० १३६, पु० १५–१६।

ख्यालीराम, श्री--

जिला मुरादाबाद में चार वर्षों से अधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर। खं० १३६, पृ० ३८४।

गंगाघर मैठाणी, श्री--

कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का वितरण। खं० १३६, पृ० १८–१६।

नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में ध्रानेवाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या (सं० १३६, पृ० ३७४-३७४।

गंगाघर शर्मा, श्री---

कारीपाकर (सीतापुर) में उकती स्नौर उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पु० ३८७। गंगः प्रसाद सिंह, श्री---

जिला बिलया में इरिज्ञों के लिये सकान तथा पीने के पानी के लिये सहायना एवं कुओं का निर्माण वंटर्डर, ए० ३८७–३८८।

बिल्या में पंचायत मंत्रियों को बेतन मिलने में बिलम्ब । खं० १३६, पूष्ठ १८०।

गज्जूराम. श्री--

जिला झांमी में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुन की ग्रावक्यकता । खंब १३६. यु० ११५ ।

गुप्तार मिह, श्री--

जिला रायवरेली के थाना नरेनी की
पुलिस तथा ग्राम वनपुरवा मजरे
रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और
उसमें गिरफ्तारियां। खं० १३६,
पृ० ३७१–३७२।

गुरु प्रमाद, श्री --

मुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि। खं० १३६, पु० १०४-१०४।

गेंदा सिंह, श्री--

गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये सम्मेलन। खं० १३६, पृ० २८२ -२८३।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण। खं० १३६, पु० २६५-२६६।

टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें। खं० १३६, पु० २२–२४।

फर्रुलाबाद के थाना कायमगंज तथा कस्पिल में गत वर्ष डकंतियां, कल्ल, राहजनी तथा चोरियां। खं० १३६, पु० ३६३-३८४।

बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली। खं० १३६, पृ० ५–६।

भूमि संबंधी समस्त नियमों तथा श्रादेशों के संहित प्रकाशन की श्रावञ्यकता। खं० १३६, पु० ६। [प्रक्तोत्तर]

गोवर्द्धन तिवारी, श्री--

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ग्रनुदान में कटौती। खं० १३६, पृ० ३८४।

घनश्याम दास, श्री--

बाराबंकी जिले के भूमिधर किसःन। खं०१३६,पृ०२६।

चन्द्र सिंह रावत, श्री--

खाम स्टेट कोटद्वारा तराई व भावर से किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १६।

चिरंजी लाल जाटव, श्री --

एटा गंजडुंडवाड़ा सड़क का सुधार। खं० १३६, पृ० १८६।

जगन्नाथ प्रसाद, श्री--

थाना ईसानगर जिला खेरी का भवन ग्रोर थाना कर्मचारियों के लिये क्वार्टर। खं० १३६, पृ० ३७३-३७४।

जोरावर वर्मा, श्री---

पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल। खं० १३६, पृ० २८४।

महोबा एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत। खं० १३६, प्० २६–३०।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन। खं० १३६, पृ० २८४।

विधायक निवासों के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में हरिजनों को न लेना । खं० १३६, पृ० ११३ ।

झारखंडेराय, श्री---

ग्राजमगढ़ जिले में कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पू० ३६१।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छटनी। खं० १३६, पृ० १८५–१८६।

गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृं० र्रहदं। नैपाल भेजी गई पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७८।

बस्ती जिले में राप्ती के किनारे बने हुये बांघ पर व्यय। खं० १३६, पृ० ११६-११७।

भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, प्० २८२।

भूदान यज्ञ में दी गई भूमि। खं० १३६, पृ० १०--१२।

विधान भवन को एयर कंडीशन्ड कराने की ब्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० १०१।

शिक्षा पुनः संगठन योजना के स्रन्तगंत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३७७–३७८।

तेज प्रताप सिंह, श्री--

जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत । खं० १३६, पृ० १२३।

तेजा सिंह, श्री--

श्रागरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांघ की श्रावश्य-कता । खं० १३६, पृ० ११८।

दल बहादुर सिंह, श्री--

तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहर के विस्तार की भ्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० १०७।

मौजा डीह, जिला रायबरेली ईमें डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, पृ० ३७६।

लखनऊ ग्रौर फंजाबाद डिबीजन के सुपरबाइजर कानूनगो। खं० १३६, पृ० १६–२१।

दाताराम, श्री---

तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में नलकूपों का कार्य। खं० १३६ पु० ११८। होन दयान् दास्त्री, श्री--

कन्नवन की कृष्णनार कार्रेली में जन-द्यवस्था: प्रेंट १३२. पृट १७२ १७६।

ंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत रहकी बहसील में कार्य। खं० १३६. पु० २७७ '

देवदन निश्र, श्री--

उटाव जिने में थानेवार करत ग्राँर डाके, तथा गुंडों, व्यमाशों ग्रादि की सूर्या। छं० १३६. पु० ३८८।

देवमूर्ति रानः श्री--

बनारन जिले के कमदार राजा परगने में ग्रोले ने क्षति। खं० १३६. प्०१५।

देवेन्द्र प्रताप नारायण निहः श्री-गोरखपुर जिने के पश्चिमी क्षेत्र में बनने
वाले नत्तकूप। खं० १३६, पृ०
१२३।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री--

गोरखपुर जित्ते में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७६-२८०।

गोरखपुर विश्वविद्यालय तंत्रंथी बिल । खं० १३६, पृ० ३८१।

धर्मदत्त वंद्य, श्री--

रामनगर में फूड प्रिजवेंशन फेक्ट्री की योजना। खं० १३६. पृ० २८५।

धर्म सिंह, श्री--

ग्रन्न की पैद:बार में वृद्धि। खं० १३६, प० १७।

पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों कः निर्माण। खं० १६६, पृ० १०३-१०४।

पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत बुन्तन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० २७४–२७५। द्वा है स्त्रहार प्रस्ति से जन्दी सड़क का श्रमदान द्वारा किसीय । त्वार १३६. पूर २३२ — २७३ (

बुक्स्वताहर जिले जे जायेश शामे हे जामसीत डाले प्रोर कत्म । विश १३६. प्रशास ३६४-३६१ ।

राज्य की पंच यंगी के लेखीं की ब्राडिट ट्यबस्यः , खंब १३६, पृष् १७६-१०० ,

नन्यू सिंह. श्री--

जिला बरेनी में बन्दूक राइकन ब्राट दिवान्वर के लाइमेस। खंट १३६. ए० ३७६-३७७।

नम्दकुमार देव वाहिएठ. श्री---

१६८७ में हायरम में सामूहिक जुर्माने की घनराद्यि श्रोर उसका व्यय किया जाना। खं० १३६, पू० ३८७।

हायरम तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप । खं० १३६, पृ० १२२।

नागेश्वर द्विवेदीः श्री--

जानपुर जिले में "घोड़। रोशन घास" को नब्ट करने का प्रवन्य। खं० १३६, पृ० १८।

जोनपुर जिले में वाड़-पीड़ित फ्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता । खं० १३६, पृ० २८।

नारायण दत्त तिवारी, श्री--तराई स्टेट फार्म के संबंध में पूछताछ । वं० १३६, पु० =-६।

नेत्रपाल सिंह, श्री---

चीराहा कासगंज सङ्क को पक्की करने की ग्रावस्यकता। खं० १३६. पृ० १२०-१२१।

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री--

लखनऊ जेल ट्रोनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के प्रथ्यपन के लिये यात्राश्रीर उस पर ब्यय । खं० १३६, प्०३८१–३८२ । [प्रइनोत्तार]

पातीराम, श्री---

निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी श्रौर नीरा बेचने की सुविधा। खं० १३६, पू० ११५।

पुत्तूलाल, श्री---

आगरा िले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३७८-३७६।

उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये १९५२-५४ में सोशल वर्क्स की नियुक्ति एवं उन पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८८।

लेबर श्राफिसर्स तथा कांसिलियेशन श्राफि सर्स की नियुक्तियां श्रीर उनमें हरिजनों का श्रनुपात। खं० १३६, पु० ३६४।

फजलुलहक, श्री---

राजकीय इन्टर कालिज, रामपुर में कक्षा ११वीं में कामर्स की शिक्षा। खं० १३६, पू० ३८६।

बद्रीनारायण मिश्र, श्री--

देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से खेती को हानि। खं० १३६, पृ० १०।

मथुरा जिले मे श्रमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना श्रौर कुछ श्रार्य समाजियों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६५-३६७।

बलदेव सिंह, श्री---

गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों श्रौर सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन ऋम में श्रन्तर। खं० १३६, पृ० ३८२।

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री --

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पू० २७५-२७६।

बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार । खं० १३६, पू० १०८–१०६। बलवन्त सिंह, श्री--

मुजफ्फरनगर जिले में नल-कपो का निर्माण। खं० १३६, पू० १११-११२।

मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलो की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २९।

बसन्त लाल शर्मा, श्री ---

नानपारा तहसील, थाना खेरीघाट के पास चिकित्सालय भवन का निर्माण। ख० १३६, पृ० १६०।

बहराइच जिले मे सरयू नदी से नहर निकालने की योजना। खं० १३६, पृ० १२३→१२४।

बाबूनन्दन, श्री--

जौनपुर जिले के ग्राम पांडेपुर तथा सम त जिले में डकैंतियों की संख्या। खं०१३६, पृ० ३६०-३६१।

जौनपुर जिले में कलेवशन विभाग के कर्मचारी। खं० १३६, पृ० १३-१४।

जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति। खं० १३६, पृ० ६-८।

जौनपुर जेल में सजायापता, विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

नीरा से गुड़ बनाने की योजना । खं० १३६ पू० २८६ ।

बाबूराम गुप्त, श्री--

एटा जिले में ग्राम समितियां श्रौर उनका डाकुओं से मुकाबला। खं० १३६, पु० ३८५।

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री— गंगानदी में जबहीं घाट पर नाव-दुर्घटना। खं० १३६, पृ० १८७–१८८।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री---

कानपुर शहर में ईंधन सप्लाई के टेंडर खं० १३६, पृ० १६०-१६१। । प्रदेशीय माललानों में प्राहिबिटेड बोर के हिययार तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० ३८०।

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री--

प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल। खं० १३६, प्० १७६।

भगवान सहाय, श्री-

मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, पृ० २६६–२६८।

भोलासिंह यादव, श्री-

गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमें ख्रौर उनमें सजाएं। खंड १३६, पृ० ३७२।

गाजीपुर शहर में मिन्दर ग्रौर मिस्जिद का झगड़ा तथा पुलिम के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, प्० ३७१।

मथुरा प्रसाद त्रिपाठो, श्री---

ग्रस्पताल के कार्यकाल में मेडिकल श्रफ-सरों को बाहर न जाने का श्रादेश। खं० १३६, पृ० १८४-१८४।

मदनमोहन उपाध्याय भी--

भेड़िया बालक रामू के लिये बलरामपुर ऋस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८६-१६०।

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री---

जिला हमीरपुर में निर्माण की गई पक्की सड़कें। खंड १३६, पृ० १२२।

सरकार का प्रामों के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पु० ३८४।

हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के ध्रवसर पर पकड़े गये जुब्राड़ी। खं० १३६, प्०३८३।

मलबान सिंह, श्री---

जूरी प्रथा के सम्बन्घ में भारत सरकार काम्रादेश। सं०१३६,पृ० १०२।

महीलाल, श्री— ग्राबकारी से ग्राय। खं० १३६, पृ० १०६–११०। चन्दौसी (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजें दिन के तीन हत्याएं। खंड १३६, पृ० ३८५-३८६।

जिला मुरावाबाद में देशी व विलायनी शराब की दूकानें। खंड १३६, ५० १२५।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहमील में स्रोलों में हानि। खं० १३६, पृ० २४।

मुश्ताक ग्रली, श्री---

जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की ग्रावश्यकता। म्वं० १३६, पृ० २८४।

यमुनासिह, श्री---

गाजीपुर कलेश्टरी में विचाराधीन मुकदमें।सं० १३६,पृ० १४–१५।

गाजीपुर के बिरनी थाने की इमारत नई बनवाने की योजना । खं० १३६, पृ० ३७४।

रघुराज सिंह, श्री---

जिला गोंडा की तहसील तरबगंज मे विकास कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री--

उत्तर प्रदेश नगर तथा प्राम नियोजन गर व्यय । सं० १३६, पृ० २७७— २७८ ।

जीनपुर जिले में प्राम रक्षा समितियों का संगठन भ्रौर प्रामों रक्षक को बन्दूक के लाइमेंस। खं० १३६, पू० ३८६।

जौनपुर जिले में टी० बी० के टीके। सं० १३६, पृ० १८१-१८२।

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुझाविजा। सं०१३६,पृ० ११७।

मिड्याह के अन्तर्गत सीतापुर प्राम में मिहला चिकित्सालय की मांग। सं०१३६, पु०१८२।

मडियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की ग्रावस्थकता। सं० १३६, पृ० १०।

[प्रश्नोत्तर]

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री---

बसन्त कन्या इंटर कालेज, कमक्षा, शहर बनारस का स्थानान्तरण। स्रं० १३८, पु० ३८७।

शिवराज सिंह यादव, श्री--

प्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १८८। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खं० १३६, पु० २८६।

राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी योजना । ख० १३६, पृ०१ - ६-१८७।

शिवस्वरूप सिंह, श्री---

तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में स्रोलों से हानि। खंड १३६, पृ० २६।

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री---

बांदा जिले मे नरैनी-कालिजर सड़क पर पुल निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

वैद्यों ग्रौर हकीमों का रजिस्ट्रेशन। खं० १३६, पृ० १८७।

श्री चन्द, श्री---

गन्ना फंक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषेते पानी से उत्पन्न दुष्परिणाम की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था। खं० १३६, प्०३८२।

जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी। खं० १३६, पृ० १७।

श्रीनाथराम, श्री-

भ्राजमगढ़ जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण। खं० १३६, पु० १२४।

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री---

, साहित्य की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर आपत्ति। खं० १३६, प्० ११३-११४। सर्त्यासह राणा, श्री--

जिल। टेहरी-गढ़वाल की निहयो की घाटियों में सिचाई के साधनों का स्रभाव। खं० १३६, पृ० १०६-१०७।

सियाराम चौधरी, श्री---

महालों का कम्पेसेशन रोल। खं० १३६, पृ० २७-२८।

सीताराम शुक्ल, श्री---

हाई स्कूल व इंटरमीडियेट की परीक्षाभ्रो में भ्रनुचित तरीकों का प्रयोग। खं० १३६, पृ० २६६-२७०।

सुल्तान श्रालम खां, श्री---

नगरपालिका मेरठ में सहायक हाजिरी श्रफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी श्रादेश। खं०१३६, पु० ३८२—३८३।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री---

हाथरस नगर में पैविलियन के लिए नगरपालिका को ग्रांट। खं०१३६, पु० ३८१।

हरि प्रसाद, श्री---

शारदा नहर के हेड दर्स का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, पु० ११४-११४।

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री---

पंचवर्षीय योजना के श्रधीन लखनऊ जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पृ० २७३—-२७४।

मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति। खं० १३६ पु० २८६-२८७।

लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में छट । खं० १३६, प्० २८।

प्रस्ताव की सूचना-

उतर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १६५४ को १२ मई, १६५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्राइमरी---

प्र० वि०—गांव सभा की जमीनों को ——वजूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

प्राइमरी स्कूलों---

प्र० वि०—शिक्षा पुनस्संगठन योजना के ग्रन्तर्गत — को तोड़ने का विचार । खं० १३६, पृ० ३७७— ३७८ ।

प्राइवेट लारियों---

प्र० वि०—कानपुर रीजन में मोटर ट्रकः व—— के परिमिट । खं० १३६, पृ० ३०।

प्राक्कलन समिति-

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति

तथा विभिन्न स्थायो समितियों

के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशनों

के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६,
पृ० २८७-२६४।

प्राथमिकता---

प्र० वि०—हरिजन ग्रमीनों के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को —— । स्रं० १३६, पृ० २७१-२७२ ।

प्रार्थना---

विशेषाधिकार का प्रक्त उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की---। स्रं० १३६, पृ० २६६ ।

श्री मदन मोहन उपाघ्याय द्वारा विशेषा-घिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की----। खं० १३६, प्० १६१

प्रार्थना-पत्र---

प्र० वि०—हरदोई जिले से भूमि संघ व्यवस्था सम्बन्धी— —। सं० १३६, पृ० १३ ।

प्राहिबिटेड बोर---

प्र• वि०—प्रदेशीय माललानों में—— के हथियार तथा उनकी परिभाषा । सं० १३६, पृ०३८० ।

प्लाटों---

प्र० वि०—जिला नेर्न **सा**च की टनक पुर मंडी में—— —का नीलाम । लं० १३६, पृ० १५–१६ ।

फ

फ़जलुल हक, श्री— देखिये "प्रक्तोत्तर"। फर्राज्ञ तथा लिफ्टमैनों—

> प्र० वि०—विधायक निवासियों के . ——में हरिजनों को न लेना । स्रं० १३६, पृ० ११३ ।

फसल--

प्र० वि०—झांसी जिले में जंगली गायों व बैलों से——को हानि । खं० १३६, पृ० १६ ।

फूड प्रजवेंशन फैक्टरी-

प्र० वि०—रामनगर में की योजना। स्रं० १३६, पृ० २८४।

ब

बंद---

प्र० वि०-देवरिया जिले में तरया सुजान के टेस्ट वर्क का-होना । सं० १३६, पृ० २४-२५।

बद्री नारायण मिश्र, श्री— देखिये "प्रक्नोत्तर"।

बन्दूक के लाइसेंस-

जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन श्रौर ग्राम रक्षकों को——। खं० १३६, पृ० ३८६।

बन्दूक, राइफल्स ग्रौर रिवाल्वर—

प्र० वि०--जिला बरेली में----के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३७६-३७७।

बलदेव सिंह, श्री— देखिये "प्रक्तोत्तर"। बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री— देखिये "प्रक्तोत्तर"। बलरामपुर प्रस्पताल--

प्र० वि०-भेड़िया बालक, रामू के लिये---लखनऊ में प्रबन्ध। ख० १३६, पृ० १८९-१६०।

बलवन्त सिह, श्री---

देखिये "प्रक्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन) विघेयक, १९४४ । ख० १३६, पु० २३०।

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन) विधेयक, १९४४। ख० १३६, पृ० ४३१-४३३।

श्री नारायण वत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्घ विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषा धकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। ख० १३६, प० ४१६—४१७।

बसन्तलाल शर्मा, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बसे---

प्र० वि०—मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गई———। खं० १३६, पृ० ३० – ३१।

बाय--

प्र० वि०—बस्ती जिले में राप्ती के किनारे बने हुये——पर व्यय । ख० १३६, प्० ११६–११७ ।

बाघो---

प्र० वि०—बस्ती जिले में ——की मरम्मत की प्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० १०५-१०६।

बाढ---

प्र० वि० — जोनपुर जिले मे गोमती की — से क्षति । खं० १३६, पु० ६ — द ।

बाढ पीड़ित ग्रामो---

प्र० वि०-जौनपुर जिले मे ----- हो ग्रामो को गृह निर्माण के लिये सहायता। ख० १३६, पृ० २८। बाढ़-पीड़ितो---

प्र० वि०—लखनऊ जिले के —— को लगान में छूट। ख० १३६, पु० २८।

बाबूनन्दन, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बाबूराम गुप्त, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार---

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन)
विधेयक, १६५४। खड १३६, पृ०
३६, ४१-४२, ४३, ४७, ५७,
५६-६०, ६३, ६७, ७°, ७३
१३१, १३२, १३४, १५७-१४८
१४६-१६१, १६३, १७०-१७१,
१६२, १६३-१६४, १६४, १२०,
२२६-२३०, ३१७-३२१,३३०,

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। ख० १३६, प्०३६२, ४०१,४०८,४०६।

बिल---

प्र० वि०—गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी——। खं० १३६, पृ० ३८१।

बी० सी० जी० के टीके---

प्र० वि०—बस्ती जिले मे— । ख॰ १३६, पृ० १८२-१८४।

ैबेतवा नदी---

प्रव वि०—जिला झामी मे——के नोट घाट पर पुल की ग्रावश्यकता। ख०१३६, पृ० ११५। बेदलली---

प्र० वि०— बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की———। खं० १३६, प्० ४–६।

बैजनाय प्रसाद सिंह, श्री---बेखिये "प्रक्नोत्तर"।

H

भंग किया जाना-

प्र० वि०—प्राम ग्रसलाई (ग्राजमगढ़) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा श्रायो-जित सभा का ——। र्लं० १३६, प्० ३६१–३६४।

भगवती प्रसाद शुक्ल, (बाराबंकी) श्री— उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोघन) विघेयक, १६५४। खंड १३६, पृ० ५४, १५२, १५३।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, प्० ३६४, ४१५-४१६।

भगवान दीन वाल्मीकि, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भगवान सहाय, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भर्ती---

प्र० वि०—लखनक कलेक्टरी में हरिजन क्तकों तथा चपरासियों की——। र्ख० १३६, पृ० २१–२२।

भागों—

प्र० वि०—फैजाबाद तथा ग्राजमगढ़ जिलों के कुछ — को बदलने के लिये सुप्ताव। खं० १३६, पृ० १५–१३।

भारत सरकार-

प्र० वि०--जूरी प्रथा के सम्बन्ध में ----का आदेश। चं० १३६, प्० १०२। भूदान--

प्र० वि०———यज्ञ में दी गई भूमि। सं० १३६, पृ० १०-१२।

भूमि-

प्र० वि०--भूदान यज्ञ में दी गई----। स्रं० १३६, पृ० १०-१२।

प्र० वि०——संबंधी समस्त नियमों तथा ग्रावेशों के संहित प्रकाशन की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पृ०६।

प्र० वि०—हरदोई जिले से——संघ ध्यवस्था संबंघी प्रार्थना-पत्र। सं १३६, पृ० १३।

भूमियर--

प्र० वि०-बाराबंकी जिले के----किसान । खं०१३६, पृ०२६।

भेड़िया बालक रामू---

प्र० वि०——के लिये बलराम पुर ग्रस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८६-१६०।

भोला सिंह यादव, श्री--देखिये "प्रश्नोत्तर।"

Ħ

मंडी--

प्र० वि०--जिला नैनीताल की टनकपुर ----में प्लाटों का नीलाम। कं० १३६, पृ० १४-१६ ।

मंदिर ग्रौर मस्जिद-

प्र० वि०—गाजीपुर शहर में —— का सगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० ३७१।

मऊ-कासिमाबाद सड़क---

ग्राजमगढ़ जिले में का निर्माण । खं० १३६, पृ० १२४।

मजदूरी-

प्र० वि०——टेस्ट वर्क्स पर दी जाने वाली——की वरें । सं० १३६, पृ० २२–२४ ।

मयुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री---देसिये "प्रक्लोत्तर"। मथुरा प्रसाद पाण्डंय— देखिये "प्रश्नोत्तर।" मदन मोहन उपाघ्याय, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर।"

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
विषेयक, १९४४ । खं० १३६,
पृ० ३३,३९,४०,४४,४५,४६,
१४२-१४३, १५३-१४४, १५५,
१५७, ३११, ३२४-३२५ ।

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषा-धिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६,पृ० १२७।

——द्वारा विशेषाधिकार की भ्रवहेलना का प्रक्त उठाने की प्रार्थना । खं० १३६, पृ० १६१ ।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये

-----की प्रार्थना । खं० १३६,
पु० २६६ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी
से सम्बद्ध विशेषाधिकार की
श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार
समिति के प्रतिवेदन पर विचार।
सं० १३६, पू० ३६३-३६४, ३६४
३६४, ४०८, ४११, ४२०।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की श्रव-हेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८९।

मन्नी लाल गुरुदेव, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर।"

मरम्मत--

प्र० वि०--जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांच की ---। खं०१३६, पु० १२३।

मलखान सिंह, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर ।" उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विघेयक, १९४४। सं० १३६, पृ०४०।

महालों---

प्र० वि०——का कम्पेसेशन रोल। खं० १३६, पृ० २७–२८।

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री---

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की ग्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ४१७, ४१८ ।

महिला चिकित्सालय--

प्र० वि०—मङ्ग्याह् के ग्रन्तर्गत सीतापुर ग्राम में——की मांग। खं० १३६, पु० १८२।

महीलाल, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९४४। खं० १३६, पृ० ४२६-४२६, ४३३, ४३४, ४३४, ४३६।

माध्यमिक विद्यालयों---

प्र० वि०—राज्य के उच्चतर—के ध्रनुदान में कटौती । खं० १३६, प्०३८४।

मालखानों---

प्र० वि०-प्रदर्शीय---में प्राहिबिटेड बोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, प्०३८०।

मालगुजारी-

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर, मेरठ, तथा सहारतपुर जिलों की——तथा कृषि टैक्स । खं० १३६, पृ० २६ ।

मिलों--

प्र० वि०- — में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति । सं० १३६, पृ० २८६ –२८७ । मद्यत्तली---

प्र० वि०—देवरिया जिले में दुदेही ग्रदालत पंचायत के सरपंच की—। सं० १३६, पृ० १८०–१८१।

मुद्राविजा---

प्र० वि० — जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का — । खं० १३६, पृ० ११७ ।

मुकदमे-

प्र० वि०—गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये — ग्रौर उनमें सजाएं। खं० १३६, प्० ३७२।

मुखियों-

प्र० वि०—सरकार का ग्रामों के—— के पद को तोड़ने का विचार । खं० १३६, पु० ३८४।

मुरलीधर कुरील, श्री---

उत्तर प्रदेश पंच।यत राज (संशोधन) विषेयक, १६४४ । सं० १३६, पु० ५०, ५५ ।

मुक्ताक ग्रली, श्री---देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

मसलमानों---

प्र० वि०—नेहरू-लियाक्त पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में ग्राने वाले तथा यहां से जाने वाले——की संख्या । खं० १३६, पू० ३७४— ३७५ ।

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज--

श्री राजनारायण की कथित गैर-कानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

मुहम्मद तकी हादी, श्री-

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १२६, पृ० ४२४-४२१।

मृत्य--

प्र० वि०—गन्ने का——निश्चित करने के लिये सम्मेलन । सं० १३६, पृ० २८२-२८३ ।

प्र० वि०—गन्ने के —— का निर्घारण। खं०१३६, पृ०२६५— २६६।

मृत्यु--

प्र० वि०—मौजा डीह, जिला रायबरेली में डाके से एक व्यक्ति की—— । खं० १३६, पृ० ३७६ ।

मेडिकल ग्रफसरों-

प्र० वि० — ग्रस्पताल के कार्यकाल में ——को बाहर न जाने का ग्रादेश। खं० १३६, प्० १८४–१८४।

मेहतर--

प्र० वि०—प्रदेश त्यापी—हड़ताल । स्रं० १३६, प्० १७६ ।

मोटर ट्कॉ---

प्र० वि०—कानपुर रीजन मे—— व प्राइवेट लारियों के परिमट । खं० १३६, पृ० ३०।

मोटर लाइसेंसों---

प्र० वि०—ग्रार० टी० ग्रो० द्वारा रह किये जाने वाले — की ग्राजाओं के विरुद्ध ग्रपीलें। खं० १३६, पृ० १६।

मोहनलाल गौतम, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोवन)
विघेयक, १६४४। खं० १३६, पृ०
३३, ३४, ३४, ३६, ३७, ३८, ४६, ४६, ४४, ४६–४६,
४४, ४६, ४७, ६६, ६७, ६८, १२६१३०, १३१, १३२, १३३, १३३,
१३४, १४१, १४४, १४६, १४७,
१४८, १७१, १६३, १६४–१६४,
१६६, १६८, २०४, २१८, २२७,
२२६, २३२, २३३, ३०१, ३०२,
३०३, ३०३, ३०४, ३०४, ३०७,
३०८, ३२६, ३२४, ३२२–३२४,
३२४, ३२६, ३२७, ३२८,

म्युनिसिपल बोर्ड---

पिहानी (हरदोई) मे——द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता। खं० १३६, प्०३७६-३८०।

म्युनिसिपैलिटियां---

प्र० वि०—फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में वाटर वर्क्स योजना तथा पृथक-पृथक् ——बनाने की मांग। खं० १३६, प्०१८१।

य

यज्ञ---

प्र० वि० — भूदान — में दी गयी भूमि। खं० १३६, पृ० १० – १२।

यमुना सिंह, श्री— "देखिए प्रश्नोत्तर।"

योजना---

प्र० वि०--द्वितीय पंचवर्षीय--। खं० १३६, पृ० २८६ ।

प्र० वि०—नीरा से गुड़ बनाने की ———। खं० १३६, पृ० २८६।

प्र० वि०—बांदा जिले में नरैनी-कालिजर सड़क पर पुल निर्माण— । खं० १३६, पृ० ११० ।

प्र० वि०—राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी—— । खं० १३६, पू० १८६–१८७ ।

प्र० वि०---रामनगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की----। खं० १३६, पृ० २८५ ।

प्र० वि०—शिक्षा पुनः संगठन——के श्रन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पू० ३७७— ३७८।

₹

रंगाई—

प्र० वि०—मऊ (ग्राजमगढ़) में—— व बुनाई का कारलाना। लं० १३६, पृ० २८४। रघुराज सिंह, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"। रजिस्ट्री—

> प्र० वि०—जालौन ग्रौर इगलास में ——के दफ्तर खोलने का हुक्स। खं० १३६, पृ० ११५–११६।

> प्र० वि—होमियोपैथिक डाक्टरों की ———। खं० १३६, पू० १८२।

रजिस्ट्रेशन---

प्र॰ वि॰—वैद्यों ग्रौर हकीमों का ——। खं॰ १३६, पृ० १८७।

रमेश चन्द्र शर्मा, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"

राज कुमार शर्मा, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"

राजनारायण, श्री---

——की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की ग्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पू० ३८६–३६०।

----की पुनः गिरफ्तारी के सम्बद्ध में सूचना । खं० १३६, पृ० ३१ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये
गये विशेषाधिकार के प्रदन से
सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के
प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण
तथा—की पुनः गिरफ्तारी ।
खं० १३६, पृ० ३२ ।

राजनैतिक पीडितों---

प्र० वि०---को पेंशन । खं० १३६, पृ० २८४ ।

राजाराम किसान, श्री---देखिए ''प्रक्नोत्तर''।

> प्रतापगढ़ जिले मे रिवाल्वर के लाइसेंस्। सं० १३६, पृ० ३८२।

राजाराम शर्मा, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" । रावामोहन सिंह, श्री —
श्री नारायण दस तिवारी की गिरफ्तारी
से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना है
के विषय में विशेषाधिकार सिमिति के
प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६,
प्०३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ४२६।

राप्ती---

प्र० वि०—बस्ती जिले में———के किनारे बने हुए बांघ पर व्यय। स्रं० १३६, पृ० ११६–११७।

राप्ती नदी-

प्र० वि०—बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच—पर डेक बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १०८—१०६।

राम ग्रधार तिवारी, श्री— देखिए "प्रक्तोत्तर" ।

रामकुमार शास्त्री, श्री— उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९४४ । खं० १३६, प्० २२४ ।

रामचन्द्र विकल, श्री— देखिए "प्रक्नोत्तर" ।

रामजी लाल सहायक, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

रामदास ग्रायं श्री-

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विषेयक, १९४४। खं० १३६, पू० २३१ — २३२, ३३२ — ३३३, ४४७।

रामदुलारे मिश्र, श्री---देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम नरेश शुक्ल, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)

विषेयक, १६५४ । कं० १३६,
पू० ६६—७०, १६४–१६५, १६६,
१६७, २०४, २०६।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

> उत्तर प्रदेश पंचायत राज (मंशोधन) विषेयक, १६५४, खं० १३६, पृ० ४१, ४७-४८, २३३, २३४, २३५, ३००, ३०१, ३०२।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की ब्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, प्० ३६५—३६७।

श्री नारायण वत्त तिवारी की गिरफ्तारी से मम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रक्त पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पु० २९७।

राम प्रसाद श्री---देखिए "प्रक्नोत्तर" ।

> शारवा नहर, पुरवा बांच, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि। सं० १३६, प्० ११२।

राम प्रसाद देशमृख, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

राम प्रसाद नौटियाल, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम रतन प्रसाद, श्री देखिये "प्रक्रनोत्तर" ।

रामलखन मिश्र, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९४४ । खं० १३६, पू० ६३, ६४,७३, १४३–१४४, १४३, ३१७, ३२१ ।

रामसुन्दर पांडेय, श्री--

देखिए "प्रक्नोत्तर" ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (मंशोधन) विषेयक, १६५४। खं० १३६ पृ० १४४, १४५, ⁸३७ रामसुन्दर राम, श्री देखिये, "प्रदनोत्तर" ।

राम सुभग वर्मा, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

> उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९५४, खं० १३६, पू० ४२, ६०, १४८-१४६, ४३६।

राम हेत सिंह, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"। रामेश्वर लाल, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रिक्त स्थान--

प्र० वि०—पंचायत राज इन्स्पेक्टरों के—ग्रौर उन पर नियुक्तियां। खं० १३६, पु० ३४६।

प्र० वि०—पुस्तकालय समिति के— की पुति । खं०१३६, पु० ३१ ।

ूँ रिपोर्ट--

प्र० वि०—ग्रागरा जिले में डकैतियाँ व कत्लों की दर्ज — खं० १३६, (पु० ३७८-३७६।

प्रविष्-सांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां धौर उनकी—। संव १३६, पृष्ट ३८४।

रिवाल्वर-

प्र० वि० प्रतापगढ़ जिले में के लाइसेंस । सं० १३६, पू० ३६२ ।

रूरल हाउसिंग--

प्रं० वि० राज्य में — सम्बन्धी योजना। सं० १३६, पु० १८६-१८७।

रोडवेज कारलाने-

प्र० वि०—मेरठ के सरकारी— हारा चालू की गयी वसें। चं० १३% पु० ३०-३१। रोडवेज की बसों —

प्र० वि०—रायबरेली जिले में— को चलाने का विचार। खं० १३६, पृ० २४।

ल

लकड़ी---

प्र० वि—बहिपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर बन विभागकी—में ग्रागलगना। खं० १३६, पृ० २८१–२८२ ।

लक्ष्मण राव कदम, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

तक्सी शंकर यादव, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लखनऊ फेजाबाद डिवीजन-

प्र० वि०—के सुपरवाइजर कानूनगो खं० १३६, पृ० १६–२१।

लगान--

प्र० वि० लखनऊ जिले के बाइ पीड़ितों को में छूट खं० १३६, पृ० २८।

तट्ठों के पुल—

प्र० वि०—रिखणी खाल—बनजिया देवी सङ्क पर—— का निर्माण। खं० १३६, पृ० १२२–१२३।

लाइम फेबट्री-

प्र० वि०—फिरोजाबाव की की कोयले का कोटा । खं० १३६ पु० २८६ ।

लाइसेंस—

प्र० वि०—जिला बरेली में बन्तूक राइफल ग्रीर रिवाल्वर के— सं० १३६, पृ० ३७६—३७७ ।

प्र० वि०—प्रतापगढ़-जिले में रिवाल्बर के-खं० १३६, पू० ३८२। लाउडस्पोकर ग्रोर पंखों की खराबी खं० १३६, प्० १२४। लाक-ग्रप--

प्र० वि०—देवरिया—में कैदियों की जगह । खं० १३६, प्० ३७६ ।

लाल बहादुर सिंह, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लेखपार्लो---

प्र० वि०—बिलया जिले में हरिजन ——की संख्या। खं० १३६, पृ० ३१।

लेबर ग्राफिसर्स—

प्र० वि० — तथा कांसिलिएशन श्राफिसर्स की नियुक्तियां श्रौर उनमें हरिजनों का अनुपात। खं० १३६, पृ० ३६५।

व

वंश नारायण सिंह, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

वन---

प्र० वि०—पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर, के———का क्षेत्रफल । खं० १३६, पृ० २८४ ।

वन विभाग-

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में—— की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही । खं० १३६, पु० २७६–२८० ।

प्र० वि०—बहिसपुरया स्टेशन, जिला बांदा, पर——की लकड़ी में ग्राग लगना। सं० १३६, प्०२८१–२८२।

प्र० वि०—मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। सं० १३६, पृ० २८०–२८१।

वर्वा---

प्र० वि०—वस्ती जिले में झनेक गांवों की———से क्षति । खं० १३६,

पु० २६।

वाटर वर्क्स योजना--

प्र०-वि० फर्रसाबाद-फतेहगढ़ में-----

तथा पृथक्-पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने की मांग। खं०१३६, प्०१८१।

विकास---

प्र० वि०—जिला मेरठ में—— तया नियोजन पर व्यय खं० १३६, पृ० २७६–२७६।

विकास कार्य-

प्र० वि०—जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में— खं० १३६, पृ० २७७।

प्र० वि०—जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में—की ग्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० २७५—२७६।

विचार---

प्र० वि०—खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर के किसानों को हिस्सेदार बनाने का—— । खं० १३६, पू० १६।

प्र० वि०—मई, १९४४, में श्रमदान ग्रांदोलन चलाने का——। खं० १३६, पृ० २७०–२७१।

प्र० वि०---रायबरेली जिले में रोडवेंब की बसों को चलाने का ---- । सं० १३६, पृ० २४ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की स्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर—— । खं० १३६, पु० ३७६–४०४, ४०५, ४२६।

विचाराघीन मुकद्दमे-

प्र० वि०—गाजीपुर कलेक्टरी में ——। खं० १३६, पृ० १४–१४।

विचारायं--

भी नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विश्वषाधिकार के प्रक्त से सम्बद्ध विश्वषाधिकार समिति के प्रतिबेदन पर——समय निर्धारण तक्का भी राजनारायण को पुनः गिरफ्तारी। बं० १३६, पु० ३२ ।

बितरण-

प्र० वि०—कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का।—— खं० १३६, पृ० १८–१६ ।

वित्त समिति---

— सार्वजिनिक लेखा सिमिति, प्राक्कलन सिमिति तथा विभिन्न स्थायी सिम-तियों के निर्वोचन में प्राप्त नाम— निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, गृ० २८७–२९४।

विदेशी शराब---

मेरठ में --- बेचने के स्थान। खं० १३६, गृ० ११६-१२०।

विदेशी सलाहकार--

प्र॰ वि॰—मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के निर्माण के लिये——। खं॰ १३६, गु॰ २६६–२६८।

विद्यायियों--

प्र० वि०—लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के—— की मुख्य जेलों के ग्रध्ययन के लिये यात्रा ग्रीर उस पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८१-३८२।

विद्यार्थी ग्रांदोलन---

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में--के सम्बन्ध में विद्यार्थियों पर ग्रभियोग। खं० १३६, पृ० ३६७-३६८।

विघान-भवन--

प्र० वि० को एयर कंडोशन्ड कराने की प्रावश्यकता। खं०१३६, पु० १०१।

विद्यान सन्त---

प्र० वि० के सवस्य श्री नारायण

दत्त तिवारी पर ग्रभियोग ग्रौर उनकी पेशी। खं० १३६, पृ० ३६६-३७१।

विधायक निवासों---

प्र० वि० के फर्राज्ञों तथा लिफटमंनों में हरिजनों को न लेना। सं०१३६, पृ०११३।

विधेय क---

उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक गृह-व्यवस्था --१९४४। खं० १३६, पृ० ३३।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
----१६४४। खं० १३६, पृ०
३३-७३,१२७-१७१। १६२-२३४, ३००-३३४ २६६, ४२६,

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
---१९४४ को १२ मई, १९५४,तक
पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव
की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०५।

विलीनीकरण---

प्र० वि०—-के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी में लिया जाना। खं० १३६, पृ० २८३-२८४।

विशेषाधिकार--

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध---के प्रश्न पर विशेषा-घिकार समिति का प्रतिवेदन । खं० १३६, पृ० २९९ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध---के प्रक्त पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । सं० १३६, पृ०
२६४-२६८।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये ----के प्रक्त से सम्बद्ध विशेषा-धिकार । समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थं समय निर्घारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। सं० १३६, पृ० ३२।

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा---की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना । खं० १३६, प्० १६१ ।

विशेषाधिकार का प्रश्न--

— उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाच्याय की प्रार्थना । खं० १३६, । प्० २६६ ।

विशेषाधिकार की श्रवहेलना--

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में——का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध ——— के विषय में विशेष्ट में विशेष्ट में विशेष्ट में विशेष्ट समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ३७६—४०४, ४०५—४०६।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में——का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की व्यवस्था। सं० १३६, पृ० ३८६–३६०।

विशेषाधिकार समिति-

भी नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में——के प्रतिवेदन पर विचार । सं० १३६, पृ० ३७६, ४०४, ४०५-४२६।

भी नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर—का प्रतिवेदन । खं० १३६, प्० २६६।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर—के प्रतिवेदन पर विचार । सं० १३६, पृ० २६४–२६८।

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध -----के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्नारी । त्व० १३६, पु० ३२ ।

विश्वविद्यालय---

प्र० वि० — गोरखपुर — मम्बन्धी बिल । ल० १३६, पृ० ३८१।

बिच्णुदयाल वर्मा, श्री--

देखिए ''प्रश्नोत्तर''।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ । ख० १३६, पृ० ५७-५८, ६५-६६, ६७, १३८-१३६, १४१ ।

वीरसेन, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विघेयक, १९५४ । खं० १३६, प० ३६, ३८।

वीरेन्द्र नाय मिश्र, श्री--देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

वीरेन्द्रपति यादव, श्री —

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की श्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, नृ० ४०६--४१० ।

वीरेन्द्र शाह, राजा--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १६५४। खं० १३६, पृ० १४७, १४८, २०८–२१०, २१५, २१६, २२६, २३१, २३२।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरपतारी से सम्बद्ध दिशेषाधिकार सिमिति के विषय में विशेषाधिकार सिमिति के प्रतिवेदन पर विचार। सं० १३६, पृ०३६७, ४०३-४०४।

[वीरेन्द्र शाह, राजा]

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७, २९८।

वृद्धि---

प्र० वि०—-ग्रन्न की पैदावार में---। स्रं० १३६, पृ० १७ ।

वेतन--

प्र० वि०—बिलया में पंचायत-मंत्रियों को—मिलने में बिलम्ब । खं० १३६, प्० १८० ।

वेतन ऋम--

प्र० वि०—गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों ग्रोर सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के—-- में ग्रन्तर । खं० १३६, प्० ३८२ ।

वैद्यों---

प्र० वि०—-ग्रौर हकीमों का रजिस्ट्रेशन। स्रं० १३६, पु० १८७ ।

व्यक्तिगत प्रक्त

दत्रशृंगार दुबे, श्री---

त्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला गाजीपुर, के मंत्री---पर ग्राक्रमण की जांच। खं० १३६, पृ० ३६८--३६६।

नारायण दत्त तिवारी, श्री--

विधान सभा के सदस्य----पर ग्रभियोग ग्रौर जनकी पेशी । खं० १३६, प्०३६६---३७१।

मान सिह--

डाकू---के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना । खं० १३६, पु० ३७५-३७६ ।

व्यय--

प्र० वि०---उत्तर प्रदेश नगर तथा
ग्राम नियोजन पर---- । खं० १३६,
प्० २७७--२७८ ।

प्र० वि०-- उत्तर प्रदेश में हिस्जिन उत्थान के लिए १६५३-५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर-- । खं० १३६, पृ० ३८८।

प्र० वि०—१६४७ में हाथरस में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका— किया जाना। खं० १३६, पृ० ३८७।

प्र० वि०—जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन पर———। खं० १३६, प्० २७६—२७६ ।

प्रव विव -- नैपाल भेजी गयी पीव एवसीव की युनिटों पर--- । खंब १३६, पृव ३७८ ।

प्र० वि०--प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क पर----। खं०१३६, पृ०१२३।

व्यवस्था--

प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की—। खं० १३६, पृ० २७४— २७५।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की———। खं०१३६, प्० ३८६–३६०।

प्र० वि०—हरदोई जिले से भूमि सं ——सम्बन्धी प्रार्थना ^{८ त्र} स्वं० १३६, पृ० १३।

ब्रजभूषण मिश्र, श्री---

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १९५४ । खं० १३६, प्०१४६-१५०।

वज विहारी मिश्र, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषयक, १६४४ । खं० १३६, पृ० ७०-७१,२०४---२०६ । হা

राक्कर---

प्रव वि०-मिलो में ज्ञा न पहुंचने मे---के उत्पादन में क्षति। खं० १३६. १० २८६-२८३ ।

कारका नहर-

प्र० वि०—को हेड वर्क्स का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण। खं० १३६,११४—११४।

प्र० वि०—पुरवा ब्रान्च जिला रायवरेली में खांदी के कारण किमानों को हानि । खं० १३६, प० ११२ ।

द्याकमी--

प्र० वि०—बनारम जिले के——— काइतकारों की बेदलली । खं० १३६ पृ० ५–६।

शिकायत---

प्र० वि०—भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट ' के विरुद्ध-। खं० १३६, पृ० २८२।

शिक्षापुनः संगठन योजना---

प्र० वि०—क मन्तर्गत प्राइमरो स्कूलों । को तोड़ने का विचार । खं० १३६, । प्० ३७७–३७८ ।

शिव नारायण, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)
विधेयक, १६५४ । खं० १३६,
पू० ५२, ६३,१४६-१४७,१४७१४८, १५८, २३०, २३१,३११,
४३०---४३१।

लाउडस्पीकर ग्रौर पंखों की खराबी। खं० १३६, पृ० १२४।

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री— देखिए ''प्रश्नोत्तर" ।

शिवराज सिंह यादव, श्री— देखिए "प्रश्नोत्तर" । उत्तर प्रदेश प्रचायन गाज स्थानियन विषेत्रक १६.: वट १३६ पृष्ट ४४ ८६

हिन्द स्वरूप सित्र, धी---

देवित् 'प्रदर्गेचर

गेला माइनर ---

प्र० वि०—वहातुरी पुर ग्रीर सहिजनी के कुषकी द्वारा——वोदने के निये प्रार्थना । वि० १३६ प्०११८—११६ ।

इयामाचरण वाज्येयी ३ स्त्री श्री--देखिए प्रज्ञोलर

श्रमदान--

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के ग्रहार परगने में कच्ची मड़क का——द्वारा निर्माण । ख० १३६. पृ० २७२— २७३।

प्र० वि०—सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा—। ख० १३६, पु० २७८ ।

श्रमदान ग्रांदोलन-

प्र० वि०—मई, १६४४. मे—— जनाने का विचार । खं० १३६, नु० २७०-२७१।

श्रमदान सप्ताह---

प्र० वि०—में सरकारी कर्मग्रान्यों द्वारा श्रमदान । खं० १३६, प्० २७८ ।

श्री चन्द्र श्री--

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

संख्या--

प्र० वि०—विलया जिले में हरिजन लेखणलो की——। खं० १३६, पु०३१।

सहित--

प्र० वि०—-भूमि सम्बन्धी समस्त नियमों तथा श्रादेशों के—-प्रकाशन की श्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० ६।

सिच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री--देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

सड़क--

प्र० वि० — जौनपुर जिले में रामपुर बाजार — परिचत बाजार में ली गयी भूमि का मुग्नावजा। खं० १३६, प्० ११७ ।

प्र० वि०---- बुलन्दशहर जिले के ग्रहार परगने में कच्ची---का श्रमदान द्वारा निर्माण । ख० १३६, पृ० २७२--२७३ ।

सड़क का सुधार---

प्र० वि०--एटा-गंजबुडवाडा-- । खं० १३६, प्० १८६ ।

सडके--

प्र० वि०—जिला बोर्ड बस्ती को पी० डब्लू० डी० द्वारा वापस की हुयी। खं० १३६, पृ० ११०—१११।

सड़कों---

प्र० वि०--गोरखपुर---जिले ्मे वन विभाग की--पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७६-२८०।

सर्त्यांसह राणा, श्री--देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

सदन--

---- के स्रागामी कार्यक्रम के सम्बन्ध मे सूचना । खं० १३६, पृ० ३२।

सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स ग्राफ स्कूल्स ——
प्र० वि०—१६४६ के मध्य में
ग्रस्थायी रूप से नियक्त——

की सख्या श्रीर उनका स्थायीकरण। खं० १३६, पु० ३८६।

सब-डिवोजनल मजिस्ट्रेट--

प्र० वि०--फिरोजाबाद का हेड क्वार्टर। खं० १३६, पृ० २८५, २८६।

समय निर्धारण--

श्री नारायण बत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रक्त से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ——तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। ख० १३६, पु०३२।

समय मे वृद्धि--

स्थायी समितियो की निर्वाचन से नाम वापस लेने के——की सूचना। खं० १३६, पृ०४०४-४०५।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर--

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री श्रध्यक्ष की व्यवस्था । स॰ १३६, पृ० ३८६, ३६० ।

सम्मेलन--

प्र० वि०—गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये— ख० १३६, प्०२६२—२६३।

सरकारी कर्मचारियो--

प्र० वि०--श्रमदान सप्ताह मे--द्वारा श्रमदान । खं० १३६, पृ० २७८ ।

सरकारी नौकरी-

प्र० वि०—विलीनीयकरण के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियो का--में लिया जाना। खं० १३६, पृ० २८३—२८४। मन्यू नदी--

प्रव वि०--बहराइच जिले हे-----में नहर निकालने की योजना १ व्वं० १३६. पू० १२३--१२४ ।

महकारी नलकूप---

प्र० वि०—मुन्तानपुर जिले मे——— खं० १३६. प्० १०४ ।

महायता--

प्र० वि०—-जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये—-। वं० १३६, पृ० २८।

माडकिल व रिक्शा--

प्रः जि॰—गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर—चलाने की मनाही। खं० १३६. प्० २७६-२८०।

नामूहिक जुर्माने--

प्र० वि०—१६४७ में हाथरस में----की धनराज्ञि ग्रौर उसका व्यय किया जाना। खं०१३६, पृ०३८७।

सार्वजनिक लेखा समिति--

वित्त सिमिति——प्राक्कलन सिमिति तथा विभिन्न स्थायी सिमितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में मूचना । खं० १३६, पृ० २८७— २६४।

साहित्य---

प्र० वि०—की प्रतियों के ग्रंग्रेजी में । प्रकाशन पर भ्रापत्ति । खं० १३६, पृ० ११३–११४ ।

सिंचाई--

प्र० वि०--जिला टेहरी गढ़वाल की निवयों की घाटियों में-के साघनों का ग्रभाव। खं० १३६, पृ० १०६-१०७।

प्र० वि०—तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, में——का प्रबन्ध । खं० १३६, पृ० ११६ । सिया राम चौथरी श्री— देखिये "प्रकारिका .

> उत्तर प्रदेश पंचापन राज स्रोधित विभेषक, १६४४ व्यव १३६ पुरु २१६

सिविन्द पुल्सि--

प्र० वि०—गुज्ज्वर पुजिस इन्स्पेक्टरों ग्रोर———स्व-इन्स्पेक्टरों के बेतन-क्स में ग्रन्तर सं ३ ३३६. पु० ३८२।

मीताराम शुक्तः श्री— देखिये " प्रश्तोत्तर"।

> उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन विधेयक, १९४४ । खं०१३६. पु० २०१.२०६-२०६ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्नारी से संबद्घ विशेषाधिकार की ग्रव-हेलना के विषय मे विशेषाधिकार समिनि के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१०, ४११, ४१२।

सीमेन्ट फ़ैक्टरी--

प्र॰ वि० — मिर्जापुर — के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार । खं० १३६, पृ० २६६ – २६ ८ ।

सुझाव---

प्र० वि० — फंजाबाद तथा ग्राजमगढ़ जिलों में कुछ भागों को बदलने के के लिये —— । खं० १३६, पू० १२-१३।

सुपरवाइजर कान्नगो---

प्र० वि०— लखनऊ भौर फ़ैजाबाद डिवीजन के —— । खं० १३६, पृ० १६-२१।

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोषन) विषेयक, १६४४ । सं० १३६, पृ० १४३, १६१-१६३, १६३--१६४, १६४ । सुस्तान म्रालम खां, श्री— देखिये "प्रदनोत्तर"।

सुविधा---

प्र० वि० — निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी श्रौर नीरा बेचने की —— । खं० १३६, पु० ११४।

सूचना--

कानपुर में श्री राजनारायण की गिर-फ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की श्रवहेलना का प्रश्न उठाने की ----। खं० १३६, पृ० १२७।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियो के निर्वाचन मे प्राप्त नाम-निर्देशनो के सम्बन्ध में — । ख० १३६, पृ० २८७-२६४।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ——— । खं० १३६, पु० ३१।

सदन के ग्रागामी कार्यत्रम के सम्बन्ध में

सोशल वर्कर्स--

प्र० वि० - उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये १६५३-५४ में ---- की नियुक्ति और उन पर व्यय। खं० १३६, पू० ३८८।

स्कूलों---

प्र० वि० पिहानी (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित — को सरकारी सहायता । खं० १३६, पृ० ३७६-३८०।

स्थानान्तरण—

प्र० वि० — बसन्त कन्या इन्टर कालेज, कमक्षा शहर बनारस, का — । खं० १३६, पृ० ३८७।

स्थानिक प्रश्न

म्रलीगढ़---

बेहली दरवाजे, ——, में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट फरने वालों की गिरफ्तारी । खं० १३६, पं० ३८१।

.ग्रसलाई (ग्राजमगढ़)---

ग्राम — में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा ग्रायोजित सभा का भग किया जाना। खं० १३६, पृ० ३६१-३६४।

भ्रागरा--

- ---- जिले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्ट । खं० १३६,पृ० ३७८-३७६ ।
- ---- तथा मथुरा जिलो की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांघ की प्रावश्यकता। खं०१३६,पृ०११६।

ग्राजमगढ्---

- —— जिले में कम्यूनिस्टो की गिरफ्तारी। खं०१३६,पृ०३६१।
- —— जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण। खं० १३६, पु० १२४।
- —— तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण । खं० १३६ पृ० १२४–१२५ ।
- फैजाबाद तथा जिलों में कुछ भागों को बदलने के लिये सुझाव। खं० १३६, पृ० १२–१३।

इगलास——

जालौन ग्रौर —— में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुकुम । खं० १३६, पृ० ११५–११६।

इलाहाबाद--

मिर्जापुर तथा - — — जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं०१३६, पृ०२८०-२८१।

ईसानगर--

थाना — जिला खीरी का भवन । ग्रीर थाना कर्मचारियों के लिये । क्वार्टर । खं० १३६, पू० ३७३ — ३७४।

ত্তমাৰ—

--- जिले में थानेवार कत्ल और डाके, तथा गुंडों, बदमाशों ग्रादि की सूची । ख० १३६, पृ० ३८८।

एटा---

- —— गजहुंडवाडा सड़क का सुघार । स्रं० १३६, पृ० १८६ ।
- —— जिले में ग्राम समितियों ग्रीर उनका डाकुग्रों से मुकाबला। खं० १३६, पु० ३८५।

कनसल--

कस्बार राजा परगने---

बनारस जिले के --- में ग्रोले से क्षति । खु० १३६, पु० १५।

कानपुर-

- में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रक्त उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।
- ——— शहर में ईंघन सप्लाई करने का टेंडर । खं० १३६, पृ० १६०— १६१।

कानपुर रीजन--

 — में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के परिमट। सं० १३६, पु० ३०।

कारीपाकर--

——-सीतापुर में डकैती और उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पू० ३८७।

कृष्ण नगर---

कनखल की —— कालोनी में जल-व्यवस्था । खं० १३६, पृ० १७८– १७६।

कोंच--

मुभाव नगर से सम्बद्ध—— (जालौन)
पुलिस स्टेशन के हिस्ट्रीशीटरों के
रिजस्टर नम्बर का गायब होना।
सं० १३६, पू० ३८४।

कोटद्वारा (गढ़वाल)---

न्न साम स्टेट में जमीन का वितरण। सं० १३६, प्० १८-१६।

स्रोरी---

थाना ईसा नगर जिला——का भवन और थाना कर्मचारियों के लिये क्वार्टर। सं० १३६, पु० ३७३-३७४।

गंजडुंडवाङ्ग--

एटा---- सड़क का सुघार । खं०१३६, पु० १८६।

गाजीपुर---

- म्राजमगढ़ तथा —— जिलों के लिये नलकूपों का वितरण । सं० १३६, पृ० १२४–१२५।
- ---- की जमनिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमें श्रौर उनमें सजाएं। खं० १३६, पृ० ३७२।
- —— कलंदटरी में विचाराधीन मुकद्दमे। खं० १३६, पृ० १४–१५।
- ---- के विरनो थाने की इमारत नई बनाने की योजना। खं० १३६, पु०३७४।
- प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला——, के मंत्री, श्री दल ग्रृंगार द्वे, पर ग्राम मण की जांच। सं०१३६, पृ०३६८-३६९।

गिन्नौर--

जिला बदायूं में सहस्रवान से — — तक पक्की सड़क की ग्रावश्यकता । सं०१३६, पृ०२८४। [स्थानिक प्रश्न]

गोंडा---

जिला —— की तहसील तरबगंज में विकास कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

जिला — में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की ग्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० २७५-२७६।

गोरखपुर—"

---- जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप । खं० १३६, पृ०१२३।

--- जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही । खं० १३६, पृ० २७६-२८०।

पक्षड़ी भउनियां, जिला ——, के वन का क्षेत्रफल। खं०१३६, पृ०२८४। ———विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल।

खं० १३६, पृ० ३८१।

चन्दौसी--

---- (मृरा ाबाद)में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३८५-३८६।

चरखारी--

महोबा एवं — के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत । खं० १३६, पु०२६-३०।

खाता---

जिला मथुरा की तहसील — में गर्की का नाला निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० ११७-११८।

जबहीं घाट---

गंगा नदी में ---- पर नाव-दुर्घटना। खं० 🎎३६, पृ० १८७-१८८।

जसराना---

तहसील —— जिला मैनपुरी में सिचाई का प्रबन्ध। खं० १३६, गु० ११६।

जालौन---

---- ब्रौर इगलास में रिजस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुक्म। खं० १३६, पृ० ११५–११६।

जौनपुर--

--- जिले के ग्राम पांडेपुर तथा समस्त जिले मे डकैतियों की संख्या। खं० १३६,पृ०३६०-३६१।

---- जिले में कलेक्झन विभाग के कर्मचारी । खं० १३६, पृ० १३– १४।

---- जिले मे गोमतीकी बाढ़ से क्षति । खं० १३६, प० ६–८।

—— जिले मे ग्राम रक्षा समितियों का संगठन ग्रौर ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेस । खं० १३६, पृ० ३८६।

------ जिले में "घोडारोशन घास" को नष्ट करने का प्रबन्ध । खं०१३६, पु०१८ ।

---- जिले में टी० बी० के टीके। खं० १३६, पृ० १८१-१८२।

---- में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता । खं०१३६, पु०२८।

---- जेल में सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल के भागे हुये केंदी तथा उनमे हरिजनों की संख्या । खं० १३६, पृ० ३७७ ।

मांसी---

जिला — में वेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की श्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० ११५ ।

--- जिले में जंगली गायों व बैलों से फसल को हानि । खं० १३६, पृ० १६। डाक् मान स्टिह के गिरोह का — की पुलिस के घेरे में निकलना। खं० १३६. पृ० ३७४-३७६।

----शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां ग्रीर उनकी रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३८४।

टनकपुर--

जिला नैनीताल की ---- मंडी में प्लाटों का नीलाम । खं० १३६, पू० १४–१६।

टेहरी-गढ़वाल---

जिला की निदयों की घाटियों में सिचाई के साधनों का स्रभाव । खं० १३६, पु० १०६-१०७।

तरबगंज--

जिला गोडा की तहसील——— मे विकास कार्य । खं० १३६, पु० २७७।

तरया-सुजान---

देवरिया जिले मे ---- के टेस्ट वर्क का बंद होना । खं० १३६, पृ० २४-२५।

तहसील ठाकुरद्वारा-

—— जिला मुरादाबाद में श्रोलों से हानि । खं० १३६, पू० २६।

तुलसीपुर---

बसरामपुर व ——— के बीच राप्ती नदी पर डंक बनाने का विचार । स्तं० १३६, पृ० १०६–१०६ ।

देवरिया---

—— जिले मे दुदेही ग्रदालत पंचायत के सरपंच की मुग्रत्तली । खं० १३६, पु० १८०-१८१।

—— लाक-म्रप में कॅदियों की जगह। खं० १३६, पु० ३७६।

नकुड़—

तहसील —— जिला सहारनपुर में नलकूपों का कार्य । खं० १३६, पृ० ११८ ।

नानपारा तहसील-

------ भाना खेरीघाट के पाम चिकि-त्मालय भवन का निर्माण । खं० १३६, पृ० १६० ।

नेपाल---

----- भेजी गयी पी० ए० मी० की यूनिटो पर व्यय। खं० १३६. पु०३७६ः

नोट घाट--

जिला झामी में वेतवा नदी के ——— पर पुल के श्रावश्यकता। सं० १३६, पृ० ११४।

पकड़ी नउनियां---

-----, जिला गोरखपुर के बन का क्षेत्रफल । खं० १३६, पू० २६४ ।

परियत-बाजार---

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार----- सड़क में ली गयी भूमि का मुग्रावजा। खं०१३६, पृ०११७।

पांडेपुर---

जौनपुर जिले के ग्राम—— तथा समस्त जिले में डकैतियों की सख्या । स्रं० १३६, पु० ३६०–३६१ ।

पिहानी---

---- (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता। खं० १३६, पृ० ३७६-३८०।

प्रतापगढ्—

- —— जिले के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मचारियों की संख्या। खं० १३६, पु० ३७७।
- ---- जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस। खं० १३६, पू० ३८२।
- ---- जिले में विद्यार्थी म्नान्दोलन के सम्बन्ध में विद्यायियों पर म्नि-योग। खं० १३६, पृ० ३६७-३६८

[स्थानिक प्रक्त]

फर्रुखाबाद---

—— के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गतवर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरिया। खं० १३६, पृ० ३८३–३८४।

फ़र्रुखाबाद-फतेहगढ़---

मे वाटर वर्क्स योजना तथा
 पृथक पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने
 की मांग । ख० १३६, पृ० १८१।

फीरोजाबाद---

---- की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा । खं० १३६, पृ० २८६। सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, -----, का हेड क्वार्टर । खं० १३६, पृ० २८४-२८६।

फंजाबाद--

- ---- के प्राइवेट जुनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का ग्रादेश। खं० १३६, पृ० ३७६।
- —— तथा स्राजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को बदलने के लिये सुझाव। ख० १३६, पृ० १२-१३।

बख़िरा—

--- (बस्ती) झील से नहर निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० १०७-१०८।

बदायूं-

श्रिला — में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की श्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० २८५ ।

बनारस--

- ---- जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली । खं० १३६, पृ० ५-६।
- ---- जिले मे जमींदारी उन्मूलन कोष मे गबन । खं० १३६, पृ० २८ ।

बसन्त कन्या ड़न्टर कालेज, कमक्षा, शहर —— का स्थानाग्तरण। खं०१३६, पृ० ३८७।

बरेली---

- जिला में बन्दूक, राइफल ग्राँर रिवाल्वर के लाइसेस। ख० १३६, पु० ३७६-३७७।
- शारदा नहर के हैडवर्क्स का हेड क्वार्टर ----- मे रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४--११५।

बलरामपुर---

--- व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डैक बनाने का विचार । ख॰ १३६, पृ० १०८-१०६।

बलिया--

- जिला——में हरिजनों के लिये मक्तान तथा पीने के पानी के लिये सहायता एवं कुद्यों का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३८७—३८८।
- --- जिले मे हरिजन लेखपालो की संख्या । खं० १३६, पृ० ३१।
 - ---- मे पंचायत-मंत्रियों को वेतन मिलने मे विलम्ब । खं० १३६, पृ० १८०।

बस्ती--

- जिला बोर्ड— को पी० डब्लू० डी० द्वारा वापस की हुई सड़के । ख० १३६, पृ० ११०-१११।
- ---- जिले में ग्रनेक गांवों को वर्षा से क्षति । खं० १३६, पृ० २६ ।
- ——— जिले मे बांघों की मरम्मत की स्रावश्यकता । ख० १३६, पृ० १०५-१०६।
- ———— जिले में बी॰ सी॰ जी॰ के टीके। खं॰ १३६, पृ॰ १८२– १८४।
- —— जिले मे राप्ती के किनारे बने हुये बांघ पर व्यय । खं० १३६, प० ११६–११७।
- थाना मेहदावल जिला में चोरियां, डकैतियां श्रौर हत्याएं। खं० १३६, पृ० ३७३।

बहराइच--

---- जिले में सम्यूनदी से नहर निकातने की योजना । खं० १३६, पु० १२३-१२४।

बहादुरीपुर--

—— ग्रीर सहिजनी के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना। खं० १३६. पृ० ११८ –११६।

बहिलपुरवा स्टेशन--

——, जिला बांदा, पर वन विभाग की लकड़ी में ब्राग लगना । खं० १३६, पृ० २८१ – २८२।

बांदा---

---- जिले में नरैनी - कार्लिजर सड़क पर पुल निर्माण योजना । खं० १३६, पृ० ११०।

महिलपुरवा स्टेशन, जिला ——, पर बन विभाग की लकड़ी में आग लगना। खं० १३६, पृ० २८१— २८२।

बाराबंकी--

--- जिले के भूमिघर किसान। खं० १३६, पृ० २६।

बिरनो--

गाजी दुर के — थाने की इमारत नई बन बाने की योजना । खं० १३६, पृ० ३७४।

विलारी तहसील--

मुरावाबाद जिले की — में स्रोलों से हानि। खं० १३६, पृ० २४।

बुलन्दशहर--

—— जिले के ग्रहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२-२७३।

—— जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत डाके और कृत्व। खं० १३६,पृ० ३६४-३६४। पंचवर्षीय योजना के प्रान्तर्गन------जिले में नलक्षीं का निर्माण गांव १३६ पर १०३--१०४।

भट्टहट--

मऊ---

---- (म्राजमगढ़) में रंगाई व धृनाई का कारम्बःना । खं० १३६. पृ० २८४।

—— थाना (ब्राज्ञमगढ़) में चोरियां ब्रोर डकैतियां। खं० १३६. पृ० ३८८।

मड़ियाहू---

—— के म्रन्तर्गत सीतापुर ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग । खं० १३६, पृ० १८२।

—— तहसील में पशु-चिकित्सालय की स्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० १०।

मथुरा-

द्रागरा तथा — जिलों की सिचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की स्रावस्थकता। खं० १३६, पृ० ११८।

—— जिले मे ग्रमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना ग्रौर कुछ ग्रार्य समाजियों की गिरफ्तारी। स्रं० १३६, पृ० ३६५–३६७।

मधुवन--

——, म्राजमगढ़, में एलोपैथिक म्रस्य-ताल का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३५१–३६०।

महोबा-

— एवं चरसारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत । खं० १३६, प्० २६-३०।

[स्थानिक प्रदत]

मिर्जापुर--

—— तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०–२८१।

—— सीमेंट फैक्टरी के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, प्० २६६-२६८।

मिलक---

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा ---- तहसीलों में श्रोले से हानि। खं० १३६, पू० २७।

मुजपफ़रनगर--

जिला—में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी । खं० १३६, पृ० १७।

---- जिले में नलकूपों का निर्माण । खं० १३६, पृ० १११–११२।

----, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २८।

मुरादाबाद--

जिला —— में चार वर्षों से ग्रधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर। खं० १३६, पू० ३८४।

जिला — में देशी व विलायती शराब की दुकानें। खं० १३६, प्०१२४।

मेंहदावल (बस्ती)---

मेरठ--

—— के सरकारी रोडवेज कारलाने द्वारा चालू की गई बसें। खं० १३६, पु० ३०–३१।

जिला — में विकास तथा नियोजन प्रस्थय। खंद १३६, पूर्व २७८— २७६। नगरपालिका——— में सहायक हाजिरी श्रफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी श्रावेश । खं० १३६, पु० ३८२-३८३।

मुजफ्फ़रनगर, —— तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २६। —— में विदेशी शराब बेचने के स्थान। खं० १३६, पृ० ११६-१२०।

रामनगर--

—— में फूड प्रिजर्वेशन फैक्टरी की योजना । खं० १३६, पृ० २८४।

रामपुर--

राजकीय इंटर कालिज, ----, में कक्षा ११वीं में कामर्स की जिक्षा। सं १३६,पृ० ३८६।

रामपुर बाजार-

जौनपुर जिले में —— परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुम्रावज । खं० १३६, पृ० ११७।

रायबरेली--

जिला — के याना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा ग्रीर उसमें गिरफ्तारियां । खं० १३६, पृ० ३७१-३७२।

--- जिले में रोडवेज की बर्सो को चलाने का विचार । खं० १३६, पृ० २५।

मौजा डीह, जिला——, में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, पृ० ३७६।

शारवा नहर, पुरवा ब्रान्च, जिला ——, में लादी के कारण किसानों को हानि। लं० १३६, पू० ११२।

रुड़की---

पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत—— तहसील में कार्य । खं० १३६, पृ० २७७।

नखनऊ---

- ---- कलक्टरी में हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की भर्ती। खं० १३६, पृ० २१–२२।
- ---- जिले के बाद पीड़ितों को लगान में छुट । खं० १३६, पृ० २८।
- --- जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यारियों की मुख्य जेलों के ग्रध्ययन के लिये यात्रा ग्रीर उस पर व्यय। खं० १३६, पु० ३८१-३८२।
- पंचवर्षीय योजना के ऋषीन—— जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पु० २७३ - २७४।
- भेड़िया बासक राम् के लिये बलरामपुर ग्रह्मताल, ———, में प्रबन्ध। खं० १३६, पू० १८६-१६०।

शाहाबाद--

रामपुर जिले की —— तथा मिलक तहसीलों में ग्रोले से हानि । खं० १३६, प्० २७।

सलोन---

तहसील —, जिला रायबरेली, में नहर के विस्तार की श्रावक्यकता। सं० १३६, पृ० १०७।

सहसवान---

जिला बदायूं में ---- से गिन्नौर तक पक्की सड़क की ग्रावश्यकता। खं० १३६, पृ० २८५।

सहारनपुर--

मुजफ्करनगर, मेरठ तथा —— जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टंक्स। खं० १३६, पृ० २६।

सहिजनी---

बहादुरीपुर झौर —— के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थनाः। खं० १३६, पु० ११८-११६।

सीतापुर---

मिंडियाहूं के घ्रन्तर्गत ---- प्राम में मिंडिला चिकित्सालय की मांग। खं० १३६, पृ० १८२।

सुल्तानपुर--

- —— जिले में नहर की खुदाई के लिये ग्रधिकृत भूमि खंट १३६ पुठ १०४—१०५:
- ----- जिले में महकारी नलक्ष खंट १३६. पृट १०४।

संदेपुर--

---- में जनाने अस्पनाल की आवश्य-कता। खं० १३६. पु० १०२।

हमीरपुर--

- जिला ---- में कम्हरिया मागर बांध की मरम्मत । खं० १३६, पृ० १२३।
- जिला ---- में निर्माण की गई पक्की सड़कें। खं० १३६, पृ० १२२।
- –––– में गत वर्ष दिवाली के ग्रवसर पर पकड़े गये जुश्राड़ी। खं० १३६, पृ० ३⊏३।

हरदोई--

—— जिले से भूमि संघ व्यवस्था संबंधी प्रार्थना पत्र । खं० १३६, पृ० १३ ।

हाथरस--

- ---- तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप। खं० १३६, पृ० १२२।
- प्र० वि० ---- नगर में पैविलियन के लिये नगरपालिका को ग्रांट । खं० १३६, पृ० ३८१।
- १६४७ में में सामूहिक जुर्माने की घनराशि श्रौर उसका व्यय किया जाना । खं० १३६, प्० ३८७।

स्यायीकरण--

प्र० वि० —— १६४६ के मध्य में ग्रस्थायी रूप से नियुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स ग्राफ स्कूल्स की संस्था ग्रीर उनका —— । खं० १३६, पृ० ३८६ ।

स्थायी समितियो-

कतिपय के निर्वाचन का कार्यक्रम। खं० १३६, पु० १७२।

---- के निर्वाचन के नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना । खं० १३६, पृ० ४०४-४०५।

जित्त सिमिति, सार्वजिनिक लेखा सिमिति, प्रावकलन सिमिति तथा विभिन्न —— के निर्वाचन में प्राप्त नाम- निर्देशनो के सम्बन्ध में सूचना । खं० १३६, पृ० २८७–२९४।

ह

हकीमों---

प्र० वि०— वैद्यों ग्रौर —— का रिजस्ट्रेशन। खं० १३६, पृ० १८७।

हड़ताल--

प्र० वि०— प्रदेश व्यापी मेहतर—— खं० १३६, पृ० १७६ ।

हत्यार्ये---

प्र० वि० चन्दौसी (मुरादाबाद)
में थाने के समीव लगभग दो बजे
दिन के तीन — । खं० १३६,
प्०३ इप्र-३ द६ ।

हथियार-

प्र० वि० प्रदेशीय मालखानों में प्राहिबिटेड बोर के —— तया उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० १८०।

हरगोविन्द सिंह, श्री--

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विघेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १९१।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

हरिजन-

प्रठ वि०— बलिया जिले में ——— लेखपालों की संस्था । खं० १३६, प० ३१ ।

हरिजन ग्रमीनों--

प्र० वि० — के रिक्त स्थानो पर हरिजनों को प्राथिमकता । खं० १३६, पृ० २७१-२७२ ।

हरिजन उत्थान-

प्र० वि०—— उत्तर प्रदेश में — के तिये १९५३ – ५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८८।

हरिजन क्लकों तथा चपरासियों-

प्र० वि०—लखनंक कलक्टरी में ——की भर्ती। खं० १३६, पृ० २१-२२।

हरिजनों---

प्र० वि० — जिला बिलया में — के लिये मकान तथा पीने के पानी के लिये महायता एवं कुग्रों का निर्माण । खं० १३६, पृ० ३८७-३८८।

प्र० वि० लेवर स्राफिससं तथा कंसिलियेशन द्याफिससं की नियु-क्तियां स्रोर उनमें — का स्रतुपात। खं० १३६, पृ० ३६५।

प्र० वि०—विवायक निवासों के फरीशों सथा लिपटमैनों में —— को न लेना। खं० १३६, पृ० ११३।

प्र० वि०—हरिजन ग्रमीनों के रिक्त स्थानों पर —— को प्रायमिकता । खं० १३६, पृ० २७१-२७२।

हरिप्रसाद, श्री---

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

'हरिश्चन्द्र ग्रष्ठाना, श्री—

स्तर प्रवेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। लं १३६० प्र १४०-१४१।

हरिश्चल वाजपेयी, श्री—ं

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिर-पतारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की ग्रवहेलना के विषय में विशेषाधिकार । समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ४२१ ।

हरि सिंह, श्री---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विषेयक, १६५४। खं० १३६, पृ०५२।

हाई स्कूल--

प्र० वि०— —— व इंटरमीडियेट कौ परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का प्रयोग । खं० १३६, पृ० २६६– २७० ।

हानि—

- प्र० वि०— झांसी जिले में जंगली गांयों व बैलों से फसल को —— । खं० १३६, प्०१६।
- प्र० वि०— तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में ग्रोलों से—— । खं० १३६, पृ० २६ ।
- प्र० वि०--- मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ग्रोलों से ------। सं० १३६, पृ० २४।
- प्र० वि०— रामपुर जिले की शाहाबाद तया मिलक तहसीलों में ग्रोलों से —— । खं० १३६, पृ० २७ ।
- प्र० वि०— शारवा नहर, पुरवा बांच, जिला रायबरेली, मे खांदी के कारण किसानों को —— । खं० १३६, पृ० ११२ ।

हिंडन नदी--

प्र० वि० — ग्रागरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये — पर बांघ की ग्रावश्यकता । खं० १३६, पृ० ११ = ।

हिस्ट्रीशीटरों---

प्र० वि० सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन से के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

हिस्सेदार-

प्र० वि० — खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर से किसानों को ——— बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १६।

हेड क्वार्टर---

- प्र० वि० शारदा नहर के हेडवर्ष स का — बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४ — ११४।
- प्र० वि०--- सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, का-----। खं० १३६, पृ० २८५-२८६।

हेड वर्क्स-

प्र० वि०-- शारदा नहर के ---- का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४-११४।

होमियोपैथिक डाक्टरों--

प्र० वि०----- की रजिस्ट्री। खं० १३६, प्०१८२।